वार्षिक रिपोर्ट

2019-20

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

सत्यमेव जयते

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

वार्षिक रिपोर्ट
2019-20

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, सूचना एवं प्रसारण तथा भारी उद्यम और लोक उपक्रम मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर पत्रकारों को मंत्रिमंडल के फैसलों से अवगत कराते हुए, 22 जनवरी, 2020 को नई दिल्ली में

सत्यमेव जयते

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

वार्षिक रिपोर्ट
2019-20

विषय सूची

	वर्ष की प्रमुख उपलब्धियां	07
1.	एक झलक	27
2.	मंत्रालय की भूमिका और कार्य	31
3.	मंत्रालय की नई पहल	35
4.	सूचना क्षेत्र की गतिविधियां	41
5.	प्रसारण क्षेत्र की गतिविधियां	97
6.	फ़िल्म क्षेत्र की गतिविधियां	165
7.	अंतरराष्ट्रीय सहयोग	221
8.	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण	225
9.	मंत्रालय की सेवाओं में दिव्यांगजनों का प्रतिनिधित्व	227
10.	राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग	231
11.	महिला कल्याण संबंधी गतिविधियां	235
12.	सतर्कता संबंधी मामले	237
13.	नागरिक चार्टर और शिकायत निवारण तंत्र	239
14.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित मामले	243
15.	लेखांकन और आंतरिक लेखा परीक्षा	247
16.	लेखा पैरा	261
17.	कैट के फैसलों/आदेशों पर अमल	263
18.	योजना परिव्यय	265
19.	मीडिया इकाई-वार बजट	269
20.	सांगठनिक चार्ट	273

26 नवंबर, 2019 को गोवा, पणजी में 50वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अवसर पर इंटरैक्टिव डिजिटल प्रदर्शनी 'इफ्फी@50' में छात्रों की भागीदारी

25 जुलाई, 2019 को दिल्ली के दूरदर्शन केंद्र में 8 डीडी स्टूडियो और भू–केंद्रों में वीडियो वॉल्स के उद्घाटन के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर का संबोधन

वर्ष की प्रमुख उपलब्धियां

सूचना स्कंध

- माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडु ने 6 सितंबर, 2019 को नई दिल्ली में प्रवासी भारतीय केंद्र में आयोजित एक समारोह में दो पुस्तकों **'लोकतंत्र के स्वर' (खंड–2)** और **'द रिपब्लिकन एथिक्स' (वॉल्यूम–2)** का विमोचन किया। ये पुस्तकें राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द के कार्यकाल के दूसरे वर्ष में (जुलाई 2018 से जुलाई 2019 तक) दिए गए उनके 95 भाषणों का संकलन हैं।

उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू 6 सितंबर, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में भारत के राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द के चुनिंदा भाषणों की दो पुस्तकों–'लोकतंत्र के स्वर' (खंड–2) और 'द रिपब्लिकन एथिक्स' (वॉल्यूम–2) का विमोचन करते हुए। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावर चंद गहलोत तथा अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे

- **'भारत छोड़ो आंदोलन'** की वर्षगांठ के अवसर पर 9 अगस्त, 2019 को सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'महात्मा गांधी : चित्रमय जीवन गाथा' पुस्तक भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द को भेंट की।

- राष्ट्रीय **प्रेस दिवस** के अवसर पर माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडु ने **'पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए 2019 के राष्ट्रीय पुरस्कार'** विजेताओं को सम्मानित किया। भारतीय प्रेस परिषद द्वारा नई दिल्ली में 16 नवंबर, 2019 को आयोजित इस समारोह में उन्होंने पत्रकारिता में उत्कृष्ट और असाधारण कार्य करने वालों को ये पुरस्कार दिए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने 'नॉर्म्स ऑफ जर्नलिस्टिक कंडक्ट' के 2019 संस्करण, भारतीय प्रेस परिषद की निर्देशिका और स्मारिका भी जारी की। माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी समारोह में हिस्सा लिया और मीडियाकर्मियों के सामने आने वाले प्रमुख मसलों पर अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर पांच देशों–बंगलादेश, भूटान, म्यामां, नेपाल और श्रीलंका की प्रेस परिषदों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया और ''रिपोर्टिंग– इंटरप्रिटेशन : ए जर्नी'' विषय पर परिचर्चा भी आयोजित की।

- माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा 11 अगस्त, 2019 को चेन्नई में आयोजित

16 नवंबर, 2019 को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडु ''नॉर्म्स ऑफ जर्नलिस्टिक कंडक्ट'' (2019 संस्करण) का विमोचन करते हुए। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, सूचना एवं प्रसारण तथा भारी उद्योग एवं लोक उपक्रम मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे

एक समारोह में लोकसंपर्क और संचार कार्यालय द्वारा **उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के दो वर्षों के बारे में प्रकाशित पुस्तक 'लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग' का विमोचन किया।** माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने समारोह की अध्यक्षता की।

➢ प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित **माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडु के चुने हुए भाषणों के संकलन (खंड–1)** का विमोचन पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने किया।

➢ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने विशेष अवसरों पर सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और प्रमुख घटनाओं को लेकर विभिन्न **संचार और मल्टीमिडिया प्रचार अभियानों की पहल की** जिनमें निम्नलिखित शामिल थे:

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली एन.डी.ए. सरकार के **शपथग्रहण समारोह** को मंत्रालय के विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर लाइव स्ट्रीमिंग मोड में प्रसारित किया गया।

➢ पत्र सूचना कार्यालय के ट्विटर पेरिस्कोप पर हुए लाइव स्ट्रीमिंग प्रसारण को 60 हजार इम्प्रेशंस मिले और पत्र सूचना कार्यालय के फेसबुक पेज को 400 हजार/40 लाख लोगों ने देखा।

➢ भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द ने शपथग्रहण समारोह की शानदार कवरेज के लिए पत्र सूचना कार्यालय सहित सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की सराहना की है।

- **महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर :**

➢ लोकसंपर्क और संचार कार्यालय ने नई दिल्ली के इंडिया गेट लॉन में 2 से 6 अक्टूबर 2019 तक ''स्वच्छ भारत, सशक्त भारत – बापू के सपनों का भारत'' नाम की प्रदर्शनी का आयोजन किया। इसका उद्घाटन माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान और संस्कृति मंत्री श्री प्रह्लाद सिंह पटेल के साथ संयुक्त रूप से किया।

➢ लोकसंपर्क और संचार कार्यालय ने देश भर में 18 स्थानों पर इसी तरह की प्रदर्शनियों का आयोजन किया।

➢ प्रकाशन विभाग ने गांधीजी के संदेश के प्रचार–प्रसार के लिए लोकसंपर्क और संचार कार्यालय द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों के साथ–साथ उदयपुर, आगरा और तुतुकुडी में आयोजित विभिन्न पुस्तक मेलों में भी हिस्सेदारी निभाई।

➢ प्रकाशन विभाग ने 'संपूर्ण गांधी वाङ्मय' के 97 खंडों

के इलेक्ट्रानिक संस्करण (कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी का हिंदी संस्करण) तैयार किया।

➢ प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित 'योजना' पत्रिका और 'आजकल' पत्रिका के अक्टूबर 2019 अंक महात्मा गांधी की विरासत और आदर्शों को समर्पित थे।

➢ महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के सिलसिले में मल्टीमीडिया प्रदर्शनियां फ्रैंकफर्ट, अबू धाबी और लंदन के अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेलों के दौरान भारतीय मंडप में आयोजित की गईं।

- **गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती के अवसर पर कार्यक्रम :**

➢ 12 नवंबर को भारत के माननीय राष्ट्रपति के सुल्तानपुर लोधी के दौरे और 9 नवंबर, 2019 को माननीय प्रधानमंत्री के पंजाब में सुल्तानपुर लोधी, करतारपुर गलियारे और डेरा बाबा नानक के दौरों का सोशल मीडिया समेत मंत्रालय के तमाम मंचों से सीधा प्रसारण किया गया।

➢ लोकसंपर्क और संचार कार्यालय द्वारा अमृतसर में 8 से 12 नवंबर, 2019 तक ध्वनि और प्रकाश प्रदर्शनी और सुल्तानपुर लोधी में डिजिटल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।

महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर 2 अक्टूबर, 2019 को नई दिल्ली में संसद भवन में आयोजित एक समारोह में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर चरखा कातते हुए

➢ लोकसंपर्क और संचार कार्यालय ने गुरु नानक देव जी के दर्शन पर विशेष लोकसंपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया। 12 नवंबर, 2019 को कार्यालय ने दैनिक समाचार पत्रों में चौथाई पेज का विज्ञापन भी जारी किया।

➢ पत्र सूचना कार्यालय ने डेरा बाबा नानक में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास ज़ीरो प्वाइंट पर करतारपुर साहिब गलियारे को आवागमन के लिए खोले जाने के बारे में भारत और पाकिस्तान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने पर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की।

- **सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती और राष्ट्रीय एकता दिवस** के अवसर पर 31 अक्टूबर, 2019 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 'स्टेच्यू ऑफ यूनिटी' पर पुष्पांजलि अर्पित करने और राष्ट्रपति द्वारा नई दिल्ली के पटेल चौक से तथा गृहमंत्री द्वारा ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम से एकता दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना करने के कार्यक्रमों का सोशल मीडिया समेत मंत्रालय के विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों पर प्रसारण/लाइव स्ट्रीमिंग किया गया।

➢ लोकसंपर्क और संचार कार्यालय ने सरदार पटेल पर करीब 30,000 ब्रोशर्स/हस्त पुस्तिकाओं का डिज़ाइन

और मुद्रण करवाया और उन्हें गृह मंत्रालय को दिया।

- 60 सेकेंड के ऑडियो–वीडियो स्पॉट्स का विभिन्न टेलीविजन नेटवर्क्स पर प्रसारण किया गया और कार्यालय ने बाहय प्रदर्शनियां भी आयोजित कीं।

- प्रकाशन विभाग ने अपनी प्रमुख पत्रिकाओं के जरिए हाल में शुरू किए गए देश के सर्वोच्च असैनिक सम्मान ''सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार'' का व्यापक प्रचार–प्रसार किया।

- माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडु द्वारा **जलियांवाला बाग नरसंहार की शताब्दी** पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के कार्यक्रम को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सोशल मीडिया चैनलों पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए प्रसारित किया गया।

- लोकसंपर्क और संचार कार्यालय के चंडीगढ़ स्थित क्षेत्रीय लोकसंपर्क कार्यालय ने 'स्वतंत्रता संग्राम' के बारे में जलियांवाला बाग में 11 से 13 अप्रैल, 2019 तक **तीन दिवसीय फोटो प्रदर्शनी** का आयोजन किया।

- प्रकाशन विभाग ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नई दिल्ली के सहयोग से 15 अप्रैल को 'याद करो कुर्बानी' नाम का विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किया जिसमें दिल्ली के तीन स्कूलों के बच्चों ने देशभक्ति के गीत गाये, गद्यांश पढ़ कर सुनाए और राष्ट्रवादी विषयों पर नाटिकाएं प्रस्तुत कीं।

- 26 जुलाई, 2019 को **करगिल विजय दिवस की 20वीं जयंती** पर आयोजित समारोह का सीधा प्रसारण किया गया।

- द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर 26 जुलाई, 2019 को माननीय राष्ट्रपति के माल्यार्पण समारोह और 27 जुलाई, 2019 को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में करगिल विजय दिवस समारोह 2019 में मुख्य अतिथि माननीय प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का रेडियो/टेलीविजन पर प्रसारण समेत मंत्रालय के सभी प्रमुख प्लेटफार्मों से प्रसारण किया गया।

- सभी निजी उपग्रह चैनलों को इससे संबंधित कार्यक्रमों का प्रसारण करने के लिए परामर्श जारी किया गया।

- मंत्रालय के मीडिया इकाइयों ने जम्मू–कश्मीर से संबंधित संविधान के **अनुच्छेद 370 को निरस्त** किए जाने, और इस संबंध में संसद में पारित विधेयक तथा भारत के माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा गृहमंत्री के भाषणों को विस्तृत कवरेज दी और इसपर विशेष अपडेट्स भी दिए।

- क्षेत्रीय प्रेस से फीडबैक प्राप्त करने के लिए विस्तृत प्रणाली भी बनायी गई और इसके जरिए क्षेत्रीय समाचार माध्यमों से सूचना एकत्र कर इसे पत्र सूचना कार्यालय की विज्ञप्तियों के जरिए प्रसारित किया गया।

- भारत सरकार ने मंत्रियों और भारतीय सेना के वरिष्ठ प्रतिनिधि के दौरे, बैठक और संपर्क कार्यक्रम के लिए भी विशेष कवरेज प्रदान किया गया।

- मंत्रालय और इसकी मीडिया इकाइयों ने 26 नवंबर, 2019 को **'संविधान दिवस'** मनाया और संविधान की प्रस्तावना का पाठ कर शपथ ली। इस अवसर पर की गई अन्य पहल इस प्रकार हैं:

- प्रकाशन विभाग ने 'भारत के संविधान' के बारे में 6 से 26 नवंबर, 2019 तक ट्विटर पर (@dpd_India) क्विज का आयोजन किया।

- लोकसंपर्क और संचार मंत्रालय के क्षेत्रीय लोकसंपर्क और संचार कार्यालयों ने देशभर में विशेष लोकसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किए।

- विभिन्न प्लेटफार्मों पर ट्वीट, फोटो और वीडियो के जरिए कार्यक्रमों का त्वरित और विस्तृत प्रचार–प्रसार किया गया।

- सरकार ने यह भी फैसला किया है कि नागरिकों के कर्तव्यों (मूल कर्तव्यों सहित) के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 26.11.2019 से 26.11.2020 तक एक साल का अभियान चलाया जाएगा जिसमें विभिन्न प्रकार की कई गतिविधियां संचालित की जाएंगी।

- माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने **सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों के प्रमुख निर्णयों** के बारे में 8 सितंबर, 2019 को नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया।

- उन्होंने सरकार के 100 दिनों के महत्वपूर्ण निर्णयों को लेकर एक पुस्तिका **'जन कनेक्ट'** भी जारी की और एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जिसका विषय था–'फरदरिंग इंडियाज डिवेलपमेंट– 100 डेज ऑफ बोल्ड इनिशिएटिव्ज एंड डिसिसिव एक्शन्स' (भारत

के विकास को बढ़ावा—महत्वपूर्ण पहल और निर्णायक कार्रवाई के 100 दिन)। इसका आयोजन लोकसंपर्क और संचार ब्यूरो ने किया।

- माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने 22 जुलाई, 2019 को मीडियाकर्मियों के साथ संवाद में **सरकार के पहले 50 दिनों का रिपोर्ट कार्ड** प्रस्तुत किया। इसमें उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्णयों का उल्लेख किया और उन क्षेत्रों पर प्रकाश डाला जिनपर सरकार मुख्य रूप से ध्यान दे रही है। यह भी बताया कि इन 50 दिनों में भारत को 5 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने की रूपरेखा तैयार कर ली गई है।

➢ मोदी सरकार के 50 दिनों के बारे में लोकसंपर्क और संचार कार्यालय ने '50 डेज ऑफ मोदी गवर्नमेंट : डिसिसिव एंड डायरेक्शनल' नाम की एक पुस्तिका का डिज़ाइन और मुद्रण भी कराया।

- **2019 के लोकसभा चुनाव** को लेकर 'देश का महात्योहार' विषय पर लोकसंपर्क और संचार कार्यालय ने व्यापक और सघन आउटडोर मीडिया अभियान चलाया। इसमें सशस्त्र सेनाओं, युवाओं, बुजुर्गों और पहली बार मतदाता बनने वालों जैसे विभिन्न लक्षित समूहों में अपने लोकतांत्रिक अधिकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी पर जोर दिया गया।

➢ लोकसंपर्क और संचार कार्यालय ने रेडियो और टेलीविजन के जरिए चुनाव से संबंधित विषयों पर कई मतदाता जागरूकता अभियान चलाए और विभिन्न टैगलाइंस के साथ मुद्रित प्रचार अभियान शुरू किए।

➢ पत्र सूचना कार्यालय के सोशल मीडिया सेल ने मतदाता जागरूकता पर आधारित दिलचस्प क्लिपिंग (मीम) भी परीक्षण के तौर पर जारी की।

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर सरकार के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर 8 सितंबर, 2019 को नई दिल्ली में एक प्रेस कांफ्रेंस में 'जन कनेक्ट' नाम की पुस्तिका जारी करते हुए

- मंत्रालय और इसकी मीडिया इकाइयों ने सिर्फ **एक बार इस्तेमाल हो सकने वाले प्लास्टिक (सिंगल यूज प्लास्टिक—एसयूपी) का प्रयोग न करने को लेकर 'स्वच्छता ही सेवा'** विषय पर एक विस्तृत अभियान चलाया।

➢ मुख्य सचिवालय में प्लास्टिक फोल्डरों, प्लास्टिक की

बनी पानी की बोतलों, प्लास्टिक/पॉलीथीन की थैलियों और इसी तरह की अन्य वस्तुओं का इस्तेमाल बंद कर दिया गया है। इसी तरह की गतिविधियां विभिन्न प्रमुख मीडिया इकाइयों/संगठनों द्वारा भी की गई हैं।

- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की मंडलीय/क्षेत्रीय/शाखा मीडिया इकाइयों ने देश भर में 'श्रमदान' और व्यापक स्वच्छता अभियान चलाये।
- कई प्रमुख टेलीविजन चैनलों ने **प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान** चलाया है और मुद्रित माध्यमों में भी इसके विज्ञापन छपे हैं।
- प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए वीडियो और ग्राफिक्स के साथ सोशल मीडिया अभियान चलाया जा रहा है।
- जागरूकता गतिविधियां :–

लोकसंपर्क और संचार कार्यालय द्वारा लोक संपर्क कार्यक्रम

भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) का अपना रेडियो कार्यक्रम

- **वार्षिक बजट में स्वच्छता गतिविधियों** और उनके लिए आवंटित धनराशि के अनुसार जवाबदेह और बजट आवंटन के प्रावधान वाली स्वच्छता कार्रवाई योजना (एसएपी) पर मंत्रालय की सभी मीडिया इकाइयों/संगठनों द्वारा अमल किया जा रहा है। 2204.06 लाख रुपये लागत की एसएपी 2020–21 पर अमल किया जा रहा है और 1433.84 लाख रुपये की एसएपी 2020–21 तैयार कर ली गई है। **वित्तवर्ष 2018–19 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को स्वच्छता कार्रवाई योजना पर अमल के मामले में श्रेष्ठतम मंत्रालयों में से एक करार दिया गया है**। माननीय जलशक्ति मंत्री ने इसके लिए 6 सितंबर, 2019 को नई दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में मंत्रालय को पुरस्कार भी प्रदान किया।
- माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा **फिट इंडिया कार्यक्रम** के शुभारंभ का 29 अगस्त, 2019 को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से सीधा प्रसारण किया गया।
- इस कार्यक्रम का पत्र सूचना कार्यालय के सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के जरिए लाइव स्ट्रीमिंग भी किया गया। इसके अलावा शुभारंभ से पहले भी प्रचार के लिए वीडियो प्रोमो, फोटो के लाइव ट्वीट्स और वीडियो बाइट्स भी जारी किए गए।
- कार्यक्रम को और व्यापक तथा असरदार बनाने के लिए पत्र सूचना कार्यालय मीडिया घरानों को अभियान में शामिल होने के लिए समय–समय पर प्रेरित करता रहता है।
- माननीय प्रधानमंत्री ने 5 नवंबर, 2019 को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोलकाता में चार दिन के **पांचवें भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान उत्सव** का उद्घाटन किया। पत्र सूचना कार्यालय ने देश भर के 36 मीडियाकर्मियों के लिए 4–9 नवंबर, 2019 तक मीडिया टूर भी आयोजित किया। उद्घाटन समारोह के सिलसिले में प्रेस विज्ञप्तियां जारी की गईं और पत्र सूचना कार्यालय के सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पर तत्काल प्रचार की भी व्यवस्था की गई।
- माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामण ने 5 जुलाई, 2019 को ससंद में **केंद्रीय बजट 2019–20** पेश किया जिसका व्यापक कवरेज और प्रचार किया गया।
- वित्त मंत्री के बजट भाषण का सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सोशल मीडिया हैंडलों समेत तमाम प्रमुख प्लेटफार्मों पर प्रसारण/लाइव स्ट्रीम किया गया।
- पत्र सूचना कार्यालय ने अपनी वेबसाइट पर सूचनात्मक आंकड़े और प्रेस विज्ञप्तियां अपलोड कीं। प्रकाशन विभाग की 'योजना' और 'कुरुक्षेत्र' पत्रिकाओं के अगस्त अंक 'केंद्रीय बजट' पर आधारित विशेषांक थे।
- **21 जून, 2019 को आयोजित पांचवें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की व्यापक कवरेज की गई।**
- कवरेज का केंद्र–बिंदु माननीय प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने झारखंड के रांची के प्रभात तारा स्कूल मैदान में योगाभ्यास करने में देश का नेतृत्व किया। इस आयोजन का सोशल मीडिया हैंडल्स समेत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सभी प्रमुख प्लेटफार्मों पर लाइव स्ट्रीम किया गया।
- अंतरराष्ट्रीय योग दिवस–2019 के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए रेडियो जॉकी का राष्ट्रीय सम्मेलन (आईडीवाई–2019) आयुष मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा 15 जून, 2019 को नई दिल्ली में संयुक्त रूप से आयोजित किया गया।

- योग पर लोकसंपर्क और संचार कार्यालय की पांच दिन की भव्य प्रदर्शनी का रांची के एसेम्बली ग्राउंड्स में 20 जून, 2019 को उद्घाटन किया गया जिसमें योगासनों और योगविद्या का प्रदर्शन किया गया।

- स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारत के राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संदेश और भारत के **73वें स्वतंत्रता दिवस–2019** के अवसर पर लाल किले की प्राचीर पर प्रधानमंत्री द्वारा ध्वजारोहण एवं राष्ट्र को संबोधन का सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सोशल मीडिया समेत सभी प्रमुख प्लेटफार्मों से रेडियो/टेलीविजन/प्रसारण/लाइव के जरिए प्रदर्शन किया गया।

- पत्र सूचना कार्यालय ने इस अवसर पर विशेष ग्राफिक्स बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर अपलोड किए।

- प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित योजना और कुरुक्षेत्र पत्रिकाओं के सितंबर 2019 अंकों में स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री के संबोधन की प्रमुखता से प्रकाशित किया।

- **आयुष्मान भारत योजना के शुभारंभ का एक साल** पूरा होने पर पत्र सूचना कार्यालय ने केंद्रीय मंत्रियों और स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में काम करने वाले जाने–माने व्यक्तियों के लेखों का देश भर के प्रिंट मीडिया और पत्र सूचना कार्यालय ब्लॉग के लिए हिंदी, अंग्रेजी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद कराया।

केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर 5वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2019 के अवसर पर 21 जून, 2019 को नई दिल्ली में योगासन करते हुए

- कुपोषण की चुनौतियों से निपटने के लिए सितंबर का महीना देश भर में **पोषण माह** के रूप में मनाया गया। पत्र सूचना कार्यालय के क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों ने देश के विभिन्न भागों में अनेक कार्यक्रमों/आयोजनों के लिए मीडिया कवरेज उपलब्ध कराई।

- **भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों का दूसरा अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन** 5 अगस्त, 2019 को प्रवासी भारतीय केंद्र में आयोजित किया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने सम्मेलन में आए प्रतिनिधियों को अपने संदेश में सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में जनता को जानकारी देने और उनका फीडबैक सरकार को उपलब्ध कराने के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी सरकार की आंख और कान हैं।

- प्रकाशन विभाग ने महात्मा गांधी के करीब 150 प्रामाणिक और दुर्लभ फोटोग्राफ्स का सुरुचिपूर्ण तरीके से तैयार किया गया एल्बम **''महात्मा गांधी : ए लाइफ थ्रू लेंसेज''** प्रकाशित किया। धरोहर के समान महत्व के इस

'गांधी एल्बम' का प्रकाशन सबसे पहले 1954 में प्रकाशन विभाग ने ही किया था। इसकी अभिकल्पना और सज्जा में व्यापक सुधार करके सुरुचिपूर्ण सज्जा के साथ पहली बार नये कलेवर में छापा गया। प्रकाशन विभाग ने इस पुस्तक का अनुवाद भी कराया। इसका हिंदी संस्करण **'महात्मा गांधी : चित्रमय जीवन गाथा'** गांधीजी और उनके समकालीन लोगों के करीब 500 फोटोग्राफ्स के साथ छापा गया है जिससे उनके जीवन और समय की झलक देखने को मिलती है।

- **एक भारत–श्रेष्ठ भारत** अभियान पर अमल को सुदृढ़ करने के लिए पत्र सूचना कार्यालय ने माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री का एक लेख पत्र सूचना कार्यालय ने प्रकाशित किया। जोड़ीदार राज्यों के क्षेत्रीय कार्यालयों ने भी इसी तरह के लेखों का आदान–प्रदान कर उन्हें क्षेत्रीय समाचारपत्रों में छपवाया। लोकसंपर्क और संचार कार्यालय ने 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' विषय पर लोकसंपर्क कार्यक्रमों का आयोजन किया।

- **प्रकाशन विभाग की कई ई–परियोजनाओं** की 31 जुलाई, 2019 को शुरुआत हुई जिनमें विभाग की नए सिरे से डिजाइन की गई डायनामिक वेबसाइट, मोबाइल एप ''डिजिटल डीपीडी'', 'रोजगार समाचार' का ई–वर्जन और गांधीजी के जीवन और कार्यों को दर्शाने वाली पुस्तक ''सत्याग्रह गीता'' का ई–संस्करण भी शामिल है।

- **आजकल हिंदी की 75वीं जयंती** पर प्रकाशन विभाग ने विशेषांक निकाला है। यह पत्रिका 1945 से प्रकाशित हो रही है। इसके जनवरी–फरवरी 2020 के संयुक्तांक का मुख्य विषय है 'स्वातंत्र्योत्तर हिंदी साहित्य' और इसमें पिछले 75 वर्षों के साहित्यिक यथार्थ को दर्शाया गया है।

- लोकसंपर्क और संचार कार्यालय ने अमेरिका में ह्यूस्टन में आयोजित **'हाउडी मोदी' कार्यक्रम पर पुस्तिका डिजाइन** और प्रकाशित की। माननीय प्रधानमंत्री के संबोधन का पत्र सूचना कार्यालय ने सोशल मीडिया (लाइव स्ट्रीमिंग) तथा प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के जरिए अंग्रेजी, हिंन्दी, उर्दू और क्षेत्रीय भाषाओं में व्यापक प्रचार–प्रसार किया गया।

- **अबू धाबी** में 24 से 30 अप्रैल, 2019 तक आयोजित **29वें अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले में भारत को सम्मानित अतिथि** बनाया गया। इसमें भारतीय मंडप का उद्घाटन 24 अप्रैल, 2019 को भारतीय राजदूत श्री नवदीप सूरी और नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रो. गोविन्द प्रसाद शर्मा की उपस्थिति में किया गया। भारतीय मंडप में महात्मा गांधी के जीवन और दर्शन को विशेष महत्व दिया गया, उसपर आधारित 100 खंडों की पुस्तकमाला 'संपूर्ण गांधी वाङ्मय' के साथ–साथ देश के स्वतंत्रता संग्राम पर विभिन्न प्रकाशन भी प्रदर्शित किए गए। प्रकाशन विभाग ने पुस्तक मेले में 28 अप्रैल, 2019 को 'मेकिंग ऑफ द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी' विषय पर एक प्रेजेंटेशन भी प्रस्तुत किया।

- मंत्रालय ने 16 से 20 अक्टूबर, 2019 तक **फ्रैंकफर्ट में आयोजित अंतरराष्ट्रीय पुस्तक** मेले में भी हिस्सा लिया और इसमें अपना मंडप लगाया। मेला देखने आने वाले दर्शकों और भारत व अन्य देशों के प्रतिनिधियों ने **भारतीय मंडप** की भरपूर सराहना की। फ्रैंकफर्ट में भारतीय समुदाय के विद्यार्थियों की मदद से एक फ्लैशमॉब कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया जिसमें उन्होंने बॉलीवुड की फिल्मों के देशभक्ति के गीतों पर डांस किया। बालगोकुलम के बच्चों ने इस अवसर पर दांडी मार्च की पुनर्प्रस्तुति भी दी, जिसमें बच्चों ने हाथों में तख्तियां और झंडे लेकर और वैष्णव जन तो... और हम होंगे कामयामब... जैसे गीत गाते हुए पुस्तक मेला परिसर में मार्च किया।

- प्रकाशन विभाग ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 11 से 15 सितंबर, 2019 तक आयोजित **25वें दिल्ली पुस्तक मेले** में भी हिस्सा लिया और मेले में पुस्तकों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गोल्ड ट्रॉफी भी जीती। मेले में भाग लेने के लिए प्रकाशन विभाग ने फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्ज की ओर से दिए जाने वाले विभिन्न श्रेणियों के नौ पुरस्कार भी जीते।

- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के शिष्टमंडल ने किर्गिस्तान के बिशकेक शहर में 23–26 मई, 2019 तक आयोजित **दूसरे शंघाई सहयोग संगठन मास मीडिया फोरम में** भारत का प्रतिनिधित्व किया। शिष्टमंडल ने देश में जन संचार परिदृश्य के विकास में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया और शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की विभिन्न जन संचार एजेंसियों, संगठनों और एसोसिएशनों के बीच बेहतरीन तौर–तरीकों के आदान–प्रदान के लिए सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया।

- पत्र सूचना कार्यालय के कोलकाता, विजयवाड़ा, भुवनेश्वर और चेन्नई स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों ने **चक्रवाती तूफान 'फणि'** और मौसम संबंधी चेतावनी के बारे में प्रेस विज्ञप्तियों के रूप में दैनिक अपडेट और दैनिक रिपोर्टें जारी कीं।

प्रसारण स्कंध

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एन.डी.ए. सरकार के **शपथग्रहण समारोह** का 30 मई, 2019 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से रेडियो/टेलीविजन पर सीधा प्रसारण किया गया। दूरदर्शन और दूरदर्शन समाचार ने राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में आयोजित इस रंगारंग समारोह की विस्तृत कवरेज की। समारोह में बिमस्टेक देशों के प्रमुखों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। भारत के राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द ने इस समारोह की उत्कृष्ट कवरेज के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की सराहना की।

- **महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम :**

- दूरदर्शन ने 'वैष्णव जन....' भजन पर वीडियो बनाया और दिखाया।

- दूरदर्शन समाचार ने साबरमती आश्रम में आयोजित भव्य समारोह को कवर किया और 'स्वच्छता – महात्मा को श्रद्धांजलि,' 'ट्रिब्यूट टू महात्मा,' 'खादी वस्त्र नहीं, एक विचारधारा,' और 'महात्मा लिव्ज' जैसे विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण किया।

- आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने 'आकाशवाणी समाचार भारती' पत्रिका का 8वां अंक हैशटैग बापू150 पर महात्मा गांधी और उनके सेवा, समर्पण, स्वदेशी, स्वावलंबन, सहयोग और स्वच्छता जैसे विचारों को समर्पित किया।

- **गुरु नानकदेव जी के 550वें जयंती समारोह की कवरेज:**

- माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रसार भारती के अभिलेखागार में उपलब्ध सामग्री से तैयार धरोहर के समान महत्व वाले 'गुरुवाणी' के डिजिटल संस्करण का 15 नवंबर, 2019 को लोकार्पण किया।

- दूरदर्शन समाचार ने 12 नवंबर, 2019 को सुल्तानपुर लोधी (पंजाब) और करतारपुर साहिब गलियारे में आयोजित 'प्रकाश पर्व' कार्यक्रम की विस्तृत कवरेज की और करतारपुर साहिब गलियारे पर एक डाक्यूमेंटरी तथा वार्ता पर आधारिक कार्यक्रम भी प्रसारित किया।

- ऑल इंडिया रेडियो (आकाशवाणी) के विदेश सेवा प्रभाग ने जाने–माने रागियों द्वारा प्रस्तुत शबद–कीर्तन कार्यक्रम – 'बाणी उत्सव' का आयोजन किया।

- दूरदर्शन ने गुरुनानक देव जी के शबद पर आधारित शबद–कीर्तन और नगर–कीर्तन पर रिपोर्टों का प्रसारण किया।

- आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने डेरा नानक साहब से विशेष रिपोर्टों और करतारपुर साहब गलियारे पर ग्राउंड रिपोर्ट के प्रसारण के अलावा शोभा यात्रा और अंतरराष्ट्रीय नगर कीर्तन पर विशेष संवाददाताओं की रिपोर्टों का भी प्रसारण किया।

- **सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती और राष्ट्रीय एकता दिवस** पर 31 अक्टूबर, 2019 को दूरदर्शन समाचार ने विशेष डॉक्यूमेंटरी और गुजरात के केवड़िया में सिविल सेवाओं के प्रोबेशनर प्रशिक्षणार्थियों के लिए प्रधानमंत्री के संबोधन का प्रसारण किया। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने देश भर से प्राप्त ग्राउंड रिपोर्टों और विशेष रिपोर्टों का अपने समाचार पत्रिका कार्यक्रम में प्रसारण किया। 31 अक्टूबर, 2019 को आकाशवाणी ने शाम 9.30 बजे से अपने समूचे नेटवर्क पर सरदार पटेल स्मारक व्याख्यान–2019 का प्रसारण किया।

- **जलियांवाला बाग नरसंहार** के 100 साल पूरे होने के अवसर पर दूरदर्शन समाचार ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया और विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया। इसके अलावा 'जलियांवाला बाग' नाम से एक विशेष कार्यक्रम बनाकर उसका प्रसारण भी किया गया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम और जलियांवाला बाग पर दूरदर्शन द्वारा निर्मित लघु फिल्मों को भी जनता के लिए प्रदर्शित किया गया। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने इस अवसर पर द्विभाषिक ''100 ईयर्स ऑफ जलियांवाला बाग मैसाकर'' नाम के विशेष कार्यक्रम का 13 अप्रैल को प्रसारण किया।

➢ **करगिल विजय दिवस की 20वीं जयंती** के अवसर पर 26 जुलाई, 2019 को आयोजित कार्यक्रमों की दूरदर्शन समाचार पर सीधी कवरेज की गई। डीडी समाचार ने इस अवसर पर विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण किया जिनमें

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में 31 अक्टूबर, 2019 को मनाई जाने वाली सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर नई दिल्ली में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए

'सैल्यूट टू ब्रेवहार्ट,' करगिल विजय पर डॉक्यूमेंटरी, शहीदों पर विशेष कार्यक्रम और एनसीसी कैडेटों के साथ 'वाई–फैक्टर' कार्यक्रम शामिल हैं। आकाशवाणी के सभी चैनलों ने 'करगिल के योद्धाओं' पर फीचर प्रसारित किए। देश भर में आयोजित कार्यक्रमों के बारे में समाचारों को आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित किया गया।

➢ **जम्मू–कश्मीर के बारे में संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त** किए जाने संबंधी घटनाक्रम की मंत्रालय की मीडिया इकाइयों ने विस्तृत कवरेज की और इस बारे में विशेष अपडेट्स भी दिए। संसद में इससे संबंधित संशोधन विधेयक पारित होने तथा भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के भाषणों को भी पर्याप्त स्थान दिया गया।

- दूरदर्शन समाचार ने अनुच्छेद 370 और जम्मू–कश्मीर पर परिचर्चा वाले कार्यक्रम, जैसे 'कश्मीर ट्रुथ,' 'कश्मीर का सच', 'जम्मू-कश्मीर–बदलाव की बयार' और जम्मू-कश्मीर पर ग्राउंड रिपोर्टों का भी प्रसारण किया गया।
- आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने श्रीनगर, जम्मू, लेह और करगिल से 43 ग्राउंड रिपोर्टों का प्रसारण किया और घाटी में प्रतिबंध हटाए जाने तथा स्थिति के सामान्य होने के बारे में विशेष अपडेट्स दिए।
- दूरदर्शन समाचार ने नये केंद्र शासित प्रदेशों–जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के नये उपराज्यपालों के शपथ ग्रहण समारोहों का भी प्रसारण किया और जम्मू-कश्मीर पर परिचर्चा पर आधारित कार्यक्रमों की 14 कड़ियां प्रसारित कीं।
- आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने दीपावली के अवसर पर प्रधानमंत्री की जम्मू–कश्मीर यात्रा, जम्मू–कश्मीर के नये उपराज्यपाल तथा नये केंद्र शासित प्रदेशों–जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के गठन और उसके बाद के घटनाक्रम पर विशेष अपडेट्स प्रसारित किए।

➢ मंत्रालय और उसकी मीडिया इकाइयों ने मतदाताओं में **जागरूकता को बढ़ावा देने और लोकसभा चुनाव–2019**

की गतिविधियों की विस्तृत कवरेज की।

- दूरदर्शन समाचार ने चुनाव के सिलसिले में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के साथ विशेष साक्षात्कार किया।

- दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित विशेष कार्यक्रमों में रोजाना एक घंटे का द्विभाषिक कार्यक्रम 'जनादेश–2019,' दर्शकों पर आधारित एक घंटे का कार्यक्रम 'हैशटेग जनमत 2019', 5 मिनट का फटाफट समाचार बुलेटिन चुनावी 5/15 और इलेक्शन 5/15, ट्रैवेलाग का विशेष अंक, विशेष कार्यक्रम 'इलेक्शन एक्सप्रेस,' और संक्षिप्त प्रोमो 'इलेक्शन ट्रीविया' शामिल थे।

- आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने पहली बार लगातार 40 घंटे तक एक विशेष द्विभाषिक कार्यक्रम **"विशेष जनादेश 2019"** आकाशवाणी के एफ.एम. गोल्ड और अन्य चैनलों से प्रसारित किया जिसे प्रभाग के आधिकारिक यू–ट्यूब चैनल पर भी सीधा उपलब्ध कराया गया।

➢ **संविधान दिवस** पर आयोजित कार्यक्रम का 26 नवंबर, 2019 को नई दिल्ली में संसद भवन के केंद्रीय कक्ष से रेडियो/टेलीविजन सहित सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सभी प्लेटफार्म्स पर सीधा प्रसारण किया गया जिसमें माननीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया।

- दूरदर्शन समाचार ने संविधान दिवस पर एक डॉक्यूमेंटरी और एक विशेष कार्यक्रम तैयार किया और बच्चों तथा आम लोगों द्वारा संविधान की प्रस्तावना पढ़ने के कार्यक्रम की चार विशेष कड़ियों का प्रसारण किया।

- मामल्लापुरम में माननीय प्रधानमंत्री की सुबह की प्लॉगिंग दौड़ (प्लास्टिक कचरे की सफाई करते हुए जॉगिंग करना) सहित देश भर में आयोजित इसी तरह की प्लॉगिंग दौड़ों के आयोजन की खबरों को समाचारों में व्यापक कवरेज दी गई।

- दूरदर्शन समाचार और आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने इस पर अनेक ग्राउंड रिपोर्ट्स, समाचार और परिचर्चा के कार्यक्रमों का प्रसारण किया।

➢ दूरदर्शन समाचार ने **माननीय प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा** का व्यापक प्रचार किया और लाइव कवरेज भी की जिनमें **'हाउडी मोदी'** कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण, न्यूयॉर्क से विशेष परिचर्चा और भारतीय तथा अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ विशेष इंटरव्यू शामिल थे। दूरदर्शन समाचार ने परिचर्चा पर आधारित 17 विशेष कार्यक्रम भी प्रसारित किए। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने प्रधानमंत्री की अमरिका यात्रा पर 14 ग्राउंड रिपोर्टों का सीधा प्रसारण किया।

➢ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 29 अगस्त, 2019 को नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से **'फिट इंडिया' कार्यक्रम** के शुभारंभ का सीधा प्रसारण किया गया।

- दूरदर्शन, दूरदर्शन समाचार, आकाशवाणी और आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने कई कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण किया जिनमें आधे घंटे के विशेष कार्यक्रम, बाइट, सफलता गाथाएं, रिपोर्ट, डाक्यूमेंटरी, समाचार बुलेटिन, ग्राउंड रिपोर्ट, विशेष रिपोर्ट, परिचर्चा, स्पॉट, विशेष इंटरव्यू आदि शामिल हैं।

➢ दूरदर्शन समाचार और आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने **चीन के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री की अनौपचारिक मुलाकात और उनकी सऊदी अरब यात्रा** को सीधी और विस्तृत कवरेज प्रदान की।

- दूरदर्शन समाचार ने 'मोदी–शी शिखर सम्मेलन' और 'मामल्लापुरम शिखर सम्मेलन' नाम के विशेष कार्यक्रम बनाए और रियाध में भविष्य की नवाचार संबंधी पहल के बारे में प्रधानमंत्री के मुख्य भाषण का भी प्रसारण किया गया।

- आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रमों में मामल्लापुरम से ग्राउंड रिपोर्टों और भारत–सऊदी अरब संबंधों पर स्पॉटलाइट/न्यूज एनालिसिस तथा वार्ता कार्यक्रमों का प्रसारण किया।

➢ **चक्रवात 'फणि'** के बारे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से मिली ताजातरीन जानकारियों को **दूरदर्शन समाचार के बुलेटिनों** में शामिल किया गया।

- तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और पश्चिम बंगाल से ताजा जानकारी/रिपोर्टों का प्रसारण किया गया।

- **माननीय प्रधानमंत्री की ओडिशा यात्रा की दिनभर विशेष रूप से कवरेज की गई।** प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई बैठकों और राष्ट्रीय संकट प्रबंधन कमेटी की बैठकों

पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। डिजिटल सैटेलाइट न्यूज गैदरिंग और रिपोर्टरों की तीन टीमें भी तैनात की गईं।

- चक्रवात के धरती से टकराने की करीब 4 घंटे तक कवरेज की गई और डीडी न्यूज तथा डीडी इंडिया पर तूफान के बारे में द्विभाषी कार्यक्रमों का प्रसारण किया गया। कवरेज का मुख्य जोर राहत और पुनर्वास पर रहा और इसमें एनडीआरएफ और आईएमडी के महानिदेशकों तथा ओडिशा सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साक्षात्कार/बातचीत की गई।

- सोशल मीडिया पर विशेष पैकेज और ट्वीट्स जारी किए गए और क्या करें और क्या न करें के रूप में एहतियात बरतने के बारे में लोगों को जानकारी दी गई।

➢ दूरदर्शन समाचार और आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की क्षेत्रीय समाचार इकाइयों ने गुजरात तट के पास पूर्व–मध्य अरब सागर से उठे जबरदस्त **चक्रवाती तूफान 'वायु'** के बारे में समाचारों को प्रमुख रूप से प्रसारित किया।

- जोखिम वाले इलाकों से करीब 2 लाख 80 हजार लोगों को निकाले जाने और सौराष्ट्र तथा कच्छ के तटवर्ती इलाकों में किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के कर्मियों को तैनात करने के साथ–साथ एसडीआरएफ, सेना और बीएसएफ कर्मियों की तैनाती की भी विभिन्न भाषाओं और बोलियों के समाचार बुलेटिनों में व्यापक कवरेज की गई।

- माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा तूफान से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा लेने के लिए नई दिल्ली में संबंधित राज्यों और केंद्रीय मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक के आयोजन को भी समाचारों में पर्याप्त महत्व दिया गया।

➢ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 5 जुलाई, 2019 को संसद में पेश किए गए **केंद्रीय बजट 2019–20** की विस्तृत कवरेज की गई और इसे प्रकाशित किया गया।

- दूरदर्शन समाचार बजट पर प्रधानमंत्री की पहली प्रतिक्रिया और बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री की विशेष बातचीत के प्रसारण की खास पहल की। दूरदर्शन समाचार ने बजट के विभिन्न क्षेत्रों और उनके लिए बजट में किए गए आबंटन/प्रावधानों के बारे में अनेक अतिथियों और विशेषज्ञों के साथ चर्चा के विशेष कार्यक्रम दिखाए।

- आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने जाने–माने विशेषज्ञों के साथ विशेष बजट बुलेटिन और बजट पेश करने के बाद की चर्चाएं आयोजित कीं।

➢ **21 जून, 2019 को पांचवें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रमों की व्यापक कवरेज की गई।**

- दूरदर्शन समाचार और आकाशवाणी ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर युवाओं, स्वास्थ्य आदि को ध्यान में रखकर विषयवार विशेष कार्यक्रमों इंटरव्यू, न्यूज स्टोरी, फीचर, ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए विशेष कवरेज/पैकेज तैयार किए गए।

- दुनिया भर के विभिन्न शहरों में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रमों का विशेष पैकेजेज में इस्तेमाल किया गया।

- आकाशवाणी ने देश के विभिन्न भागों में रेडियो जॉकी की कार्यशालाएं आयोजित कीं।

➢ **भारत की स्वतंत्रता की 73वीं जयंती (2019)** पर माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने 13 अगस्त, 2019 को नई दिल्ली में **देशभक्ति के गीत ''वतन''** का लोकार्पण किया। न्यू इंडिया के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने वाले इस गीत का निर्माण दूरदर्शन ने किया है। गीतकार श्री आलोक श्रीवास्तव के लिखे इस गीत को सुप्रसिद्ध बॉलीवुड गायक श्री जावेद अली ने गाया है और इसका संगीत श्री दुष्यंत ने दिया है। दूरदर्शन समाचार ने इस अवसर पर विशेष कार्यक्रमों 'इंडिपेंडेंस डे 2019–नये भारत की ओर' और 'क्विट इंडिया – यादें आज़ादी की' का प्रसारण किया।

- **'आयुष्मान भारत' अभियान की पहली जयंती** पर दूरदर्शन समाचार ने कई ग्राउंड रिपोर्टों का प्रसारण किया और आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. इंदु भूषण के साथ विशेष साक्षात्कार प्रसारित किया। इस योजना के अंतर्गत जम्मू–कश्मीर के सबसे अधिक गोल्डन कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बनने को भी समाचारों में कवरेज दी गई।

➢ सितंबर के महीने को देश भर में **पोषण माह** के रूप में मनाया गया ताकि कुपोषण की चुनौती से निपटा जा सके। दूरदर्शन ने 'मिशन पोषण' विषय पर चिकित्सा

विशेषज्ञों के साथ 'आरोग्य भारत' स्वास्थ्य शो का देशभर में प्रसारण किया। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने 5 ग्राउंड रिपोर्टों का प्रसारण किया और न्यूज मैगजीन कार्यक्रम, परिचर्चा कार्यक्रम तथा सोशल मीडिया मंचों पर भी इसकी कवरेज की।

➤ **एक भारत, श्रेष्ठ भारत** के अमल को और कारगर बनाने के उपाय :

- क्षेत्रीय चित्रहार/गीतों का जोड़ीदार राज्यों की भाषाओं के उपशीर्षकों के साथ प्रसारण किया जा रहा है।
- दूरदर्शन समाचार ने 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के अंतर्गत विशेष दर्शकों पर आधारित कड़ियों का प्रसारण किया।
- दूरदर्शन केंद्र जोड़ीदार राज्यों में तीर्थयात्रा, यात्रा वृत्तांत, खान–पान, संस्कृति, विरासत, जीवनशैली, कला और शिल्प, गीत, नृत्य, लोक संस्कृति, इतिहास, स्मारक, उत्सव, साहित्य, वेशभूषा, खेलकूद, कठपुतली जैसे विभिन्न विषयों पर कार्यक्रमों का प्रसारण कर रहे हैं।
- आकाशवाणी ने एक भारत, श्रेष्ठ भारत विषय को लेकर एक शानदार गीत बनाया है जिसे सरदार पटेल स्मारक व्याख्यान, 2019 के दौरान प्रस्तुत किया गया।

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर 13 अप्रैल, 2019 को नई दिल्ली में संगीतमय वीडियो गीत 'वतन' को राष्ट्र को समर्पित करते हुए। इस अवसर पर प्रसार भारती के अध्यक्ष डॉ. ए. सूर्य प्रकाश भी उपस्थित रहे

- आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने एक भारत, श्रेष्ठ भारत के प्रोमो का विस्तृत प्रसारण किया और इस पर विशेष समाचार, ग्राउंड रिपोर्ट, 100 महत्वपूर्ण संदेशों पर चर्चा आदि का क्षेत्रीय समाचार इकाइयों से जानकारी को भी प्रसारण में शामिल किया गया।
- दूरदर्शन के क्षेत्रीय केंद्र जोड़ीदार राज्यों में रोजाना एक वाक्य और उसके अनुवाद का प्रसारण करेंगे।
- दूरदर्शन समाचार जोड़ीदार राज्यों के 'गुड न्यूज' संबंधी समाचारों का सोशल मीडिया पर प्रस्तुत करेगा।
- जोड़ीदार राज्यों के विद्यार्थियों को भाषा सीखने में मदद के लिए विभिन्न भाषाओं में वाक्यों का पॉडकास्ट।

➤ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले **'मन की बात'** कार्यक्रम की पहली कड़ी का आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारण किया गया। दूरदर्शन समाचार ने देश भर में सात स्थानों से श्रोताओं की सीधी कवरेज की और उनकी बाइट्स भी ली गईं। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की क्षेत्रीय समाचार इकाइयों ने भी इस कार्यक्रम को 77 भाषाओं तथा बोलियों में अपने 223 बुलेटिनों और 256 एफ.एम. मुख्य समाचारों में भी शामिल किया।

- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने **सातवां राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन** 27 से 29 अगस्त, 2019 तक नई दिल्ली के बी.आर. अम्बेडकर भवन में आयोजित किया। 28 अगस्त, 2019 को माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने वर्ष 2018 और 2019 के लिए राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार प्रदान किए और सरकार के दूसरे कार्यकाल के 75 दिनों के महत्वपूर्ण फैसलों के संकलन को **''जन कनेक्ट : स्पष्ट नीयत, निर्णायक कदम''** नाम की पुस्तक के रूप में जारी किया।

- टेलीविजन को श्रवण विकलांग लाचार लोगों की पहुंच के दायरे में लाने में **सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय** की अग्रणी भूमिका के लिए ने मंत्रालय ने दिव्यांगजनों के लिए रोजगार बढ़ाने वाले राष्ट्रीय केंद्र (एनसीपीईडीपी) द्वारा नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित एक समारोह में **निर्णायक मंडल का विशेष पुरस्कार** प्राप्त किया।

- मंत्रालय ने फैसला किया है कि वर्तमान मल्टीपल सिस्टम ऑपरेटरों और नए आवेदकों, दोनों ही को नोटिस जारी होने के एक महीने के भीतर इस आशय का हलफनामा दायर करना होगा कि वे लोकसभा और राज्यसभा टेलीविजन चैनलों समेत दूरदर्शन के सभी 24 चैनलों को अपने टेलीविजन नेटवर्क में शामिल कर रहे हैं। ऐसा सभी **केबल टीवी नेटवर्कों पर दूरदर्शन चैनलों को शामिल करने की अनिवार्यता संबंधी वर्तमान नियमों के उल्लंघन को रोकने** के लिए किया गया है।

- **दूरदर्शन ने 16 सितंबर, 2019** को नई दिल्ली के दूरदर्शन भवन में आयोजित एक समारोह में अपना **60वां स्थापना दिवस** मनाया। माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस अवसर पर विशेष डाक टिकट जारी किया और श्री अमिताभ बच्चन के स्वर्णिम आवाज में स्वरबद्ध श्री आलोक श्रीवास्तव की एक कविता भी जारी की। इस अवसर पर दूरदर्शन के बारे में एक विशेष पुस्तिका भी जारी की गई।

- **मंत्रालय ने अपनी पहुंच का दायरा बढ़ाने और टेलीविजन दर्शकों के फायदे के लिए दो परामर्श जारी किए हैं।** मंत्रालय ने सभी निजी उपग्रह टीवी चैनलों को सलाह दी है कि वे धारावाहिकों में कलाकारों के नाम/आभार/शीर्षक हिंदी में और क्षेत्रीय भाषाओं के धारावाहिकों को संबंधित क्षेत्रीय भाषाओं में प्रदर्शित करने के बारे में विचार करें। मंत्रालय ने उन्हें यह भी परामर्श दिया है कि वे डांस के रिएलिटी शोज या इसी तरह

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर 28 अगस्त, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में सामुदायिक रेडियो के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करते हुए

के अन्य कार्यक्रमों में बच्चों को अशिष्ट, उत्तेजक या अश्लील तरीके से दिखाने से बचें। उन्हें यह भी सलाह दी गई है कि वे इस तरह के रिएलिटी शो और कार्यक्रमों को दिखाते समय अधिकतम संयम, संवेदनशीलता और सावधानी बरतें।

- दूरदर्शन समाचार सरकार के विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन पर **ग्राउंड रिपोर्टों** का प्रसारण कर रहा है। इनमें भारत में आमूल बदलाव लाने से संबंधित कार्यक्रम, न्यू इंडिया गाथाएं और आयुष्मान भारत की गाथाएं भी शामिल हैं। संबंधित कार्यक्रमों के वास्तविक लाभार्थियों से फीडबैक लेने के बाद इन कार्यक्रमों की रिपोर्ट प्रसारण के लिए तैयार की जाती है। ग्राउंड रिपोर्टों के सभी वीडियो को डीडी न्यूज की वेबसाइट पर नियमित रूप से अपलोड किया जाता है।

- आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा से 22 जुलाई, 2019 को सफलतापूर्वक भू–कक्षा में छोड़ने वाले भारत के भूसमकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान जीएसएलवी एमके–III–एम1 की पहली संचालनात्मक उड़ान की विस्तृत कवरेज की गई और प्रचार किया गया। दूरदर्शन समाचार ने **चंद्रयान–2** के बारे में दो घंटे के सीधे प्रसारण और 30 मिनट की अवधि के तीन रिकार्डेड कार्यक्रमों के अलावा विशेष कार्यक्रमों की परिकल्पना की और उनका निर्माण भी किया। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने अपने समसामयिक विषयों के कार्यक्रमों में भी इस पर चर्चा की।

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर 16 सितंबर, 2019 को नई दिल्ली में दूरदर्शन के 60वें स्थापना दिवस समारोह में सभा को संबोधित करते हुए

- दूरदर्शन समाचार ने **मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि (यूएनसीसीडी) पर हस्ताक्षर करने वाले देशों के 14वें सम्मेलन की विस्तृत कवरेज की।** इसका आयोजन ग्रेटर नोएडा में 2 से 13 सितंबर, 2019 तक किया गया। सम्मेलन के उच्च स्तरीय पूर्ण सत्र को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। समापन सत्र में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने हिस्सा लिया। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने इस सम्मेलन की कवरेज अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम के साथ–साथ सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पर भी की।

- दूरदर्शन समाचार ने **कुलभूषण जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय की सीधी रिपोर्टिंग** करने के लिए अपने विशेष संवाददाता को हेग भेजा और भारत के पक्ष में न्यायालय के निर्णय की विशेष कवरेज की।

- दूरदर्शन समाचार ने यौन अपराधों से बच्चों की **सुरक्षा के कानून (पोक्सो)** पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जिनमें दूरदर्शन समाचार के प्राइम टाइम के बुलेटिनों में विस्तार से चर्चा की गई।

फिल्म स्कंध

- राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द ने **50वां दादा साहेब फालके पुरस्कार** 29 दिसंबर, 2019 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में श्री अमिताभ बच्चन को प्रदान किया। उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडु ने वर्ष **2018 के लिए 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार** 23 दिसंबर, 2019 को नई दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में विभिन्न श्रेणियों के विजेताओं को प्रदान किए। सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर और विभिन्न पुरस्कारों के निर्णायक मंडलों के अध्यक्ष इस अवसर पर उपस्थित थे। प्रमुख विजेताओं में 'बेहतरीन फीचर फिल्म' का पुरस्कार गुजराती फिल्म 'हेल्लारो' को, साफ–सुथरा मनोरंजन प्रदान करने वाली 'सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म' का पुरस्कार 'बधाई हो' को, और 'सामाजिक मसलों' पर 'बेहतरीन फिल्म' का पुरस्कार हिंदी फिल्म 'पैडमैन' को दिया गया। आदित्य धर को 'उड़ी : द सर्जिकल स्ट्राइक' के लिए 'बेहतरीन निर्देशक' का पुरस्कार, आयुष्मान खुराना और विकी कौशल को 'अंधाधुंध' और 'उड़ी : द सर्जिकल स्ट्राइक' में उनके अभिनय के लिए संयुक्त रूप से 'बेहतरीन अभिनेता' का पुरस्कार दिया गया। कीर्ति सुरेश ने तेलुगु फिल्म 'महानटी' में अपने अभिनय के लिए 'बेहतरीन अभिनेत्री' की ट्रॉफी जीती। 'फिल्म बनाने के लिए सबसे अनुकूल राज्य' का पुरस्कार उत्तराखंड को दिया गया।

- मंत्रालय ने **फिल्म समारोहों** को संचार के सशक्त माध्यम के रूप में उपयोग किया है और देश भर में कई अवसरों पर फिल्म समारोहों और कार्यक्रमों का आयोजन किया है।

- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के फिल्म समारोह निदेशालय ने **50वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह** का 20 से 28 नवंबर, 2019 तक गोवा में पणजी में आयोजन किया। इसका उद्घाटन सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया। उद्घाटन समारोह में जाने–माने फिल्म सितारे श्री अमिताभ बच्चन और श्री रजनीकांत ने भी हिस्सा लिया। भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह का समापन समारोह 'एक भारत–श्रेष्ठ भारत' के मुख्य विषय पर आधारित था। समारोह के स्वर्ण जयंती आयोजन में

माननीय राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द श्री 29 दिसंबर, 2019 को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में अमिताभ बच्चन को सिनेमा के क्षेत्र में उनके पांच दशक से भी अधिक के अमूल्य और उत्कृष्ट योगदान के लिए दादा साहेब फालके पुरस्कार से सम्मानित करते हुए

76 देशों की 190 चर्चित फिल्में प्रदर्शित की गईं। रूस इस समारोह का केंद्रीय देश था और इसमें 12,000 से अधिक प्रतिनिधियों और फिल्म प्रेमियों ने हिस्सा लिया। श्री रजनीकांत को 'आइकन ऑफ गोल्डन जुबली पुरस्कार' से सम्मानित किया गया और फ्रांसीसी अभिनेत्री आइजाबेले हुपर्ट को फिल्मों के प्रति जीवन भर के योगदान के लिए 'लाइफटाइम एचीवमेंट अवार्ड' प्रदान किया गया। पुरस्कार खंड में नौ अलग–अलग श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए। भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह को उसकी स्थापना के शानदार 50 साल पूरे होने के अवसर पर आईसीएफटी–यूनेस्को फेलिनी मेडल से सम्मानित किया गया।

- फ्रांस के कान में 14 से 25 मई, 2019 तक आयोजित 72वें **वार्षिक कांस फिल्म समारोह 2019 में भारतीय मंडप** का उद्‌घाटन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव और फिल्म बिरादरी के सदस्यों ने 15 मई, 2019 को किया। इसमें सरकार की पहलों और मीडिया और मनोरंजन उद्योग में नये उभरते रुझानों को विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर **भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह की स्वर्ण जयंती के सिलसिले में एक विशेष पोस्टर भी जारी किया** गया। भारतीय शिष्टमंडली ने एक ही स्थान पर तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराने वाली प्रणाली के रूप में फिल्म सहायता कार्यालय की भूमिका को रेखांकित किया और कान्स में आए देशों के फिल्म आयुक्तों के साथ मिलकर फिल्में बनाने की संभावनाओं के बारे में विचार–विमर्श किया। इज़राइल ने अपने प्रतिनिधियों के साथ बैठक में आगामी येरूसलम फिल्म समारोह–2020 में भारत को मुख्य आकर्षण वाला देश बनाने की पेशकश की। कान्स फिल्म बाजार की पॉकेट गाइड में दुनिया के सबसे बड़े फिल्म उद्योग वाले देश के रूप में भारतीय सिनेमा की सराहना करते हुए उसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।
- कनाडा में भारत के उच्चायुक्त श्री विकास स्वरूप ने 6 सितंबर, 2019 को **44वें टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह 2019 में इंडिया पैवीलियन** का उद्‌घाटन किया। इस अवसर पर भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह (आईएफएफआई–2019) का पोस्टर और पुस्तिका भी जारी की गई।
- सत्यजित रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान ने भारत सरकार के विज्ञान और टेक्नोलॉजी विभाग के अंतर्गत

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन; सूचना एवं प्रसारण तथा भारी उद्यम और लोक उपक्रम मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर 20 नवंबर, 2019 को गोवा के पणजी में 50वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह के उद्‌घाटन समारोह में

विज्ञान प्रसार के सहयोग से 6–8 नवंबर, 2019 तक संस्थान परिसर में **भारतीय अंतरराष्ट्रीय विज्ञान फिल्म समारोह** का आयोजन किया। इसमें विज्ञान, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कई प्रसिद्ध फिल्में 'अनुसंधान, नवसृजन और विज्ञान से राष्ट्र का सशक्तीकरण' श्रेणी में प्रदर्शित की गई और माननीय विज्ञान और टेक्नोलाजी मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने पुरस्कार वितरित किए। सत्यजित रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान ने स्विटजरलैंड और इटली के दूतावासों के सहयोग से 19–20 नवंबर, 2019 को **स्विस और इटालियन फिल्मों का समारोह सिनेमा फ्रॉम द इटेलियन स्पीकिंग वर्ल्ड** का आयोजन किया।

- श्रीलंका में कोलंबो में 2 से 7 जुलाई, 2019 तक आयोजित **सार्क फिल्म समारोह** के लिए फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा चुनी गई फीचर फिल्म *नगरकीर्तन (बंगाली)* को बेहतरीन फीचर फिल्म, बेहतरीन निर्देशन, बेहतरीन अभिनेता और बेहतरीन ओरिजनल स्कोर वाली फिल्म के रूप में सम्मानित किया गया। समारोह में प्रदर्शन के लिए चुनी गई अन्य फिल्मों में *ना बोले वो हराम (मराठी)* को सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म और *वाकिंग विद द विंड (लद्दाखी)* को स्पेशल ज्यूरी (निर्देशन और पटकथा) पुरस्कार मिला।

- **हाल में शुरू किए गए फिल्म सुविधा कार्यालय (एफएफओ)** : मंत्रालय के वेबसाइट के होमपेज पर एफएफओ के लोगो **के साथ प्रचार फिल्में** डाली गई हैं जिन्हें एफएफओ की वेबसाइट से हाइपरलिंक किया गया है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम नई दिल्ली के फिल्म निर्माण विभाग ने ग्राहक मंत्रालयों/विभागों के लिए कई फिल्में, डॉक्यूमेंटरी, टीवीसी आदि का निर्माण किया है। इनमें महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के सिलसिले में बनायी गई फिल्म, फासटैग शुरू करने के बारे में 2 टीवीसी, एक टेलीफिल्म, एक डॉक्यूमेंटरी, भारतीय नौसेना के लिए 2 टीवीसी/प्रोमो, हवाईअड्डा आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के बारे में एक एनिमेशन फिल्म शामिल है।

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 सितंबर, 2019 को अपनी बैठक में भारत और रूस सरकार के बीच **दृश्य–श्रव्य सहयोग** के समझौते को मंजूरी दे दी। इस समझौते पर व्लादीवोस्टोक (रूस) में 4 सितंबर, 2019 को हस्ताक्षर हुए।

- **अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने अनुप्रयुक्त कला और शिल्प नाम की एक नयी श्रेणी के अंतर्गत भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान में एक वर्ष के पांच स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम शुरू करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।** संस्थान इस श्रेणी के पाठ्यक्रम संचालित करने वाला ऐसा पहला और एकमात्र संस्थान है जिसे यह मान्यता मिली है।

- बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के सलाहकार डॉ. गौहर रिज़वी, भारत में बंगलादेश के उच्चायुक्त सैयद मुअज्जम अली और **बांग्लादेश के शिष्टमंडल** के अन्य प्रतिनिधियों ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुलाकात की। उन्होंने बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान के जीवन और कृत्यों पर एक फीचर फिल्म बनाने के विभिन्न पहलुओं के बारे में चर्चा की। दोनों देशों के सहयोग से इस फिल्म के निर्माण की घोषणा भारत और बंगलादेश के प्रधानमंत्री पहले ही कर चुके हैं।

- **महात्मा गांधी की 150वीं जयंती** पर फिल्म प्रभाग ने बच्चों के लिए 'वैष्णव जन' फिल्म बनायी। भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार को पुराने जमाने के कई जाने–माने फिल्म स्टूडियो से **महात्मा गांधी पर फिल्मों की फुटेज की 30 असंपादित रीलें मिलीं**।

- **गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती** के उपलक्ष्य में सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 8 नवंबर, 2019 को अमृतसर में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा तैयार करतारपुर का थीम सांग जारी किया।

- मंत्रालय ने **विश्व पर्यावरण दिवस** समारोह धूमधाम से मनाया। सूचना एवं प्रसारण तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 6 जून, 2019 को मुंबई में गुलशन महल परिसर में तीन पौधे लगाए। फिल्म प्रभाग की इस ऐतिहासिक इमारत में भारतीय राष्ट्रीय सिनेमा संग्रहालय का एक हिस्सा स्थित है। उन्होंने नई दिल्ली में पर्यावरण मंत्रालय के परिसर में पर्यावरण राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो, क्रिकेटर कपिल देव, अभिनेता जैकी श्राफ और रणदीप हुडा तथा गायिका मालिनी अवस्थी के साथ पौधे लगाए।

- सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए मंत्रालय ने उभरते फिल्मकारों और अनेक जन संचार संस्थानों के छात्रों के लिए **एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर, आर्ट्स एंड साइंसेज** (जिसे आम तौर पर **ऑस्कर अकादमी** कहा जाता है) **के अध्यक्ष श्री जॉन बेली** के साथ 28 मई, 2019 को नई दिल्ली के सीरी फोर्ट में **विशेष प्रश्नोत्तर सत्र** का आयोजन किया। सत्र के दौरान मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों द्वारा उभरते फिल्म निर्माताओं को दिए जा रहे प्रोत्साहनों पर प्रकाश डाला और आशा व्यक्त की कि श्री बेली और एकेडमी के साथ सहयोग

से भारतीय फिल्म निर्माताओं की प्रतिभा को विश्व भर में दिखाने का मौका मिलेगा।

- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मुबई में फिल्म प्रभाग परिसर में 10–11 अक्टूबर, 2019 को **फिल्म प्रमाणीकरण और ऑनलाइन सामग्री के विनियमन पर एक सेमिनार/कार्यशाला आयोजित** की। ऑनलाइन सामग्री के विनियमन, फिल्म प्रमाणन और फिल्म बनाने में सुविधा के बारे में एक अन्य सेमिनार/वर्कशॉप 11 नवम्बर, 2019 को चेन्नई के होटल रेन ट्री में आयोजित की गई।

- राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड मुंबई ने भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, सत्यजित रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, भारतीय बाल चित्र समिति और फिल्म्स डिविजन जैसी संस्थाओं से अपने **वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म** www.cinemasofindia.com के लिए सामग्री प्राप्त करने के उद्देश्य से बातचीत का सिलसिला शुरू किया। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने 27 अगस्त, 2019 को सेंट लुई बधिर कॉलेज, चेन्नई में डिजिटल स्टिल फोटोग्राफी, मल्टीमीडिया, एनिमेशन और एडिटिंग में 290 **दिव्यांग उम्मीदवारों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान** करने के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किए हैं।

- सत्यजित रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता ने 2 अक्टूबर, 2019 को **फिट इंडिया प्लॉग रन** का आयोजन किया जिसमें प्रतिभागी तख्तियां लिए थे जिन पर सिर्फ एकबार इस्तेमाल किए जा सकने वाले प्लास्टिक पर पाबंदी लगाने के नारे लिखे थे। इसमें भाग लेने वालों ने दौड़ने के साथ–साथ एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के कचरे को इकट्ठा किया जिसे 3 अक्टूबर, 2019 को निर्धारित स्थानों में निस्तारित किया गया।

■ ■ ■

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर 23 जुलाई, 2019 को नई दिल्ली में मीडिया व मनोरंजन क्षेत्र के सीइओ के साथ गोलमेज बैठक में

1 एक झलक

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, रेडियो, टेलीविजन, फ़िल्मों, प्रेस और प्रकाशनों, विज्ञापन तथा संचार के परंपरागत माध्यमों जैसे नृत्य एवं नाटकों के जरिए जनता को सूचना की शुल्क रहित प्राप्ति में असरकारी भूमिका निभाता है। मंत्रालय विभिन्न आयु वर्ग की मनोरंजन की जरूरतों का भी ध्यान रखता है और साथ ही, राष्ट्रीय अखंडता, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, निरक्षरता का अंत और महिलाओं, बच्चों, अल्पसंख्यकों एवं समाज के अन्य पिछड़ा वर्ग के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। मंत्रालय को तीन कार्यकारी विभागों में बांटा गया है, जो हैं, सूचना विभाग, प्रसारण विभाग और फिल्म्स विभाग। मंत्रालय 18 मीडिया इकाइयों/संबंधित एवं अधीन कार्यालयों, स्वायत्त अंगों एवं सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के जरिए काम करता है। मंत्रालय का मुख्य सचिवालय एक सचिव के अंतर्गत काम करता है जिसके अधीन एक अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (एएसएंडएफए), एक अतिरिक्त सचिव, एक वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार, एक आर्थिक सलाहकार, चार संयुक्त सचिव एवं एक अतिरिक्त आर्थिक सलाहकार होते हैं। मुख्य सचिवालय के विभिन्न प्रखंडों में 21 पद निदेशक/उप-निदेशक/वरिष्ठ पीपीएस, 36 पद अंडर सेक्रेटरी/पीपीएस स्तर अधिकारियों के, 68 पद सहायक निदेशक/विभाग अधिकारियों/पीएस स्तर के अधिकारियों के एवं 260 अराजपत्रित पद हैं।

मंत्रालय का सूचना प्रभाग प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के संबंध में भारत सरकार की नीतियों एवं गतिविधियों का प्रस्तुतिकरण एवं व्याख्या का कार्य करता है, साथ ही, यह प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं ऑनलाइन मंचों पर नियत सरकारी दरों से जुड़े नीतिगत दिशानिर्देशों की भी स्थापना करता है और प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट, 1867, पत्र सूचना कार्यालय, 1978, भारतीय सूचना सेवा का कैडर मैनेजमेंट (आईआईएस) एवं मंत्रालय से जुड़ी आम सूचना का कार्य भी देखता है।

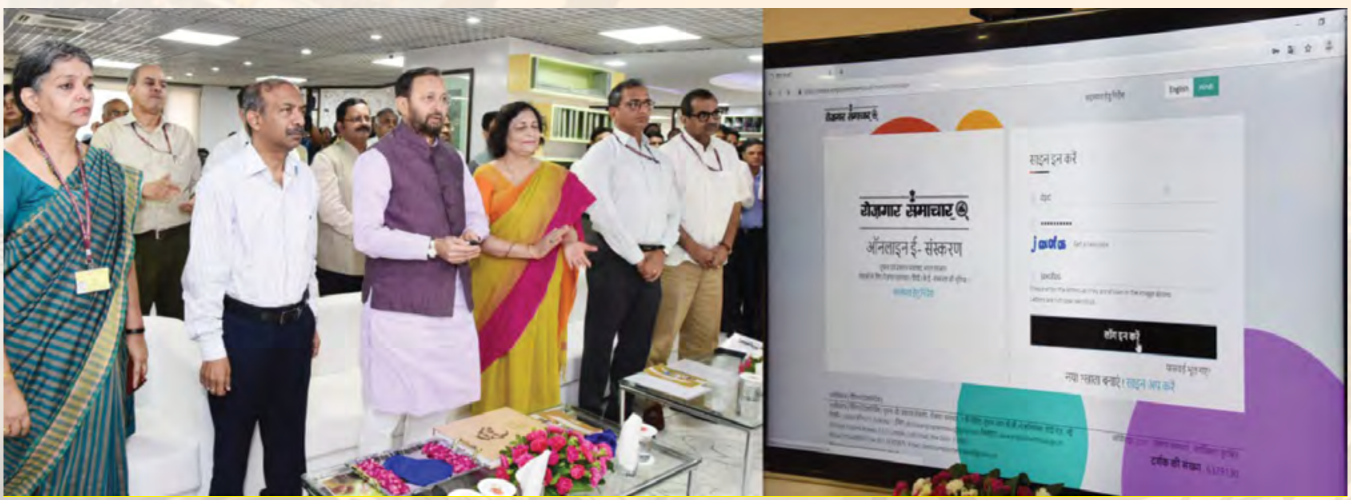

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन और सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर 31 जुलाई, 2019 को रोजगार समाचार के 'ई–संस्करण' का उद्घाटन करते हुए

प्रसारण प्रभाग प्रसार भारती अधिनियम, 1990 के प्रशासनिक कार्यों के माध्यम से ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के कार्य देखता है। यह केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (नियमन) अधिनियम 1995 और नीतिगत दिशानिर्देशों के माध्यम से समय-समय पर निजी सेटेलाइट चैनलों और मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों के नेटवर्क तथा स्थानीय केबल ऑपरेटरों के कार्यक्रमों पर नियंत्रण रखता है। प्रभाग द्वारा ही ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों के निजी एफएम रेडियो चैनलों और सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की नीलामी का कार्य संपन्न किया जाता है।

फ़िल्म प्रभाग सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952 के अंतर्गत फ़िल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन से जुड़ा प्रमाणीकरण, फ़िल्म उद्योग से जुड़े मामले जिनमें विकास एवं प्रोत्साहन गतिविधियां, फ़िल्मों का संरक्षण, वृत्तचित्रों का निर्माण एवं प्रसारण, अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सवों का व्यवस्थापन, पुरस्कारों के जरिए स्वस्थ सिनेमा को प्रोत्साहन आदि जैसे कार्यों को देखता है।

मंत्रालय के वित्त, बजट और लेखा से संबंधित मामले एकीकृत वित्त प्रभाग देखता है।

मंत्रालय का आर्थिक प्रभाग योजना, बजट, योजना समन्वयन, ओ एंड एम गतिविधियां और ऑनलाइन पोर्टल के जरिए कैबिनेट सचिव को विभिन्न मामलों की नियतकालीन सूचना देने का कार्य देखता है। आर्थिक सलाहकार द्वारा सीपीजीआरएएम पोर्टल, यातायात एवं संचार के क्षेत्रीय समूह सचिवों (एसजीओएस–09) से जुड़े कार्य, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के लिए नोडल अफसरों के अंतर्मंत्रालयी और न्यू इंडिया कोड पोर्टल का संचालन, एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) की सालाना बैठक के संयोजन से जुड़े मामले और साइबर सुरक्षा कानून के अलावा सूचना एवं प्रसारण सचिव को आर्थिक मामलों में सहयोग देने के कार्य देखे जाते हैं।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का कार्यक्षेत्र

मंत्रालय को उसके कार्यों में 10 संबद्ध और अधीन कार्यालय, 6 स्वायत्त संगठन और 2 सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां सहयोग देते हैं।

संबद्ध/अधीन कार्यालय

1. पत्र सूचना कार्यालय
2. ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन
3. भारत के समाचार–पत्रों के पंजीयक का कार्यालय
4. प्रकाशन विभाग
5. न्यू मीडिया विंग
6. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनीटरिंग सेंटर
7. फ़िल्म प्रभाग
8. केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड
9. राष्ट्रीय फ़िल्म संग्रहालय
10. फ़िल्म महोत्सव निदेशालय

स्वायत्त संगठन

1. भारतीय प्रेस परिषद
2. भारतीय जन-संचार संस्थान
3. प्रसार भारती (ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया)
4. राष्ट्रीय फ़िल्म एवं टेलीविजन इंस्टीट्यूट, पुणे

24 दिसंबर, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में 44वें आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार प्रदान करते हुए केंद्रीय भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर। साथ में हैं प्रसार भारती के चेयरमैन डॉ. ए. सूर्य प्रकाश

5. सत्यजित रे फ़िल्म एवं टेलीविजन इंस्टीट्यूट, कोलकाता
6. बाल चित्र समिति, भारत

सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयां

1. ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड
2. राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र

- देशवासियों तथा प्रवासी भारतीयों के लिए ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) तथा दूरदर्शन (डीडी) पर समाचार सेवाएं;
- प्रसारण एवं टेलीविजन का विकास;
- फ़िल्म उद्योग का विकास एवं प्रोत्साहन;
- फ़िल्म महोत्सवों एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान का आयोजन;
- भारत सरकार की ओर से विज्ञापन एवं चित्र प्रचार तथा प्रकाशन से जुड़ा फीडबैक प्राप्त करना;
- समाचार पत्रों के संबंध में प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट, 1867 का संचालन;
- फ़िल्म प्रमाणन के संबंध में सिनेमेटोग्राफ एक्ट, 1952 का संचालन;
- प्रसार भारती (ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) एक्ट, 1990 (1990 का 25) का प्रसार नियंत्रण एवं संचालन;
- केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (विनियमन) एक्ट, 1995, (1995 का 7);
- डीटीएच/एचआईटीआई ऑपरेटरों को लाइसेंस प्रदान करने की मंजूरी;
- प्रेस काउंसिल अधिनियम, 1978 का संचालन (1978 का 37);
- भारतीय सूचना सेवा का कैडर प्रबंधन (ग्रुप ए और बी);
- राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर भारत और देश से बाहर सूचना का प्रकाशनों के माध्यम से विस्तार;
- मंत्रालय की मीडिया इकाइयों को शोध, संदर्भ एवं प्रशिक्षण में सहयोग;
- मंत्रालय के संस्थानों को बड़ी मात्रा में सहयोग देने वाले प्रतिष्ठित कलाकारों, संगीतकारों, वादकों, नर्तकों, नाट्यकारों को वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराना;
- प्रसारण एवं समाचार सेवाओं के मामले में अंतरराष्ट्रीय संबंध स्थापित करना।

नई दिल्ली 5 अगस्त, 2019 को भारतीय सूचना सेवा के दूसरे अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन सत्र

2 मंत्रालय की भूमिका और कार्य

सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के संबंध में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की भूमिका और कार्य निम्न हैं :

I. प्रसारण नीति और प्रशासन

1. भारतीय संघ में रेडियो और टेलीविजन से जुड़े सभी मामले जिनमें राजनीतिक दलों द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभा चुनावों के समय ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के इस्तेमाल और किसी शीर्ष नेता के निधन के अवसर पर राष्ट्रीय शोक के समय सभी आधिकारिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा कार्यविधि का पालन किया जाता है।
2. भारत में रेडियो और टेलीविजन से जुड़े कानूनों को स्पष्ट करना और अमल में लाना।
3. प्रसार भारती (ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) अधिनियम, 1990 (1990 का 25) का प्रसारण नियंत्रण एवं प्रबंधन।
4. प्रसार भारती के सुपुर्द किए जाने तक भारतीय प्रसारण (कार्यक्रम) सेवा और भारतीय प्रसारण (अभियांत्रिकी) सेवा से जुड़े सभी मामले देखना।

II. केबल टेलीविजन नीति

1. केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (विनियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का 7)।

III. रेडियो

1. ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े सभी कार्य जिनमें घरेलू कार्यक्रमों में समाचार सेवाओं का उपयोग, विदेशों और प्रवासी भारतीयों के लिए कार्यक्रम, रेडियो जर्नल्स, प्रसारण अभियांत्रिकी के क्षेत्र में शोध, विदेशी प्रसारणों की जांच, कार्यक्रम आदान-प्रदान एवं प्रतिलेखन सेवाएं, सामुदायिक श्रवण योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को सामुदायिक सेट्स देना आदि।
2. भारतीय संघ में रेडियो प्रसारण का विकास, रेडियो

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर दूरदर्शन समाचार प्रभाग, नई दिल्ली की नई डीएसएनजी वैन को 4 जून, 2019 को हरी झंडी दिखाते हुए

स्टेशनों की स्थापना और रखरखाव एवं ट्रांसमीटरों तथा प्रसारण सेवाओं का संचालन।

IV. दूरदर्शन

1. टीवी कार्यक्रमों के सांस्कृतिक एवं अन्य आदान-प्रदान।
2. देशभर में कार्यक्रम निर्माण केंद्रों एवं ट्रांसमीटरों तथा टेलीविजन सेवाओं की स्थापना, रखरखाव और संचालन सहित उनकी सेवाएं चलाना।
3. दूरदर्शन से बाहर के टेलीविजन कार्यक्रमों को प्रोत्साहन।

V. फ़िल्में

1. संघीय सूची की प्रविष्टि 60 के अंतर्गत, 'प्रदर्शन के लिए सिनेमेटोग्राफ फ़िल्मों को मंजूरी'।
2. सिनेमेटोग्राफ एक्ट, 1952 (1952 का 37) का प्रबंधन।
3. थियेटर और गैर-थियेटर प्रदर्शन के लिए फ़ीचर एवं लघु फ़िल्मों का आयात।
4. विकास एवं प्रोत्साहन सहित फ़िल्म उद्योग से जुड़े सभी मामले।
5. राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कारों की स्थापना के जरिए भारत में निर्मित सार्थक सिनेमा को प्रोत्साहन। इसमें राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम लिमिटेड का सहयोग रहता है।
6. आंतरिक और बाहरी प्रचार के लिए फ़िल्म अंश, वृत्तचित्रों एवं न्यूज़ रीलों का निर्माण तथा वितरण।
7. फ़िल्मों और फ़िल्म संबंधी सामग्री का संरक्षण।
8. भारत में अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोहों का आयोजन और भारत को विदेशी अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोहों में सहभागिता में सहयोग
9. सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के अंतर्गत फ़िल्म समारोहों का आयोजन।
10. फ़िल्म सोसाइटी अभियान को सहयोग।

VI. विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार

1. भारत सरकार की ओर से मीडिया योजनाएं, निर्माण एवं विज्ञापन वितरण तथा सरकारी विज्ञापनों से संबंधित विज्ञापन नीति के निर्माण में सहयोग करना।

VII. प्रेस

1. प्रेस के माध्यम से भारत सरकार की नीतियों एवं गतिविधियों का प्रस्तुतिकरण और व्याख्या।
2. सरकार को प्रेस से जुड़ी सूचना समस्याओं से अवगत कराना, प्रेस में प्रकाशित प्रमुख जन रुझानों की जानकारी सरकार को देना और सरकार तथा प्रेस के बीच संपर्क का कार्य।
3. सशस्त्र सेवाओं के लिए प्रसार कार्य।
4. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 95 और 96 के संचालन से इतर प्रेस के प्रति सरकार के आचार-व्यवहार की देखरेख।
5. समाचार-पत्रों के संबंध में प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 (1867 का 25) का संचालन।
6. प्रेस काउंसिल अधिनियम, 1978 (1978 का 37) का संचालन।
7. न्यूज़प्रिंट आयात के लिए प्रकाशकों के स्व-प्रमाण पत्रों का प्रमाणीकरण।
8. सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों तथा फोटोग्राफिक दस्तावेजों का दृश्य प्रचार।

VIII. प्रकाशन

1. भारत के बारे में देश एवं बाहर आमजन को सही सूचना प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर आंतरिक एवं बाहरी प्रचार के लिए लोकप्रिय प्रचार पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का प्रकाशन, बिक्री और वितरण।

IX. शोध एवं संदर्भ

1. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, अन्य मंत्रालयों तथा सरकार से बाहर के संस्थानों की मीडिया इकाइयों को शोध सामग्री वाले प्रकाशित कार्यों आदि में संकलन, एकत्र एवं तैयार करने में सहयोग करना।
2. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, अन्य मंत्रालयों एवं सरकार से इतर संगठनों की मीडिया इकाइयों को मौजूदा एवं अन्य मुद्दों पर दिशानिर्देश तथा पृष्ठभूमि नोट जारी करना और महत्वपूर्ण विषयों पर संक्षिप्त सूचना तैयार करना।

X. विविध

1. भारत सरकार के कार्यक्रमों एवं नीतियों का प्रचार।
2. पत्रकार कल्याणकारी योजना का संचालन।

3. ऑल इंडिया रेडियो और मंत्रालय की अन्य इकाइयों की सफलता में असीम योगदान देने वाले प्रतिष्ठित संगीतकारों, गायक और वादकों, नर्तकों तथा नाटककारों या विषम परिस्थितियों में रहने वाले उनके उत्तराधिकारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

4. एशिया–पेसेफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन, कॉमनवेल्थ ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन और गुट–निरपेक्ष न्यूज़ एजेंसी पूल से जुड़े मामलों की देखरेख।

5. विभिन्न देशों के साथ सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रमों (सीईपी)/अनुबंध/समझौता ज्ञापन/प्रोटोकॉल से जुड़े मामले; इंटरनेशनल प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन (आईपीडीसी)/यूनेस्को, उदाहरण के तौर पर बजट मामले, नामांकन आदि से जुड़े सभी कार्य देखना।

6. भारतीय सूचना सेवा (ग्रुप ए और बी) के कैडर प्रबंधन से जुड़े कार्य।

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा सूचना एवं प्रसारण तथा भारी उद्यम और लोक उपक्रम मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर 7 जनवरी, 2020 को नई दिल्ली में प्रथम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए

3 मंत्रालय के नए प्रयास

- प्रधानमंत्री कार्यालय के माननीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह और माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर की उपस्थिति में 22 जून, 2019 को जम्मू और कश्मीर के माननीय गवर्नर श्री सत्यपाल मलिक ने जम्मू और कश्मीर में **दूरदर्शन के फ्री डिश सेट टॉप बक्सों का वितरण** किया। जम्मू और कश्मीर के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को दूरदर्शन की ओर से 30,000 डीडी फ्री डिश रिसीव सेट्स का वितरण किया गया। इस अवसर पर चैनल की ओर से अपनी चिर-परिचित धुन के साथ डीडी कशीर पर समाचार बुलेटिन और आधे घंटे के डोगरी कार्यक्रमों का भी शुभारंभ किया गया।
- 13 सितंबर, 2019 को **118 नए सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सीआरएस)** को स्थापित किए जाने की प्रक्रिया की घोषणा की गई। इनमें से 16 वामपंथी आतंकवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों, 6 तीव्र एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों, 25 तटवर्ती जिलों, 17 आकांक्षित क्षेत्रों, 3 पूर्वोत्तर तथा 2 जम्मू और कश्मीर में स्थापित किए जाएंगे।
- इस वर्ष से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा योग का संदेश प्रसारित करने में मीडिया की भूमिका के योगदान के लिए **अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान (एवाईडीएमएस)** की स्थापना की गई। 7 जनवरी, 2020 को नई दिल्ली में नेशनल मीडिया सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने 30 विजेताओं को यह सम्मान प्रदान किया।
- 11 सितंबर, 2019 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने **श्रवण बाधित व्यक्तियों तक सरल पहुंच बनाने के लिए टीवी कार्यक्रमों की घोषणा की।** यह कार्य भारतीय संकेत भाषा और अनुशीर्षकों के आधार पर किया जा रहा है। इसके अंतर्गत सभी न्यूज चैनल्स प्रतिदिन एक बार न्यूज बुलेटिन और संकेत भाषा व्याख्या प्रसारित करेंगे तथा सभी टीवी चैनल्स एवं सेवा प्रदाता

गोवा के पणजी में 20 नवंबर, 2019 को भारत के 50वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह (इफ्फी–2019) के उद्घाटन के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, सूचना एवं प्रसारण तथा भारी उद्यम और लोक उपक्रम मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर, के साथ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री बाबुल सुप्रियो तथा मुख्य अतिथि महानायक अमिताभ बच्चन एवं श्री रजनीकांत

सप्ताह में सब्टाइटल्स/कैप्शनिंग सहित एक कार्यक्रम प्रसारित करेंगे। इन मानकों को अगले पांच वर्षों में चरणबद्ध तरीके से अमल में लाया जाएगा। प्रत्येक दो वर्ष बाद नीति का पुनर्आकलन भी किया जाएगा।

- गोवा के पणजी में 20-28 नवंबर, 2019 तक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के फिल्म महोत्सव निदेशालय ने भारत के **अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 50वें संस्करण** का आयोजन किया। इस अवसर पर इफ्फी के इतिहास में पहली बार प्रथम दिवस स्मारक कवर जारी किया गया और मास्टर फ्रेम्स, गोल्डन पीकॉक रेट्रोस्पेक्टिव, रिस्टोर्ड इंडियन क्लासिक्स, सोल ऑफ एशिया, साइलेंट फिल्म विद लाइव म्यूजिक आदि जैसे नए सेक्शन भी प्रदर्शित किए गए। आईएफएफआई 2019 के आरंभ के तौर पर 13 नवंबर, 2019 को नई दिल्ली में 50वें इफ्फी ऑडियो-विजुअल गान को जारी किया गया जिसका उद्देश्य भारत से आने वाले मनोरंजन का उद्भव था। इस अवसर पर, गोवा में बीओसी और भारतीय राष्ट्रीय फिल्म पुरातत्व (एनएफएआई) द्वारा 'एनएफएफआई@50' नामक विशेष मल्टीमीडिया डिजिटल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।

- **सोशल मीडिया और फेक न्यूज पर रोक** लगाने के लिए मंत्रालय ने निम्न पहल की हैं :

1) पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) द्वारा प्रादेशिक भाषाओं में सोशल मीडिया हैंडल्स का विकास।

2) फेक न्यूज पर रोक लगाने के लिए पीआईबी के अंतर्गत एक विशेष सेल का गठन।

- **ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के लिए,** टीवी चैनलों की अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए दिशानिर्देशों संबंधी पहल की गई हैं। इसके अंतर्गत, एप्लिकेशन ट्रेकिंग प्रक्रिया विकसित करना, अंतरिक्ष विभाग द्वारा प्रार्थनापत्रों के ऑनलाइन आवंटन आदि शामिल हैं।

- 4 दिसंबर, 2019 को बीएमएस मंच पर एनएमआईसी टिकटों की उपलब्धता बनाए रखने के लिए फिल्म प्रभाग और बुक माई शो (बीएमएस) के बीच भारतीय सिनेमा के **राष्ट्रीय संग्रहालय (एनएमआईसी) की ऑनलाइन टिकेटिंग** के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। यह एमओयू भारत एवं विदेशी सिनेप्रेमियों की सुविधा और एनएमआईसी तक अधिकाधिक लोगों की पहुंच बनाने के लिए की गई पहल का हिस्सा है।

- 31 अगस्त, 2019 को माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने **केंद्रीय फिल्म प्रमाणपत्र बोर्ड (सीबीएफसी) के नए लोगो एवं प्रमाणपत्र डिजाइन** का अनावरण किया। मुंबई में इस अवसर पर मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी एवं फिल्म जगत की अनेक जानी-मानी हस्तियां मौजूद थे।

- **भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) के स्थानीय कैम्पस**

माननीय प्रधानमंत्री ने जम्मू में फरवरी 2019 में आईआईएमसी के नए स्थायी कैम्पस का शिलान्यास किया। स्थायी कैम्पस निर्माण कार्य पूरी तेजी से चल रहा है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए, मिजोरम विश्वविद्यालय के परिसर में आईआईएमसी के नए कैम्पस का निर्माण संपूर्ण किया गया और अब शीघ्र ही नए कैम्पस में कक्षाएं आरंभ होंगी।

2019-20 के अकादमिक सत्र के लिए आईआईएमसी के कोट्टयम कैम्पस की शुरुआत की गई।

- भारतीय फिल्म एवं टीवी इंस्टीट्यूट (एफटीआईआई) ने अपने विशेष डायमंड जुबली लोगो का अनावरण किया और उन जिन **भूतपूर्व छात्रों को पहले डिप्लोमा नहीं मिला था उन्हें डिप्लोमा प्रदान करने की घोषणा की। भारत को फिल्म एवं टेलीविजन में सिद्धहस्त (एसकेआईएफटी)** करने की पहल के चलते, एफटीआईआई ने जयपुर में जवाहर कला केंद्र (राजस्थान सरकार) के सहयोग से पहले 'बेसिक कोर्स इन विजुअल स्टोरीटेलिंग (चित्रों एवं टेक्स्ट तथा ऑडियो-वीडियो के माध्यम से)' की शुरुआत की।

- 7 मई, 2019 को एक समझौते के अंतर्गत **बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के जीवन पर संयुक्त रूप से बनाई जाने वाली फिल्म** और बांग्लादेश मुक्ति संघर्ष पर एक वृत्तचित्र बनाने का निर्णय लिया गया। इस फिल्म का

निर्माण प्रख्यात फिल्म निर्देशक श्री श्याम बेनेगल करेंगे। दोनों देशों के माननीय प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त प्रयास से बनाई जाने वाली फिल्म की घोषणा की।

- मंत्रालय ने **1997 के केबल एवं टेलीविजन नेटवर्क नियमों** में प्रस्तावित संशोधन की सिफारिश के आधार पर कहा है कि टीवी चैनलों पर दिखाए जाने वाले विभिन्न भाषाओं के धारावाहिकों में नाम/सूची/हिंदी शीर्षक/क्षेत्रीय भाषाओं में भी दिखाए जाएं।

- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बलतल की 103.7 मेगाहट्र्ज फ्रीक्वेंसी पर **अमरनाथ यात्रा** रूट के लिए एक **एफएम रेडियो ट्रांसमीटर स्थापित** किया है। 'अमरनाथ यात्रा' कार्यक्रम **बालटाल** बेस कैम्प से निर्मित किया जा रहा है जहां स्टूडियो सुविधा मौजूद है।

- ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन (बीओसी) द्वारा **निजी सीएंडएस चैनलों के मनोनयन एवं शुल्क निर्धारण संबंधित संशोधित दिशानिर्देश** से जुड़ी सूचना प्रेषित की गई। संशोधित दिशानिर्देशों में वृहद पहुंच वाले समाचार एवं जीईसी चैनलों के लिए विभिन्न शुल्कों का प्रावधान है। सार्वजनिक क्षेत्र के महारत्न एवं नवरत्न कंपनियों के शुल्क अन्य की अपेक्षा 1.5 गुना होंगे। अन्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम साधारण बीओसी शुल्क पर रहेंगे।

- 14 नवंबर, 2019 को माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने मंत्रालय द्वारा पुणे के क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो (आरओबी) **अनोखी यात्रा-संबंधी प्रदर्शनी 'जलदूत'** को हरी झंडी दिखाई। 'जलदूत' आमजन को जल संरक्षण के लिए प्रेरित करेगी और यह पहल **'जल शक्ति अभियान'** के अंतर्गत किया जा रही है।

- **बांग्लादेश एवं दक्षिण कोरिया के साथ संबंधों में मजबूती** लाने के लिए केंद्र सरकार ने 19-06-2019 को भारत में दूरदर्शन के दर्शकों के लिए दोनों देशों के एक-एक चैनल को दूरदर्शन फ्री डिश प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रसारित करने का निर्णय लिया। देश के पूर्वी हिस्से के दर्शकों के लिए बांग्लादेश टीवी का बीटीवी वर्ल्ड विशेष रुचिकर हो सकता है। इसी तरह कोरियन पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग चैनल केबीएस वर्ल्ड को डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रसारित किया गया। 16-09-2019 को रिपब्लिक ऑफ कोरिया के केबीएस वर्ल्ड के माईकेओटीटी प्लेटफॉर्म से डीडी इंडिया का प्रसारण आरंभ किया गया।

- देश भर में **'जल शक्ति अभियान'** के अवसर पर दूरदर्शन समाचार ने 1 जुलाई, 2019 से स्वच्छता समाचार के स्थान पर दिन में दो बार **'जल शक्ति समाचार'** का आरंभ किया।

- 4 जून, 2019 को माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर द्वारा **दूरदर्शन समाचार के लिए** सत्रह **नई डिजिटल सर्विस न्यूज गैदरिंग (डीएसएनजी) वैन्स को हरी झंडी** दिखाई। यह वैन्स विभिन्न कैमरा के माध्यम से वीडियो चित्रों का सीधा प्रसारण और हाई डेफिनिशन कंटेंट प्रसारण को सहयोग करती हैं।

- 25 जुलाई, 2019 को माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने दिल्ली स्थित दूरदर्शन केंद्र में 8 डीडी स्टूडियोज में **अत्याधुनिक वीडियो वॉल्स** का उद्घाटन किया।

- 15 नवंबर, 2019 को माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने नई दिल्ली में **ऑल इंडिया रेडियो के नए ब्रॉडकास्ट ऑडिटोरियम** का उद्घाटन किया। नए ऑडिटोरियम में बहुउपयोगी हॉल, एडिटिंग स्टूडियो, मल्टीमीडिया सुविधाएं आदि होंगी।

- सरकार के प्रमुख प्रयासों और मंत्रिपरिषद के फैसलों की जानकारी प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो के न्यूज सर्विसेज डिविजन (एनएसडी, एआईआर) ने 9 दिसंबर, 2019 को **नया रोज प्रसारित टॉक शो 'मंथन - फैसलों का'** का शुभारंभ किया। इस शो का प्रसारण राजधानी चैनल पर किया जा रहा है और इसमें विशेष साक्षात्कार एवं विचार-विमर्श भी प्रसारित किया जा रहा है। एनएसडी, एआईआर ने यूट्यूब चैनल पर समाचार आधारित कार्यक्रम जैसे 'लैट्स कनेक्ट', 'फ्रॉम द स्टेट्स', 'इंटरनेशनल न्यूज', 'द वीक-एंडर' और 'द ईयर-एंडर भाग I और II' को भी अपलोड करना आरंभ किया है।

25 जुलाई, 2019 को दिल्ली के दूरदर्शन केंद्र में 8 डीडी स्टूडियो एवं अर्थ स्टेशन में वीडियो वॉल्स का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर। साथ में हैं, प्रसार भारती के चेयरमैन डॉ. ए. सूर्य प्रकाश

- ऑल इंडिया रेडियो न्यूज एवं उसकी पुणे तथा नागपुर की **क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा दृष्टि बाधित विद्यार्थियों तथा अधिकारियों** द्वारा प्रसारित समाचार पढ़ने की अभिनव विधि के आधार पर विश्व ब्रेल दिवस (4 जनवरी 2020) का आयोजन किया गया। समाचार लिपि ब्रेल में लिखित थी और उसे सीधे प्रसारण के दौरान पढ़ा गया।

- भारतीय राष्ट्रीय फिल्म आर्काइव (एनएफएआई) में 15 सितंबर, 2019 को माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने **पुणे के प्रसिद्ध स्मारक जयकर बंगले का उद्घाटन** किया जिसका हाल में जीर्णोद्धार किया गया है। इस बंगले में एक डिजिटल फिल्म पुस्तकालय होगा जहां शोधकर्ता आर्काइव के व्यापक फिल्म डाटाबेस का लाभ उठा सकेंगे।

- देश में **इलेक्ट्रिक-मोबिलिटी को प्रोत्साहन** देते हुए, 1 नवंबर, 2019 को माननीय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा हाल में प्राप्त **ई-वाहनों** को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर घोषणा की गई कि सरकार एवं उसकी एजेंसियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली 5 लाख पेट्रोल एवं डीजल कारों को चरणबद्ध तरीके से ई-वाहनों द्वारा बदला जाएगा।

- माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **रेडियो एवं टेलीविजन के क्षेत्र में भारत एवं विदेशी प्रसारकों के बीच समझौता ज्ञापन** (एमओयू) को मंजूरी प्रदान की है। इस एमओयू के आधार पर प्रसारकों को वैश्वीकरण एवं मीडिया स्वायत्ता, नई तकनीकों की मांग और कड़ी प्रतिस्पर्धा के लिए नीतियां तैयार करने एवं नए आयाम खोजने में सहायता मिलेगी।

- 9 से 11 अगस्त, 2019 को पहली बार पूर्वी भारत में एसआरएफटीआई द्वारा एक तीन दिवसीय **वर्कशॉप 'थियेटर ऑन स्क्रीन'** का आयोजन किया गया जिसमें

1 नवंबर, 2019 को शास्त्री भवन नई दिल्ली में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्राप्त किए गए इलेक्ट्रिक वाहनों का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर

बंगाल के थियेटर और पर्दे पर उसके चित्रण को दर्शाया गया जिसके अंतर्गत उसके इतिहास और अकादमिक क्षेत्र में उसके विकास पर जोर दिया गया।

- 30 सितंबर से 7 अक्टूबर, 2019 भारत के फिल्म एवं टेलीविजन इंस्टीट्यूट (एफटीआईआई) द्वारा पहली बार **पुद्दुचेरी के ऑरोविले में फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स** का आयोजन किया गया।

8 सितंबर, 2019 को नई दिल्ली में सरकार के 100 दिन पूरे होने पर 'भारत का विकास : साहसिक पहल और निर्णायक कार्रवाई के 100 दिन' पर प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर

4 सूचना क्षेत्र की गतिविधियां

पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)

पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों, पहलों तथा उपलब्धियों से संबंधित सूचना के प्रसार के लिए भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। यह विभाग सरकार और मीडिया के बीच सेतु का काम करता है और मीडिया में दिख रही लोगों की प्रतिक्रियाओं पर सरकार को फीडबैक देता है।

1. पीआईबी का विज़न

भारत की जनता को शिक्षित और सशक्त बनाने के लिए सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों के बारे में सूचना का प्रचार–प्रसार करना।

2. पीआईबी के कार्य

पीआईबी सरकार और मीडिया के बीच सेतु का काम करता है। सरकार को मीडिया की आवश्यकताओं की पूर्ति की दृष्टि से उपयुक्त संचार कार्यनीतियों के बारे में सरकार को परामर्श देता है। पत्र सूचना कार्यालय का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में मीडिया में दिख रही लोगों की धारणाओं के बारे में सरकार को सूचित करना है।

पीआईबी प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस नोट्स, फ़ीचर लेख, विषय संबंधी पृष्ठभूमि, प्रेस ब्रीफिंग्स, साक्षात्कारों, संवाददाता सम्मेलनों और प्रेस दौरों आदि जैसे विविध साधनों के माध्यम से सूचना का प्रसार करता है। पीआईबी सूचना का प्रसार करने के लिए ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल भी करता है। सूचना अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू के साथ–साथ 11 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में जारी की जाती है, जो देशभर के अखबारों और मीडिया संगठनों तक पहुंचती है।

पीआईबी में न्यूज़ रूम/न्यूज़ मॉनिटरिंग सेल है, जो सूचना के प्रसार संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सालभर क्रियाशील रहता है।

पीआईबी मीडियाकर्मियों को प्रत्यायन की सुविधा भी उपलब्ध कराता है, ताकि वे सरकारी स्रोतों से सूचना प्राप्त करने के लिए उन तक पहुंच बना सकें।

3. संगठनात्मक ढांचा

पीआईबी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके प्रमुख प्रधान महानिदेशक (मीडिया एवं कम्युनिकेशन) होते हैं। इसके अतिरिक्त ब्यूरो में महानिदेशक, अपर महानिदेशक, निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक तथा मीडिया और कम्युनिकेशन अधिकारी तथा सूचना सहायक होते हैं, जो विभिन्न मंत्रालयों में अधिकारियों के रैंक, मंत्रालय के आकार, महत्व और संवेदनशीलता को देखते हुए संबद्ध किए जाते हैं।

क्षेत्रीय मीडिया की सूचना आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पीआईबी के पांच ज़ोन हैं, जिनमें अपर महानिदेशक स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व वाले 19 क्षेत्रीय कार्यालय और एक सूचना केंद्र सहित 17 शाखा कार्यालय शामिल हैं।

4. पीआईबी की प्रचार से संबंधित गतिविधियां

क. मंत्रालयों/विभागों का प्रचारः

पीआईबी के अधिकारी मंत्रालय/विभाग से संबद्ध होते हैं और वे उसके अधिकृत प्रवक्ता होते हैं। अधिकारी मंत्रालय/विभाग की नीतियों और कार्यक्रमों की जानकारी मीडिया को देते हैं, सूचना का प्रसार करते हैं, प्रश्नों का उत्तर देते हैं और आवश्यकता पड़ने पर स्पष्टीकरण देते हैं या गलतफहमियां दूर करते हैं। अधिकारी अख़बारों के संपादकीय, लेखों तथा टिप्पणियों में व्यक्त जन प्रतिक्रिया का विश्लेषण करते हैं, ताकि मंत्रालय/विभाग को लोगों की प्रतिक्रियाओं से अवगत कराया जा सके। पीआईबी के अधिकारी मंत्रालय/विभाग को मीडिया तथा आईईसी कार्यनीति के बारे में सलाह देते हैं।

ख. क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों द्वारा सूचना प्रसार संबंधी गतिविधियांः

क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों में पीआईबी अधिकारी, मुख्यालय से प्राप्त होने वाली सूचनाओं को प्रसारित करने के अलावा, केंद्रीय मंत्रालयों या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपने क्षेत्र में आयोजित किसी भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम का कवरेज भी सुनिश्चित करते हैं। ये कार्यालय निरंतर आधार पर सूचना प्रसार के आधार पर केंद्रित प्रचार के लिए एक विशेष क्षेत्र के लिए, केंद्र सरकार के निर्णय भी ले सकते हैं, जो विशेष

महत्व का हो सकता है। पीआईबी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय एक क्षेत्र/राज्य के अपने आधिकारिक दौरे पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और सचिवों के मीडिया कवरेज को सुविधाजनक बनाने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं।

पीआईबी के क्षेत्रीय और शाखा कार्यालय के अधिकारी मुख्यालय द्वारा जारी सूचना का प्रसार करने के अलावा अपने–अपने क्षेत्रों में केंद्रीय मंत्रालयों या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण आयोजनों का प्रचार करते हैं। ये कार्यालय किसी क्षेत्र विशेष के लिए महत्वपूर्ण केंद्र सरकार के लक्षित प्रचार निर्णयों को भी सतत सूचना प्रसार के आधार पर लागू करते हैं। पीआईबी के स्थानीय/शाखा कार्यालय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों तथा सचिवों के क्षेत्र/राज्य के दौरों के अवसर पर भी मीडिया कवरेज सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सूचना संचार के अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए पत्र सूचना कार्यालय द्वारा निम्नलिखित संचार रणनीतियां अपनाई जाती हैं:

1. संचार के परंपरागत स्वरूप, यानी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर संवाददाता सम्मेलन (वीडियो माध्यम सहित),
2. महत्वपूर्ण घोषणाओं और आयोजनों से संबंधित प्रेस विज्ञप्तियां और फोटो जारी करना। इनके बारे में मीडियाकर्मियों को एसएमएस अलर्ट, ट्वीट् तथा फोन कॉल भी किए जाते हैं।
3. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर साक्षात्कार, विशेष चर्चाओं आदि का प्रबंध।
4. वेबसाइट्स पर नियमित रूप से जानकारी प्रदान करने के अलावा ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वेबसाइट जैसे नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का उपयोग करना।
5. पीआईबी द्वारा प्रद्रत्त सूचनाओं का प्रचार होता है। पीआईबी के एप एन्ड्राइड और आइओएस प्लेटफार्म पर डाउनलोड किया जाता है और पत्रकारों द्वारा इस्तेमाल होता है। साथ ही पीआईबी वेबसाइट एप से अन्य व्यक्ति भी इसका लाभ प्राप्त करते हैं। एन्ड्राइड प्लेटफार्म और एप का डाउनलोड सैकड़ों और हजारों बार होता है।
6. पीआईबी के क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों द्वारा हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के अतिरिक्त प्रमुख भाषाओं– मलयालम, ओडिया, कन्नड़, तेलुगू, तमिल, पंजाबी, गुजराती, मराठी, असमी तथा बांग्ला में अखिल भारतीय कवरेज सुनिश्चित करना।
7. स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, आम बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, भारत का अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोह (आईएफएफआई), राष्ट्रीय एकता दिवस, योग दिवस, स्वच्छ भारत सप्ताह आदि महत्वपूर्ण आयोजनों के प्रचार के विशेष प्रबंध किए जाते हैं।
8. अंग्रेजी और हिंदी में दैनिक मीडिया रिपोर्ट के रूप में मीडिया से मिले फीडबैक को प्रधानमंत्री कार्यालय भेजना, प्रत्येक मंत्रालय के अधिकारी द्वारा दैनिक मीडिया फीडबैक अपने मंत्रालय को भेजना संबंधित विशेष अवसरों पर विशेष फीडबैक सहित।
9. पीआईबी जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों सहित दूरस्थ क्षेत्रों में लोक सूचना अभियान (पीआईसी) के माध्यम से अंतिम छोर तक पहुंच बनाता है।

मीडिया उत्पाद/सेवा माध्यम	संख्या (1 अप्रैल, 2019 से 05 नवंबर, 2019 के दौरान)
प्रेस विज्ञप्तियां	12471
फोटोग्राफ/इंफोग्राफिक्स/ग्राफ	8570 (31 अक्टूबर, 2019 तक)
मीडिया निमंत्रण	496
औपचारिक संवाददाता सम्मेलन	26
वार्तालाप	29
राष्ट्रव्यापी मीडिया फीडबैक	दैनिक
विशिष्ट विषयों पर विश्लेषणात्मक मीडिया रिपोर्ट्स	दैनिक/साप्ताहिक
एसएमएस	मीडिया को बल्क एसएमएस
प्रेस प्रत्यायन कार्ड जारी करना	346 (1 अप्रैल, 2019 से 7 नवंबर, 2019 के दौरान)

ग. प्रधानमंत्री इकाई

प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए प्रचार और मीडिया समर्थन देने के लिए पीआईबी की यह एक समर्पित इकाई है। यह इकाई वर्षपर्यन्त कार्य करती है और माननीय राष्ट्रपति, कैबिनेट सचिवालय, नीति आयोग और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (पीएमईएसी) के भी प्रचार का दायित्व संभालती है।

यूनिट में निम्नलिखित प्रकार के कार्य संपन्न किए जाते हैं :

(क) फीडबैक

1. दैनिक इंग्लिश मीडिया रिपोर्ट और हिंदी मीडिया रिपोर्ट सुबह तैयार की जाती है। रिपोर्ट में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रेस, दोनों को शामिल किया जाता है।
2. संपादकीयों और ओप–एड्स (विशेष आलेख) के बारे में पीएमओ को दैनिक रिपोर्ट भेजी जाती है।
3. दैनिक और साप्ताहिक उर्दू फीडबैक रिपोर्ट पीएमओ को भेजी जाती है।
4. दैनिक महत्वपूर्ण अंग्रेजी समाचार/संपादकीय हिंदी में अनुवाद कर पीएमओ भेजा जाता है।
5. नीति आयोग को दैनिक फ़ीडबैक रिपोर्ट भेजी जाती है।
6. पीएमओ और प्रधान महानिदेशक, पीआईबी को साप्ताहिक मैगज़ीन रिपोर्ट भेजी जाती है।
7. प्रमुख कार्यक्रम या प्रधानमंत्री के प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के बाद मीडिया फ़ीडबैक रिपोर्ट।
8. विभिन्न मामलों/कार्यक्रमों के बारे में पीएमओ/प्रधान महानिदेशक की आवश्यकता के अनुसार राष्ट्रीय और क्षेत्रीय फ़ीडबैक रिपोर्ट्स।

(ख) आधिकारिक कम्युनिकेशन

- प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं के दौरान प्रेस विज्ञप्तियां, यह इकाई विभिन्न टाइम ज़ोन्स से पृथक वास्तविक समय में सामग्री का प्रसार करती है।
- प्रधानमंत्री के आधिकारिक भाषण (पीएमओ के परामर्श से प्रतिलेखित, पुनरीक्षित और जारी)।
- पीआईबी के ट्विटर हैंडल पर पीएम की आधिकारिक फोटोग्राफ्स का प्रकाशन।
- 'मन की बात' का मूल पाठ हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जारी करना।
- राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से जारी भाषणों सहित विज्ञप्तियां।
- कैबिनेट की प्रेस विज्ञप्तियों और कैबिनेट ब्रीफिंग के लिए मीडिया के साथ तालमेल।
- नीति आयोग के कार्यक्रमों की प्रेस विज्ञप्तियां और तस्वीरें जारी करना।

(ग) अनुवाद

23 अक्टूबर, 2019 को नई दिल्ली में मीडिया को कैबिनेट निर्णय की जानकारी देते हुए केंद्रीय कानून एवं न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन और सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर, आवास एवं शहरी मामले, नागर विमानन (स्वतंत्र प्रभार), वाणिज्य तथा औद्योगिक राज्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी। साथ में सचिव (टेलिकॉम) श्री अंशु प्रकाश और पत्र सूचना कार्यालय प्रधान के प्रधान महानिदेशक श्री के. एस. धतवालिया

- प्रधानमंत्री के भाषणों, प्रेस विज्ञप्तियों और फोटो अनुशीर्षकों का अंग्रेजी से हिंदी में और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद।
- प्रधानमंत्री के भाषणों और संदेशों को विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद कराने के लिए मानव संसाधन सहायता का प्रावधान है।
- पीआईबी के क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों के साथ समन्वय कर प्रधानमंत्री के ट्वीट, रचनाओं इत्यादि का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद।

(घ) मीडिया सुविधा

- प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों के लिए अग्रिम सुरक्षा संपर्क (एएसएल) बैठकों में भाग लेना और मीडिया उपस्थिति के बारे में फैसला करना।
- प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए मीडिया प्रवेश पास हेतु दिल्ली पुलिस, पीएम सुरक्षा के साथ संपर्क।
- राष्ट्रपति भवन के कार्यक्रमों के लिए मीडियाकर्मियों को पास बांटना।
- नीति आयोग के कार्यक्रमों के लिए मीडिया सुविधा।

अन्य गतिविधियां

- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इस वर्ष सरकार के 50 दिनों, 75 दिनों और 100 दिनों पर एक पुस्तिका जारी की। पत्र सूचना कार्यालय के प्रधानमंत्री एकक ने सरकार की उपलब्धियों और पहलों को उजागर करते हुए, इस पुस्तिका के लिए सभी जानकारियों का संकलन किया।

(ड.) सोशल मीडिया प्रकोष्ठ

सरकार से संबंधित सूचना के प्रसार के लिए नोडल एजेंसी होने के नाते पीआईबी भारतीय और वैश्विक स्तर पर निरंतर बढ़ रहे ऑनलाइन नागरिक वर्ग के साथ संपर्क और संबंध बनाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है। विशेष रूप से 35 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम और वर्डप्रेस पर पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) की प्रभावशाली सोशल मीडिया उपस्थिति को मीडिया और जनता में पत्रकारों द्वारा सकारात्मक रूप से देखा गया है।

- वीडियो और प्रेस विज्ञप्ति कई सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर साझा किए जाते हैं,
- महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया ब्रीफिंग को फेसबुक, ट्विटर और पीआईबी के यूट्यूब चैनल पर लाइव–ट्वीट और लाइव–स्ट्रीम किया जाता है, जिससे सरकार से संबंधित नए समाचार वास्तविक समय में ही प्रदान कर दिए जाते हैं।
- समाचार साझा करने के अलावा, पीआईबी सुशासन के लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए सरकार की नीतियों और कार्यों के बारे में जागरुकता फैलाने और नागरिक सहभागिता बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया अभियान चलाता है। विशेष रूप से तैयार किए गए हैशटैग का उपयोग कर।

8 नवंबर, 2019 के मेट्रिक्स का एक संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है

ट्विटर : हमारे अंग्रेजी ट्विटर हैंडल **@PIB_India** का **1.6 मिलियन से अधिक लोग अनुसरण** करते हैं। इसमें भी हर महीने 18 हजार लोगों की संख्या बढ़ी है। लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए पीआईबी नए प्रकार की सामग्री और प्रस्तुतिकरण का उपयोग कर रहा है। **ट्विटर मुवमेंट और पेरीस्कोप** पर और 15 मिलियन से अधिक लोग फ्लो करते हैं और ज्यादातर पत्रकार और मीडिया हाउस, टीवी चैनल और ऑनलाइन पेपर पूरे देश में इसका अनुसरण करते हैं।

- पीआईबी के मुख्य हैंडल **@PIBHindi को 99.5 हजार** है और इसमें हर महीने औसतन 3 हजार की वृद्धि हो रही है। इसमें कुछ विशेष केंद्र सरकार के हिंदी ट्विटर पर फोलो करते हैं।

फेसबुक : वर्तमान वर्ष में अक्टूबर 2019 तक फेसबुक पर **पत्र सूचना कार्यालय के प्रशंसकों** की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई है और इसे **02 लाख 88 हज़ार लोगों ने अपने लाइक्स** दिए हैं। ऐसा संचार और संलग्नता के रचनात्मक साधनों को अपनाने से हुआ है।

यूट्यूब : पीआईबी यूट्यूब चैनल पर **5000 वीडियो उपलब्ध हैं जिनके 699 हजार उपभोक्ता हैं** और जिन्होंने 54 मि. लोगों ने देखा है। पीआईबी, नई दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलनों और अन्य आयोजनों के अतिरिक्त दिल्ली से बाहर होने वाले आयोजनों, जैसे– पीएम लाइव, विशेष सरकारी कार्यक्रमों आदि को भी अब चैनल पर लाइव दिखाया जाता है।

(ई) **इंस्टाग्राम** : अक्टूबर 2019 के अंत तक, पीआईबी इंस्टाग्राम के **463 हज़ार से अधिक अनुयायी** थे और इस समय यह सरकार के सबसे बड़े खातों में से एक है।

सोशल मीडिया निर्देशन और समर्थन : पीआईबी भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की अपनी पहुंच होने के बावजूद उन्हें सोशल मीडिया अपनी उपस्थिति को बेहतर ढंग से स्थापित और व्यवस्थित करने में सहायता प्रदान कर रहा है।

जी) पीआईबी के भीतर इकाई पर काम चल रहा है। इस वर्ष की गई कुछ नई पहलें इस प्रकार हैं:

अ. **असत्य समाचार चेतावनी** : सरकारी योजनाओं और गतिविधियों के बारे में सोशल मीडिया असत्य और भ्रामक समाचारों के बारे में सार्वजनिक डोमेन में चेतावनी और गृह मंत्रालय के लिए एक विशेष असत्य (फर्जी) समाचार रिपोर्ट भेजी जाती है। असत्य (फर्जी) समाचार रिपोर्ट के लिए प्रस्ताव।

ब. **मिनिस्टर स्पीक्स** : मंत्रियों की ओर से पीआईबी को दिए गए विशेष बाइट्स।

स. **इन हाउस प्रोडक्शन** : विविध मंत्रालयों के विविध कार्यक्रमों के विशेष वीडियो, जी.आई.एफ. और चित्र।

द. **मेमे आधारित मतदाता जागरूकता अभियान** : चुनाव में मतदाताओं की संख्या बढाने के लिए बॉलीवुड फिल्मों के संवादों का उपयोग करके अनूठे और मनोरंजक मीम्स तैयार करना।

त. **आगामी कार्यक्रमों की जानकारी देना** : पीआईबी के आगामी कार्यक्रमों के लिए विज्ञापन।

थ. **इस वर्ष चलाए गए नए अभियान** :
#सरकार के100दिन, #यूएनसीसीडीसीओपी14, #गांधी150, #गुरुनानक550, #आईआईएसएफ2018 #आईआईएसएफ2019, #आईएफएफआई2018, #आईएफएफआई2019, #एकभारतश्रेष्ठभारत, #लोकचुनाव2019, #इटमैटर्समीम्सअभियान, #कुंभमेलाअभियान, #आईएनएसपीआईआरईआईपुरस्कार, #एमएएनएकेअभियान।

न. मीडिया आउटरीच कार्यक्रम और विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रचार

मीडिया आउटरीच कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और जिला स्तरों पर मीडिया संपर्क सत्रों के आयोजन के द्वारा सरकार की प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों के बारे में सूचना का प्रसार करना है। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों की सफलता दर्शाने के लिए प्रेस दौरो का भी आयोजन किया जाता है।

सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में जमीनी स्तर पर जागरूकता पैदा करने के लिए क्षेत्रीय/स्थानीय स्तरों पर वार्तालाप (ग्रामीण मीडिया के लिए कार्यशालाएं) आयोजित किए जाते हैं।

प. चुनावों के दौरान सूचना का प्रसार

पीआईबी भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) तथा मीडिया के बीच सेतु का काम करता है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद पीआईबी पिछले लोकसभा आम चुनावों तथा विधानसभा चुनावों की सूचना उपलब्ध कराने के लिए 'आम चुनावों के लिए संदर्भ पुस्तिका' तथा विधानसभा चुनावों पर पुस्तिकाएं जारी करता है। इसके अतिरिक्त चुनावों से पहले नियमित रूप से संदर्भों और तथ्यों के माध्यम से

20 सितंबर, 2019 को आइजोल में पीआईबी आइजोल द्वारा आयोजित मीडिया कार्यशाला

मीडिया को सूचना उपलब्ध कराई जाती है। लोकसभा के आम चुनावों तथा विभिन्न राज्य विधानसभाओं के चुनावों के दौरान, मतदान और मतगणना प्रक्रिया की कवरेज में सहायता के लिए नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय मीडिया के प्रतिनिधियों को पीआईबी भारत निर्वाचन आयोग की ओर से अधिकृत पत्र जारी करता है। तथा मतदान के गिनती वाले दिन अपनी विशेष वेबसाइट द्वारा रूझानों/परिणामों की वस्तुस्थिति का भी प्रसार एन.आई.सी एवं भारत निवार्चन आयोग द्वारा प्राप्त काउंटिंग डाटा के अनुसार करता है।

5. फीडबैक प्रकोष्ठ

पत्र सूचना कार्यालय के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक कार्य सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में मीडिया में प्रदर्शित लोगों की धारणाओं से सरकार को अवगत कराना है। इस बारे में देश की राजधानी से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी एवं हिंदी के समाचारों से, पीआईबी के स्थानीय/शाखा कार्यालयों से स्थानीय भाषा के समाचार–पत्रों से प्राप्त होने वाले व टीवी समाचार चैनलों, वेब मीडिया एवं पत्रिकाओं से इनपुट प्राप्त किए जाते हैं। पीआईबी अधिकारी इस फीडबैक को अपने संबंधित मंत्रालयों एवं विभागों को भेजते हैं।

विशेष सेवाओं के भाग के रूप में पीआईबी का फीडबैक प्रकोष्ठ मंत्रालयों के उपयोग के लिए राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय समाचार–पत्रों और पत्रिकाओं के आधार पर दैनिक सार–संक्षेप और विशेष सार–संक्षेप तैयार करता है। **1 अप्रैल से 5 नवंबर, 2019 तक, प्रधानमंत्री कार्यालय और विभिन्न मंत्रालयों के मीडिया प्रबंधन अधिकारियों को लगभग 151 डाइजेस्ट और 30 से अधिक विशेष डाइजेस्ट और लगभग 2140 एसएमएस अलर्ट/मेल भेजे गए। 1 अप्रैल से 5 नवंबर, 2019 तक, लगभग 151 डाइजेस्ट और 30 से अधिक विशेष डाइजेस्ट थे।**

मान्यता प्रणाली

पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली के मुख्यालय में विदेशी मीडिया के सदस्यों सहित मीडिया प्रतिनिधियों को प्रेस मान्यता प्रदान की जाती है। प्रेस मान्यता का एक ऑनलाइन सिस्टम वर्ष 2010 में शुरू किया गया था जिसे मान्यता के लिए अनुरोध की बढ़ती संख्या के साथ बनाए रखने के लिए लगातार अद्यतन किया जाता है। **दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रहने वाले पत्रकारों के लिए 01/04/2019 से अब तक लगभग 354 मान्यता कार्ड जारी किए गए थे।**

6. पत्रकार कल्याण योजना (जेडब्ल्यूएस)

पीआईबी 'पत्रकार कल्याण कोष' योजना का कार्यान्वयन करता आया है। संशोधित योजना में कठिनाइयों का सामना करने वाले पत्रकारों तथा उनके परिवारों को अविलंब अनुग्रह राहत उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के तहत पत्रकार के लिए पांच लाख रुपये तक की राशि स्वीकृत की जा सकती है। पत्रकार की मृत्यु के कारण परिवार को होने वाली परेशानी और पत्रकार की स्थायी अपंगता को देखते हुए उसके परिवार को राहत दी जा सकती है। कैंसर, गुर्दा रोग, हृदय रोग तथा ब्रेन हेमरेज आदि गंभीर बीमारियों में होने वाले खर्च में सहायता दी जाती है। दुर्घटना से गंभीर चोट तथा अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में भी वित्तीय सहायता दी जाती है। **वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए आज तक इस योजना के अंतर्गत 90,25,447 रुपये की राशि का वितरण किया गया है।**

भारत का अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह

पत्र सूचना कार्यालय, इफ्फी की उस टीम का हिस्सा था जिसने गोवा में आयोजित 49वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म्स फेस्टिवल ऑफ इंडिया (इफ्फी) –2018 के स्थल पर मीडिया सेंटर में मीडिया मान्यता, सुविधा और प्रेस कॉन्फ्रेंस का कामकाज देखा। **इफ्फी 2018 में समाचार संकलन के लिए कुल 508 मीडिया व्यक्तियों को मान्यता दी गई थी।** इफ्फी के 50वें संस्करण की कवरेज के लिए मीडिया सुविधा की व्यवस्थाकी गई। **212 मीडिया व्यक्तियों को इफ्फी 2019 की कवरेज के लिए मान्यता दी गई।**

7. आपात स्थितियों में नियंत्रण कक्ष

किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पीआईबी में एक न्यूज़ रूम/नियंत्रण कक्ष 365 दिन कार्य करता है। अल्प अवधि में संवाददाता सम्मेलन आयोजित करना और साथ–साथ पूरे देश में पीआईबी केंद्रों के माध्यम से वेबकास्ट की पूरी तैयारी रखी जाती है, ताकि रात्रि 9.00 बजे के बाद अप्रत्याशित स्थिति से निपटा जा सके। आपात और संकट के समय नियंत्रण कक्ष 24X7 आधार पर काम करता है। महत्वपूर्ण समाचार चैनलों की मॉनिटरिंग की जाती है और वरिष्ठ अधिकारियों को ताज़ा घटनाओं की जानकारी देने तथा तथ्य संबंधी गलतियों के बारे में सूचित किया जाता है, ताकि मीडिया में सही समय पर हस्तक्षेप किया जा सके।

8. 2019–20 के दौरान की गई पहल

इस अवधि के दौरान पीआईबी द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए :

क) सरकार की विभिन्न पहल और उपलब्धियों पर इंफोग्राफिक्स विकसित किए गए हैं, जो संक्षिप्त और आकर्षक तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करते हैं। इन इंफोग्राफिक्स के लिए प्रतिक्रिया उत्साहजनक रही है, जो सामान्य व्याख्यान वाली विषयवस्तु के साथ जनता के औसत जुड़ाव की तुलना में इस विषयवस्तु के प्रति जनता की उच्च संबद्ध ता की दर से स्पष्ट हो जाता है।

ख) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के संचार प्रभारी पीआईबी अधिकारियों ने आधिकारिक पीआईबी– अधिकृत ट्विटर हैंडल्स का उपयोग करते हुए आधिकारिक नवीनतम जानकारी साझा करना शुरू कर दिया है।

ग) पीआईबी मुख्यालय में आयोजित सभी प्रेस सम्मेलनों का अब फेसबुक, ट्विटर और पीआईबी के यूट्यूब चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है।

घ) पीआईबी ने मई 2019 में गूगल के साथ विशेष कार्यशाला गलत सूचना और सही जांच आयोजन किया, जिससे हमारे अधिकारी बेहतर तरीके से इंटरनेट का लाभ उठा सकें और गलत सूचनाओं को दूर कर सकें।

ट) राष्ट्रीय मीडिया सेन्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम पूरी तरह से पुनर्निर्मित और यू.पी.एस बैकअप से सुविधा सम्पन्न है।

पीआईबी ने इस अवधि के दौरान निम्नलिखित नई पहल की:

9. कार्यालय का स्वचालन या ऑटोमेशन

पीआईबी ने कार्यालय के स्वचालन या ऑटोमेशन के लिए अनेक उपाय किए हैं, जैसे :

कार्यालय स्वचालन

पीआईबी ने कार्यालय स्वचालन के लिए कई उपाय किए हैं :

1. गलत सूचनाओं, फर्जी खबरों से निपटने और सोशल मीडिया पर चल रहे समाचारों की तथ्य जांच करने के लिए कार्यालय के भीतर एक भ्रामक सूचना रोधी एकक (काउंटर–मिसइनफॉर्मेशन यूनिट– सीएमयू) की स्थापना करने के लिए पहल
2. राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान द्वारा पत्र सूचना कार्यालय के लिए दृश्य पहचान (लोगो) और टैगलाइन के डिजाइन के लिए प्रयास
3. भारत सरकार द्वारा जारी सभी प्रेस विज्ञप्तियों, विशेष लेखों और पृष्ठभूमि सूचनाओं को डिजिटल कर दिया गया है और यह सभी पीआईबी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
4. जीईएम पोर्टल के माध्यम से वस्तु/सेवा की खरीद।
5. पीआईबी अपने मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में सूचना प्रौद्योगिकी कार्यों के लिए बेसिल के माध्यम से उपयुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति करता है।
6. बेसिल के माध्यम से ही पीआईबी अपने मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में सोशल मीडिया पर ग्राफिक्स और विश्लेषण के लिए आउटसोर्सिंग करता है।
7. पत्रकारों के लिए ऐप एनरॉयड और आईओएस पर पीआईबी की बहुभाषी वेबसाइट और इसके ऐप को सफलतापूर्वक चलाना।
8. मुख्यालय और क्षेत्रीय/क्षेत्रीय कार्यालयों में उपकरणों का निरंतर उन्नयन।

10. पीआईबी की 2019–20 की प्रमुख गतिविधियां

क) एक भारत श्रेष्ठ भारत

- एक जोड़े में रखे गए राज्यों में क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रत्येक लेख का आदान–प्रदान किया गया और उसे संबंधित क्षेत्र के समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया। जैसे– महाराष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत के बारे में पत्र सूचना कार्यालय, मुंबई द्वारा लिखा गया लेख पत्र सूचना कार्यालय, भुवनेश्वर को भेजा गया था जिसका अनुवाद ओडिया में किया गया था और इसे ओडिशा के समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था। ईबीएसबी पर मुख्यालय के अधिकारियों से प्राप्त सूचनाओं को भी क्षेत्रीय कार्यालयों में भेजा गया था।
- पीआईबी के सोशल मीडिया सेल ने ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर चित्र और वीडियो पोस्ट करके आयोजित कार्यक्रमों को व्यापक दृश्यता प्रदान की है। अंग्रेजी में 33 ट्वीट्स के 11 लाख 80 हजार अनुसरण हुए हैं। इस बीच 20 हिंदी ट्वीट्स को लगभग सत्तर हज़ार दृश्यता प्राप्त हुई। फेसबुक पर कुल पोस्ट 80 थे जिन्हें अब तक 162573 बार देखा गया है। यूट्यूब पर दो लाइव वीडियो को 15395 बार देखा गया। इंस्टाग्राम पर पोस्ट को करीब 2 लाख व्यूज मिल चुके हैं।

ख. राष्ट्रीय एकता दिवस

मुख्य कार्यक्रम सरदार सरोवर नर्मदा बांध परियोजना स्थल पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुआ। सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर, 2019 को **'राष्ट्रीय एकता दिवस'** के रूप में मनाई गई। पीआईबी ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर देशभर में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के लिए इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर व्यापक प्रचार किया। गुणवत्ता पूर्ण प्रचार प्रभाव के लिए पीआईबी ने लोक संपर्क ब्यूरो, आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित अन्य मीडिया इकाइयों के साथ भी समन्वय किया।

ग. योग का 5वां अंतरराष्ट्रीय दिवस

21 जून, 2019 को रांची में आयोजित 5वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के लिए राष्ट्रव्यापी प्रचार का आयोजन किया गया था। इस समारोह में पृष्ठभूमि की ब्रीफिंग, टीज़र वीडियो, योग पर बुकलेट आदि के माध्यम से इस कार्यक्रम के लिए व्यापक प्रचार किया गया और इसे पीआईबी की वेबसाइट पर जारी किया गया। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से मुख्यालय और क्षेत्रीय स्तर पर प्रमुख कार्यक्रमों के लिए व्यापक प्रचार प्रदान किया गया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सामूहिक योग प्रदर्शन में योगाभ्यास करते हुए। यह कार्यक्रम पांचवें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2019 के अवसर पर रांची, झारखंड में 21 जून 2019 को आयोजित हुआ

घ) स्वच्छता ही सेवा अभियान

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने 11 सितंबर, 2019 को 'स्वच्छता ही सेवा 'अभियान शुरू किया था, जिसके दौरान पूरे देश को चरणबद्ध रूप में एकल उपयोग प्लास्टिक से मुक्ति के लिए एकजुट किया गया। पीआईबी ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों में 'स्वच्छता ही सेवा' से संबंधित गतिविधियों को व्यापक प्रचार प्रदान किया था।

ड.) आर्थिक सर्वेक्षण और केंद्रीय बजट 2019–20

केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा 5 जुलाई, 2019 को पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण और केंद्रीय बजट 2019–20 के लिए व्यापक प्रचार की व्यवस्था की गई थी। जैसे ही बजट भाषण समाप्त हुआ, पीआईबी टीम द्वारा तैयार सभी प्रेस विज्ञप्ति और इन्फोग्राफिक्स तुरंत पीआईबी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए। देश भर में मीडिया विशेष रूप से क्षेत्रीय मीडिया की सुविधा के लिए बजट भाषण और संबंधित दस्तावेजों को पीआईबी वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया था। ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का उपयोग करके इन्फोग्राफिक्स, प्रेस रिलीज़ और विश्लेषण भी प्रसारित किए गए थे।

च) चंद्रयान–2 प्रक्षेपण

22 जुलाई, 2019 को श्रीहरिकोटा से चंद्रयान –2 के प्रक्षेपण के लिए व्यापक प्रचार किया गया। भारत के जीएसएलवी

एम के III–एम I ने पृथ्वी की कक्षा में 3840 किलोग्राम चन्द्रयान –2 अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। भारतीय, अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया के लिए मीडिया पंजीकरण पीआएबी चेन्नई के सहयोग से किया गया था। सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को पीआईबी (समन्वय इकाई) मुख्यालय द्वारा उनके संबंधित केंद्रों से लॉन्च के लिए नामांकन भेजने के लिए कहा गया था।

छ) अनुच्छेद 370 का निरस्तीकरण

धारा 370 को निरस्त करने पर प्रेस विज्ञप्ति व्यापक रूप से प्रसारित की गई। इस मुद्दे पर क्षेत्रीय प्रेस क्या कह रहा था, इसकी जानकारी एकत्र करने के लिए एक **व्यापक प्रतिक्रिया प्रणाली** रखी गई थी। पीआईबी के सभी **क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों** ने अखबारों को स्कैन किया, और कहानियों के सार को समेटा और रोजाना सुबह 6:30 बजे तक मुख्यालय को प्रतिक्रिया भेजी और **राष्ट्रव्यापी मीडिया फीडबैक को हर दिन सुबह 7 बजे तक** संकलित किया गया। इस रिपोर्ट को स्थिति की निगरानी के लिए महत्वपूर्ण इनपुट के रूप में मंत्रालय को भेजा गया था। महत्वपूर्ण समाचारों पर गौर करते हुए दिनभर रिपोर्ट को और अपडेट किया गया।

ज) 73वां स्वतंत्रता दिवस

पीएम के भाषण का **क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया गया** और इसे पीआईबी के क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों के माध्यम से **व्यापक रूप से जारी** किया गया था। विशेष ग्राफिक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बनाए और अपलोड किए गए थे। **80 ट्वीट को 1.4 मिलीयन इंप्रेशन** मिले। पूर्व प्रचार के लिए प्रोमो वीडियो के अलावा सोशल मीडिया पर उत्सव का सीधा प्रसारण किया गया, प्रधानमंत्री के भाषण की तस्वीरों और वीडियो बाइट्स के **सीधे ट्वीट के साथ–साथ**।

i) फिट इंडिया आंदोलन की शुरुआत

प्रधानमंत्री ने 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया आंदोलन की शुरुआत की। पीआईबी ने व्यापक कवरेज के लिए क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों के साथ समन्वय किया। प्रेस विज्ञप्ति और तस्वीरें जारी की गईं। कार्यक्रम को इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल प्रचार के साथ–साथ प्रिंट मीडिया में उत्कृष्ट कवरेज मिली। 22 ट्वीट किए गए, जिन्हें 808 हजार इंप्रेशन मिले। पहले से प्रचार के लिए प्रोमो वीडियो के अलावा पीआईबी सोशल मीडिया पर कार्यक्रम की शुरुआत का सीधा प्रसारण किया गया, प्रधानमंत्री और खेल मंत्री किरेन रिजिजू की फोटो और वीडियो बाइट्स के लाइव ट्वीट।

11. योजना प्रदर्शन 2019–20

वर्ष 2019–20 के दौरान, पीआईबी का संबंध दो केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं के साथ है:

(क) संचार और सूचना प्रसार का विकास और

(ख) मीडिया अवसंरचना विकास कार्यक्रम (एमआईडीपी)

क. संचार और सूचना प्रसार का विकास (डीसीआईडी) मीडिया संपर्क कार्यक्रम और विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रचार।

मीडिया संपर्क कार्यक्रम और विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रचार मंत्रालय की अम्बरेला योजना डीसीआईडी के तहत एक उप–योजना है। योजना में निम्नलिखित घटक हैं:

क) मीडिया परस्पर विचार–विमर्श सत्र (राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संपादक सम्मेलन और वार्तालाप)

ख) प्रेस दौरा

ग) प्रधानमंत्री के भाषण/संदेश के अनुवाद के लिए उपयुक्त अनुवादकों का प्रबंध/प्रशासनिक सहयोग

घ) विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रचार (आईएफएफआई/

23–24 अगस्त, 2019 को गुवाहाटी में आयोजित पूर्वोत्तर एवं कोलकाता, क्षेत्र का क्षेत्रीय सम्मेलन

पीबीडीएस)

i) पत्र सूचना कार्यालय 'मीडिया परस्पर विचार–विमर्श सत्रों' के अंतर्गत देश भर के समाचार पत्र संपादकों/पत्रकारों को आमंत्रण देकर राष्ट्रीय (सामाजिक/आर्थिक) संपादकों के सम्मेलन आयोजित करता है। इन पर औसत व्यय लगभग 30 लाख रुपये आता है। जबकि क्षेत्रीय संपादकों के सम्मेलनों में, एक विशेष क्षेत्र के पत्रकारों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। क्षेत्रीय सम्मेलन के लिए औसत खर्च लगभग 15 लाख रुपये है। इस वर्ष, तीन

क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित करने का लक्ष्य पूरा किया गया है।

ii) सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए ग्रामीण पृष्ठभूमि और छोटे शहरों के पत्रकारों के साथ वार्तालाप नामक मीडिया कॉन्क्लेव का आयोजन जिला स्तर पर किया जाता है। इसलिए ग्रामीण मीडिया का उपयोग सरकारी कार्यक्रमों के बारे में ग्रामीण आबादी के अंतिम छोर तक पहुंचने में एक प्रभावी तत्व के रूप में किया जाता है। प्रत्येक वार्तालाप के लिए औसत व्यय लगभग 1.5 लाख रुपये है। इस वर्ष 31 अक्टूबर तक निर्धारित लक्ष्य 60 में से 29 वार्तालाप कराये जा चुके हैं। तीन सम्मेलनों का लक्ष्य इस वर्ष पूरा कर लिया गया है।

iii) एक राज्य से दूसरे राज्य में पत्रकारों को केंद्र सरकार की योजनाओं की सफलता के बारे में जानकारी के लिए प्रेस दौरे आयोजित किए जाते हैं। ऐसी प्रत्येक यात्रा पर औसत व्यय 6 से 7 लाख रुपये के आस–पास है। इस वर्ष 31 अक्टूबर तक निर्धारित 6 प्रेस यात्राओं में से एक प्रेस यात्रा की जा चुकी है।

वर्तमान वर्ष के लिए आवंटित 530.00 लाख रुपये के निधि आवंटन में से अक्टूबर, 2019 तक इस प्रयोजन के 162.89 लाख व्यय किए जा चुके हैं।

(ख) मीडिया अवसंरचना विकास कार्यक्रम (एमआईडीपी)

पत्र सूचना कार्यालय की केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत **मीडिया अवसंरचना विकास कार्यक्रम (एमआईडीपी)** में निम्नलिखित उप–योजनाएं हैं:

- पीआईबी का आधुनिकीकरण
- स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी)

वर्ष 2019–20 के दौरान, इस योजना को लागू करने के लिए 5.50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इनका मद वार विवरण इस प्रकार है: –

पीआईबी का आधुनिकीकरण रु. 4.30 करोड़

स्वच्छ कार्य योजना (एसएपी) रु. 1.20 करोड़

कुल रु. 5.50 करोड़

4. इस योजना का उद्देश्य पीआईबी में संचार और सूचना प्रसार प्रणाली का आधुनिकीकरण और उन्नयन करना है ताकि निम्नलिखित गतिविधियों के लिए मुख्यालय और इसके क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों दोनों में पीआईबी की दक्षता का पूरी तरह से उपयोग किया जा सके।

- सभी अधिकारियों के लिए आईटी अवसंरचना और संचार के आधुनिक साधन।
- उपभोग्य सामग्रियों की खरीद
- वार्षिक रख रखाव शुल्क
- रंगीन बहुआयामी डिजिटल कार्यालय मशीनों की खरीद
- हार्डवेयर और अन्य उपकरणों की खरीद
- इंटरनेट डोंगल कनेक्शन के लिए भुगतान
- लैन नेटवर्किंग, आदि।
- प्रतिक्रिया और प्रभाव विश्लेषण; दैनिक रिपोर्ट
- सभी कार्यालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान करना
- पीआईबी के शाखा कार्यालयों में लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा प्रदान करना
- पीआईबी कार्यालयों में सोशल मीडिया प्लेटफार्मों की स्थापना और जनशक्ति प्रदान करना

स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) के तहत निम्नलिखित गतिविधियां शामिल हैं:

1. अवसंरचना विकास
2. ऑफिस रूम, कॉरिडोर का सौंदर्यीकरण
3. आधुनिक सुविधाओं के साथ शौचालयों का नवीनीकरण
4. पीआईबी कार्यालयों में पुराने एयर कंडीशनरों (7 वर्ष से अधिक पुराने) को बदलना।
5. सितंबर, 2019 तक पत्र सूचना कार्यालय का आधुनिकीकरण उप–योजना के अंतर्गत 1.9977 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है। उप–योजना के तहत स्वच्छता कार्य योजना पर 30–09–2019 तक 11.06 लाख रुपये का उपयोग किया गया है।
6. 2019–20 के लिए संशोधित अनुमान स्तर पर, अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी गतिविधियों के लिए उपयुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति और उन्हें बाहर से बुलाने के लिए पत्र सूचना कार्यालय के मुख्यालय में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के

लिए 'पत्र सूचना कार्यालय के आधुनिकीकरण मद' के अंतर्गत 1 करोड़ रुपए की राशि का अनुमान लगाया गया है। साथ ही गलत सूचनाओं, फर्जी खबरों से निपटने और सोशल मीडिया पर कहानियों की तथ्य जांच करने के लिए पीआईबी मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के भीतर एक फर्जी सूचना रोधी एकक (सीएमयू) का गठन करने एवं क्षेत्रीय कार्यालय घटक 'स्वच्छता कार्य योजना' के लिए 2019–20 के संशोधित अनुमान 1 करोड़ 20 लाख रुपये की आवश्यकता को 2019–20 के संशोधित अनुमान के स्तर पर बनाए रखने का प्रस्ताव दिया गया है।

2019–20 के बजट की विशेषताएं

I	1.	बजट अनुमान–2019–2020 (श्रेणी–I स्थापना व्यय।)	रु. 8932.00 लाख
	2.	संशोधित अनुमान 2019–2020 (श्रेणी– I स्थापना व्यय।)	रु. 9374.50
II	1.	बजट अनुमान 2019–2020 (केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं)	रु. 1080.00 लाख
	2.	संशोधित अनुमान 2019–2020 (केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं)	रु. 1192.00 लाख
वास्तविक व्यय			
III	1.	श्रेणी– I स्थापना व्यय	रु. 4589.82 लाख (सितंबर, 2019 तक)
	2.	केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं	रु. 342.63 लाख (सितंबर, 2019 तक)

पत्र सूचना कार्यालय मुख्यालय में आधिकारिक भाषा हिंदी का प्रगतिशील उपयोग

राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा अधिनियम, 1963 (1967 में संशोधित)और राजभाषा नियम, 1976 (1987 में संशोधित) के तहत वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों सहित विभिन्न आदेशों और निर्देशों के पालन के लिए पत्र सूचना कार्यालय, मुख्यालय में आधिकारिक भाषा हिंदी के प्रगतिशील उपयोग के लिए सभी संभव प्रयास किए जाते हैं।

प्रधान महानिदेशक (मीडिया और संचार) की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन पत्र सूचना कार्यालय, मुख्यालय में किया गया है जो अपनी तिमाही बैठकों के माध्यम से ब्यूरो कार्यालय में संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की स्थिति की निगरानी करता है। पीआईबी की वेबसाइट द्विभाषी (हिंदी और अंग्रेजी में) है।

हिंदी पखवाड़ा 01–15 सितंबर, 2019 की अवधि में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। पखवाड़ा के दौरान हिंदी निबंध लेखन, अनुवाद, नोटिंग और आलेखन, सामान्य हिंदी ज्ञान, हिंदी टाइपिंग, हिंदी एक्स्टेम्परे भाषण और एमटीएस के लिए हिंदी श्रुतलेख प्रतियोगिता आयोजित किए गए। मुख्यालय के अधिकारियों/अधिकारियों ने इन प्रतियोगिताओं में सक्रिय रूप से भाग लिया और विभिन्न पुरस्कार जीते। ब्यूरो में आयोजित एक पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान, प्रधान महानिदेशक (मीडिया और संचार) ने हिंदी पखवाड़ा प्रतियोगिताओं के विजेताओं को प्रमाणपत्र प्रदान किए और उन्हें अपने सभी आधिकारिक काम हिंदी में जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया।

सतर्कता अनुभाग

वर्ष 2019–20 के लिए पीआईबी के सतर्कता अनुभाग के संबंध में अद्यतन जानकारी निम्नानुसार है:

क) सीएटी (केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण) के निर्णयों/आदेशों का कार्यान्वयन

क्र. सं.	मीडिया एकक/अनुभाग	वर्ष 2019–20 के लिए सीएटी से प्राप्त आदेश की संख्या	2019–20 के दौरान लागू किए गए निर्णयों/आदेशों की संख्या
1	2	3	4
1	पीआईबी (सतर्कता अनुभाग)	शून्य	शून्य

II) शिकायत निवारण तंत्र

एस.एन. चौधरी, निदेशक (मीडिया और संचार), पीआईबी को विभागीय/लोक शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में नामित किया गया है और उसी के संबंध में प्राप्त सभी आवेदन समयबद्ध तरीके से निपटाए गए हैं।

iii) महिला कल्याण गतिविधियां

केंद्रीय लोक सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम 3–सी कार्यस्थलों पर उत्पीड़न के अंतर्गत आंतरिक शिकायत समिति

का पुनर्गठन पत्र सूचना कार्यालय मुख्यालय/क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों में किया गया है, जो यौन संबंध से संबंधित माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों और मानदंडों के अनुसार महिला स्टाफ सदस्यों की शिकायतों के निवारण के लिए है। हाल ही में, पत्र सूचना कार्यालय मुख्यालय में आतंरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन किया गया है। समिति की संरचना इस प्रकार है:

क्रम संख्या	नाम	पद	दूरभाष
1	सुश्री श्रुति पाटिल, निदेशक	अध्यक्ष	दूरभाष : 23388517/23488364
2	सुश्री पुनीथा एस., उप निदेशक	सदस्य सचिव	दूरभाष : 23386977/23488050
3.	श्री हिमांक कोठियाल, सहायक निदेशक	पुरुष सदस्य	23488122
4	सुश्री मधु बाला, अनुभाग अधिकारी	सदस्य	दूरभाष : 23385388
5	सुश्री सोनाली दत्ता, अनुभाग अधिकारी	सदस्य	दूरभाष : 23381137
6	सुश्री सुहासिनी धर्मार्हा, मनोचिकित्सक	बाहरी सदस्य	मोबाइल नंबर : 91–8826177144

सतर्कता प्रकोष्ठ

(1) संगठन के लिए मुख्यालयों और शाखा कार्यालयों में स्थापित सतर्कता अनुभागों का विवरण:

पीआईबी का सतर्कता ढांचा प्रधान महानिदेशक (मीडिया एवं संचार) की समग्र निगरानी में कार्य कर रहा है, जिन्हें सतर्कता अधिकारी (एडीजी/निदेशक के स्तर पर), उपनिदेशक (सतर्कता), और अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों की सहायता प्राप्त है। सतर्कता मामलों के संबंध में प्राधिकार और उत्तरदायित्व क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रमुख को भी सौंपे गए हैं। ब्यूरो के क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों के संबंध में सतर्कता के मामलों से निपटने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों में एक प्रशासनिक अधिकारी का पद है, जो ऐसे मामलों से निपटने में क्षेत्रीय प्रमुखों को सहायता देता है। क्षेत्रीय कार्यालयों को समय–समय पर मार्गदर्शन और निर्देश प्रदान किए जाते हैं।

(2) इस समयावधि में की गई निवारक सतर्कता गतिविधियां

i)	इस अवधि के दौरान किए गए सामान्य निरीक्षणों एवं औचक निरीक्षणों की संख्या–	शून्य

(3) इस अवधि में की गई निगरानी एवं पता लगाने संबंधी गतिविधियां:

1) **निगरानी के लिए चुने गए क्षेत्रों का विवरण :**

ब्यूरो के ऐसे अनुभाग अर्थात सामान्य, प्रेस संपर्क अनुभाग, एनएमसी प्रकोष्ठ और स्वचालन अनुभाग सतर्कता के लिए निर्धारित हैं। इन अनुभागों में कार्य कर रहे कर्मचारियों को संवेदनशील समझा जाता है। इन अनुभागों में कार्य कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों का नियमित आवर्तन किया जाता है।

i)	निगरानी में रखने के लिए चिन्हित किए गए व्यक्तियों की संख्या–	शून्य

(4) दंडात्मक गतिविधियां [4(1) से (x) के विपरीत (संख्या इंगित की जाएगी, जहां नियोक्ता प्राधिकारी राष्ट्रपति के अलावा कोई अन्य है) :

i)	इस अवधि के दौरान प्राप्त शिकायतें/संदर्भ–	08
ii)	कितने मामलों में शुरुआती जांच की गई–	शून्य
iii)	कितने मामलों में शुरुआती जांच की रिपोर्ट प्राप्त हुई –	शून्य
iv)	कितने मामलों में बड़े जुर्माने के लिए आरोप पत्र जारी किए गए–	शून्य
v)	कितने मामलों में छोटे जुर्माने के लिए आरोप पत्र जारी किए गए–	शून्य
vi)	कितने लोगों पर बड़ा जुर्माना लगाया गया–	शून्य
vii)	कितने लोगों पर छोटा जुर्माना लगाया गया–	शून्य
viii)	कितने लोगों को निलंबित किया गया–	शून्य
ix)	कितने लोगों के खिलाफ़ प्रशासनिक कार्रवाई, मसलन – चेतावनी आदि जारी की गई–	शून्य
x)	नियम के उपयुक्त प्रावधानों के तहत कितने लोगों को समय से पहले सेवानिवृत्त किया गया–	शून्य

इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि पहले प्राप्त की गई तीन शिकायतों के संबंध में की जा रही विभागीय जांच अभी जारी है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित मामले

पीआईबी का प्रशा.–1 अनुभाग पीआईबी (मुख्यालय) में आरटीआई से संबंधित मामलों के लिए नोडल अनुभाग नामित किया गया है। डीओपी एंड टी की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, सीपीआईओ और अपीली(प) प्राधिकरण को नागरिकों द्वारा आरटीआई अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने के लिए नामित किया गया है।

पीआईबी (मुख्यालय) सार्वजनिक प्राधिकरण के पास उपलब्ध जानकारी को स्व–प्रेरणा से उद्घाटित करने और उसे अपनी वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र में अपलोड करने से संबंधित धारा–4 (बी)(1)और 4(2) के तहत अपने दायित्व पहले ही पूरे कर चुका है। प्राप्त किए गए, खारिज और हस्तांतरित किए गए आवेदनों/अपीलों के आंकड़े दर्शाने वाली तिमाही रिपोर्ट को सीआईसी की वेबसाइट पर नियमित रूप से आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर अपलोड किया जाता है।

हिंदी तथा उर्दू यूनिट की गतिविधियां

हिंदी तथा उर्दू इकाइयों की मुख्य गतिविधियों में हिंदी/उर्दू दैनिकों के मुख्य समाचारों और संपादकीयां का अंग्रेजी अनुवाद करने सहित दैनिक प्रेस राउंडअप तैयार करना, प्रेस विज्ञप्तियों, फ़ीचरों, संदर्भों, राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री के भाषणों का हिंदी तथा उर्दू में अनुवाद करना, नियमावलियों और पुस्तिकाओं का अनुवाद एवं पुनरीक्षण करना शामिल है। हिंदी और उर्दू यूनिट द्वारा 1 अप्रैल, 2019 से 5 नवंबर, 2019 तक 8532 प्रेस विज्ञप्तियां और संदर्भ हिंदी और उर्दू में जारी किए गए।

फोटो प्रभाग

I. प्रस्तावना

फोटो प्रभाग का दायित्व भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय के विभिन्न आयोजनों की फोटो कवरेज के माध्यम से प्रचार कार्य में सहायता करना है। अक्टूबर 1959 में स्थापित, यह शायद देश का एकमात्र ऐसा संगठन है, जिसके पास डिजिटल प्रारूप में संरक्षित 10 लाख से अधिक निगेटिव्स/पारदर्शियों का ऐसा समृद्ध भंडार है, जो स्वतंत्रता–पूर्व युग से लेकर आज तक का है। इस प्रकार फोटो प्रभाग अभी भी 'अत्यधिक' ऐतिहासिक महत्त्व के छाया चित्रों (तस्वीरों) के निर्माण और भंडारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

फोटो प्रभाग हर वर्ष लगभग 4500–5000 समाचारों और विशेष रूपकों की कवरेज करता है। इसकी तस्वीरें अनुमोदित दरों पर आम जनता को बिक्री के लिए भी उपलब्ध कराई जाती हैं।

वर्ष 2010 में अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर डिवीजन ने राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कारों की शुरुआत की। पिछले कई वर्षों से दिए जा रहे इन वार्षिक पुरस्कारों ने देश भर के शौकिया और पेशेवर फोटोग्राफरों के माध्यम से फोटोग्राफी की कला को बढ़ावा देने और दृश्य प्रलेखन द्वारा विभिन्न पहलुओं जैसे कला, संस्कृति, विरासत, लोगों के जीवन, समाज, परंपराओं आदि के संरक्षण के दोहरे उद्देश्यों को पूरा किया है।

II. फोटो प्रभाग के कार्य

फोटो प्रभाग का मुख्य कार्य छायाचित्रों के माध्यम से देश की सामाजिक–आर्थिक और राजनीतिक उपलब्धियों का प्रलेखन करना और इन चित्रों को प्रचार के लिए जारी करने के साथ ही इनका भविष्य हेतु संग्रह करना है। इसके विशिष्ट कार्य इस प्रकार हैं :

1. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रचार–प्रसार के लिए अपने छाया चित्रों को मीडिया के लिए भेजता है।

क) पत्र सूचना कार्यालय के प्रचार कार्य को फोटो प्रभाग से सहायता मिलती है।

ख) लोकसंपर्क और संचार ब्यूरो की प्रदर्शनी शाखा की बड़े आकार के फोटो और अन्य फोटो सम्बन्धी आवश्यकताएं फोटो प्रभाग द्वारा पूरी की जाती हैं।

2. प्रधानमंत्री को विशेष कवरेज (365 दिन और 24X7) दी जाती है। प्रधानमंत्री के घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों के बड़े पैमाने पर फोटो शूट किए जाते हैं। इसके बाद, विशेष एल्बम जिनमें प्रधानमंत्री के दौरे की तस्वीरें होती हैं, तैयार की जाती हैं।

3. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोक सभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्रियों और अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक आयोजनों के लिए फोटो कवरेज प्रदान करना और उनका दस्तावेजीकरण करना।

4. विदेशी राष्ट्राध्यक्षों/सरकारों के अति विशिष्ट व्यक्तियों की भारत यात्रा के समय उनकी व्यापक कवरेज के उद्देश्य से विदेश मंत्रालय के विदेश प्रचार विभाग को सहायता प्रदान करता है। प्रभाग आने वाले गणमान्य व्यक्तियों की तस्वीरों वाला एक विशेष एल्बम उन्हें भेंट करता है।

5. उत्तरपूर्व के राज्यों में फोटोग्राफिक रूप से विकासात्मक गतिविधियों का दस्तावेजीकरण करके वहां के लिए विशेष अभियान शुरू करता है।

6. मूल्य निर्धारण योजना के अनुसार गैर–प्रचार संगठनों, निजी प्रकाशकों और आम जनता को भुगतान के आधार पर तस्वीरें प्रदान करता है।

III. संगठनात्मक विवरण

फोटो प्रभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में स्थित है। यह प्रभाग निदेशक (फोटो प्रभाग) के अधीन है और उप निदेशक, वरिष्ठ फोटोग्राफिक अधिकारी, फोटोग्राफिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और अन्य तकनीकी और अधीनस्थ कर्मचारी इसके कामकाज में उनकी सहायता करते हैं।

प्रभाग में कुल 76 कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं, जबकि अभी केवल 37 व्यक्ति ही कार्यरत हैं। ईआरसी की अवधि के दौरान और सीधी भर्ती पर प्रतिबंध के कारण कई पदों को समाप्त कर दिया गया है। लेखा अधिकारी का एकल पद भी समाप्त हो गया है।

निदेशक, उप निदेशक का कार्य प्रशासनिक और तकनीकी दोनों प्रकार का है, जबकि वरिष्ठ फोटोग्राफिक अधिकारी, फोटोग्राफिक अधिकारी और अन्य उत्पादन कर्मचारी तकनीकी कार्य देखते हैं। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी/लेखा अधिकारी की अनुपलब्धता के कारण वरिष्ठ फ़ोटोग्राफ़िक अधिकारी और फ़ोटोग्राफ़िक अधिकारी को प्रशासनिक कार्य/आहरण एवं वितरण अधिकारी का कार्य भी करना पड़ रहा है।

इसके अलावा, वरिष्ठ फ़ोटोग्राफ़िक अधिकारी/फ़ोटोग्राफ़िक अधिकारी और वरिष्ठ तकनीकी कर्मचारी सदस्य उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की देश और विदेश में यात्रा के समय उनके साथ जाते हैं और उनकी यात्रा की व्यापक फोटो कवरेज और फोटो प्रचार सामग्री जारी करने का कार्य करते हैं। फ़ोटोग्राफ़िक अधिकारी छवियों का उचित प्रलेखन भी करते हैं और भविष्य के लिए प्रभाग के फोटो अभिलेखागार को समृद्ध बनाते हैं।

IV. फोटो प्रभाग का आधुनिकीकरण

प्रदर्शनियों के लिए आदमकद फोटो बनाने के लिए बड़े प्रारूप वाले इंकजेट फोटो प्रिंटर जैसे उपकरणों को उन्नत करके फोटो प्रभाग की सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने का प्रयास किया गया है, अति विशिष्ट व्यक्तियों की एल्बम के लिए एक ही शीट के दोनों ओर (बैक–टू–बैक) प्रिंट तैयार करने के लिए योजना अवधि में विशेष डिजिटल फोटो प्रिंटर की व्यवस्था की योजना है। इसके अलावा, आठ से 10 लाख डिजिटल छवियों के संग्रह, अनुक्रमण, कैटलॉगिंग और पुनर्प्राप्ति के लिए एक उच्च क्षमता वाला सर्वर स्थापित किया गया है।

V. राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार

2010 में अपनी स्थापना के 50 साल पूरे होने के अवसर पर, फोटो प्रभाग ने देश के पेशेवर और शौकिया फोटोग्राफरों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार प्रदान किए। इसके अलावा प्रभाग राष्ट्र की समृद्ध विरासत, कला और संस्कृति के प्रलेखन को भी बढ़ावा देता है। प्रभाग ने

6 दिसंबर, 2019 को नई दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर बी. आर. अम्बेडकर के 64वें महापरिनिर्वाण दिवस पर पुष्प श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, सूचना एवं प्रसारण और भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर

प्रसिद्ध फोटोग्राफरों को अब तक बारह लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किए हैं।

VI. अन्य मीडिया इकाइयों के साथ तालमेल

मंत्रालय की अन्य मीडिया इकाइयों की डिजिटल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फोटो प्रभाग ने समय के साथ अपनी कार्य शैली में भी बदलाव किया है। पत्र सूचना कार्यालय और अन्य सम्बंधित हितधारकों को तस्वीरें भेजने में देरी से बचने के लिए डिवीजन का न्यूज फोटो नेटवर्क पूर्ण डिजिटल मोड पर काम कर रहा है। डिजिटल कैमरा उपकरणों का उपयोग लैपटॉप और वी–डेटा कार्ड के साथ किया गया है ताकि उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के असाइनमेंट के कवरेज के लिए और वीवीआईपी के दौरे के लिए गंतव्य के कार्यक्रम स्थल से सीधे ही डिजिटल रूप में छवियों को जारी किया जा सके। प्रभाग लोक संपर्क और संचार ब्यूरो की प्रदर्शनियों के लिए आदमकद डिजिटल इंकजेट चित्रों की आवश्यकता को भी पूरा करता है।

VII. वार्षिक योजना 2019–2020

मीडिया आधारभूत अवसंरचना विकास कार्यक्रम (मीडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम –एमआईडीपी) की 12 वीं योजना अवधि के दौरान, फोटो प्रभाग ने "राष्ट्रीय फोटोग्राफी केंद्र (नेशनल सेंटर ऑफ़ फ़ोटोग्राफ़ी –एनसीपी) और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष अभियान" उप–योजना को लागू किया है। योजना का उद्देश्य डिजिटल फोटो लाइब्रेरी का उच्च क्षमता वाले सर्वर पर वैज्ञानिक अनुक्रमण करने और डिजिटल छवियों को अपलोड करने के लिए कुशल पुस्तकालय विज्ञानियों और आईटी पेशेवरों की आउटसोर्स सेवाओं का उपयोग करना है। इससे प्रभाग अपने अभिलेखागार में छवियों का संग्रह कर सकने के साथ ही आवश्यकता पड़ने पर उन्हे दोबारा उपयोग के लिए निकाल सकता है।

राष्ट्रीय फोटोग्राफी केंद्र (एनसीपी) का एक और महत्वपूर्ण अंग राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कारों का वार्षिक आयोजन है। लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से देश के प्रतिष्ठित फोटोग्राफरों को पुरस्कृत करने के अलावा, छह पुरस्कार प्रतिवर्ष शौकिया और पेशेवर श्रेणी में दिए जाते हैं। प्रभाग ने अब तक देश के बारह प्रसिद्ध फोटोग्राफरों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है।

प्रभाग ने पूरे देश में पेशेवर और शौकिया फोटोग्राफरों को प्रोत्साहित करने के लिए 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार की प्रक्रिया शुरू की है।

VIII. इस वर्ष की गई महत्वपूर्ण फोटो कवरेज

विभाग की गतिविधियों के अनुरूप माननीय उपराष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री की विभिन्न यात्राओं के फोटो दस्तावेजीकरण का कार्य किया गया।

प्रत्येक यात्रा के पूरा होने पर, फोटो प्रभाग ने देश की यात्रा पर आने वाले गणमान्य व्यक्तियों को एक रंगीन एलबम भेंट किया।

IX. प्रोडक्शन संबंधी आंकड़े

कवर किए गए कार्यक्रम, प्राप्त की गई छवियां, अपलोड किए गए प्रिंट्स, तैयार किए गए एल्बम्स इस प्रकार हैं :

1	कवर किए गए न्यूज़ और फ़ीचर असाइनमेंट्स	1453
2	पीआईबी की वेबसाइट पर भेजी गई/अपलोड की गई छवियां	5019
3	फोटो प्रभाग की वेबसाइट पर अपलोड की गई छवियां	5533
4	आंतरिक स्तर पर प्राप्त की गई डिजिटल छवियां	259757
5	बनाए गए/आपूर्ति किए गए डिजिटल प्रिंट	13212
6	तैयार की गईं वीवीआईपी एल्बम्स	13

X. राजभाषा का कार्यान्वयन

फोटो प्रभाग मुख्यालय अपने छोटे से कार्यालय में राजभाषा के कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से शामिल है। लेखा और प्रशासन अनुभाग में बड़ी संख्या में फाइलों में सिर्फ हिंदी में काम होता है। प्रभाग ने हिंदी में कई गतिविधियां की हैं। सितंबर 2019 में हिंदी पखवाड़े के दौरान हिंदी में एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

XI. स्वीकृत बजट

(हजारों में)

		व्यय		
वर्ष	गैर– योजनागत	योजनागत	गैर– योजनागत	योजनागत
2019–2020	45800	13300	23668 रुपये	2942

XII. वर्ष 2019 के लिए सतर्कता कार्य की वार्षिक रिपोर्ट

1	संगठन में मुख्यालय और फील्ड कार्यालयों में सतर्कता ढांचे का विवरण	सतर्कता से संबंधित कार्य के लिए अलग से कोई कर्मचारी अनुमोदित नहीं किए गए हैं। हालांकि, वरिष्ठ अधिकारी आम तौर पर ऐसे मामलों का निपटारा अपने अधीनस्थों की सहायता से करते हैं।
2	इस समयावधि में की गई निवारक सतर्कता गतिविधियां :	
	i) इस अवधि के दौरान किए गए सामान्य निरीक्षणों की संख्या :	4
	ii) इस अवधि के दौरान किए गए औचक निरीक्षणों की संख्या :	2
3	इस अवधि में की गईं निगरानी एवं पता लगाने की गतिविधियां :	
	i) निगरानी के लिए चुने गए क्षेत्रों का विवरण	सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण जहां प्रोडक्शन कार्य किया गया।
	ii) निगरानी में रखने के लिए चिह्नित किए गए व्यक्तियों की संख्या	
4	दंडात्मक गतिविधियां [4(1) से (x) के विपरीत संख्या इंगित की जाएगी, जहां नियोक्ता प्राधिकारी राष्ट्रपति के अलावा कोई अन्य है] :	
	i) इस अवधि के दौरान प्राप्त शिकायतें/संदर्भ	शून्य
	ii) कितने मामलों में शुरुआती जांच की गई	शून्य
	iii) कितने मामलों में शुरुआती जांच की रिपोर्ट प्राप्त हुई	शून्य
	iv) कितने मामलों में बड़े जुर्माने के लिए आरोप पत्र जारी किए गए	शून्य
	v) कितने मामलों में छोटे जुर्माने के लिए आरोप पत्र जारी किए गए	शून्य
	vi) कितने लोगों पर बड़ा जुर्माना लगाया गया	शून्य
	vii) कितने लोगों पर छोटा जुर्माना लगाया गया	शून्य
	viii) कितने लोगों को निलंबित किया गया	शून्य
	ix) कितने लोगों के ख़िलाफ़ प्रशासनिक कार्रवाई, मसलन–चेतावनी आदि जारी की गई	शून्य
	x) नियम के उपयुक्त प्रावधानों के तहत कितने लोगों को समय से पहले सेवानिवृत्त किया गया	शून्य

लोक संपर्क और संचार ब्यूरो (बीओसी)

लोक संपर्क और संचार ब्यूरो (बीओसी) की स्थापना पूर्व के विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी), क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय (डीएफपी) तथा गीत एवं नाटक प्रभाग (एसएंडडी) को एकीकृत करके 8 दिसंबर, 2017 में की गई थी। ब्यूरो का उद्देश्य मंत्रालयों/ विभागों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू)/ स्वायत्त निकायों को 360 डिग्री संचार समाधान उपलब्ध कराना है। यह मीडिया कार्यनीति पर सरकार के परामर्शी निकाय के रूप में काम करता है। 23 क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो (आरओबी) तथा 148 फील्ड आउटरीच ब्यूरो के साथ यह बीओसी ग्रामीण और शहरी दोनों तरह के लोगों को सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में शिक्षित करने के लिए वचनबद्ध है ताकि विकासात्मक गतिविधियों में उनकी भागीदारी प्राप्त हो सके। ब्यूरो ने यह सब विभिन्न संचार साधनों अर्थात् प्रिंट मीडिया, श्रव्य–दृश्य, प्रदर्शनियों, आउटडोर तथा न्यू मीडिया आदि के माध्यम से सुनिश्चित किया है।

जन–सशक्तीकरण के प्रमुख सुविधादाता के रूप में सरकार की ब्रैंडिंग तथा इसे साकार करने के लिए प्रिंट, श्रव्य–दृश्य, आउटडोर, डिजिटल मीडिया के जरिए संदेशों को सही दिशा देना बीओसी का कार्यक्षेत्र है। सूचना प्रसारण की पहुंच अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए उभरते हुए मीडिया परिदृश्य के अनुरूप नीति दिशानिर्देशों को अनुकूल बनाया गया है।

बीओसी का विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार डिविजन, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) तथा स्वायत्त निकायों की विभिन्न स्कीमों तथा नीतियों के बारे में सूचना का प्रसार करने के लिए बीओसी का नोडल डिविजन है।

यह प्रिंट, श्रव्य–दृश्य, आउटडोर, डिजिटल और न्यू मीडिया जैसे उपलब्ध संचार साधनों के जरिए सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में ग्रामीण और शहरी जनता को सूचना देने तथा शिक्षित करने के लिए अभियान चलाता है।

बीओसी का लोक संचार डिविजन, नाटक, नृत्य–नाटक, संयुक्त–कार्यक्रम, कठपुतली–खेल, बैले, ओपेरा, लोक और पारंपरिक, पौराणिक प्रस्तुति तथा अन्य स्थानीय लोक एवं पारंपरिक नृत्य रूपों जैसी व्यापक प्रदर्शनकारी कलाओं के जरिए लाइव मीडिया के माध्यम से अंतर–वैयक्तिक संवाद कार्यान्वित करता है ताकि सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों तथा स्कीमों का अधिकतम प्रचार हो सके। इसका मुख्य कार्य जागरूकता का सृजन करना तथा संबद्धता और स्वामित्व की भावना के साथ भावात्मक ग्रहणशीलता सुनिश्चित करना है।

फील्ड आउटरीच डिवीजन, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध–शहरी क्षेत्रों में जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए प्रत्यक्ष तथा अंतर–वैयक्तिक संचार कार्यक्रम चलाता है। इस प्रकार से क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो (आरओबी) तथा फील्ड आउटरीच ब्यूरो (एफओबी) सूचना के जरिए लोगों को सशक्त करने का प्रयास करता है ताकि उन्हें ऐसे कार्यक्रमों/ स्कीमों से लाभ उठाने के लिए सक्षम बनाया जा सके। राज्य सरकार और स्थानीय कार्यकर्ताओं, सामाजिक समूहों आदि जैसे विभिन्न हितधारकों के सहयोग से विशेष आउटरीच कार्यक्रम (एसओपी) आयोजित किए जाते हैं। चूंकि ये स्थानीय भाषा में तथा आस–पास के स्थानों में होते हैं इसीलिए इन संचार कार्यक्रमों का प्रभाव अधिक होता है और इससे जनता के बीच सरकार की स्कीमों की बेहतर समझ संभव हो पाती है। इस तरह से परंपरागत और जन–मीडिया तथा अन्य पारंपारिक तथा गैर–पारंपारिक पद्धतियों के इस्तेमाल से यह प्रयास पूरे हुए हैं।

पूर्व के डीएवीपी, डीएफपी तथा एसएंडडी का एकीकरण होने से विशेष आउटरीच तथा लोक घटकों के कार्यक्रमों को एक साथ एकीकृत रूप में व्यापक रूप से आयोजित किया जाता है। इन एकीकृत संचार और आउटरीच कार्यक्रमों (आइसीओपी) का उद्देश्य एक ऐसा प्रभावशाली असर छोड़ना है कि जिससे व्यवहार परिवर्तन और विकासात्मक प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित कर सकें।

सामाजिक–आर्थिक विषयों पर जनता के बीच जागरूकता पैदा करने में बीओसी सहायक सिद्ध हुआ है ताकि विकासात्मक गतिविधियों में उनकी भागीदारी प्राप्त होने के साथ–साथ कई सामाजिक बुराइयों और रूढ़िवादिता का उन्मूलन हो सके। जनता तक पहुंचने के लिए संचार के सभी संभावित चैनलों से सहायता प्राप्त हुई है, चाहे विज्ञापन से लेकर नुक्कड़ नाटक हो, नुक्कड़–नाटक से लेकर घर–घर जाकर संवाद करना हो, इसने स्टैंडअलोन और एकाकी विज्ञापन के स्थान पर 360 डिग्री समग्र अभियान लाकर एक मिसाल कायम कर दी है।

वर्ष की मुख्य गतिविधियां

क्र. सं	विषय–वस्तु	माह
1.	"बड़ा वादा निभाया गया– बड़ी आशाएं जागी #इंडिया फर्स्ट के 6 महीने " पुस्तिका	दिसम्बर 2019
2;	देश भर में 02 अक्टूबर, 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के आयोजन पर समाचार पत्रों में आधे पृष्ठ का विज्ञापन	अक्टूबर, नवम्बर और दिसम्बर 2019
3.	श्री गुरु नानक देव जी की 550वीं वर्षगांठ	नवम्बर 2019
4.	आईएफएफआई@50 : भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह (आईएफएफआई) की स्वर्ण जयंती की शानदार शुरुआत	नवम्बर 2019
5.	"हाऊडी मोदी" शीर्षक से पुस्तिका	नवम्बर 2019
6.	लंदन बुक फेयर, अबूधाबी इन्टरनेशनल बुक फेयर 2019 और फ्रेंकफर्ट बुक फेयर 2019 में महात्मा गांधी पर प्रदर्शनी के माध्यम से वैश्विक लोक सम्पर्क (आउटरीच)	लंदन– मार्च 2019 अबू धाबी– अप्रैल 2019 फ्रेंकफर्ट– अक्टूबर 2019
7.	राष्ट्रीय एकता दिवस	अक्टूबर 2019
8.	"मोदी सरकार के दिशात्मक और निर्णायक" पचास दिन, "मोदी के 75 दिन 2.0 सरकार– स्पष्ट इरादे निर्णायक कार्रवाई" और "भारत के विकास के 100 दिन साहसिक पहल और निर्णायक कार्य" शीर्षक से पुस्तिकाएं	जुलाई, 2019 अगस्त, 2019 सितंबर, 2019
9.	जल शक्ति अभियान	सितम्बर, 2019
10.	पुस्तिका : चंद्रयान–2	सितम्बर,2019
11.	उप–राष्ट्रपति एम. वेंकय्या नायडू पर पुस्तक– "सुनना, सीखना और नेतृत्व करना	अगस्त, 2019
12.	पूर्वोत्तर क्षेत्र और कोलकाता क्षेत्र का क्षेत्रीय सम्मेलन	अगस्त, 2019
13.	अलग–अलग योजनाओं/मंत्रालय केन्द्रित विज्ञापनों के स्थान पर विषय–वस्तु आधारित शून्य बजट वाले संचार अभियान जिनसे भारत सरकार की एक समान छवि दिखाने के लिए जून 2019 से उपलब्ध संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग करते हुए अधिक ऊर्जावान एवं किफायती लोक सम्पर्क की समग्र कार्यप्रणाली अपनाना	जून, 2019
14.	स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, 2019 को देशभर के समाचार पत्रों में आधे पृष्ठ का प्रिंट विज्ञापन	अगस्त, 2019
15,	अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन	जून, 2019
16.	विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन	जून, 2019
17.	देश का महात्यौहार (आम चुनाव 2019)	अप्रैल, 2019
18.	ऐतिहासिक नागरिकता संशोधन अधिनियम के प्रावधानों पर अखिल भारतीय व्यापक प्रिंट मीडिया अभियान	दिसम्बर, 2019

महत्वपूर्ण गतिविधियां:

- लोगों को ऐतिहासिक नागरिकता संशोधन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी देना। देश भर में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं में प्रिंट विज्ञापन किए गए। भ्रामक सूचनाओं और आशंकाओं का निवारण करने के क्षेत्रवार विशेष अभियान चलाए गए।

वैश्विक आउटरीच:

- वैश्विक आउटरीच के संदर्भ में 2019 लोकसंपर्क और संचार ब्यूरो के लिए एक सकारात्मक वर्ष था। फ्रैंकफर्ट, लंदन और अबू धाबी में पुस्तक मेलों के मौके पर "ब्रांड इंडिया ऑन राइज" विषय पर केंद्रित अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया। प्रदर्शनियों में अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया और पिछले कुछ वर्षों में देश द्वारा उठाए गए सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक कदमों के चलते नए भारत के उत्थान का प्रदर्शन किया गया।

महात्मा गांधी की 150वीं जयंती

- महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर लोकसंपर्क और संचार ब्यूरो ने 2 अक्टूबर, 2019 से देश भर में इंटरेक्टिव डिजिटल प्रदर्शनियों की शृंखला का आयोजन किया।

- दिल्ली, गुवाहाटी और राजकोट में बड़े पैमाने पर तीन इंटरएक्टिव डिजिटल प्रदर्शनियां आयोजित की गईं।

- **दिल्ली, 2 अक्टूबर:** सूचना एवं प्रसारण तथा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, श्री प्रकाश जावड़ेकर ने 2 अक्टूबर को इंडिया गेट, (दिल्ली) में "स्वच्छ भारत, सशक्त भारत–बापू के सपनों का भारत" प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान और पर्यटन मंत्री, श्री प्रहलाद सिंह पटेल भी उपस्थित थे। पांच दिवसीय प्रदर्शनी 6 अक्टूबर, 2019 तक चली।

- प्रदर्शनी में बापू के जीवन को प्रौद्योगिकी संचालित उपकरणों की मदद से इंटरैक्टिव डिस्प्ले बोर्ड और स्क्रीन के माध्यम से दिखाया गया। इसके अलावा, कुछ नए उपकरणों के उपयोग जैसे कि संवर्धित वास्तविकता, वर्चुअल वास्तविकता, 3–डी होलोग्राम और सिमुलेशन आदि ने आगंतुकों को प्रदर्शनी का अच्छा अनुभव दिया। प्रदर्शनी में 'बापू के सपने का भारत' की तर्ज पर बापू की विचारधारा पर आधारित 'स्वच्छ ग्राम' के एक मॉडल को भी शामिल किया गया।

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर और केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस एवं इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान लोकसंपर्क और संचार ब्यूरो द्वारा पर्यटन पर्व-2019 के दौरान आयोजित प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर 02 अक्टूबर, 2019 को नई दिल्ली में। संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्री प्रह्लाद सिंह पटेल और पूर्व सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, श्री अमित खरे भी कार्यक्रम में उपस्थित थे

- **गुवाहाटी:** महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर सात दिवसीय मेगा इंटरेक्टिव डिजिटल प्रदर्शनी 14 अक्टूबर, 2019 से 20 अक्टूबर, 2019 तक लोकसंपर्क और संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय गुवाहाटी कार्यालय के तत्वावधान में सोनाराम हाईस्कूल के खेल मैदान में आयोजित की गई थी।

- असम के माननीय राज्यपाल, प्रो. जगदीश मुखी ने 14 अक्टूबर, 2019 को मेगा इवेंट का उद्घाटन किया। सप्ताह भर चलने वाली मेगा मल्टीमीडिया इंटरेक्टिव प्रदर्शनी पूरे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 10,000 वर्ग फुट के क्षेत्र में अपनी तरह की पहली प्रदर्शनी थी। प्रदर्शनी में महात्मा गांधी द्वारा उपयोग में लाई गयी कुछ वस्तुओं और उनके निजी सामान को दिखाया गया था और साथ ही साथ गांधीजी की असम में विभिन्न स्थानों की यात्रा की कुछ दुर्लभ तस्वीरें भी थीं। प्रदर्शनी में महात्मा गांधी जी के हस्तलिखित पत्र, उनके जीवन की दुर्लभ तस्वीरें

लोकसंपर्क और संचार ब्यूरो के तत्वावधान में क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो, गुवाहाटी द्वारा महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर डिजिटल प्रदर्शनी

और दक्षिण अफ्रीका प्रवास और पूरी जीवन यात्रा पर फिलप बुक भी रखी गयी थी।

राजकोटः लोकसंपर्क और संचार ब्यूरो के तत्वावधान में क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो (आरओबी) अहमदाबाद, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 12 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2019 तक गुजरात के राजकोट में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर सात दिवसीय मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया।

महात्मा गांधी की जयंती की पूर्व संध्या पर 2 अक्टूबर, 2019 (आधा पृष्ठ) को एक विज्ञापन जारी किया गया था।

बापू पर सोलह माध्यम स्तरीय इंटरेक्टिव डिजिटल प्रदर्शनियों का आयोजन अक्टूबर और नवंबर, 2019 के महीने में करीमनगर, कटरा, पोरबंदर, चंडीगढ़, विजयवाड़ा, मदुरै, मणिपाल, मुजफ्फरपुर, सिलीगुड़ी, गोरखपुर, हरिद्वार, बोकारो, कटक, सागर, रायपुर और उदयपुर में किया गया था। प्रदर्शनी की झलक इस प्रकार हैः

चंडीगढ़ में प्रदर्शनी का पंजाब के राज्यपाल श्री वी.पी. सिंह बदनोर द्वारा उदघाटन

असम के राज्यपाल प्रो. जगदीश मुखी 14 अक्टूबर, 2019 को गुवाहाटी, असम में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो, गुवाहाटी द्वारा आयोजित महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर मेगा मल्टीमीडिया इंटरएक्टिव प्रदर्शनी का दौरा करते हुए

नगालैंड

नगालैंड के मुख्यमंत्री, नेफिउ रियो ने लोक संपर्क और संचार ब्यूरो द्वारा आयोजित डिजिटल इंटरेक्टिव प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जो पहली दिसंबर से 10 दिसंबर तक नागालैंड के कोहिमा में किसमा में हॉर्नबिल फेस्टिवल में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित की गई थी। नगालैंड के वार्षिक हॉर्नबिल समारोह में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा पहली बार 10–दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। लोक संपर्क और संचार ब्यूरो ने एक समकालीन मुहावरे के माध्यम से गांधीवादी मूल्यों और सिद्धांतों का समावेश करने के उद्देश्य से इस प्रदर्शनी का आयोजन किया।

वर्धा

संचार रणनीति में सैद्धांतिक बदलाव

यह वर्ष संचार रणनीति में बदलाव का साक्षी रहा

करीमनगर में प्रदर्शनी का एक दृश्य

कटरा, वैष्णो देवी में डिजिटल स्क्रीन के माध्यम से दर्शकों को महात्मा गांधी के जीवन वृत्त की जानकारी

पोरबंदर में प्रदर्शनी

ऑगमेंटेड रियलिटी (एआर), रायपुर का आनंद लेते छात्र

उदयपुर में प्रदर्शनी के दौरान आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम

डिजिटल पहेली का आनंद ले रहे मदुरै न्यायालय के न्यायाधीश

मणिपाल में प्रदर्शनी का एक दृश्य

सिलीगुड़ी में प्रदर्शनी का एक दृश्य

हरिद्वार में प्रदर्शनी का एक दृश्य

युवा छात्रों द्वारा कटक में प्रदर्शनी का अवलोकन

बोकारो में प्रदर्शनी के दौरान एआर का आनंद लेते छात्र

गोरखपुर में प्रदर्शनी का अवलोकन करते अतिथि और दर्शक

सागर में प्रदर्शनी के दौरान वीआर का अनुभव लेते शिक्षक और छात्र

विजयवाड़ा में बाहर से प्रदर्शनी का एक दृश्य

ईटानगर में महात्मा गांधी के जीवन और दर्शन पर डिजिटल इंटरेक्टिव प्रदर्शनी

क्योंकि सरकार की अलग–अलग योजनाओं/मंत्रालय केंद्रित विज्ञापनों के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाया गया ताकि सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए विषयवस्तु पर आधारित कम लागत वाले संचार अभियान चलाए जा सकें और अधिकतम तालमेल के साथ संपर्क में अनावश्यक दोहराव को कम करते हुए संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग हो सके।

लाभ

- **भारत सरकार के लिए कॉमन ब्रांडिंग**

महात्मा गांधी के जीवन और दर्शन पर डिजिटल इंटरेक्टिव प्रदर्शनी

प्रदर्शनी में आए छात्र

वर्तमान संचार रणनीति कल्याणकारी उपायों को अलग–अलग इकाई के तौर पर पेश करती है। प्रचार अभियानों की विषयवस्तु को एकीकृत करके प्रस्तुत करने से इनमें सरकार के प्रयास समग्र और व्यापक दिखते हैं और सरकार एक सहकारी इकाई के रूप में सामने आती है।

➢ बेहतर प्रभाव के लिए समग्र दृष्टिकोण

उचित माध्यम से संप्रेषित किए गए सरकारी प्रयासों को लाभार्थी बेहतर ढंग से समझ पाते हैं और इनका श्रेष्ठतम उपयोग संभव हो पाता है। इससे योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रति लाभार्थियों की समझ बढ़ी। इसके अलावा, विषय आधारित अभियान में सरकार के प्रयासों को समस्या के समाधान के तौर पर प्रस्तुत करने से लोगों को इन योजनाओं से और अधिक प्रभावी रूप से जोड़ा जा सका है।

➢ अभियानों और लोक संपर्क में बेहतर तालमेल और अनावश्यक दोहराव को कम करना।

अभी तक किए जा रहे प्रचार में संदेशों का अक्सर दोहराव होता रहा है। अब विषयवस्तु पर आधारित अभियान से उन सभी योजनाओं और उन्हें अलग–अलग ढंग से प्रचारित करने वाली संस्थाओं को एक साथ लाकर एक ही संचार नीति अपनाने के योग्य बना दिया गया है।

➢ संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग

अभी तक संचार और लोक संपर्क टुकड़ों में किया जाता रहा है, जिससे अक्सर संसाधनों का बेहतर उपयोग नहीं हो पाता। बेहतर ढंग से विषयवस्तु आधारित अभियान चलाने से संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग संभव हो पाया है।

➢ अभियानों की बेहतर निगरानी और पर्यवेक्षण

विषयगत अभियान से **नियोजित रणनीतियों के प्रभाव का पता लगाना और उनका मूल्यांकन** करना आसान हो जाता है। साथ ही उसमें किसी भी प्रकार की कमी दिखने पर **जरूरी सुधार** भी किया जा सकता है।

श्री गुरु नानक देवजी की 550वीं जयंती

डिजिटल इंटरेक्टिव प्रदर्शनियां एवं ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम :

12 नवंबर, 2019 को श्री गुरु नानक देव जी की 550 वीं जयंती के अवसर पर, लोक संपर्क और संचार ब्यूरो ने सफलतापूर्वक ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम आयोजित किया। देश भर में इंटरेक्टिव डिजिटल प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया गया। इसका लक्ष्य उनकी शिक्षाओं, नैतिकता और उनके जीवन को युवाओं और हमारे देश के लोगों तक उनकी सामाजिक स्थिति, लिंग, जाति और धर्म का विचार किए बिना पहुंचाना था ताकि वो इस महाउत्सव का हिस्सा बन सकें। इसके लिए श्रव्य–दृश्य माध्यम, प्रोजेक्शन मैपिंग, वीडियो रिकॉर्डर और अन्य संबंधित गतिविधियां रखी गई थी।

सुल्तानपुर लोधी में प्रदर्शनी

गुरु नानक देव जी की तीन प्रमुख शिक्षाओं 'कीर्तकरो, नाम णपो और वंड छको' पर एक 3डी रिवोल्विंग वाला

थिएटर सुल्तानपुर लोधी में आकर्षण का केंद्र बन गया था। प्रदर्शनी में संवर्धित वास्तविकता और आभासी वास्तविकता के होलोग्राम और 3डी चित्रांकन वाले सिख गुरु के जीवन से जुड़े विभिन्न चित्र प्रदर्शित किए गए थे।

प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए लंगर सेवा का एक जीवंत अनुभव देने के लिए प्रदर्शनी में 'वीआर लंगर' प्ले स्टेशन स्थापित किए गए थे, जिससे आगंतुकों को लंगर सेवा का 3डी एक्सपोज़र मिला। प्रदर्शनी का उद्घाटन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री सुश्री हरसिमरत कौर बादल की उपस्थिति में किया।

अक्टूबर से नवम्बर 2019 की अवधि में **बड़े और छोटे पैमाने की प्रदर्शनियों** में वर्गीकृत 7 मल्टी–मीडिया प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया गया था। पटना और नांदेड़ में बड़ी प्रदर्शनी लगाई गयी जबकि कुल्लू (हिमाचल प्रदेश), जम्मू (जम्मू–कश्मीर), नगांव (असम) और वाराणसी (उप्र) में छोटे पैमाने पर प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया, साथ ही अमृतसर में **ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम** में गुरु नानक देव जी के जीवन पर प्रकाश डाला गया।

प्रदर्शनी की झलक इस प्रकार है:

पूरे माहौल को *पिंड बाबे नानक दा* 'राय–भोई–दी–तलवंडी की प्रतिकृति के रूप में रचा गया था जहां 1469 में गुरु नानक का जन्म हुआ था, ताकि लोगों को उनके जीवन के करीब ले जाया जा सके। विषय वस्तु में स्क्रीन के साथ एक रसोई बनाई गयी थी और गांव जैसा वातावरण दिखाने के लिए कुछ मिट्टी के बर्तनों के साथ गुरु नानकजी के लोकप्रिय "शबद" पर श्रव्य दृश्य कार्यक्रम भी बनाया गया था।

ऐक्रेलिक बॉक्स के अंदर अपनी धुरी पर घूमने वाला "इक ओंकार" कवर किया गया एक धुरी पर 'एक ओंकार'

परिवेश को बनाने के लिए स्थापित किया गया था। लकड़ी से आदमकद **डिजिटल पेड़** भी स्थापित किया गया था जिसकी शाखाओं पर अंदर से प्रकाश व्यवस्था वाले डिब्बे लटकाए गए थे जिनमें गुरु नानक देव जी की अलग–अलग साखियां प्रदर्शित थी। यह पेड़ एक सेल्फी लेने की जगह भी बन गया था। **बड़े एलईडी पर्दों** पर श्रव्य–दृश्य माध्यम में हिंदी और गुरुमुखी (पंजाबी) में श्री गुरु नानक देवजी के जन्म, उनकी युवावस्था और जीवन यात्रा को प्रदर्शित किया गया था।

श्री गुरु नानक देवजी की 550वीं जयंती के उपलक्ष्य में 12 नवंबर को दैनिक समाचार पत्रों में एक चौथाई पृष्ठ का रंगीन विज्ञापन जारी किया गया।

करतारपुर गलियारे के उद्घाटन पर एक आधे पृष्ठ का रंगीन विज्ञापन जारी किया गया था जिसमें करतारपुर की

तीर्थयात्रा के लिए भारत सरकार की सुविधाओं का विवरण दिया गया था।

इफ्फी @50 : इफ्फी 2019 की स्वर्ण जयंती का शानदार आगमन

इफ्फी की 2019 में स्वर्ण जयंती के अवसर पर, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय के सहयोग से आउटरीच संचार ब्यूरो के पुणे स्थित क्षेत्रीय कार्यालय ने एक इंटरैक्टिव डिजिटल प्रदर्शनी इफ्फी @50 का आयोजन किया। प्रदर्शनी का उद्घाटन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री अमित खरे ने किया।

पणजी, गोवा में कला अकादमी के निकट दरिया संगम में 20,000 वर्ग फीट क्षेत्र में लगाई गयी इस प्रदर्शनी में 1952 संस्करण के बाद से अब तक भारत के अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की नयनाभिराम यात्रा दिखाई गयी। 21 नवंबर से 28 नवंबर 2019 तक 8 दिनों तक प्रदर्शनी चलती रही।

इफ्फी के 50वें संस्करण के अवसर पर आउटरीच संचार ब्यूरो ने 3 पुस्तकों का प्रकाशन किया, ''कैटलॉग ऑन इंटरनेशनल सिनेमा फोर 50वां आईएफएफआई'' कैटलॉग ऑफ इंडियन सिनेमा फोर 50वीं आईएफएफआई 'इफ्फी हैंड बुक'।

एकता के लिए दौड़ और सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती :

- राष्ट्र ने 31 अक्टूबर, 2019 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस (एकता दिवस) के रूप में मनाया। देश भर में एकता के लिए दौड़ (रन फॉर यूनिटी) अभियान चलाया गया। जनता में जागरूकता पैदा करने और अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, समाचार पत्रों में, श्रव्य–दृश्य और बाह्य प्रचार विज्ञापन जारी किए गए।

"रन फॉर यूनिटी– अब दौड़ेगा इंडिया लक्ष्य की ओर" विषय पर आउटरीच संचार ब्यूरो ने विज्ञापन तैयार किया था जिसे 29 अक्टूबर, 2019 को विभिन्न समाचार पत्रों में जारी किया गया।

राष्ट्रीयता दिवस– आइये मनाते हैं भारत की एकता का पर्व और अंग्रेजी में 'नेशनल यूनिटी डे' "राष्ट्रीय एकता दिवस" और विज्ञापन आउटरीच संचार ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया था जिसे 30 अक्टूबर, 2019 को विभिन्न समाचार पत्रों में जारी किया गया।

मोदी सरकार के ऐतिहासिक निर्णय

दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों के लिए मोदी सरकार द्वारा ऐतिहासिक निर्णयः

राष्ट्रीय राजधानी में अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए सरकार द्वारा लिए गए निर्णय पर दिल्ली के विभिन्न समाचार पत्रों हेतु प्रिंट विज्ञापन तैयार करके जारी किए गए। विज्ञापन का विषय था "मोदी सरकार का अहम फैसला– दिल्ली की अवैध कालोनियों में रहने वालों को मिला मालिकाना हक"।

- ह्यूस्टन, अमरीका में हाउडी मोदी कार्यक्रम की कवरेज पर आउटरीच संचार ब्यूरो ने पुस्तिकाएं तैयार करके प्रकाशित की।
- अंग्रेजी में "फरदरिंग इंडियाज डेवलपमेंटः 100 डेज़ ऑफ़ बोल्ड इनिशिएटिव्स एंड डिसीसिव एक्शन" नाम से और हिंदी में ऐतिहासिक जनादेश का सम्मान : कठोर परिश्रमों और बड़े निर्णयों के 100 दिन "शीर्षक वाली पुरस्तकों को आउटरीच संचार ब्यूरो ने प्रकाशित और वितरित किया था। ये पुस्तकें सितंबर, 2019 को सूचना एवं प्रसारण मंत्री द्वारा एनक संवाददाता सम्मेलन में जारी की गई।
- बुकलेट के ई–संस्करण सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की वेबसाईट mygov.in के साथ–साथ आउटरीच संचार ब्यूरो की वेबसाइट के माध्यम से भी जारी और प्रसारित किए गए। पुस्तिका को सभी मंत्रालयों की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था और ये 9 सितंबर, 2019 से अगले दो दिनों तक मुख्य पृष्ठ के रूप में चलते रहे।
- आउटरीच संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालयों ने भी मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर प्रदर्शनियों का आयोजन किया, जिसमें प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया।
- मोदी 2.0 सरकार के 75 दिनों पर एक बुकलेट "जन

कनेक्ट" तैयार, डिज़ाइन, मुद्रित और वितरित की गयी। 28 अगस्त, 2019 को नई दिल्ली में एक समारोह में सूचना एवं प्रसारण तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, श्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंत्रालय की उपलब्धियों को उजागर करते हुए "स्पष्ट इरादों, निर्णायक कार्यों" नामक पुस्तिका का विमोचन किया।

- मोदी सरकार के 50 दिनों पर एक पुस्तिका मोदी सरकार के पचास दिन : निर्णायक और दिशात्मक" को आउटरीच संचार ब्यूरो ने डिजाइन और मुद्रित किया।

इस पुस्तिका में बजट 2019 की निम्नलिखित खासियत उल्लेखित थी। 50 खरब डॉलर अर्थव्यवस्था के लिए आधार, पहले दिन से ही काम शुरू, वादे पूरे किए पर जोर दिया गया है, मोदी सरकार के काम की विश्वभर में प्रशंसा, भारत वैश्विक मुद्दों का नेतृत्व कर रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जी–20 बैठक में– भविष्य की आउटरीच परिणाम के बारे में जानकारी देते हुए पुस्तिका को सांसदों, पत्रकारों और विश्लेषकों में हिंदी और अंग्रेजी में वितरित और प्रकाशित किया।

अगले 5 वर्षों के विकास की कार्य योजना की रूपरेखा का विवरण देने के लिए "5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमीः द टार्गेट" शीर्षक से एक अलग पुस्तिका भी प्रकाशित की गयी।

जलशक्ति अभियान

स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत के अवसर पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने 14 सितंबर, 2019 को पुणे से जल संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए और 'जलदूत' के रूप में चिह्नित एक सचल प्रदर्शनी बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस प्रदर्शनी ने एक महीने के अभियान के दौरान पूरे महाराष्ट्र में 8 चिह्नित जिलों और 27 शहरी स्थानीय निकायों की यात्रा की। उन्होंने प्रतिभागियों को स्वच्छता शपथ दिलाई। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने भारत के विकास को आगे बढ़ाने से संबंधित 100 दिनों की साहसिक पहल और निर्णायक कार्रवाई पर जिला अधिकारी कार्यालय में लगाई गयी एक प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया।

इस प्रदर्शनी में विभिन्न सूचना डिस्प्ले पैनल और श्रव्य–दृश्य घटक शामिल हैं। इस बस यात्रा में आउटरीच संचार

क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो, पुणे द्वारा आयोजित एक यात्रा प्रदर्शनी में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन और सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जलदूत को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए

ब्यूरो के अधीन गीत और नाटक प्रभाग की सांस्कृतिक मंडलियों के कलाकारों ने सरकार के जलशक्ति अभियान पहल के बारे में जागरूकता पैदा की।

उपराष्ट्रपति के दो साल के कार्यकाल पर पुस्तक

आउटरीच संचार ब्यूरो ने उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू पर एक पुस्तक प्रकाशित की। चेन्नई में 10 अगस्त 2019 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित एक समारोह में गृह मंत्री श्री अमित शाह ने उपराष्ट्रपति के पद पर दो साल के कार्यकाल के लिए ''लिसनिंग, लर्निंग एंड रीडिंग'' शीर्षक वाली इस पुस्तक का विमोचन किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति और सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर उपस्थित थे। इस पुस्तक में पिछले दो वर्षों में देश भर में उपराष्ट्रपति के 330 सार्वजनिक कार्यक्रमों का विवरण है। साथ ही इस पुस्तक में राज्यसभा के सभापति के रूप में उसकी प्रभावशीलता और क्षमता में वृद्धि कर सकने की उपराष्ट्रपति की कुशल कार्यशैली की झलक भी दृष्टिगोचर होती है।

उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू, अपने कार्यकाल के दो वर्ष पूरे होने पर 11 अगस्त, 2019 को चेन्नई में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'लिस्निंग, लर्निंग एंड लीडिंग' की पहली प्रति केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह से प्राप्त करते हुए। तमिलनाडु के राज्यपाल, श्री बनवारीलाल पुरोहित, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन और सूचना एवं प्रसारण मंत्री, श्री प्रकाश जावड़ेकर, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री एडप्पादी के. पलानीस्वामी, उप मुख्यमंत्री, श्री ओ.पन्नीरसेल्वम और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे

पूर्वोत्तर क्षेत्र और कोलकाता क्षेत्र का क्षेत्रीय सम्मेलन

पूर्वोत्तर क्षेत्र और कोलकाता क्षेत्र का एक क्षेत्रीय सम्मेलन 23 और 24 अगस्त, 2019 को गुवाहाटी, असम में आयोजित किया गया। श्री अमित खरे, सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और श्री विक्रम सहाय, संयुक्त सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, श्री सत्येंद्र प्रकाश, महानिदेशक, आउटरीच संचार ब्यूरो, श्री एलआर विश्वनाथ, महानिदेशक, उत्तर–पूर्व और क्षेत्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के सूचना और जनसंपर्क विभाग के अधिकारी बैठक में शामिल हुए। सम्मेलन में इस बात पर विचार किया कि कैसे केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारी संचार सेवाओं के प्रभावी प्रचार के लिए प्रभावी समन्वय कर सकते हैं।

21 जून, 2019 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन

5वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रांची के प्रभात तारा मैदान में आयोजित समारोह में भाग लिया। रांची में योग दिवस समारोह में प्रधानमंत्री की भागीदारी के अवसर पर, आउटरीच

संचार ब्यूरो ने 20 से 24 जून 2019 तक विधानसभा मैदान में 5 दिवसीय योग प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने किया। योग पर 5 दिनों की डिजिटल प्रदर्शनी रांची के लोगों के लिए पूरी अवधि के दौरान आकर्षण का विषय रही। इसमें छात्रों और युवाओं की भीड़ देखी गई। 21 जून को आउटरीच संचार ब्यूरो मुख्यालय और अन्य क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो में भी विभिन्न कार्यक्रम और समारोह आयोजित किए गए।

विभिन्न क्षेत्रीय आउटरीच संचार ब्यूरो और उसकी क्षेत्र इकाइयों द्वारा की गई गतिविधियां निम्नलिखित हैः–

अंतरराश्ट्रीय योग दिवस पर क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा चलाई गयी गतिविधियां		
प्रदर्शनी	योग सत्र	अन्य क्रियाकलाप (प्रचार पूर्व कार्यक्रम, सभाएं, फिल्म प्रदर्शन, पहेली (क्विज) प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, निबन्ध लेखन, संगोष्ठियां, समूह वार्ताएं
272	221	1692

इस प्रदर्शनी में डिजिटल माध्यमों से योग के बारे में जानकारी दी गई। हर साल 21 जून को योग दिवस मनाने के पीछे योग का इतिहास और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की विचारधारा को प्रदर्शनी के माध्यम से समझाया गया। योग के अलावा, केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का विवरण भी प्रदर्शनी में दिया गया। इसके साथ ही, योग के बारे में गांधीजी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों को प्रश्नावली के माध्यम से दिखाया गया।

आउटरीच संचार ब्यूरो में योग

➢ आउटरीच संचार ब्यूरो मुख्यालय के साथ ही देश भर के क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो और क्षेत्र आउटरीच ब्यूरो इकाइयों में 5वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आउटरीच संचार ब्यूरो मुख्यालय, सूचना भवन में एक बड़े योग प्रदर्शन का

विधान सभा मैदान, रांची में योग दिवस प्रदर्शनी का बृहद् दृश्य

रांची में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह

आयोजन किया गया। सूचना भवन में स्थित सभी मीडिया संगठनों ने बड़े उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया। योग को हर किसी के जीवन का हिस्सा बनाने के महत्व को दर्शाने के लिए, सूचना भवन के परिसर में एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। योग विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में योग सत्र आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम में आउटरीच संचार ब्यूरो के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ब्यूरो के श्री सत्येंद्र प्रकाश, महानिदेशक, भी शामिल थे।

5वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर जागरूकता पैदा करने के लिए 20.06. 2019 और 21.06. 2019 को 200 अखबारों में आधे पृष्ठ का रंगीन विज्ञापन और भारत भर के 2018 अखबारों में एक चौथाई पृष्ठ का रंगीन विज्ञापन 20.06.2019 और 21.06.2019 को जारी किया।

5 जून 2019 को विश्व पर्यावरण दिवस

- आउटरीच संचार ब्यूरो मुख्यालय के साथ ही में देश भर के क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो और क्षेत्र आउटरीच ब्यूरो इकाइयों में 5 जून, 2019 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। आउटरीच संचार ब्यूरो के महानिदेशक और वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों की मौजूदगी में इसी दिन 03:30 बजे, सूचना भवन के गेट नंबर 2 के पास

क्षेत्रीय लोकसंपर्क ब्यूरो चेन्नई द्वारा महर्षि विद्या मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, चेन्नई के वेद भवन हॉल में 5वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2019 का आयोजन

कार्यालय परिसर में पौधारोपण किया गया।

सूचना भवन के पास पौधारोपण

- विश्व पर्यावरण दिवस 2019 के अवसर पर 'सेल्फी विद सैपलिंग' शीर्षक वाला एक स्ट्रिप कलर विज्ञापन भारत के 68 समाचार पत्रों में जारी किया गया था।

क्षेत्रीय लोकसंपर्क ब्यूरो, गुवाहाटी (उत्तर) द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय योग दिवस

भारतीय सिनेमा प्रदर्शनी

- यह कार्यक्रम भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईआईएफ) के लिए स्वर्ण जयंती की तैयारी में आयोजित किया गया था, आउटरीच संचार ब्यूरो ने सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम, नई दिल्ली में 28.05.2019 को **इंडियन सिनेमा** शीर्षक से एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। प्रदर्शनी का उद्घाटन एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस के अध्यक्ष श्री जॉन बेली और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री अमित खरे ने संयुक्त रूप से किया। फिल्म जगत के गणमान्य व्यक्तियों, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और मीडिया प्रमुखों ने प्रदर्शनी का दौरा किया और इसकी सराहना की।

सूचना भवन में पौधारोपण

- एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस के अध्यक्ष श्री जॉन बेली की यात्रा के अलावा, फिल्म महोत्सव निदेशालय (डीएफएफ) ने एक संवादात्मक कार्यक्रम और अन्य गतिविधियों का आयोजन किया। फिल्म महोत्सव निदेशालय (डीएफएफ) के अनुरोध पर आउटरीच संचार ब्यूरो ने 80 डिस्प्ले पैनल के साथ एक प्रदर्शनी का आयोजन किया।

देश का महात्योहार अभियान

- आम चुनाव 2019 में अपनी अधिकतम भागीदारी के लिए और आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए आउटरीच संचार ब्यूरो ने प्रिंट, ऑडियो–विजुअल, आउटडोर मीडिया, न्यू मीडिया का उपयोग करते हुए अभियान चलाया। यह अभियान एकाधिक मंचों पर अप्रैल 2019 के पूरे महीने के दौरान जारी रहा। ये जागरूकता अभियान भारत के चुनाव आयोग की ओर से चलाए गए थे।

- चुनावों के लिए बड़े पैमाने पर गहन आउटडोर मीडिया अभियान चलाया गया था। 1 अप्रैल, 2019 को व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी (एसवीईईपी) मतदाता जागरूकता जैसे विभिन्न लक्षित समूहों जैसे

सशस्त्र बल कार्मिक, युवा, बुजुर्ग, पहली बार मतदाता आदि पर जोर देने के साथ एक महीने का अभियान जारी किया गया था। अभियान का विषय था 'देश का महात्योहार'।

- आउटरीच संचार ब्यूरो ने विभिन्न शीर्षकों के साथ प्रिंट विज्ञापन जारी किए। इनमें "मतदाता जागरूकता", "मेरा वोट बिक्री के लिए नहीं है" शामिल था। विज्ञापन में मुख्य रूप से भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और आम चुनाव 2019 के बारे में जागरूकता के साथ संदेश थे। चुनाव आयोग के जागरूकता अभियान ने अपने रचनात्मक डिजाइनों के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों अर्थात किसान, महिला, युवा, श्रमिक वर्ग, सशस्त्र बलों के कर्मियों और बुजुर्गों को लक्षित किया। लोक सभा चुनाव–2019 के लिए चलाए जा रहे विभिन्न जागरूकता अभियानों में प्रेरक सुलभ चुनाव, लोक सभा –सेवा मतदाता, सुलभ चुनाव–धवक, ईटीपीबीएस–सेवा मतदाता, लोक सभा–1950, भारत की मिसाल, ईवीएम वीवीपीएटी–एनिमेशन, वीवीपीएटी जागरूकता, लोकसभा –फैसिलिटेशन इन पीएस, सुलभ चुनाव–परिवार, लोकसभा– सूचित और नैतिक मतदान, हम वोट देने जाएंगे देश के लिए जैसे विषय शामिल थे।

एकीकृत संचार और आउटरीच कार्यक्रम (आईसीओपी)

सीमावर्ती क्षेत्रों, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों और अल्पसंख्यक आबादी वाले क्षेत्रों सहित देश के सभी हिस्सों में क्षेत्र आउटरीच ब्यूरो इकाइयों/आउटरीच ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा 597 एकीकृत संचार और आउटरीच कार्यक्रम (आईसीओपीज) आयोजित किए गए थे। इनके विषय हैं: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 2.0 केंद्र सरकार के 100 दिन, जल संरक्षण/जल शक्ति अभियान, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, स्वच्छ भारत सेवा– प्लास्टिक कचरा प्रबंधन अभियान, पोषण–पोषण माह/राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, फिट भारत, महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ, गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती। जागरूकता कार्यक्रमों के अन्य विषय थे:– सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना, ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, परिवर्तनशील भारत, राष्ट्रीय पोषण मिशन, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना।

लोकप्रिय फिल्म शो की स्क्रीनिंग के अलावा कार्यक्रमों के दौरान पुस्तिका और पोस्टर के आकार में फ्लैगशिप सरकारी योजनाओं पर जागरूकता सामग्री वितरित की गई। सरकार के प्रमुख कार्यक्रम के विभिन्न घटकों के प्रचार के लिए वाद–विवाद, संगोष्ठी, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, सांस्कृतिक गतिविधियां, छात्रों की रैली और संवादात्मक संचार सत्र भी आयोजित किए जा रहे हैं। सरकार की विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में लोगों की प्रतिक्रिया भी प्राप्त की जा रही है।

पोषण माह

क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो इकाइयों/क्षेत्र आउटरीच कार्यालयों ने सितंबर, 2019 के दौरान पोषण माह मनाया। 6 साल तक के बच्चों, किशोरी बालिकाओं, गर्भवती, बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार करने के संदेश के साथ स्तनपान कराने वाली माताओं को कम वजन वाले शिशुओं के पोषण में कमी, पोषण में वृद्धि और एनीमिया से बचाव के प्रसार के लिए विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करने हेतु पोषण अभियान (राष्ट्रीय पोषण मिशन) के महत्व पर 58 एकीकृत संचार और आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन किया। इन कार्यक्रमों के अलावा, 291 फिल्म शो, 749 मौखिक सन्देश कार्यक्रम, 378 फोटो प्रदर्शनी और लक्षित दर्शकों के लिए क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो इकाइयों द्वारा 51 फीडबैक प्रतिक्रियाएं एकत्र की गईं।

अल्पसंख्यक कल्याण पर कार्यक्रम:

लोक संपर्क और संचार ब्यूरो की क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो इकाइयों ने चुनावी प्रक्रिया के बारे में नागरिकों, निर्वाचकों और मतदाताओं को जागरूक और शिक्षित करने के साथ ही उनकी सहभागिता बढ़ाने लिए व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी (एसवीईईपी) पर अप्रैल से सितंबर, 2019 की अवधि के दौरान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। इसके अलावा क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो इकाइयों ने अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जल संरक्षण/जल शक्ति अभियान, विश्व जनसंख्या

दिवस, करगिल विजय दिवस, पी.एम. जनऔषधि योजना, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वतंत्रता दिवस समारोह, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती, गुरु नानक देव जी की 550 वीं जयंती, केंद्र सरकार के दूसरे कार्यपाल के 2.0 की 100 दिन और स्वच्छता भारत सेवा– प्लास्टिक कचरा प्रबंधन अभियान और प्रबंधन की अन्य प्रमुख योजनाओं के बारे में कार्य किया।

अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में लाभार्थियों की सक्रिय भागीदारी के साथ सामूहिक चर्चाओं, प्रश्न–उत्तर सत्रों, सार्वजनिक बैठकों, रैली, क्विज प्रतियोगिता, और फिल्म प्रदर्शन आदि का भी आयोजन किया गया था।

अल्पसंख्यक केंद्रित क्षेत्रों में क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो इकाइयों/क्षेत्र आउटरीच कार्यालयों द्वारा संचालित गतिविधियों का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	गतिविधि	संख्या
1.	आयोजित कार्यक्रम	343
2.	फिल्म प्रदर्शन	229
3.	मौखिक सन्देश/समूह वार्ता	379
4.	फोटो प्रदर्शनी	235
5.	प्रतिक्रिया विवरण	119
6.	कवर किए गए गांवों की संख्या	299
7.	कार्यक्रम में आए दर्शकों की संख्या	114876

वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में प्रचार गतिविधियां:

आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल (दक्षिण) के नौ क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो के तहत आने वाली क्षेत्र आउटरीच ब्यूरो इकाइयों ने अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सरकार के सभी प्रमुख कार्यक्रमों/योजनाओं पर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया।

विशेष रूप से आयोजित कार्यक्रमों (एसओपी) के अलावा, अक्टूबर, 2019 तक एलडब्ल्यूई क्षेत्रों में लोक संपर्क और संचार ब्यूरो की क्षेत्र आउटरीच ब्यूरो इकाइयों ने 547 नियमित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें 263 फिल्म शो, 540 मौखिक संवाद कार्यक्रम, 337 फोटो प्रदर्शनी शामिल हैं और लक्षित दर्शकों से 131 प्रतिक्रियाएं एकत्र की हैं।

क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो ने 90 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 237 लोकनृत्य कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रमों की प्रस्तुति का विषय आतंकवाद–विरोधी, राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव, सामाजिक सद्भाव, भाषाई सद्भाव, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ–सबका विकास, ग्रामीण विकास और सरकार की विकासवादी नीति और योजनाओं को लोगों के कल्याण के लिए अधिग्रहित किया।

सीमावर्ती क्षेत्र में प्रचार गतिविधियां:

लोकसंपर्क और संचार ब्यूरो के तहत **अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, मेघालय–मिजोरम–त्रिपुरा (एमएमटी), नगालैंड और मणिपुर, उत्तर–पश्चिम (पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश), राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल (उत्तर) और सिक्किम और पश्चिम बंगाल (दक्षिण)** के क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो ने अपने अधिकार क्षेत्र के तहत सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रचार अभियान चलाया। इकाइयों ने सीमा क्षेत्र के ग्रामीणों को भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी। राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया।

महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं/दिनों/सप्ताह का आयोजन:

क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो (आरओबी) के तहत क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो इकाइयों (एफओबी) ने भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं/दिनों/सप्ताह का आयोजन करते हुए अपनी नियमित गतिविधियों में सरकार की विभिन्न योजनाओं पर प्रकाश डाला। **आतंकवाद विरोधी दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, करगिल विजय दिवस, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वतंत्रता दिवस समारोह, सद्भावना दिवस/सप्ताह, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस** आदि मनाया गया।

1	आयोजित फिल्म प्रदर्शनों की संख्या	3412
2	आयोजित सामूहिक चर्चाओं की संख्या	7994
3	लगाई गयी फोटो प्रदर्शनियों की संख्या	5391
4	एकत्र प्रतिक्रियाओं की संख्या	1248
5	दौरा किए गए गांवों की संख्या	4099
6	कार्यक्रमों में आए कुल दर्शकों की संख्या	3185144

लोकसंपर्क और संचार ब्यूरो ने अप्रैल, 2019 से नवंबर, 2019 के महीने के दौरान हिंदी और अंग्रेजी भाषा में पुस्तिकाएं, पोस्टर, फोल्डर और विविध प्रचार सामग्री की कुल 6,42,500 प्रतियां छापी हैं।

प्रकाशन के प्रकार	प्रकाशनों की संख्या	मदों की संख्या	प्रतियों की संख्या
पुस्तिकाएं	21	22	2,00,900
पोस्टर	1	15	3,00,000
फोल्डर	6	7	35,800
विविध	8	8	1,05,300
कुल	36	52	6,42,000

वर्ष के दौरान किए गए प्रमुख कार्य

क्र. सं.	कार्य का नाम
1.	उपराष्ट्रपति कार्यालय के लिए कॉफ़ी टेबल बुक
2.	प्रधानमन्त्री के भाषण पर पुस्तिका (नया भारत)
3.	50 खरब की भारतीय अर्थव्यवस्था पर पुस्तिका
4.	मोदी सरकार के 50 दिनों पर पुस्तिका (जन कनेक्ट)
5.	प्रधानमंत्री के भाषणों की पुस्तिकाओं के लिए लिफ़ाफ़े
6.	जन कनेक्ट पुस्तिका (मोदी सरकार के 75 दिन)
7.	लिफाफों के साथ 100 दिन पुस्तिका
8.	जन कनेक्ट पुस्तिका (मोदी सरकार के 75 दिन)–अतिरिक्त प्रतियां
9.	100 दिनों पर पॉकेट साइज पुस्तिकाएं
10.	100 दिन पुस्तिकाएं–अतिरिक्त प्रतियां
11.	लौह पुरुष पर फोल्डर
12.	भारतीय पैनोरमा नियमावली 2019
13.	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के लिए ब्रोशर
14.	डी.पी. कोहली स्मारक व्याख्यान के लिए ब्रोशर
15	भारतीय वायुसेना के लिए सूचना पत्रक (डीआईएसएचए)
16.	महानिदेशक, सैन्य आसूचना (सेना) के लिए सुरक्षा पोस्टर
17.	एनसीसी के लिए 'द कैडेट' पत्रिका
18.	महानिदेशक, सेना भर्ती के लिए क्लिकर पेन
19.	हार्ड बाउंड फोल्डरों और प्रमाणपत्रो की छपाई
20.	गांधी@150 और गुरु नानक जी पर पुस्तिका
21.	महिला सशक्तीकरण पर फ्लायर पुस्तिका (हिंदी और अंग्रेजी)
22.	भारत के राष्ट्रपति पर पुस्तकों के विमोचन के कार्यक्रमों का विवरण
23.	हाउडी मोदी पर पुस्तिका
24.	कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन (ईपीएफओ) पर विशेष रूप से बनाए गए कॉफ़ी मग
25.	कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन (ईपीएफओ) के लिए पेन
26.	कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन (ईपीएफओ) के लिए पुस्तिका
27.	वीआरपी और एनएसए पुस्तिका
28.	एनपीसी कॉर्पोरेट ब्रोशर
29.	विचार विमर्श पत्र पुस्तिका
30.	हिंदी दिवस पर लोक संपर्क और संचार ब्यूरो के महानिदेशक का आह्वान
31.	हिंदी दिवस पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री का आह्वान
32.	विचार–विमर्श पर ऑन रिकॉर्ड पुस्तिका
33.	चन्द्रयान–2 पर पुस्तिका
34.	गुरु नानक देव जी पर पुस्तिका
35.	वायु सेना दिवस पर पुस्तिका
36.	दिशा (डीआईएसएचए) पर कॉफ़ी टेबल बुक

भारत का समाचार–पत्र पंजीयक कार्यालय (आरएनआई)

भारत के समाचार–पत्र पंजीयक कार्यालय (आरएनआई) की स्थापना 1 जुलाई, 1956 को प्रथम प्रेस आयोग की 1953 की सिफारिश के आधार पर और प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 के संशोधन के द्वारा की गई थी। यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का संबद्ध कार्यालय है। आरएनआई वैधानिक और गैर–वैधानिक कार्यों का निर्वहन करता है।

संगठनात्मक ढांचा

इसके प्रमुख प्रेस पंजीयक होते हैं, जिनकी सहायता एक अपर प्रेस पंजीयक, दो उप प्रेस पंजीयक और तीन सहायक प्रेस पंजीयक करते हैं। कार्यालय में शीर्षक के सत्यापन, प्रसार और प्रशासन संबंधी कार्यों के लिए पृथक अनुभाग हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा पुनर्गठन किए जाने के बाद आरएनआई के मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, भोपाल और गुवाहाटी कार्यालय बंद कर दिए गए और पत्र सूचना कार्यालय तथा पूर्ववर्ती क्षेत्र प्रचार निदेशालय (अब ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन) के सहायक निदेशक स्तर के अधिकारियों को पंजीकरण सुपरवाइजर और उपनिदेशक/निदेशक/अपर महानिदेशक स्तर के अधिकारियों को क्रमशः सहायक/उप/अपर प्रेस पंजीयक निर्दिष्ट किया गया, जो प्रेस पंजीयक के अधीक्षण और निर्देशन में अपनी शक्तियों का निर्वहन कर रहे हैं।

आरएनआई के कार्य

आरएनआई के कार्यों में देशभर में प्रकाशित होने वाले समाचार–पत्रों और प्रकाशनों का रजिस्टर रखना, समाचार–पत्रों और प्रकाशनों के पंजीकरण का प्रमाण–पत्र जारी करना, समाचार–पत्रों के नए नाम शीर्षक की स्वीकृति के बारे में संबंधित जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) को जानकारी देना तथा समाचार–पत्रों और प्रकाशनों के प्रकाशकों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक वक्तव्यों की जांच और विश्लेषण करना शामिल है। आरएनआई प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर तक देश में प्रिंट मीडिया की स्थिति को दर्शाने वाली ''भारत में प्रेस'' रिपोर्ट सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को प्रस्तुत करता है। अपने ग़ैर वैधानिक कार्यों के अंतर्गत यह कार्यालय आरएनआई से पंजीकृत वास्तविक उपयोगकर्ताओं को अख़बारी काग़ज़ आयात पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी करता है और साथ–साथ मुद्रण मशीनरी के आयात के लिए आवश्यक प्रमाण–पत्र भी जारी करता है। आरएनआई पीआईबी द्वारा नामित अधिकारियों से प्रकाशकों से प्राप्त अनुरोध या सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों के आधार पर पंजीकृत प्रकाशनों के प्रसार का सत्यापन करता है।

शीर्षक का सत्यापन

आरएनआई को शीर्षकों के सत्यापन के लिए इच्छुक प्रकाशकों के आवेदन जिलाधिकारी द्वारा विधिवत अग्रेषित किए जाते हैं और कार्यालय पीआरबी अधिनियम की धारा 6 के तहत सत्यापन प्रक्रियाओं पर कार्य करता है। आवेदकों की सुविधा के लिए आरएनआई ने अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू की है। आवेदक को भरे हुए फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर संबद्ध डीएम के पास जमा कराना होता है, ताकि वह उसका सत्यापन करके उसे आरएनआई को अग्रेषित कर सके। आरएनआई द्वारा आवेदन प्राप्ति और सत्यापन की स्थिति के बारे में आवेदकों को एसएमएस और ई–मेल के माध्यम से सूचित किया जाता है। आवेदनों की स्थिति के बारे में आरएनआई की वेबसाइट www.rni.nic.in से जाना जा सकता है। शीर्षक से संबंधित पत्र भी आरएनआई वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। अप्रैल, 2019 से अक्टूबर, 2019 तक आरएनआई ने शीर्षकों के सत्यापन वाले 7,548 आवेदनों की जांच की, जिनमें से 1,909 शीर्षकों का सत्यापन किया जा चुका है।

शीर्षकों से रोक हटाना

दो वर्ष की निर्धारित समय सीमा के भीतर समाचार पत्रों के पंजीयक के साथ पंजीकृत नहीं होने पर सत्यापित शीर्षकों को डी–ब्लॉक कर इच्छुक आवेदकों को सत्यापन के लिए उपलब्ध कराया गया। अप्रैल, 2019 से अक्टूबर, 2019 के बीच 1,891 शीर्षकों को डी–ब्लॉक किया गया।

पंजीकरण

एक बार शीर्षक का सत्यापन हो जाने के बाद प्रकाशक को प्रकाशन का पंजीकरण कराना जरूरी होता है। इसके लिए संबंधित जिलाधीश द्वारा प्रमाणित घोषणा–पत्र के साथ, समाचार पत्रों के पंजीयक द्वारा निर्धारित आवश्यक दस्तावेज भी देने होते हैं। पीआरबी अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रकाशन को एक पंजीकरण संख्या आवंटित की जाती है और प्रकाशक को एक पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इसे समाचार पत्रों के पंजीयक के रजिस्टर में दर्ज किया जाता

है। 31 मार्च, 2018 तक पंजीकृत 1,18,239 प्रकाशनों में से 18,193 समाचार पत्र और 1,01421 पत्रिकाएं हैं। 1 अप्रैल, से 31 अक्टूबर, 2019 के दौरान 1,026 प्रकाशनों का पंजीकरण किया जा चुका है।

वार्षिक विवरण

पीआरबी अधिनियम, 1867 की धारा 19डी के अनुसार, समाचार–पत्र के प्रकाशक से अपेक्षा की जाती है कि वह हर वर्ष मई के अंतिम दिन से पहले तक फॉर्म–2 में वार्षिक विवरण, जोकि समाचार–पत्र पंजीकरण (सेंट्रल) नियम, 1956 में निर्दिष्ट है, प्रेस रजिस्ट्रार को सौंपे। यह हर प्रकाशक के लिए बाध्यकारी है कि वह अपने प्रकाशन पहले अंक में (हर साल फरवरी माह के अंतिम दिन के बाद) फॉर्म–4 के स्वामित्व और अन्य संबंधित विवरणों को इंगित करने वाला वक्तव्य प्रकाशित करे। प्रकाशकों द्वारा जमा कराए गए वार्षिक विवरण के आधार पर आरएनआई प्रिंट मीडिया के संबंध में हुई वृद्धि संकलन और विश्लेषण करते हुए हर साल 'भारत में प्रेस' रिपोर्ट लाता है।

2013–14 के दौरान शुरू की गई वार्षिक विवरण ऑनलाइन जमा करने की प्रक्रिया सफलतापूर्वक लागू की जा रही है। वर्ष 2018–19 के दौरान 37,938 प्रकाशनों ने वार्षिक विवरण दाखिल किया।

कंप्यूटरीकरण

वर्तमान में शीर्षक के लिए आवेदन ऑनलाइन जमा कराए जा सकते हैं। शीर्षक सत्यापन और पंजीकरण की कंप्यूटरीकृत प्रोसेसिंग के बाद सभी सत्यापित शीर्षकों को आरएनआई की वेबसाइट पर डाला जाता है और इसे आवेदक डाउनलोड कर सकते हैं। इस सुविधा के लागू होने से कोई भी व्यक्ति/संभावित प्रकाशक वर्तमान शीर्षक डाटा बेस तक पहुंच सकता है। यह डाटा राज्यवार/भाषा के अनुसार उपलब्ध होता है। आरएनआई ने नई उपयोग–सुलभ वेबसाइट विकसित की है। डिजिटलीकरण के दूसरे चरण में, शीर्षक के आवेदन और पंजीकरण से संबंधित कार्यालय की विभिन्न प्रक्रियाएं पूरी तरह ऑनलाइन उपलब्ध करा दी जाएंगी। प्रक्रियाओं के ऑनलाइन होते ही, सभी संबद्ध जिला अधिकारियों को आवेदनों को विधिवत सत्यापित करने के बाद आरएनआई को अग्रेषित करने के लिए व्यक्तिगत लॉगइन उपलब्ध कराया जाएगा।

'प्रेस इन इंडिया' का प्रकाशन

पीआरबी अधिनियम,1867 की धारा 19 (जी) के अनुसार, प्रेस पंजीयक केंद्र सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट सौंपता है, जिसमें भारत में समाचार–पत्रों के बारे में पिछले वर्ष प्राप्त की गई सूचनाओं का सारांश शामिल होता है। 'भारत में प्रेस' शीर्षक वाली यह रिपोर्ट हर साल दिसंबर में सौंपी जाती है। वर्ष 2013–14 से, 'प्रेस इन इंडिया' सीडी जैसे डिजिटल प्रारूप में भी लाई जा रही है।

प्रसार सत्यापन

प्रकाशन की नियमित प्रसार जांच/सत्यापन का उद्देश्य वार्षिक रिटर्न/रिपोर्ट में प्रकाशनों द्वारा दिए गए प्रसार आंकड़ों की सत्यता की पुष्टि करना है, क्योंकि प्रसार के इन आंकड़ों का उपयोग पूर्ववर्ती विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय–डीएवीपी (अब ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन) सहित विभिन्न सरकारी विभाग सरकारी विज्ञापन आवंटित करने के बारे में निर्णय लेने के लिए करते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा 7 जून, 2016 को जारी की गई नई प्रिंट मीडिया विज्ञापन नीति के अंतर्गत 45 हजार से ऊपर के प्रसार दावों का आरएनआई/एबीसी द्वारा सत्यापन अनिवार्य बना दिया गया। इस नीति का अनुसरण करते हुए प्रसार जांच से संबंधित आरएनआई के दिशानिर्देशों में 2017 में संशोधन किया गया और इससे प्रसार सत्यापन की ज्यादा प्रभावी व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त हुआ, ताकि समाचार–पत्रों द्वारा फर्जी प्रसार दावों की समाप्ति सुनिश्चित की जा सके। संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार प्रसार जांच का कार्य आरएनआई/पीआईबी अधिकारियों द्वारा प्रेस पंजीयक के सामान्य अधीक्षण एवं नियंत्रण में लेखाकारों (यानी चार्टेड एकाउंटेंट फर्म्स) के प्रमाणित पैनल के साथ किया जाता है, जो एबीसी, कैग या आरबीआई के पैनल में शामिल लेखाकार होते हैं। साथ ही बीओसी की ओर से प्रेस विशेषज्ञों की आवश्यकता के स्थान पर स्व–घोषणा पत्र फॉर्म को शामिल किया गया है, जिसमें प्रकाशकों द्वारा प्रसार सत्यापन के लिए मुद्रण से संबंधित विवरण उपलब्ध कराया जाता है।

अख़बारी कागज़

किसी समाचार–पत्र द्वारा आयात की जा सकने वाली अख़बारी कागज की अधिकतम मात्रा को निर्दिष्ट करने से संबंधित पात्रता प्रमाण–पत्र जारी करने की प्रक्रिया आरएनआई द्वारा 2017 में समाप्त कर दी गई। वर्तमान में, पंजीकृत प्रकाशकों को अख़बारी कागज आयात करने से पहले एक

स्व–घोषणा प्रमाण–पत्र जमा कराना होता है, जिसमें वर्ष के दौरान आयात किए गए अख़बारी कागज की मात्रा और उपरोक्त मात्रा में से आज की तिथि तक वास्तव में कितनी खपत की गई, इसकी जानकारी दी जाती है। आरएनआई और पीआईबी के क्षेत्रीय शाखा कार्यालय यह सुनिश्चित करने के बाद स्व–घोषणा प्रमाण–पत्र को प्रमाणित करते हैं कि प्रकाशक न्यूज़प्रिंट का 'वास्तविक उपयोगकर्ता' है, अर्थात प्रकाशन आरएनआई के साथ पंजीकृत है। आरएनआई अब आयात होने वाले अख़बारी कागज की मात्रा तय नहीं करता।

राजभाषा

आरएनआई कार्यालय ने 1 से 14 सितंबर, 2019 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया, जिसमें सरकारी कामकाज में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इस कार्यालय में अनुवाद में सहायता प्रदान करने और भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए एक सहायक निदेशक (ओएल) नियुक्त हैं। आरएनआई को 2018–19 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ।

जन शिकायत तथा आरटीआई

कार्यालय में एक जन शिकायत प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है। शीर्षक आवेदक तथा प्रकाशक ईमेल pqrcrni@nic.in के माध्यम से सीधे या आरएनआई की वेबसाइट के माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हैं। एक उप प्रेस पंजीयक को इस कार्यालय की आंतरिक शिकायत निवारण व्यवस्था का प्रमुख बनाया गया है। अप्रैल 2019 से अक्टूबर 2019 के दौरान आरटीआई कानून के अंतर्गत लगभग 440 आवेदन प्राप्त हुए और उनके उत्तर दिए गए।

नागरिक चार्टर

नागरिक चार्टर तैयार किया गया है। इसे कार्यालय की वेबसाइट (http://www.rni.nic.in) पर डाल दिया गया है।

चौदहवें वित्त आयोग की शेष अवधि के लिए प्लान योजना

आरएनआई मुख्यालय का सुदृढ़ीकरण

12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आरएनआई ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की व्यापक योजना 'मीडिया अवसंरचना विकास कार्यक्रम' के अंतर्गत 'आरएनआई मुख्यालय का सुदृढ़ीकरण' के अंतर्गत योजना पर 1.65 करोड़ रुपये की राशि खर्च की। योजना अवधि के दौरान प्रस्तावित विविध लक्ष्यों में से एक उप–संघटक 'वार्षिक विवरणों की ई–फाइलिंग' को पूरी तरह प्राप्त कर लिया गया। अब चौदहवें वित्त आयोग की शेष अवधि, यानी 2017–20 तक के लिए योजना निम्नलिखित लक्ष्यों के साथ जारी है :–

- रिकॉर्ड्स / दस्तावेजों का डिजिटलीकरण
- शीर्षक आवेदन दाखिल करना और डीएम द्वारा ऑनलाइन अग्रेषित करना
- घोषणापत्र फॉर्म ऑनलाइन जमा कराना
- पंजीकरण प्रमाणपत्र ऑनलाइन उत्पन्न करना
- दस्तावेज जमा कराने सहित पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन
- पब्लिक इंटरफेस सिस्टम की स्थापना और पब्लिक रिस्पांस क्वेरी सिस्टम को मजबूत बनाना

प्रकाशन विभाग

प्रमुख गतिविधियां और उपलब्धियां

- प्रकाशन विभाग ने भारत के माननीय राष्ट्रपति के कार्यकाल के दूसरे वर्ष के उपलक्ष्य में उनके चुनिंदा भाषणों को हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित किया। इनका शीर्षक था–(अंग्रेजी में) *द रिपब्लिकन एथिक –वोल्यूम II* और हिंदी में *लोकतंत्र के स्वर–खंड 2*। इनमें राष्ट्रपति के भाषणों को 8 वर्गों में बांटा गया है। ये भाषण राष्ट्र निर्माण से संबंधित पहलुओं पर उनके दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने 6 सितंबर, 2019 को इन पुस्तकों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर माननीय पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन और सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर, माननीय सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्री श्री थावर चंद गहलोत और सूचना व प्रसारण सचिव श्री अमित खरे उपस्थित थे। इस अवसर पर इन पुस्तकों का ई–संस्करण भी जारी किया किया।
- माननीय प्रधानमंत्री के चुनिंदा भाषणों की दस पुस्तकों (हिंदी और अंग्रेजी में पांच–पांच) के प्रकाशन की परियोजना मई 2019 में पूरी की गई। इसके सभी संस्करणों का एक

ही शीर्षक था– *सबका साथ सबका विकास*। ये भाषण, राष्ट्र निर्माण, बुनियादी ढांचागत विकास, सामाजिक क्षेत्र के लिए देखभाल तथा सरोकार और विज्ञान, कृषि तथा राष्ट्रीय सुरक्षा पर जोर और विदेशों के साथ संबंधों के बारे में प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण पर आधारित हैं। इन वर्षवार संस्करणों में प्रधानमंत्री के 2014–2019 के उनके कार्यकाल के दौरान दिए गए भाषण हैं। लगभग 10 हजार पृष्ठों में प्रधानमंत्री के साढ़े तीन सौ से अधिक भाषणों को हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया है।

- पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के माननीय मंत्री, श्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में सूचना भवन में एक समारोह में प्रकाशन विभाग की पुस्तक दीर्घा में कई ई–परियोजनाओं की शुरुआत की। ये हैं–प्रकाशन विभाग की फिर से डिजाइन की गई सक्रिय वेबसाइट, मोबाइल ऐप– डिजिटल डीपीडी, रोजगार समाचार का ई–संस्करण और *सत्याग्रह गीता* शीर्षक से गांधीजी पर महत्वपूर्ण संग्रहणीय पुस्तक का ई–संस्करण।

- भारत छोड़ो आंदोलन (9 अगस्त, 2019) की वर्षगांठ पर, माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने संग्रहणीय पुस्तक *"महात्मा गांधीः ए लाइफ थ्रू लेंसेस"* और *"महात्मा गांधीः चित्रमय जीवन गाथा"* नामक गांधी एल्बम भारत के राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द को प्रस्तुत की। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद के प्राक्कथन के साथ मूल रूप से 1954 में प्रकाशित इस पुस्तक को प्रकाशन विभाग ने फोटो की गुणवत्ता और प्रस्तुति में सुधार कर सुंदर कलेवर के साथ फिर से प्रकाशित किया। इस एल्बम में 450 तस्वीरों के माध्यम से महात्मा गांधी के जीवन और समय की कहानी को सचित्र बयान किया गया है। इसे बड़ी संख्या में पाठकों तक पहुंचाने के लिए पहली बार, एल्बम का हिंदी संस्करण निकाला गया है।

- प्रकाशन विभाग ने **गांधीजी की 150वीं जयंती** के उपलक्ष्य में पुस्तकों के प्रकाशन और आउटरीच गतिविधियों से संबंधित अपना महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जारी रखा।

- इस अवधि के दौरान अब तक हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं में 25 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं। कुछ उल्लेखनीय पुस्तकों में शामिल हैं– *'मेरे गांधी', 'कस्तूरी परिमल', 'चंपारण पुराण', 'सत्याग्रह में महिलाएं' (गुजराती), 'एम.के गांधी : एन इंडियन पेट्रोएट इन साउथ अफ्रीका' (तमिल)* आदि।

केंद्रीय पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के माननीय मंत्री, श्री प्रकाश जावड़ेकर माननीय राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द को विरासत महत्व की गांधी एल्बम देते हुए

- सितंबर 2019 में दिल्ली पुस्तक मेले के दौरान सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री अमित खरे ने गांधीजी के जीवन और विचारों पर पांच पुस्तकों का विमोचन किया।
- इसके अलावा, महात्मा गांधी से संबंधित व्यापक पाठक वर्ग सुनिश्चित करने के लिए 45 से अधिक ई–पुस्तकें भी प्रकाशित की गई हैं। विभाग की संस्कृत की धरोहर पुस्तकें– *'सत्याग्रह गीता'* और *'उत्तर सत्याग्रह गीता'* शामिल हैं। 1930 और 40 के दशक में डॉ. क्षमा राव द्वारा लिखित इन पुस्तकों में सुंदर संस्कृत छंदों में गांधीजी के जीवन को प्रस्तुत किया गया है।
- योजना के विशेष अंक और अन्य पत्रिकाओं– कुरुक्षेत्र, आजकल, बाल भारती और रोजगार समाचार में लेख भी प्रकाशित किए गए।
- गांधीजी के जीवन और कार्यों से संबंधित विषयों पर परिचर्चा कार्यक्रम हर महीने पुस्तक दीर्घा में आयोजित की गई। अन्य गांधीवादी और सांस्कृतिक संगठनों के सहयोग से गांधीवादी मूल्यों पर परिचर्चा कार्यक्रम और विशेष व्याख्यान हर महीने आयोजित किए गए।
- देश भर में क्षेत्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में गांधीजी पर पुस्तकों का विशेष प्रदर्शन और बिक्री की गई। गांधी@ 150, अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेलों में भी मुख्य आकर्षण था। अबू धाबी इंटरनेशनल बुक फेयर (24–30 अप्रैल, 2019) और न्यूयॉर्क में बुक एक्सपो –19 में गांधीजी पर पुस्तकें प्रमुखता से प्रदर्शित की गईं। अबू धाबी मेले में 'मेकिंग ऑफ द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी' पर प्रकाशन विभाग द्वारा आयोजित सेमिनार मुख्य आकर्षण था।
- प्रकाशन विभाग के सोशल मीडिया चैनलों पर नियमित रूप से व्यापक ऑनलाइन प्रचार गतिविधियां की गईं। संगठन की वेबसाइट पर एक विशेष अनुभाग गांधी@ 150 भी बनाया गया है।
- जलियांवाला बाग त्रासदी के 100 साल पूरे होने के सिलसिले में, 15 अप्रैल, 2019 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए), नई दिल्ली के सहयोग से प्रकाशन विभाग ने एक विशेष कार्यक्रम – 'याद करो कुर्बानी' का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में स्कूलों के बच्चों की प्रस्तुतियां बहुत प्रेरक थीं, जिन्होंने प्रकाशन विभाग की पुस्तक – 'ज़ब्तशुदा तराने' (औपनिवेशिक शासन के दौरान निषिद्ध देशभक्ति गीत) के कुछ अंश गाये थे। कार्यक्रम में विभाग की एक और पुस्तक– 'याद कर लेना कभी' (क्रांतिकारियों के पत्र) प्रदर्शन किया गया तथा गद्यांश पढ़े गए और देशभक्ति के विषयों पर लघु नाटक किए गए।

प्रकाशन विभाग, सूचना भवन की पुस्तक दीर्घा में महात्मा गांधी पर मासिक परिचर्चा कार्यक्रम

- गुरु नानक देवजी की 550वीं जयंती के अवसर पर, प्रकाशन विभाग ने *'गुरु नानक'* शीर्षक से अंग्रेजी और हिंदी में गत वर्षों के विद्वानों द्वारा लिखे गए लेखों की सामग्री से एक समृद्ध संकलन निकाला।
- प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित असमिया में शीर्षक– *कोर्ट्स ऑफ इंडिया: पास्ट टू प्रेजेंट* में देश के कानून और कानूनी संस्थानों के इतिहास की एक झलक पर प्रकाश डाला गया है। भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने असम के मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में 10 नवंबर, 2019 को इसका लोकार्पण किया।
- **एक भारत श्रेष्ठ भारत** के तहत प्रकाशन विभाग ने बच्चों के लिए 15 भारतीय भाषाओं में 15 प्रेरक शीर्षकों के अनुवादित संस्करणों के प्रकाशन के काम को आगे बढ़ाया है। इस परियोजना के तहत प्रकाशित पुस्तकों की कुल संख्या 156 तक हो गई।

प्रकाशन विभाग ने इससे पहले सस्ता साहित्य मंडल के सहयोग के परिणामस्वरूप *'शहीद भगत सिंह' (खंड : I–IV)* शीर्षक से चार पुस्तकों का प्रकाशन किया। इनमें शहीद भगत सिंह के सभी उपलब्ध दस्तावेज – पत्र, लेख, संस्मरण आदि प्रकाशित किए गए हैं।

- प्रकाशन विभाग ने हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं की

विभिन्न श्रेणियों में पुस्तक प्रकाशन में **उत्कृष्टता के लिए 9 पुरस्कार और एक योग्यता प्रमाण–पत्र** प्राप्त किया। 29 सितंबर, 2019 को नई दिल्ली में फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स द्वारा स्थापित वार्षिक पुरस्कार वितरित किए गए। प्रकाशन विभाग की पुस्तकों *'महात्मा गांधी : चित्रमय जीवन गाथा', 'पराक्रम गाथा', 'लोकतंत्र के स्वर', 'गुवाहाटी–हाइकोर्ट हिस्ट्री एंड हेरिटेज (अंग्रेजी)', 'कहो चिरैया', 'सरल पंचतंत्र भाग–1', 'कुरुक्षेत्र–जुलाई 2018 (हिंदी)', 'महात्मा गांधी'* पर पुस्तकों की कैटलॉग को पुरस्कार मिला। *'वुमेन इन सत्याग्रह (अंग्रेजी)'* ने योग्यता प्रमाण–पत्र प्राप्त किया। प्रकाशन विभाग ने दिल्ली पुस्तक मेला में **उत्कृष्ट प्रदर्शनी के लिए गोल्ड ट्रॉफी** प्राप्त की।

- प्रकाशन विभाग ने तीन अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेलों यानी यूएई में आयोजित अबू धाबी अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला (24–30 अप्रैल, 2019), बुक एक्सपो एण्ड न्यूयॉर्क राइट्स फेयर (29–31 मई, 2019) और फ्रैंकफर्ट अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला (16–20 अक्टूबर, 2019) में भाग लिया।
- प्रकाशन विभाग ने अप्रैल 2019 से जनवरी 2020 तक 20 घरेलू पुस्तक मेलों में भाग लिया। सितंबर, 2019 में दिल्ली पुस्तक मेला में बड़े पैमाने पर भाग लिया।
- *योजना* और *कुरुक्षेत्र* सहित प्रकाशन विभाग की पत्रिकाएं सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में सूचनाओं को प्रसारित करने के प्रयास जारी रखे हुए हैं। योजना की ओर से *'केंद्रीय बजट 2019–20', 'इनवैल्युबल लीगेसी'* (महात्मा गांधी की 150वीं जयंती) *'इन्फ्रास्ट्रक्चर', सेनिटेशन* चार विशेषांक निकाले गए हैं। *कुरुक्षेत्र* ने अपने अंक कृषि उद्योग, ग्रामीण अवसंरचना, ग्रामीण स्वास्थ्य, एमएसएमई, पंचायती राज आदि को समर्पित किए हैं, जिनमें मंत्रालयों के सचिव/मंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों तथा विषय विशेषज्ञ के लेख शामिल रहे। रोज़गार समाचार ने अप्रैल, 2019 से 30 नवंबर, 2019 तक 2940 से अधिक विज्ञापन प्रकाशित किए हैं।
- **'मीडिया अवसंरचना विकास कार्यक्रम'** उपयोजना के तहत प्रकाशन प्रभाग ने डिजिटाइज पुस्तकों की संख्या अधिक करते हुए अपनी पुस्तकों के डिजिटल भंडार को और समृद्ध करने की दिशा में काम किया। इनमें से 405 से अधिक ई–पुस्तकों को अमेजन और गूगल प्ले जैसे

फ्रेंकफर्ट पुस्तक मेले में गांधीजी को श्रद्धांजलि

विभिन्न प्लेटफॉर्मों के माध्यम से बिक्री के लिए प्रस्तुत किया गया। ई–पुस्तकों की लगभग 5,000 प्रतियों की बिक्री हुई।

- प्रकाशन विभाग ने डीपीडी बिक्री केंद्रों में कम्प्यूटरीकृत बिल सहित इन्वेंटरी मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के कम्प्यूटरीकरण के अधिकतर मोड्यूल की शुरुआत की। विभाग ने अपनी नई सक्रिय वेबसाइट शुरू की और इसके डिजिटल अधिकार प्रबंधन समर्थकृत ऐप–डिजिटल डीपीडी की शुरुआत की।

परिचय

राष्ट्रीय महत्व और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत जैसे विषयों पर प्रकाश डालने वाली पुस्तकों और पत्रिकाओं के भंडार प्रकाशन विभाग की स्थापना 1941 में की गई थी। यह भारत सरकार के ऐसे प्रमुख प्रकाशन गृह के रूप में उभर कर सामने आया है जो ज्ञान के राष्ट्रीय भंडार को समृद्ध करने में निम्नलिखित तरीके से अपना योगदान कर रहा है: 1) भारत भूमि और यहां के लोगों, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास, कला और संस्कृति, जीव–जंतुओं और वनस्पतियों, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले आधुनिक भारत के निर्माताओं की जीवनियों, संस्कृति, दर्शन, विज्ञान, साहित्य आदि के क्षेत्र की महान हस्तियों के बारे में श्रेष्ठ पुस्तकें प्रकाशित करके भारत की धरोहर का संरक्षण और प्रदर्शन, (2) राष्ट्रपति/प्रधानमंत्री के भाषणों के प्रकाशन से समसामयिक घटनाक्रम को लिपिबद्ध करना; समसामयिक विज्ञान, अर्थव्यवस्था, इतिहास और अन्य विषयों पर भारतीय समाज और पाठकों पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित करते हुए पुस्तकें छापना और (3) कथात्मक और गैर–कथात्मक बाल साहित्य का प्रकाशन।

विभाग ने गांधीवादी दर्शन पर अनेक पुस्तकों का प्रकाशन किया है जिनमें 100 खण्डों में अंग्रेजी में 'कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी (सीडब्ल्यूएमजी)' शामिल हैं। इसे गांधीजी के लेखन का सबसे व्यापक और प्रामाणिक संग्रह माना जाता है। प्रकाशन विभाग ने गुजरात विद्यापीठ के साथ मिलकर प्रमुख गांधीवादी विद्वानों की निगरानी में कलेक्टे वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी का ई–संस्करण (ई–सीडब्ल्यूएमजी) भी तैयार किया है। मास्टर कॉपी सुरुचिपूर्ण ढंग से डिजाइन की गई डीवीडी के सेट के रूप में उपलब्ध है, इसमें किसी भी विषय को आसानी से खोजा जा सकता है, जो गांधी हैरिटेज पोर्टल पर भी उपलब्ध है। प्रकाशन विभाग और राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय कई प्रामाणिक और सुरुचिपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित करने में सहयोग कर रहे हैं।

प्रकाशन विभाग चार मासिक पत्रिकाओं *योजना, कुरुक्षेत्र, बाल भारती और आजकल* तथा साप्ताहिक *रोज़गार समाचार* का भी प्रकाशन करता है। ये पत्रिकाएं आर्थिक विकास, ग्रामीण पुनर्निर्माण, सामुदायिक विकास, साहित्य, संस्कृति, बाल साहित्य और रोज़गार एवं करियर के विकल्पों पर सूचना जैसे समकालीन विषयों को प्रकाशित करती हैं।

संगठनात्मक ढांचा

प्रकाशन विभाग निदेशालय के प्रमुख महानिदेशक (डीजी) होते हैं। उनकी सहायता के लिए एक अपर महानिदेशक और निदेशक स्तर के अधिकारी होते हैं जो संपादकीय, व्यावसायिक, उत्पादन और प्रशासन प्रभागों एवं रोज़गार समाचार को देखते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली स्थित सूचना भवन में है और इसके बिक्री केंद्र– नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, पटना, लखनऊ, हैदराबाद तथा तिरुअनंतपुरम में हैं। *योजना* पत्रिका के कार्यालय नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, तिरुअनंतपुरम तथा बंगलुरु में हैं।

प्रमुख गतिविधियां

पुस्तकों का प्रकाशन

वर्ष 2019–20 में, प्रकाशन विभाग ने नवंबर 2019 तक 86 पुस्तकें प्रकाशित कीं। इनमें से 16 अंग्रेजी में, 59 हिंदी में और 11 क्षेत्रीय भाषाओं में थीं। इनमें से कुछ प्रमुख हैं: भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के दूसरे वर्ष में दिए गए चुनिंदा भाषण – *द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम II (अंग्रेजी)* और *लोकतन्त्र के स्वर खंड II, गणित का जादू (हिंदी), भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के चुनिंदा भाषणों के पांच खंड* और *वार्षिक संदर्भ ग्रंथ – इंडिया 2020* और *भारत 2020*।

महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष में उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप गांधीवादी पुस्तकों पर इस वर्ष विशेष ध्यान केंद्रित किया गया था। इस खंड की सर्वाधिक उल्लेखनीय पुस्तकें हैं: गांधीवादी साहित्य पर पांच पुस्तकें– *कस्तूरी परिमल (हिंदी), 1921 के असहयोग आंदोलन की झांकियां (हिंदी), गांधी कथा (उर्दू और अंग्रेजी), सत्याग्रह में महिलाएं (गुजराती) और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि (तमिल)*। इन्हें 11–15 सितंबर, 2019 तक आयोजित दिल्ली पुस्तक मेले में सूचना एवं प्रसारण सचिव ने

दिल्ली पुस्तक मेले में प्रकाशन विभाग की पुस्तकों का विमोचन

जारी किया।

प्रकाशन विभाग ने शीर्ष संस्थानों पर पुस्तकों के प्रकाशन के अपने निरंतर प्रयासों के तहत, असमिया में शीर्षक– *कोर्ट्स ऑफ इंडियाः पास्ट टू प्रेजेंट* प्रकाशित की। इसमें देश के कानून और कानूनी संस्थानों के इतिहास पर प्रकाश डाला गया है। भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने असम के मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में 10 नवंबर, 2019 को इसका लोकार्पण किया।

- कुछ अन्य महत्वपूर्ण शीर्षकों में शामिल हैंः *फॉर ए यूनाइटेड इंडिया–'स्पीचिज ऑफ सरदार पटेल (1947–50), 2500 ईयर्स ऑफ बुद्धिज्म, गांधी– हिज लाइफ एंड थॉट्स', 'न्यू मेजर्स फॉर कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन' (अंग्रेजी), 'जब आजादी खतरे में हो', 'अजेय क्रांतिकारी राजगुरू', 'गांधीजी के संस्मरण', 'गांधी कथा', 'प्राचीन भारत की स्त्री', 'नगालैंड की लोककथाएं', 'महात्मा गांधी का संदेश', 'मेरे गांधी', 'परी कथाएं' एवं 'विज्ञान लेखन' (हिंदी), 'सत्याग्रह में महिलाएं' (गुजराती), 'गांधी कथा और लाल बहादुर शास्त्री' (उर्दू), 'गीत रामायण' (मराठी), 'लाइव्स दैट इंस्पायर वॉल्यूम III (तमिल), 'पंडित दीन दयाल उपाध्याय' (तेलुगु) और 'सरल पंचतंत्र' (मैथिली)*।

प्रकाशनों का डिजिटलीकरण

मीडिया आधारभूत ढांचा विकास कार्यक्रम की उप–योजना के तहत 2000 से अधिक शीर्षकों का डिजिटलीकरण किया गया। इस दिशा में निरंतर आगे बढ़ते हुए हर नई पुस्तक को पी–बुक और ई–बुक दोनों रूपों में प्रकाशित किया जा रहा है। इनमें से 405 ई–पुस्तकों को अमेजन और गूगल प्ले जैसे विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से बिक्री के लिए रखा गया था। ई–पुस्तकों की लगभग 5000 प्रतियां बेची गईं।

ई–परियोजनाओं का शुभारंभ

माननीय पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन और सूचना एवं प्रसारण मंत्री, श्री प्रकाश जावड़ेकर ने 31.7.2019 को नई दिल्ली के सूचना भवन में विभाग की पुस्तक दीर्घा में कई ई–परियोजनाओं की शुरुआत की। ई–परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार हैः

(i) **पुनर्निर्मित वेबसाइटः** नई सक्रिय वेबसाइट (www.publicationsdivision.nic.in) एकीकृत भुगतान गेटवे के साथ वास्तविक समय में खरीद सुविधाएं प्रदान करने में सक्षम है और साथ ही यह प्रकाशन विभाग की पुस्तकों और पत्रिकाओं के बारे में अद्यतन जानकारी प्रदान करती है। सभी पुस्तकें भारतकोष के भुगतान गेटवे के माध्यम से बिक्री के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। उपयोगकर्ता के अनुकूल यह वेबसाइट देखने में आकर्षक लगती है और आसानी से सुलभ सोशल मीडिया उपकरण है।

(ii) **मोबाइल ऐप 'डिजिटल डीपीडी'**: यह डाउनलोड के लिए गूगल प्लेस्टोर पर मुफ्त उपलब्ध है और विभाग की पुस्तकों के बारे में पढ़ने और आसान खरीदारी की सुविधा प्रदान करता है। मोबाइल ऐप को पायरेसी पर नियंत्रण के लिए डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट सिस्टम के साथ जोड़ा गया है और भुगतान में आसानी के लिए भारतकोष भुगतान गेटवे के साथ एकीकृत किया गया है।

(iii) **रोजगार समाचार का ई–संस्करणः** एम्प्लॉयमेंट न्यूज (अंग्रेजी) के समरूप रोजगार समाचार हिंदी समाचार पत्र है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों सहित केंद्र सरकार में नौकरी के अवसरों की जानकारी प्रदान की जाती है। इसमें विशेषज्ञों द्वारा करियर–उन्मुख लेखों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश और करियर के अवसरों के बारे में जानकारी और मार्गदर्शन होता है। ई–रोज़गार समाचार, इसे डिजिटल रूप में उपलब्ध कराता है और इसकी वार्षिक सदस्यता 400 रुपये है।

(iv) **ई–पुस्तक 'सत्याग्रह गीता'**: प्रख्यात कवि डॉ. क्षमा राव द्वारा लिखित 1930 के दशक में संस्कृत के छंदों में धरोहर स्मणोत्सव पुस्तक, गांधीजी के जीवन और गतिविधियों को प्रस्तुत करती है। गांधीजी की 150वीं जयंती मनाने के लिए, प्रकाशन विभाग ने पुस्तक का एक पीडीएफ संस्करण प्राप्त किया और ई–संस्करण तैयार

किया। व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इसमें अंग्रेजी अनुवाद को भी शामिल किया गया है। अट्ठारह अध्यायों (भागवत गीता के अध्यायों की तरह) में विभाजित, सत्याग्रह गीता गांधीवादी लोकाचार और सिद्धांतों के साथ गांधीजी के विचारों, जीवन दर्शन और संस्कृत के पद्य रूप में उनके कार्यों के तरीकों को प्रस्तुत करती है।

पत्रिकाओं का प्रकाशन

विभाग ने कुल 18 पत्रिकाएं प्रकाशित की हैं जिनमें योजना अंग्रेजी, हिंदी और 11 अन्य भाषाओं में, *कुरुक्षेत्र* (अंग्रेजी तथा हिंदी में), *आजकल* (हिंदी तथा उर्दू में) और *हिंदी में बाल भारती* के अलावा *एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, रोजगार समाचार* अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में शामिल हैं। इन सभी पत्रिकाओं में पूरे वर्ष के दौरान, इनकी अपनी विधाओं के साथ–साथ अन्य प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए गांधीजी के जीवन, आदर्शों और विचारों पर नियमित रूप से लेख प्रकाशित किए गए।

क) योजना (अंग्रेजी, हिंदी और 11 क्षेत्रीय भाषाएं)

1957 से प्रकाशित योजना, 13 भाषाओं के संस्करणों– अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बंगाली, कन्नड़, मराठी, गुजराती, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू में आर्थिक विकास के विषयों को समर्पित पत्रिका है। पिछले एक वर्ष के दौरान, पत्रिका ने समसामयिक मुद्दों और तीन विशेष विषयों पर ध्यान केंद्रित किया। ये हैं– आधारभूत ढांचा, केंद्रीय बजट 2019–20 और अमूल्य धरोहर (महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने के लिए)। इसके अलावा, स्वच्छता कर्मियों के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में और कार्यक्षेत्र के संबंध में नीति प्रारूप का गहराई से अध्ययन करने और परिवर्तन की कहानियों को साझा करने के लिए स्वच्छता पर एक अंक निकाला गया था। इस अंक का उल्लेख यूनिसेफ के ग्लोबल न्यूजलेटर में किया गया।

योजना में प्रख्यात व्यक्तियों और सरकार के थिंक–टैंक सहित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के विचारों और राय को प्रकाशित किया जाता रहा है।

ख. कुरुक्षेत्र (अंग्रेजी और हिंदी)

1952 से प्रकाशित कुरुक्षेत्र ग्रामीण विकास और जमीनी स्तर के विषयों के लिए समर्पित है जो शिक्षाविदों, योजनाकारों, गैर–सरकारी संगठनों और विचारकों को एक मंच प्रदान करती है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कुरुक्षेत्र में विशेष अंकों के अलावा अन्य में सरकार की पहलों और कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला गया। विशेष अंकों के विषयों में– ग्रामीण पर्यटन, जैविक खेती, ग्रामीण भारत के लिए पेय जल, ग्रामीण गैर–कृषि क्षेत्र, कृषि सुधार, ग्रामीण शिक्षा इत्यादि शामिल थे।

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री, श्री प्रकाश जावड़ेकर 31 जुलाई, 2019 को नई दिल्ली में प्रकाशन विभाग की विविध ई–परियोजनाओं के शुभारंभ पर संबोधित करते हुए

ग) आजकल (हिंदी और उर्दू)

साहित्य और संस्कृति के लिए समर्पित, *आजकल* (हिंदी) पत्रिका 1945 से प्रकाशित की जा रही है। पत्रिका ने जनवरी–फरवरी 2020 में 75वीं वर्षगांठ समारोहों के लिए समर्पित विशेष अंक निकाला। पिछले एक साल के दौरान, प्रमुख साहित्यकारों जैसे मन्नू भंडारी, ज्ञानरंजन, गिरधर राठी आदि पर विशेष अंक प्रकाशित किए गए। पत्रिका में महिलाओं के मुद्दों और कला तथा संस्कृति पर कई लेख प्रकाशित किए। इस वर्ष के दौरान हर अंक में गांधी जयंती के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कुछ लेख शामिल थे।

उर्दू में साहित्यिक पत्रिका– *आजकल* ने 2017 में निरंतर प्रकाशन के 75 साल पूरे किए। इसमें कविताओं या गजलों के अलावा दिलचस्प लेखों का प्रकाशन नियमित रूप से जारी रखा गया। 2019–20 के दौरान, अल्लामा इकबाल, मुजतबा हुसैन, स्वतंत्रता दिवस, खुमार बाराबंकवी की शताब्दी, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती, मजरूह सुल्तानपुरी की जन्मशताब्दी पर आजकल में विशेषांक निकाले गए।

घ) बाल भारती (हिंदी)

1948 से लगातार प्रकाशित की जा रही *बाल भारती*, बच्चों को स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करने के अलावा, सूचनात्मक लेखों, लघु कथाओं, कविताओं और सचित्र कहानियों के माध्यम से उनमें सामाजिक मूल्यों को स्थापित करने में मदद करती है।

इंप्लायमेंट न्यूज़/रोज़गार समाचार (अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू)

1976 में शुरू किया गया, *इंम्पाइमेंट न्यूज़* सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का प्रमुख साप्ताहिक पत्र है, जो अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में प्रकाशित होता है। यह विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त केंद्र, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त संस्थाओं में रोज़गार की सूचना प्रदान करने वाली एकल खिड़की के रूप में कार्य करता है। यह व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के प्रवेश नोटिस, परीक्षा सूचनाओं तथा यूपीएससी, एसएससी तथा अन्य सामान्य भर्ती निकायों के परिणामों को भी प्रकाशन करता है। इसके अतिरिक्त *इंप्लायमेंट न्यूज़* में संपादकीय अनुभाग भी होता है जो युवाओं के व्यावसायिक तथा सूक्ष्म कौशल को उन्नत बनाने के अतिरिक्त बाजार में उपलब्ध विभिन्न रोज़गारों के लिए तैयारी में सहायता देता है। इसके ई–संस्करण तथा मुद्रित संस्करण को उपभोक्ता वेबसाइट www.e-employmentnews.co.in से सब्सक्राइब किया जा सकता है। इसकी ट्विटर तथा फेसबुक जैसे विविध सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर भी उपस्थिति है।

रोज़गार समाचार ने 1 अप्रैल, 2019 से 30 नवंबर, 2019 के दौरान 2940 से अधिक विज्ञापनों का प्रकाशन किया।

व्यापार और विक्रय

प्रकाशन विभाग की व्यापार शाखा अपनी पत्रिकाओं/पुस्तकों/प्रकाशनों के प्रचार और बहु–आयामी विपणन में लगी हुई है। इनका प्रकाशन राष्ट्रीय महत्व के विषयों के बारे में जानकारी और जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। प्रकाशन विभाग महानगरों से नए युग के पाठकों के साथ–साथ शहरों और गांवों के पाठकों तक पहुंचने के लगातार प्रयास कर रहा है। बिजनेस विंग विभाग के प्रकाशनों को नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, पटना, लखनऊ, हैदराबाद तथा तिरुवनंतपुरम में अपने बिक्री केंद्रों, क्षेत्रीय बिक्री इकाइयों (अहमदाबाद और बंगलुरु में) तथा पंजीकृत एजेंटों के जरिए और पुस्तक प्रदर्शनियों तथा पुस्तक मेलों में भाग लेकर और सार्वजनिक सूचना अभियान तथा बिक्री संवर्धन गतिविधियों के माध्यम से बेचता है।

तेजी से डिजिटलीकरण करने वाले भारत और दुनिया की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, प्रकाशन विभाग ने भी ई–बुक्स और डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में अपना स्थान बनाया है। प्रकाशित पुस्तकें वर्तमान में ऑनलाइन बिक्री के लिए भारतकोष पोर्टल और प्रकाशन प्रभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। ई–बुक्स का विपणन और बिक्री ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म (अमेजन, गूगल प्ले) और ई–रिसोर्स एग्रीगेटर्स (जीआईएसटी) के जरिए की जा रही है।

ई–कॉमर्स

1. ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ई–बुक्स की बिक्री

- 405 ई–बुक्स शीर्षक अमेजन किंडल और गूगल प्ले पर उपलब्ध हैं।
- 2018–19 में ई–रिसोर्स एग्रीगेटर (जीआईएसटी) के माध्यम से ई–बुक्स की लगभग 5000 प्रतियां बेची गईं।
- वर्ष 2017–18 में 7439 ई–बुक्स की तुलना में 2018–19 में 11,451 ई–बुक्स की बिक्री हुई। इस तरह एक वर्ष में इनकी बिक्री में लगभग 54 प्रतिशत की वृद्धि हुई। (2015–16 में) स्थापना के बाद से अब तक इनकी कुल

संख्या 29,771 हो गई है।

2. मुद्रित पुस्तकों की ऑनलाइन बिक्री

- ➢ बिक्री के लिए उपलब्ध 1700 से अधिक प्रिंट पुस्तकें प्रकाशन विभाग की वेबसाइट के माध्यम से और 300 से अधिक प्रिंट पुस्तकें भारतकोष पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन खरीदी जा सकती हैं।
- ➢ 2015–16 में स्थापना के बाद से भारतकोष पोर्टल पर पी–पुस्तकों की 8423 प्रतियां (31 अक्टूबर, 2019 तक) बेची गईं।
- ➢ पीडी वेबसाइट पर (अगस्त 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक) कुल 1081 पी–बुक्स बेची गईं।

3. भारतकोष पोर्टल पर पत्रिकाओं (योजना और अन्य पत्रिकाओं) के लिए सदस्यता ग्राह्यता

- ➢ स्थापना के बाद से बेची गई पत्रिकाओं की कुल संख्या (31 अक्टूबर, 2019 तक) – 67,662 है।

4. डिजिटल डीपीडी ऐप विकसित किया गया है और इसे ई–बुक्स बेचने के लिए शुरू कर दिया गया है।

- ➢ बिक्री राजस्व (31 अक्टूबर, 2019 तक)
- ➢ डीपीडी – 643.95 लाख रु.
- ➢ ईएन (प्राप्तियां) – 1407.35 लाख रु.

आउटरीच गतिविधियां

पुस्तक मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी

प्रकाशन विभाग ने पाठकों तक अपनी पहुंच बढ़ाने की अपनी गतिविधियों के तहत मूल स्थान पर पुस्तक प्रदर्शनियों के अलावा महत्वपूर्ण घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेलों में भाग लिया।

1. अंतरराष्ट्रीय मेले– प्रकाशन विभाग ने तीन अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लिया। 2019 में 24 से 30 अप्रैल तक यूएई में अबू धाबी अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला 2019 में भाग लिया, न्यूयॉर्क में 2019 में 29 से 31 मई तक बुक एक्सपो एण्ड न्यूयॉर्क राइट्स फेयर 2019 और 2019 में ही 16 से 20 अक्टूबर तक फ्रैंकफर्ट इंटरनेशनल बुक फेयर में भाग लिया। विभाग की पुस्तकों के प्रकाशन अधिकार/विपणन अधिकार/ई–बुक्स विपणन के लिए कुछ प्रमुख वैश्विक प्रकाशकों और ई–बुक्स एग्रीगेटर्स से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली।

2. राष्ट्रीय मेले– प्रकाशन विभाग ने अप्रैल 2019 से जनवरी 2020 तक उदयपुर, पटना, ओडिशा, गुवाहाटी, उज्जैन, अजमेर, लखनऊ, नेयवेली, पुणे, थूथुकुडी, धर्मशाला, दिल्ली, मदुरै, कोच्चि, अगरतला, फैजाबाद, आगरा, महाराष्ट्र, आदि में 20 राष्ट्रीय पुस्तक मेलों में भाग लिया।

   11 से 15 सितंबर, 2019 तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 25वें दिल्ली पुस्तक मेले में प्रकाशन विभाग का थीम मंडप था। पुस्तक मेले में प्रकाशन विभाग हैंगर को ''हिंदी श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन'' के लिए गोल्ड ट्रॉफी से सम्मानित किया गया था। विभाग ने नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2020 में भी बड़े पैमाने पर भाग लिया।

3. मूल स्थान पर प्रदर्शनियां– पूरे साल दिल्ली में मुख्यालय के साथ–साथ बिक्री एम्पोरिया और बिक्री इकाइयों ने स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, हिंदी पखवाड़ा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, डॉ. आम्बेडकर जयंती, गणतंत्र दिवस आदि जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अवसरों पर मूल स्थानों पर प्रदर्शनियां आयोजित कीं।

25वें दिल्ली पुस्तक मेले में प्रकाशन विभाग का मंडप

4. प्रदर्शनियों में प्रदर्शन/बिक्री– प्रकाशन विभाग देश के विभिन्न हिस्सों में समय–समय पर बीओसी द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों में प्रकाशनों की बिक्री और प्रदर्शन के लिए स्टॉल लगाता है। अक्टूबर 2019 के दौरान, बीओसी ने 'गांधी@150' समारोहों के तहत विशेष प्रदर्शनियों का आयोजन किया। गांधीवादी साहित्य के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक होने के नाते, प्रकाशन

विभाग ने 8 शहरों में आयोजित प्रदर्शनियों में भाग लिया और गांधीजी पर अपने प्रकाशनों को प्रमुखता से प्रदर्शित किया। ये शहर हैं– दिल्ली, गुवाहाटी, उदयपुर, गोरखपुर, राजकोट, विजयवाड़ा, (मसौढ़ी) पटना और मणिपाल, बंगलुरु।

सरकार/संस्थानों से सीधे ऑर्डर

प्रकाशन विभाग सरकारी निकायों, स्वायत्त संगठनों, राज्य सरकार के अधिकारियों, संस्थानों, सार्वजनिक पुस्तकालयों आदि तक सक्रिय रूप से पहुंच बना रहा है और उनसे बिक्री ऑर्डर ले रहा है। इस वित्तीय वर्ष में प्रगति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः

1. यूजीसी के सचिव ने सभी विश्वविद्यालयों को प्रकाशन विभाग की पुस्तकों और पत्रिकाओं की खरीद के लिए परामर्श जारी किया।
2. प्रकाशनों की खरीद के लिए असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड में राज्य सरकार के निकायों द्वारा परामर्श जारी किए गए।
3. राज्य स्तरीय निविदाओं के लिए सरकारी स्कूल पुस्तकालयों/संस्थानों में आवेदन करना।
4. समूचे भारत में प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के एजेंटों द्वारा जानकारी मांगना और ऑर्डर देना।
5. उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी प्री–प्राइमरी और प्राइमरी स्कूलों में पुस्तकों की थोक आपूर्ति।
6. विभिन्न राज्यों और जिलों के जवाहर नवोदय विद्यालयों से ऑर्डर।
7. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित एक प्रदर्शनी में भागीदारी के परिणामस्वरूप दिल्ली सरकार के स्कूलों से ऑर्डर मिले।
8. एनएचपीसी, एमईए, एनपीसीआईएल जैसे निकाय बल्क ऑर्डर के लिए संपर्क कर रहे हैं।
9. सार्वजनिक पुस्तकालय और विश्वविद्यालय/कॉलेज नियमित रूप से ऑर्डर दे रहे हैं।

(क) प्रकाशन विभाग ने मैसर्स जीआईएसटी के साथ एक समझौता करके ''डिजिटल संस्करण'' विपणन में कदम रखा। डिजिटल पुस्तकालयों को अपनी पुस्तकें बेचने के लिए ई–रिसोर्स एग्रीगेटर के रूप में जीआईएसटी ने पिछले वर्ष लगभग 3500 ई–पुस्तकें कॉलेजों/विश्वविद्यालयों को बेचीं।

(ख) एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया जिसके माध्यम से खरीद और जानकारी प्राप्त करने की सुविधा भी प्रदान की गई।

वित्तीय वर्ष के दौरान प्रकाशन विभाग का कुल राजस्व 44.56 करोड़ रुपये था।

सूची कार्य प्रबंधन का कम्प्यूटरीकरण

सूची कार्य प्रबंधन और अन्य व्यावसायिक प्रक्रियाओं का कम्प्यूटरीकरण (सीआईएम परियोजना), प्रकाशन विभाग के नए–पुराने पाठकों तक पहुंचने, उन्हें उनकी पसंद के प्लेटफार्मों के माध्यम से सूचित तथा शिक्षित करने और बदलती तकनीकी तथा व्यावसायिक परिस्थितियों के अनुरूप कार्य करने का जरिया है। प्रकाशन विभाग ने इस परियोजना का अधिकांश महत्वपूर्ण कार्य पूरा किया। इस ईआरपी परियोजना के सभी मॉड्यूल शुरू किए गए थे, इनमें विभाग के सभी बिक्री केंद्रों में कम्प्यूटरीकृत बिलिंग का परीक्षण प्रचालन भी शामिल था। विभाग ने अपनी नई सक्रिय वेबसाइट और इसके डिजिटल अधिकार प्रबंधन सामर्थ्य से ऐप–डिजिटल डीपीडी की शुरुआत की। इस नए वेब पोर्टल के माध्यम से प्रिंट और ई–बुक दोनों को सीधे ग्राहकों को बेचना संभव होगा। इसी तरह, डिजिटल डीपीडी ऐप के माध्यम से, मोबाइल उपकरणों को ई–पुस्तकों के डिजिटल अधिकारों को बेचना और प्रबंधित करना संभव होगा। प्रकाशन विभाग ने कई गतिशील विशेषताओं को जोड़कर अपनी वेबसाइट को नया रूप दिया।

सोशल मीडिया

प्रकाशन विभाग ने अपने फॉलोअर्स और संभावित पाठकों तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया का प्रभावी ढंग से उपयोग किया। फेसबुक और ट्विटर अकाउंट के माध्यम से राष्ट्रीय रुझानों के मद्देनजर प्रकाशन विभाग और रोजगार समाचार दोनों के लिए प्रभावी ढंग से कार्य किया गया। सोशल मीडिया पर विभाग की उपस्थिति से उसे ट्विटर हैंडल पर 20,610 से अधिक और फेसबुक पर 4,32,315 से अधिक फॉलोअर्स के साथ उत्साही प्रतिक्रिया मिली। ये आंकड़े अप्रैल से नवंबर 2019 की अवधि के हैं।

भारतीय जनसंचार संस्थान

परिचय

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) 17 अगस्त 1965 को अस्तित्व में आया। इस संस्थान की स्थापना सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जनसंचार के क्षेत्रों में शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान के मूल उद्देश्यों के साथ की थी। संस्थान का मुख्य परिसर नई दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा, इसके पांच क्षेत्रीय परिसर हैं, जो आइजोल (मणिपुर), अमरावती (महाराष्ट्र), ढेनकनाल (ओडिशा), जम्मू (जम्मू–कश्मीर) और कोट्टायम (केरल) में स्थित हैं।

भारतीय जनसंचार संस्थान, मुख्य भवन

भारतीय जनसंचार संस्थान के उदय की शुरुआत 1960 के दशक में हुई, जब भारत सरकार ने देश के विकास के लिए संचार का प्रभावी उपयोग करने के लिए एक मंच की स्थापना में सहायता के लिए यूनेस्को से संपर्क किया। इस योजना में विकासशील दुनिया के इस हिस्से में जनसंचार प्रशिक्षण मंच स्थापित करना भी शामिल था। जनसंचार अध्ययन के जनक के रूप में चर्चित अमरीकी विद्वान विल्बर श्राम्म के नेतृत्व में संचार विशेषज्ञों के एक दल ने इसका खाका तैयार किया और 1965 में इसका जन्म हुआ।

शुरू के कुछ वर्षों में, संस्थान ने मुख्य रूप से केंद्रीय सूचना सेवा के अधिकारियों (अब भारतीय सूचना सेवा) के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए और मामूली स्तर पर शोध अध्ययन किया। वर्ष 1969 में, एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम– विकासशील देशों के लिए पत्रकारिता में पोस्ट–ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स गुट–निरपेक्ष देशों के कामकाजी पत्रकारों के लिए शुरू किया गया था। पत्रकारिता और जनसंचार को व्यवसाय के रूप में अपनाने के इच्छुक संचार पेशेवरों और विद्यार्थियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाद में संस्थान ने कई विशिष्ट लघु पाठ्यक्रम और स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किए।

शासी संरचना

भारतीय जनसंचार संस्थान को 50 सदस्यीय सोसायटी द्वारा प्रशासित किया जाता है, जिसका गठन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा द्विवार्षिक रूप से किया जाता है। सोसाइटी के सदस्यों को सामाजिक सेवा संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों, सार्वजनिक जीवन के प्रतिष्ठित व्यक्तियों आदि में से चुना जाता है। सोसाइटी के कार्यों का प्रशासन कार्यकारी परिषद के पास है, जिसमें 15 सदस्य शामिल हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों के अलावा, कार्यकारी परिषद के सदस्यों में सार्वजनिक जीवन के प्रतिष्ठित व्यक्ति और शैक्षिक संस्थानों तथा संस्थान के प्रतिनिधि शामिल हैं।

पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स

पिछले तीन दशकों में जनसंचार माध्यमों में क्रान्ति का दौर चला है और इसकी पहुंच और प्रभाव कई गुना बढ़ी है, जिसके लिए बड़ी संख्या में प्रशिक्षित जनशक्ति की आवश्यकता है। वर्तमान में, भारतीय जनसंचार संस्थान निम्न डिप्लोमा कार्यक्रम चला रहा है जो विद्यार्थियों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं:

पाठ्यक्रम का नाम	केंद्र
अंग्रेजी पत्रकारिता में स्नात्कोत्तर डिप्लोमा	सभी केंद्र
हिंदी पत्रकारिता में स्नात्कोत्तर डिप्लोमा	आईआईएमसी, नई दिल्ली
रेडियो और टीवी पत्रकारिता में स्नात्कोत्तर डिप्लोमा (द्विभाषी – अंग्रेजी और हिंदी)	आईआईएमसी, नई दिल्ली
विज्ञापन और जनसंपर्क में स्नात्कोत्तर डिप्लोमा (द्विभाषी – अंग्रेजी और हिंदी)	आईआईएमसी, नई दिल्ली

उर्दू पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	आईआईएमसी, नई दिल्ली
उड़िया पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	आईआईएमसी, ढेकानाल
मराठी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	आईआईएमसी, अमरावती
मलयालम पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	आईआईएमसी, कोट्टायम

2019–20 के दौरान डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए कुल 433 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा के माध्यम से चुना गया है। यह परीक्षा 6,000 से अधिक उम्मीदवारों ने दी।

आईआईएमसी द्वारा चलाए जा रहे डिप्लोमा पाठ्यक्रम कक्षा शिक्षण के अनुरूप सार्थक हैं, इसके लिए कठोर अभ्यास, प्रयोगशाला पत्रिकाओं, परियोजनाओं, क्षेत्र के दौरे आदि के माध्यम से विधिवत व्यावहारिक रूप से अभिविन्यास किया जाता है। वर्ष के दौरान, नई दिल्ली और अन्य क्षेत्रीय कैंपस में कई कार्यशालाओं और संगोष्ठियों का आयोजन किया गया था। ये मोबाइल पत्रकारिता, ड्रोन पत्रकारिता, दृश्य कहानी, फोटो पत्रकारिता, कैमरे का सामना करना, इन्फो–ग्राफिक्स और उन्नत सोशल मीडिया तकनीक आदि विषयों पर थे।

विल्सन सेंटर, वाशिंगटन डीसी, की अमरीकी पत्रकार सुश्री लिंडा रोथ, अटलांटिक काउंसिल के यूरेशिया केंद्र की एसोसिएट डायरेक्टर, सुश्री ग्येशा गोनज़ालेज़, न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध पत्रकार चिके फ्रेंकी एडोजियन और बोस्निया से सेल्मा हादज़ीहालोविक जैसे कई अंतरराष्ट्रीय विद्वान पुरस्कार विजेता हैं। मीडिया और संचार से संबंधित समकालीन विषयों की विविधता को कवर करने वाले शिक्षण कार्य किए।

आईआईएमसी अपने विद्यार्थियों को इंटर्नशिप हासिल करने में सहायता करता है, इससे उन्हें आमतौर पर कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से समाचार पत्रों, टीवी चैनलों और मीडिया घरानों के साथ–साथ विज्ञापन और जनसंपर्क एजेंसियों में रोजगार मिल जाता हैं।

31 अक्टूबर, 2019 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति, श्री राम नाथ कोविन्द भारतीय सूचना सेवा (2018 बैच) के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ राष्ट्रपति भवन में

भारतीय सूचना सेवा–आईआईएस अधिकारियों का प्रशिक्षण

1965 में अपनी स्थापना के बाद से आईआईएमसी, भारतीय सूचना सेवा की प्रशिक्षण अकादमी के रूप में कार्य कर रहा है। यह आईआईएस ग्रुप ए के अधिकारियों के लिए प्रेरण प्रशिक्षण प्रदान करता है, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भर्ती किया जाता है। यह आईआईएस ग्रुप बी अधिकारियों के लिए संस्थापन प्रशिक्षण भी आयोजित करता है, जिन्हें पत्रकारिता में पूर्व अनुभव के आधार पर भर्ती किया जाता है।

2018 बैच के 21 प्रशिक्षु अधिकारी अभी संस्थान में प्रेरण प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। आईआईएस प्रेरण पाठ्यक्रम में मॉड्यूल आधारित प्रशिक्षण शुरू किया गया है और प्रशिक्षु अधिकारियों को क्लास रूम शिक्षण, व्यावहारिक कार्य, सिंडिकेट प्रोजेक्ट, प्रस्तुतीकरण आदि के माध्यम से जनसंचार के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया गया है। प्रशिक्षण और प्रदर्शन के इस कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षु अधिकारियों को दो सप्ताह के लिए शिलांग में असम राइफल्स और वन्य जीवन तथा सामाजिक वानिकी पर संरक्षण अध्ययन संस्थान में भेजा गया। प्रशिक्षु अधिकारियों ने आम चुनाव 2019 के दौरान भारत के निर्वाचन आयोग के साथ, अंतरिम बजट की प्रस्तुति के दौरान पीआईबी के साथ, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय के साथ और अन्य के साथ जुड़ कर काम किया। आईआईएस भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे में टेलीविजन प्रोडक्शन और फिल्म एप्रीसिएशन के क्षेत्र में चार सप्ताह का व्यापक प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षु अधिकारियों ने 31 अक्टूबर, 2019 को राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति से मुलाकात की।

आईआईएस प्रशिक्षु अधिकारियों ने मार्च 2018 में लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी, मसूरी के तत्वावधान में आयोजित अंतर–सेवा बैठक में भी भाग लिया। दृष्टिबाधित प्रशिक्षु अधिकारी सुश्री प्रज्ञा देवरा, ने मैनेजमेंट गेम्स में रजत पदक जीता। नए शुरू किए गए विदेशी घटक प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में, 2017 बैच के आईआईएस प्रशिक्षु अधिकारियों ने थॉमसन फाउंडेशन, लंदन के सहयोग से आयोजित अध्ययन दौरे पर यूनाइटेड किंगडम का दौरा किया।

लघु पाठ्यक्रम

आईआईएमसी अपनी स्थापना के बाद से, सशस्त्र बलों, केंद्रीय तथा राज्य सरकार के विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए संचार, जनसंपर्क और अनुसंधान में अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन में सबसे आगे रहा है। वर्ष के दौरान, संस्थान ने रक्षा बलों के लेफ्टिनेंट कर्नल के समकक्ष अधिकारियों के लिए या जूनियर कमीशन अधिकारियों और गैर–कमीशन अधिकारियों के लिए कौशल आधारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए 6 विशेष लघु पाठ्यक्रम आयोजित किए। भारतीय आयुध कारखाना बोर्ड के अधिकारियों के लिए एक विशेष लघु पाठ्यक्रम भी संचालित किया गया था।

आईआईएमसी दिल्ली ने विशेषकर उत्तर भारत के फिल्म उत्साहियों के लिए फिल्म एप्रीसिएशन और निर्माण के विभिन्न पहलुओं में लघु अवधि पाठ्यक्रम के संचालन के लिए भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे के साथ हाथ मिलाया। संस्थान ने डिजिटल छायांकन, स्मार्ट फोन फिल्म निर्माण, अभिनय, समीक्षा की कला, गीत चित्रांकन आदि में सात लघु पाठ्यक्रम संचालित किए। सिविल सोसायटी संगठन – कला अभयारण्य के सहयोग से विशेष आवश्यकता वाले युवा वयस्कों के लिए एक विशेष लघु पाठ्यक्रम संचालित किया गया।

विकास पत्रकारिता

आईआईएमसी का विकास पत्रकारिता पाठ्यक्रम, संचार के क्षेत्र में विकास के एक माध्यम के रूप में अनुभव, विशेषज्ञता और नवाचारों के जरिए विशेष रूप से विकासशील दुनिया के देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय सहयोग और समझ को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रयास है। यह भारत सरकार आईटीईसी/एससीएएपी और कोलंबो प्लान स्कीम के तहत प्रमुख पाठ्यक्रमों में से एक है।

इन वर्षों में, आईआईएमसी ने 127 देशों के 1,600 से अधिक विदेशी पत्रकारों को प्रशिक्षित किया है, जो अफगानिस्तान से जिम्बाब्वे तक वर्णानुक्रम में हैं। वर्ष के दौरान, एशिया, अफ्रीका, पूर्वी यूरोप और दक्षिण अमरीका के 19 पत्रकारों ने विकास पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया। संस्थान ने सितंबर 2019 के दौरान विभिन्न देशों के कामकाजी पत्रकारों के लिए एक महीने के नए लघु पाठ्यक्रम की शुरुआत की।

संचार अनुसंधान

आईआईएमसी एशिया का पहला संस्थान है जिसके पास विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए अनुसंधान/विश्लेषण और प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन आयोजित करने वाला एक समर्पित संचार अनुसंधान विभाग है। अनुसंधान

मुख्य रूप से सरकारी अभियानों, प्रभाव विश्लेषण, प्रतिक्रिया इत्यादि पर केंद्रित है, जो सरकारी अभियानों और संचार कार्यक्रमों की लोगों तक प्रभावी और व्यापक पहुंच के लिए नीतियां बनाने के वास्ते गुणवत्तापूर्ण जानकारी प्रदान करता है। मंत्रालयों और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों आदि के लिए 1965 से विभिन्न विषयों जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दों, ग्रामीण विकास, उपभोक्ता संरक्षण आदि के बारे में 200 से अधिक शोध और मूल्यांकन अध्ययन पूरे किए गए हैं।

वर्तमान में आईआईएमसी, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर) द्वारा शुरू किए गए भारत में समाचारों और मनोरंजन मीडिया में महिलाएं विषय पर एक राष्ट्रीय अध्ययन कर रहा है। इस अध्ययन का उद्देश्य महिलाओं के लिए काम के अवसरों, भूमिका और कार्य की स्थितियों के संदर्भ में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के समाचारों और मनोरंजन मीडिया में महिलाओं के चित्रण की पड़ताल करना है।

सामुदायिक रेडियो

आईआईएमसी 2015 से अपना सामुदायिक रेडियो चला रहा है। इसे अपना 'रेडियो 96.9' कहा जाता है। पिछले छह वर्षों से अधिक इस सामुदायिक रेडियो स्टेशन को नया रूप देने के लिए कई पहल की गई हैं। अगस्त 2014 में शुरू हुआ डेली लाइव कार्यक्रम 'अपने आसपास', 'अपना रेडियो' का प्रमुख कार्यक्रम बन गया है। इस कार्यक्रम में श्रोताओं को शामिल करके उनके साथ उस दिन के विषयों पर लाइव चर्चा करने के लिए एक विषय–विशेषज्ञ को स्टूडियो में आमंत्रित किया जाता है या उनसे फोन पर बातचीत की जाती है।

संचार पत्रिकाएं

आईआईएमसी, जनसंचार से संबंधित दो एकसमान समीक्षात्मक पत्रिकाएं हिंदी में **समाचार माध्यम** और अंग्रेजी में कम्यूनिकेटर निकालता है। **कम्यूनिकेटर** का पहला अंक 1965 में प्रकाशित हुआ था, जबकि समाचार माध्यम की शुरुआत 1980 में हुई थी।

ये पत्रिकाएं शिक्षाविदों, अनुसंधान विद्वानों और मीडिया कर्मियों को जनसंचार के क्षेत्र से संबंधित अपने लेख, केस स्टडी और शोध पत्रों को प्रकाशित करने के लिए एक मंच प्रदान करती हैं। इनमें पुस्तकों और शोध लेखों की समीक्षा भी प्रकाशित की जाती हैं।

2018–19 के दौरान संस्थान ने कम्यूनिकेटर के विशेष संस्करण महात्मा **गांधी ऐज़ ए कम्युनिकेटर** में जाने –माने शिक्षाविदों और लेखकों के विद्वतापूर्ण लेख प्रकाशित किए गए। 2018–19 के दौरान आईआईएमसी में भारतीय भाषा पत्रकारिता पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रस्तुत की गई सामग्री पर कम्युनिकेटर का विशेष संस्करण निकाला गया।

स्मारक व्याख्यान

उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने 20 मार्च 2019 को **अटल बिहारी वाजपेयी स्मारक व्याख्यान** में उद्घाटन व्याख्यान दिया। इसका विषय था–''प्रबुद्ध जनमत को बदलने में मीडिया की भूमिका।'' उपराष्ट्रपति ने अपने 45 मिनट के संबोधन में जीवंत लोकतंत्र बनाने में मीडिया के महत्व पर प्रकाश डाला।

मीडिया लाइब्रेरी

आईआईएमसी, दिल्ली में पांच दशकों से अधिक अवधि में निर्मित मीडिया और जनसंचार प्रकाशनों का सबसे बड़ा विशिष्ट पुस्तकालय है। इसमें जनसंचार और संबद्ध विषयों जैसे प्रिंट मीडिया, प्रसारण, विज्ञापन, संचार, संचार अनुसंधान, जनसंपर्क, रेडियो तथा टेलीविजन, फिल्म सूचना प्रौद्योगिकी और पारंपरिक मीडिया के विभिन्न पहलुओं पर 40,000 से अधिक पुस्तकों और जिल्दबंद पत्रिकाओं का संग्रह है। सभी क्षेत्रीय केंद्रों में अपने स्वयं के पुस्तकालय हैं।

बुनियादी ढांचे का विकास

प्लान स्कीम (अब सेंट्रल सेक्टर स्कीम) के तहत आईआईएमसी का उन्नयन कर इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए आईआईएमसी दिल्ली के 16.22 एकड़ के कैंपस के 12,933 वर्गमीटर में एक अकादमिक ब्लॉक, हॉस्टल ब्लॉक और एक अतिथि गृह के निर्माण का प्रस्ताव है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने अपनी रिपोर्ट में अन्य सभी विनियमों का ध्यान रखते हुए, संस्थान के निर्माण की अनुमति देने की सिफारिश की है।

आईआईएमसी के क्षेत्रीय परिसर, निर्माण/पूर्ण होने के विभिन्न चरणों में हैं। कोट्टायम कैंपस इस शैक्षणिक वर्ष में चालू हो गया है। आइजोल में निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और शीघ्र ही इसके संचालित होने की आशा है। जम्मू में निर्माण कार्य प्रगति पर है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 3 फरवरी 2019 को जम्मू कैंपस के लिए ई–शिलान्यास किया था। अमरावती में, महाराष्ट्र सरकार ने बडनेरा में इसके लिए15 एकड़ भूमि आवंटित की है।

वर्ष के दौरान, आईआईएमसी ने स्मार्ट बोर्ड, नवीनतम डिजिटल वीडियो और डीएसएलआर कैमरों, वीडियो एडिटिंग कक्षों और डिजाइन तथा पेज मेकिंग के आधुनिक सॉफ्टवेयर की खरीद करके अपने शिक्षण और प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे का उन्नयन भी किया है।

डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में आईआईएमसी

आईआईएमसी ने संचार तकनीक पर विशेष जोर देने के साथ देश में एक संचार विश्वविद्यालय की स्थापना की दृष्टि से, डी–नोवो श्रेणी के तहत डीम्ड विश्वविद्यालय के लिए आवेदन किया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित समिति की सिफारिश पर डी–नोवो श्रेणी के तहत डीम्ड विश्वविद्यालय बनने के लिए आईआईएमसी को आशय– पत्र जारी किया है।

आशय– पत्र की शर्तों के अंतर्गत आईआईएमसी को नवंबर 2021 तक निम्न शर्तों को पूरा करना होगाः

1. संस्थान, आशय –पत्र जारी होने के 3 साल के भीतर ज्ञान के उभरते क्षेत्रों में कम से कम 5 स्नातकोत्तर विभाग (5 पाठ्यक्रम नहीं) शुरू करेगा।
2. संस्थान प्रस्तावित पाठ्यक्रमों और अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम प्रस्तुत करेगा जो ज्ञान के उभरते क्षेत्रों में प्रस्तावित हैं।
3. संस्थान यूजीसी विनियम, 2016 (संस्थानों के डीम्ड विश्वविद्यालय होने के लिए) के अनुसार प्रत्येक विभाग के लिए, अपेक्षित योग्यता के साथ पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की भर्ती करेगा।
4. संस्थान यूजीसी विनियम, 2016 (संस्थानों के डीम्ड विश्वविद्यालय होने के लिए) के अनुसार अपने एमओए/ नियम प्रस्तुत करेगा।
5. संस्थान यूजीसी के विनियमों, 2016 (संस्थानों के डीम्ड विश्वविद्यालय होने के लिए) के अनुसार अपने मुख्य परिसर और क्षेत्रीय कैंपस में अकादमिक भवनों, केंद्रीय पुस्तकालय, शिक्षकों के निवास, खेल क्षेत्रों आदि जैसी आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करेगा। गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान के लिए भी यूजीसी विनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार आधारभूत ढांचा होना चाहिए।
6. सभी क्षेत्रीय परिसर यूजीसी के विनियमों, 2016 (संस्थानों के डीम्ड विश्वविद्यालय होने के लिए) की आवश्यकता के अनुसार डीम्ड विश्वविद्यालय बनाए जाने वाले संस्थान के ऑफ–कैंपस केंद्र को शुरू करने के लिए लागू होने वाली आवश्यकताओं को पूरा करेंगे।

अन्य प्रमुख गतिविधियां

1. रूस के दूरसंचार और मास मीडिया उपमंत्री श्री एलेक्सी वोलिन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल, ने 5 अप्रैल 2019 को आईआईएमसी का दौरा किया और जनसंचार प्रशिक्षण तथा अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की।
2. आईआईएमसी ने अप्रैल 2019 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून में भारतीय वन सेवा के 2017 बैच के 91 प्रोबेशनर्स के लिए मीडिया प्रबंधन मॉड्यूल का आयोजन किया।
3. इंडिया टुडे ने अपने मई 2019 के अंक में आईआईएमसी को भारत में पत्रकारिता और जनसंचार के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा दिया।
4. इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मालदीव के 20 सदस्यीय मीडिया प्रतिनिधिमंडल ने 4 जुलाई, 2019 को आईआईएमसी का दौरा किया। भूटान के एक अन्य मीडिया प्रतिनिधिमंडल ने 18 नवंबर, 2019 को संस्थान में आधा दिन बिताया, इस दौरान उसे भारत में मीडिया शिक्षा की स्थिति से परिचित कराया गया।
5. आईआईएमसी एलुमनाई एसोसिएशन के नेपाल चैप्टर की पहली बैठक 7 सितंबर, 2019 को काठमांडू में आयोजित की गई थी। काठमांडू में भारत के राजदूत और आईआईएमसी के महानिदेशक ने बैठक को संबोधित किया।
6. आईआईएमसी ने फेसबुक के साथ मिलकर सितंबर 2019 में समाचार साक्षरता पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया जिसमें संस्थान के क्षेत्रीय निदेशक, विभिन्न संस्थानों के मीडिया शिक्षकों और चुनिंदा पत्रकारों ने भाग लिया।
7. महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर, आईआईएमसी के विद्यार्थियों ने एक विशेष अंक– इकोइंग गांधी निकाला। महात्मा गांधी के जीवन और संदेश पर एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के अलावा, गांधी के रूप में एक संवादकर्ता विषय पर एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा

कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

8. अक्टूबर 2019 में, आईआईएमसी ने लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मसूरी के साथ मिलकर फाउंडेशन कोर्स के तहत 350 से अधिक सिविल सेवा प्रोबेशनरों के लिए मास कम्युनिकेशन पर एक मॉड्यूल का संचालन किया।

9. नेशनल वार कॉलेज, महू में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 30 सैन्य अधिकारियों ने 13 अक्टूबर, 2019 को आईआईएमसी का दौरा किया और संकाय सदस्यों के साथ बातचीत की।

10. सरदार वल्लभभाई पटेल की 144वीं जयंती के उपलक्ष्य में 31 अक्टूबर 2019 को राष्ट्रीय एकता दिवस आयोजित किया गया था। संस्थान फिट इंडिया के तहत रन फॉर यूनिटी और 'प्लॉगिंग मार्च' का आयोजन किया गया।

भारतीय प्रेस परिषद

परिचय

भारतीय प्रेस परिषद संवैधानिक अर्ध–न्यायिक स्वायत्त प्राधिकरण है, जिसे संसद के एक कानून प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के तहत प्रेस की स्वतंत्रता सुरक्षित रखने तथा भारत में समाचार–पत्रों और समाचार एजेंसियों के स्तर को बरकरार रखने व उसे सुधारने के दोहरे कार्यों की पूर्ति करने के लिए 1979 में पुनःस्थापित किया गया।

यह परिषद शाश्वत उत्तराधिकार वाली संस्था है। परिषद में एक अध्यक्ष और 28 सदस्य होते हैं। परिपाटी के अनुसार, इसके अध्यक्ष भारत के उच्चतम न्यायालय के वर्तमान/सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, जिन्हें एक समिति द्वारा मनोनीत किया जाता है, जिसके सदस्यों में राज्य सभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष और परिषद के सदस्यों के बीच से चुना गया एक व्यक्ति शामिल होता है। इसके 28 सदस्यों में से 20 विशेषतौर पर प्रेस के निर्धारित खंड का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा इसके 8 अन्य सदस्य–संसद के दोनों सदनों तथा देश के प्रमुख साहित्यिक एवं विधिक निकायों यथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय विधि परिषद तथा साहित्य अकादमी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल की अवधि तीन वर्ष होती है।

अधिनियम की धारा 13 में सम्मिलित किए गए प्रेस परिषद के उत्तरदायित्वों में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करना और समाचार–पत्रों व समाचार एजेंसियों के स्तर को बनाए रखना तथा उसमें सुधार लाना शामिल है। यह अधिनियम परिषद सलाहकार की भूमिका भी प्रदान करता है, जिसके तहत यह या तो स्वयं संज्ञान लेकर या कानून की धारा 13(2) के तहत सरकार द्वारा संदर्भित किए जाने पर वह प्रेस से संबंधित किसी भी विधेयक, विधान, कानून या अन्य मामलों का अध्ययन करती है और उनके बारे में सरकार को या अन्य संबद्ध व्यक्ति को अपनी राय से अवगत कराती है। सार्वजनिक महत्व के मामलों में भी, परिषद अपने संवैधानिक उत्तरदायित्वों के तहत स्वतः संज्ञान ले सकती है और मौके पर जांच करने के लिए विशेष समिति का गठन कर सकती है।

शिकायतों के मामलों में परिषद –चाहे वे प्रेस के खिलाफ पत्रकारिता के आदर्शों के उल्लंघन की शिकायत हो या प्रेस द्वारा अपनी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप की शिकायत हो, अधिनिर्णय के माध्यम से प्रमुख रूप से अपने कार्यों का निर्वहन करती है। जांच के बाद यदि परिषद इस बात पर आश्वस्त हो जाती है कि किसी समाचार–पत्र या समाचार एजेंसी ने पत्रकारिता के आदर्शों के मानकों या लोक रुचि का उल्लंघन किया है अथवा किसी संपादक या श्रमजीवी पत्रकार ने कोई पेशेवर कदाचार किया है, तो परिषद उन्हें चेतावनी दे सकती है, डांट सकती है या उनकी भर्त्सना कर सकती है या उनके आचरण की निंदा कर सकती है। प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में परिषद के पास यह अधिकार है कि वह प्रेस की स्वतंत्रता में बाधक सरकार सहित किसी भी संस्था के आचरण पर अपनी टिप्पणी कर सकती है। धारा (4) के तहत परिषद के निर्णय अंतिम होते हैं और न्यायालय में इन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती।

संसद के एक अधिनियम के तहत गठित होने के कारण परिषद को अपने कोष का एक बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार से अनुदान सहायता के रूप में संसद द्वारा उचित विनियोजन के बाद प्राप्त होता है, क्योंकि समाचार–पत्रों से ग्रेडेड या श्रेणीबद्ध संरचना के तहत एकत्र की जाने वाली फीस और अन्य प्राप्तियों के माध्यम से इसके पास अपना धन भी होता है।

वित्त वर्ष 2019–20 के लिए कौंसिल द्वारा स्वीकृत बजट 7.45 करोड़ रुपये का है।

परिषद के समक्ष शिकायतें

समीक्षाधीन अवधि 1 अप्रैल, 2019 से 30 नवंबर, 2019 तक के दौरान, परिषद में कुल **611** शिकायतें पहुंचीं। इनमें

से, **175** शिकायतें प्रेस की स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए सरकार के अधिकारियों के खिलाफ प्रेस द्वारा की गई थीं और **436** शिकायतें पत्रकारिता के आदर्शों के उल्लंघन के लिए प्रेस के खिलाफ की गई थीं। पिछले वर्ष से लंबित **747** मामलों सहित परिषद को कुल 1337 मामलों का निपटान करना था। इनमें से, 815 मामलों को या तो अधिनिर्णय के माध्यम से या अध्यक्ष की मध्यस्थता से हुए समझौते पर अध्यक्ष द्वारा संक्षिप्त निपटान के माध्यम से या पूछताछ के लिए पर्याप्त आधार न होने या गैर–अनुपालन के कारण; मामला वापस लेने या विचाराधीन होने के कारण वर्ष के दौरान निपटाया गया। इनमें से 522 मामलों में से दो मामलों को अधिनिर्णय के लिए सीधे परिषद के समक्ष रखा गया था। वर्ष के अंत में कुल मिलाकर 520 मामलों पर कार्रवाई की जा रही थी।

परामर्श कार्य

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान परिषद को उसकी परामर्शदाता की हैसियत से विभिन्न मुद्दों पर पत्रकारिता संबंधी नैतिकता के बारे में सरकार या अन्य प्राधिकरणों द्वारा भेजे जाने वाले या अन्य मुद्दों पर निम्न प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है।

1. आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी से संबंधित विज्ञापन प्रकाशित करते समय सावधानी बरतने के बारे में औषधि और सौंदर्य प्रसाधन नियम (संशोधन) में नियम 170 (3) और 170 (4) (iv) शामिल किए गए।
2 आम चुनाव के दौरान चुनाव प्रक्रिया पर मीडिया और प्राधिकरणों को परामर्श दिया।
3 मीडिया को जनप्रतिनिधित्व कानून,1951 के अनुच्छेद 126 क का उल्लंघन न करने की सलाह दी।
4 मानसिक बीमारी और आत्महत्या के मामलों की रिपोर्टिंग के लिए दिशानिर्देश जारी किए।
5 खाद्य सुरक्षा पर गैर–जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग के बारे में चिंता व्यक्त की।

परिषद ने मीडियाकर्मियों के खिलाफ हिंसा और प्रेस की स्वतंत्रता के लिए खतरे के निम्नलिखित मामलों में स्वतः संज्ञान लिया।

1. .एक फिल्म निर्देशक और निर्माता को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए रोकने पर आंध्र प्रदेश सरकार के खिलाफ स्वतः संज्ञान लिया।
2. शामली (उ.प्र.) में रेलवे पुलिस द्वारा पत्रकार, श्री अमित शर्मा पर हमले के मामले में स्वतः संज्ञान लिया।
3. चंडीगढ़ में पत्रकारों पर पुलिस कार्रवाई के मामले में स्वतः संज्ञान लिया।
4. जनसंदेश टाइम्स, मीरापुर (उ.प्र.) के संवाददाता श्री पवन जायसवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के संबंध में स्वतः संज्ञान लिया।
5. आंध्र ज्योति के पत्रकार श्री के. सत्यनारायण की मृत्यु पर स्वतः संज्ञान लिया।
6. आंध्र प्रदेश सरकार के दिनांक 30.10.2019 के जी.ओ. आर.टी. नं. पर स्वतः संज्ञान लिया।

प्रेस और पंजीकरण अपीलीय बोर्ड

प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 की धारा 8ग के तहत भारतीय प्रेस परिषद को अनुच्छेद 6 के तहत घोषणा के गैर–प्रमाणीकरण के मजिस्ट्रेट के आदेश पर या उक्त अधिनियम की धारा 8ख के तहत बाद में इसके रद्द होने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अपीलीय बोर्ड में एक अध्यक्ष और भारतीय प्रेस परिषद द्वारा इसके सदस्यों में से नामित एक सदस्य होता है।

दो बेंच बोर्ड जिसमें माननीय अध्यक्ष के साथ वैकल्पिक सदस्यों के रूप में श्री यू.सी. शर्मा/प्रो सुषमा यादव शामिल हैं, ने 1 अप्रैल, 2019 से 30 नवंबर, 2019 के बीच 4 बैठकें कीं। इनमें 16 अपीलों पर विचार किया गया। इनमें से 2 का निस्तारण किया गया, 13 को अलग रखा गया और एक अपील में बोर्ड ने इसे परिषद के समक्ष रखने का निर्देश दिया, और परिषद ने इसे विचार के लिए जांच समिति को भेज दिया।

राष्ट्रीय प्रेस दिवस, 2019

राष्ट्रीय प्रेस दिवस समारोह हर साल आयोजित किया जाता है और इस वर्ष, देशव्यापी चर्चा का विषय था, रिपोर्टिंग–व्याख्याः एक यात्रा।

नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू मुख्य अतिथि थे और सूचना एवं प्रसारण और पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री माननीय श्री प्रकाश जावड़ेकर सम्मानित अतिथि थे। भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति चंद्रमौली कुमार प्रसाद ने समारोह की अध्यक्षता की। पांच देशों यानि बांग्लादेश, भूटान, म्यामां, नेपाल और श्रीलंका की प्रेस परिषदों के प्रतिनिधियों ने उपरोक्त विषय पर पैनल चर्चा में भाग लिया।

उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू 16 नवंबर, 2019 को नई दिल्ली में, राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर, भारतीय प्रेस परिषद द्वारा आयोजित समारोह में सभा को संबोधित करते हुए

इस अवसर पर भारत के माननीय उपराष्ट्रपति, श्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा कि प्रेस, भ्रष्टाचार और महिला–पुरुष असमानता तथा जातिगत भेदभाव जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर करने की आवश्यकता पर जनता की राय बनाने में सकारात्मक भूमिका निभा सकती है। उन्होंने कहा कि मीडिया को विकासात्मक समाचारों और कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को अधिक स्थान देना चाहिए। श्री नायडू ने यह भी कहा कि मीडिया को स्व–विनियमन, सटीकता, निष्पक्षता, औचित्य, वस्तुनिष्ठता, समाचार पात्रता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करनी चाहिए क्योंकि इन मूलभूत मूल्यों से कभी समझौता नहीं किया जाएगा।

माननीय सूचना एवं प्रसारण और पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपने भाषण में जिम्मेदारीपूर्ण स्वतंत्रता की आवश्यकता पर जोर दिया और फर्जी समाचारों के बारे में भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ये इन दिनों पेड न्यूज से भी अधिक खतरनाक हैं और इनसे प्रभावी तरीके से निपटने की आवश्यकता है।

भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति चंद्रमौली कुमार प्रसाद ने एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि डब्ल्यू से शुरू होने वाले अंग्रेजी के पांच शब्द–हू यानि कौन, व्हाट् यानि क्या, वैन यानि कब, वेयर यानि कहां और वाए यानि क्यों सुनहरे शब्द हैं जो निष्पक्ष रिपोर्टिंग के लिए मार्गदर्शन करते हैं।

माननीय अध्यक्ष आशावादी थे और उनका मानना था कि दोषों पर बात करना भी इनमें सुधार करने का एक तरीका है। भारतीय मीडिया, जो हमारे देश की रीढ़ है, वह सम्मान और ईमानदारी के साथ खड़ा होने का हर दिन बेहतर प्रयास कर सकता है।

राष्ट्रीय प्रेस दिवस, 2019 के अवसर पर भारत के माननीय उपराष्ट्रपति ने परिषद के प्रकाशनों – परिषद की निर्देशिका, अपडेटेड नॉर्म्स ऑफ जर्नलिस्टिक कंडक्ट, संस्करण 2019 और स्मारिका, 2019 को 16.11.2019 को जारी किया।

भारत के माननीय उपराष्ट्रपति ने पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, 2019 प्रदान किए। ये पुरस्कार सात श्रेणियों में दिए गए। **राजा राम मोहन राय पुरस्कार** श्री

गुलाब कोठारी को, **ग्रामीण पत्रकारिता** पुरस्कार श्री राज चेंगप्पा और श्री संजय सैनी को संयुक्त रूप से दिया गया था। **विकासात्मक रिपोर्टिंग** का पुरस्कार श्री शिव स्वरूप अवस्थी तथा श्री अनु अब्राहिम को संयुक्त रूप से दिया गया। श्री पी. जी. उन्नीकृष्णन और श्री अखिल ई.एस. को संयुक्त रूप से **फोटो पत्रकारिता– सिंगल न्यूज पिक्चर** सम्मान से और सुश्री शिप्रा दास को **फोटो फीचर** के लिए सम्मानित किया गया। श्री सौरभ दुग्गल को **स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग/स्पोर्ट्स फोटो फीचर** पुरस्कार प्रदान किया गया। श्री संदीप सिंह तथा श्री कृष्ण कौशिक को एक ही लेख के लिए संयुक्त रूप से **वित्तीय रिपोर्टिंग** पुरस्कार प्रदान किया गया। **जेंडर बेस्ड रिपोर्टिंग** का पुरस्कार संयुक्त रूप से सुश्री रूबी सरकार और सुश्री अनुराधा मस्कारेन्हास को संयुक्त रूप से दिया गया था।

15 नवंबर, 2019 को बांग्लादेश, भूटान, म्यामां, नेपाल और श्रीलंका की प्रेस/मीडिया परिषदों ने रिपोर्टिंग–व्याख्याः एक यात्रा विषय पर एक गोलमेज सम्मेलन में चर्चा की।

देश भर में विभिन्न मंचों पर विचार–विमर्श किया गया था और इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रिंट मीडिया द्वारा व्यापक रूप से कवर किया गया था।

संक्षेप में परिणाम इस प्रकार हैं:

1. रिपोर्टिंग–व्याख्याः एक यात्रा पर विचार–विमर्श को बढ़ावा देना और जिम्मेदार स्वतंत्रता तथा राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिपोर्टिंग और व्याख्या को प्रभावित करने वाले विभिन्न अन्य कारकों के लिए मीडिया की आवश्यकता उत्पन्न करना।
2. मीडिया बिना किसी विकृति/व्याकुलता के केवल तथ्यात्मक रिपोर्टिंग प्रस्तुत करने के लिए दीर्घकालिक उद्देश्य के साथ व्याख्यात्मक समाचारों के बीच असाधारण संतुलन पर आत्मनिरीक्षण करेगा।
3. विविध श्रेणियों को कवर करने वाले पत्रकारिता लेखन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कार देकर पत्रकारिता के उच्च मानदंडों को प्रोत्साहित करना।
4. राष्ट्र की सेवा के लिए बदलते रुझानों के साथ, पत्रकारों और समाचारपत्रों के मानकों को बनाए रखकर और उनमें सुधार करके पत्रकारिता के आचार–व्यवहार के अद्यतन मानदंडों का संस्करण 2019 निकाला।

अंतरराष्ट्रीय संवाद

वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष प्रो. डॉ. सुले अकेर के निमंत्रण पर, भारतीय प्रेस परिषद के दो सदस्यों –श्री कमल नयन नारंग और श्री प्रदीप कुमार जैन का एक प्रतिनिधिमंडल, वार्षिक आम बैठक में भाग लेने के लिए बाकू, अजरबैजान गए। 11 सितंबर से 15 सितंबर, 2019 तक आयोजित इस बैठक में अंतरराष्ट्रीय मीडिया में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सुरक्षा के बारे में समस्याओं और विकास पर चर्चा की गई। 2019 में 22–25 सितंबर तक प्रेस काउंसिल नेपाल के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेने के लिए उसके निमंत्रण पर परिषद के दो सदस्यों– श्री ओम प्रकाश खेमकर्णी और श्री श्याम सिंह पंवार के प्रतिनिधिमंडल ने काठमांडू का दौरा किया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के अनुच्छेद 13 (2) (ख), (ग) और (घ) के आदेश के अनुसार, भारतीय प्रेस परिषद ने प्रत्येक सत्र में पत्रकारिता के छात्रों के लिए वर्ष में 30 दिनों की अवधि का प्रशिक्षण यानी ग्रीष्म प्रशिक्षण कार्यक्रम और शरद प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है।

शुल्क

भारतीय प्रेस परिषद, प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के अनुच्छेद 16 (1) के तहत अपने कार्यों के संचालन के लिए 25,000 और उससे अधिक की प्रसार संख्या वाले पंजीकृत समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दर पर शुल्क लेती है। इसके लिए परिषद ने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, नकद, एनआरएफटी/आरटीजीएस के जरिए यूपीआई में भुगतान के साथ भुगतान के नए तरीके अपनाए हैं और यह जानकारी परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

राजभाषा

14 सितंबर को समूचे भारत में 'हिंदी दिवस' के रूप में मनाया जाता है। हर साल की तरह, हिंदी के उपयोग पर जोर देने के लिए, परिषद के सचिवालय में 14.9.2019 से 27.9.2019 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया।

हिंदी दिवस का मुख्य समारोह 27 सितंबर, 2019 को आयोजित किया गया था। इस अवसर पर महाकवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन और लेखन पर वृत्तचित्र फिल्म परिषद के सचिवालय में दिखाई गई। तत्पश्चात, भारतीय प्रेस परिषद के माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री चंद्रमौली

कुमार प्रसाद और सचिव श्रीमती अनुपमा भटनागर ने संदेश दिया और परिषद के कर्मचारियों को हिंदी में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके अलावा, वर्ष 2018–19 के दौरान हिंदी शिक्षण योजना के तहत अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को प्रमाण पत्र भी दिए गए।

सतर्कता रिपोर्ट

भारतीय प्रेस परिषद का सचिव, कार्यालय का मुख्य सतर्कता अधिकारी होता है। परिषद के सतर्कता ढांचे में शामिल अवर सचिव (प्रशासन) और अनुभाग अधिकारी (प्रशासन), सतर्कता सचिव (मुख्य सतर्कता अधिकारी) और परिषद के अध्यक्ष के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में काम करते हैं। इसने सचिवालय में भ्रष्टाचार को रोकने/निपटने के लिए औचक और नियमित रूप से जांच की।

इस अवधि के दौरान सचिवालय में सतर्कता जांच का कोई मामला सामने नहीं आया।

उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू फिल्म 'अंधाधुंध' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का रजत कमल पुरस्कार आयुष्मान खुराना को प्रदान करते हुए। यह पुरस्कार 46वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार महोत्सव में 23 दिसंबर, 2019 को नई दिल्ली में दिया गया। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा भारी उद्यम और लोक उपक्रम मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री रवि मित्तल भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे

24 दिसंबर, 2019 को नई दिल्ली में 44वें आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, सूचना एवं प्रसारण तथा भारी उद्यम और लोक उपक्रम मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर। साथ में हैं प्रसार भारती के चेयरमैन डॉ. ए. सूर्य प्रकाश एवं गणमान्य व्यक्ति

5 प्रसारण क्षेत्र की गतिविधियां

विहंगावलोकन

प्रसारण क्षेत्र को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है– 'कंटेंट' यानी अंतर्वस्तु और 'कैरिएज सर्विस' प्रसारित करने वाली सेवा। मंत्रालय निजी उपग्रह चैनलों की अंतर्वस्तु और मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों के नेटवर्क तथा स्थानीय केबल ऑपरेटरों को केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (विनियमन) अधिनियम, 1995 तथा समय–समय पर जारी नीति संबंधी दिशानिर्देशों के जरिए विनियमित करता है। प्रसारण कैरिएज सेवाओं में मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स (एमएसओ)/स्थानीय केबल ऑपरेटर (एलसीओ), डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) ऑपरेटर, हेडएंड इन द स्काई (एचआईटीएस) ऑपरेटर और इंटरनेट प्रोटोकोल टेलीविजन (आईपीटीवी) सेवा प्रदाता शामिल हैं। मंत्रालय डीटीएच/एचआईटीएस ऑपरेटरों को उनकी गतिविधियों के लिए लाइसेंस भी जारी करता है।

डायरेक्ट टू होम (डीटीएच)

डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) एक निश्चित लक्ष्य या पते पर प्रसारण को पहुंचा सकने वाली प्रणाली है जिसके अंतर्गत समूचा देश शामिल है। डीटीएच सेवा में बड़ी संख्या में टेलीविजन चैनलों को डिजिटल तरीके से कम्प्रेस और एनक्रिप्ट करके उपग्रह के अत्यंत शक्तिशाली केयू बैंड के जरिए एक खास दिशा में प्रसारित किया जाता है। डीटीएच के जरिए प्रसारित कार्यक्रमों को मकान में किसी उपयुक्त स्थान पर डिश लगाकर सीधे घरों में रिसीव किया जा सकता है। देश के पहले डीटीएच सेवा प्रदाता ने 2003 में अपनी सेवाएं चालू कीं और 2007 तक इनकी संख्या बढ़कर छह हो गयी थी। इन छह डीटीएच सेवा प्रदाताओं में से दो का आपस में विलय हो गया। इस समय निजी डीटीएच ऑपरेटरों की संख्या पांच रह गयी है। इसके अलावा दूरदर्शन भी अपनी मुफ्त डीटीएच प्रसारण सेवाएं उपलब्ध करा रहा है।

हेडएंड इन द स्काई (हिट्स)

हेडएंड इन द स्काई (हिट्स) उपग्रह टेलीविजन और केबल टीवी का मिला–जुला रूप है। हिट्स ऑपरेटर टीवी प्रसारण को उपग्रह से जोड़ता है जिसे एमएसओ/एलसीओ द्वारा डाउनलिंक कर केबल नेटवर्क के जरिए उपभोक्ताओं के घरों तक पहुंचाया जाता है। इस तरह हिट्स ऑपरेटर ग्राहकों को केबल टीवी नेटवर्क के माध्यम से सिग्नल उपलब्ध कराते हैं। हिट्स ऑपरेटर और मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ) में बुनियादी फर्क सिर्फ इतना है कि हिट्स ऑपरेटर उपग्रह के माध्यम से केबल ऑपरेटरों को चैनलों के समूचे बंडल का प्रसारण करता है जबकि एमएसओ केबल के जरिए यह कार्य करता है। हिट्स अपने ग्राहकों को डिजिटल चैनलों का आनंद लेने के कई विकल्प प्रदान करता है। इसकी प्रसारण की गुणवत्ता भी श्रेष्ठ होती है और इसकी मूल्य सवंर्धित सेवाएं किफायती दामों पर उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने अब तक सिर्फ छह हिट्स ऑपरेटरों को लाइसेंस जारी किए हैं जिनमें से केवल एक हिट्स ऑपरेटर कार्य कर रहा है।

खेल प्रसारण सिग्नल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य साझेदारी) अधिनियम, 2007

खेल प्रसारण सिग्नल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य साझेदारी) अधिनियम, 2007 भारत तथा विदेशों में आयोजित राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं के निःशुल्क प्रसारणों को अधिक से अधिक श्रोताओं तक पहुंच बनाने के लिए बनाया गया है। अधिनियम का अनुच्छेद 2(1)(एस) केंद्र सरकार को राष्ट्रीय महत्व के खेल आयोजनों को अधिसूचित करने का अधिकार प्रदान करता है ताकि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उनकी कवरेज की जा सके। मंत्रालय राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय महत्व के किसी खास खेल–कूद आयोजन/आयोजनों को राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय महत्व का होने की अधिसूचना समय–समय पर जारी करता रहता है ताकि निःशुल्क प्रसारित किए जाने वाले चैनलों के जरिए अधिक से अधिक श्रोता उनका आनंद उठा सकें।

प्रसारण क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुख गतिविधियां

(क) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 7.05.2019 को 'डीडी अरुणाभा' को तमाम प्रसारण प्लेटफार्म्स के आपरेटरों जैसे एमएसओ/एलसीओ/डीटीएच/एचआईटीएस/आईपीटीवी ऑपरेटरों द्वारा अनिवार्य रूप से प्रसारित किए जाने वाले चैनल के रूप में अधिसूचित किया।

(ख) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 11.09.2019 को श्रवण बाधित लोगों के लिए टेलीविजन कार्यक्रमों की पहुंच संबंधी मानदंड जारी किए ताकि ऐसे व्यक्ति इनका फायदा उठा सकें।

भारत में उपग्रह टीवी चैनलों की स्थिति

1) नीति

भारत में 2000 में पहले उपग्रह टेलीविजन चैनल को देश से अपलिंक करने की इजाजत दी गयी। इससे पहले निजी टीवी चैनलों को विदेशों से ही अपलिंक किया जा

सकता था। जनसंचार माध्यमों और मनोरंजन क्षेत्र के विकास से टेलीविजन चैनलों को भारत से अपलिंक/डाउन लिंक करने की मांग कई गुना बढ़ गयी थी, जिससे इस बारे में नीति संबंधी दिशानिर्देश बनाना जरूरी हो गया था। इसके लिए 2002 में अपलिंकिंग के तथा 2005 में डाउनलिंकिंग के दिशानिर्देश तैयार किए गए। ये दिशानिर्देश मंत्रालय की वेबसाइट www.mib.gov.in पर उपलब्ध हैं।

क. टेलीविजन चैनलों की संख्या में बढ़ोतरी

1. पहले निजी उपग्रह टेलीविजन चैनल 'आजतक' को वर्ष 2000 में स्वीकृति प्रदान की गयी। तब से भारत में निजी उपग्रह टीवी चैनलों के गुलदस्तों का बड़ी तेजी से विस्तार हो रहा है। मंत्रालय 31.12.2019 तक 918 चैनलों को स्वीकृति प्रदान कर चुका था। अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग दिशानिर्देशों के अंतर्गत स्वीकृत टेलीविजन चैनलों का वर्ष वार विवरण नीचे दिया गया है:

मंत्रालय द्वारा स्वीकृत टेलीविजन चैनलों की संख्या

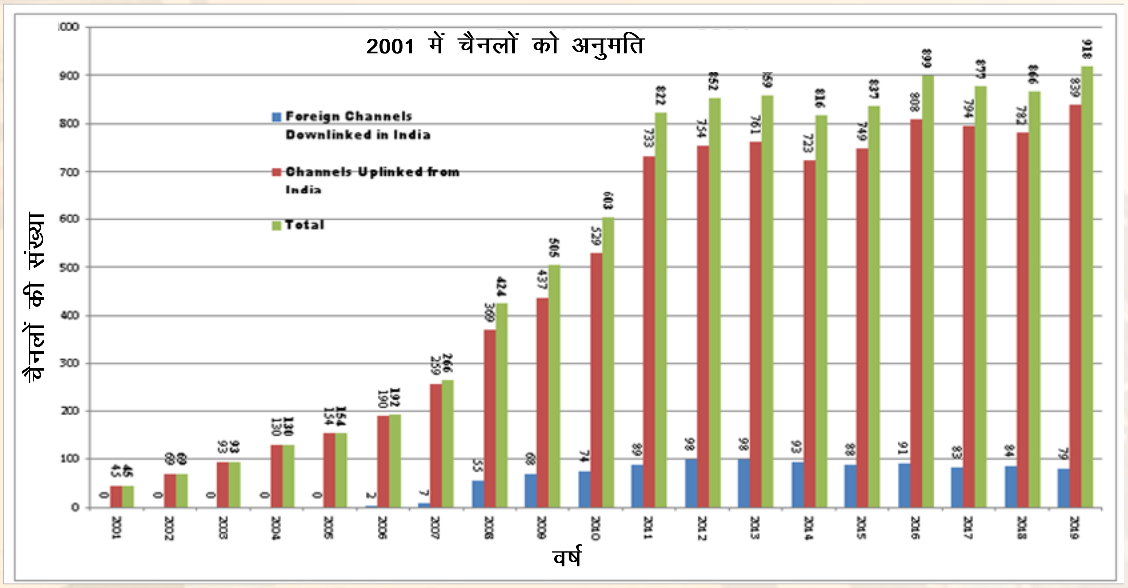

2. मंत्रालय केवल दो श्रेणियों के अंतर्गत टीवी चैनलों के संचालन की अनुमति प्रदान करता है–'समाचार और समसामयिक मामलों के टीवी चैनल' और 'समाचार और समसामयिक मामलों से अलग टीवी चैनल'। मंत्रालय द्वारा स्वीकृत कुल टीवी चैनलों में से समाचार और गैर–समाचार चैनलों का हिस्सा नीचे दर्शाया गया है। (392 समाचार और 526 गैर–समाचार)।

श्रेणी वार स्वीकृत चैनल
अनुमति दी गई टीवी चैनल
समाचार और गैर–समाचार

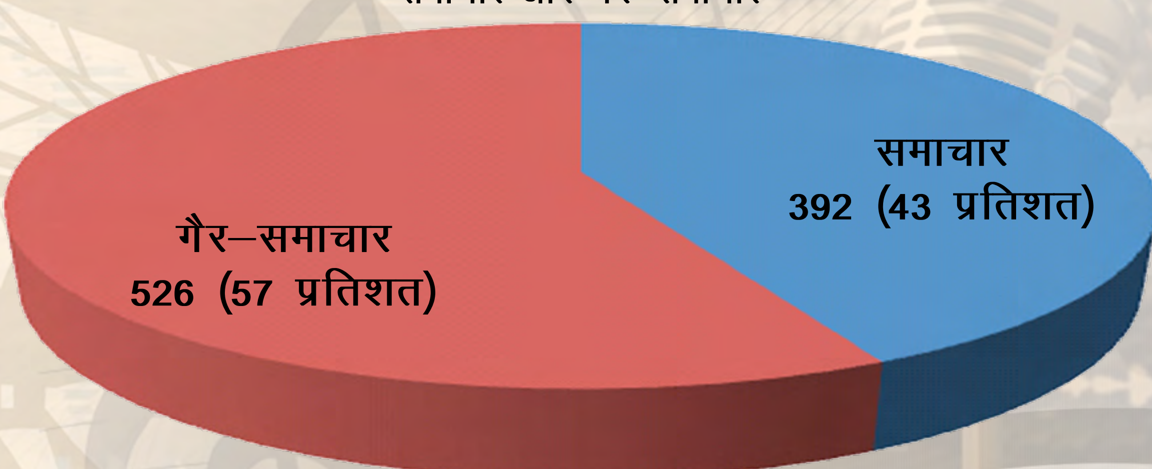

ख. टेलीपोर्ट्स का विकास : 31.12.2019 की स्थिति–70 टेलीपोर्ट्स

मंत्रालय द्वारा स्वीकृत टेलीपोर्ट्स की संख्या

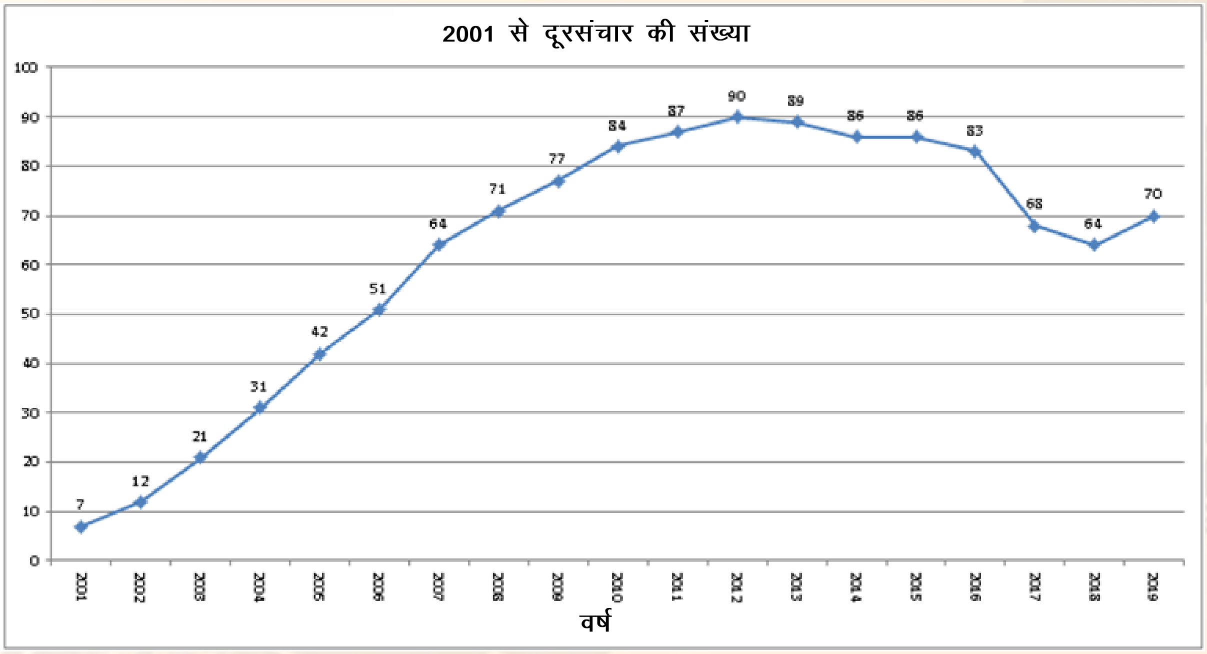

2) नयी पहल

क. प्रसारण स्कंध के ऑटोमेशन की योजना

कंपनियों के लंबित मुद्दों के बारे में और अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 21 जनवरी, 2010 को चालू की गयी उपग्रह टेलीविजन अनुप्रयोग ट्रैकिंग प्रणाली के स्थान पर मौजूदा स्वीकृति धारकों/आवेदकों के लिए डेटा के पूर्ण डिजिटाइजेशन की प्रणाली अपनायी जा रही है। ऑटोमेशन परियोजना के एक भाग के रूप में इस परियोजना को बेसिल द्वारा चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत मंत्रालय ने सभी प्रसारण सेवाओं के लिए ब्रॉडकास्टसेवा नाम का एक पोर्टल विकसित किया है ताकि वे प्रसारण क्षेत्र के विकास और प्रबंधन के लिए कुशल और पारदर्शी व्यवस्था बनायी जा सके। ब्रॉडकास्टसेवा अपने निम्नलिखित माड्यूल के जरिए आवेदकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराती है:

1. मौजूदा प्रसारकों द्वारा वार्षिक अनुमति शुल्क का भुगतान
2. अस्थायी अपलिंकिंग अनुमति के लिए आवेदन
3. टेलीपोर्ट लगाने के लिए अनुमति
4. विदेशी मुद्रा प्रेषण के लिए आवेदन
5. चैनल में विभिन्न बदलावों, जैसे नाम और प्रतीक चिह्न में परिवर्तन, उपग्रह में परिवर्तन, टेलीपोर्ट और उसकी स्थिति में बदलाव, चैनल की श्रेणी/भाषा तथा प्रसारण के प्रकार में बदलाव के लिए आवेदन।

3) पारदर्शिता और जवाबदेही लाना

1. ओपन हाउस बैठकें

प्रसारकों के साथ हर महीने आयोजित की जाने वाली 'ओपन हाउस' बैठकें बड़ी उपयोगी साबित हुई हैं। इन बैठकों में शामिल होने वाले प्रसारकों की संख्या पिछले एक साल में बहुत बढ़ी है। बैठकों से प्राप्त फीडबैक से मंत्रालय को स्वीकृति प्रदान करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के नये उपाय करने और पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिली है। इन बैठकों से आवेदकों को मंत्रालय के अधिकारियों से न केवल सीधे संपर्क का अवसर प्राप्त हुआ है, बल्कि इनसे उन्हें लगातार सीधे सूचनाएं भी मिलने लगी हैं जिससे किसी बिचौलिए की कोई आवश्यकता नहीं रह गयी है।

2. ऑनलाइन आवेदनों/प्रस्तावों की लाइव ट्रैकिंग

आवेदक कंपनियां (प्रसारक/टेलीपोर्ट ऑपरेटर) अब अपने ऑनलाइन आवेदनों के बारे में वेब पोर्टल www.broadcastseva.gov.in पर जाकर लाइव ट्रैकिंग के जरिए आवेदन की स्थिति का पता कर सकते हैं। इस संबंध में प्रसारकों को अपने आवेदनों को लाइव ट्रैक करने के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के बारे में बता दिया गया है।

4. मानक फॉर्म और आवेदन

कंपनी से सूचना प्राप्त करने और स्वीकृति की प्रक्रिया को चुस्त–दुरुस्त कर दिया गया है। इसके तहत सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने की समयावधि कम कर दी गयी है और अब यह प्रकिया तेजी से निपटने लगी है।

टेलीविजन चैनलों की अंतर्वस्तु का विनियमन

मंत्रालय ने 917 निजी उपग्रह टेलीविजन चैनलों को मंजूरी दी है जिसमें से 534 समाचार और समसामयिक विषयों से इतर चैनल हैं। समाचार और समसामयिक विषयों के चैनलों की संख्या 393 है।

2. केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (विनियमन) अधिनियम, 1995 और भारत से टीवी चैनलों की अपलिंकिंग की 2011 की नीति के अनुसार प्रत्येक ब्राडकास्टर के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता का पालन करना अनिवार्य है

3. वर्ष के दौरान जहां कहीं कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता के उल्लंघन की पुष्टि हुई, मंत्रालय ने केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत उचित कार्रवाई की और जहां कहीं जरूरी हुआ परामर्श, चेतावनी, क्षमा याचना करने के आदेश आदि जारी किए।

4. वर्ष 2018–19 के दौरान (नवंबर, 2019 तक) मंत्रालय ने चैनलों को जो परामर्श, चेतावनियां और आदेश जारी किए उनका विवरण नीचे दिया गया है:

1) 12 सामान्य परामर्श – ये परामर्श टीवी चैनलों को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार दिए गए :

क्र. सं.	विषय वस्तु	परामर्श की तिथि
1	गणतंत्र दिवस समारोह/परेड का सांकेतिक भाषा में निर्वचन के साथ प्रसारण	24.01.2018
2	माननीय बम्बई उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिए 'दलित' नाम का उपयोग से बचना और भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत अधिसूचित राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार सभी आधिकारिक गतिविधियों, मामलों, व्यवहार, प्रमाणपत्र आदि में संवैधानिक अंग्रेजी शब्द 'शेड्यूल्ड कास्ट' और अन्य राष्ट्रीय भाषाओं में इसके उपयुक्त अनुवाद का ही उपयोग करना	07.08.2018
3	स्वतंत्रता दिवस समारोह/कमेंट्री का सांकेतिक भाषा में निर्वचन के साथ प्रसारण	13.08.2018
4	किशोर न्याय अधिनियम और पोक्सो अधिनियम के अनुपालन में बच्चों की पहचान उजागर न करना	10.10.2018
5	गणतंत्र दिवस समारोह/परेड का संकेत भाषा में निर्वचन के साथ प्रसारण	24.01.2019
6	पुलवामा (जम्मू–कश्मीर) प्रकरण के मद्देनजर कार्यक्रम संहिता के नियम 6 (1)(ई) और (एच) का अनुपालन	14.02.2019
7	महिला सुरक्षा/संकटग्रस्त व्यक्तियों के एमरजेंसी रिस्पोंस सपोर्ट सिस्टम (ईआएसएस) का प्रचार	05.03.2019
8	हिंदी/क्षेत्रीय भाषा के टीवी सीरियलों में पात्रों की भूमिका/आभार/शीर्षक को संबंधित भाषाओं में भी दिखाना	14.06.2019
9	नृत्य पर आधारित रिएलिटी शो में बच्चों के भौंडे, अश्लील, कामोद्दीपक और अनुचित तरीके से चित्रण	18.06.2019
10	टीवी कार्यक्रमों तक दिव्यांगों की पहुंच के मानदंडों के अनुसार स्वतंत्रता दिवस समारोह/आंखों देखा हाल का सांकेतिक भाषा के साथ प्रसारण	14.08.2019
11	अयोध्या मालिकाना हक विवाद के सिलसिले में कार्यक्रम संहिता के नियम 6(1)(6),(सी), (डी), (ई), (एफ), (एच) और (आई) पर कड़ाई से अमल	09.11.2019
12	भविष्य में भारत के नये राजनीतिक मानचित्र का उपयोग करने संबंधी	18.11.2019

2) 29 खास परामर्श – टीवी चैनलों को परामर्श दिया गया कि वे कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता का पालन करें।

3) 39 चेतावनियां – टीवी चैनलों को चेतावनी दी गयी कि कार्यक्रम और विज्ञापन संहित का कड़ाई से पालन करें।

4) 30 आदेश – टीवी चैनलों को निर्देश दिया गया कि वे क्षमा याचना स्क्रॉल जारी करें।

5) 4 आदेश – चैनलों को निर्देश दिया गया कि वे अलग–अलग अवधियों के लिए प्रसारण बंद करें।

अंतर–मंत्रालयी समिति

5. उपग्रह टीवी चैनलों पर अंतर्वस्तु के विनियमन के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अपर सचिव की अध्यक्षता में एक अंतर–मंत्रालयी समिति गठित की गयी है जिसमें गृह मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय, महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विदेश, रक्षा तथा उपभोक्ता मामलों के मंत्रालयों के अलावा भारतीय विज्ञापन मानदंड परिषद में इस उद्योग के प्रतिनिधि को शामिल किया गया है। समिति संहिता का उल्लंघन हुआ है या नहीं हुआ है, इस बारे में अपनी सिफारिशें देती है। अंतर–मंत्रालय समिति केवल सिफारिशें करती है। दंड देने के बारे में अंतिम निर्णय और इसके परिमाण के बारे में फैसला अंतर मंत्रालयी समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है।

इलेक्ट्रानिक मीडिया निगरानी केंद्र

6. सरकार ने अत्याधुनिक सुविधाओं वाले इलेक्ट्रानिक मीडिया निगरानी केंद्र की स्थापना की है ताकि केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (विनियमन) अधिनियम, 1995 और इसके अंतर्गत बने नियमों के तहत निर्मित कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता के प्रावधानों के तहत टीवी प्रसारणों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय निगरानी समितियां

7. राज्य, जिला/स्थानीय स्तर पर केबल अधिनियम और इससे संबंधित नियमों को लागू करने और केबल टेलीविजन चैनलों द्वारा प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों और विज्ञापनों की निगरानी समिति से निगरानी कराने के लिए मंत्रालय ने 6 सितंबर, 2005 को एक आदेश जारी किया। इसके बाद 19 फरवरी, 2008 को मंत्रालय ने विस्तृत दिशानिर्देश भी जारी किए जिनमें जिला और राज्य स्तरीय निगरानी समितियां बनाने की भी व्यवस्था है। लेकिन बाद में पिछले सभी आदेशों को समेकित कर जिला/राज्य स्तरीय निगरानी समितियां गठित करने संबंधी उपर्युक्त विस्तृत दिशानिर्देश बनाकर 26 अप्रैल, 2017 को कार्यालय ज्ञापन के जरिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मुख्य सचिवों, राज्यों के सूचना सचिवों और सभी जिला मजिस्ट्रेटों को जारी किए गए। समितियों को निजी एफएम रेडियो चैनलों और सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की निगरानी के लिए भी अधिकृत किया गया। इस संबंध में विस्तृत निर्देश मंत्रालय की वैबसाइट www.mib.gov.in पर उपलब्ध हैं।

नये चैनलों के मामले में स्वयं–विनियमन

8. न्यूज ब्राडकास्टर्स एसोसिएशन (समाचार प्रसारक संघ–एनबीए) ने अपनी स्वयं–विनियमन प्रणाली के हिस्से के रूप में कोड ऑफ एथिक्स एंड ब्राडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स यानी आचार संहिता और प्रसारण मानदंड तैयार किए हैं जिसमें समाचार प्रसारणों को प्रसारकों द्वारा खुद विनियमित करने के व्यापक नियम दिए गए हैं। प्रसारित की जाने वाली सामग्री से संबंधित शिकायतों से निपटने के लिए दो स्तरों वाला ढांचा भी बनाया गया है। पहले स्तर पर प्रसारक शिकायतों को अपने ही स्तर पर निपटाते हैं, जबकि दूसरे स्तर पर एनबीए द्वारा 2008 में गठित समाचार प्रसारण मानदंड प्राधिकरण (एनबीएसए) शिकायतों का निपटारा करता है।

समाचारों से इतर (सामान्य मनोरंजन) चैनल के मामले में स्वयं–विनियमन

9. इंडियन ब्राडकास्टिंग फाउंडेशन (आईएफबी) ने गैर–समाचार चैनलों के मामले में भी स्वयं–विनियमन की प्रणाली कायम की है। फाउंडेशन ने अंतर्वस्तु संहिता और प्रमाणन नियम 2011 तैयार किए हैं जिनमें अंतर्वस्तु संबंधी तमाम सिद्धांत और टेलीविजन प्रसारण के मानदंडों को शामिल किया गया है। इस प्रणाली के तहत दो स्तरों वाली शिकायत निवारण प्रणाली कायम की गयी है। प्रथम स्तर पर प्रत्येक प्रसारक अपने यहां मानक और व्यवहार विभाग बनाएगा और चैनलों पर प्रसारित सामग्री को लेकर शिकायतें प्राप्त करने के लिए कंटेंट ऑडिटर (अंतर्वस्तु परीक्षक) नियुक्त करेगा।

10. द्वितीय स्तर पर ब्राडकास्टिंग कंटेंट कम्प्लेंट्स काउंसिल (बीसीसीसी) बनायी गयी है जिसने 1 जुलाई, 2011 से काम करना शुरू किया। फिलहाल बीसीसीसी 12 सदस्यों वाली संस्था है जिसके अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवातनवृत्त न्यायाधीश होते हैं और समाज के चार जाने–माने लोग इसके सदस्य होते हैं। इस समय बीसीसीसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) विक्रमजित सेन हैं। ब्यौरा आईबीएफ की वेबसाइट http://www.ibfindia.com पर उपलब्ध है।

टीवी चैनलों में विज्ञापनों का स्वयं–विनियमन

11. टीवी चैनलों में प्रसारित होने वाले विज्ञापनों के विनियमन के बारे में स्वयं–विनियामक संगठन एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया (एएससीआई) ने संहिता तैयार की है जिसे केबल टेलीविजन नेटवर्क्स रूल्स, 1994 में विज्ञापन संहिता के रूप में शामिल किया गया है। एएससीआई ने उपभोक्ता शिकायत परिषद (सीसीसी) बनायी है जो विज्ञापनों के संबंध में शिकायतों की सुनवाई करती है। सीसीसी में इस समय 28 सदस्य हैं जिनमें से 12 उद्योग से ही हैं और अन्य 16 में सिविल सोसाइटी जैसे जाने–माने डॉक्टर, वकील, पत्रकार, विद्वान, उपभोक्ता आंदोलन से जुड़े लोग आदि शामिल हैं। विवरण एएससीआई की वेबसाइट https://www.ascionline.org पर उपलब्ध है।

केबल टीवी को डिजिटाइज करने की स्थिति

1. देश भर में केबल टीवी के डिजिटाइजेशन के लिए अंतिम तारीख 31.03.2017 थी और इसे पहले चरण में चार मेट्रो शहरों, दूसरे चरण में 10 लाख या इससे अधिक आबादी वाले 38 शहरों में और तीसरे चरण में अन्य शहरी इलाकों में लागू करके पूरा कर लिया गया। चौथे चरण में डिजिटाइजेशन का 90 प्रतिशत से अधिक कार्य पूरा हो चुका था। अब प्रत्येक केबल ऑपरेटर के लिए यह जरूरी है कि वह किसी भी चैनल के कार्यक्रमों को सिर्फ डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम के जरिए इनक्रिप्टेड रूप में प्रसारित या पुनर्प्रसारित करे।

2. अक्टूबर 2019 तक मंत्रालय ने 1596 एम.एस.ओ. पंजीकरणों की अनुमति दी।

सामुदायिक रेडियो

समग्र परिदृश्य

सामुदायिक रेडियो (सीआर) प्रसारण का तीसरा महत्वपूर्ण स्तर है जो लोक सेवा प्रसारण और वाणिज्यिक प्रसारण मीडिया से एकदम अलग है। यह आम आदमी के जीवन से संबंधित मुद्दों पर स्थानीय समुदाय के बीच स्थानीय आवाज की अभिव्यक्ति के लिए माध्यम उपलब्ध कराता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में इस क्षेत्र का धीरे–धीरे मगर कारगर तरीके से विकास हो रहा है। सामुदायिक रेडियो स्टेशन मूलतः कम शक्ति के रेडियो स्टेशन ही होते हैं जिनकी स्थापना और संचालन स्थानीय समुदायों द्वारा किया जाता है। भारत में स्थानीय रेडियो स्टेशन स्थापित करने की अनुमति मुनाफे का ध्यान रखे बिना कार्य करने वालों को दी जाती है जिनमें शैक्षिक संस्थाएं, कृषि संगठन और सिविल सोसाइटी शामिल हैं। स्थानीय रेडियो स्टेशनों की जड़ें स्थानीय समुदायों में समाई रहती हैं और इनका स्वामित्व व प्रबंधन समुदायों द्वारा ही किया जाता है। इससे उन्हें स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि जैसे स्थानीय मुद्दों पर अधिक ध्यान केन्द्रित कर पाने का फायदा मिलता है। इतना ही नहीं, सामुदायिक रेडियो क्षेत्र, समाज के उपेक्षित वर्गों को अपने सरोकारों को सशक्त तरीके से अभिव्यक्त करने का अवसर भी प्रदान करता है।

इसके अलावा प्रसारण स्थानीय भाषाओं और बोलियों में होने से लोग तत्काल अपने आप इससे जुड़ जाते हैं। सामुदायिक रेडियो में विकास कार्यक्रमों को लेकर समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए लोगों की भागीदारी सुदृढ़ करने की क्षमता भी होती है। भारत जैसे देश में जहां हर राज्य की अपनी भाषा और अलग सांस्कृतिक पहचान है, सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थानीय लोक संगीत और सांस्कृतिक विरासत का भंडार भी है। कई सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थानीय गीतों को रिकार्ड कर आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित कर रहे हैं और स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा समुदाय के सामने प्रस्तुत करने का मंच प्रदान कर रहे हैं। सार्थक सामाजिक बदलाव के औजार के रूप में सामुदायिक रेडियो का अनोखा दर्जा इसे सामुदायिक सशक्तीकरण का आदर्श माध्यम भी बना देता है। सामुदायिक रेडियो के नीतिगत दिशानिर्देश और इस समय प्रसारण कर रहे सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की सूची https://mib.gov.in/all_broadcasting_documents पर देखी जा सकती है।

दिसंबर 2002 में भारत सरकार ने प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थाओं को सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना की अनुमति प्रदान करने संबंधी नीति को मंजूरी दी। नीतिगत दिशानिर्देशों को 2006 में संशोधित किया गया और मुनाफे को ध्यान में रखकर काम न करने वाली समितियों को भी आवेदन की इजाजत दी गयी ताकि विकास और सामाजिक बदलाव से संबंधित मुद्दों पर और अधिक भागीदारी संभव हो सके। नीतिगत दिशानिर्देशों में 2017 और 2018 में और संशोधन किया गया ताकि सामुदायिक रेडियो क्षेत्र में विकास और प्रामाणिकता को और बढ़ावा मिले। नवंबर 2019 तक कुल 712 आशय पत्र जारी किए जा चुके थे जिनमें से 347 संगठनों ने अनुमति प्रदान करने के समझौते पर दस्तखत कर लिए थे और 276 सामुदायिक रेडियो स्टेशनों ने प्रसारण भी शुरू कर दिया था।

आवेदन के तरीके, आवेदनों को निपटाने में और अधिक पारदर्शिता, संबद्ध पक्षों के साथ बेहतर तालमेल, जागरूकता में बढ़ोतरी और सामुदायिक रेडियो प्रसारण में अन्य मंत्रालयों को भागीदार बनाने जैसी पहल से भारत में सामुदायिक रेडियो के सार्थक विकास की बुनियाद सुदृढ़ हुई है।

जुलाई 2018 में सरकार ने 'भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को सहायता' नाम की मौजूदा योजना का जारी रखने की इजाजत दे दी और 2019–20 की अवधि के लिए 25 करोड़ रुपये मंजूर किए। उपकरणों की खरीद के लिए अनुदान देने की प्रक्रिया को भी आसान बनाया गया है।

भारत में सामुदायिक रेडियो सेवा की स्थिति

आज की तारीख में देश में 276 सामुदायिक रेडियो स्टेशन काम कर रहे हैं जिनमें से 132 का संचालन सिविल सोसाइटीज, 129 का शैक्षिक संस्थाएं और 15 का राज्य कृषि विश्वविद्यालय/कृषि विज्ञान केंद्र कर रहे हैं। प्रसारण कर रहे सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को नीचे रेखाचित्र के जरिए से प्रदर्शित किया गया है।

मंत्रालय की पहल

भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन की सफलता के लिए जागरूकता उत्पन्न करने की अत्यधिक आवश्यकता को

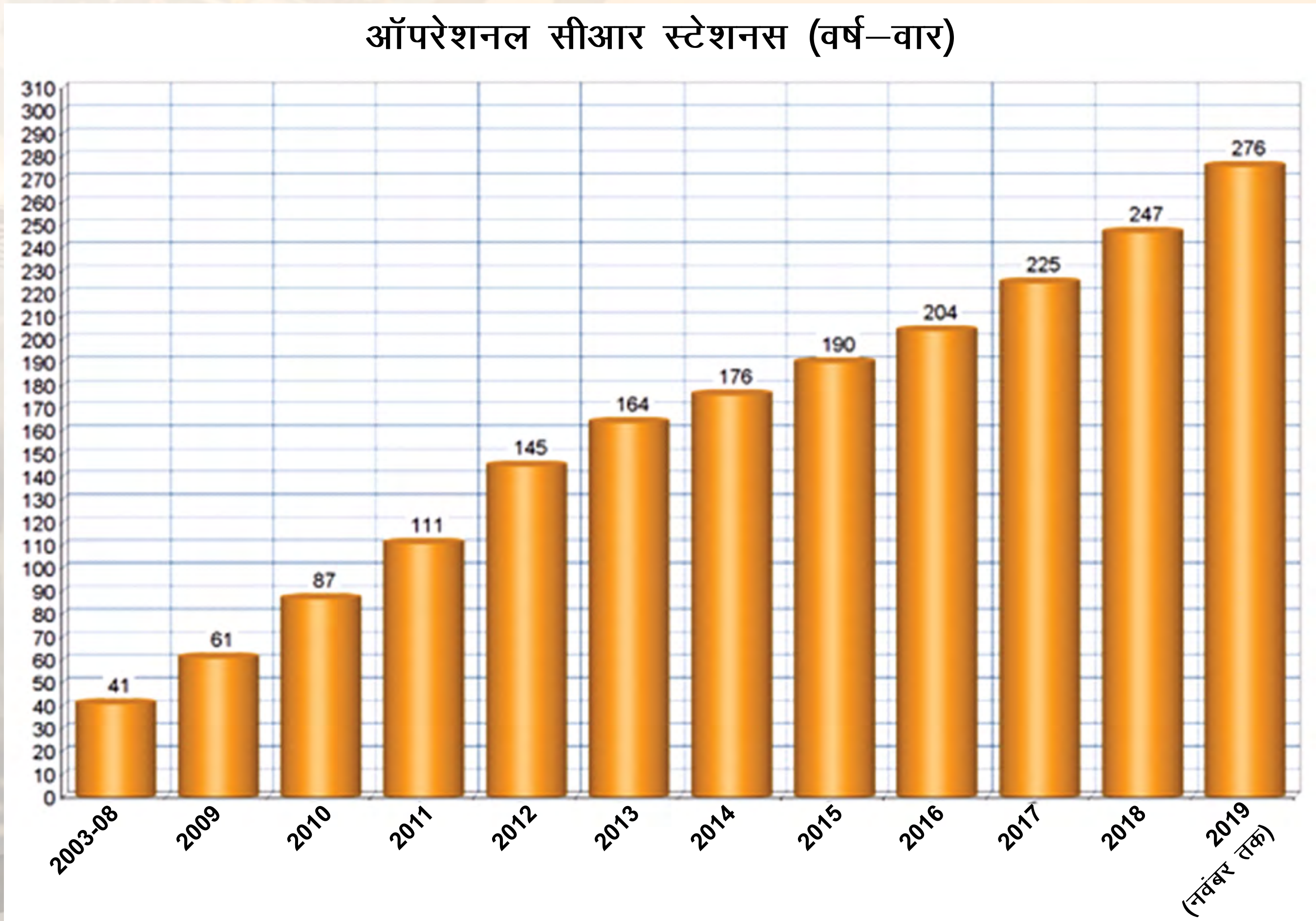

ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने संबद्ध पक्षों के साथ जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन करके सामुदायिक रेडियो योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार किया है। ये कार्यशालाएं दिशानिर्देशों, आवेदन की प्रक्रिया, अंतर्वस्तु और सामुदायिक रेडियो सेवा के स्थायित्व से संबंधित मसलों पर ध्यान देने में सफल रही हैं। वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान महत्वाकांक्षी जिलों और सामुदायिक रेडियो विहीन जिलों में 8 जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित करने लक्ष्य रखा गया है। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य सामुदायिक रेडियो संबंधी नीतिगत दिशानिर्देशों और योजनाओं के बारे में संभावित संगठनों में जागरूकता पैदा करना और ऐसे संगठनों को देश के दूरदराज इलाकों में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना के लिए आवेदन करने को प्रेरित करना है।

सामुदायिक रेडियो के लिए अतिरिक्त फ्रीक्वेंसी स्पॉटः फ्रीक्वेंसी स्पॉट्स उपलब्ध न होने के कारण कई आवेदनों के अस्वीकार होने की समस्या के समाधान के लिए मंत्रालय ने यह मुद्दा संचार मंत्रालय के साथ उठाया और सामुदायिक रेडियो के लिए अतिरिक्त फ्रीक्वेंसी स्पॉट्स आवंटित करने का अनुरोध किया। इसे स्वीकार कर लिया गया। अब दो अतिरिक्त फ्रीक्वेंसी स्पॉट्स 89.6 मेगाहर्त्ज और 90.0 मेगाहर्त्ज आवंटित कर दिए गए हैं। सितंबर 2019 में 72 नये आवेदकों को अतिरिक्त फ्रीक्वेंसी स्पॉट्स में से फ्रीक्वेंसी आवंटित की गयी हैं।

राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन 2019ः देश में सामुदायिक रेडियो संचालित करने वालों की उपलब्धियों और प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रालय ने तीन साल के अंतराल के बाद 27 से 29 अगस्त, 2019 तक नई दिल्ली में राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का आयोजन किया। इसका उद्घाटन माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया। अपने संबोधन में उन्होंने सभी सामुदायिक रेडियो संचालकों के कार्यों की सराहना की और इस क्षेत्र में लगातार सुधार के लिए सभी संबद्ध पक्षों और सरकार के बीच बेहतर तालमेल कायम करने का आग्रह किया। इस अवसर पर माननीय मंत्री ने विभिन्न सामुदायिक रेडियो संचालकों को पांच अलग–अलग श्रेणियों के अंतर्गत राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए और सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के बारे में एक संकलन भी जारी किया। उन्होंने सामुदायिक रेडियो पुरस्कार प्राप्त करने वालों के बारे में हिंदी और अंग्रेजी में एक पुस्तिका का विमोचन किया जिसकी बड़ी सराहना की गयी। सम्मेलन में सामुदायिक रेडियो क्षेत्र के 300 से अधिक प्रतिभागियों, मंत्रालय के अधिकारियों और अन्य संबद्ध लोगों ने भी भाग लिया। तीन साल के बाद आयोजित इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और सामुदायिक रेडियो से जुड़े लोगों की सराहना की।

मंत्रालय द्वारा उठाये गए अन्य कदमः मंत्रालय ने अन्य मंत्रालयों और सरकारी विभागों तथा सभी राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों से संपर्क कर उनसे अपनी मीडिया

केंद्रीय पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर 28 अगस्त, 2029 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए

राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन 2019 में भाग ले रहे प्रतिभागी

संबंधी गतिविधियों के लिए सामुदायिक रेडियो का उपयोग सुनिश्यित करने को भी कहा है। इसके लिए राज्यों के सचिवों और मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर उनसे अपने वार्षिक मीडिया प्लान में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को भी सम्मिलित करने को कहा गया है।

कारोबारी सुविधा सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक रेडियो के नीतिगत दिशानिर्देशों को और सरल बनाने के लिए भी कदम उठाये गए हैं। देश के महत्वाकांक्षी जिलों, तटवर्ती जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना के लिए निष्ठापूर्वक प्रयास किए जा रहे हैं।

एफएम प्रभाग

1. एफएम रेडियो देश में नौजवानों और वयस्कों के मनोरंजन के पसंदीदा तरीकों में से एक है। विभिन्न एफएम रेडियो स्टेशन स्थानीय भाषाओं जिस तरह का विविधापूर्ण मनोरंजन उपलब्ध कराते हैं उसे जनता बड़ा पसंद करती है और हाल के वर्षों में एफएम रेडियो चैनलों की संख्या में बढ़ोतरी से इसकी पुष्टि हो जाती है। एफएम तृतीय चरण के अंतर्गत ई–नीलामी के दो दौर में नये एफएम चैनलों के लाइसेंस हासिल करने के लिए निजी एफएम प्रसारकों ने जो उत्साह दिखाया उससे भी एफएम रेडियो की लोकप्रियता का अनुमान लगाया जा सकता है। एफएम प्रसारण, रेडियो पर विज्ञापनों के जरिए स्थानीय कारोबार को बढ़ाने की क्षमता रखने वाले संभावित माध्यम के रूप में भी उभरा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी निजी एफएम रेडियो का उपयोग सरकार के विकास कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए जनता तक पहुंचने के माध्यम के रूप में कर रहा है। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के बारे में जनता को जागरूक बनाने और स्वच्छ भारत अभियान जैसे प्रमुख सरकारी कार्यक्रमों की पहुंच का दायरा बढ़ाने वाले जिंगलों की लोकप्रियता इसके उदाहरण है।

2. मंत्रालय का एफएम प्रकोष्ठ निजी एजेंसियों के माध्यम से एफएम रेडियो प्रसारण के विस्तार के तीसरे चरण के नीतिगत दिशानिर्देशों के तहत भारत में निजी एफएम रेडियो प्रसारण से संबंधित तमाम मामलों को देखता है। इन दिशानिर्देशों को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 जुलाई 2011 को अनुमति प्रदान की। ये नीतिगत निर्देश अद्यतन रूप में मंत्रालय की वेबसाइट https://mib.gov.in/all_broadcasting_documents पर उपलब्ध हैं।

3. सरकार ने एफएम रेडियो क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलने की शुरुआत जुलाई 1999 में 21 निजी एफएम रेडियो चैनलों से देश के 12 शहरों में की (इनमें से ज्यादातर राज्यों की राजधानियों वाले शहर थे।) एफएम द्वितीय चरण की शुरुआत 2005 में हुई जिसके अंतर्गत 3 लाख या इससे अधिक आबादी वाले शहरों में एफएम प्रसारण का विस्तार किया गया। इस चरण में 26 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 86 शहरों में 245 एफएम चैनल शुरू हुए। इनमें प्रथम चरण से प्रव्रजन करने वाले 21 निजी चैनल भी शामिल थे।

4. एफएम रेडियो की पहुंच का दायरा और बढ़ाने के लिए सरकार ने 25 जुलाई 2011 को एफएम तृतीय चरण के नीतिगत दिशानिर्देशों की घोषणा की। इसमें जम्मू–कश्मीर के 11 सीमावर्ती शहरों, पूर्वोत्तर राज्यों और द्वीप प्रदेशों के एक लाख से कम आबादी वाले शहरों समेत देश के एक लाख या इससे अधिक आबादी वाले बाकी सभी शहरों में एफएम प्रसारण का विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया था। एफएम रेडियो तृतीय चरण की ई–नीलामी के दो दौर पूरे होने के बाद मंत्रालय ने देश भर में एफएम के 162 चैनल और बढ़ाए हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लेह और करगिल तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू–कश्मीर के सीमावर्ती भदरवाह, कठुआ और पुंछ में निजी एफएम रेडियो चैनलों की नीलामी की गई है। सरकार एफएम तृतीय चरण के अगले दौरों में 805 और चैनलों की ई–नीलामी कराने की तैयारी कर रही है।

5. संलग्न मानचित्र में देश के उन शहरों को दर्शाया गया है जहां निजी एफएम रेडियो चैनल चल रहे हैं। इसमें उन शहरों को भी दर्शाया गया है जहां एफएम तृतीय चरण में

रेडियो चैनल शुरू करने का प्रस्ताव है। 30 नवंबर, 2019 को देश के 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के 108 शहरों में 382 एफएम रेडियो चैनल प्रसारण कर रहे थे।

पारदर्शिता के उपाय और पर्यवेक्षण

1. कंपनियों को एफएम रेडियो चैनल चलाने की अनुमति ई–ऑक्शन के जरिए सबसे ऊंची बोली के आधार पर दी जाती है। निजी प्रसारकों से राजस्व की प्राप्ति त्रैमासिक लाइसेंस शुल्क के रूप में होती है जिसे भारतकोष पोर्टल के जरिए आनलाइन प्राप्त किया जाता है।

2. पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रसारण सेवाओं का डिजिटाइजेशन ऑनलाइन पोर्टल 'ब्राडकास्ट सेवा' के जरिए चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है और प्रसारकों से लाइसेंस शुल्क तथा अन्य वित्तीय दस्तावेज इसी के माध्यम से एकत्र किए जा रहे हैं।

3. एफएम तृतीय चरण के नीतिगत दिशानिर्देश और निजी प्रसारकों द्वारा हस्ताक्षरित अनुमति प्रदान करने के समझौते के प्रावधानों पर अमल सुनिश्चित कराने के लिए मंत्रालय के एफएम प्रकोष्ठ के अधिकारी रेडियो स्टेशनों और साझा प्रसारण अवसंरचना (सीटीआई) सुविधाओं का दौरा करते हैं।

सरकार को राजस्व प्राप्ति

4. सरकार को निजी प्रसारकों से अप्रतिदेय एकमुश्त प्रवेश शुल्क, प्रव्रजन शुल्क, वार्षिक लाइसेंस शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क और टावर के किराये के रूप में आमदनी हुई।

5. वित्त वर्ष 2019–20 की पहले तीन तिमाहियों में 30 नवंबर, 2019 तक सरकार को 128.46 करोड़ रुपये की आमदनी हुई।

6. सरकार को निजी प्रसारकों से अप्रतिदेय एकमुश्त प्रवेश शुल्क, प्रव्रजन शुल्क, वार्षिक लाइसेंस शुल्क और निजी एफएम प्रसारकों से टावर के किराये और प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में वर्ष 2000 से करीब 5925.35 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई है।

वार्षिक लाइसेंस शुल्क	प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण	सिर्फ एक बार प्रवसन के लिए अप्रतिदेय शुल्क	एक बार प्रवेश के लिए अप्रतिदेय शुल्क	निजी एफएम रेडियो ऑपरेटर से टावर शुल्क	कुल
1672.44 करोड़	0.10 करोड़	1993.63 करोड़	2252.74 करोड़	6.44 करोड़	5925.35 करोड़

प्रसार भारती : विहंगावलोकन

क. भूमिका

प्रसार भारती (भारत का लोक सेवा प्रसारक) देश का एकमात्र लोक सेवा प्रसारक है और आकाशवाणी और दूरदर्शन इसके दो संघटक हैं। यह 23 नवंबर 1997 को अस्तित्व में आया और इसे जनता को सूचनाएं देने, शिक्षित करने और उनके मनोरंजन हेतु रेडियो और टेलीविजन प्रसारण का संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक प्रसारण सेवाओं की संस्थापना तथा संचालन की जिम्मेदारी मिली हुई है।

प्रसार भारती ने डिजिटल प्लेटफार्म में भी अपनी उपस्थिति दर्ज की है। कार्यक्रमों का लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए प्रसारण, सूचनाप्रद नये वेबसाइट, यू–ट्यूब, मोबाइल एप और एलेक्सा पर कार्यक्रमों की उपलब्धता से इन प्लेटफार्मों पर प्रसार भारती की जीवंत उपस्थिति सुनिश्चित हुई है। ट्विटर और फेसबुक के जरिए सोशल मीडिया पर भी प्रसार भारती की सक्रिय उपस्थिति बनायी जा रही है। व्यावसायिक कार्यक्रमों पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करने वाले 800 से अधिक चैनलों को ध्यान में रखते हुए प्रसार भारती जैसे लोक सेवा प्रसारक की आवश्यकता और भी जरूरी हो जाती है। मुनाफे के लिए काम करने वाले वाणिज्यिक चैनलों के साथ संतुलन कायम करने वाला प्रसार भारती एकमात्र इलेक्ट्रोनिक मीडिया है। असल में प्रसार भारती द्वारा एक लंबे अरसे में विकसित नैतिक मूल्य और दिशानिर्देश इस उद्योग के मानदंडों का कार्य कर रहे हैं।

ख. उद्देश्य

प्रसार भारती अधिनियम, 1990 में निर्धारित प्रसार भारती के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं:

1) देश की एकता, अखंडता और संविधान में प्रतिष्ठित मूल्यों को बनाए रखना।

2) राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना।

निजी एफ.एम केन्द्रों के चरण 1, 2 और 3 की प्रस्तावित एवं संचालित

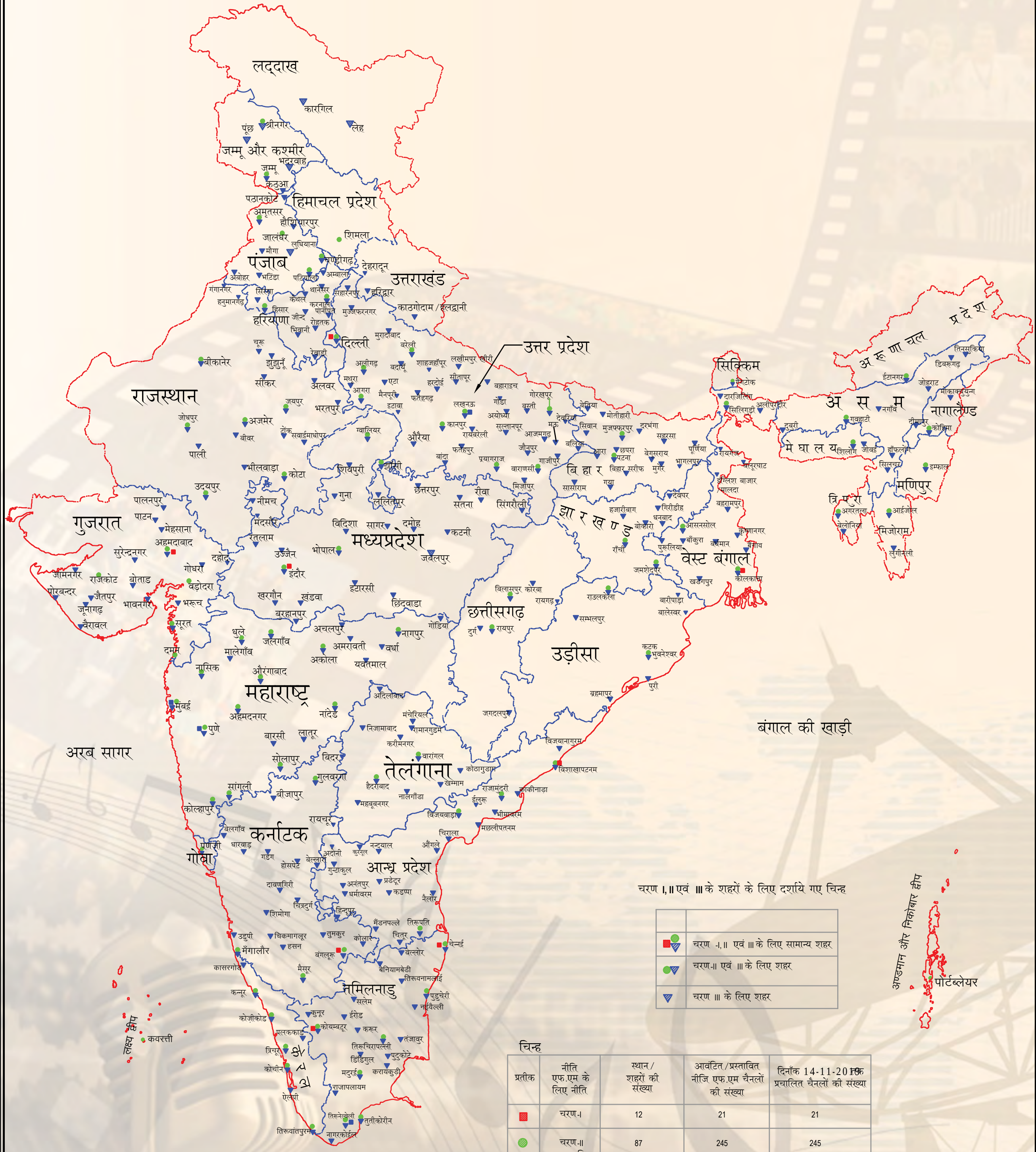

चरण I, II एवं III के शहरों के लिए दर्शाये गए चिन्ह

■●▼	चरण -I, II एवं III के लिए सामान्य शहर
●▼	चरण-II एवं III के लिए शहर
▼	चरण III के लिए शहर

चिन्ह

प्रतीक	नीति एफ.एम के लिए नीति	स्थान / शहरों की संख्या	आवंटित / प्रस्तावित नीजि एफ.एम चैनलों की संख्या	दिनाँक 14-11-2019 तक प्रचालित चैनलों की संख्या
■	चरण-I	12	21	21
●	चरण-II (चरण -I सहित)	87	245	245
▼	चरण -III (चरण -II सहित)	101 (कुल प्रस्तावित **313**)	395 (कुल प्रस्तावित-**839**)	382

THIS DRAWING IS COPYRIGHT AND THE PROPERTY OF "B E C I L" AND IS NOT TO BE REPRODUCED, COPIED HANDED OVER TO A THIRD PARTY OR USEDFOR ANY PURPOSE OTHER THAN THAT FOR WHICH IT HAS BEEN ISSUED.

Map No. BECIL/FM/E&P/STATION/001/A

BECIL
BROADCAST ENGINEERING CONSULTANTS INDIA LIMITED
HEAD OFFICE:- 14-B, RING ROAD, I. P. ESTATE, NEW DELHI-110 002 (INDIA),
Tele:- 2337 8823, Fax No. 2337 9885

3) लोक हित के तमाम मामलों पर जानकारी हासिल करने के नागरिकों के अधिकार की रक्षा करना और सूचनाओं का निष्पक्ष और संतुलित प्रवाह बनाए रखना।

4) शिक्षा के क्षेत्र का विशेष ध्यान रखना और साक्षरता, कृषि, ग्रामीण विकास, पर्यावरण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी का प्रसार करना।

5) महिलाओं के मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाना और बच्चों, बुजुर्गों और समाज के अन्य कमज़ोर वर्गों के संरक्षण के लिए विशेष कदम उठाना

6) देश की विविधतापूर्ण संस्कृति, खेल–कूद और युवाओं से संबंधित मामलों की पर्याप्त कवरेज उपलब्ध कराना।

7) सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, कामगार तबकों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय समुदायों के अधिकारों का संरक्षण करना।

8) अनुसंधान को बढ़ावा देना और प्रसारण सुविधाओं का विस्तार करना और प्रसारण टेक्नोलॉजी का विकास।

ग. प्रसार भारती बोर्ड

प्रसार भारती का संचालन प्रसार भारती बोर्ड करता है जिसमें अध्यक्ष, एक कार्यपालक सदस्य (मुख्य कार्यकारी अधिकारी), एक सदस्य (वित्त), एक सदस्य (कार्मिक), छह अंशकालिक सदस्य और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का एक प्रतिनिधि तथा पदेन सदस्य के रूप में आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक शामिल होते हैं। अध्यक्ष का कार्यकाल तीन साल या 70 साल की उम्र में से जो भी पहले हो तब तक का होता है। कार्यकारी सदस्य का कार्यकाल पांच साल का या 70 साल की उम्र तक पहुंचने में से जो भी पहले हो तब तक कार्य कर सकता है। कार्यकारी सदस्य का कार्यकाल भी पांच साल या 65 साल की उम्र में से जो भी पहले हो तब तक का होता है। सदस्य (वित्त) और सदस्य (कार्मिक) पूर्णकालिक सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल छह साल का होता है लेकिन उन्हें 62 साल से अधिक का नहीं होना चाहिए। प्रसार भारती बोर्ड आम तौर पर साल में छह बार बैठकें करता है।

2019–20 के दौरान प्रसार भारती बोर्ड का स्वरूप इस प्रकार रहा :

•	अध्यक्ष	डॉ. ए. सूर्यप्रकाश
•	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	श्री शशि शेखर वेम्पति
पूर्णकालिक सदस्य		
•	सदस्य (कार्मिक)	रिक्त
•	सदस्य (वित्त)	श्री राजीव सिंह
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा मनोनीत सदस्य		
•	अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और मनोनीत सदस्य	श्री अली आर. रिजवी
अंशकालिक सदस्य		
•	श्री अशोक कुमार टंडन	21.11.2019 तक
•	श्री सुनील अलघ	21.11.2019 तक
•	श्रीमती काजोल देवगण	
पदेन सदस्य		
•	श्री एफ. शहरयार	1.12.2019
•	सुश्री सुप्रिया साहू	28.09.2019

घ. संगठनात्मक ढांचा

प्रसार भारती बोर्ड सर्वोच्च स्तर पर कार्य करता है ताकि संगठन की नीतियों का निर्माण और कार्यान्वयन सुनिश्चित हो और प्रसार भारती अधिनियम, 1990 के माध्यम से प्राप्त जिम्मेदारियों को पूरा किया जा सके। बोर्ड के कार्यकारी सदस्य प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में कार्य करते हैं। प्रसार भारती सचिवालय में कार्य कर रहे विभिन्न सेवाओं के अधिकारी सीईओ, सदस्य (वित्त) और सदस्य (कार्मिक) को विभिन्न गतिविधियों के समन्वय, संचालन, नियोजन और नीतियों पर अमल के साथ–साथ बजट, लेखे और संगठन के सामान्य वित्तीय मामलों की देखरेख में मदद करते हैं। बोर्ड की सहायता के लिए सचिवालय है जिसमें कार्यक्रम, तकनीकी, वित्त और प्रशासनिक स्कंधों के अधिकारी शामिल हैं।

आकाशवाणी निदेशालय और दूरदर्शन निदेशालय के अपने अपने महानिदेशक हैं। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग का प्रमुख भी महानिदेशक समाचार सेवा प्रभाग (एनएसडी) होता है और दूरदर्शन के समाचार स्कंध का प्रमुख महानिदेशक समाचार और समसामयिक विषय (एनएंडसीए) होता है।

ङ. महत्वपूर्ण गतिविधियां और उपलब्धियां

1. जनशक्ति लेखा परीक्षा

जनशक्ति लेखा परीक्षा कराने के लिए प्रसार भारती ने एम/एस अर्न्स्ट एंड यंग के साथ नवंबर 2018 में एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। यह एक अरसे से लंबित पड़ी गतिविधि थी जिसे 2014 में पेश की गयी सैम पित्रोदा कमेटी की सिफारिशों के अनुसार किया जाना था। एजेंसी को विभिन्न दस्तावेजों

के अध्ययन और विभिन्न पक्षों के साथ विचार–विमर्श के बाद संगठन की वर्तमान स्थिति (जैसी है) का जायजा लेना था। एजेंसी को प्रकियाओं में बदलाव, सूचना टेक्नोलॉजी के विस्तृत उपयोग, प्रक्रियाओं को ऑटोमैटाइज करने और मुख्य सेवाओं से इतर सेवाओं को आउटसोर्स करने आदि के बारे में अपनी सिफारिशें करनी थीं। एजेंसी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश कर चुकी है जिसकी अभी जांच की जा रही है। रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिए जाने और प्रसार भारती द्वारा इसे मंजूर कर लिये जाने के बाद एजेंसी सिफारिशों पर अमल और प्रबंधन में बदलाव के लिए कदम उठायेगी।

2. वाणिज्यिक गतिविधियों (बिल तैयार करना और विक्रय) का पुनर्गठन

आकाशवाणी और दूरदर्शन के विक्रय ढांचे दो अलग–अलग द्वीपों की तरह थे और उनके बीच कोई तालमेल नहीं था। इस काम में विशेषज्ञता तथा काम–काज के पेशेवर तौर–तरीके अपनाने, विक्रय प्रक्रिया में तालमेल सुनिश्चित करने और राजस्व संग्रह की दक्षता में सुधार के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन की इन गतिविधियों का विलय कर दिया गया है। दोनों संगठनों की विक्रय गतिविधियों की देखरेख के लिए पेशेवर विक्रय प्रमुख भर्ती किया गया है। विक्रय टीम में कुछ अन्य पेशेवर विशेषज्ञ भी शामिल किए गए हैं। क्षेत्रीय स्तर पर आंचलिक विक्रय ढांचे का निर्माण किया गया है। इससे पहले आंचलिक सीआरडी (जिन्हें अब विक्रय प्रभाग–एसडी कहा जाता है) केवल दूरदर्शन की विक्रय गतिविधियों की देखरेख करते थे। पुनर्गठित ढांचे के अंतर्गत विक्रय प्रभाग आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों की विक्रय गतिविधियों के लिए उत्तरदायी हैं। सीबीएस (विक्रय केंद्र–एससी) स्तर पर और स्टेशन तथा दूरदर्शन केंद्र स्तर पर भी और पुनर्गठन किया गया है। आंचलिक और स्टेशन/दूरदर्शन केंद्र स्तर पर भी विक्रय गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए भर्ती की जा रही है।

3. विपणन, खरीद और अंतरराष्ट्रीय संबंध जैसे गतिविधियों को मजबूत करना

प्रसार भारती ने अब खरीद का काम समेकित कर दिया गया है जिससे सभी घटक संगठनों की ज्यादातर खरीद एकमुश्त की जाएगी।

तदंतर अंतरराष्ट्रीय संबंधी गतिविधियों को भी समेकित कर दिया गया है।

4. आईआईटी कानपुर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और आईआईटी कानपुर के निदेशक ने 11.07.2019 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

दूरदर्शन और आकाशवाणी में टेक्नोलॉजी पर आधारित अगली पीढ़ी के प्रसारण मानदंडों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती ने 11 जुलाई, 2019 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.) कानपुर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

अनुसंधान में सहयोग के क्षेत्रों में डायरेक्ट टू मोबाइल ब्रॉडकास्टिंग (डीटीएम), 5–जी के साथ तालमेल, ग्रामीण प्रसारण और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस शामिल हैं। अनुसंधान के अलावा सहयोग के दायरे में प्रसारण से संबंधित नीतिगत और विनियामक मुद्दे और प्रसार भारती द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना भी शामिल हैं। विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत आईआईटी कानपुर में प्रसार भारती कर्मचारियों के लिए अध्यापन और शिक्षा कार्यक्रम के अवसर पैदा करना और प्रसार भारती में आईआईटी कानपुर के छात्रों को इंटर्नशिप पूरी करने के अवसर प्रदान करना भी शामिल हैं। चूंकि टेक्नोलॉजी में बड़ी तेजी से बदलाव हो रहे

24.10.2019 को प्रसार भारती अध्यक्ष द्वारा पीबीएनएस ढांचे का उद्घाटन

हैं और नयी–नयी टेक्नोलॉजी की खोज हो रही है, जाहिर है मीडिया का ज्यादातर उपयोग मोबाइल और स्मार्ट फोन के जरिए होगा। इसलिए इस सहयोग से प्रसार भारती भविष्य के प्रसारकों के लिए अपने को तैयार कर सकेगा।

यह पहला मौका है जब प्रसार भारती ने अनुसंधान और विकास के लिए किसी टेक्नोलॉजी संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर दस्तखत किए हैं।

5. प्रसार भारती समाचार सेवा का गठन

प्रसार भारती समाचार सेवा (पीबीएनएस) का गठन प्रसार भारती के दोनों समाचार स्कंधों (आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग और दूरदर्शन के समाचार और समसामयिक विषयों के स्कंध) की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी समाचार तैयार करने वाली एजेंसी के रूप में किया गया था। इन दोनों समाचार स्कंधों की अपनी–अपनी समाचार संकलन प्रणालियां है और उनके बीच तालमेल की कमी है। पीबीएनएस के गठन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण पहलू प्रसार भारती की समाचार संकलन गतिविधियों में दक्षता लाना ताकि एक मजबूत प्रणाली कायम हो और इसकी गतिविधियों को अधिकतम किया जा सके। दूसरा पहलू प्लेटफार्म को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त सामग्री की आवश्यकता को स्वीकार किया जाना। यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण और तत्काल ध्यान देने की है कि प्रसार भारती ने ऐसी सामग्री तैयार करना शुरू कर दिया है जो डिजिटल प्लेटफार्म के लिए तैयार की गयी है और जिसमें डिजिटल को प्राथमिकता दी गयी है। यह न सिर्फ दर्शकों को जोड़े रखने की लिहाज से महत्वपूर्ण है बल्कि तेजी से विकास कर रही डिजिटल अर्थव्यवस्था की जबरदस्त मौद्रिक क्षमता का फायदा उठाने के लिए भी अहम है।

पीबीएनएस का गठन दूरदर्शन समाचार और आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के साथ–साथ क्षेत्रीय समाचार एकांशों को टेक्स्ट, ऑडियो, फोटो और वीडियो फार्मेट में समाचार उपलब्ध कराने के लिए मजबूत और कुशल नेटवर्क प्रणाली कायम करने के लिए किया गया था। पीबीएनएस और डिजिटल प्लेटफार्म के प्रमुख को मार्च, 2019 में नियुक्त किया गया था और उसे इन गतिविधियों से संबंधित प्रणाली को शुरू करने की जिम्मेदारी सौंपी गयी। इसके लिए इंद्रप्रस्थ एस्टेट में प्रसार भारती की इमारत में पीबीएनएस के लिए अत्याधुनिक ढांचा खड़ा किया गया जिसका उद्घाटन प्रसार भारती के अध्यक्ष ने अक्टूबर में किया। कई समाचार, सोशल मीडिया, समाचार संपादन और समाचारों से जुड़े पेशेवर विशेषज्ञों को पीबीएनएस टीम में शामिल किया गया है।

6. डीडी फ्री डिश निति संबंधी दिशानिर्देश

प्रसार भारती बोर्ड की 23.10.2019 को हुई 157वीं बैठक में उपग्रह टीवी चैनलों के डीडी फ्री डिश डायरेक्ट टू होम प्लेटफार्म पर जगह आवंटित करने संबंधी नीतिगत दिशानिर्देशों में 1.11.2019 से और संशोधन किया गया है। इसका उद्देश्य प्रसारित की जाने वाली सामग्री में विविधता लाने के लिए इस प्लेटफार्म पर चैनलों की भागीदारी बढ़ाकर अधिक से अधिक करना है। .

अंतरराष्ट्रीय संबंध

प्रसार भारती का अंतरराष्ट्रीय संबंध स्कंध अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों जैसे दूसरे देशों, लोक सेवा प्रसारकों/संगठनों, के साथ समझौतों और समझौता ज्ञापनों पर दस्तखत करने तथा सांस्कृतिक विनिमय से संबंधित मामलों पर अमल आदि का कार्य देखता है। यह दूसरे देशों के गण्यमान्य लोगों की यात्राओं में आतिथ्य और समन्वय, अंतरराष्ट्रीय प्रसारण यूनियनों जैसे एबीयू, एआईबीडी आदि समेत समझौता ज्ञापनों के सहयोगियों के साथ देश में/उप–क्षेत्रीय कार्यशालाओं/सम्मेलनों/कार्यक्रमों के आयोजन तथा अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं/कार्यक्रमों/सम्मेलनों में अपने अधिकारियों की भागीदारी का कार्य भी देखता है।

क्र. सं.	देश	प्रसारक/संगठन	प्रसार भारती का एकांश	हस्ताक्षर की तिथि
1	बांग्लादेश	बांग्लादेश टेलीविजन (बीटीवी)	दूरदर्शन	07.05.2019
2	मोजाम्बिक	रेडियो मोजाम्बिक	प्रसार भारती	29.08.2019

क. वर्ष के दौरान समझौता ज्ञापनों (एमओयू)/समझौतों पर हस्ताक्षर

1) वर्ष 2019–20 के दौरान प्रसार भारती ने विभिन्न विदेशी प्रसारकों/संगठनों के साथ प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग और सहभागिता के निम्नलिखित समझौतों पर दस्तखत किए :

क. प्रसार भारती ने 7.05.2019 को बांग्लादेश टेलीविजन (बीटीवी) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत बीटीवी को भारत के डीडी फ्री डिश (डीडी डीटीएच प्लेटफार्म) और डीडी इंडिया को बांग्लादेश के बीटीवी डीटीएच प्लेटफार्म पर दिखाया जाएगा। बीटीवी का चैनल 2 सितंबर, 2019 को डीडी फ्री डिश में शामिल

माननीय केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर 16.09.2019 को नई दिल्ली में केबीएस वर्ल्ड चैनल को डीडी फ्री डिश के डीटीएच प्लेटफार्म पर शुरू करते हुए

कर लिया गया है। रेडियो मोजाम्बीक के साथ कार्यक्रमों के विनिमय और क्षमता निर्माण के बारे में सहयोग के एक और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर रेडियो मोजाम्बीक के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अब्दुल नागुइबो अब्दुल्ला के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल की प्रसार भारती की यात्रा के दौरान 29.08.2019 को हस्ताक्षर किए गए। माननीय सूचना एवं प्रसारण तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने 16.09. 2019 को नई दिल्ली में केबीएस वर्ल्ड चैनल डीडी फ्री डिश के डीटीएच प्लेटफार्म पर शुरू किया और इसी तरह डीडी–इंडिया चैनल को केबीएस के एमवाईके–ओटीटी प्लेटफार्म पर शुरू किया गया। इसके लिए 22.02.2019 को प्रसार भारती और कोरिया की केबीएस के बीच समझौता हुआ था।

ख. **कार्यक्रम निर्माण में सहयोग** : दूरदर्शन ने ईबीएस कोरिया के साथ 8.5.2019 को सियोल में एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए जिसके अंतर्गत 'फैमिली एशिया' का अंतरराष्ट्रीय सह–निर्माण किया जाएगा। दिल्ली दूरदर्शन केंद्र को सह–निर्माण की समग्र जिम्मेदारी सौंपी गयी है। ईबीएस ने दूरदर्शन को स्थानीय निर्माण सहयोग हासिल करने के लिए 10,000 अमरीकी डॉलर दिए हैं। सह–निर्माण का कार्य पूरा होने को है। भारतीय इतिहास और सभ्यता पर चौथी अंतरराष्ट्रीय सह–निर्माण परियोजना के सिलसिले में ईबीएस कोरिया की कार्यकारी निर्माता सुश्री ह्यूनसूक ने नवंबर, 2019 में प्रसार भारती के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के साथ बैठक की है। इस परियोजना के निर्माण के लिए प्रसार भारती और ईबीएस कोरिया संयुक्त रूप से धन उपलब्ध कराएंगे।

ग. विदेशी शिष्टमंडलों / गणमान्य व्यक्तियों के दौरे

प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने और इसके विकास के लिए नौ से अधिक देशों, रूस, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, तंजानिया, दक्षिण कोरिया, म्यामां, जर्मनी, फीजी और ताजिकिस्तान के शिष्टमंडलों / गण्यमान्य लोगों ने प्रसार भारती का दौरा किया। इसका उद्देश्य प्रसारण के क्षेत्र में आपसी सहयोग के संभावित क्षेत्रों का पता लगाना और चर्चा करना था। अफगानिस्तान से पत्रकारों / संपादकों के 20 सदस्यों वाले शिष्टमंडल ने दूरदर्शन समाचार का दौरा किया। इसका उद्देश्य समसामयिक भारत और विदेशों में उसकी विरासत के

बारे में जागरूकता तथा समझ बढ़ाना था। मालदीव में भारत के राजदूत ने प्रसार भारती का दौरा किया और दोनों देशों के बीच मीडिया के क्षेत्र में सहयोग के संभावित क्षेत्रों के बारे में चर्चा की।

घ. एशिया प्रशांत ब्राडकॉस्टंग यूनियन (एबीयू), एशिया प्रशांत इंस्टीट्यूट फार ब्रॉडकास्टिंग डेवेलपमेंट (एआईबीयू) और अन्य अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां
बैठक के बाद डीडीजी दूरदर्शन मालदीव की यात्रा पर गए और उन्होंने वहां दूरदर्शन/आकाशवाणी के चैनलों को मालदीव के स्थानीय नेटवर्क पर दिखाने की संभावनाओं का पता लगाया। इसरो के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के अधिकारियों समेत (जिसमें विदेशी विद्यार्थी भी शामिल थे) 34 सदस्यों वाले एक शिष्टमंडल ने अध्ययन यात्रा के हिस्से के रूप में दूरदर्शन समाचार और स्टूडियो का दौरा किया।

1) **प्रसार भारती एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग (एआईबी) में शामिल** : प्रसार भारती जुलाई 2019 में एसोसिएशन फार इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग का सदस्य बन गया। प्रसार भारती के अध्यक्ष ने ब्रिटेन के लंदन में 10–11 जुलाई, 2019 को आयोजित मीडिया की स्वतंत्रता पर वैश्विक सम्मेलन में हिस्सा लिया। प्रसार भारती/दूरदर्शन ने आईआईटी दिल्ली के सहयोग से भारत में घरेलू रोबोकॉन प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसमें अंतिम रूप से विजेता टीम ने अगस्त, 2019 में उलानबाटर में एबीयू रोबोकॉन 2019 में प्रसार भारती का प्रतिनिधित्व किया।

2) **एबीयू की प्रशासनिक परिषद की 107वीं बैठक** : एबीयू की प्रशासनिक परिषद की 107वीं बैठक चीन के मकाऊ में 15–16 अप्रैल, 2019 को आयोजित की गयी जिसमें दूरदर्शन के तत्कालीन महानिदेशक ने दूरदर्शन के अपर महानिदेशक (आई.आर) के साथ हिस्सा लिया।

3) **एबीयू की महासभा और संबद्ध बैठकें 2019** : एबीयू की महासभा की 56वीं बैठक और एबीयू प्रशासनिक परिषद की 108वीं बैठक में प्रसार भारती के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने टेक्नोलॉजी, खेल–कूद और अंतरराष्ट्रीय संबंध के चार अधिकारियों के शिष्टमंडल के साथ हिस्सा लिया। महासभा 17–22 नवंबर, 2019 को जापान के तोक्यो में आयोजित की गयी। प्रसार भारती के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने 'क्रिएटिव इकोनॉमी ऑफ द फ्यूचर बियांड' विषय पर एक प्रेजेंटेशन प्रस्तुत

एबीयू ग्रीन ब्रॉडकास्ट इंजीनियरी पुरस्कार 2019 आकाशवाणी को अपनी तमाम डिजिटाइजेशन परियोजनाओं में हरित टेक्नोलॉजी अपनाने और जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रदान किया गया

किया। भारतीय संगीत की महान हस्ती ए.आर. रहमान एबीयू गीत उत्सव में पधारे और उन्होंने प्रसार भारती की ओर से भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए गीत पेश किया।

ङ अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार

1. आकाशवाणी ने अपनी तमाम डिजिटाइजेशन परियोजनाओं में पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित टेक्नोलॉजी अपनाने और जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एशिया ब्रॉडकास्टिंग यूनियन–एबीयू का ग्रीन ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग अवार्ड प्राप्त किया।

2. दूरदर्शन के डीडीजी (ई) श्री एम.एस. दुहान को उनके लेख 'एनेटॉमी ऑफ आर.एफ. एम्प्लिफायर्स–फेल्योर मेकेनिक्स एंड मेंटीनेंस स्ट्रैटेजीज' के लिए एबीयू का बेहतरीन लेख पुरस्कार मिला।

3. आकाशवाणी की प्रविष्टि 'साइति राखिबा असा मेघारा मुरछाना' (आइये हम बादलों के मधुर घोष की रक्षा करें) ने 2019 में ईरान के 14वें अंतरराष्ट्रीय रेडियो समारोह में शैक्षिक मनोरंजन श्रेणी का पहला पुरस्कार जीता। इस कार्यक्रम का निर्माण आकाशवाणी कटक के कार्यक्रम निष्पादक ललितेन्दु कानूनगो ने किया। इसी समारोह में आकाशवाणी की दूसरी प्रविष्टि 'महात्मा गांधी आमा भीतरे' (हमारे अंदर महात्मा गांधी) को लोक सेवा घोषणा श्रेणी का दूसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ। कार्यक्रम का निर्माण आकाशवाणी कटक के सहायक कार्यक्रम निदेशक श्री तरुण कांति राउत ने किया।

च. साल में हुए अंतरराष्ट्रीय आयोजनों की सूची जिनमें प्रसार भारती ने भाग लिया

क्रम. सं.	आयोजन का नाम	अवधि	स्थान/देश
1.	ग्रुप रिपोर्टिंग कार्यक्रम 2019	1-7 अप्रैल 2019	सियोल, दक्षिण कोरिया
2.	107वीं एबीयू मध्यवार्षिक प्रशासनिक परिषद बैठक	15-16 अप्रैल 2019	मकाऊ, चीन
3.	14वां अंतरराष्ट्रीय रेडियो उत्सव	22-25 अप्रैल 2019	तेहरान, ईरान
4.	एशिया मीडिया समिट और प्री-समिट 2019	10-14 जून 2019	सिएम रीप, कंबोडिया
5.	अंतरराष्ट्रीय सहनिर्माण सम्मेलन 2019	19-20 जून 2019	सियोल, दक्षिण कोरिया
6.	बीएसएफ द्वारा भारतीय मीडिया के लिए भारत-बांग्लादेश सीमा की यात्रा का आयोजन	14-17 जुलाई 2019	बांग्लादेश
7.	18वां एआईबीडी महासम्मेलन 45वां वार्षिक सम्मेलन और अन्य संबद्ध बैठकें	22-24 अगस्त 2019	पारो, भूटान
8.	एबीयू रोबोकॉन 2019	23-27 अगस्त 2019	उलानबाटार, मंगोलिया
9.	खेल पत्रकारिता पर एआईबीडी क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन (परामर्शदाता के तौर पर)	22-24 सितंबर 2019	कुआलालम्पुर, मलेशिया
10.	एनएबी शो 2019	17-18 अक्टूबर 2019	न्यूयॉर्क, अमरीका
11.	प्रसार भारती के सीईओ और पत्र सूचना कार्यालय की बैठक	10-11 सितंबर 2019	फिनलैंड
12.	56वीं एबीयू आम सभा और इससे संबद्ध बैठकें	17-22 नवंबर 2019	तोक्यो, जापान
13.	8वां एबीयू टीवी गीत उत्सव 8जी	19 नवंबर 2019	तोक्यो, जापान

आकाशवाणी

आकाशवाणी – तथ्य एक नजर में

(31.12.2019 की स्थिति)

प्रसारण केंद्र

क्षेत्रीय स्टेशन	136
स्थानीय रेडियो स्टेशन	88
रिले केंद्र	253
सामुदायिक रेडियो स्टेशन	05
कुल :	**482**

ट्रांसमीटर

- मीडियम वेव 130
- शॉर्ट वेव 22
- एफएम 501

कुल : 653

अन्यः

डीटीएच प्लेटफार्म पर उपग्रह डिजिटल रेडियो के मौजूदा आकाशवाणी चैनल	37
क्षेत्रीय समाचार एकांश	47

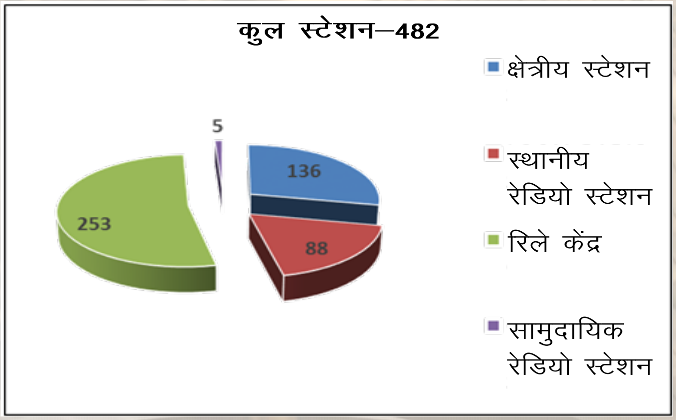

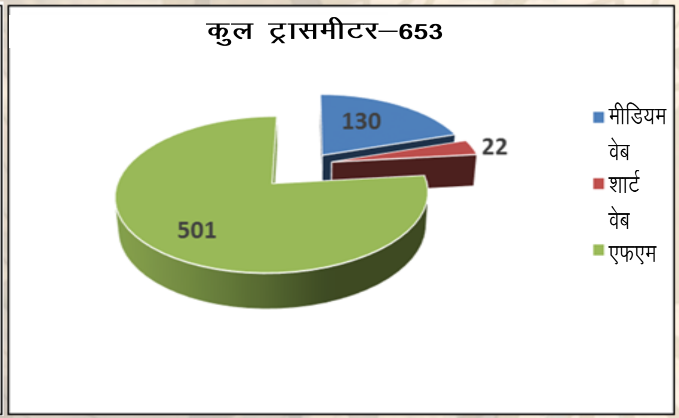

आकाशवाणी के चैनल और कार्यक्रम

क. भूमिका

आकाशवाणी (ऑल इंडिया रेडियो) का उद्देश्य व्यापक जनसमुदाय की भलाई और खुशहाली को बढ़ावा देने के लिए (बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय) उन्हें सूचना, शिक्षा और मनोरंजन उपलब्ध कराना है।

पिछले आठ दशकों में आकाशवाणी का अभूतपूर्व विकास हुआ है जिससे यह जिससे वह दुनिया के सबसे बड़े मीडिया संगठनों में से एक बन गया है। आज इसके 482 रेडियो स्टेशन और 653 ट्रांसमीटर हैं। भारत के बहुल समाज की संचार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आकाशवाणी के नेटवर्क का लगातार विस्तार किया गया और ऐसा करते समय नयी टेक्नोलॉजी और कार्यक्रम निर्माण तकनीकों को आत्मसात किया गया। नयी–नयी टेक्नोलॉजी अपनाना जारी रखते हुए आज आकाशवाणी की तमाम सेवाओं का डिजिटलीकरण किया जा रहा है।

ख. संगठनात्मक ढांचा

परम्परा से ही आकाशवाणी के प्रमुख महानिदेशक होते हैं जिनकी मदद के लिए अपर महानिदेशक (एडीजी) होते हैं जो कार्यक्रम, प्रशासन और वित्त स्कंधों को देखते हैं। इसके अलावा इंजीनियरी स्कंध का प्रमुख इंजीनियर इन चीफ होता है। समाचार स्कंध का प्रमुख महानिदेशक (समाचार) होता है।

आकाशवाणी महानिदेशालय नीति निर्माण, नियोजन और विकास, बुनियादी ढांचे व टेक्नोलॉजी के उन्नयन, बजट संबंधी नियोजन और नियंत्रण; मानव संसाधन विकास तथा संचालन व रखरखाव जैसी गतिविधियों की निगरानी आदि के लिए उत्तरदायी है।

ग. आकाशवाणी की सेवाएं और चैनल

1. क्षेत्रीय चैनल

आकाशवाणी के क्षेत्रीय (प्राथमिक) चैनल आमतौर पर राज्यों की राजधानियों और हर राज्य के प्रमुख भाषायी तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में स्थित हैं। देश के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस तरह के कुल 136 चैनल कार्य कर रहे हैं। अपने श्रोताओं के जीवन को और समृद्ध बनाने के लिए आकाशवाणी के लोक सेवा प्रसारण स्कंध के तहत क्षेत्रीय चैनल सूचना और मनोरंजन प्रदान करने वाले कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं। क्षेत्रीय चैनल आमतौर पर मीडियम वेव फ्रीक्वेंसी पर प्रसारण करते हैं जिनमें कई तरह के कार्यक्रम शामिल होते हैं। वे भारतीय शास्त्रीय संगीत पर खासा जोर देकर कला और संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। प्राथमिक चैनलों के कुल प्रसारण का करीब 40 प्रतिशत संगीत के रूप में होता है जिसमें शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, लोकप्रिय संगीत और विभिन्न भाषाओं का संगीत शामिल रहता है। कुल प्रसारण समय का 20 से 30 प्रतिशत हिस्सा समाचार और समसामयिक विषयों के कार्यक्रमों का होता है। रेडियो नाटक और ड्रामा, महिलाओं और बच्चों के कार्यक्रम, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम, खेती–बाड़ी और घर–गृहस्थी से संबंधित कार्यक्रम भी प्राथमिक चैनलों के प्रसारण का मुख्य भाग होते हैं जिनका उद्देश्य ग्रामीण जनसमुदाय का सशक्तीकरण करना है। रेडियो चैनल आसानी से उपलब्ध होने के कारण इनमें श्रोताओं द्वारा सबसे अधिक सुनी और समझी जाने वाली भाषा में उन तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है।

2. स्थानीय रेडियो स्टेशन (एलआरएस)

इस समय देश भर में 88 स्थानीय रेडियो स्टेशन है जो इलाके की स्थानीय आबादी की आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं। ये अपने श्रोताओं को ऐसी सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं जो उनके लिए उपयोगी हैं और उस स्थानीय समुदाय के दिल को छूती हैं जो अपने जीवन को समृद्ध बनाने के लिए माइक्रोफोन का उपयोग करता है।

मौजूदा परिदृश्य में जब आकाशवाणी से ज्यादातर स्थानीय रेडियो स्टेशन एफएम चैनलों पर हैं, ये रेडियो स्टेशन स्थानीय सामग्री के साथ–साथ विविध भारती कार्यक्रमों को भी रिले करते हैं। इस समय अधिकतर स्थानीय रेडियो स्टेशन रोजाना 17 घंटे का प्रसारण कर रहे हैं जिसमें 7 घंटे विविध भारती के कार्यक्रमों के रिले के भी शामिल हैं। प्रसारित की जाने वाली सामग्री में से 60 प्रतिशत स्थानीय और 40 प्रतिशत रिले की जाने वाली होती है (समाचार और क्षेत्रीय स्टेशनों के रिले किए जाने वाले कार्यक्रम भी इसमें शामिल हैं)। इस तरह स्थानीय रेडियो स्टेशन उस मकसद को पूरा कर रहे हैं जिसके लिए उन्हें बनाया गया था।

आकाशवाणी

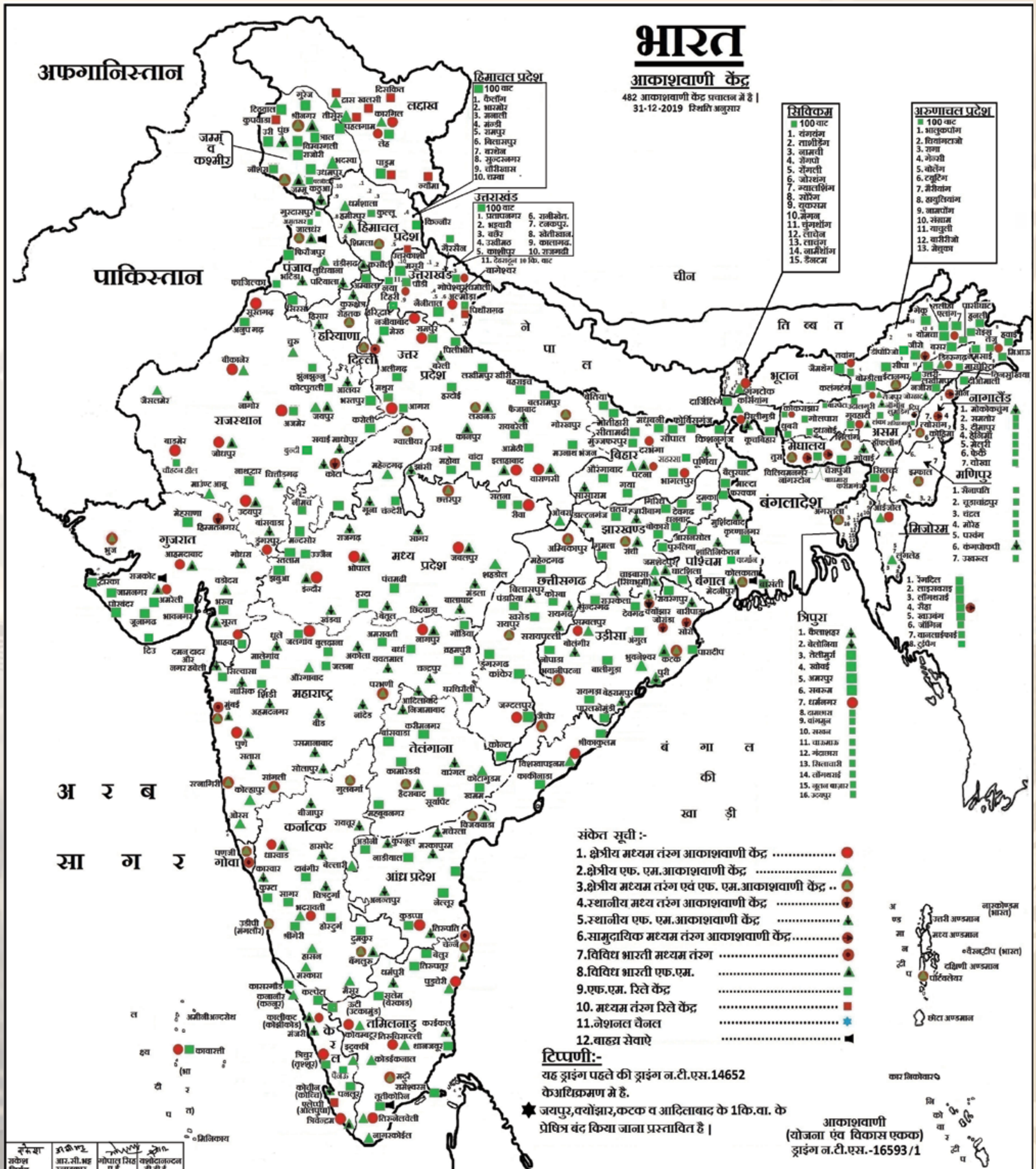

भारत
आकाशवाणी केंद्र
482 आकाशवाणी केंद्र प्रचालन में है।
31-12-2019 स्थिति अनुसार
अफगानिस्तान
पाकिस्तान
चीन
नेपाल
तिब्बत
भूटान
बंगलादेश
अरब सागर
बंगाल की खाड़ी
संकेत सूची :-
1. क्षेत्रीय मध्यम तरंग आकाशवाणी केंद्र
2. क्षेत्रीय एफ. एम. आकाशवाणी केंद्र
3. क्षेत्रीय मध्यम तरंग एवं एफ. एम. आकाशवाणी केंद्र
4. स्थानीय मध्य तरंग आकाशवाणी केंद्र
5. स्थानीय एफ. एम. आकाशवाणी केंद्र
6. सामुदायिक मध्यम तरंग आकाशवाणी केंद्र
7. विविध भारती मध्यम तरंग
8. विविध भारती एफ.एम.
9. एफ. एम. रिले केंद्र
10. मध्यम तरंग रिले केंद्र
11. नेशनल चैनल
12. बाह्य सेवाएं
टिप्पणी:-
यह ड्राइंग पहले की ड्राइंग न.टी.एस.14652 केअधिक्रमण में है।
जयपुर, क्योंझार, कटक व आदिलाबाद के 1कि.वा. के प्रेषित्र बंद किया जाना प्रस्तावित है।
आकाशवाणी
(योजना एंव विकास एकक)
ड्राइंग न.टी.एस.-16593/1

3. सामुदायिक रेडियो स्टेशन (सीआरएस)

पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थानीय जनजातीय लोगों की सेवा के लिए पांच स्थानों पर सामुदायिक रेडियो केंद्र खोले गए।

1.	मोन	1 किलोवॉट मीडियमवेव	1584 किलोहटर्ज़
2.	तुएनसांग	1 किलोवॉट मीडियमवेव	1602 किलोहटर्ज़
3.	नोंगस्टोइन	1 किलोवॉट मीडियमवेव	1485 किलोहटर्ज़
4.	विलियमनगर	1 किलोवॉट मीडियमवेव	1602 किलोहटर्ज़
5.	शाइहा	1 किलोवॉट मीडियमवेव	1602 किलोहटर्ज़

4. एफएम रेनबो

इस समय आकाशवाणी के देशभर में 501 एफएम ट्रांसमीटर है जिनके जरिए देश की मुख्यभूमि का 54 प्रतिशत और जनसंख्या का 64 प्रतिशत इसके प्रसारण के दायरे में आता है। इनमें से एफएम रेनबो चैनल देश में 23 स्थानों–दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, लखनऊ, पणजी, जालंधर, कानपुर, कोची, पुद्दुचेरी, शिलांग, चंडीगढ़, कटक, कोडइकनाल, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर, हैदराबाद, विशाखापत्तनम, रायबरेली, मदुरै, तिरुनलवेली और विजयवाड़ा में सुना जा सकता है। इसके अलावा दिल्ली रेनबो का भी मसूरी और अलीगढ़ से पूरा और धर्मशाला और भटिंडा से आंशिक रूप से प्रसारण किया जाता है। एफएम चैनलों के कार्यक्रमों में पॉप म्यूजिक, फिल्मी गाने, शास्त्रीय व भक्ति संगीत, मुख्य समाचार आदि शामिल हैं।

5. एफएम गोल्ड

एफएम गोल्ड चैनल की शुरुआत 1 सितंबर, 2001 से नई दिल्ली में एक विशिष्ट सूचना एवं मनोरंजन चैनल के रूप में हुई जिसमें 30 प्रतिशत समाचार और समसामयिक विषयों के कार्यक्रम और 70 प्रतिशत मनोरंजक कार्यक्रम शामिल थे। आज एफएम गोल्ड चैनल रोजाना चौबीसों घंटे उपलब्ध रहता है। इसे चार महानगरों–दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के अलावा लुधियाना में भी सुना जा सकता है। यह अतिरिक्त चैनल ने श्रोताओं को आकाशवाणी के सामान्य चैनलों और निजी एफएम चैनलों के अलावा चुनाव का एक विकल्प उपलब्ध कराया है। इसके माध्यम से श्रोताओं को सूचना के साथ–साथ मनोरंजन उपलब्ध कराने और यातायात, विमान सेवाओं, रेलवे तथा मौसम आदि से संबंधित ताजातरीन जानकारी भी उपलब्ध करायी जा रही है।

6. डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) सेवा

डीटीएच रेडियो चैनल एक उपग्रह सेवा है जो उन श्रोताओं के लिए है जिनके पास टीवी सेट है। डीटीएच सेवा प्रसार भारती के डीटीएच प्लेटफार्म के जरिए उपलब्ध है और इसकी अपलिंकिंग सुविधा दिल्ली में टोडापुर में उपलब्ध है। यह ट्रांसमीटरों द्वारा प्रसारित की जाने वाली जमीनी प्रसारण सेवा नहीं है और इसके प्रसारण सामान्य रेडियो सेट पर नहीं सुने जा सकते। समूचा भारत और पड़ोस के देश डीटीएच प्रसारण के दायरे में आते हैं। यह 24 घंटे चलने वाली सेवा है जिसका प्रसारण डिजिटल तरीके से किया जाता है। इसकी प्रोग्रामिंग इस तरह से की जाती है कि दोहरावट की गुंजाइश कम से कम रहे।

डीटीएच सेवा विभिन्न भाषाओं में देश के हर गली–कूचे में उपलब्ध है। डीटीएच प्रसारण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसका डिजिटल क्वालिटी का होना है।

7. विविध भारती

विविध भारती सेवा 24 घंटे चलने वाली सेवा है जो उपग्रह प्रसारण के जरिए देश भर में विभिन्न रेडियो स्टेशनों से ट्रांसमिशन के लिए उपलब्ध है। इसके कार्यक्रमों का निर्माण मुंबई में किया जाता है और वहीं से इसे अपलिंक भी किया जाता है। मूलतः विविध भारती के प्रसारण 41 सीबीएस–विविध भारती केंद्रों से रिले किए जाते हैं। इसके अलावा देश भर के 65 स्थानीय रेडियो स्टेशन और 100 वॉट के एफएम ट्रांसमीटर भी भी इन्हें रिले करते हैं।

8. लाइव स्ट्रीमिंग

आकाशवाणी लाइव न्यूज 24X7, एफएम रेनबो, एफएम गोल्ड, विविध भारती सेवाएं, रागम आदि सहित आकाशवाणी के 225 से अधिक लोकप्रिय चैनल इंटरनेट के माध्यम से प्रसार भारती की वेबसाइटः prasarbharati.gov.in पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा, इन चैनलों को आईओएस और एंड्रॉइड आधारित मोबाइल फोन पर newsonair नामक एप्लिकेशन का उपयोग करके भी सुना जा सकता है।

विदेशों के लिए सेवाएं

आकाशवाणी का विदेश सेवा प्रभाग (ईएसडी) पहुंच और रेंज दोनों दृष्टियों से दुनिया भर के विदेश नेटवर्कों में सबसे पहले पायदान पर है। वर्तमान में मीडियम वेव पर 28 भाषाओं में विदेश सेवा प्रसारण किया जाता है। इसने 27 वेब पोर्टल और मोबाइल एप पर लाइवस्ट्रीमिंग के माध्यम से एक वैश्विक छाप छोड़ी है। आकाशवाणी विदेशों में अपने श्रोताओं के लिए अरबी, बलूची, बर्मी, चीनी, दारी, अंग्रेजी, फ्रेंच, इंडोनेशियाई, फारसी, पश्तो, रूसी, सिंहला, स्वाहिली, थाई और तिब्बती भाषा में कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। विदेशों में बसे भारतीयों के लिए कई भारतीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। ये भाषाएं हैं– बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, नेपाली, पंजाबी, सिंधी, सरायिकी, तमिल, तेलुगु, उड़िया और उर्दू।

वर्ष के दौरान नई पहल

i. अभियांत्रिकी

वर्ष के दौरान नई पहल इस प्रकार हैः

a.	सीमित उत्पादन सुविधा के साथ नए एफएम ट्रांसमीटर।	2 स्थान
b.	10 किलावाट एफएम ट्रांसमीटर।	6
c.	1 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर।	4
d.	एफएम ट्रांसमीटर के साथ अतिरिक्त चैनल	1 स्थान

e. क्रिएशन ऑफ आर्काइवल फेसिलिटी, गुवाहाटी में 6 स्थानों पर 29 स्टूडियो का डिजिटलीकरण और 6 आकाशवाणी स्टूडियो का नवीकरण कार्य जारी है।

f. आकाशवाणी के लोकप्रिय चैनलों की लाइव स्ट्रीमिंग को एनआईसी स्ट्रीमिंग से सीडीएन आधारित स्ट्रीमिंग में स्थानांतरित कर दिया गया है।

ii. कार्यक्रम

आकाशवाणी लोकसंपदा संरक्षण महा परियोजना, के तहत परंपरागत लोकगीत– ''संस्कार गीत'' के प्रकाशन के लिए आकाशवाणी, साहित्य अकादेमी और राष्ट्रीय बुक ट्रस्ट के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

प्रसार भारती ने परंपरागत लोकगीत– ''संस्कार गीत'' आम लोगों तक पहुंचाने के लिए यूट्यूब चैनल शुरू किया है। इस पर अब तक विभिन्न भाषाओं और बोलियों के 500 से अधिक लोक गीतों के वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं।

आकाशवाणी की वैश्विक पहुंच बढ़ाने की दिशा में पहले कदम के रूप में, प्रसार भारती और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से विदेश मंत्रालय और अन्य हितधारकों के साथ फिर से जुड़ने के लिए पिछले दो वर्षों में पहल की गई है। विदेश मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि वे उन देशों और क्षेत्रों के बारे में बताएं जिन्हें वे देश की विदेश नीति और विदेशी संबंधों की दृष्टि से आकाशवाणी द्वारा कवर करना चाहते हैं।

आकाशवाणी की विदेश सेवाओं के तहत पिछले दो वर्षों में अपनी सभी मौजूदा 28 भाषा सेवाओं (15 विदेशी और 13 भारतीय) के लिए एक मल्टीमीडिया वेबसाइटः airworldservice.org विकसित की गई है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की है। इसमें विदेशों में आकाशवाणी के प्रसारण को वास्तव में वैश्विक बनाने के लिए कार्यक्रमों की लाइव स्ट्रीमिंग, पोडकास्ट, टेक्स्ट, वीडियो तथा पिक्चर और मोबाइल एप्लीकेशन एयरवर्ल्डसर्विस उपलब्ध कराए गए हैं। इसमें रेडियो गार्डन, ट्यून इन, एमेजॉन एलेक्सा जैसे अतिरिक्त प्लेटफार्मों के इस्तेमाल को भी शामिल किया जा रहा है।

विदेश सेवा प्रभाग के सभी वेब पोर्टलों को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर आदि के साथ जोड़ा गया है ताकि वे अधिक संवादपरक और सहभागी बन सकें जहां दुनिया के किसी भी कोने से श्रोता अपने अनुरोध और प्रतिक्रिया भेज सकें।

आकाशवाणी ने दुनिया भर में बसे बंगाल और बांग्लादेश के श्रोताओं के लिए 2016 में वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग और 1000 मेगावाट डीआरएम ट्रांसमीटर के माध्यम से दैनिक 16 घंटे का आकाशवाणी मैत्री चैनल भी शुरू किया। आकाशवाणी मैत्री चैनल बहुत सुचारू रूप से चल रहा है और विदेशों से उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया मिल रही है। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके तहत आकाशवाणी और बांग्लादेश बेतार, श्रव्य और दृश्य दोनों प्रकार के कार्यक्रमों का आदान–प्रदान करेंगे।

आकाशवाणी ने भूटान के लिए जोंग्खा भाषा में एक विशेष सेवा शुरू करने के लिए भी कदम उठाए हैं जिसे सैद्धांतिक रूप से विदेश मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है। इस सेवा को पड़ोसी देशों को तरजीह देने की सरकार की नीति के अनुपालन के तहत प्रस्तावित किया गया है।

अगस्त, 2019 से, आकाशवाणी पर प्रधानमंत्री के मासिक कार्यक्रम ''मन की बात'' का 15 भाषाओं में अनुवाद कर नियमित रूप से प्रसारित किया जा रहा है। इसे विदेश सेवा प्रभाग के यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड किया जा रहा है। इसके अलावा, मन की बात कार्यक्रम को स्पेनिश, जर्मन और जापानी भाषाओं में भी प्रसारित किया जाता है।

प्रसार भारती बोर्ड ने अपनी 157वीं बैठक में जम्मू–कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत जम्मू–कश्मीर और लद्दाख के केंद्रशासित प्रदेश बनने के सिलसिले 31.10.2019 से ''रेडियो कश्मीर'' का नाम बदलकर ''ऑल इंडिया रेडियो'' करने को मंजूरी दी। इन केंद्रों का नया नाम निम्न प्रकार होगाः

i. ऑल इंडिया रेडियो, जम्मू

ii. ऑल इंडिया रेडियो, श्रीनगर

iii. ऑल इंडिया रेडियो, लेह

iii. समाचार सेवा

1. आकाशवाणी समाचार ने 9 दिसंबर, 2019 को नागरिकता संशोधन अधिनियम जैसे महत्वपूर्ण कानून और सरकार की अन्य पहलों पर चर्चा के लिए विशेष साक्षात्कार का एक नया टॉक शो– "मंथन– फैंसलों का" शुरू किया।

2. आकाशवाणी समाचारों का यूट्यूब चैनलः न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर महिलाओं पर केंद्रित लैट्स कनेक्ट, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में होने वाली घटनाओं का एक विशेष कार्यक्रम फ्रॉम द स्टेट्स, वैश्विक घटनाक्रम पर आधारित इंटरनेशनल न्यूज़ और सप्ताह भर की प्रमुख घटनाओं पर केंद्रित वीक ऐंडर शुरू किया गया है।

3. भारत सरकार के मंत्रालयों की पहलों/कार्यक्रमों के विश्लेषण पर केंद्रित वर्षांत शृंखला के अंतर्गत प्रतिदिन प्रमुख बुलेटिनों में कहानियों का प्रसारण किया गया।

ड़. कार्यक्रम गतिविधियां

महत्वपूर्ण कवरेज का विवरण, वर्ष 2019–20 के लिए प्रसारण और रेडियो रिपोर्ट (1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक) अनुलग्नक–I में दी गई है। अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम गतिविधियां भी नीचे दी गई हैं:

क. भारत के 73वें स्वतंत्रता दिवस पर 15.08.2019 को लालकिले की प्राचीर से ध्वज फहराने की रस्म और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र को संबोधन का सीधा प्रसारण किया गया।

ख. एक भारत श्रेष्ठ भारत और स्वच्छ भारत अभियान दो बड़े अभियान हैं जिनके लिए सभी आकाशवाणी केंद्र इनकी शुरुआत से ही व्यापक प्रचार कर रहे हैं। इस बारे में मंत्रालय को कार्यवाही रिपोर्ट नियमित रूप से भेजी जा रही है।

ग. महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर व्यापक प्रचार किया जा रहा है और आकाशवाणी के सभी केंद्रों को विभिन्न प्रारूपों के माध्यम से व्यापक कवरेज देने का अनुरोध किया गया है।

घ. 26 नवंबर, 2019 को संविधान दिवस के साथ शुरू हुए अभियान के 14 अप्रैल, 2020 को अंबेडकर जयंती (राष्ट्रीय समरसता दिवस) पर समापन के बारे में यथोचित प्रचार किया जाता है।

ङ प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम सहित विभिन्न विषयों पर समय–समय पर सूचना प्रसारण मंत्रालय/प्रसार भारती को रिपोर्ट भेजी गई।

च. सरकार की 100 दिनों की उपलब्धियों को उजागर करने और जमीनी स्तर पर सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की सफलता की कहानियों पर विशेष कार्यक्रम बनाए गए।

ज. 31 अक्टूबर, 2019 को जम्मू–कश्मीर और लद्दाख को नया केंद्रशासित प्रदेश बनाने के बाद 2 नवंबर, 2019 को देश के नये राजनीतिक मानचित्र पर कार्यक्रम प्रसारित किए गए।

झ. 2022 तक सबके लिए आवास के उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (पीएमएवाई–जी) योजना को प्रचारित किया गया।

ज. राज्यसभा में पेश किए गए सिनेमैटोग्राफ संशोधन विधेयक, 2019 को जांच के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति को भेजे जाने और लोकसभा के माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रेस विज्ञप्ति पर रिपोर्ट को प्रचार दिया गया।

झ. विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के अभियानों को दिए गए प्रचार का विवरण अनुलग्नक–II में दिया गया है।

30 जून, 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात में, समारोह में अपने प्रिय का स्वागत फूलों के बजाए पुस्तक भेंट करने के मंत्र का प्रचार किया गया।

ट. विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा विभिन्न दिवसों/सप्ताह

तक आयोजित कार्यक्रमों/गतिविधियों जैसे, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, करगिल विजय दिवस, सशस्त्र सेना झंडा दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस आदि का प्रचार।

ठ. सरदार पटेल, डॉ. बी. आर. आम्बेडकर और अन्य नेताओं के शताब्दी समारोह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों/आयोजनों का प्रचार किया गया। सरदार पटेल की शताब्दी को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया था।

ड. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के तीनों राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के बारे में श्री एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में 1985 की याचिका (सिविल) संख्या 13029 के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की कार्रवाई के 4 नवंबर, 2019 की कार्रवाई।

ढ. भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेड फंड को भारत बॉन्ड ईटीएफ के तंत्र के बारे में चर्चा को प्रमुखता देते हुए प्रचार किया गया।

ण. पेयजल और स्वच्छता विभाग के स्वच्छ भारत मिशन द्वारा शुरू किए गए फ्लैगशिप कार्यक्रम को गति देने के लिए 16 से 31 जनवरी, 2020 तक स्वच्छ पखवाड़ा पर कार्यक्रमों और गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सभी आकाशवाणी केंद्रों से कहा गया था।

त. सरदार पटेल मेमोरियल लेक्चर 2019 को एक अलग प्रारूप में प्रसारित किया गया, इसे श्रोताओं के लिए एक कैप्सूल के रूप में प्रस्तुत किया गया जिसमें गुजरात के केवड़िया में माननीय प्रधानमंत्री का संबोधन, भारत के लौह पुरुष को गुजरात की श्रद्धांजलि और दिल्ली में माननीय गृहमंत्री के संबोधन में भारत के पुनर्गठन में उनके पूर्ववर्ती, सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का जिक्र किया गया था जिसका समापन जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन में हुआ। इस कैप्सूल में इन दोनों भाषणों के अलावा अक्टूबर, 2019 'मन की बात' कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस का उल्लेख और 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के बारे में आकाशवाणी द्वारा बनाया गया गीत शामिल था।

थ. सर्वभाषा कवि सम्मेलन कार्यक्रम – भारतीय भाषाओं की समृद्ध सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत को दर्शाता है। यह देश में अपनी तरह का एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जहां 22 भाषाओं के कवि अपनी सर्वश्रेष्ठ काव्यात्मकता पेश करने के लिए एक मंच पर आते हैं और यहां तक कि यह एक विश्व रिकॉर्ड भी है। अंतिम कार्यक्रम 27.12.2019 को आकाशवाणी, नई दिल्ली के परिसर में आयोजित किया गया था।

ii. आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कारः

क. आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों में काम करने वाले पेशेवरों में रचनात्मक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने तथा उन्हें और बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते हर साल आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार घोषित किए जाते हैं।

ख. आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार 2018 की कार्यक्रम श्रेणियों की प्रविष्टियों के लिए आकाशवाणी के महानिदेशालय, में 24 से 27 सितम्बर, 2019 तक जूरी सत्र आयोजित किया गया था। देश भर के विभिन्न आकाशवाणी केंद्रों से कार्यक्रम की 14 श्रेणियों के लिए प्राप्त 106 प्रविष्टियों पर विचार किया गया और आकाशवाणी महानिदेशक द्वारा पुरस्कारों की घोशणा की गई थीं।

ग. 12 नवंबर, 2019 को लोक सेवा प्रसारण दिवस पर आकाशवाणी, दिल्ली परिसर में आयोजित एक समारोह में गांधीवादी दर्शन और लोक सेवा प्रसारण पुरस्कार 2019 घोषित किए गए। डॉ. हुकम सरमा की प्रविष्टि समझौता को गांधीवादी दर्शन श्रेणी में और "शांतिदूत–रेडियो" को लोक सेवा प्रसारण श्रेणी में विजेता के रूप में घोषित किया गया।

घ. आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार 2016–2017 का प्रस्तुति समारोह 24 दिसंबर, 2019 को आयोजित किया गया था।

iii. अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमः

कृषक समुदाय की मौसमी जरूरतों को पूरा करने के लिए कार्यक्रम तैयार किए गए हैं जिनमें सर्वश्रेष्ठ कृषि उत्पादन के लिए नवीनतम सूचना और प्रौद्योगिकी को शामिल किया गया है। इनके अलावा रोजगार योजनाओं, ऋण, बीमा और प्रशिक्षण सुविधाओं, स्वच्छता, स्वास्थ्य और पोषण आदि पर भी कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं।

आकाशवाणी ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग के सहयोग से फरवरी, 2004 से कृषि विस्तार के लिए मास मीडिया समर्थन पर एक विशेष परियोजना किसानवाणी के शुभारंभ के साथ अपने कृषि प्रसारण का विस्तार किया ताकि स्थानीय किसानों को दिन–प्रतिदिन की बाजार दरों, मौसम

की रिपोर्ट और अपने क्षेत्रों के बारे में सूक्ष्म स्तर पर दैनिक जानकारी दी जा सके। वर्तमान में किसानवाणी का प्रसारण देश भर के चयनित 96 आकाशवाणी केंद्रों से किया जा रहा है। सितंबर 2018 से, किसानवाणी की तर्ज पर एक नया कृषि कार्यक्रम 'किसान की बात', भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से शुरू किया गया है और आकाशवाणी, दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल से प्रसारित किया जा रहा है। इसने स्वास्थ्य कल्याण, बाल कार्यक्रम, संगीत और परिवार और खेल पर विभिन्न कार्यक्रम किये।

क. कीटनाशकों के सुरक्षित और विवेकपूर्ण उपयोग पर अभियान

कीटनाशकों के सुरक्षित तथा विवेकपूर्ण उपयोग और उपभोग से पहले फलों व सब्जियों में कीटनाशक अवशेषों को कम करने के तरीकों और साधनों के बारे में आम जनता और विशेष रूप से कृषक समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करने वाले कार्यक्रम, प्रसारित किए गए हैं।

कीटनाशकों की खरीद, भंडारण, रखरखाव और छिड़काव करते समय किसानों को क्या करना है और क्या नहीं करना है इस बारे में प्रचार करने के लिए आकाशवाणी केंद्रों को व्यापक दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। केंद्रों ने अपने कार्यक्रमों में खाद्य पदार्थों, फलों और सब्जियों में कीटनाशक के अवशेषों को कम से कम करने के लिए उपभोक्ताओं और नागरिकों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस बारे में भी कार्यक्रम प्रसारित किए।

ख. किसानों के लिए मौसम का व्यापक पूर्वानुमान

सभी आकाशवाणी केंद्रों से कृषि और गृह कार्यक्रमों में किसानों के लिए पांच मिनट की अवधि का मौसम का व्यापक पूर्वानुमान और सभी 96 केंद्रों से किसानवाणी का दैनिक प्रसारण किया जाता है। दैनिक मौसम पूर्वानुमान कवरेज में वर्षा, तापमान, मिट्टी और वायु नमी, गर्मी, सर्दी, शुष्कता, जैसे महत्वपूर्ण मापदंडों और चरम स्थितियों जैसे सूखा, बाढ़, आंधी तूफान, चक्रवात, ओले, विकिरण आदि के बारे में जानकारी दी जाती है ताकि किसानों को सतर्क किया जा सके और उन्हें फसल की विफलता को रोकने में मदद मिल सके।

ग. पर्यावरण

पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन कर हर साल 5 जून को सभी आकाशवाणी केंद्रों में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सामाजिक वानिकी के मुद्दे, भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण को रोकने, ओजोन रिक्तीकरण, फसल कटाई के बाद के प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, जल संचयन, स्वच्छता (स्वच्छ भारत अभियान), ध्वनि प्रदूषण और पर्यावरण के अनुकूल कृषि पद्धतियों के बारे में विशेषज्ञों से साक्षात्कार करके उनका प्रसारण किया जाता है।

वायु प्रदूषण कम करने और पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पर जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ष 2019 के लिए विषयः **'वायु प्रदूषण को कम करना'** को सभी केंद्रों द्वारा उजागर किया गया था।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 29 अगस्त से 14 सितंबर, 2019 तक, ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क II में इंडिया एक्सपो मार्ट में यूएनसीसीडी के सीओपी 14 की मेजबानी की। इसमें 150 से अधिक देशों ने भाग लिया। आकाशवाणी ने इस आयोजन को कवर किया और इससे पहले तथा बाद के घटनाक्रम को भी कवरेज प्रदान की गई।

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए 'स्वच्छ भारत अभियान' के लिए निरंतर प्रचार किया जा रहा है, इसमें सभी के लिए स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करने में ग्रामीण और शहरी दोनों की स्वच्छता के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

कृषि तथा गृह और किसानवाणी कार्यक्रमों का प्रसारण करने वाले आकाशवाणी केंद्रों को सुझाव दिया गया है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत मीडिया अभियान के भाग के रूप में, कृषि कार्यों में खाद के रूप में जैविक ठोस अपशिष्टों के उपयोग के बारे में, किसानों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए, विभिन्न प्रारूपों में उपयुक्त कार्यक्रमों को बढ़ाएं। आकाशवाणी केंद्रों को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों पर ऑडियो स्पॉट प्रसारित करने का निर्देश दिया गया है।

घ. किसानों को फसल विशेष के बारे में सलाह का प्रचार

आलू उगाने वाले क्षेत्रों में स्थित केंद्रों को सलाह दी गई है कि वे केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, मेरठ द्वारा अनुमानित मौसमी आलू की फसलों के लिए फफूंदी रोगों के लिए निवारक उपायों को अपनाने के लिए किसानों में जागरूकता पैदा करने वाले कार्यक्रम प्रसारित करें।

हरियाणा और पंजाब राज्यों में स्थित केंद्रों को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की गई सलाह के अनुसार

खरीफ कपास फसलों में सफेद मक्खी के संक्रमण की घटनाओं के मद्देनजर किसानों के लिए जागरूकता अभियान चलाने का सुझाव दिया गया था।

ङ. किसानवाणी प्रभाव आकलन और क्षमता निर्माण कार्यशालाएं

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और आकाशवाणी महानिदेशालय के अधिकारियों के प्रतिनिधित्व के अलावा, इन कार्यशालाओं में क्षेत्रीय विषय वस्तु/कृषि उद्योग के विशेषज्ञों, कृषि वैज्ञानिकों, मौसम विभाग के कृषि मौसम वैज्ञानिकों, राज्य कृषि विभाग/जिला प्रशासनिक अधिकारियों, एनआईसी के वैज्ञानिकों, आईटी विशेषज्ञों, प्रगतिशील किसानों आदि ने भाग लिया। चार ऐसी कार्यशालाएं सफलतापूर्वक आयोजित की गई हैं, जो महाराष्ट्र में नागपुर के केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान में 06 से 08 फरवरी, 2019 तक, कर्नाटक में मैसूर के प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान में 18 से 20 मार्च, 2019 तक, हिमाचल प्रदेश में पालमपुर के चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय में 3 से 5 जुलाई, 2019 तक और अंतिम कार्यशाला मणिपुर में इंफाल के केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में 18 से 20 दिसंबर, 2019 तक सफलतापूर्वक आयोजित की गई थीं।

vi. खेलः

1 अप्रैल, 2019 से 31 दिसंबर, 2019 की अवधि के दौरान, आकाशवाणी ने अपने नेशनल हुक–अप के साथ–साथ क्षेत्रीय स्टेशनों पर विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की समुचित कवरेज की। आकाशवाणी के एफएम, एएम और डीआरएम चैनल के अलावा, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप की पूर्ण कमेंट्री भी प्रसार भारती यूट्यूब चैनल और मोबाइल ऐप पर दी गई, जिसमें लाइव कमेंट्री के लिए रेडियो का उपयोग करने वाले लाखों श्रोता इससे जुड़े हैं।

पांच साल के अंतराल के बाद प्रसार भारती और बीसीसीआई ने घरेलू मैचों सहित भारत में बीसीसीआई द्वारा आयोजित क्रिकेट मैचों की लाइव कमेंट्री के प्रसारण के लिए दो साल के राजस्व साझा करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए।

विवरण निम्न प्रकार है–

क. क्रिकेट

2020 में कवर किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यक्रम (1 जनवरी से 31 मार्च तक)

आकाशवाणी ने, जहां भी आवश्यकता हो, प्रसारण अनुमति –अधिकारों के अधिग्रहण के अधीन, 1 जनवरी, 2020 से 31 मार्च, 2020 के दौरान अपने राष्ट्रीय हुक–अप पर विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों को लाइव कवरेज प्रदान करने का प्रस्ताव किया है। ऐसे कुछ आयोजनों का विवरण इस प्रकार हैः

1) क्रिकेट

च. आकाशवाणी की समाचार सेवा

आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग (एनएसडी) भारत और विदेशों में श्रोताओं को समाचार और समाचार आधारित कार्यक्रमों का प्रसार करता है। यह रेडियो प्रसारण में उच्चतम पेशेवर नैतिकता और मानकों का पालन करते हुए, प्रतिदिन 92 भाषाओं और बोलियों में 607 से अधिक बुलेटिनों का प्रसारण करता है। नई तकनीक का उपयोग करके आकाशवाणी समाचार अब वेबसाइट पर अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती और ट्विटर पर मराठी भाषा में उपलब्ध है।

1. संगठनात्मक संरचना

समाचार सेवा प्रभाग का नेतृत्व प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक (समाचार) करता है, जो भारतीय सूचना सेवा के सबसे वरिष्ठ अधिकारियों में से एक है। प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक (समाचार) को अतिरिक्त महानिदेशकों (समाचार), निदेशकों (समाचार), उप निदेशकों (समाचार), सहायक निदेशकों (समाचार), समाचार संपादकों और रिपोर्टरों की एक टीम द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

दिल्ली मुख्यालय में एनएसडी के विभिन्न परिचालन शाखाओं में शामिल हैं– जनरल न्यूज रूम, हिंदी समाचार कक्ष, रिपोर्टिंग इकाई, वार्ता और करंट अफेयर्स यूनिट, न्यूजरील यूनिट, भारतीय भाषा इकाइयां, संदर्भ एवं पीपी एंड डी इकाई, आईटी तथा वेबसाइट इकाई और प्रशासनिक विंग।

ii. क्षेत्रीय समाचार इकाइयां

विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय समाचार इकाइयों (आरएनयू) का नेतृत्व निदेशक या उप/सहायक निदेशक के पद के अधिकारी करते हैं और समाचार संपादक, रिपोर्टर और समाचार वाचक सह अनुवादक इनकी सहायता करते हैं। देश भर में 46 क्षेत्रीय समाचार इकाइयां हैं।

iii. वार्ता और करंट अफेयर्स कार्यक्रम

वार्ता और करंट अफेयर्स यूनिट विभिन्न विषयों पर

विश्लेषणात्मक समाचार आधारित कार्यक्रमों का प्रसारण करती है। इसका उद्देश्य श्रोताओं को प्रमुख नए घटनाक्रम को समझने में मदद करना है, चीजों को उनके परिप्रेक्ष्य में पेश करना और किसी विषय के बारे में विस्तार से जानकारी पहुंचाना है। इसके कार्यक्रमों में सामयिक महत्व के विषयों पर चर्चा में संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ भाग लेते हैं। दैनिक और साप्ताहिक कार्यक्रमों में विभिन्न विषयों पर व्यापक रूप से चर्चा की जाती है, समाचार विश्लेषण, सामयिकी, मार्किट मंत्र, स्पोर्ट्स स्कैन, समाचार दर्शन, प्रेस कमेंट्स, परिक्रमा, आज सवेरे, गल्फ चर्चा, पब्लिक स्पीक, वाद–संवाद, मनी टॉक, चर्चा का विशय, सुर्खियों में, कंट्रीवाइड और करंट अफेयर्स शामिल हैं।

पब्लिक स्पीक एक बहुत ही लोकप्रिय फोन–इन कार्यक्रम है। पैंतीस मिनट के इस द्विभाषी कार्यक्रम में सप्ताह के विषय पर श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए दो विशेषज्ञों को बुलाया जाता है, इनमें मंत्री और अधिकारी भी शामिल हैं।

न्यूजरील यूनिट रोजाना न्यूजरील और समाचार दर्शन कार्यक्रम प्रसारित करती है। इसमें दैनिक समाचारों के अलावा, स्वच्छ भारत अभियान, योग दिवस और अन्य गतिविधियों और कार्यक्रमों के बारे में सामग्री प्रसारित की जाती है।

iv महत्वपूर्ण कवरेज (अप्रैल–दिसंबर, 2019)

क. विषयगत दृष्टिकोण

आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विषय आधारित संचार करता है। प्रभाग के बुलेटिनों, वेबसाइट और सोशल मीडिया (ट्विटर, फेसबुक) में आम चुनावों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण समाचारों, जम्मू और कश्मीर व लद्दाख के संघ शासित प्रदेशों के निर्माण संबंधी घटनाक्रम, महाराष्ट्र, हरियाणा में विधानसभा चुनाव और उप–चुनाव, नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, एक भारत श्रेष्ठ भारत और राष्ट्रीय एकता दिवस, गांधी की 150वीं जयंती और राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय महत्व की अन्य घटनाओं, को कवर किया गया।

ख. विशेष कार्यक्रम

1) चुनावः लोकसभा और विधानसभा

समाचार सेवा प्रभाग ने आम चुनाव 2019 और विधानसभा चुनावों की विस्तृत कवरेज दिल्ली मुख्यालय और पूरे देश में स्थित क्षेत्रीय समाचार इकाइयों से दी। समाचार सेवा प्रभाग ने अंग्रेजी और हिंदी में अपने तीन–तीन प्रमुख समाचार बुलेटिनों के माध्यम से चुनाव परिणाम के साथ–साथ मतदान, चुनाव प्रचार, चुनाव प्रक्रिया को कवर करने के लिए समाचार आइटमों में बाईट और वॉयसकास्ट को प्रसारित किया गया। परिचर्चाएं और समाचार पत्रिका कार्यक्रम भी प्रसारित किए गए। इसके अलावा, अन्य भारतीय भाषाओं और क्षेत्रीय समाचार बुलेटिनों में भी चुनाव की खबरें दीं और विशेष चर्चा कार्यक्रम किए।

चुनाव परिणामों पर विशेष कार्यक्रम हिंदी और अंग्रेजी में विशेष जनादेश 2019 आकाशवाणी एफएम गोल्ड और अन्य चैनलों पर लगातार 40 घंटे प्रसारित किया गया। यह पहली बार था जब आकाशवाणी ने लगातार 40 घंटे तक किसी विषय पर कवरेज दी। 40 घंटे की लंबी लाइव द्विभाषी चर्चा के अलावा प्रमुख समाचार बुलेटिनों और प्रति घंटा समाचार बुलेटिनों में चुनाव नतीजों संबंधी समाचार दिए गए। चुनाव नतीजों पर लाइव द्विभाषी कार्यक्रम –रेडियो ब्रिज का प्रसारण किया गया। मुख्यालय के कुछ बुलेटिनों की अवधि बढ़ाई गई तथा चुनाव परिणामों और राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाओं को व्यापक और निष्पक्ष कवरेज दी गई। इसी प्रकार, क्षेत्रीय समाचार बुलेटिनों ने भी श्रोताओं को उनकी भाषा में जानकारी देने के लिए समाचार बुलेटिनों की अवधि को बढ़ाया। प्रभाग और इसकी क्षेत्रीय समाचार इकाइयों के अधिकारियों, संवाददाताओं और संपादकों के साथ–साथ आकाशवाणी के अंशकालिक संवाददाताओं के लिए लोकसभा और विधानसभा चुनावों की कवरेज के बारे में जानकारी देने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर गहन जागरूकता अभियान चलाने के अलावा मिनट–दर–मिनट अपडेट भी दिया गया। लाइव ट्वीट के रूप में और मतदान प्रतिशत अपडेट पर व्यापक कवरेज भी दी गई। आम चुनाव–2019 के लिए एक अलग वेबपेज बनाया गया था। जागरूकता सामग्री, विशेष कार्यक्रमों के विभिन्न खंड नियमित रूप से अपडेट किए गए। क्षेत्रीय समाचार इकाइयों से इनपुट के साथ व्यापक सामग्री तैयार की गई थी।

ii) नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019

दिसंबर, 2019 के दौरान नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 और इसके प्रावधानों को व्यापक कवरेज दी गई। माननीय राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द, उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, कैबिनेट मंत्रियों और कई शीर्ष अधिकारियों के बयान बुलेटिन और समाचार आधारित कार्यक्रमों में शामिल किए गए। समाचार पत्रिका कार्यक्रमः आज

सवेरे और परिक्रमा तथा अन्य सभी बुलेटिनों में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम की मुख्य विशेषताएं बताई गईं और अधिनियम के बारे में अफवाहें फैलाने वालों को उजागर किया गया था। इसके अलावा, अधिनियम के व्याख्याताओं के बयानों को सभी बुलेटिनों में प्रसारित किया गया था, कानून का समर्थन करने वाले शरणार्थियों की प्रतिक्रियाएं ली गईं। विशेष बातचीत और चर्चाओं में इस कानून के बारे में संदेह और गलत जानकारी तथा भ्रम को प्रमुखता से स्पष्ट किया गया। क्षेत्रीय समाचार इकाइयों ने भी इस बारे में विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए।

iii) करतारपुर साहिब कॉरिडोरः गुरु नानक देवजी की 550वीं जयंती

समाचार सेवा प्रभाग ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर से संबंधित घटनाओं और गुरु नानक देवजी की जयंती पर समाचार प्रसारित किए। संबंधित समाचारों के साथ गृह मंत्रालय का विशेष प्रोमो भी चलाया गया। डेरा ननकाना साहिब पर विशेष रिपोर्ट और करतारपुर कॉरिडोर तथा सुल्तानपुर लोदी पर ग्राउंड रिपोर्ट प्रसारित की गई। उद्घाटन के लिए 8 और 9 नवंबर, 2019 को तीन अलग–अलग स्थानों पर संवाददाताओं को तैनात किया गया था, साथ ही प्रधानमंत्री के भाषण का लाइव प्रसारण भी किया गया था।

क्षेत्रीय समाचार इकाइयों– चंडीगढ़, शिमला, जम्मू, औरंगाबाद, मुंबई, नागपुर और पुणे ने अपने बुलेटिनों और कार्यक्रमों में 16 अगस्त, 2019 से संबंधित समाचार प्रसारित किए। विशेष न्यूजरील कार्यक्रम भी प्रसारित किया। विशेष संवाददाताओं द्वारा शोभा यात्रा और अंतरराष्ट्रीय नगर कीर्तन से संबंधित कवरेज नियमित रूप से की गई।

मानवता से संबंधित गुरु नानक के संदेश समाचार बुलेटिन और समाचार पत्रिका कार्यक्रमों में भी प्रसारित किए गए थे।

iv) जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन

समाचार सेवा प्रभाग के बुलेटिनों, वेबसाइट और सोशल मीडिया (ट्विटर, फेसबुक) ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण समाचारों को कवर किया, जिसमें संसद में विधेयक पारित होना, विधेयक की मुख्य विशेषताएं और लोकसभा तथा राज्यसभा में गृहमंत्री के भाषण शामिल हैं। प्रधानमंत्री का राष्ट्र को संबोधन लाइव प्रसारित किया गया, साथ ही यूट्यूब पर इसका लाइव कश्मीरी अनुवाद भी दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों के भाषणों के प्रमुख अंश और पूरा भाषण कश्मीरी, डोगरी और लद्दाखी में अनुवादित किया गया, डीडी न्यूज के साथ साझा किया गया और जम्मू और कश्मीर में व्यापक रूप से यूट्यूब पर प्रसारित किया गया।

विशेषकर कश्मीरी, डोगरी और लद्दाखी बुलेटिन में जम्मू कश्मीर स्थिति के अपडेट, स्थिति के सामान्य होने के बारे में नियमित रूप से सामग्री का प्रसारण किया गया। लोगों तक आधिकारिक जानकारी पहुंचाने के लिए इसमें उपराज्यपाल और अन्य अधिकारियों के साउंड बाइट्स भी शामिल किए गए।

प्रभाग ने समाचार एजेंसियों, जम्मू और कश्मीर की और अन्य की खबरों पर आधारित हर आठ घंटे पर दी जाने वाली स्थिति रिपोर्ट 5 से 9 अगस्त 2019 तक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ साझा की। क्षेत्रीय समाचार इकाई, जम्मू द्वारा प्रतिदिन सुबह 7 बजे तैयार की गई प्रेस फीडबैक को भी साझा किया गया। प्रेस के साथ की गई बातचीत बाईट के साथ बुलेटिनों में शामिल की गई थी।

कश्मीरी बुलेटिनों की अवधि भी 10 मिनट बढ़ा दी गई थी।

अनुच्छेद 370, 35 ए पर पृष्ठभूमि, अनुच्छेद–370 को खत्म करने के निहितार्थ, महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों और अल्पसंख्यकों पर प्रभाव को त्वरित संदर्भ के लिए जारी किया गया। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के भाषण के मुख्य अंश एक पुस्तिका में संकलित किए गए और डीएवीपी के साथ साझा किए गए।

डीडी न्यूज के इनपुट्स के साथ जम्मू, लेह, करगिल और श्रीनगर से ग्राउंड रिपोर्ट भी नियमित रूप से प्रसारित की गई।

दीपावली पर माननीय प्रधानमंत्री की जम्मू और कश्मीर यात्रा, जम्मू और कश्मीर व लद्दाख को संघ शासित प्रदेश बनाने और उपराज्यपाल के शपथ ग्रहण जैसे कार्यक्रमों पर भी विशेष अद्यतन जानकारी प्रसारित की गई।

स्थिति पर चर्चा के कार्यक्रम, विश्व मंच पर भारत को समर्थन, जम्मू और कश्मीर के विकास, बीडीसी चुनाव, मुद्दे और रोडमैप को अगस्त, 2019 से नियमित रूप से प्रसारित किया गया। विधेयक पर प्रधानमंत्री के भाषण और अन्य संबंधित विषयों पर विशेष द्विभाषी कार्यक्रमों का प्रसारण भी किया गया।

v) संसद का शीतकालीन सत्र

सभी चैनलों पर व्यापक कवरेज दी गईः संविधान (126वां संशोधन) विधेयक, लोकसभा तथा विधानसभाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की अवधि बढ़ाने, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक, 2019, दिवाला तथा ऋण शोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2019, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अनधिकृत कॉलोनियों में निवासियों के संपत्ति अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2019।

vi) तीन तलाक/अन्य ऐतिहासिक निर्णय

तीन तलाक और संसद में विभिन्न विधेयकों/संशोधनों के पारित होने सहित ऐतिहासिक निर्णयों के लिए प्रमुख कवरेज प्रदान की गई थी। इन विषयों पर चर्चा कार्यक्रम भी प्रसारित किए गए। ये समाचार पत्रिका के कार्यक्रमों में भी शामिल थे।

vii) संविधान दिवस

नागरिकों के मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए संविधान दिवस संबंधी गतिविधियों को सभी बुलेटिनों और चर्चा आधारित कार्यक्रमों में शामिल किया गया था। क्षेत्रीय समाचार इकाइयों ने इस दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए घटनाओं को विस्तृत कवरेज दिया। सोशल मीडिया ने संविधान और मौलिक कर्तव्यों से संबंधित एक अभियान चलाया। इसके ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब चैनलों ने भी संविधान दिवस से संबंधित घटनाओं को पोस्ट किया और इसके महत्व पर प्रमुख सरकारी अधिकारियों के बयान भी शामिल किए गए। संविधान दिवस पर मुख्यालय और क्षेत्रीय समाचार इकाइयों में कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई।

viii) एक भारत श्रेष्ठ भारत और राष्ट्रीय एकता दिवस

अक्टूबर–नवंबर, 2019 में क्षेत्रीय समाचार इकाइयों से प्राप्त जानकारी के साथ इस विशय पर विशेष सामग्री का प्रसारण किया गया। इसके साथ ही, समाचार सेवा प्रभाग ने सरदार पटेल और गृह मंत्रालय के कार्यालय द्वारा जारी प्रोमो को बड़े पैमाने पर प्रसारित किया। एक भारत श्रेष्ठ भारत पर टॉक शो भी प्रस्तुत किए गए।

आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के सोशल मीडिया सेल ने राज्यों की जोड़ी और 100 प्रमुख संदेशों की क्षेत्रीय बातचीत के साथ ही राज्यों के बीच सांस्कृतिक आदान–प्रदान पर ध्यान केंद्रित किया।

राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, रन फॉर यूनिटी और सरदार पटेल के योगदान पर प्रकाश डाला गया।

एकता दिवस के लिए, केवडिया और नई दिल्ली में कार्यक्रमों की तैयारियों से संबंधित समाचार प्रमुखता से प्रसारित किए गए। आयोजन के दिन भी व्यापक कवरेज दी गई। केवडिया और देश के अन्य हिस्सों से बुलेटिनों में लाइव इनपुट दिए गए थे।

जम्मू–कश्मीर, मध्यप्रदेश, पंजाब, हरियाणा, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पुद्दुचेरी, तमिलनाडु और अन्य राज्यों से ग्राउंड रिपोर्ट प्रसारित की गई। समाचार पत्रिका के कार्यक्रमों पर विशेष रिपोर्ट भी प्रसारित की गई।

इसके अतिरिक्त, समाचार सेवा प्रभाग ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर व्यापक प्रसार किया।

प्रधान महानिदेशक सुश्री इरा जोशी ने आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग में सभी कर्मियों को एकता शपथ दिलाई।

ix) महात्मा गांधी की 150वीं जयंती

महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के लिए समाचार सेवा प्रभाग और इसकी क्षेत्रीय समाचार इकाइयों द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में प्रभावी प्रचार की गई।

सभी संबंधित घटनाओं की मौके पर कवरेज, विशेष रूप से जयंती के दिन और पूर्व संध्या पर सफलतापूर्वक आयोजित की गई थी।

समाचार पत्रिका के कार्यक्रमों में विशेष चर्चा, ग्राउंड रिपोर्ट और साथ ही विशेष साक्षात्कार प्रसारित किए गए।

गांधीजी के भाषणों और ग्राफिक्स के साथ एक सामाजिक मीडिया अभियान, समर्पित हैशटैग के साथ काफी लोकप्रिय साबित हुआ है। जयंती पर समाचार सेवा प्रभाग की वेबसाइट का गुजराती संस्करण भी शुरू किया गया था।

समाचार सेवा प्रभाग ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर उन्हें समर्पित अपनी समाचार भारती पत्रिका भी जारी की। एक जाने–माने गांधीवादी विशेषज्ञ ने इस अवसर की शोभा बढ़ाई। गांधी प्रश्नोत्तरी भी आयोजित की गई और पुरस्कार के रूप में गांधीजी पर प्रकाशन विभाग की पुस्तकें दी गईं। गांधीजी पर एक फोटो प्रदर्शनी भी आयोजित की गई थी।

x) सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करने/स्वच्छता ही सेवा के लिए अभियान

दशहरे सहित विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान और मामल्लपुरम में सवेरे की सैर के दौरान प्रधानमंत्री के कचरा उठाने सहित देश भर में प्लॉगिंग रन को व्यापक कवरेज दी गई।

गुवाहाटी, जयपुर, विजयपुरा सिटी कॉर्पोरेशन, त्रिपुरा और अन्य जगहों से ग्राउंड रिपोर्ट प्रसारित की गई।

संबंधित विषयों पर चर्चा कार्यक्रम और समाचार पत्रिका कार्यक्रम भी प्रसारित किए गए।

प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो और ग्राफिक्स के साथ अभियान चलाया गया।

xi) फिट इंडिया

स्पॉट न्यूज कवरेज के अलावा, मामल्लपुरम, तमिलनाडु में प्रधानमंत्री और फिट इंडिया के लिए रन फॉर यूनिटी के महत्व के बारे में प्रधानमंत्री के बयान को समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रमुखता से कवर किया गया था। समाचार सेवा प्रभाग और इसकी क्षेत्रीय समाचार इकाइयों ने युवा मामलों के केंद्रीयमंत्री किरेन रिजिजू और प्रमुख खेल हस्तियों–पीवी सिंधु, गौतम गंभीर, दीपा करमाकर, सुशील कुमार, दीपा मलिक, सतपाल, प्रणब रे और बासवारेड्डी के विशेष साक्षात्कार प्रसारित किए। फिट और चुस्त रहने के बारे में, विभिन्न राज्यों से क्षेत्रीय समाचार इकाइयों की विशेष ग्राउंड रिपोर्ट पूरे सप्ताह प्रसारित करने के अलावा समाचार सेवा प्रभाग और इसकी क्षेत्रीय समाचार इकाइयों ने परिचर्चा कार्यक्रमों का प्रसारण भी किया।

xii) मन की बात

आकाशवाणी पर हर महीने मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री के संबोधन को सभी प्रमुख समाचार बुलेटिनों में शामिल किया गया, जिनमें क्षेत्रीय भाषाओं के बुलेटिन भी शामिल हैं। समाचार सेवा प्रभाग की वेबसाइट पर लाइव वेबकास्टिंग भी की गई थी। वार्ता और करंट अफेयर्स में भी मन की बात पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया गया था।

समाचार सेवा प्रभाग और इसकी क्षेत्रीय समाचार इकाइयां: आकाशवाणी ने मन की बात को अपने 223 बुलेटिनों, और 77 भाषाओं तथा बोलियों में 255 एफएम मुख्य समाचारों में कवर किया। इसके अलावा, इसकी क्षेत्रीय समाचार इकाइयों ने अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में ट्वीट करके अपने संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर व्यापक प्रचार किया।

राष्ट्र को प्रधानमंत्री के मासिक संबोधन के पारंपरिक प्रसारण के अलावा, इसकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव वेबकास्टिंग, ट्वीट और अपडेट भी किया गया था।

माननीय प्रधानमंत्री के भाषण में उद्धृत उदाहरणों पर आधारित विशेष ग्राफिक्स और सफलता की कहानियां भी उसी दिन प्रसारित की जाती हैं।

प्रभाग ने मन की बात से संबंधित समाचारों और कार्यक्रमों को 223 बुलेटिनों, 77 भाषा और बोलियों में 256 एफएम मुख्य समाचारों में प्रसारित किया। इसके अलावा, समाचार सेवा प्रभाग मुख्यालय और क्षेत्रीय समाचार इकाइयां, समाचार–आधारित चर्चा के कार्यक्रमों के साथ–साथ लोगों की प्रतिक्रियाएं भी साझा करते हैं।

ग. नई पहल

i) मंथन– फैसलों का

आकाशवाणी समाचार ने 9 दिसंबर, 2019 को एक नया टॉक शो– "मंथन– फैसलों का" शुरू किया, जिसमें नागरिकता संशोधन अधिनियम और सरकार की अन्य पहलों जैसे महत्वपूर्ण कानूनों पर चर्चा के लिए विशेष साक्षात्कार प्रसारित किए गए। 20 से अधिक एपिसोड में शामिल कुछ प्रमुख विषयों में शस्त्र संशोधन विधेयक और व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा विधेयक, आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने वाली योजनाएं, स्वच्छ भारत अभियान, जम्मू-कश्मीर में विकास को गति देने की पहल शामिल हैं।

आकाशवाणी समाचार का यूट्यूब चैनल-न्यूज़ ऑन एआईआर ऑफिशियल नए कार्यक्रमों के लिए शुरू किया गया। ये कार्यक्रम है- महिलाओं पर केंद्रित लेटअस कनेक्ट, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में होने वाली विशेष घटनाओं पर केंद्रित राउंडअप- फ्राम द स्टेट्स, वैश्विक घटनाक्रम पैकेज -इंटरनेशनल न्यूज़, सप्ताह भर के प्रमुख समाचार- सप्ताहांत।

भारत सरकार के मंत्रालयों की पहल/कार्यक्रमों के विश्लेषण पर केंद्रित वर्षांत शृंखला के अंतर्गत प्रमुख बुलेटिनों में कहानियों का दैनिक प्रसारण होता है। अर्थव्यवस्था, स्वच्छ और हरित पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए जल संरक्षण से लेकर अटल भूजल योजना तक के विषयों को कवर करते हुए वर्षांत कार्यक्रम में परिचर्चा और टॉक शो किए गए।

ii) महत्वपूर्ण दौरे और यात्राएं

माननीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के विदेश दौरे को प्रमुखता से कवरेज दी गई। माननीय प्रधानमंत्री ने

भारत और विदेशों में राष्ट्रीय विदेश संबंधों के लिए कई उच्च स्तरीय बैठकों में भाग लिया। इनमें प्रधानमंत्री की शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए बिश्केक की यात्रा, जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान की यात्रा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ ही पूर्वी एशिया, पश्चिम एशिया और यूरोप के अन्य हिस्सों की यात्राएं शामिल हैं। आगामी महत्वपूर्ण यात्राओं में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दूसरा अनौपचारिक शिखर सम्मेलन शामिल है।

इनके लिए, समाचार सेवा प्रभाग ने बुलेटिन में लाइव इनपुट सहित नियमित समाचार कवरेज प्रसारित किया। यूट्यूब, वेबसाइट और फेसबुक पर भी लाइव कवरेज की गई।

बैठकों से पहले पृष्ठभूमि की जानकारी देकर सभी आयोजनों और बैठकों की व्यापक कवरेज की गई।

समाचार पत्रिका के कार्यक्रमों, आज सवेरे और परिक्रमा में ग्राउंड रिपोर्ट, साथ ही वार्ता और चर्चा कार्यक्रमों में गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया गया।

iii) भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्मोत्सव 2019

भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्मोत्सव 2019 से संबंधित समाचार प्रमुख बुलेटिनों और समाचार पत्रिका कार्यक्रमों में विशेश प्रोमो के साथ शामिल किए गए। भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्मोत्सव की स्वर्ण जयंती पर समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी के यूट्यूब चैनल पर एक घंटे का कार्यक्रम इफ्फी@50 प्रसारित किया गया।

iv) जलियांवाला बाग नरसंहार की सालगिरह

समाचार सेवा प्रभाग ने जलियांवाला बाग नरसंहार की वर्षगांठ पर 13.04.2019 को व्यापक कवरेज दी। प्रभाग और उसकी क्षेत्रीय समाचार इकाइयों ने अमृतसर से माननीय उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू की श्रद्धांजलि, स्मारक सिक्का तथा डाक टिकट जारी करने और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संचार एवं लोक संपर्क कार्यालय द्वारा नरसंहार पर आयोजित एक प्रदर्शनी के दौरे को मौके पर जाकर कवर किया। इस दिन समाचार सेवा प्रभाग ने जलियांवाला बाग नरसंहार के 100 वर्ष शीर्षक से एक विशेष द्विभाषी कार्यक्रम भी प्रसारित किया। नरसंहार पर टेम्पलेट्स की एक शृंखला 06 अप्रैल, 2019 से साझा की गई थी। प्रभाग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मो ने जलियांवाला बाग नरसंहार की सालगिरह से संबंधित गतिविधियों की तस्वीरें साझा करने के अलावा उचित ट्वीट और फेसबुक प्रविष्टियां भी तैयार कीं। क्षेत्रीय समाचार इकाइयों ने भी इसी तरह के कार्यक्रम किए। सोशल मीडिया के लिए इस घटना पर एक विशेष संक्षिप्त इतिहास तैयार किया गया। जलियांवाला बाग पर ब्रिटेन की संसद में बयान देते हुए वहां के प्रधानमंत्री का एक वीडियो भी ट्विटर और फेसबुक पर साझा किया गया था।

v) डॉ. भीमराव रामजी आम्बेडकर जयंती

समाचार सेवा प्रभाग और उसकी क्षेत्रीय समाचार इकाईयों ने भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार डॉ. भीमराव रामजी आम्बेडकर की 128वीं जयंती पर 14.4.2019 को राष्ट्र द्वारा उन्हें याद किए जाने को प्रमुखता से कवर किया। उन्होंने इस अवसर पर देशभर में आयोजित कार्यक्रमों को कवर किया। इन कार्यक्रमों में माननीय राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा संसद भवन परिसर में बाबासाहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करना शामिल था। एक विशेष कार्यक्रम– ''डॉ. बी. आर. आम्बेडकर– एक महान समाज सुधारक'' किया गया था और इसे स्पॉटलाइट तथा सामायिकी कार्यक्रम में प्रसारित किया गया था।

vi) चक्रवात और बाढ़ की कवरेज

वर्ष 2019 के दौरान कुछ राज्यों में आए भयंकर चक्रवाती तूफानों पर केंद्र सरकार की एजेंसियों, भारतीय नौसेना, सेना, वायु सेना, तटरक्षक बल, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य सरकारों आदि द्वारा किए गए बचाव और राहत कार्यों को प्रमुखता से कवरेज दी गई।

समाचार सेवा प्रभाग और उसकी क्षेत्रीय समाचार इकाइयों ने भारत सरकार के मौसम विभाग द्वारा मौसम की जानकारी/भविष्यवाणी, बाढ़ की स्थिति पर अद्यतन जानकारी और बाढ़ के दौरान विभिन्न एजेंसियों द्वारा बचाव तथा राहत कार्यों की व्यापक कवरेज की।

vii) 5वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर कवरेज

समाचार सेवा प्रभाग और उसकी क्षेत्रीय समाचार इकाइयों ने देश और विदेश में 5वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह से संबंधित कार्यक्रमों का व्यापक रूप से समाचारों और समसामयिक कार्यक्रमों में प्रचार किया और इससे पहले आयोजित किए गए कार्यक्रमों का भी प्रचार किया। रांची में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुख्य कार्यक्रम को प्रमुखता से कवर किया गया था। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2019 पर विदेशों में आयोजित कार्यक्रमों को भी

आकाशवाणी के विशेष संवाददाताओं द्वारा कवर किया गया था। राज्यों के संवाददाताओं ने भी इन आयोजनों को प्रमुखता से कवर किया। इन कवरेज में संवाददाताओं से वॉयस कास्ट और प्रमुख हस्तियों तथा योग गुरुओं के साउंड-बाइट्स शामिल थे। योग-2019 के संवर्धन और विकास के लिए उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार की घोषणा के अलावा, समाचार पत्रिका के कार्यक्रम- आज सवेरे में परिचर्चा कार्यक्रम स्वस्थ जीवन के लिए योग और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस-19 प्रसारित किए गए।

आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने जून, 2019 में योग पर दो कार्यशालाओं का आयोजन किया जिसमें बड़ी संख्या में स्टाफ सदस्यों ने भाग लिया।

viii) करगिल विजय दिवस

आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने 26.07.2019 को करगिल विजय दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों को व्यापक रूप से कवर किया। स्पॉट न्यूज कवरेज में द्रास युद्ध स्मारक और पूरे देश में अन्य स्थानों पर आयोजित समारोह शामिल थे। क्षेत्रीय समाचार इकाई, करगिल से प्राप्त वीडियो/तस्वीरें भी प्रभाग के सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर पोस्ट की गईं।

ix) इसरो द्वारा चंद्रयान–2 और उपग्रहों का प्रक्षेपण

चंद्रमा पर भारत के अभियान चंद्रयान-2 के सफल प्रक्षेपण, लैंडर के अलग होने और इसकी सॉफ्ट लैंडिंग के बारे में प्रमुखता से अद्यतन जानकारी दी गई। माननीय प्रधानमंत्री के विद्यार्थियों के एक समूह के साथ लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग को देखने, इसरो अध्यक्ष के साथ विशेष भेंटवार्ता, भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा आगे की दिशा पर टॉक शो के अलावा ग्राउंड रिपोर्ट भी प्रसारित की गई।

इसरो द्वारा रीसैट 2बी, पर्यवेक्षक उपग्रह- एमीसैट के प्रक्षेपण और डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित 500 किलोग्राम वर्ग के गाइडेड बम के सुखोई लड़ाकू जेट से सफल परीक्षण को भी समाचार सेवा प्रभाग और उसकी क्षेत्रीय समाचार इकाइयों ने प्रमुखता से कवर किया।

x) स्वतंत्रता दिवस 2019

समाचार सेवा प्रभाग और उसकी क्षेत्रीय समाचार इकाइयों ने देश और विदेश में 73वें स्वतंत्रता दिवस समारोह से आयोजित कार्यक्रमों से संबंधित समाचारों का प्रसारण। माननीय प्रधानमंत्री का जल जीवन मिशन, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करने, आज़ादी के 75वें वर्ष तक किसानों की आय को दोगुना करने, हर गरीब परिवार को अपना पक्का मकान और बिजली कनेक्शन प्रदान करने संबंधी समाचारों का प्रसारण किया। 1 से 15 अगस्त, 2019 तक स्वतंत्रता दिवस और विभिन्न विषयों पर टॉक शो के अलावा ग्राउंड रिपोर्ट प्रसारित की गई।

xi) स्वच्छ भारत मिशन की कवरेज

विभिन्न मंत्रालयों के स्वच्छ भारत पखवाड़ा सहित स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों की मौके पर जाकर कवरेज की गई। देश के सबसे बड़े स्वच्छता सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2019 के शुभारंभ को प्रमुखता से कवर किया गया।

xii) जल शक्ति अभियान

समाचार सेवा प्रभाग और उसकी क्षेत्रीय समाचार इकाइयों ने जल संचयन और संरक्षण उपायों में तेजी लाने के लिए देश भर में जल शक्ति अभियान के शुभारंभ की पर्याप्त कवरेज की। इसमें जमीनी स्तर की हल्की फुल्की कहानियों का नियमित प्रसारण भी शामिल था। जल शक्ति पर समसामयिक विषयों के कार्यक्रमों में भी चर्चा कार्यक्रम प्रसारित किए गए थे।

xiii) एनडीए सरकार के 100 दिन

एनडीए सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों सहित विभिन्न विषयों पर व्यापक और विशेष कवरेज प्रसारित की गई। माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने एनडीए सरकार के 100 दिनों पर एक रिपोर्ट कार्ड पेश किया जिसमें सरकार के प्रमुख फैसलों पर प्रकाश डाला गया, पुस्तिका- जन कनेक्ट का विमोचन तथा भारत के विकास को और आगे बढ़ाने पर एक प्रदर्शनी - 100 दिन की साहसिक पहल और निर्णायक कार्य का उनके द्वारा उद्घाटन और भारत भर के विभिन्न शहरों में केंद्रीय मंत्रियों द्वारा मीडिया से बातचीत को व्यापक रूप से कवर किया गया था। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा कार्यक्रमः पहले 100 दिनों में मुख्य निर्णय, सरकार के 100 दिन के कार्यकाल में आर्थिक सुधार, सुशासन- एनडीए-2 सरकार के 100 दिन, 'सरकार के प्रथम सौ दिन और कृषि क्षेत्र में सुधार', एनडीए-2 के 100 दिनों में बुनियादी ढांचा क्षेत्र में सुधार, 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के लिए प्रतिबद्ध सरकार और इसके प्रथम सौ दिन', एनडीए-2 सरकार के 100 दिनों में सामाजिक सुधार जैसे कार्यक्रम

प्रसारित किए गए। सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों पर ग्राउंड रिपोर्ट के प्रसारण के अलावा, समर्पित हैशटैग, अच्छी प्रतिक्रियाओं के प्रसारण के अलावा सभी संवाददाता सम्मेलनों पर लाइव ट्वीट करना और फेसबुक अपडेट भी शामिल है।

xiv) आयुष्मान भारत दिवस

समाचारों में माननीय प्रधानमंत्री के ट्वीट को व्यापक कवरेज दिया गया- आयुष्मान भारत एक स्वास्थ्य देखभाल योजना से अधिक है क्योंकि यह भारत के सबसे कमजोर लोगों के 50 करोड़ से अधिक लोगों के लिए आशा की किरण है, आयुष मंत्रालय इस योजना के तहत 2019-20 के दौरान 4200 आयुश स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों को संचालित करने का लक्ष्य रखा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत राजस्थान, ओड़िशा तथा झारखंड में आयुष अस्पतालों की स्थापना की जाएगी, 306 आयुष अस्पतालों का उन्नयन किया जा रहा है और योजना के तहत सबसे अधिक स्वर्ण कार्ड जारी करने वाला जम्मू और कश्मीर पहला राज्य बन गया है। **''प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना''** पर आयुष्मान भारत की मुख्य कार्यकारी अधिकारी- इंदु भूषण का विशेष साक्षात्कार और परिचर्चा कार्यक्रम प्रसारित किए गए।

xv) पोषण अभियान–2019/पोषण माह

समाचार सेवा प्रभाग ने मौके पर समाचार कवरेज, केरल पोषण अभियान मिशन के निदेशक के साथ विशेष साक्षात्कार, क्षेत्रीय समाचार इकाइयों से विशेष और विभिन्न राज्यों में पोषण माह पर डेस्क, ग्राउंड रिपोर्ट समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रसारित किए गए थे। समाचार पत्रिका कार्यक्रम 'आज सवेरे' में **''पोषण मिशन : पोषाहार के लिए सरकार की महत्वाकांशी योजना''** पर चर्चा और **सोशल मीडिया कैम्पेन**– विडियोज और ग्राफिक्स के साथ हैशटैग भी बनाए गए।

xvi) राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर रिलीज

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, असम अपडेट, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के बारे में जागरूकता पैदा करना, हेल्पलाइन के बारे में जागरुकता बढ़ाने, विदेशियों के ट्रिब्यूनल पर समाचारों के अलावा असम के माननीय मुख्यमंत्री, अतिरिक्त मुख्य सचिव के विशेष साक्षात्कार प्रसारित किए गए थे। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर रिलीज पर वाताएँ भी प्रसारित की गई हैं।

xvii) ग्राउंड रिपोर्ट

सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के बारे में जमीनी स्तर पर, तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करने के लिए, सभी प्रमुख बुलेटिनों में दैनिक रूप से ग्राउंड रिपोर्टों का प्रसारण किया जा रहा है। देश भर में कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के बाइट भी ग्राउंड रिपोर्ट में शामिल किए गए। सभी 46 क्षेत्रीय समाचार इकाइयों ने भी संबंधित क्षेत्रीय भाषाओं में ग्राउंड रिपोर्ट प्रसारित की। सरकार की सभी प्रमुख फ्लैगशिप योजनाओं के लाभार्थियों का साक्षात्कार लिया जाता है और इन्हें बुलेटिनों में शामिल किया जाता है। ग्राउंड रिपोर्ट को व्यापक पहुंच प्रदान करने के लिए समाचार सेवा प्रभाग वेबसाइट सहित सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर भी साझा किया जा रहा है।

xviii क्षेत्रीय समाचार इकाइयां

आकाशवाणी की 46 क्षेत्रीय समाचार इकाइयां क्षेत्रीय रंग के साथ लोगों की सूचना आवश्यकताओं की पूर्ति और जमीनी स्तर पर इनकी पहुंच बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

क्षेत्रीय समाचार इकाइयां समाचारों को क्षेत्र विशेष का और श्रोता हितैषी बनाने के लिए 77 क्षेत्रीय भाषाओं/बोलियों में बुलेटिन और कार्यक्रमों का प्रसारण करती हैं। प्रत्येक राज्य में कम से कम एक क्षेत्रीय समाचार इकाई है और बड़े राज्यों में घटनाओं की प्रभावी कवरेज के लिए चार क्षेत्रीय समाचार इकाइयां हैं। क्षेत्रीय समाचार इकाइयां हर दिन लगभग 39 घंटे की कुल अवधि के लिए 478 बुलेटिनों का प्रसारण करती हैं, जिनमें राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, विदेशी, डीटीएच सेवाएं और एफएम मुख्य समाचार शामिल हैं।

ये इकाइयां गणतंत्र दिवस जैसे अवसरों पर विशेष कार्यक्रमों को प्रसारित करने के अलावा एक महीने में लगभग 140 घंटे की अवधि के लिए 1060 समाचार-आधारित कार्यक्रमों का भी निर्माण करती हैं। राज्य विधानसभा सत्र के दौरान विशेष कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाते हैं।

एफएम हेडलाइंस, शहरों और कस्बों में अपने सूचना प्रेमी श्रोताओं की तत्काल जरूरतों को पूरा करती हैं। वर्तमान में, 17 भाषाओं में 255 हेडलाइन बुलेटिन प्रसारित किए जा रहे हैं।

घ. विस्तार और नवाचार

आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग गांधी के 150 वर्ष, राष्ट्रीय एकता दिवस, चुनाव, स्वतंत्रता दिवस, गुरु नानक की 550वीं वर्षगांठ आदि जैसे प्रमुख अभियानों के लिए विषयगत संचार योजनाएं चला रहा है।

प्रभाग ने बुलेटिनों और समाचार पत्रिका कार्यक्रमों के साथ-साथ वार्ता और करंट अफेयर्स कार्यक्रमों में कवरेज के अलावा, रेडियो प्लस रणनीति को अपनाया है। इस प्रकार अभियान कई सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर दिए जाते हैं। सभी प्रसारण सामग्री केवल ऑनलाइन वेब पर पोस्ट की जाती है और विशेष सामग्री भी अपलोड की जाती है। ग्राफिक्स, दृश्य, श्रव्य और

संवादमूलक सामग्री जैसे क्विज को पहुंच बढ़ाने के लिए समर्पित अभियान–विशिष्ट हैशटैग के साथ साझा किया जाता है।

ड. आकाशवाणी वेबसाइट पर समाचार

आकाशवाणी समाचार की 24x7/365 वेबसाइट पर एबीसी-प्रामाणिकता, संतुलन और विश्वसनीयता के अपने हॉलमार्क के साथ अद्यतन किए गए समाचार विभिन्न क्षेत्रों से चौबीसों घंटे प्रदान किए। श्रोताओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2019 में, वेबसाइट बहुभाषी रही है। न्यूज़ऑनएआईआर वेबसाइट अब अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, मराठी और गुजराती में उपलब्ध है। इसे सभी क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने का प्रयास जारी है। इसे निम्नलिखित वेबसाइट यूआरएल पर एक्सेस किया जा सकता है।

भाषा	यूआरएल
अंग्रेजी	http://newsonair.com/
हिंदी	http://newsonair.com/hindi/Hindi-Default.aspx
उर्दू	http://newsonair.com/urdu/Urdu-Default.aspx
मराठी	http://newsonair.com/Marathi/Marathi-Default.aspx
गुजराती	http://newsonair.com/Gujarati/Language-Default.aspx

सोशल मीडिया सांख्यिकी : एनएसडी

ब	यूआरएल	टिप्पणियां
फेसबुक	आकाशवाणी समाचार	3.4 मिलियन से अधिक लाइक्स
ट्विटर-अंग्रेजी	@airnewsalerts	2.17 मिलियन फालोअर्स
ट्विटर-हिंदी	@AirNewsHindi	30 हजार फालोअर्स
यू ट्यूब	NEWS ONAIR OFFICIAL	151 हजार सबस्क्राइबर्स
इन्स्टाग्राम	airnewsalerts	1.92 लाख फालोअर्स

सोशल मीडिया सांख्यिकी आरएनयू (क्षेत्रीय समाचार एकांकी)

प्लेटफार्म	आरएनयू की कुल संख्या
फेसबुक	26
ट्विटर	46
यू ट्यूब	21

च. वार्ता और करंट अफेयर्स यूनिट

वार्ता और करंट अफेयर्स यूनिट को विभिन्न विषयों पर विश्लेषणात्मक समाचार आधारित कार्यक्रमों को प्रसारित करने का काम सौंपा गया है। इसका उद्देश्य श्रोताओं को प्रमुख नए घटनाक्रम को समझने में मदद करना है, चीजों को परिप्रेक्ष्य में रखता है और किसी विषय के बारे में विस्तार से बताता है।

दैनिक और साप्ताहिक कार्यक्रमों जैसे विभिन्न विषयों पर व्यापक रूप से चर्चा की गई। सामयिकी, स्पॉटलाइट/न्यूज एनालिसिस, पब्लिक स्पीक, मनी टॉक, वाद सम्वाद, चर्चा का विशय, कंट्रीवाइड, सुर्खियों से परे और करंट अफेयर्स प्रोग्राम।

वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान प्रसारित महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में आम चुनाव-2019, जम्मू और कश्मीर में धारा 370 को हटाना, तीन तलाक और अयोध्या पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, बालाकोट हवाई हमला, भारत छोड़ो आंदोलन और महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा कार्यक्रम शामिल हैं।

जम्मू और कश्मीर और उत्तर पूर्व, राष्ट्रीय पोषण मिशन, आयुष्मान भारत, किसान कल्याण, केंद्रीय मंत्रियों के साथ साक्षात्कार, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस और स्वच्छ भारत अभियान जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सरकार की पहल और उपलब्धियों पर कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए।

यूनिट का विशेष ध्यान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सुरक्षा पर आधारित कार्यक्रमों पर है। भारत को एकजुट करने में सरदार पटेल के योगदान पर लाइव चर्चा कार्यक्रम और माननीय प्रधानमंत्री की विभिन्न देशों की यात्रा पर कार्यक्रम भी प्रसारित किए गए। महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं को चर्चा कार्यक्रमों के माध्यम से उचित कवरेज दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री के मासिक प्रसारण- 'मन की बात' पर भी चर्चाएं प्रसारित की गईं। अंग्रेजी में इश्युज़ बिफोर द पार्लियामेंट और हिंदी में संसद के समक्ष मुद्दे विशेष कार्यक्रम संसद के मानसून सत्र के प्रारंभ होने से पहले प्रसारित किया गया।

छ. संदर्भ और पीपीएंडडी

संदर्भ और पीपीएंडडी यूनिट समाचार सेवा प्रभाग की विभिन्न इकाइयों को दैनिक आधार पर सरकार और राजनीतिक दलों की विभिन्न गतिविधियों/कार्यक्रमों के बारे में पूर्व जानकारी प्रदान करता है। यह यूनिट, कार्य योजना, की गई कार्यवाही की रिपोर्ट और विभिन्न रिपोर्टों के अनुपालन

से संबंधित है। इसमें स्वच्छता कैलेंडर के अनुसार मासिक गतिविधियों के संबंध में सरकार की उपलब्धियों, योजनाओं तथा संदेशों और की गई कार्यवाही की रिपोर्ट का प्रसार करने के लिए समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रसारित मासिक कैबिनेट सारांश और प्रगति रिपोर्ट शामिल हैं। यह इकाई आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कारों के लिए आवेदनों की जांच भी करती है।

ज. पुस्तकालय

समाचार सेवा प्रभाग में एक पुस्तकालय भी है जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और अन्य भाषाओं में 21,793 पुस्तकें/संदर्भ पुस्तकें हैं। कुल संग्रह में से लगभग 860 पुस्तकें मास मीडिया और प्रसारण पर हैं। पुस्तकालय में लगभग 27 समाचार पत्र और 75 पत्रिकाएं आती हैं।

पुस्तक चयन समिति की अनुशंसा पर, अप्रैल से नवंबर, 2019 तक 244 पुस्तकें खरीदी गईं और पुस्तकालय का वार्षिक सत्यापन भी पूरा किया गया।

वाणिज्य स्कंध

वाणिज्यिक राजस्व प्रभाग (सीआरडी) (बदला नाम पब्लिक आउटरीच सर्विस-पीओएस)। पब्लिक आउटरीच सर्विस (पीओएस) की जिम्मेदारी अखिल भारतीय स्तर पर राजस्व प्राप्त करना है। विज्ञापनदाताओं को अपने उत्पादों का प्रचार करने के लिए यह सिंगल विंडो का काम करती है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए पीओएस का राजस्व लक्ष्य रु. 375 करोड़ कुल है।

अच्छी संख्या में राजस्व प्राप्त करने वाले कार्यक्रमों में भारत के माननीय प्रधानमंत्री का कार्यक्रम 'मन की बात' (रु. 1.30 करोड़) और खेल प्रसारण (रु. 6.03 करोड़) हैं। राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक समाचार भी राजस्व प्राप्ति में भारी अंशदान करते हैं क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित होने वाले बहुत कम कार्यक्रम होते हैं।

विदेश सेवा विभाग :

i. संक्षिप्त परिचय

रेडियो हमारी विदेश नीति एवं जन कूटनीति के महत्वपूर्ण अंश के तौर पर भूमिका निभाता है। विभिन्न राष्ट्र दुनिया में अपनी छवि और अपने विचारों को प्रसारित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रसारण को बहुत महत्व देते हैं।

तब से एआईआर का विदेश सेवा विभाग भारत और शेष विश्व के बीच महत्वपूर्ण सेतु के तौर पर कार्यरत है। खासकर उन देशों के साथ जहां बड़ी संख्या में रहने वाले प्रवासी भारतीयों के कारण भारत के हित गहरे तौर पर जुड़े हैं। ऑल इंडिया रेडियो की विदेश सेवा, बड़ी संख्या में मौजूद इन प्रवासी भारतीयों को उनकी मूल जमीन से, उसकी संस्कृति और धरोहर से विदेशी भूमि पर जोड़े रखने का काम करती है।

दुनिया भर के 150 देशों में 28 भाषाओं के प्रसारण के आधार पर ऑल इंडिया रेडियो के विदेश सेवा प्रभाग की गिनती पहुंच एवं विस्तार में विदेश रेडियो नेटवर्क सेवाओं में ऊंचे स्थान पर होती है। अपने विदेशी प्रसारणों के माध्यम से ऑल इंडिया रेडियो विदेशी श्रोताओं को भारत की सदाचारिता से अवगत कराता है। विदेशी श्रोताओं तक एआईआर के प्रसारण अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्वाहीली, अरबी, फारसी, तिब्बती, चीनी, थाई, बर्मी एवं इंडोनेशिया की भाषाओं तक में पहुंचते हैं। हिंदी, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ओड़िया, कन्नड़ एवं गुजराती भाषाओं में प्रसारण प्रवासी भारतीयों तक पहुंचते हैं, जबकि उर्दू, पंजाबी, सिंधी, सरैकी, सिंहाली, बांग्ला एवं नेपाली में प्रसारण भारतीय उप-महाद्वीप एवं पड़ोसी देशों में प्रसारित होते हैं। ईएसडी सेवाओं के कार्यक्रम मिश्रित प्रकृति के होते हैं जिनमें शामिल हैं : समाचार बुलेटिन, समसामयिक मुद्दों पर विचार एवं भारतीय प्रेस द्वारा उनकी व्याख्या। इनमें विशेषज्ञ वार्ताएं, साक्षात्कार, वृत्तचित्र, फीचर्स, सब प्रकार का भारतीय संगीत, रेडियो नाटक आदि भी शामिल होते हैं।

iii. नई शुरुआत एवं आधुनिकीकरण के प्रयास

- 2016 में इसकी स्थापना के बाद से, विदेश प्रसारण को मीडियम वेव (निकटवर्ती देशों के लिए) एवं शॉर्टवेव (सुदूर देशों के लिए) पर प्रसारित किया जा रहा है। तकनीकी प्रगति के साथ, उपर्युक्त माध्यमों को डिजिटल मंचों के माध्यम से मजबूती प्राप्त हो रही है। इसके साथ ही, पूर्वोत्तर एशिया के लिए चीनी प्रसारण, यूके एवं पश्चिमी यूरोप के लिए सामान्य विदेश सेवा iii एवं iv प्रसारण तथा यूके एवं पश्चिमी यूरोप के लिए हिंदी सेवा प्रसारण I को डीआरएम मोड के जरिए प्रसारित किया जा रहा है। गत दो वर्षों के दौरान ऑल इंडिया रेडियो ने अपनी मौजूदा 28 भाषा सेवाओं (15 विदेशी एवं 13 भारतीय) के लिए एक मल्टीमीडिया वेबसाइट airworldservice.org भी शुरू की है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की है। इस मल्टीमीडिया वेबसाइट में प्रोग्रामों के

सीधे प्रसारण, पॉडकास्ट, टेक्स्ट, वीडियो एवं तस्वीरों के अलावा एक मोबाइल एप एयरवर्ल्डसर्विस भी है, जिसके माध्यम से ऑल इंडिया रेडियो की यह विदेश सेवा सही मायने में वैश्विक बनती है। रेडियो गार्डन, ट्यून इन, अमेजन एलेक्सा आदि जैसे प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से इसे और अधिक सशक्तता मिली है।

- ईएसडी के सभी वेब पोर्टल्स को वॉट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं ट्विटर आदि जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ भी जोड़ा गया है ताकि इनके माध्यम से पारस्परिक आदान-प्रदान बढ़े और दुनिया के किसी भी कोने में बैठे श्रोता अपने अनुरोध एवं फीडबैक भेज सकें।
- मौजूदा वर्ष में, ईएसडी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में एक स्मार्ट टीवी एप जोड़ने की पहल भी की गई जिससे बीबीसी, सीआरआई, वीओए आदि अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रसारकों की तरह दर्शनीय सामग्री के प्रचार में सहायता मिल सके।
- 2019 के दौरान, एआईआर विश्व सेवा ने वैश्विक पहुंच में वृद्धि के लिए 'विजुअल रेडियो', 'साउंडस्केप इंडिया' एवं इंटरनेट आधारित सामुदायिक रेडियो चैनलों का शुभारंभ किया।
- एआईआर ने विदेश मंत्रालय की अनुमति के आधार पर भूटान के लिए ज़ोंग्का भाषा में एक विशेष सेवा आरंभ करने की शुरुआत की है। इस सेवा को भारत सरकार की नेबरहुड फर्स्ट योजना के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया है।
- एआईआर की विदेश प्रसार सेवा की 80वीं सालगिरह पर, 1 अक्टूबर, 2018 को विदेश प्रसारण दिवस (ईबीडी) का आयोजन किया गया। इस विशाल कार्यक्रम में विदेशी राजनयिक, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों एवं विदेश संवाददाताओं को एआईआर की विदेश प्रसारण सेवा के बारे में जानकारी दी गई।
- अगस्त 2019 से, प्रधानमंत्री के मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' को 15 भाषाओं में निरंतर प्रसारित किया जा रहा है। इन भाषाओं में यह कार्यक्रम ईएसडी के यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड किया जाता है। मन की बात को स्पेनिश, जर्मन एवं जापानी भाषाओं में भी प्रसारित किया जाता है।

उपरोक्त उपलब्धियों के अलावा, एआईआर अपनी वैश्विक पहचान बनाने के लिए विभिन्न अंतरराष्ट्रीय प्रसारण संगठनों के साथ समझौता ज्ञापनों के जरिए लगातार सहभागिता कर रहा है।

1. श्रोता अनुसंधान खंड

जनसंचार के बदलते परिदृश्य में, श्रोता अनुसंधान का कार्य केंद्रीय रूप ले चुका है।

इस क्षेत्र में ऑल इंडिया रेडियो अग्रणी रहा है। इसकी देश भर में दर्शक अनुसंधान इकाइयां हैं जो 1946 से कार्यरत हैं। यह कार्यक्रम निर्माताओं को श्रोताओं को उनकी जरूरत, रुचियों एवं आकांक्षाओं के अनुसार कार्यक्रमों की नीति, डिजाइन एवं संशोधन संबंधित फीडबैक देता है। इसके अलावा, प्रायोजकों, विज्ञापनदाताओं एवं मार्केट कर्मियों को उनके वाणिज्यिक लक्ष्य पूरे करने के लिए कार्यक्रम मूल्यांकन/श्रोता आधारित डाटा भी उपलब्ध कराया जाता है। संगठन के लिए श्रोता अनुसंधान इकाइयां डाटा बैंक एवं संदर्भ अनुभाग के तौर पर भी काम करती हैं।

2019-20 के लिए 1 अप्रैल से 31 दिसंबर, 2019 तक, निम्न श्रोता अनुसंधान कार्रवाई/अध्ययन किए जा चुके हैं :

1. जून, 2019 में सात स्टेशनों में एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्र (फेज-अप) में प्रचार अभियान का प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन।
2. जून, 2019 के दौरान सात स्टेशनों में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में क्रिकेट कमेंटरी पर त्वरित टेलिफोनिक फीडबैक सर्वेक्षण।
3. मई, 2019 में प्रसार भारती-2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट संकलन।
4. जून-जुलाई, 2019 में आईआरएस-2017 डाटा का आकलन।
5. जुलाई-अगस्त, 2019 में दिल्ली दो निजी एफएम चैनलों बनाम एआईआर एफएम रेनबो चैनल की निगरानी।
6. सितंबर, 2019 के दौरान इंडिया एनुअल रेफरेंस-2020 (एआईआर से संबंधित संकलित इनपुट्स)।
7. एआईआर इम्फाल में 12 दिसंबर, 2019 को भारत बनाम वेस्ट इंडीज टी-20 एकदिवसीय सिरीज-2019 की क्रिकेट कमेंटरी पर त्वरित टेलिफोनिक फीडबैक सर्वेक्षण।

सत्यम् शिवम् सुन्दरम्

दूरदर्शन

भारत

वर्तमान दूरदर्शन नेटवर्क

(अक्टबूर ३१, २०१८ की स्थिति के अनुसार)

दूरदर्शन – एक झलक में तथ्य

31.12.2019 तक

संदर्भ	सं.
सेटेलाइट चैनल	
राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय	7
क्षेत्रीय (24X7)	17
क्षेत्रीय (गैर 24X7)	11
कुल	35
स्टूडियो केंद्रित	
मुख्य स्टूडियो	20
अन्य स्टूडियो केंद्रित	46
कुल	66

टैरेस्टियल ट्रांसमीटरों			
	क्षेत्रीय चैनल	**डीडी नेशनल**	**डीडी न्यूज़**
एचपीटी	04	114	55
एलपीटी		392	22
वीएलपीटीएस		19	6
डीटीटी (डिजिटल)		23	
कुल		**635**	

दूरदर्शन – शाब्दिक रूप से दूर से एक झलक – 15 सितंबर, 1959 को लोक सेवा प्रसारण में एक मामूली प्रयोग की शुरुआत से लेकर, डिजिटल संचार के क्षेत्र में दुनिया में अग्रणी बनकर भारत के कायापलट का चेहरा बना है। यह प्रयोग 1965 में एक सेवा बन गया, जब दूरदर्शन ने देश की राजधानी, नई दिल्ली और उसके आस–पास के इलाकों तक पहुंचने के लिए सिग्नलों को दीप्तीमान करना शुरू किया। वर्ष 1972 तक, सेवाओं का विस्तार मुंबई तथा अमृतसर और 1975 तक सात और शहरों तक किया गया। उस समय यह आकाशवाणी का हिस्सा था। 1 अप्रैल, 1976 को इसके लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में एक अलग विभाग बना और बाद में यह प्रसार भारती के अंतर्गत आ गया।

संगठनात्मक संरचना

दूरदर्शन का प्रमुख महानिदेशक होता है जिसकी सहायता कार्यक्रम विंग और प्रशासन तथा वित्त विंग में अतिरिक्त महानिदेशक, इंजीनियरिंग विंग में इंजीनियर–इन–चीफ और समाचार विंग में महानिदेशक (समाचार) करते हैं।

नीति निर्माण, नियोजन तथा विकास, बुनियादी ढांचे तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन, बजटीय नियोजन तथा नियंत्रण, मानव संसाधन प्रबंधन, संचालन कार्यों की निगरानी और रखरखाव गतिविधियों आदि की देखरेख महानिदेशक, दूरदर्शन की जिम्मेदारी है।

इसके अलावा, छह प्रोग्रामिंग जोन–दिल्ली (उत्तर क्षेत्र), मुंबई (पश्चिम क्षेत्र), चेन्नई (दक्षिण क्षेत्र), लखनऊ (मध्य क्षेत्र), कोलकात्ता (पूर्व क्षेत्र) और गुवाहाटी (उत्तर पूर्व क्षेत्र) महानिदेशक को रिपोर्ट करते हैं। समानांतर में, चार इंजीनियरिंग क्षेत्रीय कार्यालय एक–एक अतिरिक्त महानिदेशक (अभियांत्रिकी) की अध्यक्षता में परियोजना और रखरखाव गतिविधियों के लिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में स्थित हैं।

वर्तमान तकनीकी संरचना

दूरदर्शन के पास 66 स्टूडियो केंद्रों का एक विशाल नेटवर्क है। देशभर में 66 स्टूडियो केंद्र इन–हाउस कार्यक्रम निर्माण की आवश्यकता को पूरा करते हैं। इनमें राज्यों की राजधानियों में 17 प्रमुख स्टूडियो केंद्र, और देश में विभिन्न स्थानों पर स्थित 49 अन्य स्टूडियो केंद्र शामिल हैं।

दूरदर्शन केंद्रों की वृद्धि

दूरदर्शन के पास अलग–अलग शक्ति के 635 टैरेस्ट्रियल ट्रांसमीटर हैं। यह फ्री–टू–एयर डीटीएच सेवा भी प्रदान करता है।

दूरदर्शन का टैरेस्ट्रियल ट्रांसमीटर नेटवर्क मुख्य रूप से एनालॉग ट्रांसमीटरों से युक्त होता है। दूरदर्शन

द्वारा इस्तेमाल की गईं नई तकनीकें डिजिटल टैरेस्ट्रियल ट्रांसमिशन (डीटीटी) का उपयोग करके एकल ट्रांसमीटर के साथ कई टीवी चैनलों को प्रसारित करना संभव बनाती हैं। यह एनालॉग टैरेस्ट्रियल ट्रांसमिशन को डीटीटी में परिवर्तित करने की वैश्विक प्रवृत्ति के अनुरूप है और इसके कई फायदे हैं, जैसे कि चित्र तथा ध्वनि की बेहतर गुणवत्ता, दर्शकों के लिए बड़ी संख्या में चैनल आदि। आधुनिक प्रसारण प्रवृत्तियों के मद्देनजर प्रसार भारती ने एनालॉग टैरेस्ट्रियल ट्रांसमीटरों को चरणबद्ध तरीके से बंद करने और डिजिटल टैरेस्ट्रियल ट्रांसमीटरों की स्थापना को मंजूरी दी है। तदनुसार, दूरदर्शन ने अपने एनालॉग ट्रांसमीटरों को चरणबद्ध तरीके से बंद करना शुरू कर दिया है। स्टूडियो केंद्रों की राज्यवार सूची अनुलग्नक–I में दी गई है।

प्रमुख तकनीकी उन्नयन

66 स्टूडियो केंद्रों में से 62 पहले ही पूरी तरह से डिजिटल हो चुके हैं। शेष 4 स्टूडियो केंद्र एनालॉग हैं। पिछले वर्षों में दूरदर्शन नेटवर्क का विकास निम्नवत ढंग से हुआ है:

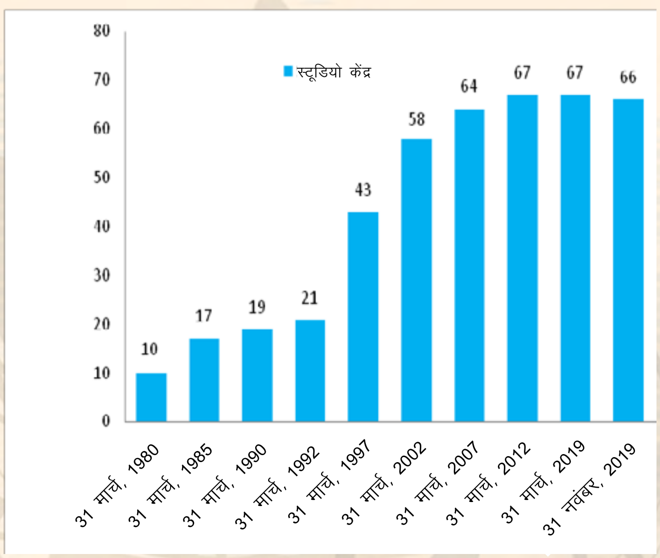

दूरदर्शन के स्थलीय ट्रांसमीटर नेटवर्क में मुख्य रूप से एनालॉग ट्रांसमीटर होते हैं। नई तकनीकों के आगमन के साथ, डिजिटल स्थलीय ट्रांसमिशन (डीटीटी) का उपयोग करते हुए एकल ट्रांसमीटर के साथ कई टीवी चैनल संभव हैं। एनालॉग टेरेस्ट्रियल ट्रांसमिशन भारत सहित दुनिया भर में डिजिटल किया जा रहा है क्योंकि डिजिटल टेरेस्ट्रियल ट्रांसमिशन (डीटीटी) में कई फायदे हैं जैसे तस्वीर और ध्वनि की बेहतर गुणवत्ता, दर्शकों के लिए अधिक संख्या में चैनल आदि। आधुनिक प्रसारण रुझानों के मद्देनजर, प्रसार भारती द्वारा एक अंतर अनुशासनात्मक समिति का गठन किया गया था। स्थलीय ट्रांसमिशन के युक्तिकरण के संबंध में प्रसार भारती ने समिति की सिफारिश पर 766 एनालॉग स्थलीय ट्रांसमीटरों को चरणबद्ध तरीके से बंद करने को मंजूरी दे दी है। तदनुसार, 735 एटीटी (380 एलपीटी, 341 वीएलपीटी और 14 ट्रांसपोज़र्स) तब से बंद हैं। इसके अलावा, उन जगहों के 38 एनालॉग एचपीटी को बंद कर दिया गया है जहां डिजिटल एचपीटी को चालू किया गया है।

दूरदर्शन ट्रांसमीटरों की वृद्धि

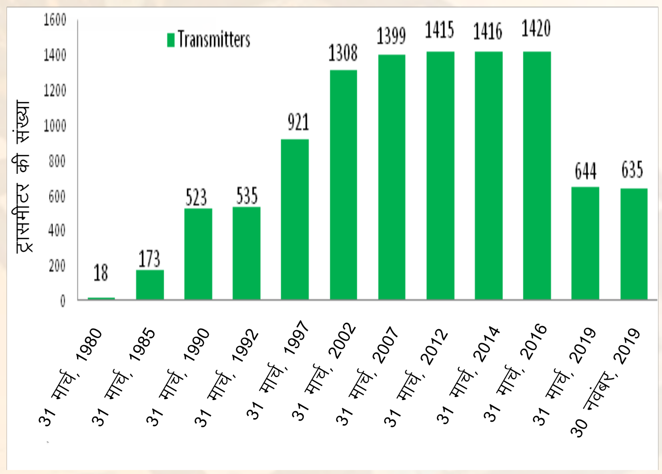

वर्ष के दौरान विकास की उल्लेखनीय गतिविधियां

क) भौगोलिक रूप से स्थलीय प्रसारण से वंचित क्षेत्रों में वितरण के लिए 30,000 एनटीएच डीटीएच सेट खरीदे गए और जम्मू–कश्मीर सरकार द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारियों को सौंप दिए गए।

ख) दूरदर्शन केंद्र दिल्ली, दूरदर्शन समाचार और सीपीसी में एलईडी प्रत्यक्ष दृश्य आधारित वीडियो वॉल्स लगाई गईं। वीडियो वॉल से सेट और समग्र उत्पादन की गुणवत्ता को देखने और महसूस करने में व्यापक सुधार होता है।

ग) सीपीसी में किसान चैनल के लिए नया भू केंद्र (अर्थ स्टेशन) चालू।

घ) डीडी डीटीएच प्लेटफार्म की चैनल क्षमता 104 एसडीटीवी चैनल से बढ़कर 112 एसडीटीवी चैनल हुई।

ड) दिल्ली, देहरादून, रायपुर, रांची और श्रीनगर में भू केन्द्रों का आधुनिकीकरण पूरा हुआ।

च) अहमदाबाद, हैदराबाद, जालंधर, भुवनेश्वर और गुवाहाटी में एकल चैनल एकीकृत स्वचालित प्लेआउट सुविधा चालू। यह प्रणाली एचडी सक्षम स्वचालन और निर्बाध 24x7 प्रसारण की सुविधा प्रदान करेगी।

फ्री–टू–एयर डीटीएच ''डीडी फ्री डिश''

दूरदर्शन ने दिसंबर 2004 में 33 टीवी चैनलों के साथ अपनी फ्री–टू–एयर डीटीएच सेवा "डीडी फ्री डिश" (पहले डीडी डायरेक्ट प्लस़) शुरू की। बाद में डीटीएच प्लेटफार्म की क्षमता बढ़ाकर 59 टीवी चैनल कर दी गई। छोटे आकार की डिश रिसीवर इकाइयों की मदद से देश में कहीं भी (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर) डीटीएच सिग्नल प्राप्त किए जा सकते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सितंबर, 2009 से 10 चैनलों के साथ सी–बैंड में डीटीएच सेवा शुरू की गई थी। दूरदर्शन के डीटीएच प्लेटफॉर्म ''डीडी फ्री डिश'' के 59 से 104 चैनलों की उन्नयन दिसंबर, 2014 में पूरा हो गया था। वर्तमान में, 112 टीवी चैनल डीटीएच प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं।

टीवी चैनलों के लिए डीडी फ्री डिश डीटीएच प्लेटफार्म का भी उन्नयन एमपीईजी–4 डीवीबी–एस 2 प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डीडी फ्री डिश डीटीएच प्लेटफॉर्म के लिए विकसित आईसीएएस की स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग का काम पूरा हो गया है। इसके अलावा, दूरदर्शन ने दर्शकों को दक्ष और मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए आईसीएएस सक्षम भारतीय सेट टॉप बॉक्स 'की भी शुरुआत की है। इसका विवरण वेबसाइट www.doordarshan.gov.in और www. prasarbharati.gov.in पर उपलब्ध है।

तीन साल की विस्तारित योजना के तहत डीडी के डीटीएच प्लेटफॉर्म के 120 टीवी चैनलों तक के और उन्नयन को मंजूरी दी गई है।

डीडी फ्री डिश चैनलों का 25.11.2019 तक का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक– II** में दिया गया है।

टैरेस्ट्रियल ट्रांसमीटरों का डिजिटलीकरण

डीटीटी कई उच्च गुणवत्ता वाले चैनलों के प्रसारण की सुविधा प्रदान करता है जो विभिन्न उपकरणों जैसे कि फिक्स्ड टीवी, मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट आदि पर प्राप्त की जा सकती हैं।

11वीं और 12वीं योजना परियोजनाओं के तहत, 63 डीटीटी ट्रांसमीटरों को चरणबद्ध तरीके से देश के विभिन्न हिस्सों में स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। पहले चरण में, स्थापित किए जाने वाले 19 डीटीटी ट्रांसमीटरों में से एक–एक, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, पटना, अहमदाबाद, रायपुर, लखनऊ, भोपाल, गुवाहाटी, इंदौर, बेंगलुरु, जालंधर, रांची, कटक, औरंगाबाद, हैदराबाद तिरुअनंतपुरम और श्रीनगर में चालू किया गया है। ये डीटीटी ट्रांसमीटर, 5 डीडी चैनल जैसे कि डीडी नेशनल, डीडी न्यूज़, डीडी भारती, डीडी स्पोर्ट्स और डीडी किसान, क्षेत्रीय रिले कर रहे हैं। विस्तार के लिए उपलब्ध फंड और स्वीकृत योजना पर निर्भर है। 63 में से 44 स्थानों पर टावर को सुदृढ़ एवं विभागीय कार्य आरंभ किए गए।

दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई में दूसरा डिजिटल भू–क्षेत्रीय (टेरेस्ट्रियल) ट्रांसमीटर चालू किया गया।

हाई डेफिनिशन टीवी (एचडीटीवी)

दूरदर्शन का एचडीटीवी में स्थानांतरण 2007 में एक पायलट प्रोजेक्ट के साथ शुरू हुआ और दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक फील्ड प्रोडक्शन (ईएफपी) वैन तथा एचडीटीवी ईएनजी कैमकोर्डर और एडिट सूट उपलब्ध कराया गया। 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान एचडी ईएफपी वैन का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया था।

मल्टी–कैमरा एचडी स्टूडियो निर्माण सुविधाएं स्थापित की गई हैं और 11वीं योजना के दौरान दिल्ली और मुंबई में 10 एचडी कैमरों से सुसज्जित आउटडोर निर्माण के लिए मल्टी–कैमरा मोबाइल सुविधा प्रदान की गई है। दिल्ली में प्लेऑउट सुविधा स्थापित करने के अलावा चार महानगरों में ईएनजी आधारित निर्माण, पोस्ट प्रोडक्शन और पूर्वावलोकन

सुविधाएं प्रदान की गई हैं। बाहरी निर्माण के लिए आठ एचडी कैमरों से लैस मल्टी–कैमरा मोबाइल सुविधाएं चेन्नई और कोलकाता में भी उपलब्ध कराई गई हैं।

12वीं योजना के भाग के रूप में, एचडीटीवी प्रारूप में एक मल्टी कैमरा स्टूडियो निर्माण सुविधा को सीपीसी, दिल्ली में स्थापित किया गया है। दूरदर्शन केंद्र, दिल्ली में एचडीटीवी अपलिंकिंग की सुविधा उपलब्ध है।

दो एचडी चैनल डीडीएचडी और डीडी न्यूज़ एचडी, डीटीएच प्लेटफार्म पर उपलब्ध है। दूरदर्शन की 3 साल (2017–20) की विस्तार योजना के हिस्से के रूप में, दिल्ली से प्रसारित होने वाले सभी 7 चैनलों को (एसडी) से उच्च कोटि (एचडी) प्रसारण में स्थानांतरित करने के लिए डीडीके दिल्ली, डीडी न्यूज और सीपीसी दिल्ली में स्टूडियो केंद्र का उन्नयन किया गया है।

महत्वपूर्ण घटनाओं का एचडी कवरेजः

ओबी/ईएफपी वैन का उपयोग करके 2019–20 (26.11.2019 तक) के दौरान दूरदर्शन द्वारा 112 से अधिक महत्वपूर्ण घटनाओं को लाइव कवर किया गया है।

1. राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय चैनल

NATIONAL

डीडी नेशनल– दूरदर्शन का सर्वोत्कृष्ट चैनल

राष्ट्र के लोक सेवा प्रसारक के मुख्य और प्रमुख चैनल के रूप में, डीडी नेशनल मनोरंजन, सूचना और शिक्षा का स्वस्थ मिश्रण प्रदान करता है। यह स्थलीय मोड में प्रातः 05.30 बजे से मध्य रात्रि तक और उपग्रह मोड में चौबीसों घंटे उपलब्ध है।

प्रमुख घटनाओं का सीधा प्रसारण डीडी नेशनल के प्रमुख घटकों में से एक है। वर्ष 2019 में, डीडी नेशनल ने सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों को हाइलाइट करते हुए देश के विभिन्न हिस्सों में होने वाले कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण भी किया। इसके अलावा, गणतंत्र दिवस और प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस के भाषण जैसे राष्ट्रीय महत्व के आयोजनों का सीधा प्रसारण किया।

महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों की जयंती/पुण्यतिथि (जैसे स्वामी विवेकानंद, बाबा साहेब डॉ. बी.आर. आम्बेडकर, सरदार पटेल, पं. दीनदयाल उपाध्याय, नानाजी देशमुख) को कवर किया गया और डीडी नेशनल समुचित महत्व प्रदान करते हुए प्रसारित किया गया। सतर्कता जागरुकता और राष्ट्रीय एकता दिवस के कार्यक्रम भी डीडी नेशनल पर प्रसारित किए गए।

माननीय प्रधानमंत्री के भाषण का प्रसारण डीडी नेशनल पर किया जाता है और इसके देश की जनता व्यापक इसे देख और सुनते हैं।

वर्ष के दौरान बड़ी पहल और उपलब्धियांः

- दर्शकों को वापस खींचने के लिए डीडी नेशनल पर ब्लॉक बस्टर फ़िल्म और सामाजिक रूप से प्रासंगिक सामग्री वाली उच्च मनोरंजन मूल्यों के साथ निर्मित फ़िल्म प्रदर्शित करना।
- डीडी नेशनल भी लुक और फील बढ़ाने, ग्राफिक्स, सेट डिजाइन, प्रोमो और लोगो टेम्प्लेट पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है।
- समर्पित प्रचार अभियान और एक सुविचारित बिक्री रणनीति का प्रस्ताव किया गया है ताकि सामग्री का उचित मुद्रीकरण सुनिश्चित किया जा सके और दर्शकों को आकृष्ट किया जा सके।
- गणतंत्र दिवस समारोह, बीटिंग द रिट्रीट समारोह आदि जैसी प्रमुख घटनाओं को भी पिछले वर्षों की तरह कवर किया जाएगा।

दूरदर्शन पर फिल्मों का प्रसारण

वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान फिल्म विभाग की उपलब्धियां

2019–20 में दूरदर्शन महानिदेशालय के फिल्म विभाग ने महत्वपूर्ण सफलता और प्रगति की क्योंकि फिल्म टीम ने न केवल अपने दर्शकों को अच्छी फ़िल्में दिखाईं बल्कि पुराने सभी बकायों का भुगतान भी कर दिया। फिल्में अभी भी दूरदर्शन प्रसारण का प्रमुख अंग हैं। सभी बाधाओं के बावजूद, इसे डीडी के लिए अधिकतम दर्शक और राजस्व

मिल रहा है।

दूरदर्शन महानिदेशालय के फिल्म विभाग की उपलब्धियों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

वित्त वर्ष 2019–20 (अप्रैल–अक्टूबर 2019 की अवधि) में फिल्म प्रभाग ने **12.1** करोड़ रुपये का व्यय करके 36. 8 करोड़ रुपये का राजस्व सफलतापूर्वक अर्जित किया है। पिछले 6 वर्षों में फिल्म द्वारा अर्जित राजस्व का रेखांकन इस प्रकार है:

(सभी आंकड़े करोड़ में)

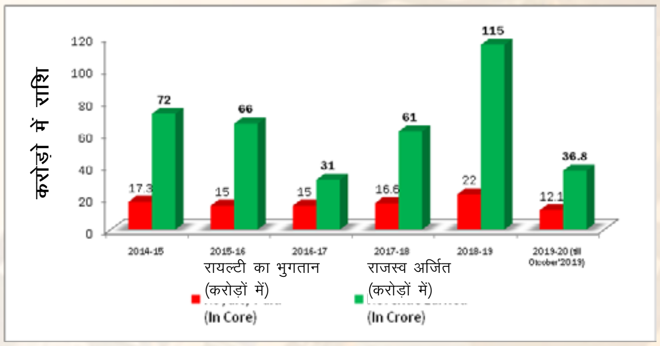

(केवल पहले छह महीनों के लिए)

वर्ष 2015 से औसत दर्शक संख्या में 200 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि डीडी–नेशनल के कुल दर्शकों का लगभग 61 प्रतिशत फिल्म देखने वाले दर्शक थे।

पिछले 05 वर्षों में दूरदर्शन के फिल्म देखने वाले दर्शकों का रेखीय अंकन इस प्रकार है :

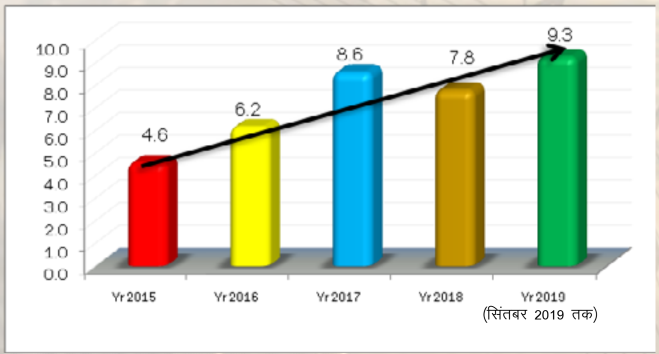

फिल्म प्रभाग वित्त वर्ष 2019–20 के लिए आबंटित कुल बजट में से 20.00 करोड़ रूपये व्यय किए। इसे आगे के लिए 10 करोड़ का अतिरिक्त बजट आवंटित किया गया है।

11–16 अगस्त, 2019 से **'जश्न–ए–आज़ादी स्पेशल'** सप्ताह का आयोजन। स्वतंत्रता दिवस मनाने और दर्शकों में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए दूरदर्शन पर सात देशभक्ति फिल्में प्रसारित की गईं।

- 31 अक्टूबर, 2019 अर्थात राष्ट्रीय एकता दिवस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन पर आधारित फिल्म 'सरदार' का प्रसारण।
- महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर 'अहिंसा' का संदेश देने के लिए 2 अक्टूबर, 2019 को फिल्म 'लगे रहो मुन्ना भाई' का प्रसारण।
- प्रसार भारती बोर्ड ने दूरदर्शन के लिए हिंदी फीचर फिल्मों की आपूर्ति के लिए एक नई नीति को मंजूरी दी है।

डीडी न्यूज़

डीडी न्यूज़ देश का एकमात्र स्थलीय–सह–उपग्रह और बहुभाषी समाचार चैनल है। डीडी न्यूज़ गैर–केबल, गैर–उपग्रह घरों में स्थलीय संचरण मोड के माध्यम से भी उपलब्ध है।

डीडी न्यूज़ 3 नवंबर, 2003 डीडी मेट्रो चैनल को 24 घंटे के समाचार चैनल में में परिवर्तित करके शुरू किया गया था। दिल्ली स्थित मुख्यालय से यह वर्तमान में मूक बधिर लोगों के लिए दो विशेष बुलेटिनों के अलावा, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत भाषाओं में समाचार प्रसारित कर रहा है। इसमें प्रतिदिन कुल 17.5 घंटे लाइव प्रसारण द्वारा इन भाषाओं में 40 से अधिक समाचार बुलेटिनों का प्रसारण होता है।

चैनल पर प्रसारित होने वाले विशेष कार्यक्रमों में स्वास्थ्य, युवा मामले, सिनेमा, कला और संस्कृति, फ्लैगशिप योजना, प्रमुख योजनाएं, अंतरराष्ट्रीय आयोजन, बाज़ार के घटनाक्रम और सामाजिक मुद्दों पर कार्यक्रम शामिल हैं।

समाचार संग्रहण

डीडी न्यूज़ में नवीनतम उपग्रह आधारित प्रौद्योगिकियों के जरिए, डीएसएनजी/ओबी वैन के साथ और फाइल

इंटरनेट/सेलुलर मोबाइल आधारित प्रौद्योगिकियों के माध्यम से दूर–दराज इलाकों सहित देशभर से समाचारों का संग्रहण किया जाता है। डीडी न्यूज़ अपने अधिकांश समाचार निम्नलिखित स्रोतों से एकत्रित करता है :

– मुख्यालय और क्षेत्रीय समाचार इकाइयों में कार्यरत अपने संवाददाताओं से

– स्ट्रिंगर और अंशकालिक संवाददाताओं से

– एजेंसियों (पीटीआई, यूएनआई, रायटर्स, एएनआई) से

– अंतरराष्ट्रीय साझेदारों (उदाहरण के लिए अन्य राष्ट्रीय प्रसारकों, एशियाविजन) से

उपलब्धियां

चैनल के प्रारूप और सामग्री का पुनर्गठन डीडी न्यूज़ की एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। हाल ही में कई नए कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं।

डीडी न्यूज में पारंपरिक गतिविधियों के प्रारूप का पुर्नगठन और चैनल के विषय वस्तु में उल्लेखनीय परिवर्तन किया गया है। विगत कुछ दिनों में कई नए कार्यक्रम आरंभ किए गए। इनमें से कुछ माननीय प्रधानमंत्री का साक्षात्कार, डीडी न्यूज पर हिंदी प्राइम टाइम, जनादेश 2019 : मिड डे प्राइम टाइम ग्राउंड रिपोर्टर्स। जमीनी हकीकत, जल शक्ति समाचार मूक बधिरों के लिए अतिरिक्त समाचार, वार्ता संस्कृत समाचार, दो टूक रंग–तरंग, टोटल हेल्थ, तेजस्विनी, सोशल कनेक्शन, वार्तावली नया सवेरा, ब्रेकफास्ट शो, मार्केट दिस वीक, किसान समाचार और गुड न्यूज इंडिया।

डीडी न्यूज़ ने प्रधानमंत्री के "मन की बात" संबोधन को रेडियो प्रसारण के साथ–साथ टीवी प्रसारण के लिए अपनाया है, जिसे कई निजी चैनलों पर भी प्रसारित किया गया। इसे पैकेज्ड स्टोरीज, चर्चाओं और लोगों की प्रतिक्रियाओं के जरिए पूर्ण कवरेज प्रदान की गई।

तकनीकी अवसंरचना

इस 24x7 न्यूज़ चैनल का दिल्ली में अपना राष्ट्रीय न्यूज़ रूम और दो स्टूडियो हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से उपग्रह आधारित समाचार एकत्र करने के लिए, विभिन्न राज्यों में 16 डीएसएनजी वैन मौजूद हैं। सबसे बढ़कर, जहां डीएसएनजी वैन उपलब्ध नहीं हो पाती हैं या तैनात नहीं की जा सकती हैं, तो वहां मोबाइल कनेक्टिविटी आधारित बैकपैक उपकरण तैनात किए जाते हैं। 3 दिसंबर, 2018 को डीडी न्यूज ने हाईडेफिनेशन फार्मेट आरंभ किए हैं।

डीडी न्यूज़ अपने सहयोगी चैनलों के लिए समाचार तैयार करता है। डीडी न्यूज़, डीडी उर्दू के लिए भी 9 लाइव बुलेटिन और समाचार स्क्रोल्स बनाता है। किसान चैनल की शुरुआत के साथ ही डीडी न्यूज़ किसानों की दिलचस्पी के दो नए बुलेटिन प्रसारित कर रहा है।

डीडी न्यूज़ ने अपने निर्माण में वीडियो वॉल्स जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं की शुरुआत की है। अधिकांश समाचार बुलेटिन, कार्यक्रम और लाइव शो वीडियो वॉल्स की सहायता से प्रस्तुत किए जाते हैं।

इंटरनेट और सोशल मीडिया पर डीडी न्यूज़

न्यूज़ चैनल ने अपनी वेबसाइट के अलावा भी सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति दर्ज की है जिसमें फेसबुक पेज, अंग्रेजी और हिंदी में ट्विटर हैंडल और एक यूट्यूब चैनल शामिल है। डीडी न्यूज़ की वेबसाइट तक www.ddinews.gov.in या www.ddinews.com. पर देखी जा सकती हैं। सितंबर, 2013 में वीडियो देखने की सुविधा के साथ वेबसाइट को एक नए अंदाज में लांच किया गया था और इसे और संवारा गया है और उपयोग सुलभ बनाया गया है।

डीडी न्यूज़ के इंग्लिश ट्विटर हैंडल @DDNewslive की शुरुआत जनवरी 2013 में की गई थी और अब इसे **26 लाख** से अधिक लोगों द्वारा फॉलो किया जाता है। हिंदी में इसके नए ट्विटर हैंडल @DDNewsHindi की शुरुआत जनवरी 2014 में की गई थी और इसके भी **7 लाख** से ज्यादा फॉलोअर्स हैं।

इसी तरह डीडी न्यूज़ के **19 लाख** से ज्यादा फॉलोअर हैं और दिन प्रतिदिन ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं।

एक समर्पित यूट्यूब चैनल http://www.youtube.com/ddnews की शुरुआत फरवरी 2013 में की गई थी। डीडी न्यूज़ के यूट्यूब चैनल के **21 लाख** से अधिक सब्सक्राइबर हैं।

डीडी न्यूज़ मोबाइल एप लोगों को समाचार और समसामयिक मामलों की जानकारी देने के लिए सहज सुलभ हो गया है। इस एप का नया संस्करण जल्द ही शुरू किया जाएगा। डीडी न्यूज़ तक निम्नलिखित साधनों के माध्यम से भी पहुंच बनाई जा सकती है :

- वेबसाइट
- मोबाइल एप
- यूट्यूब चैनल
- एनआईसी का लाइव कास्ट चैनल : http://webcast.gov.in

क्षेत्रीय समाचार इकाइयां

डीडी न्यूज़ ने बीते वर्षों में देशभर में 31 क्षेत्रीय समाचार इकाइयों/ब्यूरो स्थापित किए हैं। ये आरएनयू एक दिन में 23 भाषाओं/बोलियों में 227 से अधिक समाचार बुलेटिनों का प्रसारण करते हैं और प्रतिदिन कुल मिलाकर 48 घंटे से अधिक समय तक प्रसारण करते हैं।

डीडी भारती

डीडी भारती चैनल कला और संस्कृति को समर्पित है। जनवरी 2002 में आरंभ होने के बाद से ही यह चैनल भारत की सांस्कृतिक विरासत का ऑन–एयर भंडार बन गया है। यह चैनल भारतीय शास्त्रीय और लोक संगीत और नृत्य के स्वरूपों, कला–शिल्प, रंगमंच, भारतीय वास्तुकला, विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियों की जीवनियों के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं के समृद्ध संग्रहों के जरिए इतिहास, विरासत और आधुनिक संस्कृति को बढ़ावा और संरक्षण दे रहा है।

डीडी भारती अनेक सराहनीय और विख्यात नृत्य (प्रसिद्ध कलाकार, विभिन्न जनजातीय नृत्यों और कला रूपों, नृत्यांजली नृत्य महोत्सव माटी के रंग), संगीत और साहित्य महोत्सवों का सीधा प्रसारण करता आ रहा है। उपर्युक्त अवधि के दौरान इसने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ख्याति के लगभग 50 से अधिक सीधे प्रसारण किए हैं, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल शामिल हैं। दीपावली, होली, रक्षाबंधन, ईद, क्रिसमस आदि जैसे सभी त्योहारों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं।

डीडी उर्दू

डीडी उर्दू 15 अगस्त, 2006 को दूरदर्शन के उर्दू चैनल के रूप में लॉन्च किया गया था, जिसमें प्रतिदिन आठ घंटे का प्रसारण होता था। बाद में, 14 नवंबर, 2007 से चैनल के 24x7 घंटे के प्रसारण की शुरुआत हो गई। इस समृद्ध भाषा की महान सांस्कृतिक विरासत और साहित्यिक पहलू के संरक्षण और संवर्धन को प्रोत्साहित करने के लिए एक विरासत चैनल के रूप में परिकल्पित डीडी उर्दू देश के उर्दू चैनलों में से सबसे अधिक देखा जाने वाला चैनल है। यह चैनल प्रतिदिन 10 समाचार बुलेटिनों का प्रसारण करता है।

डीडी इंडिया

यह चैनल डीडी इंडिया दूरदर्शन का 24X7 फ्री टू एयर चैनल है। 14 मार्च, 1995 को अंतरराष्ट्रीय चैनल प्रारंभ हुआ। इसका दो बार नाम बदला गया। पहले यह चैनल 2000 में 'डीडी वर्ल्ड' के नाम से था। इसे बाद में 2002 में बदल कर 'डीडी इंडिया' कर दिया गया। डीडी इंडिया 28.12.2017 महानिदेशक (एनएंडसीए) को सौंपा गया। विगत दो वर्षो से इंग्लिश न्यूज़ और हिंदी समाचार चैनल बनाने के लिए वर्तमान में डीडी और आरएसटीवी आदि से प्रसारण करता है। मार्च 2019 के बाद डीडी इंडिया को इंग्लिश न्यूज़ चैनल की बीएआरसी से पहचान मिली और निरंतर टीआरपी रेटिंग प्राप्त हो रहा है।

इसमें इंग्लिश न्यूज और कुछ प्रोग्राम प्रसारित किए जाते हैं। डीडी इंडिया को टॉप रेटिंग मिला हुआ है। यह अंतरराष्ट्रीय दर्शकों के साथ–साथ देश के गैर हिंदी भाषा क्षेत्र के दर्शकों को आकर्षित करने में सक्षम है। यह चैनल भारत की संस्कृति, मूल्यों, आर्थिक–क्षमता, इसके गौरवशाली इतिहास और प्रतिभाशाली युवाओं सही मायनों में दर्शाता और विस्तार करता है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्दों का ध्यान रखते हुए समाचार का विषय, करेंट अफेयर पर कार्यक्रम बनाता है जो समानरूप से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं जिसका प्रभाव प्रमुख राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर पड़ता है।

उपलब्धि

क) डीडी न्यूज के सभी अंग्रेजी विषय का डीडी इंडिया पर प्रसारण

ख) डीडी इंडिया के शाम के प्राइम टाइम में न्यूज नाइट शो और अन्य करेंट अफेयर कार्यक्रम महत्वपूर्ण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जैसे

ग) प्रधानमंत्री के विदेशयात्राः डीडी इंडिया ने आरंभ किया है, इसमें अलग से विशेषकर अंग्रेजी में परिचर्चा भी की जाती है।

घ) डीडी इंडिया का अपना अलग आकर्षण है। इसका नया आईडी और लोगो बना है। ऐस्टन सुपर, तारीख, टाइम बेंड, वाइप, स्लग और अन्य कलेवर इसे नया रूप और स्पर्श ज्ञान दे रहे हैं।

ङ) डीडी न्यूज के पास नया न्यूज टिकट आया है जिसमें न्यूज फ्लैश के फीचर, ब्रेकिंग न्यूज, कमिंग अप और लेटर टू को स्थान दिया जाता है।

च) मोनटॉज, स्क्रीन प्रोपर्टी, संगीत इत्यादि को नया लाया गया है।

छ) डीडी न्यूज के कार्यक्रम का अलग और नया आधुनिक एवं आकर्षक प्रोमो बनाया गया है। डीडी इंडिया का डीडी न्यूज में अंतरचैनल प्रचार किया जाता है।

ज) डीडी न्यूज नए विषय पर डीडी इंडिया के लिए करेंट अफेयर पर कार्यक्रम तैयार किया।

डीडी इंडिया पर नए और विशेष कार्यक्रम बनाए गए।

क) ग्लोब स्कैनः पूरे विश्व की अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर साप्ताहिक समाचार पत्रिका का आविष्कार के 2:00 बजे प्रसारण

ख) (एम) न्यूज नाईट इंग्लिशः राजनैतिक से सामाजिक आर्थिक विकास, मीडिया, मनोरंजन से खेल तक हर क्षेत्र को न्यूज नाईट में लिया जाता है। यह एक घंटे का क्रार्यक्रम रात 8 बजे सोमवार से शुक्रवार प्रसारित किया जाता

ग) स्पोर्ट्स 360 का प्रसारण शनिवार शाम और पुनःप्रसारण रविवार 7 बजे किया जाता है।

घ) सोशल कनेक्शनः सोशल मिडिया और नई तकनीकी पर समाचार एकत्र कर एक समाचार पत्रिका डीडी इंडिया पर बनाई जाती है।

ङ) सिनेमा स्कोपः नए फिल्मों की जानकारी दर्शकों को दी जाती है और फिल्म एवं मनोरंजन उद्योग के शीर्षस्थ व्यक्तित्व से साक्षात्कार और बातचीत की जाती है।

च) वाई फैक्टरः युवाओं से ताजा मुद्दों पर परिचर्चा करने का कार्यक्रम का विचार है

छ) द कश्मीर ट्रूथः घाटी की वास्तविक परिस्थिति पर रिपोर्ट, अपडेट, परिचर्चा और विकास पर सभी को सूचना देने के लिए कार्यक्रम तैयार किया

ज) फॉलोइंग महात्मा – महात्मा गांधी के 150वीं जयंती के अवसर पर गाना, कार्यक्रम, परिचर्चा, बातचीत के शोकेस की शृंखला डीडी इंडिया में तैयार किया गया।

DD SPORTS

डीडी स्पोर्ट्स

यह चैनल दर्शकों को रोचक वृत्तांतों और खेलों के दृश्यों के माध्यम से खिलाड़ियों के जीवन, उनके परिवारों, और खेलों के दौरान खिलाड़ियों के दिमाग में क्या चल रहा होता है, की एक झलक दिखाता है। वित्त वर्ष 2019–2020 डीडी स्पोर्ट्स के लिए बदलाव का महत्वपूर्ण साल है। इस अवधि के दौरान, विशेष कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है और लोगों को फिट इण्डियाअभियान के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए तैयार किया गया है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 और नॉर्थ ईस्ट स्पोर्ट्स के दौरान श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए सांकेतिक भाषा के साथ विशेष कार्यक्रम नॉर्थ ईस्ट स्पोर्ट्स न्यूज को प्रसारित करके पूरे देश को दिखाया गया था।

पथ प्रवर्तक पहल

स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल ने क्रिकेट विश्व कप 2019 के दौरान अपने उपभोक्ता आधार में नौ गुना वृद्धि की। खेल प्रेमियों के लिए आकाशवाणी और डीडी स्पोर्ट्स से श्रव्य–

दृश्य सामग्री का आंखों देखा हाल डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर सीधा प्रसारित किया गया। ऑल इंडिया रेडियो के विशेष स्टूडियो आधारित स्पोर्ट्स शो का वीडियो बनाया गया और दर्शकों को समृद्ध अनुभव प्रदान किया गया। ऐतिहासिक विषयवस्तु को डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए फिर से तैयार करके अपलोड किया गया। साप्ताहिक "स्पोर्ट्स डायरी" में विभिन्न खेलों, खेल हस्तियों, स्वदेशी खेल, क्षेत्रीय खेल और उनके संघर्ष और सफलता की कहानियों के बारे में विजेताओं के साक्षात्कार का प्रसारण किया जाता था।

उत्तराखंड क्षेत्र में रामगंगा नदी के किनारे खूबसूरत पहाड़ी इलाकों में मरचुला महोत्सव, केरल की नौका दौड़, पूर्वोत्तर में पोलो, राजस्थान की मरुभूमि में कार रैली और गोवा में समुद्र के किनारे खेल गतिविधियों की डीडी स्पोर्ट्स द्वारा कवरेज की गयी थी। ऐसा इन क्षेत्रों की संस्कृति और पर्यटन के साथ–साथ खेलों को बढ़ावा देने के लिए किया गया था।

डीडी स्पोर्ट्स भी राष्ट्रीय महत्व के खेल आयोजनों के दौरान अपने दर्शकों के लिए दो तरह से प्रसारण करता है। जहां डीडी की फ्री डिश से दर्शक दुनिया भर से राष्ट्रीय महत्व के खेलों ही को देख सकते हैं, वहीं निजी डीटीएच और एमएसओ प्लेटफार्मों पर इसके नियमित रूप से प्रसारण चलते रहते हैं।

डीडी किसान

दूरदर्शन के स्वामित्व में 26 मई, 2015 को लॉन्च किया गया किसान टीवी किसानों और विशाल कृषि क्षेत्र के लिए विशेष रूप से समर्पित 24 घंटे का चैनल शुरू करने की दिशा में लोक प्रसारणकर्ता की प्रथम पहल है। किसानों को नई तकनीक, फसल सुरक्षा, उर्वरक, बीज, सिंचाई और जल संरक्षण, फसल चयन, खेत मशीनीकरण, कृषि व्यवसाय तथा अन्य मामलों के अलावा विशाल खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, डेयरी और पशुपालन, बागवानी और जैविक खेती की जानकारी सहित विभिन्न कृषि और कृषि संबंधी मुद्दों पर वास्तविक समय पर जानकारी देता है। इसे खेती के लिए महत्वपूर्ण सभी चीजों – जल संरक्षण और जैविक खेती से लेकर सरकारी कृषि कार्यक्रमों के माध्यम से ऋण कैसे प्राप्त करें तक को दर्शाने के लिए तैयार किया गया है।

यह चैनल किसानों को कृषि तकनीकों के नए नवाचारों से अवगत कराने के लिए वृत्तचित्रों का भी प्रसारण करता है, इसके अलावा किसानों की दिलचस्पी वाले रियलिटी और कुकरी शो की भी मेज़बानी करता है तथा मौसम की जानकारियां भी नियमित रूप से देता है।

चैनल का आईएमडी, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों के साथ गठजोड़ है। अधिकांश कार्यक्रम इन–हाउस में निर्मित किए जाते हैं।

किसान चैनल द्वारा दैनिक आधार पर औसत सात घंटे की नवीनतम सामग्री का निर्माण किया जाता है। चैनल ने सभी डीडीके और पीजीएफ को डीडी किसान के कार्यक्रमों के निर्माण करने से जोड़कर दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क को जोश से भर दिया है।

निम्नलिखित पहल लगातार और स्थाई क्वालिटी पर केंद्रित है।

2019–20 की नई पहल

- मौसम ख़बर – सुबह, दोपहर और शाम के समय बैंड में नवीनतम बुलेटिन। भारत मौसम विभाग के सहयोग से कार्यक्रम के प्रस्तुतीकरण को पूरी तरह से बदला जा रहा है।
- कृषि और संबद्ध गतिविधियों में सर्वोत्तम कार्यविधि का प्रदर्शन करने के लिए "ये है मेरा भारत" नामक कार्यक्रम की एक श्रृंखला। कार्यक्रम यात्रा वृतांत प्रारूप में है।
- डीडी महिला किसान पुरस्कारों का एक मेगा रियेलिटी शो प्रसारित किया गया। यह एक अनूठा प्रदर्शन था, जिसमें देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 114 महिला किसानों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा नामित किया गया था। रियलिटी शो के कुल 56 एपिसोड प्रसारित हुए हैं।

नए कार्यक्रम

- महानगरों से शिक्षित युवाओं/महिलाओं का कृषि और उससे जुड़े कार्यों से जुड़कर अपने भविष्य की रूपरेखा बनाने के लिए एग्रो स्टार्ट अप शुरू करने का महत्व बताने के लिए "बिजनेस किसान" शीर्षक से कार्यक्रम।

- कृषि के क्षेत्र में नवीनतम जानकारियों और गतिविधियों के बारे में विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रकाशित विभिन्न कृषि आधारित पत्रिकाओं के माध्यम से किसानों को सूचित करने और शिक्षित करने के लिए "कृषि परिक्रमा" शीर्षक से कृषि साहित्य पर कार्यक्रम।
- देश भर में पशुपालन के विभिन्न पहलुओं पर विशेष कार्यक्रम श्रृंखला।
- औषधीय पौधों, उनकी व्यवहार्यता और वाणिज्यिक पहलुओं पर विशेष कार्यक्रम श्रृंखला।

कई पहलों के माध्यम से जागरूकता लाने के साथ ही चैनल को बढ़ावा देना

- डीडी किसान का सीधा यूट्यूब प्रसारण
- दूरदर्शन नेटवर्क परस्पर चैनल प्रचार।
- सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय उपस्थिति।
- आपसी संवाद वाले क्षेत्र आधारित कार्यक्रम

डीडी सह्याद्री

डीडी सह्याद्री 24X7 क्षेत्रीय मराठी चैनल है जिसमें सुबह 6 बजे से 9 बजे (रविवार को छोड़कर) और अपराह्न 3 बजे से सायं 7 बजे (सभी दिन) तक स्थलीय समर्थन प्राप्त है। यह चैनल 2 अक्टूबर, 1972 को चालू किया गया था और मराठी में क्षेत्रीय भाषा उपग्रह सेवा 15 अगस्त, 1994 से शुरू हुई थी। 5 अप्रैल, 2000 को इसने चौबीसों घंटे की सेवा शुरू की। आज, डीडी सह्याद्री पांच स्टूडियो और एचडी ट्रांसमिशन से लैस है।

2019–20 के दौरान उपलब्धियां:

- डीडी सह्याद्री को अपने सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रमों और उच्चतम राजस्व संग्रह के लिए डीडी अवार्ड से सम्मानित किया गया।
- डीडी सह्याद्री ने 15 अगस्त, 2019 से अपने दर्शकों के लिए दोपहर 1.30 बजे दैनिक मराठी फिल्म का प्रसारण शुरू किया।
- यूट्यूब पर (अप्रैल–2019 में) ग्राहक संख्या एक लाख करने के लिए सिल्वर बटन प्राप्त किया।

डीडी गिरनार

गुजराती में उपग्रह क्षेत्रीय भाषा चैनल डीडी–11, दिल्ली से अपलिंकिंग के माध्यम से 1 अक्टूबर, 1993 को प्रारंभ हुआ और इसी सेवा ने 15 अगस्त, 1994 को स्थानीय स्तर से अपलिंकिंग प्रारंभ कर दी। क्षेत्रीय उपग्रह भाषा सेवा पर 01.05.2000 से चौबीस घंटे का प्रसारण आरंभ हो गया और डीडी गिरनार 02.10.2007 से जाना–पहचाना ब्रांड बन गया।

डीडी पोधिगई

क्षेत्रीय भाषा का तमिल उपग्रह चैनल–पोधिगई 15 जनवरी, 2001 से प्रसारण के साथ प्रारंभ हुआ।

डीडी यदागिरी

संयुक्त आंध्र प्रदेश के दो राज्यों में विभाजित होने के बाद डीडी सप्तगिरि चैनल को हैदराबाद में डीडी–यदागिरी चैनल का नाम दिया गया और उसने 27 सितंबर, 2014 से कार्य करना शुरू कर दिया।

डीडी सप्तगिरि

डीडी सप्तगिरि 27 सितंबर, 2014 को आंध्र प्रदेश की जनता को समर्पित किया गया।

डीडी बांग्ला

20 अगस्त, 1992 को शुरू किया गया डीडी बांग्ला 1 जनवरी, 2000 से 24 घंटे का चैनल बन गया। डीडी बांग्ला बंगाल की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

डीडी पंजाबी

डीडी पंजाबी एक 24 घंटे का पंजाबी चैनल है, जिसे उपग्रह जीसैट–17 के माध्यम से भारत और अन्य देशों में व्यापक रूप से देखा जाता है। डीडी पंजाबी चैनल उपग्रह जीसैट–15 पर डीटीएच प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है और इसे पूरी दुनिया में इंटरनेट के माध्यम से देखा जा सकता है।

दूरदर्शन केंद्र जालंधर को जुलाई 2019 में सर्वोत्तम कुशल परिचालन पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

डीडी कशीर

डीडी–कशीर चैनल 26 जनवरी, 2000 को लॉन्च किया गया था, जिसे बाद में 15 मार्च, 2003 से 24 घंटे के चैनल में परिवर्तित कर दिया गया। चैनल राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों द्वारा बोली जा रही 12 अलग–अलग भाषाओं/बोलियों में कार्यक्रमों का निर्माण कर रहा है। चैनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब का उपयोग डीडी–कशीर के सभी कार्यक्रमों और इंटरैक्टिव शो की लाइव स्ट्रीमिंग को बढ़ावा देने के लिए कर रहा है। यह चैनल डीडी–किसान में भी योगदान दे रहा है।

डीडी ओडिया

डीडी ओडिया ने 2 अक्टूबर, 1993 से डीडी–5 के रूप में कार्य करना शुरू किया। 1 अप्रैल, 2001 को इसे 24–घंटे का चैनल बनाया गया।

उपलब्धियां

- 16.09.2019 को दूरदर्शन वार्षिक पुरस्कारों–2019 में 2017 (पूर्वी क्षेत्र) के लिए सर्वश्रेष्ठ रखरखाव वाले केंद्र का पुरुस्कार प्राप्त किया।
- उभयलिंगी (ट्रांसजेंडर) पर निर्मित वृत्तचित्त नाटिका "तथापिजीवन" को 2019 के दूरदर्शन वार्षिक पुरस्कार समारोह में वर्ष 2018 के लिए वृत्तचित्र श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यू–ड्रामा पुरस्कार मिला।

डीडी मलयालम

डीडी मलयालम ने 1985 में अपनी शुरुआत से ही पूरे देश में अपनी उपस्थिति महसूस कराई है। केंद्र में तिरुअनंतपुरम, त्रिचूर और कालीकट में निर्माण की सुविधाएं और राज्य भर में स्थलीय ट्रांसमीटरों का नेटवर्क है।

डीडी चंदना

15 अगस्त, 1994 को प्रारंभ किया गया डीडी चंदना कन्नड़ भाषा का उपग्रह चैनल है जिसे बंगलुरु एवं गुलबर्गा के दूरदर्शन स्टूडियो का सहयोग मिलता है। वर्ष 2000 में यह चौबीस घंटे प्रसारण वाला चैनल हो गया तथा 24 मार्च, 2003 से इसकी कवरेज 30 से अधिक देशों में होने लगी।

28.12.2018 को नया डिजिटल अर्थ स्टेशन स्थापित और आरंभ किया गया।

डीडी पूर्वोत्तर

डीडी पूर्वोत्तर 1 नवंबर, 1990 में कमीशंड किया गया और अंततः 15 अगस्त, 1994 को इसका शुभारंभ किया गया। 27 दिसंबर, 2000 से यह 24 घंटे प्रसारण वाला चैनल हो गया।

डीडी अरुण प्रभा

दूरदर्शन केंद्र इटानगर से शुरू किए गए डीडी अरुणप्रभा को 9 फरवरी, 2019 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह चैनल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है, जिसमें 24x7 टेलीकास्ट के लिए दूरदराज के क्षेत्रों से सीधे समाचार भेजने के लिए एक डिजिटल सैटेलाइट समाचार संकलन इकाई शामिल है। डीडीके ईटानगर में स्थापित प्लेआउट सुविधा और पृथ्वी स्टेशन डीडी अरुणप्रभा का निर्बाध प्रसारण सुनिश्चित करते हैं।

डीडी अरुण प्रभा का उद्घाटन समारोह, ईटानगर, फरवरी, 2019

यह चैनल पूरे देश के साथ पूर्वोत्तर को जोड़ता है। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं के समसामयिक मनोरंजन के साथ ही उन्हें नवीनतम समाचारों के लिए आकर्षित करना होगा। चैनल नैसर्गिक प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के साथ ही उन्हें सक्षम बनाएगा और योग्य कार्यक्रम निर्माताओं/कलाकारों को एक मंच प्रदान करता। इसके अलावा यह चैनल पूर्वोत्तर में दूरदर्शन के दर्शकों के लाभ के लिए आवश्यक भाषाओं/बोलियों में कार्यक्रमों के निर्माण को प्रोत्साहित करता है।

कार्यक्रमों का प्रसारण पूर्ण रूप से चल रहा है और इसमें 111 प्रोग्राम विभिन्न विषयों पर प्रसारित किए जा रहे हैं। जैसे कि डेली सॉप, तिलाविलोग्यू रियलटी शो, डाक्यूमेंट्री, रोमांचक, धार्मिक, पत्रिका, टेलीफिल्म और क्विज़ इत्यादि।

चैनल शुरू होने से पूर्व प्रसिद्ध गायक शान (शांतनु मुखर्जी) ने चैनल का थीम सॉग तैयार किया। चैनल ने विभिन्न तरह के घरेलु कार्यक्रम का भी निर्माण किया है। जैसे कॉल ऑफ द वाइल्ड, पूर्वोत्तर का खान–पान, इस्पेक्ट्रमः बैंड ऑफ नार्थ ईस्ट इत्यादि।

चैनल ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया है और दूरदर्शन इसके स्तर को बढ़ाने के लिए कार्यरत है जिससे चैनल और आकर्षक हो।

डीडी राजस्थान

डीडी राजस्थान, चौबीस घंटे प्रसारण वाले हिंदी क्षेत्रीय चैनल के रूप में 1 अगस्त, 2013 को अस्तित्व में आया और 15 अगस्त 2013 से इसने औपचारिक रूप से कार्यक्रमों का प्रसारण प्रारंभ किया। 24 घंटे प्रसारण वाला यह केंद्र विभिन्न शैलियों के कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।

डीडी बिहार

डीडी–बिहार, 24×7 क्षेत्रीय उपग्रह चैनल 01.05.2013 को लॉन्च किया गया। इसने उपग्रह चैनल के रूप में अपनी शुरुआत के बाद से देशभर में अपने क्षितिज का विस्तार जारी रखा।

डीडी उत्तर प्रदेश

डीडी उत्तर प्रदेश, 24×7 हिंदी क्षेत्रीय उपग्रह चैनल 16 अगस्त, 2013 को अस्तित्व में आया। यह 24 घंटे का चैनल लोक संगीत, सुगम संगीत, नाटक, टॉक शो, क्विज़ और कुछ अभिलेखीय कार्यक्रमों जैसी शैलियों को कवर करता है।

डीडी मध्य प्रदेश

डीडीके, भोपाल उपग्रह के माध्यम से पहले 24 घंटे की टेलीकास्ट सेवा के रूप में लॉन्च किया गया था, बाद में 25 जून, 2013 को इसका नाम बदलकर डीडी मध्य प्रदेश कर दिया गया। पीजीएफः ग्वालियर और पीजीएफः इंदौर डीडी मध्य प्रदेश पर प्रसारण के लिए कार्यक्रम तैयार करते हैं। हिंदी के अलावा, मालवी, बुंदेली, बघेली और निमरी जैसी स्थानीय बोलियों में भी कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं।

व्यवसायिक, विक्रय और विपणन

दूरदर्शन व्यावसायिक सेवा

कारोबार करने में सुगमता के साथ, एक नई पंजीकरण और प्रत्यायन नीति शुरू की गई है।

यह स्कंध प्रसारण समय या एयर टाइम की बिक्री के लिए विभिन्न विज्ञापन एजेंसियों के साथ बातचीत करता है। निरंतर बदलते बाज़ार परिदृश्य को देखते हुए इस संबंध में नियम और नीतियां समय–समय निर्धारित किए जाते हैं और उनकी समीक्षा की जाती है। ग्राहकों के लिए मैनुअल बिलिंग के स्थान पर ऑनलाइन बिलिंग के लिए ब्रॉडकास्टिंग ऑटोमेटेड शेड्यूलर (बीएटीएस) शुरू किया गया।

- दूरदर्शन ने वित्त वर्ष 2019–20 (नवंबर, 2019 तक) के दौरान जीएसटी और छूट को छोड़कर 619.65 करोड़ रु का अनुमानित राजस्व अर्जित किया।

सार्वजनिक आउटरीच सेवा (पीओएस)

दूरदर्शन के सार्वजनिक आउटरीच सेवा (पीओएस) की स्थापना मार्च, 2001 में की गई ताकि वह सिंगल विंडो विपणन प्रभाग और सरकार के विभिन्न विभागों, विभिन्न मंत्रालयों और सार्वजनिक उपक्रमों की संचार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नवीन विकास संचार मॉडल सहित प्रॉडक्शन हाउस के रूप में कार्य कर सके। यह मीडिया प्लानिंग, कार्यक्रम निर्माण, शेड्यूलिंग और प्रभाव मूल्यांकन के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए टर्न–की समाधान प्रदान करता है। विकास संचार विभाग निम्नलिखित के लिए सिंगल विंडो सुविधा प्रदान करता है :

- दूरदर्शन एयरटाइम और निर्माण क्षमता का विपणन
- कंसल्टेंसी और कस्टमाइज़्ड मीडिया प्लानिंग
- देशव्यापी स्टेशनों में क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रमों का निर्माण; और
- ग्राहकों से प्रतिक्रिया और अनुसंधान सर्वेक्षण।

2019–20 के दौरान प्रसारित अभियान

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याणमंत्रालय का तंबाकू–विरोधी, चिकनगुनिया, डेंगू, टीकाकरण और स्वास्थ्य औरस्तनपान अभियान। योग, पर्यटन और स्वच्छता परपर्यटन मंत्रालय के प्रचार अभियान और वित्त मंत्रालय के आयकर पर अभियान।
- उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का "जागो ग्राहक जागो" को दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया है।
- महिला और बाल विकास मंत्रालय की साझेदारी में "पोषण" पर एक विशेष अभियान शुरू किया गया था।
- स्वच्छ गंगा पर राष्ट्रीय अभियान (एनएमसीजी) के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम 'रग रग में गंगा' (के 21 एपिसोडो) का डीसीडी द्वारा सफलतापूर्वक निर्माण औरप्रसारण किया गया। यह कार्यक्रमदर्शकों के बीच लोकप्रिय भी हुआ।
- पीसीआरए के लिए एक और क्विज़ कार्यक्रम सक्षम 2020 डीसीके साथ मिलकर दूरदर्शन केंद्र दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर और कोलकाता द्वारा बनाकर प्रसारित किया जा रहा है।
- आयुर्वेद दिवस पर अभियान तैयार कर प्रसारित किए गए।
- गंगा के किनारे स्वच्छ गंगा पर राष्ट्रीय मिशन के लिए राफ्टिंग अभियान का 30 दिनों तक विशेष कवरेज किया गया था।

भविष्य के लिए नई पहल

मीडिया प्रचार प्रभाग

मीडिया प्रचार प्रभाग एक गतिशील इकाई है जो मीडिया

और प्रचार गतिविधियों का कार्य करती है। दूरदर्शन की सभीगतिविधियों और कार्यक्रमों के प्रचार के लिए हर प्रकार के संचार, विज्ञापन, बाह्य प्रचार, प्रेस विज्ञप्ति, पुस्तिकाओं का प्रकाशन और सम्वाददाता सम्मेलन आदि इस प्रभाग द्वारा किए जाते हैं।

वर्ष के दौरान गतिविधियांः

- 13 मई, 2019 को अमेज़न पर सफलतापूर्वक स्मारिका दीर्घा शुरू की गयी थी, इस प्रकार दूरदर्शन ई–प्लेटफॉर्म पर अपनी उपस्थिति जताने वाला पहला प्रसारक बन गया। इसके लिए इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में एक समारोह का आयोजन किया गया था।
- 12वें दूरदर्शन वार्षिक पुरस्कारों के लिए फ्रेम के साथ प्रमाण पत्रों और वैजयन्तियों का प्रारूप तैयार करना।
- डाक विभाग द्वारा "मेरा स्वनिर्धारित डाक टिकट" के लिए पूरी की गयी आवश्यक कार्यवाही के बाद दूरदर्शन की 60वीं वर्षगांठ के लिए प्रचार और जनसंपर्क कार्य किया गया। इस कार्यक्रम के लिए डीडी विवरण पुस्तिकाएं (ब्रोशर), बिल्ले और सूचना पटल तैयार किए गए थे।
- डीडी, फिल्म विज्ञापन, डीटीएच, नियुक्तियां, निविदाएं/नोटिस, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के विज्ञापनों सहित वर्ष के दौरान कई अन्य विज्ञापन जारी किए गए।
- डीडी परिसर के बाहर की कई सजावटी वस्तुओं को बदला गया।
- 6 से 8 नवंबर, 2019 तक इंडिया हैबिटेट सेंटर में डीडी स्मारिका की मदों, डीडी इंडिया के सूचना पटल, डीडी फ्री डिश और आकाशवाणी समाचार/न्यूज ऑन एआईआर को प्रदर्शित करते हुए प्रदर्शनी लगाई गयी थी। आकाशवाणी समाचार/न्यूज ऑन एयर के पर्चे भीछपवाए गए थे।
- 9 नवंबर से 11 नवंबर, 2019 तक "संस्कृत विश्व सम्मेलन" पर छतरपुर मंदिर, नई दिल्ली में प्रदर्शनी लगाई गयी और डीडी स्मारिका वस्तुओं की बिक्री और प्रदर्शन के साथ डीडी इंडिया, डीडी फ्री डिश और न्यूज ऑन एयर के स्टैंड भी प्रदर्शित किए गए।
- CII बिग पिक्चर समिट 2019 में डाक टिकट का प्रदर्शन।

दर्शक अनुसंधानः

- दूरदर्शन की दर्शक अनुसंधान इकाई 1976 से पूरे देश में स्थापित अपने केंद्रों के माध्यम से दूरदर्शन प्रसारण के विभिन्न पहलुओं पर शोध अध्ययन कर रही है। इस अवधि के दौरान दर्शक अनुसंधान इकाई का योगदान निम्नानुसार हैः
- साप्ताहिक आधार पर प्रसारण दर्शक अनुसंधान परिषद (बीएआरसी) टेलीविज़न दर्शक रिपोर्ट का विश्लेषण और प्रस्तुतिकरण।
- प्रसार भारती की वार्षिक रिपोर्टः 2018–19 तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्टः 2019–20 तैयार करना।
- दूरदर्शन चैनल के वित्तीय वर्ष 2019–20 के दर्शकों के डाटा के अनुसार एजेंडा तैयार कर बार्क में हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत करना और कार्यों का वर्णन तैयार कना है।
- वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान दर्शक अनुसंधान इकाई, डीडीके चेन्नई द्वारा तमिलनाडु के डिंडीगुल और मदुरै जिलों में डीडी पोधिगई कार्यक्रमों पर सामान्य दर्शक सर्वेक्षण।
- बार्क और बीएमडब्ल्यू साफ्टवेयर का संगठित प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत मूलभूत और आधुनिक मॉड्यूलर का प्रशिक्षण।

अनुलग्नक–I

दूरदर्शन उपग्रह चैनल

अखिल भारतीय चैनल (6)	डीडी नेशलन	डीडी न्यूज़	डीडी स्पोर्ट्स
	डीडी भारती	डीडी उर्दू	डीडी किसान
क्षेत्रीय चैनल (17) (24x7)	डीडी मलयालम	डीडी चांदना	डीडी यदागिरी
	डीडी पोधिगई	डीडी सहयाद्री	डीडी गिरनार
	डीडी उडिया	डीडी कशीर	डीडी पूर्वोत्तर
	डीडी बांग्ला	डीडी पंजाबी	डीडी राजस्थान
	डीडी बिहार	डीडी उत्तरप्रदेश	डीडी मध्यप्रदेश
	डीडी सप्तगिरी	डीडी अरुणप्रभा	

क्षेत्रीय चैनल (24x7 नहीं चलता है।)	हिमाचल प्रदेश	झारखंड	चंडीगढ़
	हरियाणा	उत्तराखंड	त्रिपुरा
	मिज़ोरम	मेघालय	मणिपुर
	नगालैंड	गोवा	
अंतरराष्ट्रीय चैनलस	डीडी इंडिया		

अनुलग्नक -II

डीडी फ्री चैनल का संक्षिप्त विवरण 28.11.19						
टीएस -1	टीएस -2	टीएस -3	टीएस -4	टीएस -5	टीएस -6 (टेस्ट)	
फ्रीक्वेंसी (मेगाहर्टस) यू/एल -14140 डी/एल - 11090, एस.आर. - 29.5 एमएसपीएस, एफईसी - 3/4	फ्रीक्वेंसी (मेगाहर्टस) यू/एल -14220 डी/एल - 11170, एस.आर. - 29.5 एमएसपीएस, एफईसी - 3/4	फ्रीक्वेंसी (मेगाहर्टस) यू/एल -14270 डी/एल - 11470, एस.आर.- 29.5 एमएसपीएस, एफईसी - 3/4	फ्रीक्वेंसी (मेगाहर्टस) यू/एल -14310 डी/एल - 11510, एस.आर. -29.5 एमएसपीएस, एफईसी - 3/4	फ्रीक्वेंसी (मेगाहर्टस) यू/एल -14350 डी/एल - 11550, एस.आर. .- 29.5 एमएसपीएस एफईसी - 3/4	फ्रीक्वेंसी (मेगाहर्टस) यू/एल -14430 डी/एल - 11630, एस.आर. - 30 एमएसपीएस, एफईसी- 3/5	
चैनल (As per एमपीईजी 4 सेट टॉप बॉक्स डीकोडिंग के अनुरूप)						
1. डीडी न्यूज़	18. टेस्ट–118	35. टेस्ट–217	52. डीडी पूर्वोत्तर	69. एबीपी न्यूज़	86.एम.टी.वी. बीट	
1. डीडी नेशलन	19. डीडी इम्फाल	36. टेस्ट–2018	53. टेस्ट–317	70. ज़ी न्यूज़	87. फकाट मराठी	
3. डीडी स्पोर्ट्स	20. डीडी उड़िया	37. सिनेमा टीवी इंडिया	54. टेस्ट 318	71. टेस्ट–417	88.संस्कार	
4. डीडी किसान	21. डीडी घोथिगई	38. डीडी देहरादून	55. बिग मैज़िक	72. टेस्ट–418	89. होम चैनल	
5. एबीजेडवाई धाकड़	22. डीडी पंजाबी	39. इंडिया फैशन टीवी	56. न्यूज़ 18 इंडिया	73. मनोरंजन मूवी	90. चार्दीकाला टाइम टीवी	
6. डीडी बांग्ला	23. डीडी सहयाद्री	40. इंडिया फैशल टीवी	57. 9 एक्सएम	74. बी4यू कड़क	91.डीडी गोवा	
7. डीडी चांदना	24. डीडी थादगिरी	41. डीडी सप्तगिरी	58. महामूवी	75. साधना भक्ति	92. डीडी हिसार	
8. डीडी गिरनार	25. डीडी मलयालम	42. बीपयू भोजपुरी	59. जी हिन्दुस्तान	76. डीडी राजस्थान	93. डीडी शिमला	
9. डीडी कशीर	26. लोसभा	43. मनोरंजन टीवी	60. डीडी भारती	77. झिंगार	94. टेस्ट 605	
10. एवीजेडवाई मुवीज़	27. राज्य सभा	44. न्यूज़ नेशन	61. डीडी ऊर्दू	78. डीडी बिहार	95. आस्था भजन	
11. डीडी अरुणप्रभा	28. सूर्या समाचार	45. डीडी यूपी	62. मस्ती	79. डीडी रांची	96.आर्यन टीवी नेशनल	102. टेस्ट 613
12. बी -4यूमूवीज़	29. दंगल	46. दबंग	63. बी4यू म्यूज़िक	80. मनोरंजन ग्रांड	97. सत्संग	103. इंटर 10 बंगला

13. आजतक तेज़	30. भोजपुरी सिनेमा	47. डीडीएमपी	64. न्यूज 18 यूपी/यूके	81. टी टीवी	97. $ टेस्ट 617	104. टेस्ट 615
14. इंडिया न्यूज़	31. शिलांग	48. सोनी मिक्स	65. न्यूज़ स्टेट यूपी/यूके	82. आस्था	98. अरिहंत	105. बीटीवी वर्ल्ड
15. न्यूज़ 18 राजस्थान	32. डीडी आइजोल	49. एनडी टीवी	66. न्यूज़ 24	83. ज़िग	99. शुभ टीवी	106. केबीएस वर्ल्ड
16. बिग मैजिक गंगा	33. डीडी अगरतला	50. डीडी रायपुर	67. रिपब्लिक भारत	84. $ टेस्ट 604 डीडी इंडिया	100. वैदिक टीवी	107. डीडी यूज एचडी
17. टेस्ट–117	34. डीडी उर्दू	51. इंटर 10	68. आजतक	85. स्टार स्पोर्टस फर्स्ट	101. एबीपी गंगा	108. डीडी नेशनल एच डी

न्यू मीडिया विंग

1945 से कार्यरत गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग का ही नया नाम न्यू मीडिया विंग है। **''न्यू मीडिया विंग''** एनएमडब्ल्यू सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के लिए सूचना सेवा इकाई के रूप में कार्य करता है। यह मंत्रालय, इसकी मीडिया इकाइयों और जनसंचार में लगे अन्य लोगों के उपयोग के लिए पृष्ठभूमि, संदर्भ और शोध सामग्री उपलब्ध कराता है।

यह विंग 2013 से विंग सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया प्रचार, सार्वजनिक सूचना और जन–संचार संबंधी गतिविधियों में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के न्यू मीडिया सेल को कार्यात्मक और परिचालन सहायता प्रदान करता है।

भारतीय सूचना सेवा (आईआईएस) अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए यह भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) को भी सहयोग करता है। 2018 बैच के आईआईएस ग्रुप 'ए' अधिकारियों के लिए एनएमडब्ल्यू ने एक दिवसीय प्रशिक्षण सत्र का भी आयोजन किया था।

एनएमडब्ल्यू अनुसंधान, संदर्भ एवं प्रशिक्षण खंड के लिए सभी मौजूदा स्टाफ/अवसंरचना का उपयोग करता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के न्यू मीडिया सेल से संबद्ध अधिकारियों को भी न्यू मीडिया विंग का हिस्सा माना जाता है।

संगठनात्मक ढांचा

न्यू मीडिया विंग (एनएमडब्ल्यू) का मुख्यालय सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में है। इसका प्रमुख महानिदेशक है जिसकी सहायता के लिए एक निदेशक, एक उप निदेशक, सहायक निदेशक और सहायक कर्मचारी होते हैं। अतिरिक्त महानिदेशक, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर, (ईएमएमसी) के पास न्यू मीडिया विंग का अतिरिक्त प्रभार है।

अप्रैल 2019 से न्यू मीडिया विंग की गतिविधियां

1. सोशल मीडिया

1.1 परिचय

हाल के दिनों में सोशल मीडिया बड़े पैमाने पर लोगों के बीच विविधतापूर्ण बातचीत का एक प्रभावी साधन बन गया है। इसकी संवादात्मक प्रकृति के कारण, जानकारी प्रदान करने और उनसे प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से सरकार और नागरिकों के बीच कुशलता पूर्वक संबंध स्थापित किया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का न्यू मीडिया विंग वर्चुअल दुनिया में बड़े पैमाने पर सरकार और जनता के बीच एक माध्यम के रूप में कार्य करके अंतःक्रियाओं को संभव बना रहा है।

मंत्रालय के सोशल मीडिया हैंडल से संबंधित आंकड़े नीचे दी गई तालिका में संक्षेप में प्रस्तुत किए गए हैं।

हैंडल	प्लेटफॉर्म	सब्क्राइबर/फालोअर
@एमआईबी इंडिया	ट्विटर, इंग्लिश हैंडल	1.1 मिलियन
@एमआईबी हिंदी	ट्विटर, हिंदी हैंडल	32.1 हजार
@सूचना और प्रसारण मंत्रालय	फेसबुक	1.3 मिलियन
@एमआईबी इंडिया	इंस्टाग्राम	92.7 हजार
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	यू ट्यूब	121 हजार
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	ब्लॉग	पेज न्यूज़– 4.2 मिलियन फोलोअर– 778

मंत्रालय का ट्विटर हैंडल @एमआईबी इंडिया हर महीने औसतन 2 मिलियन इंप्रेशन तैयार करता है और यू ट्यूब चैनलों को प्रतिमाह 500 हजार व्यू मिलते हैं। मंत्रालय के फेसबुक पेज पर सामग्री हर महीने औसतन 389 हजार से अधिक उपयोगकर्ताओं तक पहुंचती है।

1.2 सोशल मीडिया सहभागिता

दो अलग–अलग स्वरूपों में सोशल मीडिया सहभागिता टाकाथॉन और #फेसटूफेस/फेसबुक लाइव ने आम जनता के साथ मंत्रियों और निर्णय लेने वालों के बीच सीधे संवाद के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया है।

आईएफएफआई सचिवालय में 22 से 27 नवंबर, 2019 तक न्यू मीडिया विंग ने सात फेसटूफेस पारस्परिक संवाद कार्यक्रम संपन्न किए। इनमें से प्रत्येक सत्र की अवधि करीब 20 मिनट की थी। सत्र के दौरान पैनल सदस्यों ने ट्विटर, फेसबुक एवं इंस्टाग्राम से प्राप्त जनता के प्रश्नों का उत्तर देते हुए विभिन्न मुद्दों पर अपनी चिंताएं एवं विचार साझा किए।

समूचे फेसटूफेस सत्रों से ट्विटर पर 86 हजार इम्प्रेशंस, फेसबुक पर 72 हजार रीच, यूट्यूब पर 17 हजार व्यूज़ और इंस्टाग्राम पर 67 हजार व्यूज सामने आए।

1.3 कार्यक्रमों और आयोजनों की कवरेज

न्यू मीडिया विंग भारत सरकार के कई आयोजनों और कार्यक्रमों के प्रचार और सूचना प्रसार के लिए मंत्रालय के सोशल मीडिया एकाउंट का लाभ उठाने में सक्षम रहा है।

न्यू मीडिया विंग ने सरकार के विभिन्न सोशल मीडिया अभियानों जैसे स्वच्छ भारत मिशन, पोषण अभियान का समर्थन किया है। इन्हें इन प्लेटफार्मों पर लोकप्रिय बनाने के लिए इन अभियानों के अवसरों पर सोशल मीडिया सामग्री तैयार कीजाती है। इस तरह की सभी गतिविधियों को एक अन्य विभागों के साथ भी समन्वित किया गया ताकि इनका प्रभाव ज्यादा हो।

66वां फिल्म पुरस्कार और महात्मा गांधी मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का बॉक ने सोशल मीडिया पर पूरे देश में प्रचार किया। इसी तरह उसने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की प्रचार गतिविधियों को विस्तार दिया।

न्यू मीडिया विंग ने 2019 के भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह को कवर किया। यह भव्य आयोजन गोवा के पणजी में 20 नवंबर से 28 नवंबर, 2019 तक आयोजित किया गया। आईएफएफआई 2019 के उद्घाटन के अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस और भाषण को एमआईबी के यूट्यूब चैनल पर भी साझा किया गया। आईएफएफआई की स्वर्ण जयंती के दृश्य–श्रव्य गान और स्वर्ण जयंती उपलक्ष्य में रेडियो जिंगल भी रिलीज किया गया। इन सभी आयोजनों को समस्त सोशल मीडिया मंचों पर भी साझा किया गया। आईएफएफआई के दौरान 30 से अधिक मास्टर क्लासेज एवं वार्तालाप सत्रों को यूट्यूब, फेसबुक एवं एमआईबी के ट्विटर हैंडल पर प्रसारित किया गया। सोशल मीडिया पर 19 गणमान्य अतिथियों की बातचीत भी प्रसारित की गई जिनमें आईएफएफआई 2019 के ज्यूरी अध्यक्ष श्री जॉन बेली, ज्यूरी सदस्य श्री रमेश सिप्पी, श्रीमती कैरल लिटिलटन, श्री इम्तियाज अली एवं अन्य शामिल थे।

महात्मा गांधी के 150वीं जन्म शताब्दी और स्वच्छ भारत अभियान के अवसर पर एनएमडब्ल्यू ने व्यापक सोशल मीडिया कवरेज किया है।

एनएमडब्ल्यू ने गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और मन की बात को लगातार कवर किया और सोशल मीडिया में प्रचार की नीति और सरकार पर कार्यक्रमों को प्रचारित किया इसके साथ ही मंत्रीमंडल की ब्रीफिंग और पत्रकार सम्मेलन तथा प्रेस विज्ञप्ति को सोशल मीडिया में प्रचारित किया।

2. भारत– वार्षिक संदर्भ ग्रंथ

प्रकाशन विभाग, हर साल केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन और सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्त निकायों द्वारा किए गए विकास और प्रगति पर संदर्भ पुस्तक, 'भारत– वार्षिक संदर्भ ग्रंथ का संकलन करता है। यह भारत के मंत्रालयों, विभागों और राज्यों से प्राप्त जानकारी के आधार पर देश के विभिन्न पहलुओं, इसकी राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति के बारे में जानकारी का मूल्यवान स्रोत है। यह हिंदी में **भारत** और अंग्रेजी में **इंडिया** शीर्षक से एक साथ प्रकाशित होता है। **भारत 2019** और **इंडिया 2019,** वार्षिक संदर्भ ग्रंथ का 7 मार्च, 2019 को केंद्रीय सूचना एवं

प्रसारण मंत्री ने अवलोकन किया। **वर्ष 2020 के संदर्भ ग्रंथ के संकलन का काम अपने अंतिम चरण में है।**

3. प्रशिक्षण

न्यू मीडिया विंग ने भारतीय सूचना सेवा अधिकारियों के लिए एक दिवसीय सोशल मीडिया प्रशिक्षण मॉड्यूल का आयोजन किया। प्रशिक्षण का नेतृत्व फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और ब्रांडवाच के विशेषज्ञों ने किया।

4. राजभाषा कार्यान्वयन के तहत राजभाषा हिंदी का प्रगतिशील उपयोग

न्यू मीडिया विंग में, सरकारी कार्यों में हिंदी के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जाता है। विंग में हिंदी समिति की त्रैमासिक बैठकें अतिरिक्त महानिदेशक की अध्यक्षता में आयोजित की जाती हैं। 'हिंदी कर्मशाला' कर्मचारियों के लाभ के लिए और आधिकारिक कार्यों में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हर तिमाही आयोजित की जाती है। हिंदी 'पखवाड़ा' का आयोजन इस वर्ष 14 से 28 सितंबर तक किया गया था। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं।

5. सूचना का अधिकार

एक सीपीआईओ और एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है और आरटीआई अधिनियम के तहत तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के निर्देशों के अनुसार जानकारी प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को जानकारी प्रदान करने के लिए अपीलीय प्राधिकरण को नामित किया गया है।

1. सतर्कता गतिविधियां

5.1 संगठन के मुख्यालय एवं फील्ड कार्यालय में सतर्कता व्यवस्था से जुड़ा ब्यौरा

चूंकि एनएमडब्ल्यू एक अधीनस्थ कार्यालय है, इसलिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव संगठन के मुख्य सतर्कता अधिकारी होते हैं।

5.2 अवधि के दौरान सतर्कता गतिविधियां

2018–2019 की अवधि में नियमित एवं औचक निरीक्षण संचालित किए गए।

5.3 वर्ष के दौरान निगरानी एवं पहचान गतिविधियां

1) चुनिंदा निगरानी क्षेत्रों का ब्यौरा।

एनएमडब्ल्यू एक छोटा अधीनस्थ कार्यालय है और अपने अधिकार क्षेत्र के अनुसार इसका निगरानी क्षेत्र छोटा है।

2) निगरानी के अंतर्गत लाए गए व्यक्तियों की संख्या।

रिक्त – उपरोक्त III(1) के अनुसार।

2. सीएटी के निर्णयों/आदेशों के अमलीकरण संबंधित ब्योरा

क्र. सं.	मीडिया इकाइयां/ संभाग	2018–19 के लिए सीएटी द्वारा प्राप्त आदेशों की संख्या	2018–19 के दौरान अमल में लाए गए निर्णय/आदेशों की संख्या
1.	न्यू मीडिया विंग	शून्य	शून्य

6. दिव्यांगों के लिए आरक्षण

- "दिव्यांग (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995", दिव्यांगों के लिए समान अवसर और राष्ट्र निर्माण में उनकी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास है।
- न्यू मीडिया विंग ने पीडब्ल्यूडी का आरक्षण लागू करने और समय–समय पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों तथा सभी संबद्ध नीतिगत निर्णयों का पालन के लिए सभी आवश्यक उपाय किए हैं।

ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बेसिल)

1. बेसिल का संक्षिप्त इतिहास

ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बेसिल) आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 27001:2013, आईएसओ/आईसी 20000:2012 प्रमाणित, सार्वजनिक क्षेत्र का मिनी रत्न उद्यम है जो भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन है। इसकी स्थापना 24 मार्च, 1995 को

ध्वनिकी और ऑडियो–वीडियो सिस्टम सहित टेरस्ट्रियल एंड सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग, केबल और आईटी से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ क्षेत्रों में टर्नकी सोल्यूशन सहित प्रसारण और निर्माण प्रौद्योगिकियों में प्रसारण के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों की परामर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई थी।

बेसिल भारत और विदेशों में रेडियो और टेलीविजन प्रसारण इंजीनियरिंग, यथा–सामग्री निर्माण सुविधाओं, टेरेस्ट्रियल ब्रॉडकास्टिंग, ट्रांसमिशन और सैटेलाइट एंड केबल ब्रॉडकास्टिंग के संपूर्ण पहलुओं को शामिल करते हुए परियोजना परामर्शी सेवाएं और टर्नकी सोल्यूशन प्रदान करता है। यह प्रसारण से संबंधित डिजाइन और निर्माण, मानव संसाधन से संबंधित प्रशिक्षण जैसी गतिविधियां, प्रशिक्षण, मानव संसाधन प्रदान करने जैसी सहायक सेवाएं भी प्रदान करता है। बेसिल रक्षा, पुलिस विभागों और विभिन्न अर्ध–सैन्य बलों को विशेष संचार, निगरानी, सुरक्षा और निगरानी प्रणाली की आपूर्ति भी करता है। बेसिल का मुख्यालय नई दिल्ली में, कॉरपोरेट कार्यालय नोएडा में और क्षेत्रीय कार्यालय बंगलुरु में है। बिजनेस पोर्टफोलियो में विविधता के कारण यह कई राज्यों में भौगोलिक विस्तार की संभावनाएं तलाश रहा है।

बेसिल ने पिछले वर्षों में, कोशिश करके अपने को तैयार किया है और इन–हाउस, बहुमुखी और समर्पित इंजीनियरों की एक टीम बनाई है और सार्वजनिक तथा निजी प्रसारण सहित प्रसारण उद्योग जिसमें प्रसारक, रक्षा और केबल उद्योग शामिल हैं, के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े पेशेवरों की बड़ी जमात को भी तैयार कर रहा है और उनकी प्रतिभा को निखार रहा है। साधन संपन्न तकनीकी पेशेवरों के इस नेटवर्क के माध्यम से, बेसिल ने उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी अखिल भारतीय उपस्थिति स्थापित की है।

बेसिल के पास बड़ी संख्या में विशेषज्ञ हैं और यह भारत के राष्ट्रीय प्रसारक आकाशवाणी (एआईआर) और दूरदर्शन (डीडी) की विशेषज्ञता को एकीकृत करता है, और देश–विदेश में लाखों टीवी घरों तक पहुंचने वाली एनालॉग और डिजिटल उपग्रह प्रसारण सेवाओं द्वारा लगभग एक बिलियन लोगों और दुनिया के सबसे बड़े टेरेस्ट्रियल टेलीविजन नेटवर्क की जरूरतें पूरी करने वाले सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क का निर्माण करता है। यह ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कंसल्टेंसी एजेंसी, सिस्टम इंटीग्रेटर के साथ–साथ टर्नकी सोल्यूशन प्रदाता के रूप में काम करता है।

बेसिल की ग्राहक सूची में सरकारी, अर्ध सरकारी, प्रवासी और निजी संगठन शामिल हैं। इसे कई कार्य सबसे पहले करने का श्रेय हासिल है जैसे भारत में पहला टेलीपोर्ट तथा बुंनियादी ढांचा स्थापित करना, बंगलुरु में 7 एफएम चैनलों के संयोजन से भारत में मल्टी–चैनल एफएम ट्रांसमिशन को सबसे पहले स्थापित करना और राष्ट्रपति सचिवालय तथा लोकसभा टीवी के लिए एचडीटीवी स्टूडियो सेट–अप को डिजाइन करना और स्थापित करना आदि।

2. परिकल्पना

भारत और विदेश में कुल परियोजना समाधान के लिए संबंधित अवसंरचना विकास और ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञ क्षेत्रों के लिए एक ब्रांड के रूप में मान्यता प्राप्त विश्व स्तरीय परामर्श संगठन बनना।

3. लक्ष्य

भारत और विदेशों में टेरेस्ट्रियल, केबल तथा उपग्रह प्रसारण के माध्यम से रेडियो और टेलीविजन प्रसारण के आधुनिकीकरण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना और उत्कृष्टता प्राप्त करना।

4. उद्देश्य

i. और अधिक संख्या में ग्राहकों को विशेषज्ञता और अनुकूलित समाधान प्रदान करके बाज़ार में वर्तमान हिस्सेदारी बढ़ाना।

ii. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को नीति, विनियामक और प्रसारण से संबंधित विभिन्न पत्रों के सूत्रीकरण में तकनीकी ज्ञान और परामर्श प्रदान करना।

iii. विदेशी बाज़ार में अवसरों का पता लगाना।

iv. उत्पाद विकास के लिए बाज़ार सर्वेक्षण करना।

v. टीवी चैनलों और दूरस्थ शिक्षा केंद्रों के लिए सैटेलाइट अपलिंक और डाउनलिंक सिस्टम स्थापित करना।

vi. प्रसारण केंद्रों के संचालन को स्थापित करने और बनाए

रखने के लिए।

vii. प्रसारण पेशेवर प्रशिक्षित करना और उपलब्ध कराना।

viii. विशेषज्ञ प्रसारण उपकरणों के डिजाइन, विकास और निर्माण के लिए।

5. परियोजनाओं की प्रमुख बातें–निष्पादित की गईं प्रमुख परियोजनाएं

- एफएम चरण– III प्रसारण।
- डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम।
- एचएफ/वीएचएफ सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम।
- निगरानी और अभिगम नियंत्रण प्रबंधन प्रणाली(एसएसीएमएस)।
- एक्सेस कंट्रोल एवं इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम का आपूर्ति, स्थापन, परीक्षण एवं प्रवर्तन।
- सुरक्षा एवं निगरानी तंत्र का आपूर्ति, स्थापन, परीक्षण एवं प्रवर्तन।
- आकाशवाणी (प्रसार भारती) के 18 स्थलों पर 16 पैनल एफएम एंटीना की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और परिचालन।
- मथुरा और मेरठ में आकाशवाणी टावर।
- विश्व–भारती के लिए स्टूडियो प्रसारण उपकरण तथा अवसंरचना कार्यों का आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण एवं प्रवर्तन।
- कोलकाता के गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई) के लिए सीसीटीवी सिस्टम की आपूर्ति।
- पूर्वी रेलवे के लिए एकीकृत सुरक्षा सिस्टम का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, प्रवर्तन एवं रखरखाव।
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए प्रिंट (समाचार–पत्र/पत्रिकाएं), टेलीविजन और डिजिटल मीडिया (सोशल मीडिया सहित) के लिए एक निगरानी और विश्लेषण मंच की स्थापना।
- भारत के निर्वाचन आयोग के लिए सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब और रणनीति, शक्ति, दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली।
- सूचना और जनसंपर्क विभाग, लखनऊ के लिए सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब की स्थापना और कामकाज, संचालन तथा रखरखाव से संबंधित सेवाएं प्रदान करना।
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रसारण विंग के स्वचालन के लिए वेब–पोर्टल का डिजाइन, विकास और रखरखाव।
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग निदेशालय के इन्वेंटरी प्रबंधन और अन्य व्यावसायिक प्रक्रियाओं का कंप्यूटरीकरण।
- नई दिल्ली में सूचना भवन की 10वीं मंजिल पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर (ईएमएमएस) में स्थापित विभिन्न मदों, उपकरणों, सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और परिचालन।
- म्यांमा के मंडल स्थित म्यांमा इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, प्रवर्तन एवं कक्षाओं को ऑनसाइट सहायक उपकरण उपलब्ध कराए गए।
- अखिल भारतीय स्तर पर सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के 254 गोदामों में सीसीटीवी सर्वेलेंस सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, प्रवर्तन एवं रखरखाव।
- पूर्वी कमान के अंतर्गत विभिन्न सैन्य स्टेशनों के लिए सीसीटीवी सॉल्यूशंस की प्राप्ति एवं स्थापना।
- टीआरएआई नियामकों के अनुसार ऑडिट।
- माननीय टीडीएसएटी के निर्देशों के अनुसार ऑडिट।
- मिशन डिजिटलीकरण परियोजना।
- खुली नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से प्रसार भारती के लिए मानव संसाधन परीक्षण के लिए एक एजेंसी के चयन हेतु पेशेवर सेवाएं।
- दूरदर्शन समाचार चैनल (चैनलों) को रूचिकर बनाने तथा इनके प्रति दर्शकों का आकर्षण बढ़ाने और रचनात्मक

सामग्री, तकनीकी बुनियादी ढांचे और मानव संसाधन प्रदान करने के लिए पेशेवर ग्राफिक्स एजेंसी हेतु पेशेवर सेवाएं।

- बीओसी के लिए जिला स्तरीय जमीनी सक्रियता और आउटरीच कार्यक्रम
- पांडिचेरी के जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन के लिए एचडीटीवी स्टूडियो, इंटरनेट रेडियो, सीआरएस एवं डिजिटल साइनेज सॉल्यूशन की स्थापना।
- भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) दक्षिण एवं पश्चिम क्षेत्र के गोदामों/डिपो के लिए सीसीटीवी सर्वेलेंस सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, प्रवर्तन एवं रखरखाव।
- मैनपावर प्लेसमेंट सर्विसेज के लिए परियोजना।

6. बेसिल – प्रबंधन और संगठन

बेसिल के निदेशक मंडल में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, एक पूर्णकालिक निदेशक (संचालन और विपणन), भारत सरकार द्वारा नामित दो निदेशक और एक अंशकालिक गैर–आधिकारिक निदेशक शामिल हैं। बोर्ड स्तर से नीचे महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक, प्रबंधक, उप प्रबंधक, सहायक प्रबंधक और कनिष्ठ प्रबंधक हैं। परियोजना का काम आगे चलकर कंपनी द्वारा अनुबंध के आधार पर नियुक्त किए गए कंसल्टेंट्स और प्रोजेक्ट मैनेजरों को सौंपा गया।

बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होते हैं :

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक	श्री जॉर्ज कुरुविला
पूर्णकालिक निदेशक (ओ एंड एम)	श्री दीपक रंजन गोगोई
सरकार के नामित निदेशक	सुश्री अंजू निगम और श्री विनोद कुमार
अंशकालिक गैर–आधिकारिक निदेशक	सुश्री रंजना उपाध्याय

7. व्यावसायिक गतिविधियां

- एफएम प्रसारण
- टीवी चैनलों की स्थापना
- टेलीपोर्ट की स्थापना
- डिजिटल न्यूज़ रूम सिस्टम का डिजाइन
- डीटीएच (डायरेक्ट टू होम) सिस्टम
- भारतीय मानकों से वायर–लाइन ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क की अनुरूपता
- उपग्रह के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा प्रणाली
- ध्वनिकी, स्टेज प्रकाश, ध्वनि सुदृढ़ीकरण प्रणाली
- वायर–लाइन नेटवर्किंग में प्रशिक्षण/कौशल विकास
- ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करना

8. कार्यक्षेत्र

- रेडियो और टीवी प्रसारण
- टी. वी. वितरण प्लेटफार्म– टेरेस्ट्रियल, सैटेलाइट, डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) प्रणाली, केबल हेड–एंड सिस्टम
- उपग्रह टीवी चैनलों की निगरानी, लॉगिंग और पुरालेखण
- सामुदायिक रेडियो स्टेशन
- इलेक्ट्रॉनिक्स निगरानी और निगरानी प्रणाली
- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को तकनीकी इनपुट
- एड्रेसेबल केबल सिस्टम का तकनीकी परीक्षण और प्रमाणन
- सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेटअप
- निगरानी और अभिगम नियंत्रण प्रबंधन प्रणाली
- ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करना
- मानव संसाधन आउटसोर्सिंग

9. वित्तीय विशिष्टताएं

वित्त वर्ष 2018–19 के तुलनात्मक आंकड़ों के साथ वित्त वर्ष 2017–18 के लिए कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन इस प्रकार है :

	विवरण	वित्त वर्ष 2018-19	वित्त वर्ष 2017-18
क	संचालन का नतीजा		
	संचालन से आय	32046.24	23934.54
	अन्य आय	509.23	266.34
	वर्ष के दौरान कुल कारोबार	**32555.47**	**24200.88**
	व्यय	31372.02	24169.35
	ऑपरेटिंग लाभ/(हानि)	1183.45	31.53
	वित्त लागत	767.30	408.43
	मूल्य ह्रास और ऋण परिशोधन	199.60	201.19
	संदिग्ध प्राप्तियों और अग्रिम के लिए अनुमति	-	-
	पूर्व अवधि समायोजन और असाधारण मदें	(17.46)	(8.60)
	व्यय से पहले लाभ/(हानि) कर	**199.09**	**(586.69)**
	विलंबित कर	194.50	(158.91)
	व्यय से पहले प्रति शेयर	**4.60**	**(427.78)**
	Transfer to Corporate Social Responsibility	9,192	-
	Earnings/(Loss) Per Share (Rs.)	3	(313)
ख	**धन के स्त्रोत**		
	जारी की गई, सब्सक्राइब की गई चुकता पूंजी संचय और अधिशेष	136.50	136.50
	संचय और अधिशेष	1107.25	1104.31
	गैर – चालू उत्तरदायित्व	2674.90	699.97
	चालू उत्तरदायित्व	35916.45	30330.34
	कुल	**39835.10**	**32271.12**
	निधियों का इस्तेमाल		
	अचल संपत्तियां	1184.69	1297.99
	चालू संपत्ति	37815.40	30069.29
	विलंबित कर संपत्तियां (शुद्व)	672.43	866.93
	दीर्घावधि ऋण और अग्रिम	-	-
	अन्य गैर चालू संपत्तियां	162.58	36.91
	कुल	**39835.10**	**32271.12**
ग	**अन्य जानकारी**		
	अधिकृत पूंजी	**250.00**	**250.00**
	लगाई गई पूंजी	1243.75	1240.81
	शुद्ध शेयर कैपिटल संपत्ति	571.32	373.88

शेयर पूंजी

बेसिल को 250 लाख रुपये की अधिकृत पूंजी के साथ निगमित किया गया था। वर्ष 1995–96 में चुकता इक्विटी 25 लाख रुपये से बढ़कर 136.5 लाख रुपये हो गई। वर्तमान में भारत की केंद्र सरकार के पास 100 प्रतिशत इक्विटी शेयर पूंजी है। बेसिल को सरकार से कोई बजटीय सहायता नहीं मिलती है।

उपलब्धियां

- गत वर्ष की अपेक्षा कार्य आधारित (बैंक डिपॉजिट सहित) राजस्व रुपये 239.35 करोड़ से बढ़कर रुपये 320.46 करोड़ तक पहुंचा।
- गत वर्ष के अपेक्षा हानि रुपये 5.86 करोड़ की अपेक्षा लाभ रुपये 1.99 करोड़ तक पहुंचा।
- गत वर्ष की अपेक्षा कुल हानि रुपये 4.27 करोड़ की अपेक्षा कुल लाभ रुपये 4.60 करोड़ पहुंचा।
- समावेशन के बाद से सर्वाधिक टर्नओवर।
- मैनपावर सेवाओं में सर्वाधिक टर्नओवर।

10. वर्ष के दौरान प्रबंधात्मक पहल और व्यावसायिक गतिविधियां

वर्ष 2018–19 के दौरान, बेसिल ने निम्नलिखित प्रमुख परियोजनाओं को अंजाम दिया है :

एफएम चरण–III रेडियो चैनल के बैच–1 और बैच–2 के लिए ई–नीलामी के माध्यम से रोज़गार पैदा करते हैं।

सीटीआई पूर्णता स्थिति एफएम चरण–III(बैच–1 और 2) :

सीटीआई पूर्णता स्थिति एफएम चरण–III (बैच–1 एवं 2)

एचएफ, वीएचएफ सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम

बेसिल स्थापित उच्च आवृत्ति विद्युत चुंबकीय सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम के लिए पूर्ण संचालन और रखरखाव सहायता प्रदान करता है।

निगरानी अभिगम नियंत्रण प्रबंधन प्रणाली (एसएसीएमएस)

यह परियोजना भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना है। यह परियोजना सभी मौजूदा सुविधाओं के इंटरफेस से जुड़े होने सहित संपूर्ण सेना भवन, साउथ ब्लॉक और इसके आस–पास के क्षेत्र की दूर से निगरानी, एकीकृत नियंत्रण और केंद्रीय सुरक्षा प्रबंधन उपलब्ध कराने वाली संहिताओं और ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप पूरी तरह परिचालित निगरानी अभिगम नियंत्रण प्रबंधन प्रणाली के लिए डिजाइन, प्राप्ति, स्थापन, समेकन, परीक्षण, संचालन और संबद्ध सेवाओं के बारे में है। एसएसीएमएस सख्त नियमों का पालन करेगा और अत्याधुनिक सुरक्षा तकनीकों, विश्वसनीयता के उच्चतम स्तर को अपनाएगा और इंट्रानेट, इंटरनेट, एलएएन, डब्ल्यूएएन जैसी नेटवर्किंग अवसंरचनाओं को एकीकृत करेगा। एसएसीएमएस के भीतर सभी इंटरफेस कॉरपोरेट इंट्रानेट, इंटरनेट/लैन, वैन पर टीसीपी, आईपी नेटवर्क प्रोटोकॉल कनेक्टिविटी पर आधारित होंगे। बेसिल इन परियोजनाओं को जीवनकाल सहायता प्रदान करता है और सतत संचालन और रखरखाव के लिए अंतिम उपयोगकर्ता की मदद करता है।

एक्सेस कंट्रोल एवं इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण एवं प्रवर्तन

सर्वेलेंस एवं एक्सेस कंट्रोल क्षेत्र में जारी विविधीकरण के लिए बीईसीआईएल (बेसिल) ने इस वर्ष समझौते के आधार पर नए साझीदार को जोड़ा है। इस परियोजना में 21 मेट्रो स्टेशनों एवं नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन डिपो में एक्सेस कंट्रोल एंड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम की एसआईटीसी को शामिल किया गया है। परियोजना की कीमत रुपये 12.73 करोड़ रही। परियोजना सफलतापूर्वक पूरी हुई।

सुरक्षा एवं निगरानी तंत्र की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण एवं प्रवर्तन

बेसिल ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) के ट्रांसपोर्ट भवन में सीसीटीवी सर्वेलेंस एवं एक्सेस कंट्रोल की एसआईटीसी सफलतापूर्वक पूरी की है। एएमसी सहित परियोजना की लागत रुपये 8.47 करोड़ रही।

मंत्रिमंडल सचिव से व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध

मंत्रिमंडल सचिव ने बेसिल को 3 लॉग पीरियॉडिक एंटेना एवं 15 मल्टी–कूप्लर्स के व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध संबंधित आदेश पारित किया है। इस कार्य को पूरा किया जा रहा है।

एसआरएफटीआई के लिए टीवी स्टूडियो सेटअप

एसआरएफटीआई के लिए टीवी स्टूडियो की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण एवं प्रवर्तन

बेसिल की विशेषज्ञता एवं अनुभव को देखते हुए सत्यजित राय फिल्म एवं टेलीविजन इंस्टीट्यूट ने उसे टर्न–की आधार पर टीवी स्टूडियो सेटअप के एसआईटीसी देने का निर्णय किया है। इस अत्याधुनिक टीवी स्टूडियो में हाई डेफिनिशन कैमरा, प्रोडक्शन स्विचर, टेलिप्रॉम्प्टर, मीडिया एसेट मेनेजमेंट सिस्टम, प्लेआउट सर्वर्स, एनआरसीएस, ग्राफिक्स सिस्टम आदि होंगे। इसके आधार पर एसआरएफटीआई को टीवी कार्यों, विशेषकर न्यूज चैनल परिवेश में अपने विद्यार्थियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण देना संभव हो सकेगा।

कोलकाता के गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एवं इंजीनियर्स (जीआरएसई) के लिए सीसीटीवी सिस्टम आपूर्ति

इस जारी परियोजना में आईपी आधारित सीसीटीवी सिस्टम के डिजाइन, अभियांत्रिकी, आपूर्ति, परियोजना प्रबंधन सलाह सहित एकीकरण, परीक्षण, प्रवर्तन तथा रखरखाव शामिल है। यह आईपी आधारित सीसीटीवी तंत्र उपयुक्त अवसंरचना के आधार पर जीआरएसई की 5 इकाइयों से जीआरएसई मेन के केंद्रीकृत कंट्रोल स्टेशन (सीसीएस) के साथ जोड़ा जाएगा। सभी जीआरएसई इकाइयों को एमपीएलएस या लीज़्ड लाइन के माध्यम से जीआरएसई मेन से जोड़ा जाएगा। इसके जरिये सीआईएसएफ कमांडेंट एवं डिप्टी कमांडेंट के कार्यालयों से लाइव फीड दिखेगी एवं प्रमाण हेतु लाइव फीड की रिकॉर्डिंग का अधिकार भी होगा। इस प्रणाली के माध्यम से नवीन विधियों से सूचना प्रौद्योगिकी और सुरक्षा को जोड़ा जाएगा तथा स्थान एवं प्रणाली की स्थिति अनुरूप सुरक्षा उद्देश्य को भी यह तंत्र पूरा करेगा।

पूर्वी रेलवे की एकीकृत सुरक्षा का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, प्रवर्तन एवं रखरखाव

पूर्वी रेलवे के हावड़ा एवं अन्य स्थानों में सीसीटीवी सर्वेलेंस सिस्टम एवं पर्सनल बैगेज सिस्टम की डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, प्रवर्तन एवं रखरखाव का कार्य किया गया है।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) के लिए प्रिंट (समाचार पत्र/पत्रिकाएं), टेलीविजन एवं डिजिटल मीडिया (सोशल मीडिया सहित) निगरानी एवं विश्लेषण मंच की स्थापना

बीईसीआईएल (बेसिल) ने एमओआरटीएच की दृश्यता बढ़ाने के लिए सभी प्रमुख पक्षों को मजबूत किया है।

- नया फेसबुक पेज
- ट्विटर पेज संचालन
- यूट्यूब चैनल बनाया
- एमओआरटीएच गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक ब्लॉग साइट की शुरुआत
- इंस्टाग्राम पेज बनाया
- ज़ी पेज का आरंभ
- पीएमओ एवं प्रधानमंत्री ने एमओआरटीएच ट्विटर पेज फॉलो करना शुरू किया।

भारत के निर्वाचन आयोग के लिए सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब (एसएमसीएच) और नीति, शक्ति, दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली उपलब्ध कराता है।

- इस परियोजना में आवश्यक आईटी बुनियादी ढांचे के साथ सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की स्थापन गतिविधियां शामिल हैं।
- ईसीआई की आवश्यकता या इसके संबंधित नोडल अधिकारियों के सुझावों के अनुरूप, फेसबुक आदि जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने की क्षमता है।
- रचनात्मक डिजाइनिंग, सामग्री में नयापन तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामग्री प्रकाशित करने, सुनने, वेब क्रॉलिंग, मॉनिटरिंग सिस्टम, कंटेंट को इंगेज, प्रकाशित करने के लिए एंटरप्राइज लेवल टूल एसआरएम (सोशल रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर) प्रदान किया है, अनुक्रिया का विभाजन तथा पृथकरण,
- स्पेशल मीडिया पर रचनात्मक डिजाइन और पुर्नपैकेजिंग कर विषय को प्लेटफार्म पर प्रस्तुत किया।
- संवेदी विश्लेषण के साथ विश्लेषणात्मक रिपोर्टिंग,
- सोशल मीडिया ट्रैकिंग, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के साथ प्रतिक्रिया प्रबंधन, ब्रांडिंग और विज्ञापन सहायता,
- इंटरनेट और सोशल मीडिया का विषय को बढ़ावा देना
- वायरल होने का विषय अपलोड किया गया।
- लोगो डिजाइनिंग तथाा संग्रह आदि का काम किया है।
- एसएमसीएच के प्रशिक्षित कर्मचारी व्यवस्था और संचालन कार्य करने के लिए हैं।

सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब (एसएमसीएच) की स्थापना और सूचना तथा जनसंपर्क विभाग, लखनऊ के लिए एसएमसीएच कामकाज, संचालन और रखरखाव से संबंधित सेवाएं प्रदान करना।

बेसिल ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना और जनसंपर्क विभाग के लिए सप्ताह के सातों दिन चौबीसों घंटे काम करने वाली, संचालन और रखरखाव से संबंधित सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब सेवाओं के लिए निगरानी और प्रतिक्रिया सेवाएं उपलब्ध कराईं। इसके कार्यक्षेत्र में शामिल है–

- सोशल मीडिया पर होने वाली विभिन्न गतिविधियों का विश्लेषण
- समस्याग्रस्त गतिविधियों का पृथक्करण
- पेड और निजी मीडिया डेटा सहित पूरे सोशल मीडिया के लिए क्रालिंग क्षमता
- ब्रोकर सब सिस्टम – प्रारंभिक चेतावनी
- सोशल मीडिया ट्रेंड्स निगरानी
- सोशल मीडिया के संकेतक सूचक निगरानी सरकार से संबोधित व्यापार की ट्रेकिंग सोशल प्रचार/घटना की निगरानी
- सुनने का उपकरण सोशल मीडिया की सूचक निगरानी
- कार्रवाही योग्य डाटा की सूची
- सोशल मीडिया ट्रैकिंग
- विशेषणात्मक रिपोर्ट बनाना

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रसारण विंग के ऑटोमेशन के लिए वेब–पोर्टल का डिजाइन, विकास और रखरखाव

निम्न प्रोजेक्ट्स

- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की प्रसारण शाखा की सहायता से प्रोजेक्ट विज़न को संग्रहालय में डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन करने के लिए आवेदकों की प्रक्रियाएं पूरी की गईं।
- वंछित कंपनियों/आवेदकों को वेब पोर्टल पर विभिन्न प्रकार के आवेदन एक आसान, कुशल और पारदर्शी तरीका से दे सकते हैं और आवेदन देने के बाद आवेदन की स्थिति जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- नियमित आवश्यक और प्रासंगिक सूचना उपलब्ध करवाना
- क्षमता की बढ़ोतरी और मॉनिटरिंग को अच्छा करना और बेहतर प्रशासनिक क्षमता के निर्णय लेना
- विभिन्न प्रकार के सूचना को पेपर पर लेना कम किया
- बेहतर और अग्रिम निर्णय समर्थन प्रणाली और उच्च स्तरीय समर्थित प्रणाली तथा संचालन की मापनीयता।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग के निदेशालय के इन्वेंटरी प्रबंधन और अन्य व्यावसायिक प्रक्रियाओं का कंप्यूटरीकरण।

प्रकाशन विभाग के निम्न मानदंडों सहित सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन :

1. ऑथर मैनेजमेंट सिस्टम (एएमएस)
2. इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम (आईएमएस)
3. सेल्स/ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम (ओएमएस)
4. फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (एफएमएस)
5. ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम (जीएमएस)

डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट सिस्टम (डीआरएमएस)

प्रकाशन विभाग के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के लिए विभिन्न मॉड्यूल तथा एसएमएस गेटवे, पेमेंट गेटवे के साथ वेबसाइट इंटरफेस के लिए विशेष रूप से एसएमएस गेटवे, के साथ–साथ मॉड्यूल के एकीकरण के लिए सेवाएं प्रदान कीं।

नई दिल्ली सूचना भवन की 10वीं मंजिल पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर (ईएमएमसी) में, लगाई गई प्रणाली के लिए विभिन्न मदों, उपकरणों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और परिचालन।

बेसिल ने ईएमएमसी को अतिरिक्त मशीनरी, उपकरण, अन्य तकनीकी सेटअप और कार्यालय स्थान के लिए प्रदान किए गए केंद्रीकृत निगरानी तंत्र की स्थापना के साथ 900 टीवी चैनलों की निगरानी के संवर्द्धन को अंजाम दिया है।

म्यांमा के मंडल स्थित म्यांमा इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्लासरूम उपकरणों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, प्रवर्तन एवं ऑनलाइस सपोर्ट।

बेसिल ने म्यांमा के मंडल स्थित म्यांमा इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्लासरूम उपकरणों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, प्रवर्तन एवं ऑनलाइन सपोर्ट कार्य संपन्न किया है।

अखिल भारतीय स्तर पर सेंट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन के 254 गोदामों को सीसीटीवी सर्वेलेंस सिस्टमों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, प्रवर्तन एवं रखरखाव।

बेसिल ने अखिल भारतीय स्तर पर सेंट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन के 254 गोदामों को सीसीटीवी सर्वेलेंस सिस्टमों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, प्रवर्तन एवं रखरखाव का कार्य संपन्न किया।

पूर्वी कमान के अंतर्गत विभिन्न सैन्य स्टेशनों के लिए सीसीटीवी सॉल्यूशंस की प्राप्ति एवं स्थापना

बेसिल ने पूर्वी कमान के अंतर्गत विभिन्न सैन्य स्टेशनों के लिए सीसीटीवी सॉल्यूशंस की प्राप्ति एवं स्थापना कार्य संपन्न किया।

नई दिल्ली के रायसीना रोड स्थित नेशनल मीडिया सेंटर में व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध (सीएएमसी) एवं ऑडियो–विजुअल कार्य एवं सीसीटीवी सिस्टम स्थापना

बेसिल ने नई दिल्ली के रायसीना रोड स्थित नेशनल मीडिया सेंटर में ऑनसाइट व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध (सीएएमसी) एवं ऑडियो–विजुअल कार्य एवं सीसीटीवी सिस्टम स्थापना कार्य संपन्न किया।

प्रसार भारती के मानव संसाधन के ऑडिट के लिए पेशेवर एजेंसी का चयन करने के लिए पेशेवर सेवाएं

प्रसार भारती के अनुरोध पर, बेसिल प्रसार भारती के मानव संसाधन के ऑडिट के लिए एक पेशेवर एजेंसी के चयन के लिए अपनी पेशेवर सेवाएं प्रदान कर रहा है।

इस संबंध में, संभावित बोलीदाताओं से विस्तृत तकनीकी–व्यावसायिक प्रस्तावों की मांग के लिए एक खुली निविदा जारी की गई थी और एजेंसी के चयन का यह कार्य जारी है।

प्रसार भारती ने अपने मैनपावर ऑडिट के लिए पेशेवर एजेंसी की पहचान एवं चुनाव करने के लिए बेसिल के साथ अनुबंध किया है।

ट्राई विनियमन के अनुरूप परीक्षण

ट्राई विनियमन की अनुसूची–I के अनुसार डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम (सीएएस, एसएमएस, एसटीबी) की जांच की गई है। ट्राई विनियमन की अनुसूची–I के अनुपालन के अनुसार जांच में डीएएस प्रणाली के लिए ग्राहक को सलाह देने के साथ–साथ परामर्श भी शामिल है। आवश्यकता के अनुसार सभी जांचें की गई हैं।

माननीय टीडीसैट के निर्देशों के अनुसार ऑडिट

बेसिल ने टीडीसैट के विशिष्ट निर्देशों के अनुसार ऑडिट किया है। ऑडिट कार्य का दायरा टीडीसैट के निर्देश के अनुसार मामले की स्थिति पर निर्भर करता है। यह वाणिज्यिक ऑडिट के साथ–साथ तकनीकी ऑडिट भी हो सकता है। टीडीसैट के सभी संदर्भों पर आवश्यकता के अनुसार काम किया गया।

केबल टीवी डिजिटलीकरण के चरण III और चरण IV के कार्यान्वयन के लिए मिशन डिजिटीकरण परियोजना

कार्य के दायरे में देशभर में 12 क्षेत्रीय इकाइयों की स्थापना, इन क्षेत्रीय इकाइयों में अनुबंध पर कर्मचारियों (पीडी, एपीडी, ओए और डीईओ) की भर्ती, बहुभाषी कॉल सेंटर की स्थापना, एसटीबी सीडिंग की निगरानी के लिए एमआईएस एप्लीकेशन का विकास, केबल टीवी डिजिटीकरण के सभी हितधारकों को अद्यतन और आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए वेबसाइट का विकास शामिल हैं। चरण–III और चरण–IV का कार्य प्रगति पर है। सभी गतिविधियों को अंजाम दिया गया है, हालांकि, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बाद में परियोजना की पूर्णता तिथि मार्च 2020 तक बढ़ा दी है और परियोजना जारी है।

प्रशिक्षण और अन्य गतिविधियां

1. बेसिल ने वायरलाइन ब्रॉडकास्टिंग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। बेसिल के पास देशभर में प्रो दृश्य–श्रव्य स्थापन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए इंफोकॉम इंटरनेशनल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

   बेसिल ने इसके अलावा, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के तहत आईएएससी की सेक्टर स्किल काउंसिल की संचालन परिषद का सदस्य होने के नाते, विभिन्न एनओएस (राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों) और पाठ्यक्रम के विकास में शामिल है।

2. सीएटीव सेक्टर में कौशल प्रशिक्षण के लिए मैसर्स एमसीबीएस, गांधी नगर के साथ समझौता ज्ञापन।

दूरदर्शन समाचार चैनल (चैनलों) को रूचिकर बनाने और इनके प्रति दर्शकों का "आकर्षण बढ़ाने और रचनात्मक सामग्री, तकनीकी बुनियादी ढांचा और मानव संसाधन प्रदान करने के लिए पेशेवर ग्राफिक्स एजेंसी के लिए पेशेवर सेवाएं और दूरदर्शन समाचार को दैनिक ग्राफिक्स प्रदान करना।"

दूरदर्शन समाचार के अनुरोध पर, चैनल (चैनलों) को रुचिकर बनाने और इनके प्रति दर्शकों का आकर्षण बढ़ाने और रचनात्मक सामग्री, तकनीकी बुनियादी ढांचा और मानव संसाधन प्रदान करने के लिए पेशेवर एजेंसी को शामिल करने के लिए पेशेवर सेवाएं और दूरदर्शन समाचार को दैनिक ग्राफिक्स प्रदान करना।

ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन (बीओसी) के लिए 380 जिलों में जिला स्तरीय आउटरीच कार्यक्रम

ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन (बीओसी) ने ग्रामीण जनता के लिए बीओसी की जिला स्तरीय आउटरीच कार्यक्रमों/जमीनी स्तर पर क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए बेसिल के साथ उसकी पेशेवर सेवाएं प्राप्त करने के लिए संपर्क किया है। कार्य को निश्चित समयावधि में संपन्न करने के लिए बीओसी का प्रशिक्षित पेशेवर एजेंसियों से संपर्क करना आवश्यक था। बेसिल ने अपने एवं तत्कालीन क्षेत्र प्रसार निदेशालय (अब बीओसी में सम्मिलित) के साथ, अपनी

प्रोडक्शन कंट्रोल रूम

संपूर्ण स्तरीय पेशेवराना सेवाएं देने के आधार पर अनुबंध किया।

केयू–बैंड (जीसैट–8) डीएसएनजी और मोबाइल वैन का शुरू से अंत तक पूर्ण सोल्यूशन किराये के आधार पर प्रारंभिक तीन महीनों के लिए एसएपीएनईटी के वास्ते एसएपीएनईटी, आंध्र प्रदेश, एनएलई एंड डीटीपी वर्क्स को उपलब्ध कराना

सैपनैट माना टीवी दो शैक्षिक टेलीविजन चैनल, माना टीवी1 (प्ले बैक चैनल) और माना टीवी 2 (लाइव चैनल) चला रहा है। इस चैनल की स्थापना भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान

संगठन (इसरो), अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार के सहयोग से 17 मेगाहर्ट्स–बैंड (एपी और टीएस) में उपग्रह संचार के माध्यम से शैक्षिक और मानव विकास सामग्री का प्रसारण करने के लिए की गई।

बेसिल को यह कार्य शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि विस्तार, महिला विकास, ई–गवर्नेंस, ग्रामीण विकास, स्वयं–सहायता समूहों में जागरुकता पैदा करने, मानव संसाधन विकास, दूरस्थ प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, डिजिटल इंडिया के क्षेत्रों में सामाजिक क्षेत्र के लाइव कार्यक्रमों को कवर करने के लिए आवश्यक मानवसंसाधन के साथ डीएसएनजी और ओबी वैन प्रदान करने के लिए निविदा के आधार पर मिला।

पांडिचेरी स्थित जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन के लिए एचडीटीवी स्टूडियो, इंटरनेट रेडियो, सीआरएस एवं डिजिटल साइनेज सॉल्यूशन

जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (जेआईपीएमईआर) ने अपने परिसर में शैक्षिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कंटेंट के सजीव रिकॉर्डिंग एवं पोस्ट प्रोडक्शन के लिए एचडीटीवी स्टूडियो एवं इंटरनेट रेडियो स्टूडियो सुविधा की स्थापना की है। साथ ही जेआईपीएमईआर ने पंजीकरण डेस्क पर आगंतुकों की सुविधा हेतु अभिवादन, दिशानिर्देश एवं ब्रांडिंग के लिए एक विशिष्ट डिजिटल हस्ताक्षर सुविधा भी स्थापित की है। एलिवेटरों में डिजिटल हस्ताक्षर आगंतुकों को विभिन्न विभागों के साथ स्वास्थ्य के बारे भी उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराता है। बिना जटिल आईटी अवसंरचना एवं कर्मियों के, बदलती जरूरतों के अनुसार कंटेंट भी जल्दी एवं प्रतिदिन संशोधित होता रहता है।

मानव संसाधन प्लेसमेंट सेवाओं के लिए परियोजना

बेसिल ने पिछले कुछ वर्षों में आउटसोर्सिंग का एक नया कार्यक्षेत्र शुरू करके युवाओं के लिए रोज़गार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बेसिल निर्धारित भर्ती प्रक्रियाओं का पालन करके समूचे भारत में विभिन्न सरकारी संगठनों को तकनीकी और गैर–तकनीकी मानव संसाधन प्रदान कर रहा है।

बेसिल मानव संसाधन, वित्त, विपणन आदि के क्षेत्र में तकनीशियन, इंजीनियर, तकनीकी सहायक, प्रोग्रामर, सलाहकार, परामर्शदाता, डाटा एंट्री ऑपरेटर, एमटीएस, चपरासी, संदेशवाहक, अकुशल, अर्ध–कुशल और कुशल मानव संसाधन आदि विभिन्न सरकारी कार्यालयों में उनकी आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध करा रहा है और संभावित उम्मीदवारों का एक डेटाबेस रखता है। बेसिल उल्लेखित सरकारी संगठनों को मानवसंसाधन प्रदान कर रहा है :

1) प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ)
2) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए)
3) भारत का निर्वाचन आयोग (ईसीआई)
4) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई)
5) लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एलपीएआई)
6) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
7) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी)
8) 2008 से दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय (डीटीयू)
9) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी)
10) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
11) ग्रामीण विकास मंत्रालय
12) फरवरी 2015 से संस्कृति मंत्रालय, मीडिया सेल।
13) आकाशवाणी (एआईआर)
14) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), झज्जर, गाजियाबाद, रायपुर, नई दिल्ली
15) पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) – अक्टूबर, 2014 के बाद से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) के तहत देशभर के अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ दिल्ली में मुख्यालय।
16) फरवरी 2015 से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन भारत के समाचार पंजीयक (आरएनआई), आर.के. पुरम, दिल्ली और भोपाल कार्यालय।
17) 2010 से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर (ईएमएमसी)।
18) राज्यसभा टीवी चैनल।
19) दिसंबर 2013 से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू)।
20) मई 2011 से राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान

(एनआईओएस)।

21) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए)

22) जून 2013 से राष्ट्रपति भवन

23) एसआरएसएसी, सैटकॉम, जयपुर

24) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू)

25) सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग स्कूल (सीडीटीआई) जयपुर

26) आयकर महानिदेशालय (सतर्कता)

11. भविष्य की व्यावसायिक गतिविधि

कंपनी का प्रबंधन वित्त वर्ष 2019–20 में परिचालन लाभ बढ़ाने का इरादा रखता है और इसके लिए निम्न गतिविधियां चलाता है :

- कंसल्टेंसी कारोबार बढ़ाना
- विदेशी निविदाओं में भागीदारी
- उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम उपयोग
- वार्षिक रखरखाव अनुबंध में वृद्धि
- नए क्षेत्रों में दोबारा आर्डर प्राप्त करना
- बेसिल ने ईएससीओ मॉडल के आधार पर एलईडी लाइटों की रेट्रोफिटिंग का नया कार्य आरंभ किया है। इसके लिए बेसिल ने उत्तर प्रदेश की तीन नगर पालिकाओं के साथ तीन अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। यह नगर पालिकाएं हैं – नगर पालिका परिषद उन्नाव, नगर पालिका परिषद कासगंज एवं नगर पंचायत सिद्धपुरा, कासगंज। अगले 7 वर्षों में उपरोक्त परियोजनाओं से अनुमानित आय निम्न रहेगी :

(रुपये लाख में)

परियोजना का नाम (एलईडी परियोजना)	अनुबंधित अवधि का कुल राजस्व (7 वर्ष)	वार्षिक राजस्व	मासिक राजस्व	एलईडी स्ट्रीट लाइट्स
उन्नाव, उत्तर प्रदेश	2583.00	369.00	30.81	8700
कासगंज, उत्तर प्रदेश	2100.00	300.00	25.00	5600
सिद्धपुरा, उत्तर प्रदेश	504.00	72.00	6.00	2000
कुल	**5187.00**	**741.00**	**61.81**	**16300**

- बेसिल ने मैनपावर की आउटसोर्सिंग के लिए नई शुरुआत की है। बेसिल ने मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को '33/11 सबस्टेशनों एलटी/एचटी वितरण लाइनों के क्रियान्वयन/रखरखाव के लिए स्किल्ड एवं अनस्किल्ड मैनपावर' उपलब्ध कराने हेतु जारी निविदा में भाग लिया और उसे सफलतापूर्वक प्राप्त किया। अगले दो वर्षों के लिए परियोजनाओं की कुल लागत रुपये 205 करोड़ होगी। परियोजनाओं पर 2019–20 वित्तीय वर्ष में काम शुरू हो गया।

नए क्षेत्रों में विविधता

12. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन

वित्त वर्ष 2019–20 के लिए बेसिल में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक के लिए संबंधित उम्मीदवारों की नियुक्ति

कंपनी आरक्षण नीतियों पर सरकार के दिशानिर्देश/निर्देशों का पालन करती है। तदनुसार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में आरक्षण के मामलों पर सरकार के दिशानिर्देशों/निर्देशों और कंपनी में भर्तियां और पदोन्नति करते समय अल्पसंख्यकों की नियुक्ति के लिए ध्यान रखा गया है।

13. सूचना का अधिकार

पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए, किसी भी स्रोत से प्राप्त प्रश्नों का उत्तर देने के लिए समय पर उचित कार्रवाई की जाती है। सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुपालन में, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों को नियुक्त किया गया है और सूचनाओं को समयबद्ध रूप से देने के अनुपालन और प्रसार के लिए अत्यंत सावधानी बरती जा रही है।

14. सतर्कता गतिविधियां

बेसिल में सतर्कता अनुभाग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सार्वजनिक उद्यम विभाग और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के निर्देश के अनुसार बेसिल में अनुपालन के लिए निवारक सतर्कता के सभी पहलुओं को मजबूत करने के उपायों के बारे में नियमित रूप से नियम और दिशानिर्देश जारी कर रहा है।

समय–समय पर केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय जांच ब्यूरो और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को नियमित रूप से विवरणियां भेजी जाती हैं और समुचित तरीके से तुरंत जांच की जाती है, समय–समय पर औचक निरीक्षण किए जाते हैं और निरंतर सतर्कता बरती जाती है।

17. सामान्य

बेसिल का बजट खुले बाज़ार में प्रतिस्पर्धी निविदा प्रणाली के माध्यम से विभिन्न प्राप्तियों से संबंधित प्राप्तियों और व्यय की अपनी आंतरिक व्यवस्था है। कंपनी को सरकार से कोई बजटीय सहायता नहीं मिलती है और अपने स्वयं के संसाधन उत्पन्न करता है।

कंपनी को, महिलाओं, उत्तर–पूर्व (सिक्किम सहित), रोज़गार सृजन, ग्रामीण घटक, आदिवासी उप योजना, विशेष घटक योजना, स्वयंसेवी क्षेत्र, सूचना और प्रचार, अल्पसंख्यक कल्याण आदि से संबंधित किसी भी केंद्रीय/केंद्र प्रायोजित योजना नहीं सौंपी गयी है।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर

टेलीविजन चैनल विभिन्न आयु वर्ग के लोगों, संस्कृतियों तथा पृष्ठभूमि के लिए एक विशाल पहुंच के साथ संचार क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। टेलीविजन चैनलों द्वारा उपभोक्ताओं को अवांछनीय सामग्री से बचाने के लिए, दुनिया में लगभग सभी प्रमुख लोकतंत्रों देशों में मानकों का पालन किया जाता है। केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1994 के तहत कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं के किसी भी उल्लंघन के लिए भारत में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर (ईएमएमसी) को टीवी चैनलों के लिए प्रसारित सामग्री की निगरानी का काम सौंपा गया है।

एमएमसी द्वारा देखे गए कार्यक्रम और विज्ञापन कोड का स्पष्ट उल्लंघन मासिक आधार पर एक संवीक्षा समिति के पास भेजा जाता है जिसमें महिला राष्ट्रीय आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, सीबीएफसी, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो आदि के सदस्य होते हैं। सुरक्षा समिति – कथित उलंघन का परीक्षण करते हैं और कार्रवाई के लिए अंतर–मंत्रालयों समिति और अन्य निकायों के लिए अपनी खोज को आगे बढ़ाते हैं।

भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा आयोजित चुनावों के दौरान, ईसीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों/निर्देशों के अंतर्गत ईएमएमसी ने कंटेंट निगरानी कार्य किया और उस संबंध में रिपोर्ट जमा कराई। वर्ष के दौरान, ईएमएमसी ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 2019 के आम चुनावों से संबंधित समाचारों एवं 2019 में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम, हरियाणा एवं महाराष्ट्र के विधान सभा चुनावों से संबंधित समाचारों पर नजर रखी। मतदान के दिन एवं उससे पूर्व दिवस पर सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों की सूचना भी एसएमएस अलर्ट के जरिए चुनाव आयोग को भेजी गईं।

2019–20 के दौरान ईएमएमसी ने अपने कार्यालय में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की। कार्यालय में योग दिवस समारोह, हिंदी पखवाड़ा, गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किए गए। 'स्वच्छता ही सेवा' के अवसर पर 2019 में भाषण एवं निबंध लेखन प्रतियोगिता तथा सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन हुआ।

सतर्कता गतिविधियां

(1) संस्थान के लिए मुख्यालय एवं फील्ड कार्यालयों में सतर्कता ढांचा। चूंकि ईएमएमसी अधीनस्थ कार्यालय है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव संस्थान के मुख्य सतर्कता अधिकारी होते हैं।

(2) अवधि के दौरान सुरक्षात्मक सुरक्षा गतिविधियां।

शून्य

(3) अवधि के दौरान निगरानी एवं पहचान गतिविधियां

(i) निगरानी क्षेत्रों के लिए चुने गए क्षेत्रों का ब्योरा।

शून्य

(ii) निगरानी के अंतर्गत रखे जाने वाले व्यक्तियों की संख्या।

शून्य

(4) दंडात्मक कार्रवाइयां (4(i) से 4(x) के समक्ष संख्या वर्णित होगी जिसमें नियुक्ति अधिकारी राष्ट्रपति से इतर हों)

i. अवधि के दौरान प्राप्त शिकायत/संदर्भ।

शून्य

ii. मामलों की संख्या जिनमें आरंभिक जांच की गई।

शून्य

iii. मामलों की संख्या जिनमें आरंभिक जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई।

शून्य

iv. मामलों की संख्या जिनमें बड़े जुर्माने से संबंधित चार्जशीट दायर की गई।

शून्य

v. मामलों की संख्या जिनमें छोटे जुर्माने से संबंधित चार्जशीट दायर की गई

शून्य

vi. व्यक्तियों की संख्या जिन पर बड़ा जुर्माना लगाया गया

शून्य

vii. व्यक्तियों की संख्या जिन पर छोटा जुर्माना लगाया गया।

शून्य

viii. निलंबित व्यक्तियों की संख्या

शून्य

ix. व्यक्तियों की संख्या जिनके खिलाफ चेतावनी देना आदि जैसी प्रशासनिक कार्रवाइयां की गई।

शून्य

x. व्यक्तियों की संख्या जो प्रासंगिक नियम प्रावधानों के अंतर्गत समयपूर्व सेवानिवत्त हुए।

शून्य

xi. 2018–19 के दौरान सीएटी से प्राप्त आदेशों की संख्य।

शून्य

20 नवंबर, 2019 को पणजी, गोवा में 50वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह के उद्घाटन के अवसर पर दर्शकों को संबोधित करते हुए इफ्फी के मुख्य अतिथि सुपरस्टार रजनी कांत, साथ में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, सूचना एवं प्रसारण तथा भारी उद्यम और लोक उपक्रम मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर, इफ्फी के मुख्य अतिथि सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, गोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्यमंत्री श्री बाबुल सुप्रियो

6 फ़िल्म क्षेत्र की गतिविधियां

फ़िल्म प्रभाग

गत 68 वर्षों से फिल्म प्रभाग भारतीय जनमानस को राष्ट्र निर्माण हेतु प्रेरित करता रहा है। फिल्म प्रभाग के लक्ष्य और उद्देश्य आमजन को राष्ट्रीय कार्यक्रमों के संबंध में शिक्षित एवं प्रेरित करना और भारतभूमि और उसकी धरोहर को भारतीय एवं विदेशी दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करना है। फिल्म प्रभाग सिनेमा थियेटरों में तथा क्षेत्रीय प्रसार निदेशालय, दूरदर्शन, शैक्षणिक संस्थानों, फिल्म सोसाइटियों एवं स्वायत्त संस्थाओं जैसे गैर–थियेट्रिकल क्षेत्रों में दिखाए जाने वाले वृत्तचित्रों, लघु एवं एनिमेशन फिल्मों का निर्माण करता है।

भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय (एनएमआईसी) की स्थापना भारत के समृद्ध सिने इतिहास और धरोहर को प्रदर्शित करने के लिए की गई। इसका लक्ष्य हमारे सामाजिक–सांस्कृतिक इतिहास और उसके उदय को सिनेमा के माध्यम से दर्शाना है। 19 जनवरी, 2019 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था।

भारत के माननीय उप–राष्ट्रपति एवं महाराष्ट्र के राज्यपाल 26 अप्रैल, 2019 को एनएमआईसी दौरे पर आए थे। दस देशों के कौन्सूल जनरल्स भी 25 अप्रैल, 2019 को संग्रहालय देखने गए थे। कैलिफॉर्निया की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस के अध्यक्ष श्री जॉन बेली भी 26 मई, 2019 को संग्रहालय देखने पहुंचे। 22 मई, 2019 को यहां लाइव संगीत के साथ मूक फिल्म 'कालिया मर्दन' का प्रदर्शन किया गया था।

इस वर्ष आयोजित कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां इस प्रकार रहीं :

1. विश्व पर्यावरण दिवस :

6 जून, 2019 को संग्रहालय परिसर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री एवं जानी–मानी फिल्मी हस्तियों ने संग्रहालय के सामने पौधे लगाए।

2. फिल्म प्रभाग द्वारा 10–11 अक्टूबर, 2019 को ऑनलाइन विषयवस्तु से संबद्ध फिल्म प्रमाणन एवं विनियमन हेतु दो दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया।

3. एनएमआईसी की गतिविधियां :

क. कैलिफॉर्निया की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 6 जून, 2019 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन और सूचना एवं प्रसारण मंत्री माननीय श्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा पौधारोपण

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर 10 अक्टूबर, 2019 को 'ऑनलाइन विषय–वस्तु से संबद्ध फिल्म प्रमाणन एवं विनियमन' पर संगोष्ठी को वीडियो संदेश से संबोधित करते हुए

एंड साइंस के अध्यक्ष श्री जॉन बेली, 26 मई, 2019 को संग्रहालय देखने पहुंचे।

ख. लाइव संगीत के साथ मूक फिल्म 'कालिया मर्दन' का प्रदर्शन 22 मई, 2019 को किया गया।

ग. 9 जुलाई, 2019 को एनएमआईसी के पाक्षिक न्यूज

कैलिफॉर्निया की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस के अध्यक्ष श्री जॉन बेली, 26 मई, 2019 को संग्रहालय देखने पहुंचे

बुलेटिन का शुभारंभ किया गया।

घ. नए संग्रहालय की इमारत के ऑडिटोरियम–द्वितीय में फिल्म प्रभाग की फिल्मों की प्रतिदिन की स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया।

लाइव ऑर्केस्ट्रा के साथ 22 मई, 2019 को 'कालिया मर्दन' का प्रदर्शन

ङ. भारतीय वृत्तचित्र निर्माता संघ के सहयोग से क्षितिज–पाक्षिक वृत्तचित्र प्रदर्शन का आयोजन किया गया।

च. ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम द्वारा आउटरीच की पहल।

छ. विद्यार्थियों, वरिष्ठ नागरिकों एवं अन्य के लिए विशेष संचालित पर्यटन का आयोजन।

ज. मुंबई दर्शन के लिए एनएमआईसी को शामिल करने के लिए एमटीडीसी के साथ एक समझौते पर कार्य अंतिम चरण में।

झ. राजस्व प्राप्ति के लिए एनएमआईसी के थियेटरों को सीबीएफसी प्रीव्यू स्क्रीनिंग्स, उत्सवों एवं ऐसे अन्य

आयोजनों के लिए किराए पर लेने का प्रावधान।

ट. 9 नवंबर, 2019 तक एनएमआईसी में 17093 दर्शक आ चुके हैं।

4. महात्मा गांधी का 150वीं जयंती स्मरणोत्सव :

महात्मा गांधी के 150वीं जयंती स्मरणोत्सव पर फिल्म प्रभाग ने निम्न आयोजन किए :

- एनएमआईसी में भारतीय सिनेमा में गांधी पर एक विशेष गैलरी, 'इमेजिंग गांधी' के अंतर्गत महात्मा गांधी के जीवन पर बनी अनेक फिल्मों का प्रदर्शन चरखे द्वारा संचालित विडियो स्पिनर द्वारा विशिष्ट घटनाओं का प्रदर्शन फिल्मों एवं सामाजिक उद्धार, फिल्में एवं स्वतंत्रता अभियान जैसे विषयों पर परस्पर संवादात्मक मल्टीमीडिया प्रदर्शन। गांधी सेल्फी कॉर्नर के साथ महात्मा गांधी द्वारा देखी गई एकमात्र फिल्म 'राम राज्य' का प्रदर्शन।
- राष्ट्रव्यापी स्तर पर 'वैष्णव जन तो...' नामक विशेष एनिमेशन फिल्म रिलीज।
- महात्मा गांधी के विचारों एवं जीवन पर 5 फिल्मों का निर्माण तथा निर्माणाधीन 17 अन्य फिल्में जल्दी ही पूरी की जाएंगी।
- मुंबई में फिल्म प्रभाग द्वारा 2 अक्टूबर, 2019 को स्वच्छता पर महात्मा गांधी का संदेश प्रसारित करने के लिए एक पदयात्रा का आयोजन किया गया। पदयात्रा फिल्म प्रभाग से अगस्त क्रांति मैदान तथा मणि भवन से आरंभिक स्थल तक की रही। कर्मचारियों एवं नागरिकों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए, फिल्म प्रभाग द्वारा 11 सितंबर से 2 अक्टूबर, 2019 तक राष्ट्रपिता एवं उनके संदेश को श्रद्धांजलि देते हुए स्वच्छता अभियान भी आयोजित किए गए।
- स्मृति उत्सव के दौरान फिल्म प्रभाग मुख्यालय एवं निर्माण केंद्रों तथा वितरण शाखाओं द्वारा विभिन्न स्थानीय गैर सरकारी संगठनों, फिल्म सोसाइटियों/क्लबों, शैक्षणिक संस्थानों, राज्य सरकारों/जिला प्रशासनों आदि के सहयोग से वृत्तचित्रों का फिल्मोत्सवों एवं विशेष प्रदर्शनों में आयोजन किया गया।

महात्मा गांधी पर बनी हुई निम्न फिल्मों को प्रदर्शन हेतु भेजा गया :

वैश्विक स्तर पर दूतावासों एवं उच्चायोगों में दिखाए जाने के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में 20–08–2019 को बापू (11 फिल्मों का पैकेज) का आयोजन।

15–10–2019 को दूरदर्शन केंद्र, राज्य सभा टीवी और लोक सभा टीवी को 'यू मस्ट बी द चेंज ....महात्मा गांधी' भेजी गई।

- देश भर में थियेटरों पर महात्मा गांधी पर निम्न पीएसए फिल्में रिलीज की गई :–
  - **28–06–2019 से 12–07–2019 तक गांधी जी और अहिंसा**
  - **16–07–2019 से 30–07–2019 तक गांधी जी की सोच**
  - **15–08–2019 से 30–08–2019 तक महात्मा और मार्टिन लूथर किंग**
  - **31–08–2019 से 14–09–2019 तक सत्यमेव जयते**
  - **01–10–2019 से 15–10–2019 तक साबरमती संत**
  - **16–11–2019 से यू मस्ट बी द चेंज ...महात्मा गांधी**
- फिल्म प्रभाग एमआईएफएफ' 2020 के सोलहवें संस्करण के दौरान मुंबई के जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट्स के साथ महात्मा गांधी पर निर्मित मूर्तिकला एवं कलाकृतियों की एक विशेष प्रदर्शनी के आयोजन पर कार्य कर रहा है। इस प्रदर्शनी की विशिष्टता महात्मा गांधी की 72वीं पुण्यतिथि पर 30 जनवरी, 2020 को स्कूल के छात्रों द्वारा मूर्तिकला निर्माण करना होगा।
- फिल्म प्रभाग स्कूलों एवं विश्वविद्यालयों में महात्मा गांधी पर निर्मित फिल्मों के प्रदर्शन को लेकर एक विशेष वितरण क्षेत्र/तंत्र विकसित करने हेतु विचार कर रहा है।
- मिफ्फ में गांधीजी पर एक विशेष सत्र प्रदर्शित किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
- एनएमआईसी में पहुंचने वाले प्रस्तावित आगंतुकों एवं मुंबई में एनएमआईसी को आकर्षण का विषय बनाने हेतु 2 से 6 अक्टूबर, 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर फिल्म प्रभाग मुख्यालय ने भारतीय पर्यटन के सहयोग

से एक सप्ताह लंबे फिल्म महोत्सव का आयोजन किया। इस महोत्सव के दौरान महात्मा गांधी पर बनी फीचर फिल्मों एवं वृत्तचित्रों का प्रदर्शन किया गया।

- देश भर के स्कूलों एवं शैक्षणिक संस्थानों में महात्मा गांधी पर 12 चुनिंदा वृत्तचित्रों को प्रदर्शन के लिए भारतीय पर्यटन के 18 क्षेत्रीय कार्यालयों को उपलब्ध कराया गया। सभी केंद्रीय एवं नवोदय विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए गांधी पैकेज की फिल्मों को विशेष प्रदर्शन हेतु उपलब्ध कराया जा रहा है।

5. वर्ष की प्रमुख झलकियां

26 अप्रैल, 2019 को माननीय उप–राष्ट्रपति ने एनएमआईसी का दौरा किया।

26 अप्रैल, 2019 को महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल ने एनएमआईसी का दौरा किया।

6. फिल्म प्रभाग के विभिन्न खंड

फिल्म प्रभाग को चार खंडों में बांटा गया है :

(1) निर्माण

माननीय उप–राष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू 26 अप्रैल, 2019 को भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय (एनएमआईसी) के दौरे पर

(2) प्रशासन

(3) वितरण

(4) वित्त

6.1 निर्माण प्रखंड :–

निर्माण प्रखंड, (वृत्तचित्र, ग्रामीण दर्शकों के लिए विशेष तौर पर तैयार शॉर्ट फीचर्स, एनिमेशन एवं वीडियो फिल्म्स) का मुख्यालय मुंबई में है और इसके बंगलुरु, कोलकाता एवं नई दिल्ली में तीन अन्य निर्माण केंद्र भी हैं।

2019–20 (31.10.2019) तक पूरी की गई फिल्मों का विवरण –

वर्गीकरण	5 मिनट तक	5 से 26 मिनट तक	26 से 52 मिनट तक	52 से अधिक	कुल
कृषि	-	2	-	-	2
कला एवं संस्कृति	4	2	3	1	10
जीवनी	-	1	2	1	4
स्वच्छता	3	-	-	-	3
शिक्षा	2	-	1	-	3
पर्यावरण	-	2	-	-	2
परिवार कल्याण	1	-	-	-	1
मत्स्य पालन	-	1	-	-	1
स्वतंत्रता संघर्ष	3	1	-	-	4
ऐतिहासिक	-	-	1	-	1
राष्ट्रीय एकता	1	-	-	-	1
दर्शनशास्त्र (गांधीवाद)	3	2	-	-	5

वर्गीकरण	5 मिनट तक	5 से 26 मिनट तक	26 से 52 मिनट तक	52 से अधिक	कुल
राजनीति विज्ञान	-	1	1	-	2
लोक प्रशासन	3	-	-	-	3
समाजशास्त्र	-	4	-	1	5
वन्य जीवन	-	1	-	1	2
				कुल	49

वर्तमान में 188 फिल्में निर्माणाधीन हैं जिनमें से 144 इन–हाउस, 35 बाहरी फिल्मकारों द्वारा तथा 9 फिल्में गैर–सरकारी संस्थानों द्वारा निर्मित की जा रही हैं।

स्मरणीय फिल्में

- महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर, **5** फिल्में पूरी हो चुकी हैं और 17 अन्य निर्माणाधीन हैं। इनके अलावा, **'क्वोट्स ऑफ महात्मा गांधी'** पर 12 पीएसए फिल्मों पर कार्य जारी है।
- **'स्वच्छता'** पर 3 एनिमेशन फिल्में निर्माणाधीन।
- **'जल संरक्षण'** पर 5 फिल्में पूरी होने के निकट।
- **'गुरु नानक देव जी'**, **'मास्टर तारा सिंह'** और **'एंटी पायरेसी'** पर बनने वाली फिल्मों की चुनाव प्रक्रिया पूर्ण।
- **'जलियांवाला बाग'**, **'पंढारी के रंग'** और **'देविका रानी'** पर फिल्में निर्माणाधीन।
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार **'प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड एब्यूज़'** फिल्म को व्यापक प्रसारण एवं प्रदर्शन किया जाएगा।
- एनिमेशन फिल्म **'वैष्णव जन तो...'** को दूरदर्शन प्रसारण एवं निर्माण केंद्रों तथा शाखाओं के लिए आवंटित किया गया।

6.2 वितरण प्रभाग :–

वितरण प्रभाग के बंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, तिरुअनंतपुरम एवं विजयवाड़ा में 6 शाखा कार्यालय हैं जो सिनेमा थियेटरों के लिए 'पारित फिल्में', जन सूचना अभियानों में सहभागिता, विदेश विभाग के विदेश प्रचार विभाग द्वारा पारित फिल्म प्रभाग की चुनिंदा फिल्मों को भारतीय उच्चायोगों में दिखाए जाने के लिए उनके प्रिंट्स/वीडियो एवं डीवीडी की बिक्री का कार्य करते हैं।

6.3 अंतरराष्ट्रीय वृत्तचित्र, लघु एवं एनिमेशन फिल्म समारोह :–

1990 से फिल्म प्रभाग द्विवर्षीय मुंबई इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटरी, शॉर्ट एंड एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल (एमआईएफएफ) का आयोजन करता आ रहा है। एमआईएफएफ फिल्मकारों, निर्माताओं, वितरकों, प्रदर्शनकर्ताओं एवं फिल्म समीक्षकों को आपसी समन्वय एवं विचार–विनिमय तथा फिल्म संस्कृति के व्यापक विस्तार हेतु अनोखा अवसर उपलब्ध कराता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एमआईएफएफ वृत्तचित्र, लघु एवं एनिमेशन के अग्रणी फिल्म समारोह के तौर पर अपनी पहचान स्थापित करा चुका है। समारोह के प्रत्येक संस्करण पर अनुमानतः 35 देशों की 800 प्रविष्टियां आती हैं। एमआईएफएफ का 16वां सत्र मुंबई के फिल्म्स डिविजन कॉम्प्लेक्स में 28 जनवरी से 3 फरवरी 2020 के दौरान आयोजित किया जाएगा।

वर्ष के दौरान फिल्म प्रभाग ने विभिन्न संस्थानों एवं संगठनों की सहभागिता से थ्रिसूर, कोट्टयम, आइजोल एवं रांची में 4 छोटे एमआईएफएफ आयोजित किए।

6.4 प्रशासनिक प्रभाग

प्रशासनिक प्रभाग में वित्त, कार्मिक, स्टोर्स, लेखा, निर्माण प्रबंधन एवं सामान्य प्रशासन आते हैं। 31.10.2019 तक फिल्म प्रभाग की कार्मिक शक्ति/कार्मिक अवस्थिति निम्न रही :–

क्रम संख्या	श्रेणी	अनुमोदित संख्या	मौजूदा स्टाफ	रिक्त स्थान
क	ख	ग	घ	ङ
1	ग्रुप 'ए'	31	15	16
2	ग्रुप 'बी'	192	160	32
3	ग्रुप 'सी'	386	293	93
	कुलः	**609**	**468**	**141**

6.5 शामिल/चुनी गई/पुरस्कृत फिल्में – 2019–20

फिल्म महोत्सवों में पहुंचने वाली फिल्में	8 फिल्म महोत्सवों में 62 फिल्में शामिल
चुनी गई फिल्में	6 फिल्म महोत्सवों में 17 फिल्मों का चुनाव
पुरस्कार	'जी. डी. नायडु – द एडिसन ऑफ इंडिया' फिल्म को एक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का एक राष्ट्रीय पुरस्कार।
फिल्म महोत्सवों में प्रदर्शित फिल्में	5 फिल्म महोत्सवों में 10 फिल्में (50वें इफ्फी के इंडियन पैनोरामा में दो फिल्मों 'एलिफेंट्स डू रिमेम्बर' और 'सत्यार्थी')
विशेष प्रदर्शन	35 आयोजनों में 307 फिल्में

6.6 वेबसाइट

फिल्म प्रभाग के वेब पोर्टल को परस्पर संवादमूलक एवं यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए उस पर मौजूदा घटनाओं के अपडेट, स्क्रीनिंग्स, डीवीडी एवं फिल्म रिलीज के माध्यम से वेबसाइट दर्शकों के साथ निरन्तरता बनाए रखता है। फिल्म प्रभाग द्वारा निर्मित तथा मौजूद सभी फिल्मों से जुड़ी सूचना के फिल्म प्रभाग कैटालाग को भी अपलोड रखा जाता है।

6.7 वीडियो ऑन डिमांड

वीडियो ऑन डिमांड सुविधा में 70 टाइटल्स वाले वीडियो उपलब्ध हैं। इनके डीवीडी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदा जा सकता है। फिल्म प्रभाग के वृत्तचित्रों को एमआईबी वेबसाइट के मीडिया सेक्शन में देखा जा सकता है और यहां 476 वीडियो दर्शकों के लिए उपलब्ध हैं।

6.8 अभिलेखीय अनुसंधान केंद्र

फिल्मकारों एवं फिल्म विद्यार्थियों के पूर्वावलोकन एवं शोध कार्यों के लिए 2013 से पंद्रह वर्क स्टेशनों वाला अभिलेखीय अनुसंधान केंद्र कार्य कर रहा है।

6.9 यूट्यूब

फिल्म प्रभाग की चुनिंदा फिल्में आमजन के लिए यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं। मौजूदा समय में फिल्म प्रभाग के यूट्यूब चैनल पर 625 वीडियो मौजूद हैं। चैनल पर 7.4 मिलियन व्यूज़ और इसके कुल 64.5 हजार ग्राहक हैं।

6.10अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व

सरकार के दिशानिर्देशों द्वारा कार्यस्थल पर समय–समय पर अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों के प्रतिनिधित्व से जुड़े ब्योरे एवं प्रस्तावित नियमों के अनुसार आरक्षण तालिका तैयार रखी जाती है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला कर्मचारी का विवरण 31.10.219 के अनुसार सेवा में निम्नलिखित हैः

पदों का वर्गीकरण	वर्तमान में सेवारत कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति कर्मचारी	अनु. सु. कर्मचारियों का %	अनुसूचित जाति कर्मचारी	अनु. सु. जनजाति कर्मचारियों का %	अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी	ओबीसी कर्मचारियों का %	महिला कर्मचारी	शारीरिक विकलांग
समूह क	15	3	20.00	1	6.66	4	26.66	3	–
समूह ख	160	37	23.13	12	7.50	33	20.63	25	03
समूह ग	293	86	29.35	22	7.50	81	27.65	42	11
कुल	**468**	**126**	–	**35**	–	**118**	–	**70**	**14**

6.11 दिव्यांग व्यक्ति

मंत्रालय के अनुसार निम्न श्रेणी पदों पर दिव्यांग व्यक्तियों की नियुक्तियां की जाएंगी।

ग्रुप बी	ग्रुप सी
सहायक लेआउट आर्टिस्ट	सहायक रिकॉर्डिस्ट
आर्टिस्ट श्रेणी I	सहायक लेआउट आर्टिस्ट
आर्टिस्ट श्रेणी II (पद समाप्त)	निम्न श्रेणी क्लर्क
सहायक संपादक श्रेणी I	चपरासी (एमटीएस)
सहायक	पैकर (एमटीएस)

दिव्यांग व्यक्तियों के लिए फिल्म प्रभाग में ग्रुप 'ए' में निर्धारित कोई भी पद नहीं है। सीधी भर्ती के आधार पर दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित पदों की संख्या निम्न है :

ग्रुप	कर्मचारियों की संख्या				
	कुल	चुनिंदा पदों पर	दृष्टि दिव्यांग	श्रपण दिव्यांग	अस्थि दिव्यांग
1	2	3	4	5	6
ग्रुप ए	31	-	-	-	-
ग्रुप बी	192	1	-	1	2
ग्रुप सी	386	4	-	-	13
कुल	**609**	**5**	**-**	**1**	**15**

पदों की संख्या का वार्षिक ब्यौरा जिन पर दिव्यांग व्यक्ति कार्यरत हैं (31.10.2019 तक)

मंत्रालय/विभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार					
संबंधित/अधीनस्थ कार्यालय फिल्म प्रभाग					
ग्रुप			कर्मचारियों की संख्या		
	कुल (30.10.2019 तक)	चिन्हित पद	दृष्टि दिव्यांग	श्रपण दिव्यांग	अस्थि दिव्यांग
1	2	3	4	5	6
ग्रुप ए	31	0	0	0	0
ग्रुप बी	192	1	0	1	2
ग्रुप सी एवं डी	386	4	0	0	13
कुल	**609**	**5**	**0**	**1**	**15**

दिव्यांग व्यक्तियों की कोई पद रिक्त नहीं है।

6.12 नागरिक घोषणापत्र

फिल्म प्रभाग ने 'इन्फॉर्मेशन ब्रॉशर ऑफ फिल्म्स डिविजन' नाम से नागरिक घोषणापत्र तैयार किया है जो उसकी वेबसाइट http://www.filmsdivision.org पर उपलब्ध है। इस विभाग में एक नोडल अफसर नियुक्त होता है। उपरोक्त घोषणापत्र को सही तरीके से अमल में लाने के लिए, कार्य से जुड़े फिल्म प्रभाग के अफसरों के कॉन्फ्रेंस/सेमिनार को व्यवस्थित किया जाता है।

6.13 लोक शिकायत निवारण तंत्र

सरकार द्वारा जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों के अनुसार, लोक शिकायत निवारण तंत्र को स्थापित किया गया है। महानिदेशक को फिल्म प्रभाग के लोक शिकायत अधिकारी के तौर पर मनोनीत किया जाता है। लोक एवं कर्मचारी शिकायतों का ब्योरा रखा जाता है और लोक शिकायत निपटान से संबंधित आवश्यक रिपोर्टों को नियमित तौर पर मंत्रालय को भेजा जाता है।

6.14 हिंदी विभाग

हिंदी विभाग कार्यालयी पत्राचार में हिंदी (राजभाषा) के इस्तेमाल को देखता है। फिल्म प्रभाग में केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा (ओएल) के इस्तेमाल की नीति को देखते हुए और गृह मंत्रालय के ओएल विभाग के संशोधित मानकों के अनुसार, फिल्म प्रभाग में कनिष्ठ हिंदी अनुवादकों के पद स्थापित किए गए हैं।

6.15 सतर्कता कार्रवाइयां

प्रभाग में कर्मचारियों के विरुद्ध सतर्कता/अनुशासन मामलों पर नजर रखने के लिए सहायक प्रशासनिक अधिकारी के अंतर्गत गठित सतर्कता कक्ष में एक सुपरिन्टेंडेंट, दो सहायक एवं एक अवर श्रेणी लिपिक कार्यरत रहते हैं।

(1) से (10) दंडात्मक कार्रवाइयां (अभ्यारोपितों की संख्या जिनकी नियुक्ति में राष्ट्रपति के अलावा अन्य नियुक्ति प्राधिकरणों की भूमिका रही)

1	अवधि के दौरान प्राप्त शिकायतें/संदर्भ	8
2	मामलों की संख्या जिनमें शुरुआती जांच की गई	03
3	मामलों की संख्या जिनमें आरंभिक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई	02
4	मामलों की संख्या जिनमें बड़े जुर्माने से संबंधित चार्जशीट जारी की गई	02
5	मामलों की संख्या जिनमें कम जुर्माने से संबंधित चार्जशीट जारी की गई	00
6	व्यक्तियों की संख्या जिन पर बड़ा जुर्माना लगाया गया	01
7	व्यक्तियों की संख्या जिन पर छोटा जुर्माना लगाया गया	00
8	निलंबित व्यक्तियों की संख्या	00
9	व्यक्तियों की संख्या जिनके विरुद्ध चेतावनी देने आदि से संबंधित प्रशासनिक कार्रवाइयां की गई	2
10	उपयुक्त नियमों के अंतर्गत समयपूर्व सेवानिवृत्त हुए व्यक्तियों की संख्या	00

6.16 आरटीआई

2005 के सूचना का अधिकार अधिनियम एवं समय–समय पर भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों/दिशानिर्देशों के आधार पर फिल्म प्रभाग ने निदेशक (प्रशासन) को अपीलीय अधिकारी के रूप में नामित/नियुक्त किया है। एवं एक निदेशक को केंद्रीय जन सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। सूचना का अधिकार अधिनियम से जुड़े सभी मामलों को अमल में लाने का कार्य मुख्यालय का एक नोडल विभाग अर्थात एस्टेब्लिशमेंट–I अनुभाग देखता है।

चिल्ड्रेन्स फिल्म सोसाइटी, भारत

अप्रैल, 2019 से अक्टूबर, 2019 तक की विपणन/वितरण गतिविधियां

➢ वितरण

- पूर्वोत्तर को छोड़कर महाराष्ट्र के ''स्कूलों में सीएफएसआई फिल्मों के प्रदर्शन'' के योजनागत कार्यक्रम के अंतर्गत चिल्ड्रेंस फिल्म बोनांज़ा के जरिए आयोजित 11 थियेटर शोज को 1,082 बाल दर्शकों ने देखा।
- पूर्वोत्तर को छोड़कर महाराष्ट्र के ''स्कूलों में सीएफएसआई फिल्मों के प्रदर्शन'' के योजनागत कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित किए गए 600 एलसीडी शोज को 1,63,511 बाल दर्शकों ने देखा।
- स्वच्छता ही सेवा – प्लास्टिक अशिष्ट प्रबंधन पर कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।
- समूचे भारत में 893 विशेष शो आयोजित किए गए जिन्हें विवरण के अनुसार 3,11,27,371 लोगों ने देखा।

ये शो इन उपलक्ष्यों में आयोजित किए गए :

- गुरु नानकदेव जी की 550वीं जयंती
- महात्मा गांधी की 150वीं जयंती
- राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय दिवस समारोहों, जैसे मदर्स डे, शिक्षक दिवस और विश्व विज्ञान दिवस के अवसर पर।
- राष्ट्रीय एकता दिवस
- स्वच्छता ही सेवा–प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन

कार्यक्रमों का आयोजन किया गया

बाल चित्र समिति, द्वारा महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर बिहार में पटना के बाल भवन 'किलकारी' में आयोजित शो

- रिमांड और ऑब्जर्वेशन होम के बच्चों के लिए।
- कैंसर सेवा केंद्र के बच्चों के लिए
- मानसिक रूप से अल्पविकसित बच्चों के लिए
- एचआईवी देखभाल केंद्रों के लिए
- दृष्टिबाधिक बच्चों के लिए
- अनाथ बच्चों के लिए
- झुग्गी–झोंपड़ी और उपेक्षित बच्चों के लिए

चिल्ड्रेन्स फिल्म सोसाइटी, भारत की फिल्मों को अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाने के लिए इन्हें हरियाणा में एड्यूसेट नेटवर्क पर दिखाया ताकि राज्य के सभी जिलों के साथ–साथ मुंबई में वृहन्मुंबई महानगरपालिका के स्कूलों को भी इसके दायरे में लाया जा सके।

सीएफएसआई फिल्मों का विपणन

- सात फिल्में दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर 'चुलबुली फिल्में, चटपटी गपशप' कार्यक्रम में दिखायी गयीं।
- दस फिल्में लोकसभा टीवी पर दिखायी गयीं।
- महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के सिलसिले में सीएफएसआई की फिल्में दूरदर्शन पर नियमित रूप से दिखाई गयीं। इसके अलावा स्वच्छता ही सेवा – प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अभियान के दौरान भी इन्हें दिखाया गया।
- अप्रैल, 2019 से विभिन्न सीएफएसआई फिल्मों के 1,583 डीवीडी बेचे गए।
- अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भागीदारी।
- सीएफएसआई की 12 फिल्मों ने आठ देशों में 8 अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भाग लिया।
- इससे कुल 70,02,120 रुपये की आमदनी हुई।
- अन्तरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में भागीदारी

नवंबर, 2019 से मार्च, 2020 तक की अवधि के लिए प्रस्तावित विपणन/वितरण गतिविधियां

➢ बाल दिवस यानी 14 नवंबर, 2019 के अवसर पर

निम्नलिखित गतिविधियां प्रस्तावित थीं:–

➢ निम्नलिखित स्थानों पर बाल फिल्म समारोह

1. उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में जिला प्रशासन के सहयोग से
2. महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में जिला प्रशासन के सहयोग से
3. कर्नाटक के कोप्पल जिले में जिला प्रशाासन के सहयोग से
4. तमिलनाडु के चेन्नई में राजकीय संग्रहालय के सहयोग से
5. सीएफएसआई दिल्ली में फिल्म प्रभाग के सहयोग से बाल फिल्म समारोह का आयोजन कर रहा है। यह समारोह महादेव रोड दिल्ली स्थित फिल्म प्रभाग के ऑडिटोरियम में आयोजित किया जा रहा है।

निम्नलिखित स्थानों पर फिल्मों का प्रदर्शन :

1. डॉ. भाऊ दाजी लाड संग्रहालय, मुंबई (महाराष्ट्र)
2. राज भवन, चेन्नई (तमिलनाडु)

➢ दूरदर्शन पर प्रदर्शन : सीएफएसआई फिल्म 'करामाती कोट' 14 नवंबर, 2019 को दूरदर्शन पर प्रदर्शित की गई।

➢ नयी पहल के रूप में सीएफएसआई महाराष्ट्र में वृहन्मुंबई महानगर पालिका के सहयोग से समूची मुंबई में शेल्टर होम के बच्चों के लिए फिल्में दिखाई जा रही हैं। परियोजना की शुरुआत 14 नवंबर, 2019 को डॉन बॉस्को शेल्टर होम में फिल्म के प्रदर्शन से हुई। इसके बाद 'पप्पू की पगडंडी' फिल्म दिखाई गई।

अन्य प्रस्तावित गतिविधियां :

➢ पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और ओडिशा राज्यों में एलसीडी शोज का आयोजन किया गया। कुल 300 शोज आयोजित किए गए जिनमें करीब 75,000 बाल दर्शकों इनका आनंद लिया।

➢ पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुल तीन बाल फिल्म समारोह मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा में आयोजित किए गए। इनमें कुल 18 शो आयोजित किए गए जिन्हें करीब 2,700 बाल दर्शकों ने देखा।

➢ पूर्वोत्तर के अलावा देश में 5 बाल फिल्म समारोह आयोजित किए गए। इनमें कुल 30 शो थे जिनका आनंद 6,000 बाल दर्शकों ने उठाया।

➢ सीएफएसआई की क्लासिक फिल्मों का दूरदर्शन से पुनर्प्रसारण किया।

राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोहों (एनसीएफएफ) का आयोजन

सीएफएसआई दिल्ली ने भारतीय रेल संग्रहालय में 9–12 दिसंबर, 2019 तक तीसरा राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह आयोजित करने की योजना बनाई।

अप्रैल, 2019 से अक्टूबर, 2019 तक निर्माण गतिविधियां

➢ पूरी की गयी फिल्में

पांच स्वच्छता फिल्मों– 'मास्टर की क्लास,' 'सोच शौचालय,' 'स्वच्छता की खोज,' आदि को प्रमाण पत्र दिए गए। हाथ साफ रखने के बारे में बच्चों को जागरूक बनाने, व्यक्तिगत साफ–सफाई के फायदों, शौचालयों की कमी और खुले में शौच न करने के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाकर उन्हें आधुनिक भारत का उपयोगी नागरिक बनाने के लिए स्वच्छता कार्रवाई योजना के अंतर्गत 6–16 साल के आयु वर्ग के विद्यार्थियों (लिटिल डायरेक्टर्स) की 'द स्टोरी ऑफ कचरापुर एंड बचपन' का प्रथम चरण बिहार में पूरा कर लिया गया।

➢ निर्माणाधीन फिल्में

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की जांच समिति ने 7.10.2019 को फिल्म 'चिड़ियाखाना' (हिंदी फीचर फिल्म) का फिर से पूर्वावलोकन किया जिसके बाद एनबीएफसी की पुनरीक्षण समिति ने भी 6.11.2019 को इसे फिर से देखा।

➢ फिल्मों की डबिंग :

मंत्रालय के निर्देशानुसार सीएफएसआई की दस फिल्मों की एनएफडीसी द्वारा पूर्वोत्तर की छह भाषाओं में डबिंग और पूर्वोत्तर के विषयों पर आधारित तीन फिल्मों की 13 क्षेत्रीय भाषाओं में डबिंग कर ली गयी है। इस तरह 94 फिल्मों में से 93 को एनबीएफसी से प्रमाणपत्र प्राप्त हो चुके हैं।

➢ प्रिंट निर्माण :

बाल चित्र समिति के 17 डीसीपी, 6 ब्लू रे और 241

डीवीडी टाइटल जारी करने के लिए तैयार हो चुके हैं।

नवंबर, 2019 से मार्च, 2020 तक निर्माण गतिविधियां

- **फिल्म निर्माण**

- स्वच्छता कार्रवाई योजना के अंतर्गत राजस्थान में 6–16 साल के विद्यार्थियों (लिटिल डायरेक्टर्स) द्वारा दूसरे चरण के अंतर्गत 'सफाई,' 'लोक्या,' 'ए क्लीन गेम,' 'बनजद,' 'रेवा' जैसी स्वच्छता फिल्मों की प्रमाणन से पहले जांच की जा रही है।

- मंत्रालय के निर्देशानुसार गांधीजी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर आधारित लिटिल डायरेटर्स की 40 फिल्में प्रमाणन के लिए वेंडर्स के जरिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को भेजे जाने से पहले उपयुक्त फार्मेट में बनाये जाने की प्रक्रिया में हैं।

- **फिल्मों की डबिंग**

निम्नलिखित कार्यों के लिए टेंडर आमंत्रित किए जा रहे हैं:

1. 7 फिल्मों की 10 क्षेत्रीय भाषाओं और पूर्वोत्तर की 6 भाषाओं में लिपसिंक डबिंग (कुल 112)।
2. 17 फिल्मों की 16 भाषाओं (यानी 10 क्षेत्रीय भाषाएं और पूर्वोत्तर की 6 भाषाएं) में निर्धारित ऑडियो फार्मेट में डबिंग जिसमें कुल 272 फिल्में डब की जाएंगी।

- **अल्संख्यक कल्याण गतिविधियों पर कार्यक्रम :**

सीएफएसआई एक छोटा संगठन है जिसमें सीमित संख्या में कर्मचारी हैं। कल्याण संबंधी गतिविधियां समूचे संगठन के लिए संचालित की जाती हैं जिनमें अल्पसंख्यक भी शामिल हैं।

केंद्रीय प्रशासनिक ट्राइब्यूनल के फैसले/आदेश पर अमल:

सीएफएसआई से संबंधित कोई भी निर्णय/आदेश प्राप्त नहीं हुआ।

नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुच्छेद:

निरीक्षण रिपोर्ट के सभी 24 लेखापरीक्षा अनुच्छेदों का उत्तर दे दिया गया है और इनके समाधान की प्रतीक्षा है।

दिव्यांग जनों के फायदे के लिए किए गए नीतिगत फैसले और गतिविधियां:

मंत्रालय द्वारा जारी और सीएफएसआई पर लागू होने वाले सभी निर्देशों का पालन किया जा रहा है। भर्ती में आरक्षण पर अमल किया जा रहा है।

आधुनिकीकरण और कम्प्यूटरीकरण :

सीएफएसआई प्रत्येक विभाग की वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर कम्प्यूटरों का उपयोग कर रहा है और इन्हें समय–समय पर अपग्रेड भी किया जाता है।

ई–कॉमर्स गतिविधियां :

फिल्मों के निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजने और शिष्टमंडलों के पंजीकरण को पेमेंट गेटवे के समन्वय से ऑनलाइन कर दिया गया है। सीएफएसआई द्वारा आयोजित फिल्म समारोह के लिए प्रविष्टियों के भेजने का कार्य ऑनलाइन किया जाता है। सीएफएसआई की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक मोबाइल एप विकसित किया गया है जिसमें फिल्मों के प्रोत्साहन की सुविधा भी उपलब्ध है। सभी भुगतान और प्राप्तियां ऑनलाइन की जा रही हैं। ई–टेंडरिंग की प्रक्रिया के बाद ही सेवाएं प्राप्त की जाती हैं।

भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान

1960 में स्थापित फ़िल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को 1974 में टेलीविजन विंग को जोड़ा गया। इसका नाम बदलकर 'फ़िल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया' रखा गया और सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन, 1860 के तहत अक्टूबर, 1974 में इसे एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया। एफटीआईआई सोसायटी जो अध्यक्ष द्वारा संचालित फ़िल्म, टेलीविज़न, संचार, संस्कृति के साथ जुड़े, संस्थान के पूर्व छात्रों और पूर्व–सरकारी अधिकारियों, प्रतिष्ठित व्यक्ति और एक गवर्निंग काउंसिल द्वारा शासित है।

संस्थान के दो स्कंध हैं– फ़िल्म और टेलीविजन स्कंध। जो फ़िल्म और टेलीविजन दोनों में पाठ्यक्रम संचालित करते हैं। तीन वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम, सिनेमेटोग्राफी, साउंड रिकॉर्डिंग और साउंड डिज़ाइन, के पाठक्रम शामिल हैं। संपादन और डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन डिज़ाइन का पुरस्कार दिया जाता है। संस्थान एक्टिंग में दो साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स, फ़ीचर फ़िल्म स्क्रीनप्ले राइटिंग में एक साल का पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स भी प्रदान करता है। टेलीविजन पाठ्यक्रम में निर्देशन, इलेक्ट्रॉनिक सिनेमेटोग्राफी, वीडियो संपादन, साउंड रिकॉर्डिंग और टीवी इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता के साथ टेलीविज़न में एक वर्षीय स्नातकोत्तर

प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम शामिल हैं।

वर्ष 2019–20 की झलकियां

- एफटीआईआई ने द्रास (लद्दाख) में अपने कार्यालय के मुख्य द्वार पर करगिल युद्ध स्मारक की जीवन सदृश प्रतिकृति स्थापित की है। करगिल विजय दिवस (26 जुलाई, 2019) की संध्या पर दक्षिणी कमान के एमजी आर्मी सिग्नल्स कोर (एएससी) के मेजर जनरल आर.वी. सिंह, वीएसएम ने इसका उद्घाटन किया।

- महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर एफटीआईआई ने 3 मिनट 47 सेकेंड की लघु फिल्म 'हे राम' का निर्माण किया। माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने इस फिल्म को ट्विटर पर रिलीज किया।

- अक्टूबर महीने में रिकॉर्डिंग एवं प्रसारण जैसे नियमित कार्यों के साथ, रेडियो एफटीआईआई ने चुनाव आयोग के सहयोग से एक संचार कार्यक्रम अभियान में सहभागिता की। चुनाव आयोग द्वारा 10 एवं 11 अक्टूबर को 'यशदा' में एक वर्कशॉप आयोजित की गई जिसे नई दिल्ली के 'स्मार्ट' का सहयोग प्राप्त था।

- स्मरणांजलि : रिमेम्बिरिंग द लीजेंड श्रंखला के अंतर्गत, मार्च, 2019 में नबेंदु घोष (स्क्रीनप्ले), अक्टूबर, 2019 में गुरुदत्त (अभिनेता एवं निर्देशक) तथा नवंबर, 2019 में संजीव कुमार (अभिनेता) की याद में 2 दिवसीय आयोजनों में फिल्म प्रदर्शन, चर्चा, प्रेजेन्टेशन्स एवं सामूहिक विमर्श आयोजित किए गए।

- एफटीआईआई ने **'पदार्पण – मोमेंटस माइलस्टोन्स'** के अंतर्गत विद्यार्थियों की डिप्लोमा फिल्म्स और प्रोजेक्ट फिल्म्स का प्रदर्शन किया। यह आयोजन 18 मई, 2019 को किया गया। आयोजन में एफटीआईआई के 1981 बैच के विद्यार्थी और प्रसिद्ध फिल्मकार श्री दिलीप घोष शामिल हुए। आयोजन में उनकी एफटीआईआई डिप्लोमा फिल्म 'तीरा' और उनकी नवीन हिंदी फिल्म 'कमांडो' का प्रदर्शन किया गया।

- 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में एफटीआईआई विद्यार्थी सार्थक भसीन द्वारा निर्देशित डिप्लोमा फिल्म **'एकांत' के लिए नीरज सिंह को कला निर्देशन का विशेष ज्यूरी पुरस्कार प्रदान किया गया।** पुरस्कार में विशेष उल्लेख था : फिल्म के कठोर, आसन्न आपदा दर्शाने वाले तथा अतियथार्थवादी डिजाइन के लिए।

- **66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019** के लिए रमन दम्पाल द्वारा निर्देशित एफटीआईआई छात्र वृत्तचित्र **'ग्लो वॉर्म इन ए जंगल' को स्पेशल मेंशन पुरस्कार** दिया गया। पुरस्कार में उल्लिखित शब्द थे : शहर में बिना मूलभूत सुविधाओं के असाधारण जीवन जीने वाली लेखक, दार्शनिक एवं पूर्व प्रोफेसर हेमा साने के विशद अभिनय एवं निर्देशक की अनोखी खोज को।

- एफटीआइ एवं एनएफएआइ ने 6 मई और 1 जून, 2019 को फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स का आयोजन किया।

- वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार अनेक अतिथि शिक्षकों ने विभिन्न विषयों पर एफटीआईआई में वर्कशॉप्स/सेमिनार/मास्टर क्लासेज का संचालन किया।

फिल्म महोत्सवों में एफटीआईआई की सहभागिता

- 4 से 6 अप्रैल, 2019 को फ्रांस में आयोजित चालोन तू कोर्ट फिल्मोत्सव के 10वें संस्करण में।

- 1 से 6 मई, 2019 को ओबेरहाउसेन, जर्मनी के 65वें अंतरराष्ट्रीय लघु फिल्मोत्सव में।

- मई, 2019 को सिलेक्त, बल्गारिया में आयोजित इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन स्कूल्स में।

- 14 से 25 मई, 2019 को कान में आयोजित सिने फाउंडेशन सेलेक्शन पेरिस में।

- 17 से 31 मई, 2019 को स्पेन के मैड्रिड में इमेजिन इंडिया अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में।

- 16 से 22 जून, 2019 को इजराइल के टेल अवीव में 21वें टेल अवीव अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी फिल्म महोत्सव में।

- 16 से 23 जून, 2019 को तेहरान, ईरान के 16वें नहाल विद्यार्थी लघु फिल्म महोत्सव में।

- 23 से 27 जुलाई, 2019 को पोस्टिरा, क्रोएशिया के 9वें पोस्टिरा सीसाइड फिल्म महोत्सव में।

एफटीआईआई की पुरस्कृत फिल्में

भारतीय			
1	सार्थक भसीन	'एकांत' को कला निर्देशन में विशेष ज्यूरी पुरस्कार	2018 के 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में विशेष उल्लेख : फिल्म के कठोर, आसन्न आपदा दर्शाने वाले तथा अतियथार्थवादी डिजाइन के लिए।
2	रमन दम्पाल	'ग्लो वॉर्म इन ए जंगल' को विशेष उल्लेख पुरस्कार	66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 : शहर में बिना मूलभूत सुविधाओं के असाधारण जीवन जीने वाली लेखक, दार्शनिक एवं पूर्व प्रोफेसर हेमा साने के विशद अभिनय एवं निर्देशक की अनोखी खोज को।
3	आकांक्षा चिटकारा	वृत्तचित्र संभाग में 'द बीस्ट कॉल्ड ब्यूटी' को प्रथम पुरस्कार	आठवां आरोग्य फिल्मोत्सव, पुणे
4	रिद्धि छाबड़ा	वृत्तचित्र अनुभाग में 'आई होल्ड ब्लड' को द्वितीय पुरस्कार।	
5	सुरंजनय मंडल	'रंग रखड़ी' को सर्वश्रेष्ठ छात्र फिल्म	आठवां राष्ट्रीय लघु फिल्मोत्सव (एनएसएफएफ)
6	रमेश होलबोले	'आगसवाडी' को सर्वश्रेष्ठ गैर–कथा चित्र	
7	हिमांशु प्रजापति	'तीन दोन एक' को ज्यूरी चॉयस अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ स्क्रीनप्ले पुरस्कार	
8	रमन दम्पाल	'ग्लो वॉर्म इन ए जंगल' का ज्यूरी द्वारा विशेष उल्लेख	
9	सुरंजनय मंडल	'रंग रखड़ी' के लिए कनिष्क भोकले को सर्वश्रेष्ठ साउंड डिजाइन पुरस्कार।	
विदेशी			
1	स्वप्निल कापुरे	प्रतिष्ठित कापा सर्वश्रेष्ठ फिल्म वृत्तचित्र पुरस्कार 'थिया (लेबर अड्डा)' को।	सीआईएलइसीटी, फिल्म एवं टेलीविजन स्कूलों की एक अंतरराष्ट्रीय समिति।
2	रमन दम्पाल	'ग्लो वॉर्म इन ए जंगल' को सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र पुरस्कार	हांगकांग बैप्टिस्ट यूनिवर्सिटी के ग्लोबल यूनिवर्सिटी फिल्म अवाड्र्स।
3	रमेश होल्बोले	रोमानियाई फिल्ममेकर्स यूनियन (यूसीआईएन) द्वारा 'आगसवाडी' को सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र का 'पॉल कलिनेस्कू' पुरस्कार	बुखारेस्ट का 22वां सिनेमाइयूबित अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी फिल्मोत्सव।

विद्यार्थी विनिमय, कार्यक्रम

ल फेमी, पेरिस एडिटिंग एक्सचेंज प्रोग्राम : एफटीआईआई 2013 से ल फेमी, पेरिस में एडिटिंग बैच के दो विद्यार्थियों को भेजता रहा है। 3 सप्ताह लंबे इस विनिमय कार्यक्रम में एफटीआईआई विद्यार्थियों को फ्रांस के फिल्म स्कूलों में इमेज एडिटिंग, विजुअल इफेक्ट्स और मोशन कैप्चर और वहां की संपादन तकनीकों की बारीकियों जानने का मौका मिलता है।

ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी विनिमय कार्यक्रम : 2016 बैच की सुश्री संस्कृति चट्टोपाध्याय (निर्देशन), श्री पी. कुमारास्वामी (सिनेमेटोग्राफी) एवं श्री आर. नितिन (साउंड डिजाइन) को एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन की ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी भेजा गया। 2 सप्ताह लंबे इस एक्सचेंज प्रोग्राम में अन्य फिल्म स्कूलों के साथ वृत्तचित्र निर्माण एवं वृत्तचित्र फिल्मोत्सव का आयोजन था। इस प्रोग्राम के अंतर्गत एफटीआईआई विद्यार्थियों को विदेशी सदस्यों के साथ काम के दौरान अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर, वृत्तचित्र के विषयों एवं निर्माण तकनीकों के मामले में अनुभव प्राप्त होगा।

सत्यजित रे फिल्म एवं टेलीविजन इंस्टीट्यूट

सत्यजित रे फिल्म एवं टेलीविजन इंस्टीट्यूट (एसआरएफटीआई) की स्थापना एक स्वायत्त अकादमिक संस्थान के तौर पर 1995 में पश्चिम बंगाल सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट. 1961 के अंतर्गत हुई थी। महान फिल्मकार सत्यजित राय के नाम पर आधारित यह इंस्टीट्यूट फिल्म शिक्षण के क्षेत्र में 6 विषयों में 3 वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम कराता है– (1) निर्देशन एवं स्क्रीनप्ले लेखन, (2) सिनेमेटोग्राफी, (3) संपादन, (4) साउंड रिकॉर्डिंग एवं डिजाइन, (5) फिल्म एवं टेलीविजन प्रोडक्शन और (6) एनिमेशन सिनेमा एवं 6 विषयों में विशेषज्ञता के 2 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम इन इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया (ईडीएम), जिनमें (1) मैनेजमेंट ऑफ ईडीएम, (2) सिनेमेटोग्राफी फॉर ईडीएम, (3) राइटिंग फॉर ईडीएम, (4) डायरेक्शन एंड प्रोड्यूसिंग फॉर ईडीएम, (5) एडिटिंग फॉर ईडीएम और (6) साउंड फॉर ईडीएम।

वर्ष की प्रमुख झलकियां

- 24 मई को कांस में आयोजित सिनेमेटोग्राफी उपलक्ष्य पियेर एंजेन्यू एक्सेललेंस में 2019 के लिए एंजेन्यू स्पेशल एनकरेजमेंट के लिए एसआरएफटीआई के सिनेमेटोग्राफी के 11वें बैच की सुश्री मधुर पलित पहली भारतीय बनीं।
- 14 से 25 मई, 2019 को आयोजित कांस फिल्म महोत्सव के 72वें संस्करण में फेस ऑफ इंडिया रहे तीन एसआरएफटीआई छात्र (1) लेखक–निर्देशक, श्री सौरव राय, (2) निर्देशक–सिनेमेटोग्राफर श्री डॉमिनिक संगमा और (3) कोलकाता स्थित सिनेमेटोग्राफर, मधुर पलित ने महोत्सव के विभिन्न सत्रों में अपने नए कार्यों का प्रदर्शन किया। प्रत्येक का लक्ष्य विश्व के विभिन्न कोनों में उभर रहे युवा सिनेमा को प्रोत्साहन देना था।
- एसआरएफटीआई के दो विद्यार्थियों, श्री जयब्रत दास एवं श्री प्रागदीश मारुथु (15वां बैच, सिनेमेटोग्राफी विद्यार्थी) का भारत, रूस, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के 10 छात्रों में चुनाव हुआ जिन्हें जुलाई 2019 में चीन में अपनी फिल्में बनाने का अवसर प्राप्त होगा।
- संस्थान के सिनेमेटोग्राफी के 9वें बैच के विद्यार्थी श्री आचार्य वेणु को शांघाई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सम्मानित किया गया। गारो भाषा (मेघालय) की फिल्म मा. अमा के लिए उन्हें 22वें शांघाई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव–2019 के एशियन न्यू टेलेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। यह फिल्म 300 प्रविष्टियों में से चुनी गई 14 फिल्मों में शीर्ष पर रही।
- पहली बार एसआरएफटीआई के विद्यार्थियों की फिल्मों का प्रसारण अखिल भारतीय दूरदर्शन पर किया जाएगा। दूरदर्शन एसआरएफटीआई के छात्रों को अपने चैनलों में इन्टर्न के तौर पर भी रखेगा। दूरदर्शन एसआरएफटीआई के छात्रों को **कंटेंट क्रिएशन** के लिए भी कार्य देगा।
- एसआरएफटीआई में एडिटिंग के सहायक प्रोफेसर श्री साकेत शेखरेश्वर राय को 1 से 6 जुलाई–2019 को एमस्टर्डम में आयोजित आईडीएफए एकेडमी समर स्कूल में सहभागिता के लिए चुना गया। आईडीएफए बर्थ फंड एक गैर–सरकारी संगठन है जो विकासशील देशों में वृत्तचित्र निर्माण को सहयोग करती है और डच विदेश मंत्रालय के साथ सहयोगरत है।

- सिनेमेटोग्राफी के प्रोफेसर श्री समीरन दत्ता को म्यूनिख, जर्मनी में फिल्स स्कूल फेस्ट–2019 को एसआरएफटीआई की विद्यार्थी फिल्म 'एन इरेलिवेंट डायलॉग' को प्रदर्शित करने के लिए नवंबर–2019 को आमंत्रित किया गया। इस फिल्म को निर्देशन एवं स्क्रीनप्ले लेखन के 12वें बैच के विद्यार्थी श्री मोनिक गुहा ने निर्देशित किया।

- समाचारों में नवीकृत तकनीकी संचार प्रक्रिया के इस्तेमाल के लिए संस्थान के इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया के डीन, श्री अभिजित दासगुप्ता को बीबीसी अकादमी लंदन से पुरस्कृत किया गया।

- सत्यजित रे फिल्म एवं टेलीविजन इंस्टीट्यूट (एसआरएफटीआई) ने भारत सरकार के विज्ञान एवं तकनीकी विभाग, विज्ञान प्रसार के साथ मिलकर, 6–8 नवंबर, 2019 को एसआरएफटीआई कैम्पस में भारत के अंतरराष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का आयोजन किया।

- 'आईएनपीयूटी' दुनिया का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का टेलीविजन संस्थान है। 29–30 अगस्त, 2019 को एसआरएफटीआई ने दूसरा 'मिनी आईएनपीयूटी' का आयोजन किया जिसमें सहभागियों को स्काइप के जरिए दुनिया भर के टेलीविजन प्रोफेशनल्स (चैनल एग्जिक्यूटिव्स, कमीशन एडिटर्स, निर्माण एवं निर्देशक) के साथ बात करने का अवसर मिला।

- 2 मई, 2019 को महान फिल्मकार सत्यजित रे की 98वीं जयंती के अवसर पर 12वें बैच के लिए 9वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता श्री टी. एस. नागभरणा मुख्य अतिथि थे एवं प्रख्यात फिल्म निर्देशक श्री ए. के. बीर भी विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित थे।

- लखनऊ की भारतेन्दु नाट्य अकादमी के विद्यार्थियों के लिए फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स : 18 नवंबर से 27 दिसंबर–2019 तक लखनऊ की भारतेन्दु नाट्य अकादमी के छात्रों के लिए संस्थान द्वारा 6 सप्ताह के फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स का आयोजन किया गया। इस सत्र के दौरान बीएनए के छात्रों को स्क्रीन एक्टिंग और फिल्म एप्रिसिएशन का प्रशिक्षण दिया गया।

- 30 मार्च से 26 मई, 2019 को एसआरएफटीआई ने फिल्म संपादन अभ्यास का एक अल्पावधि कोर्स आयोजित किया।

- एसआरएफटीआई ने भारत सरकार के राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) से संबद्ध मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के द्वितीय सत्र फाउंडेशन कोर्स का शुभारंभ किया। इन कोर्सेज में (1) डिजिटल फिल्म–मेकिंग, (2) स्क्रीन एक्टिंग एवं (3) रामाकृष्णा मिशन एवं मठ तथा पीयरलेस स्किल अकादमी के सहयोग से पटकथा लेखन शामिल हैं। इनका आरंभ 5 अप्रैल, 2019 को किया गया। इन कोर्सेज के अंतर्गत पश्चिम बंगाल के युवाओं को 2018 से कौशल विकास मिशन के अधीन स्व–रोजगार हेतु प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अभी तक दूसरे राज्यों के प्रतिभागियों के साथ यह प्रशिक्षण 10 जिलों में दिया जा रहा है।

- अशक्त बच्चों के लिए अल्पावधि कोर्स : मनोविकास केंद्र के अशक्त बच्चों के लिए 12 दिसंबर, 2019 को एसआरएफटीआई द्वारा स्क्रीन एक्टिंग का दो माह का अल्पावधि कोर्स आयोजित किया गया।

- एसआरएफटीआई में 5 से 6 दिसंबर, 2019 को डिजिटल मीडिया के लिए स्मार्टफोन एप्लिकेशन फॉर ए/वी का दो दिवसीय सेमिनार एवं वर्कशॉप आयोजित की गई।

- न्यू ऑटोमेशन से जुड़े विदेशी पेशेवरों के लिए भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर एसआरएफटीआई जनवरी से मार्च 2020 तक दूसरा आईटीईसी प्रोग्राम (इंडियन टेक्निकल एंड एकॉनमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम) का आयोजन करेगा।

- एसआरएफटीआई में 1 अप्रैल, 2019 को दूसरे दक्षिण एशियाई लघु फिल्मोत्सव 8 पुरस्कृत फिल्मों के चुनिंदा पैकेज का प्रदर्शन किया गया जिस दौरान इसके निर्माताओं ने एसआरएफटीआई छात्रों के साथ अपने विचार साझा किए।

- संस्थान में 11 सितंबर से 2 अक्टूबर, 2019 तक स्वच्छता ही सेवा को अभ्यास में ला रहा है।

विद्यार्थियों द्वारा निर्मित फिल्मों का फिल्मोत्सवों एवं पुरस्कारों में चुनाव

क्र. सं.	फिल्म/वृत्तचित्र शीर्षक	पुरस्कार विजेता का नाम	फिल्मोत्सव/पुरस्कार चुनाव
		भारतीय	
1.	'लुक एट द स्काई'	अशोक वेइलु	जून 2019 को आयोजित 12वें अंतरराष्ट्रीय वृत्तचित्र एवं लघु फिल्मोत्सव केरल (आईडीएसएफएफके) में बेस्ट शॉर्ट फिक्शन फिल्म।
2.	'अस्तित्व'	शरद उइके	आंध्र प्रदेश के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन में आयोजित डिजाइन ओलम्पिक्स में प्रथम पुरस्कार (स्वर्ण)।
3.	'एबरिज्ड'	गौरव पुरी	नवंबर 2019 को 25वें कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (केआईएफएफ) में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र का रॉयल बंगाल टाइगर पुरस्कार।
4.	'लाइफ'	विवेक प्रकाश एवं यांग्चेन थापा	नवंबर 2019 को मुंबई में आयोजित द एनिमेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया (टीएसएआई) द्वारा आयोजित एनिफेस्ट (मुंबई) में प्रदर्शन के लिए चुनाव।
5.	'यज्ञ'	विवेक प्रकाश	
6.	'ममत्व'	कीर्ति सिंह	नवंबर 2019 में गोवा में आयोजित भारत के अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के इंडियन पैनोरामा में प्रदर्शन के लिए चुनाव।
		विदेशी	
1.	'मा तुकी'	सूचना साहा	नवंबर 2019 में तेहरान, ईरान में आयोजित सिमोरह अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अंतरराष्ट्रीय एनिमेशन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार। जून 2019 में प्यूला, क्रोएशिया में 66वें प्यूला फिल्म महोत्सव–2019 में प्रदर्शन के लिए चुनाव।
2	'परेशान गली का भगवान सिकंदर'	इशान शर्मा	जून 2019 में जर्मन के स्टुटगार्ट में आयोजित इंडिया फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शन के लिए चुनाव।
3	'एन इरेलिवेंट डायलॉग'	कैनेथ साइरस	नवंबर 2019 म्यूनिख, जर्मनी के 39वें फिल्म स्कूल फेस्ट में श्री मानेक गुहा द्वारा निर्देशित फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी पुरस्कार।

अरुणाचल प्रदेश में फिल्म एवं टेलीविजन इंस्टीट्यूट

पूर्वोत्तर

पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास एवं वहां की युवा प्रतिभाओं को फिल्म एवं टेलीविजन क्षेत्र में प्रोत्साहन देने के सरकार के प्रयासों के अनुसार मंत्रालय ने पुणे के फिल्म एवं टेलीविजन इंस्टीट्यूट (एफटीआईआई) तथा सत्यजित राय फिल्म एवं टेलीविजन इंस्टीट्यूट (एसआरएफटीआई) जैसे संस्थानों को इस क्षेत्र में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है।

इसके लिए सीपीडब्ल्यूडी को अरुणाचल प्रदेश में एफटीआई निर्माण कार्य को मूर्तरूप देने का जिम्मा सौंपा गया है। 8 नवंबर, 2019 को भूमि पूजा का आयोजन किया गया और एफटीआई का निर्माण कार्य आरंभ हो चुका है। मौजूदा समय में, अस्थायी कैम्पस में फिल्म एवं टेलीविजन से संबंधित अल्पावधि कोर्स कराए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार

एक झलक

राष्ट्रीय फ़िल्म अभिलेखागार को फरवरी 1964 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत एक मीडिया इकाई के रूप में स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

1. भावी पीढ़ी के राष्ट्रीय सिनेमा की धरोहर का पता लगाने, उसे हासिल और संरक्षित करना और विश्व सिनेमा और राष्ट्रीय सिनेमा का प्रतिनिधि संग्रह तैयार करना।
2. फ़िल्म से संबंधित आकड़ों का वर्गीकरण और प्रलेखन और सिनेमा पर शोध संकलित और प्रोत्साहित करना और प्रकाशित कर उन्हें वितरित करना।
3. देश में फ़िल्म संस्कृति के संप्रेषण के लिए एक केंद्र के रूप में काम करना और विदेशों में भारतीय सिनेमा की सांस्कृतिक मौजूदगी सुनिश्चित करना।

एनएफएआई की फ़िल्म संग्रहण नीति

- भारत में फ़िल्मों के लिए राज्य पुरस्कार और अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोहों में पुरस्कार एवं गुणवत्ता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने वाली फ़िल्में।
- अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोहों के भारतीय पैनोरमा खंड में दिखाई जाने वाली फ़िल्में।
- बॉक्स ऑफिस पर लोकप्रियता हासिल करने वाली फ़िल्में और भारत और विदेश में बड़ी संख्या में दर्शकों को आकर्षित करने वाली फ़िल्में।
- भारतीय और विदेशी, दोनों तरह की जानी–मानी सहित्यिक कृतियों का फ़िल्म रूपांतरण।
- भारतीय और विदेशी स्थानीय परिवेश में शूट की गई तथा भारतीय अथवा विदेशी निर्माताओं द्वारा बनाई गई फ़िल्में।
- एनएफडीसी और अन्य सरकारी संगठनों द्वारा वित्त पोषित/निर्मित सभी फ़िल्में।
- बेहतरीन बाल फ़िल्मों के विशिष्ट नमूने।
- भारतीय और विदेशी फ़िल्म निर्माताओं द्वारा की गई समाचार कवरेज में दर्ज़ यथार्थ सामग्री वाली फ़िल्में।
- सरकारी और गैर–सरकारी एजेंसियों द्वारा निर्मित ऐतिहासिक महत्व के वृत्तचित्र।

जयकर बंगला

पुणे में लॉ कॉलेज रोड पर एनएफएआई के मुख्य परिसर में स्थित, बैरिस्टर मुकुल आर. जयकर के निवास "जयकर बंगला" को एक धरोहर इमारत के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बैरिस्टर मुकुल आर. जयकर जाने–माने शिक्षाविद और विधि विशेषज्ञ थे, जो पुणे विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति बने और उन्होंने पुणे की समृद्ध विरासत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लकड़ी की सीढ़ियों और खिड़कियों के साथ इमारत के पत्थर में एक सभ्य ठोस संरचना का समावेश है।

1964 में भारतीय फ़िल्म संस्थान, पुणे के परिसर में अस्थायी कमरों के लघु शेडों में हुई सामान्य शुरुआत के बाद मई 1974 में एनएफएआई का कार्यालय जयकर बंगले में स्थानांतरित किया गया। एनएफएआई ने मार्च 1981 में दो एकड़ भूमि के साथ इंडियन लॉ सोसायटी से जयकार बंगला अधिग्रहीत किया था। जयकर बंगले में एनएफएआई ने अपना कार्यालय जनवरी 1994 तक रखा। उसके बाद एनएफएआई को उसी परिसर में अपना एक नया भवन मिला, जहां फ़िल्म कक्षों का डिज़ाइन अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म संस्थान मानकों के साथ तैयार किया गया है, उपयुक्त रूप से सुसज्जित संरक्षण विभाग हैं, काफी मात्रा में किताबें हैं और पत्र–पत्रिकाओं का पुस्तकालय है और एक कैटलॉग, अनुसंधान और प्रलेखन केंद्र है, जिसमें सिनेमा पोस्टर, अचल चित्रों और अन्य अनुषंगी सामग्री का एक अनमोल संग्रहालय भी है। अभिलेखागार में 3 सिनेमा ऑडिटोरियम हैं, जहां वह अपने संग्रह से जनता के लिए फ़िल्मों का प्रदर्शन भी करता है।

धरोहर होने के कारण जयकर बंगले का ऐतिहासिक मूल्य है और इसे भावी पीढ़ियों के लिए बेहतर स्थिति में संरक्षित रखने की आवश्यकता है। भारत सरकार ने जयकर बंगले के संरक्षण कार्य और डिजिटल पुस्तकालय के लिए अपेक्षित ढांचे की स्थापना हेतु 9 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

निकट अतीत की महत्वपूर्ण उपलब्धियां :–

एनएफएआई ने 1945 की शिमला बैठक की दस मिनट की दुर्लभ फुटेज को संरक्षित किया है जिसमें महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, सी. राजगोपालाचारी आदि ने शिरकत की

थी। यह दुर्लभ फुटेज़ लंदन निवासी मारग्रेट साउथ (टेलर) से प्राप्त हुई जो विलियम टेलर की सुपुत्री हैं।

प्रसिद्ध संगीतज्ञ कल्याणजी–आनंदजी के आनंद जी ने अपनी निजी संग्रह से कुछ दुर्लभ फिल्म सामग्री एनएफएआई को संरक्षित करने के लिए दी है। एनएफएआई जाकर उन्होंने निजी तौर पर अपने कुछ गीतों की रिकॉर्डिंग्स की ऑडियो रीलें एनएफएआई के सुपुर्द कीं।

एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के अंतर्गत, प्रसिद्ध फिल्मकार जी. अरविंदन के परिवार ने अपनी निजी कलेक्शन में से कुछ तस्वीरें तथा अन्य सामग्री एनएफएआई को प्रदान कीं। जी. अरविंदन के सुपुत्र श्री रामू अरविंदन ने यह सामग्री एनएफएआई को संरक्षण हेतु दीं।

राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय (एनएफएआई) ने विख्यात फिल्म निर्देशक ऋत्विक घटक के निकटवर्ती रहे श्री महेंद्र कुमार से फिल्मों एवं अन्य सामग्री का बड़ा संकलन प्राप्त किया।

मधुर भंडारकर का हालिया राजनीतिक थ्रिलर 'इंदु सरकार' अब एनएफएआई का अंश है। फिल्मकार भंडारकर ने एनएफएआई द्वारा संरक्षित किए जाने के लिए फिल्म के डिजिटल संस्करण को एनएफएआई को प्रदान किया।

मराठी की प्रतिष्ठित फिल्म 'वंदे मातरम' (1948) जिसमें प्रसिद्ध लेखक एवं नाटककार पी. एल. देशपांडे ने अपनी पत्नी सुनीता देशपांडे के साथ अग्रणी भूमिका निभाई थी, एनएफएआई के संग्रह में शामिल हो चुकी है। फिल्म की 35 मिनट फुटेज की वीएचएस कैसेट को सुनीता देशपांडे एवं फिल्म इतिहासकार श्री सतीश जकतदार के भतीजे श्री दिनेश ठाकुर ने एनएफएआई को प्रदान किया। साथ ही, यू–मैटिक टेप्स भी एनएफएआई को प्राप्त हुई जिनमें पी. एल. देशपांडे द्वारा हारमोनियम बजाए जाने की दुर्लभ फुटेज मौजूद है।

फ़िल्म भंडारण/संरक्षण

एनएफएआई लगभग 27 अत्याधुनिक, फ़िल्म संरक्षण सुविधाओं/अभिलेखागार मानकों और विनिर्देशों के साथ वाल्ट को आश्रय देता है। इन वॉल्ट्स में लगभग 2 लाख फ़िल्म रीलों के भंडारण की क्षमता है। ब्लैक एंड व्हाइट फ़िल्मों, रंगीन फ़िल्मों और नाइट्रेट आधारित फ़िल्मों के लिए निम्न तापमान के साथ फ़िल्म वाल्ट्स बनाए रखे जाते हैं:–

फ़िल्मों का प्रकार	तापमान	सापेक्ष आर्द्रता
नाइट्रेट फ़िल्म	10 डिग्री–12 डिग्री	सी 40 फीसदी
ब्लैक एंड व्हाइट फ़िल्में	10 डिग्री–12 डिग्री C	40 प्रतिशत +/–5
रंगीन फ़िल्में	2 डिग्री–4 डिग्री C	30 प्रतिशत +/–5

फिल्म महोत्सवों में सहभागिता :

पुणे का 17वां अंतरराष्ट्रीय फिल्मोत्सव 11 से 17 जनवरी, 2019 को आयोजित हुआ। एनएफएआई मेन थियेटर में प्रतिदिन चार स्क्रीनिंग की जाती थी। **फिल्मोत्सव के दौरान एनएफएआई कलेक्शन से विभिन्न फिल्में दिखाई गईं।** इस दौरान कई गणमान्य व्यक्ति, फिल्म उद्योग के सदस्य, नुमाइंदे और फिल्म प्रेमी उपस्थित रहे।

एनएफएआई ने **नेचर वाइल्ड चेरिटेबल ट्रस्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट** के सहयोग से एनएफएआई मेन थियेटर में 1 जनवरी, 2019 को **'क्लैश ऑफ टाइग्रेस'** का प्रदर्शन आयोजित किया।

एनएफएआई ने (पुणे में आयोजित सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री राज्यवर्धन राठौर द्वारा उद्घाटित **खेलो इंडिया 2019** की पूर्व संध्या पर) **स्पोर्ट्स फिल्म फेस्टिवल** का आयोजन किया जिसमें 08 जनवरी, 2019 को एनएफएआई मेन थियेटर में 3 **दुर्लभ फिल्में/फुटेज दिखाए गए। 1) कोल्हापुर में 1948–49 में खेले गए मैत्रीपूर्ण छत्रपति शिवाजी महाराज क्रिकेट मैच, 2) बर्लिन ओलम्पिक्स 1936, 3) 1950 में कोलकाता में डलहौजी क्लब बनाम मोहन बागान के बीच खेले गए फुटबॉल मैच के अंश थे।**

26 जनवरी, 2019 से 28 जनवरी, 2019 तक एनएफएआई के मेन थियेटर में आशय फिल्म क्लब एवं संशोधन (आईएसएसआरओ) के सहयोग से एनएफएआई ने विज्ञान फिल्मोत्सव का आयोजन किया जिसमें 11 फिल्में दिखाई गईं।

एनएफएआई ने पुणे स्थित **पूर्वोत्तर सांस्कृतिक संघ (एनईसीओपी), सिम्बॉयसिस कॉलेज, ईएलटीआईएस** के सहयोग से 1 फरवरी से 3 फरवरी, 2019 तक एनएफएआई फेज़ II में पूर्वोत्तर फिल्म महोत्सव (एनईएफएफ) का आयोजन किया। यह कार्यक्रम सभी के लिए था।

पूर्वोत्तर फिल्म महोत्सव 2019

पुणे अंतरराष्ट्रीय केंद्र (पीआईसी) के साथ मिलकर एनएफएआई ने श्रीलंकाई फिल्म 'हंसा विलक' का विशेष प्रदर्शन किया। इस अवसर पर फिल्म की अभिनेत्री 'स्वर्णा मल्लावरच्छी' दर्शकों के साथ बातचीत के लिए मौजूद थीं।

एनएफएआई ने पुणे के कलामहर्षि चेरिटेबल ट्रस्ट के साथ मिलकर एनएफएआई मेन थियेटर में 16–17 फरवरी, 2019 को **'डांस फिल्म फेस्टिवल'** का आयोजन किया। इस अवसर पर एनएफएआई संग्रह में से तीन फिल्में प्रदर्शित की गईं। यह कार्यक्रम सभी के लिए था।

एनएफएआई ने **स्मार्ट सिटी पुणे** के साथ मिलकर अपने अभियानबद्ध फिल्म प्रदर्शन के तौर पर एक आयोजन किया जिसके अंतर्गत 18 से 20 फरवरी, 2019 को एनएफएआई संग्रह से तीन फिल्में प्रदर्शित की गईं। यह कार्यक्रम सभी के लिए था।

एनएफएआई ने **सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के मास कम्युनिकेशन विभाग** के साथ मिलकर एनएफएआई मेन थियेटर में 22–23 फरवरी, 2019 को **'राष्ट्रीय लघु फिल्मोत्सव'** का आयोजन किया।

एनएफएआई ने पुणे स्थित बियॉन्ड एंटरटेनमेंट के सहयोग से 24 फरवरी, 2019 को एनएफएआई मेन थियेटर में **'विष्णु पंत दामले एवं मधुबाला पर वृत्तचित्र'** का विशेष आयोजन किया। प्रदर्शन के बाद मंत्रणा सत्र आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम सभी के लिए था।

एनएफएआई ने पुणे स्थित आशय फिल्म क्लब एवं पत्रकारों की संस्था आयम के सहयोग से 8 से 10 मार्च, 2019 को एनएफएआई मेन थियेटर में 'महिला फिल्मोत्सव' के अंतर्गत 11 फिल्मों का प्रदर्शन किया। यह कार्यक्रम सभी के लिए था।

एनएफएआई ने टीआईएफए वर्किंग स्टूडियो के सहयोग से 15 मार्च, 2019 को एनएफएआई मेन थियेटर में 'सुबर्ण रेखा' एवं 'अछूत कन्या' फिल्मों का प्रदर्शन किया। यह आयोजन अंतरराष्ट्रीय सिनेमा में महिलाओं की थीम पर आधारित था और आयोजन सभी के लिए था।

एनएफएआई ने एलायंस फ्रांसेस के सहयोग से एनएफएआई मेन थियेटर में 16–17 मार्च, 2019 को 'फ्रांकोफोन फिल्मोत्सव' का आयोजन किया। इस अवसर पर छह फिल्मों का प्रदर्शन हुआ। फिल्मोत्सव सभी के लिए था।

एनएफएआई ने मुंबई स्थित थाई काउंस्लेट के सहयोग से एनएफएआई मेन थियेटर में 29 से 31 मार्च, 2019 को 'थाई फिल्म फेस्टिवल' का आयोजन किया। इस अवसर पर थाईलैंड की नौ फिल्में प्रदर्शित की गईं। आयोजन सभी के लिए था।

एनएफएआई एवं अरबात फिल्म क्लब ने 30 मार्च, 2019 को कोथरूड एनएफएआई फेज़ II में बाल फिल्मों का आयोजन किया।

एनएफएआई ने सम्वाद पुणे के साथ मिलकर एनएफएआई मेन थियेटर में 15 से 20 अप्रैल, 2019 के दौरान बाल फिल्मोत्सव का आयोजन किया। इस अवसर पर छह फिल्में आयोजित की गईं। (चार फिल्में एनएफएआई के संग्रह से जारी की गई थीं)।

एनएफएआई ने पुणे के अरबात फिल्म क्लब के सहयोग से एनएफएआई फेज़ द्वितीय में 27 अप्रैल, 2019 को **अरबात चिल्ड्रेन क्लब स्क्रीनिंग** का आयोजन किया।

एनएफएआई ने अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडल के सहयोग से 5 मई, 2019 को एनएफएआई मेन थियेटर में **'निर्माता/निर्देशकों एवं फाइनेंसरों की एक दिवसीय वर्कशॉप'** का आयोजन किया।

एनएफएआई ने अरबात फिल्म क्लब के सहयोग से एनएफएआई फेज़ द्वितीय में 25 मई, 2019 को **'चिल्ड्रेन फिल्म क्लब'** का आयोजन किया।

एनएफएआई ने एलायंस फ्रान्कोई एवं रोटरी फिल्म क्लब के सहयोग से एनएफएआई फेज़ द्वितीय में 15 एवं 16 जून, 2019 को लघु फिल्मोत्सव का आयोजन किया।

एनएफएआई ने पुणे के नेचर वॉच चेरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से एनएफएआई मेन थियेटर में 20 जून, 2019 को नवीन चलचित्र **'क्वीन ऑफ तारु'** का प्रीमियर आयोजित किया। यह कार्यक्रम सर्वजन के लिए खुला था।

एनएफएआई ने कोरियाई कन्स्यूलेट के सहयोग से एनएफएआई मेन थियेटर में 21 एवं 22 जून, 2019 को कोरियाई फिल्म महोत्सव का आयोजन किया।

एनएफएआई ने आशय फिल्म क्लब के सहयोग से

एनएफएआई मेन थियेटर में 27–28 जून, 2019 को **ट्यूनीशियन फिल्म महोत्सव** का आयोजन किया।

एनएफएआई ने **अरबात फिल्म क्लब** के सहयोग से एनएफएआई फेज़ द्वितीय में 29 जून, 2019 को चिल्ड्रन फिल्म क्लब का आयोजन किया।

एनएफएआई ने कलावर्द्धिनी चेरिटेबल ट्रस्ट पुणे के सहयोग से 30 जून, 2019 को प्रसिद्ध नर्तक श्री राम गोपाल पर सुनील कोठारी द्वारा निर्मित फिल्म का प्रदर्शन आयोजित किया। कार्यक्रम सभी के लिए खुला था।

एनएफएआई ने यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल एवं भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से 5 से 11 जुलाई, 2019 को एनएफएआई मेन थियेटर में **यूरोपीय फिल्म महोत्सव** का आयोजन किया। इस आयोजन में 22 फिल्में प्रदर्शित की गईं।

एनएफएआई ने अरबात फिल्म क्लब के सहयोग से एनएफएआई मेन थियेटर फेज़ द्वितीय में 27 जुलाई, 2019 को **चिल्ड्रेन फिल्म क्लब** का आयोजन किया।

एनएफएआई ने पुणे के रेडियो एफएम चैनल के सहयोग से एनएफएआई मेन थियेटर में 5 से 9 अगस्त, 2019 को **'मराठी फिल्म महोत्सव'** का आयोजन किया। इस अवसर पर **बनवा बनवी, दुनियादारी, माहेरची साड़ी, दोम्बिवली फास्ट और नटरंग** का आयोजन किया गया। अभिनेता सचिन, सुप्रिया, अशोक सर्राफ, निवेदिता सर्राफ इस मौके पर उपस्थित थे। श्रोताओं को जानी–मानी हस्तियों से प्रश्न करने एवं सेल्फी बूथ में सेल्फी लेने का अवसर भी मिला। प्रोग्राम पुणे के श्रोताओं द्वारा बेहद पसंद किया गया।

एनएफएआई ने प्रोटेक्टेरा ईकोलॉजिकल फाउंडेशन एवं आशय फिल्म क्लब, पुणे के साथ मिलकर एनएफएआई मेन थियेटर में 25 अगस्त, 2019 को **वृत्तचित्र 'वाइल्ड कर्नाटक'** का प्रदर्शन किया।

एनएफएआई ने पुणे के बियॉन्ड एंटरटेनमेंट ग्रुप के सहयोग से एनएफएआई मेन थियेटर में 1 अगस्त, 2019 को **एवी प्रोग्राम ऑन मदन मोहन और वसंत देसाई पर वृत्तचित्र** का प्रदर्शन किया। यह कार्यक्रम **सभी के लिए खुला** था।

एनएफएआई एवं कावादी प्रोडक्शन एलएलपी ने एनएफएआई मेन थियेटर में 11 अगस्त, 2019 को फीचर फिल्म **'हिज़ फादर्स वॉयस'** का प्रदर्शन आयोजित किया।

एनएफएआई एवं अरबात फिल्म क्लब के सहयोग से एनएफएआई मेन थियेटर में 18 अगस्त, 2019 को **लघु फिल्म क्लब स्क्रीनिंग** का आयोजन किया।

एनएफएआई एवं साहिर लुधियानवी फाउंडेशन अवार्ड सेरेमनी ने एनएफएआई मेन थियेटर में 10 अक्टूबर, 2019 को फिल्म **'अनुराधा'** का आयोजन किया।

एनएफएआई ने बियॉन्ड एंटरटेनमेंट के सहयोग से एनएफएआई मेन थियेटर में 13 अक्टूबर, 2019 को **एवी प्रोग्राम ऑन अनंत सप्रे** का आयोजन किया।

एनएफएआई एवं संवादसेतु संस्था ने एनएफएआई मेन थियेटर में 20 अक्टूबर, 2019 को **एवी प्रोग्राम ऑन अमिताभ बच्चन** का आयोजन किया।

एनएफएआई एवं ऐलान प्रोडक्शन पुणे ने एनएफएआई मेन थियेटर फेज़ द्वितीय में 20 अक्टूबर, 2019 को **लघु फिल्म 'ड्रीम'** का प्रदर्शन किया।

एनएफएआई एवं लोकमत मीडिया प्रा. लि. ने एनएफएआई मेन थियेटर में **दीपोत्सव 2019 के प्रकाशन** का आयोजन किया।

एनएफएआई ने अरबात फिल्म क्लब, पुणे के सहयोग से **बाल क्लब फिल्म** का आयोजन किया।

एनएफएआई ने संगीत नाटक अकादमी के सहयोग से एनएफएआई मेन थियेटर में 23 नवंबर, 2019 को श्री निर्मल चंदर डंडरियाल द्वारा निर्मित वृत्तचित्र **गुरु मां अन्नपूर्णा देवी** का प्रदर्शन आयोजित किया। **प्रोग्राम सभी के लिए खुला था।**

एनएफएआई ने आशय फिल्म क्लब के सहयोग से एनएफएआई मेन थियेटर में 29 नवंबर, 2019 को मराठी फिल्म **'फत्ते–शिकस्त'** का आयोजन किया।

विशेष आयोजन :

डॉ. केदार अवाती (एफटीआईआई के संगीत प्रोफेसर) ने एनएफएआई मेन थियेटर में 7 जनवरी, 2019 को अपने पिता **'वाइस एडमिरल (सेवानिवृत्त) एम.पी. अवाती'** का

प्रदर्शन किया। प्रोग्राम आमंत्रितगण के लिए था जिसे सभी के लिए कर दिया गया।

श्री विद्या एंटरप्राइजेज एवं शंकर–जयकिशन फाउंडेशन ने एनएफएआई मेन थियेटर में 24 जनवरी, 2019 को **एवी म्यूजिकल प्रोग्राम** का आयोजन किया जिसे सर्वजन के लिए रखा गया।

लोनावाला की निजी संस्था मनशक्ति प्रयोग केंद्र ने एनएफएआई मेन थियेटर में 25 जनवरी, 2019 को स्वामी दयानंद, पी.एल. देशपांड़े, सुधीर फड़के के जन्मशती वर्ष के उपलक्ष्य में **एवी प्रोग्राम ऑन फिल्म 'वंदेमातरम'** का आयोजन किया।

निजी प्रदर्शक प्रसन्न पेठे ने एनएसएआई फेज़ द्वितीय, कोथरूड में 14 मार्च, 2019 को एवी प्रोग्राम 'लाइफ ऑफ शशि कपूर' का आयोजन किया।

पुणे स्थित समाप्तिक ट्रस्ट ने एनएफएआई मेन थियेटर में 23 मार्च, 2019 को 'क्वीर (एलजीबीटीआई) फिल्मोत्सव' का आयोजन किया।

एनएफएआई ने हाल में दिवंगत श्री गिरिश कर्नाड को श्रद्धांजलि स्वरूप उनकी चार फिल्मों का प्रदर्शन एनएफएआई थियेटर में किया। यह प्रोग्राम सभी के लिए था।

एनएफएआई ने दिल्ली में एक विशेष आयोजन में डिजिटल डायलेमा के हिंदी अनुवाद का लोकार्पण किया। इस अवसर पर एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज़ (लोकप्रिय नाम ऑस्कर एकेडमी) के अध्यक्ष श्री जॉन बेली मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर प्रतिष्ठित फिल्म एडिटर एवं एकेडमी की गवर्नर श्रीमती कैरल लिटिलटन, एफसीएटी अध्यक्ष न्यायधीश मनमोहन सरीन, सूचना एवं प्रसारण सचिव अमित खरे, सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी, एकेडमी के अध्यक्ष उज्ज्वल निरगुदकर तथा एनएफएआई निदेशक प्रकाश मगदुम उपस्थित थे।

विकास इंडिया ट्रस्ट नामक एक निजी संस्था ने एनएफएआई मेन थियेटर में 14 से 16 जून, 2019 को अंतरराष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव का आयोजन किया।

श्री विद्या एंटरप्राइजेज नामक एक निजी संस्थान ने एनएफएआई मेन थियेटर में 19 जुलाई, 2019 को **'एवी प्रोग्राम ऑन शंकर–जयकिशन एंड देयर इमोर्टल हीरोइन्स'** का आयोजन किया।

एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज के अध्यक्ष श्री जॉन बेली में 28 मई, 2019 को आयोजित इंटरैक्टिव सत्र डिजीटल डायलेमा के हिंदी संस्करण का लोकार्पण किया। एनएफएआई द्वारा तैयार किया गया था और इस कार्यक्रम का आयोजन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किया

स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में एनएफएआई ने मेन थियेटर में 17 अगस्त, 2019 को देशभक्ति थीम पर तीन फिल्मों का विशेष प्रदर्शन आयोजित किया। (शहीद/हिंदी, रोज़ा/तमिल नेताजी सुभाषचंद्र बोस)।

पुनःनवीकृत जयकर बंगले का उद्घाटन : माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने पुणे के राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय में जीर्णोद्धारित जयकर बंगले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर इस विरासतरूपी संपत्ति के रख–रखाव पर एनएफएआई को बधाई दी। यह बंगला एक समय पुणे विश्वविद्यालय के पहले उप–कुलपति श्री जयकर का निवास स्थान हुआ करता था। केंद्रीय मंत्री ने इस अवसर पर एक स्मारिका 'परंपरा : एन ओड टू जयकर बंगलो' भी जारी की जिसमें बंगले के जीर्णोद्धार की कथा के साथ, इसके अतीत एवं वर्तमान के बारे में भी बताया गया है। इसकी विशेषता भारतीय सिनेमा की कुछ जानी–मानी हस्तियों द्वारा साझा किए गए अनुभव थे जो जयकर बंगले में स्थित एफटीआईआई गर्ल्स होस्टल में रुकती थीं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि जयकर बंगले में नई डिजिटल लाइब्रेरी से फिल्म शोधकर्ताओं अच्छा लाभ मिलेगा।

एनएफएआई मेन थियेटर में **महात्मा गांधी की 150वीं जयंती** के मौके पर 2 अक्टूबर, 2019 को महात्मा गांधी की दुर्लभ फुटेज का विशेष प्रदर्शन किया गया।

इफ्फी 2019 : एनएफएआई ने बीओसी के सहयोग से इफ्फी की 50वें संस्करण के अवसर पर एक विशेष मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री अमित खरे ने गोवा सरकार के प्रमुख सचिव श्री परिमल राय के सानिध्य में किया। अनेक गणमान्य व्यक्तियों एवं फिल्म हस्तियों ने प्रदर्शनी देखा। कई सरकारी प्रतिनिधि भी प्रदर्शनी देखने आए। प्रदर्शनी आमजन के लिए खुली थी, इसलिए इसे अपार प्रशंसा मिली। इफ्फी की स्वर्ण जयंती पर मल्टीमीडिया प्रदर्शनी के लिए कंटेंट तैयार कर 23 संस्थानों के लिए बाहरी एजेंसी को आउटसोर्स किया गया। कंटेंट में भारतीय सिनेमा के इतिहासादि संबंधित जानकारी थी। इसके लिए 2000 से अधिक प्रासंगिक तस्वीरें भी उपलब्ध कराई गईं।

विभिन्न कार्यक्रमों के लिए फिल्मों की आपूर्ति एवं एनएफएआई द्वारा आयोजित कार्यक्रम :–

एनएफएआई भारत में कई स्तरों पर फिल्म संस्कृति के प्रचार हेतु कार्य कर रहा है। देश भर में इसकी वितरण लाइब्रेरी में करीब 25 सक्रिय फिल्म क्लब/सदस्य हैं। अभिलेखागार भारत के अनेक फिल्मोत्सवों एवं विभिन्न स्क्रीनिंग कार्यक्रमों में प्रदर्शन के लिए फिल्मों की आपूर्ति करता है। गत वर्ष एनएफएआई ने अन्य संगठनों के सहयोग से विभिन्न फिल्मोत्सव आयोजित करते हुए फिल्में दिखाईं।

एनएफएआई, अरबात फिल्म क्लब एवं राजू सुतार ने एक फिल्म क्लब का आरंभ करते हुए वृत्तचित्रों पर विशेष तौर पर फोकस किया। फिल्म क्लब में प्रतिमाह एक वृत्तचित्र दिखाया जाता है और साथ ही फिल्मकारों एवं फिल्म विद्वानों के साथ बातचीत सत्र भी आयोजित होता है।

एनएफएआई के संग्रह में से हैदराबाद 1 डॉ. बी किन्नेरा मूर्ति को हैदराबाद लिटरेरी फेस्टिवल के लिए भेजा गया। वहीं, एनएफएआई संग्रह में से ही बंग्लुरु अंतरराष्ट्रीय फिल्मोत्सव के लिए 3 फिल्में भेजी गईं।

एनएफएआई संग्रह में से कोच्चि बाइनेल फिल्मोत्सव के लिए 7 फिल्में जारी की गईं।

एनएफएआई संग्रह में से कोल्हापुर अंतरराष्ट्रीय फिल्मोत्सव के लिए 1 फिल्म जारी की गई।

एनएफएआई संग्रह से बिमल रॉय मेमोरियल एवं मुंबई फिल्म सोसाइटी के लिए 2 फिल्में जारी की गईं।

एनएफएआई संग्रह से इटली के बोलोना में आयोजित द्वितीय भारतीय फिल्मोत्सव सिनेमा रिट्रोवेटो के लिए 1 फिल्म जारी की गई।

एनएफएआई संग्रह से मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए @मुंबई 1 फिल्म जारी की गई।

गुवाहाटी अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए @गुवाहाटी फिल्म।

अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए भेजी गई फिल्में :

एनएफएआई संग्रह से 5 फिल्में ऋत्विक घटक फिल्मोत्सव के लिए कोलंबिया यूनिवसिटी न्यूयॉर्क/लिंकन सेंटर के लिए।

फिल्म एप्रीशिएशन कोर्सेज़

एनएफएआई एवं एफटीआईआई द्वारा 6 मई से 1 जून तक **44वां फिल्म एप्रीशिएशन कोर्स** कराया गया। इस कोर्स

के लिए प्रत्याशियों का पंजीकरण, अध्ययन सामग्री से संबंधित रोजमर्रा के ईमेल, फीडबैक फॉर्म्स, आम प्रशासनिक कार्य इसी संभाग द्वारा आयोजित किए गए। कोर्स में 79 प्रत्याशी शामिल हुए। प्रख्यात फिल्मकार शाजी करुण ने इसका उद्घाटन किया। विदाई समारोह के दौरान जाने–माने फिल्मकार राकेश ओमप्रकाश मेहरा उपस्थित थे।

मराठी में फिल्म एप्रीशिएशन कोर्स :

इस पाठ्यक्रम में संबंधित सभी प्रशासनिक कार्य इस खंड द्वारा किए गए एवं उनके द्वारा भागीदारी भी हुई। कोर्स का उद्घाटन नामी फिल्मकार श्री सचिन कुदेरकर ने 19.09.2019 को किया था और समापन जानी पहचानी अभिनेत्री सुश्री तनुजा ने 24.09.2019 को किया था। पुरस्कृत फिल्म पानी की स्क्रीनिंग के बाद श्री आदिनाथ कोठारे ने प्रतिभागियों के साथ चर्चा सत्र किया। महाराष्ट्र के सभी कोनों से 67 प्रतियोगियों ने कोर्स में भाग लिया। फिल्म शिक्षकों/प्राध्यापकों ने फिल्म एप्रीशियन के लिए विभिन्न विषयों पर लेक्चर दिया। फीचर फिल्म (8) और लघु फिल्म छात्रों के लाभ के लिए कोर्स के दौरान प्रदर्शित किया गया।

तृतीय शीतकालीन फिल्म एप्रीशिएशन कोर्स 2019:–

यह कोर्स एफटीआईआई के सहयोग से 1 दिसंबर 2019 से 15 दिसंबर 2019 तक एनएफएआई फेज–II कॉम्पेलेक्स में आयोजित किया गया। इस वर्ष देश के सभी कोनों से 24 प्रतिभागी ने भाग लिया था।

पोस्टर प्रदर्शनी

पर्दे पर महात्मा : 10 से 17 जनवरी, 2019 को एनएफएआई ने पूणे अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदर्शनी रखी। बीएएफटीए की पुरस्कार विजेता अभिनेत्री रोहणी हट्टगडी, अनेक पुरस्कार विजेता निर्देशक गोविंद निहलानी, महोत्सव के निदेशक फिल्मकार जब्बार पटेल उपस्थित थे।

पर्दे पर महात्मा : मुंबई में 20 से 25 जनवरी, 2019 को आयोजित यशवंत फिल्मोत्सव में यही प्रदर्शनी पहुंची। एनएफएआई ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर एफटीआईआई द्वारा 15 प्रदर्शनीय वस्तुओं की एक प्रदर्शनी आयोजित की। प्रदर्शनी 26 जनवरी से 31 जनवरी, 2019 तक आयोजित की गई।

एनएमआईसी, एफडी, मुंबई में उद्घाटन : द महात्मा ऑन सेल्युलॉयड प्रदर्शनी के लिए एनएफएआई ने 62 प्रदर्शनीय वस्तुओं की सॉफ्ट कॉपी प्रदर्शित की। 50 दादासाहेब फाल्के पुरस्कार विजेताओं और प्रसिद्ध भारतीय फिल्मों के 71 पोस्टरों की प्रदर्शनी भी आयोजित की गई।

पर्दे पर महात्मा : एनएफएआई ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर एफटीआईआई में 15 प्रदर्शनीय वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित की। प्रदर्शनी सर्वजन के लिए खुली थी।

इफ्फी 2019 : एनएफएआई ने बीओसी के सहयोग से इफ्फी की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष मल्टीमीडिया डिजिटल प्रदर्शनी आयोजित की। प्रदर्शनी का उद्घाटन सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री अमित खरे ने गोवा सरकार के प्रमुख सचिव श्री परिमल राय की उपस्थिति में किया। अनेक गणमान्य व्यक्तियों एवं फिल्म हस्तियों ने प्रदर्शनी देखी। कई सरकारी प्रतिनिधि भी प्रदर्शनी देखने आए। प्रदर्शनी आमजन के लिए खुली थी, इसलिए इसे अपार प्रशंसा मिली। इफ्फी की स्वर्ण जयंती पर मल्टीमीडिया प्रदर्शनी के लिए कंटेंट तैयार कर 23 संस्थानों के लिए बाहरी एजेंसी को कार्य दिया गया। कंटेंट में भारतीय सिनेमा के इतिहासादि संबंधित जानकारी थी। इसके लिए 2000 से अधिक प्रासंगिक तस्वीरें भी उपलब्ध कराई गईं।

योजना एवं गैर–योजना रूपी कार्यक्रम

योजना प्रारूप

2019–20 के लिए एनएफएआई के पास अभिलेखागार फिल्मों एवं फिल्म मैटीरियल तथा जयकर बंगले तथा डिजिटल लाइब्रेरी के अवसंचरनात्मक विकास हेतु 5.50 करोड़ रुपये का प्रावधान है। नया योजना प्रारूप नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन (एनएफएचएम) है जिसके लिए 2019–20 का कुल परिव्यय 22.48 करोड़ रुपये का है।

2019–20 के लिए योजना कार्यरूप का ब्योरा अनुलग्नक–सी में दिया गया है।

जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर के लिए बजट प्रावधान

एनएफएआई की कार्य गतिविधियों को देखते हुए पूर्वोत्तर तथा जम्मू और कश्मीर के लिए किसी बजट के प्रावधान को

सहज/संभव नहीं माना गया।

योजना एवं गैर–योजना बजट का विवरण नीचे दिया गया है :

2019–20

बजट अनुमान 2019–2020

(रुपये करोड़ में)

मेजर हेड '2220'– सूचना एवं प्रचार	स्थापना	केंद्र क्षेत्रीय योजनाएं
राजस्व	6.13	22.98
पूंजी	0.00	5.00
कुल	6.13	27.98

शासन प्रबंध

संगठनात्मक स्थापना

एनएफएआई के पुणे में मुख्यालय होने के साथ बंगलुरु, कोलकाता और तिरुअनंतपुरम में तीन क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ये क्षेत्रीय कार्यालय मुख्य रूप से फ़िल्म समाज, शैक्षणिक संस्थानों और सांस्कृतिक संगठनों के माध्यम से संबंधित क्षेत्रों में फ़िल्म संस्कृति के प्रचार–प्रसार के काम में लगे हुए हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों के कामकाज की देखरेख निदेशक, एनएफएआई द्वारा की जाती है। एनएफएआई के तीन क्षेत्रीय कार्यालयों को मिलाकर कर्मचारियों की संख्या (प्रशासनिक विंग में 22 और तकनीकी विंग में 27) है।

अजा और अजजा के लिए जनजातीय उप–योजना/विशेष घटक योजना के संबंध में बजट प्रावधान।

एनएफएआई की गतिविधियों के स्वरुप को ध्यान में रखते हुए अजा और अजजा के लिए जनजातीय उप–योजना/विशेष घटक योजना के संबंध में बजट प्रावधान प्रदान करना संभव नहीं माना गया।

एफआईएएफ

एनएफएआई मई, 1969 से इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फ़िल्म अभिलेखागार का सदस्य रहा है। एफआईएएफ की सदस्यता एनएफएआई को विशेषज्ञ सलाह, संरक्षण तकनीक, प्रलेखन, ग्रंथ सूची इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। अन्य अभिलेखागारों के साथ दुर्लभ फ़िल्मों के आदान–प्रदान के साथ अभिलेखीय विनिमय कार्यक्रमों के तहत सुविधा भी देता है।

अजा/अजजा/अपिव के कल्याण हेतु

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों के लिए लाभ और कल्याण प्रदान करने के लिए समय–समय पर संशोधित मानदंडों के अनुसार ध्यान दिया जाता है।

आधिकारिक भाषा के तौर पर हिंदी का प्रयोग

14.09.2019 से 28.09.2019 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। इस अवसर पर श्रुतलेख, स्वच्छता अभियान पर प्रचार वाक्य एवं अंताक्षरी का आयोजन किया गया जिसमें एनएफएआई के सभी कर्मचारियों ने भाग लिया। 19.09.2019 को पुणे के हिंदी शिक्षण योजना के उपाध्यक्ष (ओएल) श्री राजेंद्र कुमार वर्मा द्वारा एक वर्कशॉप संचालित की गई जिसमें रोजमर्रा के कामकाज में हिंदी के असरकारी इस्तेमाल के लिए आईटी टूल्स को इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया। प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया।

आधिकारिक भाषा नीति के इस्तेमाल की उपलब्धियां:

राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय को आधिकारिक भाषा इस्तेमाल उपलब्धि में निम्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया :

1. नागरी आधिकारिक भाषा प्रयोग समिति की ओर से 2018–19 के लिए आधिकारिक भाषा प्रयोग के लिए द्वितीय पुरस्कार।
2. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा 26 नवंबर, 2019 को आधिकारिक भाषा परिपालन में तृतीय पुरस्कार।
3. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा 26 नवंबर, 2019 को आधिकारिक भाषा परिपालन में विशेष पुरस्कार।

विभागीकृत खाते

एनएफएआई 1976 से विभागीकृत लेखा प्रणाली का इस्तेमाल करता है। इसके अंतर्गत, एनएफएआई का भुगतान

एवं लेखा कार्य को पीएओ, एफडी एवं मुंबई द्वारा नियंत्रित किया जाता है। एनएफएआई के निदेशक को डीडीओ के रूप में विभाग प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया जाता है और वह यह अधिकार एनएफएआई के प्रशासनिक अधिकारी को प्रदान करता है।

नियुक्ति/प्रतिनिधित्व

1. **पेरिस के फाउंडेशन जेरोम पेथे** द्वारा 19 से 23 मार्च, 2019 को आयोजित भारतीय मूक फिल्मों के सिंहावलोकन में उपस्थित होने के लिए।
2. ब्राजील के निटेरोई में ब्राजील सरकार के सिटिजनशिप ऑफ फेडरल गवर्नमेंट मंत्रालय द्वारा 30 सितंबर से 3 अक्टूबर, 2019 को आयोजित **चौथे ब्रिक्स फिल्मोत्सव** में शामिल होने के लिए।
3. **पिंग्याओ सरकार के सहयोग से एवं पिंग्याओ फिल्म महोत्सव** कं. लि. द्वारा 10 से 14 अक्टूबर, 2019 को आयोजित **तीसरे पिंग्याओ क्राउचिंग टाइगर हिडन ड्रेगन अंतरराष्ट्रीय फिल्मोत्सव में शामिल होने के लिए।**

कैट के निर्णय/निर्देश के कार्यान्वयन के लिए

एनएफएआई के मामले में इस संदर्भ में प्राप्त रिपोर्ट को रिक्त तौर पर अपनाया जाए, क्योंकि एनएफएआई को सीएटी से संबंधित कोई भी निर्णय/निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है।

आरटीआई अधिनियम – 2005

एनएफएआई ने भारत सरकार द्वारा 2005 के सूचना का अधिकार अधिनियम को अपने यहां लागू किया है। इस संबंध में 1 मार्च, 2019 से दिसंबर, 2019 की अवधि में एनएफएआई को 25 आवेदन–पत्र प्राप्त हुए और नियमानुसार आवेदकों को आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराई गईं। इसके माध्यम से संगठन के कामकाज में पारदर्शिता आई है।

शिकायत प्रकोष्ठ

एनएफएआई के निदेशक, को विभागाध्यक्ष के रूप में शिकायत अधिकारी नामित किया गया है। सभी शिकायतों का निवारण सरकारी नियमों और मानदंडों के अनुसार किया गया है।

नागरिक चार्टर

एनएफएआई की वेबसाइट पर नागरिकों के लिए चार्टर है। नागरिक हमारी वेबसाइट (www.nfaipune.gov.in) पर जा सकते हैं और आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नागरिकों के चार्टर की जानकारी समय–समय पर दी जाती है।

कार्ययोजना का कार्यान्वयन

नई परियोजना स्कीम के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में एसएफसी की मंजूरी "जयकर बंगला सहित एनएफएआई के बुनियादी ढांचे का उन्नयन और डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना" 14.6.2013 को प्राप्त हुई थी जिसका कार्यान्वयन अभी होना है। एनएफएआई के चरण–II में सुरक्षा बाड़ लगाने और आंतरिक सड़क पूरी हो गई है, डॉल्बी डिजिटल साउंड सिस्टम को लगाना, चरण–I अंतर्गत सभागार में कुर्सियां और कालीन लगाना और डीजी सेट का काम पूरा हो गया और बिजली का काम जैसे वाल्टों के लिए एयर कंडीशनिंग के प्रतिस्थापन, सभागार, अग्निशमन प्रणाली शुरू हो गई है और उसका काम प्रगति पर है। घरोहर स्मारक, जयकर बंगले की बहाली का काम प्रगति पर है।

आधुनिकीकरण, कंप्यूटरीकरण और ई–गवर्नेंस/ई–कॉमर्स

एनएफएआई देश में फ़िल्म संस्कृति के प्रसार के लिए एक केंद्र के रूप में काम करते हुए भारतीय सिनेमा की विरासत हासिल करने और उसे संरक्षित करने के कार्य संलग्न है। अभिलेखागार की वेबसाइट के जरिए देश के विभिन्न भागों और समूचे विश्व के सामान्य जान, सिनेमा के गंभीर अध्येता और अनुसंधानकरता अभिलेखागार में संगृहीत वस्तुओं और अभिलेखागार की सेवाओं तक पहुंच कायम कर सकते हैं, फ़िल्म बोध पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन प्रपत्र वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। लोगों के प्रश्नों के उत्तर आमतौर पर ई–मेल (nfaipune@gmail.com) के माध्यम से दिए जाते हैं। एनएफएआई में इंटरनेट, फैक्स और स्कैनिंग की सुविधा है। एनएफएआई के आधिकारिक फेसबुक और ट्विटर अकाउंट चालू हैं और सक्रिय रूप से उपयोग किए जा रहे हैं।

सतर्कता गतिविधियां

रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान सतर्कता गतिविधियों के बारे में जानकारी निम्नानुसार है :

1. मुख्यालय में और क्षेत्रीय कार्यालयों में संगठन के गठन की सतर्कता का विवरण :

इस कार्यालय में मुख्य सतर्कता अधिकारी का पद नहीं है

और इस कारण निदेशक को विभाग प्रमुख के सतर्कता अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

2. इस अवधि के दौरान निरोधक सतर्कता गतिविधियां :

   i इस अवधि में किए गए नियमित निरीक्षणों की संख्या : बारह

   ii इस अवधि में किए गए औचक निरीक्षण की संख्या : बारह

3. अवधि के दौरान निगरानी और पता लगाने की गतिविधियां:

   i निगरानी रखने के लिए चुने गए क्षेत्रों का विवरण : फ़िल्मों की सुरक्षा और नकल।

   ii निगरानी में रखे जाने वाले व्यक्तियों की संख्या : शून्य

4. दंडात्मक गतिविधियां संख्या (1) से (x) इंगित होनी चाहिए जहां नियुक्ति प्राधिकारी राष्ट्रपति के अलावा कोई अन्य होगा।

   i. अवधि के दौरान

   ii. उन मामलों की संख्या जिनमें प्रारंभिक जांच की गई थी : शून्य

   iii. उन मामलों की संख्या जहां प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई थी : शून्य

   iv. उन मामलों की संख्या जिनमें प्रमुख दंड के लिए आरोप पत्र जारी किए गए थे : शून्य

   v. मामूली जुर्माना के लिए आरोप पत्र जारी करने वाले मामलों की संख्या : शून्य

   vi. उन व्यक्तियों की संख्या जिन पर भारी जुर्माना लगाया गया था : शून्य

   vii. ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिन पर मामूली जुर्माना लगाया गया था : शून्य

   viii. निलंबन के तहत रखे गए व्यक्तियों की संख्या : शून्य

   ix. उन व्यक्तियों की संख्या जिनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई जैसे चेतावनी जारी करना आदि लिया गया था : शून्य

   x. नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत समय से पहले सेवानिवृत्त व्यक्तियों की संख्या : शून्य

राष्ट्रीय फ़िल्म धरोहर मिशन (एनएफएचएम)

भारत की फ़िल्म धरोहर को बहाल करने और उसके संरक्षण के लिए 597.41 करोड़ रूपये की "राष्ट्रीय फ़िल्म धरोहर मिशन" परियोजना मंजूर की गई थी। फ़िल्म धरोहर मिशन (एनएफएचएम) के अंतर्गत बनायी गई उच्च स्तरीय समिति की आई एंड बी मंत्रालय, सरकार द्वारा अनुमोदित की गई थी। भारत की फ़िल्म विरासत को पुनर्स्थापित करने और संरक्षित करने के लिए नवंबर, 2014 में वित्त मंत्रालय के माध्यम से यह योजना शुरू की गई। यह 12वीं पंचवर्षीय योजना का एक हिस्सा है, जो योजना परिव्यय के वर्षवार आवंटन के अनुसार 13 वीं पंचवर्षीय योजना तक फैला रहेगा। फ़िल्म उद्योग द्वारा इस पहल की काफी सराहना की जाएगी। इस नई योजना योजना में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के फ़िल्म विंग के तहत NFAI के साथ–साथ अन्य मीडिया इकाइयों के साथ उपलब्ध फ़िल्मों के डिजिटलीकरण/बहाली का ख्याल रखा गया है। योजना का कार्यान्वयन भारतीय राष्ट्रीय फ़िल्म पुरालेख, पुणे को दिया जाता है। राष्ट्रीय फ़िल्म विरासत मिशन (एनएफएचएम) के अंतर्गत बनायी गई उच्च स्तरीय समिति की कुल छह बैठकें मिशन के कार्यान्वयन पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में हुईं। एएस एंड एफए, जेएस (फ़िल्म), डीजी (एफडी), श्री जाह्नु बरुआ और राजीव मेहरोत्रा, एसआरएफटीआई, कोलकाता के निदेशक ने बैठकों में भाग लिया। राष्ट्रीय फ़िल्म विरासत मिशन (एनएफएचएम) की विभिन्न गतिविधियों के लिए कार्यान्वयन एजेंसी को सूचीबद्ध करने के लिए एक परामर्शदाता की नियुक्ति की गई है।

राष्ट्रीय फ़िल्म धरोहर (एनएफएचएम) के लक्ष्य

i) फ़िल्म संग्रह में फ़िल्म की स्थिति का मूल्यांकन करना और किसी फ़िल्म के शेष बचे जीवन का पता लगाना।

ii) 1,32,000 फ़िल्म रीलों के निवारक संरक्षण।

iii) भारतीय सिनेमा की 1086 ऐतिहासिक फ़ीचर फ़िल्मों और 1152 लघु फ़िल्मों की 2के/4के पिक्चर एवं ध्वनि बहाली करना तथा प्रत्येक फ़िल्म की नई पिक्चर और साउंड इंटर नेगेटिव की रिकॉर्डिंग।

iv) 1160 फ़ीचर फ़िल्मों और लघु फ़िल्मों का डिजिटलीकरण।

v) एनएफएआई परिसर, पुणे में एनएफएआई के अंतर्गत बहाल की गई सामग्री को धूल मुक्त, न्यूनतम आर्द्रता और कम तापमान की स्थिति में सामग्री के संरक्षण सुविधाओं का निर्माण।

vi) अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में संरक्षण,

परिरक्षण और संरक्षण हेतु प्रशिक्षण कार्यशालाएं और पाठ्यक्रमों का आयोजन।

थियेटर सुविधाएं

एनएफएआई के तीन बहु–प्रयोजनीय थियेटर हैं। इनमें मुख्य परिसर में 35 सीटों का एक प्री–यू थियेटर और 300 सीटों का मुख्य थियेटर तहत कोथर्ड में 200 सीटों का एक कला थियेटर शामिल है। इसके अलावा अन्य थियेटरों में पुणे में मैक्स मूलर भवन, एलाइंस और ब्रिटिश काउंसिल परिसर में स्वयं के लिए और एनएफएआई फ़िल्म सर्कल सदस्यों के थियेटर को 311 कार्यक्रमों के लिए किराए पर दिया गया।

निर्माताओं / कॉपीराइट मालिकों को सुविधाएं

एनएफएआई निर्माताओं / कॉपीराइट धारकों को उनके मूल नेगटिव्स की मरम्मत करने, डुप्लीकेट प्रतियां तैयार करने और टेलीकास्ट प्रयोजनों के लिए वीडियो कॉपी करने जैसे कार्यों में सेवाएं प्रदान करता है। एनएफएआई के संग्रह से राष्ट्रीय और उपग्रह नेटवर्कों पर अनेक सेल्युलॉयड क्लासिक्स टेलीकास्ट किए जाते हैं।

अनुलग्नक–क

रिपोर्ट के तहत अभिलेखीय प्राप्ति में जोड़े गए कुछ महत्वपूर्ण नए शीर्षक :

महल	35मिमी	हिंदी	
दर्द	35मिमी	हिंदी	
चमन	35मिमी	पंजाबी	
श्री राम अवतार	16मिमी		
चाल बाज़	16मिमी		
पैसा ही पैसा	16मिमी		
ए आईसीसी–1938 फैज़पुर कांग्रेस	35मिमी		
आज का अर्जुन	35मिमी		
डीकारिणा मंडावा	35मिमी	गुजराती	
हांगलू वेशा	35मिमी	कन्नड़	
आधुरी	35मिमी	कन्नड़	
अमृता गालीज़	35मिमी	कन्नड़	
ऑनडू मुठिना काथे	35मिमी	कन्नड़	
उल्टा पुल्टा	35मिमी	कन्नड़	
नंजुंडी कल्याण	35मिमी	कन्नड़	
मुसांजे माथु	35मिमी	कन्नड़	
जूगुला	35मिमी	कन्नड़	
धर्म देवथे	35मिमी	कन्नड़	
चीगुरिडा कानसू	35मिमी	कन्नड़	रील्स
स्पीडिंग अहेड	35मिमी	कन्नड़	1 रील्स
अंतरा	35मिमी	कन्नड़	1 रील्स
कंगल हनुमंतहिआ	35मिमी	कन्नड़	1 रील्स

होसा ची गुरु	35मिमी	कन्नड़	1 रील्स
वन मैन वॉर	35मिमी	कन्नड़	1 रील्स
अंडमान एंड निकोबार	35मिमी	कन्नड़	1 रील्स
जनरल करिअप्पा	35मिमी	कन्नड़	1 रील्स
सुगम दारी	35मिमी	कन्नड़	1 रील्स
समानथे	35मिमी	कन्नड़	1 रील्स
नेमादिया बड़कू	35मिमी	कन्नड़	1 रील्स
डॉ. निरंजन	35मिमी	कन्नड़	1 रील्स
ज़ी. वी. जी गुंडप्पा	35मिमी	कन्नड़	1 रील्स
नया निनदु नीरू नामदू	35मिमी	कन्नड़	1 रील्स
भूकंप	35मिमी	कन्नड़	1 रील्स
डॉ. शिवराम कारंथ	35मिमी	कन्नड़	1 रील्स
साधना आराधने	35मिमी	कन्नड़	1 रील्स
दलित कासु	35मिमी	कन्नड़	1 रील्स
राष्ट्र कवि कुवेम्पु	35मिमी	कन्नड़	1 रील्स
महात्मा गांधी जीवन दर्शन	35मिमी	कन्नड़	1 रील्स
विवेकानंद	35मिमी	कन्नड़	1 रील्स
नेताजी	35मिमी	कन्नड़	1 रील्स
नगालैंड मुन्नाडा	35मिमी	कन्नड़	1 रील्स
स्त्री सावित्री	16मिमी	मराठी	
चमन	35मिमी	हिंदी	17 रील्स
दर्द	35मिमी	हिंदी	13 रील्स
चरित्र	35मिमी	हिंदी	12 रील्स
धरम करम	35मिमी	हिंदी	18 रील्स
प्रेम ग्रन्थ	35मिमी	हिंदी	18 रील्स
आ अब लौट चले	35मिमी	हिंदी	
बड़ी मां	35मिमी	हिंदी	13 रील्स
मीनार	35मिमी	हिंदी	13 रील्स
नदिया के पार	35मिमी	हिंदी	13 रील्स
			14 रील्स
कोरा कागज़	35मिमी	हिंदी	1 रील
संत रविदास की अमर कहानी	35मिमी	हिंदी	15 रील्स

अनुलग्नक–ख

31 दिसंबर, 2019 को अभिलेखीय प्राप्ति दिखाने वाला वर्णन

मद	31.12.2019 को
फ़िल्में	21692
वीडियो कैसेट्स	3687
डीवीडी	3241
पुस्तकें	30240
पटकथाएं	45040
पहले से रिकॉर्डिड ऑडियो कैसेट्स	1098
अचल चित्र (स्टिल्स)	196468
वाल पोस्टर्स	38768
गीतों की पुस्तिकाएं	24672
ऑडियो टेप्स (वाचिक परंपरा)	191
प्रेस क्लिपिंग्स	228025
पंफ्लेट्स / फ़ोल्डर्स	9464
स्लाइड्स	9144
डिस्क रिकॉर्ड्स	3249
ऑडियो कम्पैक्ट डिस्क	155
अनुषंगी फ़िल्म सामग्री का डिजिटलीकरण	383511

अनुलग्नक–ग

योजना कार्य 2019–20

कार्यक्रम / योजना	एस.बी.जी. 2019–20	आर.ई 2019–20	31.12.2019 तक वास्तविक व्यय
नई योजनाएं			
1) अभिलेखीय फ़िल्मों और फ़िल्म सामग्री का अधिग्रहण।	2.50	2.29	1.32
2) जयकर बंगला सहित एनएफएआई के बुनियादी ढांचे का उन्नयन और डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना।	3.00	2.16	2.05
3) राष्ट्रीय फ़िल्म विरासत मिशन (एनएफएचएम)	17.48	3.59	2.43
4)	5.00	0.02	0.00

एनएफएआई की सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों के बारे में आंकड़े

रीलों / फ़िल्मों की संख्या	16एमएम	35एमएम
1. फ़िल्मों की व्यापक जांच	–	324
2. फ़िल्मों की नियमित जांच	–	578
3. रीलों की नियमित जांच	–	5140
फ़िल्म संस्कृति का संप्रेषण		
1. वितरक पुस्तकालय सदस्य	274	
2. वितरक पुस्तकालय सदस्यों को आपूर्ति की गई फ़िल्मों की संख्या	–	
3. विशेष अवसरों पर आपूर्ति की गई फ़िल्में	70	
4. संयुक्त स्क्रीनिंग	88	
5. फ़िल्म बोध पाठ्यक्रम के लिए आपूर्ति की गई फ़िल्में	18	
6. अनुसंधान कार्यकर्ताओं को उपलब्ध कराई गई फ़िल्म देखने की सुविधाएं	41	
7. शैक्षणिक स्क्रीनिंग के लिए एफटीआईआई को आपूर्ति की गई फ़िल्में	157	
8. एनएफएआई में दिखाई गई फ़िल्मों की संख्या	789	
9. पुस्तकालय सेवा का लाभ प्राप्त करने वाले पाठकों की संख्या	943	
10. अनुसंधानकर्ताओं की संख्या, जिन्होंने डॉक्यूमेंटेशन अनुभाग की सेवाएं प्राप्त की प्रलेखन अनुभाग की सेवाओं की	500	
11. एनएफएआई की स्क्रीनिंग पर उपस्थित दर्शकों की संख्या	52490	

फ़िल्म समारोह निदेशालय

अप्रैल, 2019 :

कैप स्पार्टल फिल्म समारोह, मोरक्को का छठा संस्करण

फिल्म समारोह निदेशालय ने भारतीय दूतावास, मोरक्को के सहयोग से मोरक्को के टैंगियर्स में 4 से 6 अप्रैल, 2019 तक कैप स्पार्टल फिल्म समारोह सीएसएफएफ के छठे संस्करण में भाग लिया। समारोह के दौरान प्रदर्शित होने वाली फिल्मों में *प्रियमानसम (संस्कृत), स्वपनम (मलयालम), टूलेट (तमिल), राज़ी (हिंदी), अक्टूबर (हिंदी), कट्यार कालजत घुस्सली (मराठी), खनिका (उड़िया), वॉकिंग विद द विंड (लद्दाखी), सीमाबाधा (बांग्ला), सोनार केला (बांग्ला), बैश्य श्रवण (बांग्ला), खारिज (बांग्ला)* शामिल थीं।

भारत समारोह, कतर, दोहा

फिल्म समारोह निदेशालय ने भारतीय दूतावास, दोहा के सहयोग से अप्रैल, 2019 में भारत–कतर संस्कृति/समारोह वर्ष का आयोजन किया।

समारोह में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता और भारतीय पैनोरमा चयनित फिल्में *शंखाचिल (बांग्ला), चित्राकार (बांग्ला), माछेर झोल (बांग्ला), बिसर्जन (बांग्ला), एयरलिफ्ट (हिंदी), बाजीराव मस्तानी (हिंदी), सुल्तान (हिंदी), न्यूटन हिंदी), जॉली एलएलबी–2 (हिंदी), अक्टूबर (हिंदी), राज़ी (हिंदी), टाइगर जिंदा है (बांग्ला), कैडु पुक्कुनना नेरम (मलयालम), टेक ऑफ*

(मलयालम), पूमाराम (मलयालम), ई. मा.योवी (मलयालम), रिंगन (मराठी), मुरम्बा (मराठी), रेडू (मराठी), आमही दोगी (मराठी), इरुधि सुत्रु (तमिल), पेरियेरम पेरुमल बीए.बीएल (तमिल), पेरानबू (तमिल), महानति (तेलुगु) का प्रदर्शन किया गया।

मई, 2019

11वां बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह

बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह का 11वां संस्करण फिल्म समारोह निदेशालय के सहयोग से 1 से 5 मई, 2019 तक बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। यह पांच दिवसीय फिल्म समारोह सूचना और जनसंपर्क विभाग की ओर से की गई एक पहल है। इस समारोह में प्रदर्शित की गई फीचर फिल्मों में *अभ्यक्तो (बांग्ला), ओलु (मलयालम), बाराम (तमिल), सिंजर जसारी, सूडानी फ्रॉम नाइजीरिया (मलयालम), भोर (हिंदी)* शामिल थीं।

चित्रभारती – भारतीय फिल्म समारोह

चित्रभारती – भारतीय फिल्म समारोह फिल्म समारोह निदेशालय के सहयोग से 14 से 19 मई, 2019 तक वेलिंग्कर संस्थान, माटुंगा और विवियाना मॉल ठाणे में आयोजित किया गया। इस छह दिवसीय फिल्म समारोह प्रभात चित्र मंडल की पहल है। इस समारोह के दौरान प्रदर्शित फीचर फिल्मों में *सूडानी फ्रॉम नाइजीरिया (मलयालम), भयानकम (मलयालम), विलेज रॉकस्टार्स (असमिया), ई. मा. योवी (मलयालम)*, शामिल थीं।

कान्स फिल्म समारोह 2019 में भारतीय मंडप

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव श्री अमित खरे ने कान्स फिल्म समारोह 2019 में 15.06.2019 को भारतीय मंडप का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मार्शे डू फिल्म, कान्स फिल्म मार्केट के कार्यकारी निदेशक श्री जेरोम पिलार्ड, सीबीएफसी के अध्यक्ष श्री प्रसून जोशी और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता भारतीय फिल्मकार सुश्री रीमा दास भी उपस्थित थे।

भारत में फिल्म शूट करने की व्यवस्था और सरकार के प्रोत्साहन के महत्व को प्रदर्शित करने संबंधी व्यापक फिल्म गाइड के साथ इफ्फी की स्वर्ण जयंती के अवसर पर विशेष पोस्टर भी जारी किया गया।

श्री जॉन बेली के साथ एक परस्पर संवादात्मक सत्र

फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा 28 मई, 2019 को सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव श्री अमित खरे, फिल्म प्रमाणन और अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति मनमोहन सरीन और सीबीएफसी के अध्यक्ष श्री प्रसून जोशी की उपस्थिति में एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के अध्यक्ष श्री जॉन बेली के साथ परस्पर संवादात्मक सत्र का आयोजन किया गया। इस आयोजन के दौरान अनेक मास मीडिया संस्थानों के नवोदित फिल्मकारों और छात्रों को बातचीत के लिए एकेडेमी अध्यक्ष श्री जॉन बेली

एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज के अध्यक्ष श्री जॉन बेली के साथ 28 मई, 2019 को आयोजित इंटरैक्टिव सत्र

ही नहीं, बल्कि –मास्टर सिनेमेटोग्राफर श्री जॉन बेली – के साथ भी बातचीत करने का अवसर मिला।

जून, 2019

भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह, 2019

फिल्म समारोह निदेशालय ने आगामी भारतीय अन्तरराष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह की स्वर्ण जयंती मनाई जाएगी।

जून में डीएफएफ को विभिन्न खण्डों के लिए अंतरराष्ट्रीय फिल्मों की प्रविष्टियां मिली।

भारतीय पैनोरमा एक महत्वपूर्ण खण्ड है जहां हर साल 26 फीचर और 21 गैर फीचर समकालीन का चयन किया जाता है।

मंत्रालय द्वारा भारतीय पैनोरमा 2019 के नियमों का अनुमोदन किया जा चुका है। भारतीय पैनोरमा के लिए देश भर के सभी फिल्म निर्माण उद्योगों से प्रविष्टियां शुरू की जाएंगी।

जुलाई, 2019

सार्क फ़िल्म समारोह, 2019

फ़िल्म समारोह निदेशालय, डीएफएफ ने भारतीय पैनोरमा चयनित पांच फिल्मों का नामांकन किया। श्रीलंका के कोलंबो

में 2 से 7 जुलाई, 2019 तक आयोजित सार्क फिल्म समारोह के लिए तीन फीचर फिल्मों और दो लघु फिल्मों को विभिन्न वर्गों में नामांकित किया गया। फीचर फिल्म **नगरकीर्तन (बांग्ला)** *को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक– श्री कौशिक गांगुली, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता– श्री रिद्धि सेन और बेस्ट ओरिजनल स्कोर– श्री प्रबुद्ध बनर्जी और* **ना बोले वो हराम (मराठी)** *को सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म और* **वाकिंग विद द विंड (लद्दाखी)** को स्पेशल जूरी डायरेक्शन एंड स्टोरी से सम्मानित किया गया।

अगस्त, 2019

11वां राष्ट्रीय केरल फिल्म समारोह एनएफएफके

फिल्म समारोह निदेशालय ने मुवट्टुपुझा, एर्नाकुलम में केरल राज्य चलचित्र अकादमी द्वारा 10 से 14 अगस्त, 2019 को आयोजित पांच दिवसीय 11वें राष्ट्रीय केरल फिल्म समारोह एनएफएफके में भाग लिया। 11वें राष्ट्रीय केरल फिल्म समारोह एनएफएफके में दिवंगत श्री रितुपर्णो घोष पर आयोजित रेट्रोस्पेक्टिव खण्ड में **शोभ चरित्रो काल्पोनिक** *(बांग्ला),* **चित्रांगदा** *(बांग्ला)* **सत्यान्वेशी** *(बांग्ला)* का प्रदर्शन किया गया।

46वां टेलुराइड फिल्म समारोह

फ़िल्म समारोह निदेशालय ने टेलुराइड, कोलोराडो में 30 अगस्त से 2 सितंबर, 2019 तक 46वें टेलुराइड फिल्म समारोह में भाग लिया। 46वें टेलुराइड फिल्म समारोह में सुश्री अपर्णा सेन द्वारा निर्देशित **मिस्टर एंड मिसेज अय्यर** की स्क्रीनिंग हुई।

सितम्बर, 2019

भारतीय पैनोरमा फ़िल्म समारोह, तिरुअनंतपुरम

फिल्म समारोह निदेशालय ने तिरुअनंतपुरम में 21 से 30 सितंबर, 2019 तक आयोजित भारतीय पैनोरमा फ़िल्म समारोह में भाग लिया। इस दस दिवसीय फिल्म समारोह का आयोजन सूर्या स्टेज एंड फिल्म सोसाइटी द्वारा किया गया। भारतीय पैनोरमा फिल्म समारोह के दौरान निम्नलिखित फिल्मों का प्रदर्शन किया गया–**आमि दोघी (मराठी), अभ्यक्तो (बांग्ला), बाराम (तमिल), भोर (हिंदी), धप्पा (मराठी), मक्काना (मलयालम), ओलु (मलयालम), पद्ढायी टुल्लू, पद्मावत (हिंदी), सा (बांग्ला), टू लेट (तमिल), उमा (बांग्ला), उरंचोंदी (बांग्ला), वॉकिंग विद द विंड (लद्दाखी)।**

वार्षिक फिल्म समारोह, पुद्दुचेरी

सूचना और प्रचार निदेशालय, पुद्दुचेरी सरकार द्वारा फिल्म समारोह निदेशालय के सहयोग से 13 से 17 सितंबर, 2019 तक पांच दिवसीय वार्षिक फिल्म समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में भारतीय पैनोरमा चयनित फिल्मों **पेरियेरम पेरुमल बीए.बीएल (तमिल), अबयक्तो (बांग्ला), सूडानी फ्रॉम नाइजीरिया (मलयालम), महानति (तेलुगु), राज़ी (हिंदी)** का प्रदर्शन किया गया।

अक्टूबर, 2019

महात्मा गांधी की 150वीं जयंती

बिहार राज्य फिल्म विकास और वित्त निगम लिमिटेड ने पटना, बिहार में फिल्म समारोह निदेशालय के सहयोग से 1 से 7 अक्टूबर, 2019 तक महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई। इस अवसर पर समारोह में निम्नलिखित फिल्में दिखाई गईं। **गांधी (हिंदी), मेकिंग ऑफ महात्मा (हिंदी), और सरदार (हिंदी)।**

5वां शिमला अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह

हिमाचल प्रदेश के शिमला में फिल्म समारोह निदेशालय के सहयोग से 4 से 6 अक्टूबर, 2019 तक 5वां शिमला अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित किया गया। इस तीन दिवसीय फिल्म समारोह में **विलेज रॉकस्टार्स (असमिया), महानति (तेलुगू), वॉकिंग विद द विंड (लद्दाखी), ओलु (मलयालम), बाराम (तमिल), टू लेट (तमिल)** फीचर फिल्मों का प्रदर्शन किया गया।

16वां यामागाटा अंतरराष्ट्रीय वृत्तचित्र फिल्म समारोह

फिल्म समारोह निदेशालय ने 10 से 17 अक्टूबर, 2019 तक जापान के यामागाता में आयोजित यामागाटा अंतरराष्ट्रीय वृत्तचित्र फिल्म समारोह में भाग लिया। इस आठ दिवसीय फिल्म समारोह में **द मानपाज़ ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर; ऑर्किड्स ऑफ मणिपुर, मणिपुर; यलोही जागोइ मणिपुर** का प्रदर्शन किया गया।

14वां अंतरराष्ट्रीय लघु फिल्म समारोह साइप्रस

फिल्म समारोह निदेशालय के सहयोग से अंतरराष्ट्रीय लघु फिल्म समारोह का 14वां संस्करण 12 से 18 अक्टूबर, 2019 तक आयोजित किया गया। इस सात दिवसीय फिल्म समारोह में फीचर फिल्मों **आईशपथ (मराठी), भार दुपारी (मराठी),**

बर्निंग (हिंदी), हैप्पी बर्थडे (मराठी), मलाई (मराठी), मिडनाइट रन (मलयालम), मॉनीटर (उड़िया), ना बोले वो हराम (मलयालम), सम्पूर्णम (बांग्ला), साइलेंट स्क्रीम (मराठी) का प्रदर्शन किया गया।

नवम्बर, 2019

भारतीय पैनोरमा फिल्म समारोह, 2019

फिल्म समारोह निदेशालय ने सुचित्रा फिल्म सोसाइटी द्वारा बेंगलुरु में 7 से 14 नवंबर, 2019 तक आयोजित भारतीय पैनोरमा फिल्म समारोह में भाग लिया। इस दौरान *ओलु (मलयालम), नगरकीर्तन (बांग्ला), सा (बांग्ला), उमा (बांग्ला), अभ्यक्तो (बांग्ला), उरोनचोंडी (बांग्ला), अक्टूबर (हिंदी), भोर (हिंदी), सिंजर जसारी, वॉकिंग विद द विंड (लद्दाखी), भयानकम (मलयालम), मक्काना (मलयालम), पूमारम (मलयालम), सूडानी फ्रॉम नाइजीरिया (मलयालम), ई.मा. योवी (मलयालम), धप्पा (मराठी), आमी दोघी (मराठी), टू लेट (तमिल), पेरियेरम पेरुमल (तमिल), पेरनबू (तमिल)* का प्रदर्शन किया गया।

50वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह

फिल्म समारोह निदेशालय प्रत्येक वर्ष नवंबर में भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन करता है। इस कार्यक्रम का विवरण इस प्रकार है :

50वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह का उद्घाटन माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने गोवा में 20 नवंबर, 2019 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव श्री अमित खरे, अपर सचिव, श्री अतुल कुमार तिवारी, समारोह निदेशक श्री चैतन्य प्रसाद और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता श्री अमिताभ बच्चन और आइकन ऑफ गोल्डन जुबली

50वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह के अवसर पर इफ्फी के मुख्य अतिथि सुपरस्टार श्री अमिताभ बच्चन को 20 नवंबर, 2019 को गोवा के पणजी में सम्मानित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, सूचना एवं प्रसारण तथा भारी उद्यम और लोक उपक्रम मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर, इफ्फी के मुख्य अतिथि सुपरस्टार श्री रजनीकांत और गोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत भी उपस्थित थे

एडिशन ऑफ इफ्फी श्री रजनीकांत, सहित अन्य फिल्मी हस्तियों की उपस्थिति में किया, जिन्हें भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। फ्रांसीसी अभिनेत्री सुश्री इसाबेल हुपर्ट को इफ्फी में लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। उद्घाटन के बाद फिल्म ''डिस्पाइट द फॉग'' का प्रदर्शन किया गया।

इफ्फी के उद्घाटन के बाद 21 नवंबर को इफ्फी के एक प्रमुख प्रतिस्पर्धी खंड भारतीय पैनोरमा का उद्घाटन किया गया। इस खंड का उद्घाटन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सचिव श्री अमित खरे, अपर सचिव श्री अतुल कुमार तिवारी, समारोह निदेशक श्री चैतन्य प्रसाद, एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अमित सतीजा और उद्घाटन फिल्म के प्रतिनिधियों, फीचर और गैर फीचर दोनों तथा प्रख्यात जूरी सदस्यों ने किया।

21 नवंबर को, श्री अमिताभ बच्चन ने दादा साहेब फाल्के रेट्रोस्पेक्टिव पैकेज का भी उद्घाटन किया, जिसके तहत समारोह की पूरी अवधि में उनकी 6 चुनिंदा फिल्मों का प्रदर्शन किया गया।

इफ्फी के 50वें संस्करण में, 24 नवंबर को मिड फेस्ट फिल्म "ट्रॉमफेबरिक" सहित 76 देशों की 190 फिल्मों, 90 भारतीय प्रीमियर, 6 वर्ल्ड प्रीमियर और 11 एशियन प्रीमियर का प्रदर्शन किया गया। भारतीय पैनोरमा सेक्शन में, 13 विभिन्न भाषाओं में 26 फीचर फिल्मों और 8 अलग–अलग भाषाओं में 21 गैर–फीचर फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा, भारतीय खंड में 76 फिल्मों का प्रदर्शन किया गया, जिनमें की सम्मानित हस्तियों की फिल्में, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार रेट्रोस्पेक्टिव फिल्में, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए विशेष पैकेज और अन्य क्लासिक भारतीय फिल्म पैकेज शामिल थे।

8 दिनों के समारोह के दौरान 10 स्क्रीन पर प्रतिदिन लगभग 5 फिल्मों के साथ कुल 315 फिल्में प्रदर्शित की गईं। समारोह के दौरान अन्य स्थानों पर 35 से अधिक मास्टर क्लासेज और चर्चा सत्र आयोजित किए गए। इनमें संगीत रचना में मास्टर क्लास लेने वाले श्री इलैयाराजा सहित आमंत्रित प्रतिनिधि और फिल्मी हस्तियां शामिल थीं। इस दौरान रेड कार्पेट सहित पत्र सूचना कार्यालय के सहयोग से संवाददाता सम्मेलनों का आयोजन किया गया, ताकि फिल्मकार और मशहूर हस्तियां मीडिया और दर्शकों के साथ बातचीत कर सकें। इन्हें दूरदर्शन द्वारा कवर किया गया।

28 नवंबर, 2019 को समारोह के समापन समारोह के दौरान श्री इलैयाराजा और अन्य प्रसिद्ध फिल्मी हस्तियों को भी सम्मानित किया गया। समापन समारोह 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के थीम पर आयोजित किया गया, जिसमें कई नृत्य प्रदर्शनों के साथ नृत्य और संगीत की जुगलबंदी भी प्रस्तुत की गई। फिल्म मार्गी एंड हर मदर के भारतीय प्रीमियर के साथ इफ्फी का समापन हो गया था।

28 नवंबर, 2019 को पणजी, गोवा में 50वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह (इफ्फी–2019) के समापन समारोह में, वरिष्ठ अभिनेता श्री प्रेम चोपड़ा को सम्मानित किया गया। गोवा के राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक और गोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत भी इस अवसर पर मौजूद थे

समापन समारोह में, इफ्फी के पुरस्कार खंड की भी घोषणा की गई, जो इस प्रकार हैः

निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फीचर फिल्म :

1. अबू लैला के लिए अमीन सिदी बाउमिडेन
2. मॉन्स्टर्स के लिए मारियस ओल्टेनु

आईसीएफटी–यूनेस्को गांधी मेडल : रवांडा

विशेष उल्लेख : हेल्लारो

पुरस्कार श्रेणी	विजेता
गोल्डन पीकॉक अवार्ड	पार्टिकल्स
सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार	लिजो जोस पेलिसरी
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार	सेउ जोर्ज
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार	उषा जाधव
विशेष जूरी पुरस्कार	'बैलून' के लिए पेमा सेदेन

सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फीचर फिल्म के निर्देशक	अबू लीला के लिए अमीन सिदी बाउमिडेन, मॉन्स्टर्स के लिए मारियस ओल्टेनु
विशेष उल्लेख	हेल्लारो
आईसीएफटी–यूनेस्को गांधी मेडल	रवांडा
आईसीएफटी–यूनेस्को गांधी मेडल के तहत विशेष उल्लेख	बहत्तर हूरें

28 नवंबर, 2019 को गोवा के पणजी में भारतीय फिल्म हेल्लारो (गुजराती) के निर्देशक श्री अभिषेक शाह को 50वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह (इफ्फी–2019) के समापन समारोह में विशेष उल्लेखनीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया

इंडिया हैबिटेट सेंटर

फिल्म समारोह निदेशालय के सहयोग से नवंबर में इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में एक समारोह आयोजित किया गया था। समारोह के दौरान फिल्म *मेघे ढाका तारा (बांग्ला)* प्रदर्शित की गई।

केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड

1. फ़िल्म निर्माण और फ़िल्मों के प्रदर्शन का संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि ये कला के सर्वाधिक व्यापक और लोकतांत्रिक माध्यम समझे गए हैं। जनमत तैयार करने, ज्ञान प्रदान करने और विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति एवं लोक परंपराओं को समझने में फ़िल्मों की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में फ़ीचर फ़िल्मों का निर्माण अधिकतर निजी क्षेत्र में किया जा रहा है।

2. हमारा संविधान भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी देता है, परंतु यह स्वतंत्रता "भारत की सार्वभौमिकता और अखंडता, राष्ट्र की सुरक्षा, विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार और नैतिकता तथा अदालत की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के लिए उकसाने जैसे मामले को ध्यान में रख कर तर्कसंगत प्रतिबंधों के अधीन है।" संविधान के इन प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए भारत में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फ़िल्म प्रमाणन में बोर्ड का मार्गदर्शन करने वाले बुनियादी सिद्धांत सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952 में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त फ़िल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन की उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए अधिनियम की धारा 5बी(2) के अंतर्गत केंद्र सरकार ने विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं।

3. सार्वजानिक प्रदर्शन के लिए फ़िल्मों की मंजूरी देने के प्रयोजन हेतु केंद्र सरकार ने सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952 की धारा 3 के अंतर्गत फ़िल्म सेंसर बोर्ड का गठन किया। वर्तमान बोर्ड में एक अध्यक्ष और 12 गैर–सरकारी सदस्य हैं, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। बोर्ड के सदस्यों के नियुक्ति के लिए अनुवर्ती अधिसूचनाओं के साथ समय–समय पर नामित होता है।

4. बोर्ड मुंबई में अपने मुख्यालय और मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, तिरुअनंतपुरम, दिल्ली, कटक और गुवाहाटी में नौ क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ काम करता है। क्षेत्रीय कार्यालयों का नेतृत्व क्षेत्रीय अधिकारियों/ अपर क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा किया जाता है। बोर्ड और सलाहकार पैनलों के सदस्य समाज के व्यापक वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनमें शिक्षाविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, गृहिणियों, फ़िल्मी हस्तियों, डॉक्टरों, पत्रकारों आदि जैसे सभी क्षेत्रों के लोगों को शामिल होते हैं।

5. बे–रोकटोक सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली फ़िल्मों को "यू" प्रमाण–पत्र दिया जाता है। ऐसी फ़िल्में जो बे–रोकटोक सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त समझी गई, लेकिन 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए माता–पिता के मार्गदर्शन की अपेक्षा रखती है, उन्हें "यूए" प्रमाण–पत्र दिया जाता है, साथ

ही माता–पिता के लिए इस आशय की चेतावनी दे दी जाती है। गैर–वयस्कों के लिए अनुपयुक्त, परन्तु वयस्कों के लिए उपयुक्त समझी गई फिल्मों को ''ए'' प्रमाण–पत्र दिया जाता है। आम जनता के लिए अनुपयुक्त, परन्तु डॉक्टरों आदि विशेषज्ञतापूर्ण दर्शकों के समक्ष प्रदर्शन के लिए उपयुक्त फ़िल्मों को "एस" प्रमाण–पत्र दिया जाता है। सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए अनुपयुक्त समझी गई फ़िल्मों को प्रमाण–पत्र नहीं दिया जाता।

फ़िल्म प्रमाणन

6. भारत विश्व के प्रमुख फ़िल्म निर्माता देशों में से एक है। बीते वर्षों के दौरान प्रमाणित की गई भारतीय फ़ीचर फ़िल्मों की संख्या में निरंतर वृद्धि देखी गई है।

अप्रैल, 2019 से दिसंबर, 2019 के दौरान बोर्ड ने कुल **16269** प्रमाण–पत्र जारी किए, जिनमें से सेल्यूलॉइड फ़िल्मों को **'शून्य'** प्रमाण–पत्र जारी किए गए, वीडियो फ़िल्मों को **5981** प्रमाण–पत्र और डिजिटल फ़िल्मों को **10288** प्रमाण–पत्र जारी किए गए।

डिजिटल

अप्रैल, 2019 से दिसंबर, 2019 के दौरान डिजिटल फ़िल्मों को कुल **10288** प्रमाण–पत्र जारी किए गए। इनमें से **1943** प्रमाण–पत्र भारतीय फ़ीचर फ़िल्मों को, **225** विदेशी फ़ीचर फ़िल्मों को, **7703** भारतीय लघु फ़िल्मों को और **417** विदेशी लघु फ़िल्मों को दिए गए।

वीडियो

इसी प्रकार **5981** प्रमाण–पत्रों में से, **611** प्रमाण–पत्र भारतीय फ़ीचर फ़िल्मों को जारी किए गए, 681 विदेशी फ़ीचर फ़िल्मों को, **4451** भारतीय लघु फ़िल्मों को और **238** विदेशी लघु फ़िल्मों को जारी किए गए।

सेल्युलाइड

सेल्युलाइड फॉर्मेट में **'शून्य'** प्रमाण–पत्र जारी किया गया।

अप्रैल, 2019 से दिसंबर, 2019 की अवधि में प्रमाणित फ़िल्मों के प्रमाण–पत्रवार और श्रेणीवार ब्योरा अनुलग्नक–I में दिया गया;

7. **अनुलग्नक–II और III** में भारतीय फीचर सेल्युलाइड फ़िल्मों के क्षेत्रवार/भाषावार और विषयवार वर्गीकरण दिया गया है। **अनुलग्नक–IV** में भारतीय फीचर डिजिटल फ़िल्मों का क्षेत्रवार और भाषावार ब्योरा दिया गया है। सबसे अधिक फ़िल्में हिंदी भाषा में बनीं और उसके बाद कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम आदि का स्थान है। **अनुलग्नक–V** में भारतीय फीचर डिजिटल फ़िल्मों का विषयवार वर्गीकरण है। **अनुलग्नक–VI** में विदेशी फीचर डिजिटल फ़िल्मों की क्षेत्रवार और राष्ट्रवार जानकारी दी गई है और **अनुलग्नक–VII** में विदेशी फ़ीचर डिजिटल फ़िल्मों का विषयगत वर्गीकरण विवरण है। **अनुलग्नक–VIII** में भारतीय फीचर वीडियो फिल्मों का क्षेत्रवार और भाषावार विवरण है और **अनुलग्नक–IX** में विदेशी फीचर वीडियो फिल्मों का क्षेत्रवार और राष्ट्रवार विवरण है।

बोर्ड बैठक/क्षेत्रीय अधिकारियों की बैठक

8. इस अवधि के दौरान, **एक** बोर्ड बैठक–सह–कार्यशाला और **एक** क्षेत्रीय अधिकारियों की बैठक–सह–कार्यशाला आयोजित की गई थीं, जिनका विवरण निम्नलिखित है :

I) 147वीं बोर्ड बैठक–सह–कार्यशाला मुंबई में 1 सितंबर, 2019 को होटल ट्राइडेंट, बीकेसी में आयोजित की गई। बोर्ड बैठक की अध्यक्षता सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष श्री प्रसून जोशी ने की।

सीबीएफसी के अध्यक्ष श्री प्रसून जोशी 147वीं बोर्ड बैठक कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए

II) क्षेत्रीय अधिकारियों की बैठक–सह– कार्यशाला 1 सितंबर, 2019 को होटल ट्राइडेंट, बीकेसी, मुंबई में आयोजित की गई।

महत्वपूर्ण कार्यक्रम

9. फिल्म जगत और बोर्ड के सदस्यों के बीच 31 अगस्त, 2019 को होटल ट्राइडेंट, बीकेसी, मुम्बई में बातचीत हुई। बातचीत के दौरान सीबीएफसी ने नए लोगो और नए डिजाइन किए गए प्रमाणपत्र का भी अनावरण किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष श्री प्रसून जोशी ने की। माननीय सूचना एवं प्रसारण और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी इस अवसर की शोभा बढ़ाई। इस कार्यक्रम में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव श्री अमित खरे ने भी भाग लिया।

शिकायतें

10. सेंसर बोर्ड को फ़िल्मों के प्रमाणन के संबंध में जनता से निरंतर शिकायतें मिलने का सिलसिला जारी रहा। ये शिकायतें मुख्यतः सेक्स, धर्म, पर्दे पर हिंसा आदि से संबंधित थीं। अधिकतर शिकायतें सामान्य किस्म की थीं। जिन पर प्रमाणन की प्रक्रिया के दौरान उनके महत्व के आधार पर विधिवत विचार किया गया।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर 31 अगस्त, 2019 को मुम्बई में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के नए लोगो और प्रमाण पत्र के डिजाइन का अनावरण करते हुए

प्रमाणीकरण शुल्क

11. प्रमाणीकरण शुल्क के रूप में **10,68,10,550** रुपये वसूल किए गए।

12. मंत्रालय के दिनांक 24 सितंबर, 2007 के आदेश संख्या 807/3/2007 के तहत कुछ श्रेणियों की फ़िल्मों को प्रमाणन से संबंधित प्रावधान से छूट दी गई है।

महत्वपूर्ण सूचना

13. आवेदन (ई–सिनेप्रमाण) में ''अतिरिक्त सूचना'' नामक एक अतिरिक्त पृष्ठ जोड़ने के संबंध में एक महत्वपूर्ण पत्र संख्या 16 दिनांक 22 नवंबर, 2019 को जारी किया गया। ''अतिरिक्त सूचना'' के लिए पृष्ठ फिल्म के कलाकारों और श्रेय संबंधी विवरण उपलब्ध कराने के लिए शामिल

किया गया। यह दर्शकों को प्रमाण पत्र पर क्यूआर कोड की स्कैनिंग के माध्यम से फिल्म की कहानी के सार की जानकारी प्राप्त करने और उसके ट्रेलर/प्रोमो को देखने की भी अनुमति प्रदान करता है।

अनुलग्नक–I

1–4–2019 से 31–12–2019 तक की अवधि में बोर्ड द्वारा प्रमाणित फ़िल्मों का समेकित विवरण

सेल्युलाइड									
	यू	यू*	यूए	यूए*	ए	ए*	एस	एस*	कुल
भारतीय फ़ीचर फ़िल्में	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी फ़ीचर फ़िल्में	-	-	-	-	-	-	-	-	-
भारतीय लघु फ़िल्में	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी लघु फ़िल्में	-	-	-	-	-	-	-	-	-
फ़ीचर के अलावा भारतीय फ़ीचर फ़िल्में	-	-	-	-	-	-	-	-	-
फ़ीचर के अलावा विदेशी फ़ीचर फ़िल्में	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल (ए)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वीडियो									
	यू	यू*	यूए	यूए*	ए	ए*	एस	एस*	कुल
भारतीय फ़ीचर फ़िल्में	149	53	174	230	1	4	-	-	611
विदेशी फ़ीचर फ़िल्में	88	20	311	255	6	1	-	-	681
भारतीय लघु फ़िल्में	3104	100	1105	102	39	1	-	-	4451
विदेशी लघु फ़िल्में	116	0	116	6	0	0	-	-	238
फ़ीचर के अलावा भारतीय फ़ीचर फ़िल्में	0	0	0	0	0	0	-	-	0
फ़ीचर के अलावा विदेशी फ़ीचर फ़िल्में	0	0	0	0	0	0	-	-	0
कुल (बी)	**3457**	**173**	**1706**	**593**	**46**	**6**	**-**	**-**	**5981**
डिजिटल									
	यू	यू*	यूए	यूए*	ए	ए*	एस	एस*	कुल
भारतीय फ़ीचर फ़िल्में	467	277	358	668	49	124	-	-	1943
विदेशी फ़ीचर फ़िल्में	45	11	58	37	35	39	-	-	225
भारतीय लघु फ़िल्में	6574	81	857	132	50	9	-	-	7703
विदेशी लघु फ़िल्में	154	0	236	13	13	1	-	-	417
फ़ीचर के अलावा भारतीय फ़ीचर फ़िल्में	0	0	0	0	0	0	-	-	0
फ़ीचर के अलावा विदेशी फ़ीचर फ़िल्में	0	0	0	0	0	0	-	-	0
कुल (सी)	**7240**	**369**	**1509**	**850**	**147**	**173**	**-**	**-**	**10288**
कुल जोड़ (ए+बी+सी)	**10697**	**542**	**3215**	**1443**	**193**	**179**	**-**	**-**	**16269**

*कट्स के साथ

अनुलग्नक–II

1–4–2019 से 31–12–2019 तक बोर्ड द्वारा प्रमाणित भारतीय फीचर फ़िल्मों का समेकित विवरण

क्षेत्रवार–भाषावार

(सेल्युलाइड)

क्रम	भाषा	मुंबई	चेन्नई	कोलकाता	बेंगलुरु	हैदराबाद	तिरुअनंतपुरम	दिल्ली	कटक	गुवाहाटी	कुल
		शून्य									
		शून्य									

अनुलग्नक–III

1–4–2019 से 31–12–2019 तक बोर्ड द्वारा प्रमाणित भारतीय फीचर फ़िल्मों का समेकित विवरण

विषयवार वर्गीकरण

(सेल्युलाइड)

क्रम	भाषा	मुंबई	चेन्नई	कोलकाता	बेंगलुरु	हैदराबाद	तिरुअनंतपुरम	दिल्ली	कटक	गुवाहाटी	कुल
		शून्य									
		शून्य									

अनुलग्नक–IV

1–4–2019 से 31–12–2019 तक बोर्ड द्वारा प्रमाणित भारतीय फीचर फ़िल्मों का समेकित विवरण

क्षेत्रवार–भाषावार

(डिजिटल)

क्रम	भाषा	मुंबई	चेन्नई	कोलकाता	हैदराबाद	बेंगलुरु	तिरुअनंतपुरम	दिल्ली	कटक	गुवाहाटी	कुल
1	हिंदी	316	-	10	-	-	-	11	6	2	**345**
2	कन्नड़	1	2	-	3	281	-	-	-	-	**287**
3	तेलुगु	4	34	1	202	11	5	-	-	-	**257**
4	तमिल	4	189	1	17	3	1	-	-	-	**215**
5	मलयालम	1	11	-	6	4	186	-	-	-	**208**
6	बांग्ला	1	-	144	-	-	-	-	1	-	**146**
7	मराठी	119	-	-	-	-	-	1	-	-	**120**
8	भोजपुरी	71	-	4	-	-	-	3	-	-	**78**

9	पंजाबी	36	-	-	-	-	-	24	-	-	**60**
10	गुजराती	45	-	-	-	-	-	1	-	-	**46**
11	ओड़िया	1	-	-	-	-	-	-	34	-	**35**
12	असमिया	-	-	-	-	-	-	-	-	22	**22**
13	छत्तीसगढ़ी	5	-	-	-	-	-	-	14	-	**19**
14	अंग्रेजी	11	1	1	-	1	-	1	-	-	**15**
15	टुलु	-	-	-	-	11	-	-	-	-	**11**
16	मणिपुरी	-	-	-	-	-	-	-	-	10	**10**
17	कोंकणी	5	.	-	-	4	-	-	-	-	**9**
18	खासी	-	-	-	-	-	-	-	-	7	**7**
19	राजस्थानी	4	-	-	-	-	-	2	-	-	**6**
20	नागपुरी	3	-	2	-	-	-	-	-	-	**5**
21	नेपाली	-	-	4	-	-	-	1	-	-	**5**
22	बंजारा	-	-	-	2	2	-	-	-	-	**4**
23	संस्कृत	1	-	-	-	-	2	-	-	-	**3**
24	बीयरी	-	-	-	-	2	-	-	-	-	**2**
25	बोडो	-	-	-	-	-	-	-	-	2	**2**
26	गढ़वाली	-	-	-	-	-	-	2	-	-	**2**
27	हिंगलिश	2	-	-	-	-	-	-	-	-	**2**
28	खोरठा	1	-	1	-	-	-	-	-	-	**2**
29	कोडावा	-	-	-	-	2	-	-	-	-	**2**
30	हिंदी आंशिक अंग्रेजी	2	-	-	-	-	-	-	-	-	**2**
31	उर्दू	-	-	-	2	-	-	-	-	-	**2**
32	अवधी	1	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**
33	बयारी	-	-	-	-	1	-	-	-	-	**1**
34	अंग्रेजी आंशिक हिंदी	1	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**
35	हरियाणवी	1	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**
36	हिंदी में डब	1	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**
37	हिंदी आंशिक अवधी	1	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**
38	हिंदी आंशिक मराठी	1	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**

39	कुमाऊंनी	1	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**
40	मणिपुरी (मेतिइलोन)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	**1**
41	मिशिंग आंशिक असमिया	-	-	-	-	-	-	-	-	1	**1**
42	मोनपा	-	-	-	-	-	-	-	-	1	**1**
43	नागामीज़	-	-	-	-	-	-	-	-	1	**1**
44	पनिया	-	-	-	-	-	1	-	-	-	**1**
45	राजबंशी	-	-	1	-	-	-	-	-	-	**1**
46	सादरी	-	-	-	-	-	-	-	-	1	**1**
47	संथाली	-	-	1	-	-	-	-	-	-	**1**
48	तमिल में डब	-	-	-	-	1	-	-	-	-	**1**
49	तेलुगु में डब	-	-	-	-	1	-	-	-	-	**1**
50	टुलू आंशिक कन्नड़	-	-	-	-	1	-	-	-	-	**1**
	कुल जोड़	**640**	**232**	**170**	**232**	**325**	**195**	**46**	**55**	**48**	**1943**

अनुलग्नक–V

1–4–2019 से 31–12–2019 बोर्ड द्वारा प्रमाणित

भारतीय फीचर फ़िल्मों का समेकित विवरण

विषयवार वर्गीकरण

(डिजिटल)

क्रम	विषयवार वर्गीकरण	मुंबई	चेन्नई	कोलकाता	हैदराबाद	बेंगलुरु	तिरुअनंतपुरम	दिल्ली	कटक	गुवाहाटी	कुल
1	फीचर	627	231	169	232	297	189	45	55	47	**1892**
2	बाल फ़िल्में	7	-	-	-	26	5	-	-	1	**39**
3	वृतचित्र	2	-	1	-	-	1	-	-	-	**4**
4	सामाजिक	3	-	-	-	-	-	-	-	-	**3**
5	शैक्षिक	1	-	-	-	1	-	-	-	-	**2**
6	जीवन संबंधी	-	-	-	-	1	-	-	-	-	**1**
7	एनिमेशन (फीचर)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	**1**
8	अन्य	-	1	-	-	-	-	-	-	-	**1**
	कुल योग	**640**	**232**	**170**	**232**	**325**	**195**	**46**	**55**	**48**	**1943**

अनुलग्नक–VI

1–4–2019 से 31–12–2019 तक बोर्ड द्वारा प्रमाणित विदेशी फीचर फ़िल्मों का समेकित विवरण

क्षेत्र–वार – देश–वार

(डिजिटल)

क्रम	मूल देश/क्षेत्र	मुंबई	चेन्नई	कोलकाता	हैदराबाद	बेंगलुरु	तिरुअनंतपुरम	दिल्ली	कटक	गुवाहाटी	कुल
1	अमरीका	105	37	-	-	-	-	-	-	-	**142**
2	हंगरी	22	2	-	-	-	-	-	-	-	**24**
3	आस्ट्रेलिया	6	4	-	-	-	-	-	-	-	**10**
4	ब्रिटेन	9	1	-	-	-	-	-	-	-	**10**
5	जापान	6	3	-	-	-	-	-	-	-	**9**
6	संयुक्त अरब अमीरात	8	-	-	-	-	-	-	-	-	**8**
7	फ्रांस	4	2	-	-	-	-	-	-	-	**6**
8	हांगकांग	5	-	-	-	-	-	-	-	-	**5**
9	कनाडा	2	-	-	-	-	-	-	-	-	**2**
10	दक्षिण कोरिया	2	-	-	-	-	-	-	-	-	**2**
11	यूक्रेन	1	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**
12	बांग्लादेश	1	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**
13	चीन	1	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**
14	जर्मनी	1	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**
15	आयरलैंड	1	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**
16	लेबनान	1	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**
17	नेपाल	1	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**
	कुल	**178**	**49**	-	-	-	-	-	-	-	**225**

अनुलग्नक–VII

1–4–2019 से 31–12–2019 तक बोर्ड द्वारा प्रमाणित विदेशी

फीचर फ़िल्मों का समेकित विवरण

विषयवार वर्गीकरण

क्रम	विषयवार वर्गीकरण	मुंबई	चेन्नई	कोलकाता	हैदराबाद	बेंगलुरु	तिरुअनंतपुरम	दिल्ली	कटक	गुवाहाटी	कुल
1	फीचर	175	49	-	-	-	-	-	-	-	224
2	वृतचित्र	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	कुल योग	**176**	**49**	-	-	-	-	-	-	-	**225**

अनुलग्नक–VIII

1–4–2019 से 31–12–2019 तक बोर्ड द्वारा प्रमाणित भारतीय फीचर फ़िल्मों का समेकित विवरण

क्षेत्रवार–भाषावार वर्गीकरण

(वीडियो)

क्रम	भाषावार वर्गीकरण	मुंबई	चेन्नई	कोलकाता	हैदराबाद	बेंगलुरु	तिरुअनंतपुरम	दिल्ली	कटक	गुवाहाटी	कुल
1	हिंदी	221	-	-	-	-	-	40	23	-	**284**
2	मलयालम	-	52	-	1	-	1	-	-	-	**54**
3	मराठी	31	-	-	-	-	-	17	-	-	**48**
4	भोजपुरी	36	-	-	-	-	-	-	6	-	**42**
5	गुजराती	22	-	-	-	-	-	11	-	-	**33**
6	मणिपुरी	-	-	-	-	-	-	-	-	28	**28**
7	तमिल	4	9	-	13	1	1	-	-	-	**28**
8	तेलुगु	-	12	-	13	2	-	-	-	-	**27**
9	बांग्ला	5	8	5	-	-	-	3	5	-	**26**
10	कन्नड़	-	1	-	-	18	-	-	-	-	**19**
11	ओड़िया	-	-	-	-	-	-	-	7	-	**7**
12	अंग्रेजी	2	-	-	1	-	-	2	-	-	**5**
13	पंजाबी	1	-	-	-	-	-	2	-	-	**3**
14	हिंगलिश	2	-	-	-	-	-	-	-	-	**2**
15	हिंदी आंशिक अंग्रेजी	1	-	-	-	-	-	1	-	-	**2**
16	हिंदी में डब	1	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**
17	सिंधी	1	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**
18	तमिल सबटाइल्स के साथ सौराष्ट्र	-	1	-	-	-	-	-	-	-	**1**
	कुल योग	**327**	**83**	**5**	**28**	**21**	**2**	**76**	**41**	**28**	**611**

अनुलग्नक–IX

1–4–2019 से 31–12–2019 तक बोर्ड द्वारा प्रमाणित विदेशी फीचर फ़िल्मों समेकित विवरण

क्षेत्रवार–देश–वार

(वीडियो)

क्रम	मूल देश	मुंबई	चेन्नई	कोलकाता	हैदराबाद	बेंगलुरु	तिरुअनंतपुरम	दिल्ली	कटक	गुवाहाटी	कुल
1	अमरीका	440	2	12	-	-	-	15	1	-	**470**
2	बांग्लादेश	26	-	16	-	-	-	14	-	-	**56**
3	हंगरी	50	1	-	-	-	-	3	-	-	**54**

4	संयुक्त अरब अमीरात	50	-	-	-	-	-	-	-	-	50
5	ब्रिटेन	6	1	-	-	-	-	-	-	-	7
6	फ्रांस	7	-	-	-	-	-	-	-	-	7
7	जर्मनी	7	-	-	-	-	-	-	-	-	7
8	हांगकांग	2	1	2	-	-	-	-	-	-	5
9	दक्षिण कोरिया	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4
10	आस्ट्रेलिया	1	3	-	-	-	-	-	-	-	4
11	थाईलैंड	2	-	-	-	-	-	1	-	-	3
12	चीन	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3
13	कनाडा	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
14	जापान	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
15	स्पेन	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
16	भारत	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
17	लेबनान	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
18	मोंनाको	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
19	नेपाल	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
20	नीदरलैंड	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
21	उत्तर कोरिया	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	कुल	**609**	**8**	**30**	-	-	-	**33**	**1**	-	**681**

बोर्ड की वित्त व्यवस्था

सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 के प्रावधान के अंतर्गत, केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड फ़िल्मों की एक सांविधिक निकाय है, जो फ़िल्मों के सार्वजानिक प्रदर्शन का नियमन करता है। हालांकि प्रशासनिक प्रयोजन के लिए बोर्ड को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत एक अधीनस्थ कार्यालय समझा जाता है।

बोर्ड को राजस्व सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 1983 में निर्दिष्ट पैमानों के अनुसार प्रमाणन शुल्क की वसूली से प्राप्त होती है। बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय में फ़िल्मों की स्क्रीनिंग के संदर्भ में प्रोजेक्शन प्रभार भी लगाता है। **1 अप्रैल, 2019 से 31 दिसंबर, 2019** की अवधि के दौरान अर्जित कुल आय **10,68,10,550** रुपये है। वसूल किया गया– राजस्व भारत के समेकित निधि में जमा किया जाता है। बोर्ड इस संबंध में कोई बैंक खाता संचालित नहीं करता।

व्यय के साथ–साथ राजस्व के लिए खातों को बनाए रखने के उद्देश्य से, बोर्ड वित्तीय वर्ष **(1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक)** भारत सरकार द्वारा अपनाई गई प्रणाली का पालन करता है। बोर्ड को मंत्रालय से विभिन्न मदों के लिए गैर–योजना व्यय के अंतर्गत अनुदान प्राप्त होता है। 1–4–2019 से 31–12–2019 तक इन मदों के अंतर्गत खर्च की राशि का विवरण निम्नलिखित है:

बजट आवंटन और व्यय

(लाख रु. में)

	गैर–योजना बी.ई (2019–20)	31 दिसंबर, 2019 तक व्यय
वेतन	575.00	382.20
चिकित्सा	11.00	4.60
डीटीई	22.00	9.62
ओई	105.00	56.12

पीपीएसएस	300.00	262.98
किराया दरें और कर	20.00	8.92
अन्य प्रशासनिक व्यय	08.00	2.99
सूचना प्रौद्योगिकी	05.00	1.74
एसएपी	02.00	1.37
कुल	**1048.00**	**730.54**

1. योजना व्यय : सेंसर बोर्ड और प्रमाणन प्रक्रिया का उन्नयन, आधुनिकीकरण और विस्तार

योजना अवधि (2019 से 2020) के तहत सीबीएफसी की प्रस्तावित योजना "सीबीएफसी और प्रमाणन प्रक्रिया का उन्नयन, आधुनिकीकरण और विस्तार" के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियों के लिए 2.50 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए और वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए 2.50 करोड़ रु की राशि (बीई के अंतर्गत) आवंटित की गई थी।

(1) फ़िल्म अनुप्रयोग और प्रमाणन वेबसाइट की ऑनलाइन प्रोसेसिंग के लिए सॉफ्टवेयर विकास।

(2) सेंसर बोर्ड के सभी कार्यालयों के लिए डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम और डिजिटल थियेटर।

(3) सेंसर बोर्ड और मुख्यालय के क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए अतिरिक्त कार्यालय स्थान की आवश्यकता। एसएफसी ने अनुमोदन नहीं दिया है, अतः कोई व्यय नहीं किया गया।

क्रं सं	बी.ई. 2019–20 के लिए (लाख रु. में)	31–12–2019 तक व्यय (लाख रु. में)
1.	250.00	57.40

2. योजना कार्यक्रम : मानव संसाधन और विकास के लिए प्रशिक्षण।

सीबीएफसी "मानव संसाधन और विकास के लिए प्रशिक्षण" कार्यक्रम 2019–20 के दौरान निम्नलिखित गतिविधियों संचालित कर रहा है :

क) क्षेत्रीय कार्यालयों और मुम्बई में बोर्ड के सदस्यों और क्षेत्रीय अधिकारियों के लिए कार्यशाला/सेमिनार/संवाद।

ख) प्रत्येक क्षेत्र में परामर्शी पैनल सदस्यों के लिए प्रशिक्षण/कार्यशालाओं।

एसबीजी : 2019–20 : रु. 25.00 (लाख)।

31–12–2019 तक व्यय: 18.96 (लाख)।

राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम (एनएफडीसी)

राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम लिमिटेड की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित राष्ट्रीय आर्थिक नीति और उद्देश्यों के अनुसार भारतीय फ़िल्म उद्योग के एकीकृत और कुशल विकास की योजना, प्रचार और आयोजन के प्राथमिक उद्देश्य के साथ की गई थी। एनएफडीसी के साथ फ़िल्म वित्त निगम (एफएफसी) और इंडियन मोशन पिक्चर एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन (आईएमपीईसी) का विलय करके एनएफडीसी को 1980 में पुनः स्थापित किया गया था। स्थापना के बाद से, एनएफडीसी ने 21 से अधिक क्षेत्रीय भाषाओं में 300 से अधिक फिल्मों को वित्तपोषित/निर्मित किया है, जिनमें से कई ने व्यापक प्रशंसा अर्जित की है और राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। स्थापना के बाद से, एनएफडीसी ने 21 से अधिक क्षेत्रीय भाषाओं में 300 से अधिक फ़िल्मों को वित्त पोषित/निर्मित किया है, जिनमें से कई ने व्यापक प्रशंसा अर्जित की है और राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। एनएफडीसी द्वारा निर्मित/सह–निर्मित कुछ महत्वपूर्ण फिल्में हैं :–

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, एनएफडीसी ने सिनेमाज ऑफ इंडिया ब्रांड के तहत फ़िल्मों के उत्पादन और वितरण को कवर करने, विभिन्न सरकारी एजेंसियों के लिए विज्ञापन, लघु और कॉरपोरेट फ़िल्मों के निर्माण, फ़िल्म प्रदर्शन, बहाली, फ़िल्म बाज़ार, डिजिटल नॉन–लीनियर एडिटिंग, सिनेमैटोग्राफी, सबटाइटलिंग आदि में प्रशिक्षण सहित कौशल विकास के लिए मीडिया और मनोरंजन उद्योग के विभिन्न वर्टिकल्स में अपनी विशिष्टता को बढ़ाना जारी रखा। इस संदर्भ में, यहां इस बात का विशेष तौर पर उल्लेख किया जा सकता है कि वितरण संबंधी गतिविधि फिल्मों के वितरण और प्रदर्शन के लिए परम्परागत थिएटरों से लेकर वीओडी जैसे डिजिटल प्रारूपों में

रिलीज तक विविध स्थापित एवं उभरते प्रारूपों तक फैली हुई है, इस प्रकार अच्छी गुणवत्ता वाला सिनेमा किफायती दामों पर भारतीय दर्शकों को उपलब्ध है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के फिल्म सुविधा कार्यालय ने हाल ही में अपना वेबपोर्टल www.ffo.gov.in जारी किया है, यह कार्यालय एनएफडीसी के कार्यात्मक तत्वावधान में हैं। इस प्रकार भारत को समस्त अंतरराष्ट्रीय फिल्मकारों के लिए अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर ऑनलाइन स्थापित कर दिया है।

1. निर्माण

फ़िल्म निर्माण विभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की "विभिन्न भारतीय भाषाओं में फ़िल्मों का निर्माण" शीर्षक वाली योजना के तहत भारतीय सिनेमा में विविधता दर्शाने वाली फ़ीचर फ़िल्मों का निर्माण/सह–निर्माण किया है। उक्त योजना के तहत, एनएफडीसी फ़िल्म निर्माण के लिए अपने मौजूदा दिशानिर्देशों के तहत फ़िल्मों का निर्माण और सह–निर्माण करता है, जिससे पहली बार फ़िल्म निर्माण करने वाले नवोदित फ़िल्म निर्माताओं को 100 प्रतिशत निर्माण तथा भारत और विदेश में अच्छी गुणवत्ता की फ़िल्मों के सह–उत्पादन का दायित्व ग्रहण करता है।

निर्माण विभाग का उद्देश्य सिनेमा में उत्कृष्टता को प्रोत्साहन देने और भारतीय सिनेमा के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने की दृष्टि से कलात्मक फिल्मों का निर्माण करने के एनएफडीसी के मिशन में सहायता प्रदान करना और उसे संचालित करना है। इस निर्देश को ध्यान में रखते हुए निर्माण विभाग भारत को सबसे कल्पनाशील, वैविध्यपूर्ण और जीवंत फिल्म संस्कृति को परिलक्षित करने वाले सिनेमा का निर्माण करने के लिए निरंतर अनुकूल वातावरण तैयार करने की दिशा में प्रयासरत है। निर्माण विभाग निर्माण और समन्वय के माध्यम से बहुमुखी और उभरते फिल्मकारों के समुदाय को सहायता प्रदान करने का प्रयास करता है, जो विविधता, नवाचार और विलक्षणता को मूर्त रूप प्रदान करते हैं।

निर्माण/सह–निर्माण के अंतर्गत निम्नलिखित हैं :–

- पैन नलिन द्वारा निर्देशित भारत–न्यूजीलैंड की ओर से सह–निर्मित फिल्म *बीयोंड द नोन वर्ल्ड* का सेंसर प्रमाणन के लिए प्रदर्शन किया गया।
- निनाद महाजनी द्वारा निर्देशित मराठी फीचर फिल्म *लाल माटी* प्रारंभ की गई।
- वर्ष 2019–20 में, मंत्रालय ने निर्माणाधीन 2 फिल्मों के. जयदेव द्वारा निर्देशित *कोरंगी नन्ची (तेलुगु)* और इंद्राणी चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित *छाड़ (बांग्ला)* तथा 3 फिल्मों यथा अमित दत्ता द्वारा निर्देशित *पेड पे कमरा (डोगरी),* होबन पाबन कुमार द्वारा निर्देशित *जोसेफकी माचा (मणिपुरी)* और सिद्धार्थ त्रिपाठी द्वारा निर्देशित *एक लाल कमीज (छत्तीसगढ़ी)* के सह–निर्माण को मंजूरी दी थी।
- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच श्रव्य–दृश्य सह–निर्माण समझौते के अंतर्गत विख्यात फिल्मकार श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित फीचर फिल्म बंगबधु (शेख मुजीबुर्रहमान के जीवन पर आधारित) के निर्माण के लिए एनएफडीसी और फिल्म विकास निगम, बांग्लादेश को कार्यकारी निर्माता नियुक्त किया गया है।

2. वितरण

वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म

cinemasofindia.com

वर्तमान में, एनएफडीसी मंत्रालय के साथ सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, भारतीय बाल चित्र संस्था, फिल्म प्रभाग एवं सरकार के स्वामित्व वाले अन्य निकायों के साथ औपचारिक समझौतों का अनुसरण कर रहा है, ताकि सिनेमाज़ ऑफ इंडिया के तहत उनके द्वारा सृजित सामग्री को प्रदर्शित करने के लिए ओटीटी मंच पर एक साथ लाया जा सके। यह प्रस्ताव छात्रों की पात्र फिल्मों को दर्शकों तक पहुंचाने और उन्हें प्रदर्शित करने का मंच उपलब्ध कराने की मंशा के साथ किया गया है।

एनएफडीसी का आधिकारिक वीओडी साल भर प्लेटफ़ॉर्म एनएफडीसी और की गई फिल्मों को सब्सक्रिप्शन के आधार पर प्रसारित करता है। आने वाले वर्ष में, नई फिल्मों के साथ हम बेहतर ढंग से मार्केटिंग के साथ वीओडी रिलीज़ देखेंगे। वीओडी प्लेटफ़ॉर्म दुनिया भर के संस्थानों को पेश किए जाने वाले संस्थागत प्रमाणीकरण पर केंद्रित है, जिसमें सब्सक्राइबर्स को संस्थानों और विश्वविद्यालयों के शुल्क पर दुनिया भर के किसी भी हिस्से से फ़िल्में उपलब्ध होंगी।

अंतरराष्ट्रीय बिक्री

एनएफडीसी अपनी फिल्मों के जरिए टीवी, वीओडी और अन्य पर मुद्रीकृत करने के लिए प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय वितरकों, चैनलों, टेलीविजन फिल्मों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ सहयोग की परिकल्पना करता है। इस साल एनएफडीसी ने

क्राइटेरियन कलेक्शन के साथ सहयोग का नवीकरण किया है और प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइब्रेरी टाइटल्स के साथ संघ बनाया है।

एनडीएफसी की फिल्मों *ताषेर देष* और *अरुणोदय* के लिए नेटफ्लिक्स की ओर से अंतरराष्ट्रीय बिक्री इस प्लेटफॉर्म के साथ महत्वपूर्ण भागीदारी के तहत हासिल की गई।

3. प्रीव्यू थियेटर

एनएफडीसी मुम्बई स्थित अपने 81 सीटों के प्रीव्यू थियेटर और चेन्नई स्थित 100 सीटों के प्रीव्यू थियेटर को फ़िल्मों के प्रदर्शन के लिए विभिन्न सरकारी/गैर–सरकारी ग्राहकों को किराए पर देता है। ये थियेटर 3डी प्रोजेक्शन सुविधाओं सहित एनालॉग और डिजिटल प्लेटफार्मों में फ़िल्में दिखाने के लिए नवीनतम तकनीक से लैस हैं। एनएफडीसी फ़िल्म समारोहों/दूतावासों के साथ नियमित रूप से फ़िल्म समारोह आयोजित करने के लिए संबद्ध रहा है।

4. विदेशों में प्रचार और विपणन

विदेश प्रभाग अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोहों और बाज़ारों में भारतीय सिनेमा की उपस्थिति दर्ज़ करने की दिशा में काम करता है। अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समुदाय की भारतीय सिनेमा में बढ़ती रुचि को देखते हुए एनएफडीसी मुख्य रूप से भारत के सिनेमा और भारतीय प्रतिभा को अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोहों और बाज़ारों में बढ़ावा देने और प्रदर्शन करने पर ध्यान केंद्रित करता है। प्रभाग ने विश्व भर में निजी और सरकारी फ़िल्म संस्थानों के साथ साझेदारी की है। इस प्रभाग ने दुनिया भर से निजी और सरकारी फ़िल्म संस्थानों के साथ साझेदारी को बढ़ावा दिया है। वर्ष भर के दौरान, एनएफडीसी ने कान फ़िल्म समारोह, फ्रांस, अमरीकी फ़िल्म बाज़ार और संयुक्त राज्य अमरीका में भाग लिया।

5. फ़िल्म बाज़ार

फ़िल्म बाज़ार राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम (एनएफडीसी) द्वारा आयोजित किया जाने वाला दक्षिण एशिया का ग्लोबल फ़िल्म बाज़ार है, जिसे हर साल भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह (इफ्फी) के साथ–साथ, मैरियट रिपोर्ट, गोवा, भारत में आयोजित किया जाता है। इस वर्ष बाज़ार का आयोजन 20–24 नवंबर 2019 को किया गया था। फिल्म निर्माण, प्रोडक्शन और वितरण में दक्षिण एशियाई कॉन्टेंट और प्रतिभा की खोज, समर्थन और प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, यह बाज़ार दक्षिण एशियाई क्षेत्र में विश्व सिनेमा की बिक्री की सुविधा भी प्रदान करता है। फ़िल्म बाज़ार 2019 में 36 देशों की

फ़िल्म बाज़ार 2019 का उद्घाटन

भागीदारी देखी गई, जबकि 2007 में आयोजित पहले फ़िल्म बाज़ार में 18 देशों ने भाग लिया था। बीते वर्षों में, बाज़ार के एक या एक से अधिक कार्यक्रमों में *द लंच बॉक्स, मार्गरीटा विद ए स्ट्रॉ, चौथी कूट, क़िस्सा, शिप ऑफ़ थिसस, तितली, कोर्ट, अन्ने घोड़े दा दान, मिस लवली, दम लगाके हईशा, लायर्स डाइस, बॉम्बे रोज, तिथी* आदि को दर्शाया गया है।

फ़िल्म बाज़ार अब दक्षिण एशियाई फ़िल्म निर्माताओं के लिए अपनी कहानियों को अंतरराष्ट्रीय और घरेलू फ़िल्म समुदाय के लिए प्रस्तुत करने का केंद्र बन गया है। इसके अलावा, यह कार्यक्रम ऐसे सालाना आयोजनों में शुमार हो चुका है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय बिक्री एजेंटों, निर्माताओं, वितरकों, फ़िल्म समारोह आयोजकों और फ़िल्म फंड्स की उपस्थिति अनिवार्य होती है। यह एक ऐसा आयोजन होता है, जहां दुनिया भर में इस उद्योग से जुड़े पेशेवर व्यवसाय के भविष्य के रुझानों के बारे में जानने और अगली बड़ी फ़िल्म/फ़िल्मकार की पहचान करने और उसका साझेदार बनने के लिए आते हैं।

बाज़ार के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रम निम्नलिखित हैं :

सह–निर्माण बाज़ार – दक्षिण एशियाई विषयों के वाले प्रोजेक्ट्स के लिए वित्तीय और कलात्मक सहायता की तलाश करने का मंच है। इस साल हमारे पास बांग्लादेश, भूटान, फ्रांस, नेपाल, सिंगापुर और अमरीका से दक्षिण एशियाई देशों के कुल 14 प्रोजेक्ट्स थे, जो भारतीय और अंतरराष्ट्रीय निर्माताओं, वितरकों, बिक्री एजेंटों और फाइनेंसरों के समक्ष प्रस्तुत किए गए।

अवलोकन कक्ष– इसका लक्ष्य धन की आवश्यकता वाली फिल्मों, विश्व भर में बिक्री, संभावित वितरण साझेदारों और फिल्म समारोहों को प्रस्तुत करना है। फिल्म प्रोग्रामर, वितरक, विश्व बिक्री एजेंट/निवेशक विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए अवलोकन कक्ष सॉफ़्टवेयर के माध्यम से व्यक्तिगत कंप्यूटर टर्मिनलों पर फिल्में देख सकते हैं। इस साल कुल 213 फ़िल्में अवलोकन कक्ष में प्रस्तुत की गईं, जिनमें 154 लम्बी फीचर फ़िल्में और 59 लघु फ़िल्में शामिल थीं।

वर्क–इन–प्रोग्रेस लैब्स– चुनिंदा प्रोजेक्ट्स को अंतरराष्ट्रीय सलाहकारों के एक प्रतिष्ठित पैनल से संपादकीय प्रतिक्रिया लेने का अवसर दिया जाता है, जिनमें फिल्म समारोह के निर्देशक, निर्माता, विश्व बिक्री एजेंट और संपादक शामिल होते हैं। यह लैब केवल रिलीज का लक्ष्य रखने वाली फिक्शन फीचर फिल्मों के लिए ही है। इस लैब के लिए अधिकतम पांच फ़िल्में चुनी जाती हैं। इस साल डब्ल्यूआईपी लैब परियोजनाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय बिक्री एजेंटों और समारोह के आयोजकों के साथ एक–पर–एक बैठकें आयोजित की गईं।

औद्योगिक स्क्रीनिंग– फिल्म निर्माता बाजार में बिक्री एजेंटों, फिल्म समारोहों, वितरकों और निर्माताओं के चुनिंदा दर्शकों के लिए स्क्रीनिंग के लिए विशेष रूप से स्थापित डिजिटल थिएटर बुक कर सकते हैं।

पुरस्कार– फिल्म बाजार में छह फिल्मों को सम्मानित किया गया। तीन फिल्मों– नितेश हेगड़े द्वारा पैड्रो, अजीतपाल सिंह द्वारा स्विज़रलैंड, पृथ्वी कोन्नूर द्वारा पिंकी एली को प्रसाद पोस्ट प्रोडक्शन और मूवीबफ अप्रिसिएशन अवार्ड (डीआई + डीसीपी अवार्ड) दिए गए –जबकि तीन फ़िल्मों – पुष्पेन्द्र सिंह द्वारा लैला और सत्त गीत (द शेपडेस एंड द सेवेन सांग्स), अचल मिश्रा द्वारा, गमक घर, रजत कपूर द्वारा आरके/आरकेय ने वीकेएएओ पुरस्कार जीता।

6. प्रशिक्षण और विकास

एनएफडीसी ने 2012 में एक प्रशिक्षण और विकास विभाग की स्थापना की, जिसे फ़िल्म क्षेत्र में मध्य–कैरियर प्रशिक्षण के अवसरों की कमियों को दूर करने के लिए तैयार किया गया है। इसकी स्थापना भारतीय फ़िल्म समुदाय के लिए प्रमुख आउटपुट प्रदान करने हेतु ब्रांड एनएफडीसी लैब्स के तहत की गई है : पेशेवर फ़िल्म निर्माताओं के लिए प्रशिक्षण, मुख्य विषयों में कार्यशालाओं और मास्टर कक्षाएं प्रदान करना–निर्देशन, लेखन, संपादन, छायांकन और निर्माण।

स्किल इंडिया मिशन के तहत चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय में प्रशिक्षण प्रभाग दक्षिणी राज्यों में बेरोज़गार युवाओं के लिए मीडिया से संबंधित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। जहां इसने एनीमेशन, कैमरा, एडिटिंग, मल्टीमीडिया, फोटोग्राफी और ऑडियो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 16000 से अधिक युवाओं को अल्पावधि प्रशिक्षण और व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान किए हैं। ऐसा अनुमान है कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से जुड़ने वाले लगभग 70 प्रतिशत युवाओं को रोज़गार प्राप्त हुआ है। एनएफडीसी कौशल विकास–प्रशिक्षण कार्यक्रमों का देश के अन्य भागों में विस्तार करने की भी प्रक्रिया में है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को भी कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, मीडिया और मनोरंजन जगत में रोज़गार के पर्याप्त अवसरों का सृजन कर महिलाओं, अल्पसंख्यकों, ट्रांसजेंडर समुदाय

और दिव्यांगों को शामिल करने के लिए कौशल प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में एक केंद्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा), के माध्यम से छात्रों को मीडिया में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

एनएफडीसी ने राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) का समर्थन और व्यवस्थापन करते हुए आंध्र प्रदेश के 3 शहरों –विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और तिरुपति में प्रशिक्षण और प्रमाणन के लिए एक मजबूत मॉडल सहित आंध्र प्रदेश राज्य कौशल विकास निगम (एपीएसएसडीसी) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। शुरुआत में 2018–19 से 3 वर्षों के लिए लगभग 5000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जाएगा। मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष 1080 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया जाएगा, मांग के आधार पर जिनकी संख्या बढ़ाकर प्रति वर्ष अधिकतम 2160 अभ्यर्थियों तक की जा सकती है।

7. एनएफडीसी लैब्स

एनएफडीसी ने भारतीय फ़िल्म समुदाय के लिए प्रमुख आउटपुट प्रदान करने हेतु 2012 में एनएफडीसी लैब्स की स्थापना की थीः पेशेवर फ़िल्म निर्माताओं के लिए प्रशिक्षण, मुख्य विषयों में कार्यशालाओं और मास्टर कक्षाएं प्रदान करना–निर्देशन, लेखन, संपादन, छायांकन और निर्माण। यह कदम फ़िल्म क्षेत्र में मध्य–कैरियर प्रशिक्षण के अवसरों की कमियों को दूर करने के लिए उठाया गया है।

क. पटकथा लेखकों की लैब

पटकथा विकास प्रयोगशाला लेखकों, पटकथा और चरित्र विकास पर ध्यान केंद्रित करती है ताकि लेखकों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों की मदद से उनकी पटकथा लेखन तकनीक को बढ़ाया जा सके। इस लैब को 6 महीने की अवधि में 3 भागों के सत्र में डिज़ाइन किया गया है ताकि प्रत्येक प्रोजेक्ट के समग्र रचनात्मक विकास के लिए स्वस्थ निर्माण पूर्व अवधि की अनुमति दी जा सके। वर्तमान वर्ष के दौरान 6 महीनों में फैले तीन रेजीडेंशियल सत्रों के लिए 7 पटकथाओं का चयन किया गया है। एंगली मैक्फार्लेन–पटकथा डॉक्टर–यूनाइटेड किंगडम स्कॉट मार्शल स्मिथ– पटकथा–एलए, बिकास मिश्रा–फिल्मकार–भारत–इन 7 प्रोजेक्ट्स के लिए परामर्शदाता थे। ये सत्र 16–20 जुलाई, 2019 को अलीबाग में, 15–21 सितंबर, 2019 को अलीबाग में और 15–19 नवंबर, 2019 को गोवा में आयोजित किए गए ताकि प्रतिभागी फिल्म बाज़ार 2019 में अपनी पटकथा के लिए प्रयास कर सकें।

ख. फिल्म समारोह और प्रोग्रामिंग

एनएफडीसी फिल्मों के सह–निर्माता के तौर पर सामने आया है, *द गोल्ड–लेडेन षीप* और *सेक्रेड माउंटेन* जिनका निर्देशन रिद्म जानवे ने किया है और *लाल माटी* का निर्देशन निनाद महाजनी ने किया है।

द गोल्ड–लेडेन शीप और *सेक्रेड माउंटेन* 2016 में एनएफडीसी फिल्म बाजार वर्क इन प्रोग्रेस लैब का अंग थीं, जहां इसे प्रसाद लैब डीआई पुरस्कार प्राप्त हुआ था और 2018 में 20वें जियो मामी मुम्बई फिल्म फेस्टीवल विद स्टार में इसका वर्ल्ड प्रीमियर हुआ था और इसने सिल्वर गेटवे अवार्ड जीता था।

48वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रॉटरडैम (आईएफएफआर) में 'ब्राइट फ्यूचर' खण्ड के तहत फिल्म का अंतरराष्ट्रीय प्रीमियर हुआ। इसे कई अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में प्रदर्शित किया गया और हाल ही में हांगकांग अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह 2019 में इसने एफआईपीआरईएससीआई पुरस्कार जीता। रिपोर्ट में शामिल किए गए वर्ष के दौरान फिल्म को 15 प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय समारोहों में प्रदर्शित किया गया।

8. विज्ञापन फिल्म निर्माण एवं संचार

कमीशन निर्माणः एनएफडीसी ने विभिन्न मंचों पर विज्ञापन संचार के सृजन और प्रसार के लिए विश्वसनीय एकीकृत मीडिया सेवा प्रदाता के तौर पर विविध मंत्रालयों के बीच प्रतिष्ठित स्थान बनाया है।

अपनी व्यवस्थित और दक्ष प्रक्रिया के कारण एनएफडीसी ने पुराने और नए ग्राहकों से एक संबंध बनाए हुए हैं। अपने कार्य अनुभव के जरिए एनएफडीसी अद्योपरांत समाधानों, कार्यक्रम के प्रबंधन, सामग्री की रचना और सोशल मीडिया प्रसार के लिए ग्राहक मंत्रालयों के प्रति विश्वसनीय रहा है। साथ ही वह अभी तक वह ऐसे मंत्रालय जहां उसकी पैठ नहीं हैं, से संबंध बनाने के लिए प्रयासरत है।

एनएफडीसी का प्राथमिक लक्ष्य सरकार के उत्कृष्ट प्रमुख कार्यक्रमों की कार्यनीति तैयार करना और उसके कार्य को कार्यान्वित करना रहा है, ताकि विज्ञापन में तालमेल सुनिश्चित किया जा सके और इस प्रकार जनता तक बेहतर पहुंच बनाई जा सके।

➢ *360 डिग्री बुके : एक ही स्थान पर समस्त सेवाओं की उपलब्धता*

एनएफडीसी अपनी सेवाओं को वैविध्यपूर्ण बनाने और

विज्ञापन के परस्पर संवादात्मक/पारम्परिक वीडियो जैसे अपरम्परागत प्रारूपों को व्यापक रूप से अपनाने की योजना है, जो सरकार के संचार को दो–तरफा प्रक्रिया बना सकते हैं और संदेश के प्रभाव को व्यापक बना सकते हैं।

➢ *विस्तार मोड : राष्ट्रीय से राज्य स्तर पर*

निगम ने राज्य/संघशासित प्रदेशों के विभागों के साथ सहयोग की एक विशेष कार्यनीति भी तैयार की है और लक्षद्वीप पर्यटन से श्रव्य दृश्य कन्टेंट तैयार करने का एक प्रोजेक्ट भी सफलतापूर्वक हासिल किया है, ताकि उसके द्वीप गंतव्य और खासतौर पर अंतरजलीय स्थलों की विशिष्टता दर्शायी जा सके।

➢ *मशहूर हस्तियों को साथ जोड़ना : ग्राहकों के लिए अधिकतम आरओआई बनाना*

एनएफडीसी ने एनएचएआई जैसे विभागों के लिए मशहूर हस्तियों को साथ जोड़कर अभूतपूर्व श्रव्य दृश्य कन्टेंट तैयार किया है, जिसमें फास्टैग के लॉन्च को प्रचारित करने के लिए अक्षय कुमार को अनुबंधित किया। इफ्फी 2019 का गान तैयार करने के लिए अन्य हस्तियों को भी शामिल किया गया। इसमें ग्रैमी अवार्ड विजेता से लेकर पद्मश्री से सम्मानित नृतकों तक की प्रतिभा को प्रदर्शित किया गया। एनएफडीसी ने दलेर मेहंदी, सुनिधि चौहान, नूरन बहनों, जसबीर जस्सी और जावेद अली जैसी भारतीय फिल्म जगत की नामी–गिरामी हस्तियों को शामिल करते हुए करतारपुर गलियारे के उद्घाटन के बारे में गान तैयार किया था। वह बाल श्रम के खिलाफ श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अभियान की अगुवाई के लिए अमिताभ बच्चन के साथ भी बातचीत कर रहा है।

➢ *सोशल मीडिया प्रबंधन में प्रवेश :*

एनएफडीसी अपने समस्त ग्राहक मंत्रालयों के लिए परम्परागत डिजिटल प्लेटफॉर्म से परिवर्तन करते हुए सोशल मीडिया प्रबंधन के माध्यम से गतिशीलता प्रदान करने में सबसे आगे रहा है। एनएफडीसी सरकार की महत्वपूर्ण परियोजनाओं जैसे हाई स्पीड रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, राइट्स, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, आईआरसीटीसी, भारत निर्वाचन आयोग के लिए लोक सभा प्रचार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय आदि के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तैयार करने की दिशा में प्रगति करने में सफल रहा है।

9. मीडिया अभियान

एनएफडीसी के निरंतर प्रयासों और समयबद्ध सेवाओं ने कई मंत्रालयों/विभागों को अपने मीडिया प्रचार अभियानों के लिए अपनी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया है।

➢ *मीडिया संचालन का डिजिटलीकरण*

एनएफडीसी ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नीति के अनुसार मीडिया नियोजन और मीडिया संबंधी गतिविधियों में पारदर्शिता, दक्षता और प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक मीडिया ऑपरेशन अनुप्रयोग लागू किया है।

पूर्णतः त्रुटिमुक्त समाधान प्रदान करने के लिए इस मीडिया सॉफ्टवेयर के माध्यम से पूरी योजना, बिलिंग और भुगतान प्रक्रिया को एकीकृत किया गया है। इससे रिलीज़ ऑर्डर, बिल सत्यापन, भुगतान आदि जारी करने की मैनुअल प्रक्रिया को समाप्त करने में मदद मिली है और क्लाइंट मंत्रालयों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एजेंसियों के लिए वितरण सरल, तेज और कुशल हो गया है। यह मीडिया एजेंसियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करेगा बशर्ते कि क्लाइंट मंत्रालयों से राशि समय पर प्राप्त हो।

10. डिजिटल मीडिया

डिजिटल मीडिया एक मुद्रीकृत माध्यम है, जो एनएफडीसी द्वारा अपने ग्राहकों को प्रस्तुत किए जाने वाले मीडिया मिक्स के मौजूदा चैनलों को परिपूर्ण करता है। यह एक ऐसा माध्यम है, जो भारत जैसे विशाल देश के विविध भागों में मौजूद श्रोताओं तक संपर्क के लिए पर्याप्त साधनों की पेशकश करता है। डिजिटल मीडिया के लाभ और संपर्क के कारण विविध मंत्रालयों और सरकारी विभागों ने एनएफडीसी द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं के जरिए डिजिटल माध्यम से अपने नागरिकों से संपर्क बनाने का विकल्प चुना है।

एनएफडीसी द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली लेकिन इन तक ही सीमित नहीं रहने वाली डिजिटल सेवाएं : सोशल मीडिया प्रबंधन, डिजिटल विज्ञापन एसईओ सेवाएं और वेबसाइट विकास।

वित वर्ष 2018–19 के दौरान, एनएफडीसी ने अपनी डिजिटल मीडिया सेवाएं भारत निर्वाचन आयोग, आईआरसीटीसी, राइट्स, नेशनल हाई स्पीड रेल कार्पोरेशन लिमिटेड और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को प्रदान कीं।

11. फ़िल्म सुविधा कार्यालय (एफएफओ)

19 जनवरी, 2019 को नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन

सिनेमा (एनएमआईसी) का उद्घाटन करते हुए, माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि देश के विभिन्न हिस्सों में शूटिंग की मंजूरी देने के लिए सरकार फिल्म के लिए एक ही स्थान पर सभी प्रकार की मंजूरी प्रदान करने (सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम) की स्थापना करते हुए 'फिल्मांकन में सुगमता' प्रदान करने के लिए काम कर रही है। इसके बाद अंतरिम बजट 2019, में फिल्मों की शूटिंग में आसानी के लिए सिंगल–विंडो क्लीयरेंस और फैसिलिटेशन व्यवस्था लागू की, जो अब तक केवल विदेशियों के लिए उपलब्ध थी, अब उनके साथ भारतीय फिल्म निर्माताओं के लिए भी उपलब्ध होगी। इस संबंध में, यह कहा जा सकता है कि एफएफओ वेब पोर्टल, www.ffo.gov.in, ने भारतीय फिल्म निर्माताओं से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करना शुरू कर दिया है, जो भारत के विभिन्न राज्यों में स्थित विभिन्न स्थानों में शूटिंग करना चाहते हैं।

1. *अप्रैल से नवम्बर, 2019 के दौरान जारी/सुगम बनाई गई अंतरराष्ट्रीय मंजूरियों की संख्या*

एफएफओ ने वित्त वर्ष 2019 में कनाडा, ब्रिटेन, हंगरी, फ्रांस, थाईलैंड, जर्मनी, अमरीका, चीन, बैंकॉक, इटली, स्विटजरलैंड और कुवैत से मिले निर्माण संबंधी 22 अंतरराष्ट्रीय आवेदनों को फिल्माने की सुविधा प्रदान की। इनमें *अ सूटेबल ब्वाय, मेरी गो राउंड* (जिसे अब टेनेट के रूप में जाना जाता है), *ट्रेडस्टोन, द बीयर* और *द व्हाइट टाइगर* जैसे उल्लेखनीय निर्माण शामिल हैं।

2. *अप्रैल से नवम्बर, 2019 के दौरान जारी/सुगम बनाई गई घरेलू मंजूरियों की संख्या*

अप्रैल, 2019 में एफएफओ पोर्टल द्वारा भारतीय निर्माताओं से आवेदन स्वीकार करना शुरू किए जाने के बाद से 11 से अधिक घरेलू आवेदनों को सुविधा प्रदान की गई है। इनमें दिल्ली में शूट की गई बिगिल, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, लेह और लद्दाख सहित विभिन्न भारतीय शहरों में शूट की गई *सेटेलाइट शंकर* और *पल्सर डेयर वेंचर* जैसी फिल्में शामिल हैं।

3. *'नोडल आफिसर' की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना*

विभिन्न राज्य सरकारों और प्रमुख हितधारक केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों में जमीनी स्तर पर फिल्मांकन को आसान बनाने और फिल्माने की अनुमतियों को समयबद्ध तरीके से जारी करना संभव बनाने के लिए जिम्मेदार नोडल अधिकारियों का एक तंत्र बनाया गया है। वे अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में शूटिंग के लिए अनुमति मांगने वाले फिल्म निर्माताओं के सभी आवेदनों तक पहुंच बना सकते हैं। राज्य और स्थानीय अनुमति मांगने वाले घरेलू और अंतरराष्ट्रीय फिल्म निर्माता – स्थान विशेष से संबंधित अनुमतियों को संबंधित राज्य नोडल अधिकारियों द्वारा संसाधित और जारी किया जाता है, जिसका विवरण भी आवेदक के साथ साझा किया जाता है। एफएफओ इन अनुमतियों के अनुसार सुविधा प्रदान करता है।

4. *हॉलीवुड फीचर फिल्म टेनेट/मेरी गो राउंड के लिए सुविधा प्रदान करने की अनुमति*

टेनेट/मेरी गो राउंड, वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो द्वारा निर्मित एक महत्वपूर्ण फीचर फिल्म है और इसका निर्देशन वैश्विक स्तर पर सराहे जाने वाले और एकेडमी अवार्ड विजेता निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन ने किया है। मुंबई के विभिन्न हिस्सों में शूट की गई इस फिल्म की 6 दिनों की शूटिंग के दौरान 6 मिलियन डॉलर यानी लगभग 42.5 करोड़ रुपये खर्च हुए। दुनिया के विभिन्न हिस्सों के 160 से अधिक विदेशी कर्मी आए, जबकि विभिन्न विभागों में 600 भारतीय कर्मियों को नियुक्त किया गया। इसके अतिरिक्त, इस फिल्म में 4 भारतीय कलाकारों सहित 2000 एक्स्ट्रा को लिया गया, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए आय और बड़ी तादाद में रोजगार का सृजन हुआ।

5. *कांस फ़िल्म समारोह और बाजार 2019 (14–21 मई, 2019) में भारतीय मण्डप में एफएफओ की भागीदारी*

भारत में फिल्मांकन पर केंद्रित एक विज्ञापन अभियान प्रमुख प्रकाशनों – स्क्रीन, वेराइटी और हॉलीवुड रिपोर्टर के साथ–साथ कांस मार्केट गाइड में मौजूद था। देश में फिल्मांकन में सुगमता के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की पहल पर कांस में इंडिया पवेलियन में 17 मई, 2019 को एक सत्र आयोजित किया गया, जिसमें विदेशी और घरेलू फिल्म निर्माताओं को भारत में फिल्माने के लिए आमंत्रित किया गया। भारत में फिल्मांकन को बढ़ावा देने के साथ–साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग का पता लगाने के लिए विभिन्न निर्माताओं के साथ अलग से मुलाकात करने के अलावा, *न्यूजीलैंड फिल्म कमिशन, इजराइल फिल्म कमिशन, फ्रांस सेंटर नेशनल द सिनेमा, टेलीफिल्म कनाडा, प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ अमरीका, सिनेमा द ब्रासिल, क्रिएटिव बीसी कनाडा, साउदने स्वीडन फिल्म कमिशन* जैसे निर्माताओं और फिल्म निकायों के साथ बैठकें की गईं। ताकि भारत में फिल्मांकन को बढ़ावा देने के साथ ही साथ परस्पर लाभकारी सहयोगों का

पता लगाया जा सके।

12. महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाना

महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर छात्रों में गांधी के सत्य और अहिंसा के संदेश को फैलाने के लिए एनएफडीसी, चेन्नई स्कूल और टैगोर फ़िल्म सेंटर में अक्टूबर, 2018 से 2 वर्षों के लिए गांधी (तमिल भाषा में) का प्रदर्शन कर रहा है।

एनएफडीसी ने तमिल छात्रों के लिए विभिन्न स्कूलों और टैगोर फ़िल्म सेंटर में अक्टूबर, 2018 से अक्टूबर, 2019 तक 2 वर्षों के लिए गांधी (तमिल भाषा में) का प्रदर्शन कर रहा है।

महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर एनएफडीसी द्वारा फिल्म का प्रदर्शन

श्रव्य–दृश्य सेवाओं के लिए चैम्पियन सेवा क्षेत्र योजना

माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 28.02.2018 को सम्पन्न केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 12 चिह्नित चैम्पियन सेवा क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहन देने और उनकी क्षमताओं का जायजा लेने संबंधी वाणिज्य विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। श्रव्य दृश्य सेवाएं भी इन चिह्नित किए गए 12 चैम्पियन क्षेत्रों में से एक हैं। फिल्म स्कंध ने नीचे उल्लिखित किए गए संघटकों के अनुसार चैम्पियन सेवा क्षेत्र की श्रव्य दृश्य क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत फिल्म उद्योग को प्रोत्साहन देने की पेशकश की है:

(1) **अन्य देशों के साथ श्रव्य–दृश्य सह–निर्माण के लिए प्रोत्साहन** : भारत ने 14 देशों के साथ सह–निर्माण संधियां की हैं। इससे देशों के बीच कला एवं संस्कृति का आदान–प्रदान होता है और उनके बीच सद्भावना उत्पन्न होती है। इसकी बदौलत कलात्मक, तकनीकी और साथ ही साथ गैर–तकनीकी कार्यबल के लिए रोजगार के साधनों का सृजन होता है। अंतरराष्ट्रीय सह–निर्माण संधि के तहत भारत में सह–निर्माण कार्य करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सह–निर्माण फिल्मिंग सब्सिडी के रूप में सह–निर्माता/निर्माता को सब्सिडी प्रदान की जा सकती है। भारतीय भाषा की कोई भी फिल्म जिसे दोनों या समस्त भागीदार देशों द्वारा उनकी मौजूदा तत्संबंधी सह–निर्माण संधि के तहत "सह–निर्माण का दर्जा" प्रदान किया गया हो, वह निश्चित अधिकतम सीमा तक प्रोत्साहन प्राप्त करने की पात्र होगी।

(2) **भारत में विदेशी फिल्मों को फिल्मांकन के लिए प्रोत्साहनः** शूटिंग में भारत के स्थानीय लोगों का उपयोग दुनिया भर में पसंदीदा फिल्म शूटिंग गंतव्य के रूप में भारत की दृश्यता/संभावना को बढ़ाता है और भारत में पर्यटन को प्रोत्साहन देता है। प्रस्ताव रखा गया है कि भारत विदेशी फिल्मकारों शूटिंग करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु नकद छूट और प्रोत्साहन प्रदान कर सकता है। इसलिए, कोई भी अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म, रियलिटी टीवी, वेब शो/सीरीज, कमर्शियल टीवी शो/सीरीज जिसने भारत में शूट/फिल्म करने की अनुमति प्राप्त की हो, वह एक निश्चित अधिकतम सीमा तक प्रोत्साहन पाने का पात्र होगा।

(3) **वैश्विक फिल्म शिखर सम्मेलन का आयोजन** : सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की तर्ज पर 2020 के आखिर तक वैश्विक फिल्म शिखर सम्मेलन का आयोजन करने की योजना है। इसमें विभिन्न हितधारकों अर्थात फिल्म प्रोड्यूसर्स गिल्ड, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की), भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसी), म्यूजिक कंपनियां, एवीजीसी (एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स), वर्चुअल रियलिटी/ऑगमेंटेड रियलिटी के साथ–साथ भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) जैसे महत्वपूर्ण हितधारक शामिल हैं।

इस शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय सिनेमा की सॉफ्ट पॉवर, पायरेसी के संदर्भ में उद्योग के समक्ष आने वाले समकालीन मसलों, तकनीकी प्रगति और दर्शकों के प्रोफाइल में निरंतर हो रहे बदलाव और सिनेमा का उपभोग, के संबंध में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर केंद्रित विमर्शों की श्रृंखलाएं प्रस्तुत की जाएंगी। इनमें उद्योग के कारोबारी और रचनात्मक दोनों तरह प्रमुख वक्ता भाग लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में गंभीर

चर्चाओं के बीच फिल्म उद्योग में गड़बड़ी उत्पन्न करने वालों और रचनात्मक एवं कारोबारी प्रक्रियाओं के लिए प्रेरणादायी कार्यनीतियां पर भी रोशनी डाली जाएगी।

(4) **स्तर–2 और स्तर–3 शहरों में सिनेमा स्क्रीन्स की संख्या बढ़ाना** : राज्य सरकारों से स्तर–2 और स्तर–3 शहरों में सिनेमा स्क्रीन्स की संख्या बढ़ाने के लिए राज्य स्तर पर स्थानीय प्रशासन से अनुमति प्रदान करने/नवीकरण करने/लाइसेंस प्रदान करने, बिजली शुल्क के लिए प्रोत्साहन देने, अन्य देशों से प्राप्त किए जाने वाले थिएटर उपकरणों के लिए सीमा शुल्क में कटौती करने, कर में छूट और प्रोत्साहन देने का अनुरोध किया गया है।

फ़िल्म सुविधा कार्यालय (एफएफओ)

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ''कारोबार करने में सुगमता'' की सरकार की नीति के अंतर्गत भारत में फीचर फिल्म, टीवी/वेब शो और सीरीज एवं रिएलिटी टीवी/वेब शो और सीरीज की शूटिंग करने के इच्छुक अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म निर्माताओं के लिए दिसंबर, 2015 में राष्ट्रीय फ़िल्म विकास नियम (एनएफडीसी) में फ़िल्म सुविधा कार्यालय (एफएफओ) की स्थापना की थी। इस प्रकार एफएफओ का 'फिल्म इन इंडिया' अधिदेश भारत को फ़िल्मांकन गंतव्य के रूप में प्रोत्साहित करता है।

भारत में समस्त प्रकार की फिल्मिंग के लिए अनुमति के संबंध में एकल खिड़की मंजूरी प्रणाली की स्थापना के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मार्गदर्शन में एफएफओ का वेब पोर्टल www.ffo.gov.in भारतीय और विदेशी, दोनों तरह के फिल्मकारों के लिए एकल खिड़की मंजूरी एवं सुगमता तंत्र के रूप में विकसित किया गया है। यह वेब पोर्टल फिल्मों के अनुकूल व्यवस्था बनाने तथा देश को फ़िल्मांकन गंतव्य के रूप में प्रचारित करने का प्रयास करता है।

1. अप्रैल से दिसंबर, 2019 के दौरान अंतरराष्ट्रीय अनुमतियों को सुगम बनाया गया

एफएफओ ने अब तक वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान फीचर फिल्मों, टीवी/वेब शो और सीरीज एवं रिएयलिटी टीवी/वेब शो और सीरीज, 25 अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स सहित 104 अंतरराष्ट्रीय निर्माण के फिल्मांकन को सुगम बनाया गया है। ये प्रोजेक्ट्स विभिन्न देशों जैसे अमरीका, जर्मनी, ब्राजील, फ्रांस, ब्रिटेन, हंगरी, कनाडा, चीन, स्विटजरलैंड, इटली, कुवैत, थाईलैंड से थे। कुछ उल्लेखनीय निर्माणों में – *द व्हाइट टाइगर* (फिल्म), *मैरी गो राउंड* (फिल्म, जिसे अब टेनेट के नाम से जाना जाता है, की 6 दिन की शूटिंग पर लगभग 42.5 करोड़ रुपये की राशि खर्च हुई, इसमें 600 सदस्यों वाला भारतीय क्रू, 2000 एक्स्ट्रा सहित 4 भारतीय चरित्र), *अ सूटेबल ब्वाय* (टीवी सीरीज), *आगरा* (भारत–फ्रांस सहयोग), *एंटर द गर्ल ड्रैगन* (भारत–चीन सह–निर्माण), *जीनियस जीजा जी* (भारत–कनाडा सहनिर्माण) शामिल हैं।

2. अप्रैल से नवंबर, 2019 के दौरान घरेलू अनुमतियों को सुगम बनाया गया

एफएफओ पोर्टल द्वारा अप्रैल, 2019 में भारतीय निर्माताओं से आवेदन स्वीकार करना शुरू होने के बाद से 14 से ज्यादा घरेलू आवेदनों में सहायता की जा चुकी है। इसमें *बिगिल* (तमिल सिनेमा की इस साल की सबसे हिट फिल्मों में से एक), जिसे दिल्ली में शूट किया गया, *सेटेलाइट शंकर और पल्सर डेयर वेंचर* जिसे पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, चण्डीगढ़, लेह और लद्दाख सहित विविध भारतीय स्थानों पर शूट किया गया था। एफएफओ अब मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई के विविध प्रोडक्शन हाउसेज के साथ चर्चा कर रहा है, ताकि भारतीय फिल्मकार देश के विभिन्न भागों में शूटिंग करने और राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रोत्साहनों तक पहुंच बनाकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा बनाई गई व्यवस्था से लाभांवित हो सकें।

3. 'नोडल अधिकारी' व्यवस्था और भारत में फिल्मांकन में सुगमता

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों (एएसआई, रेलवे, डीजीसीए, एमईए, एमएचए आदि) के साथ सहयोग कर नोडल अधिकारियों का तंत्र तैयार किया गया है, जिसने एफएफओ, फिल्मकारों और संबंधित सरकारी निकायों के बीच कारगर सहयोग संभव बनाया है, जो फिल्मांकन की प्रक्रिया में हितधारक हैं। स्थान विशेष से संबंधित अनुमतियों का प्रबंधन और उन्हें जारी करने का कार्य संबंधित राज्य/केंद्रीय नोडल अधिकारियों द्वारा किया जाता है, जिनका विवरण आवेदक के साथ भी साझा किया जाता है। नोडल अधिकारियों को उनके अधिकारक्षेत्र में फिल्मांकन करने की अनुमति मांगने के लिए फिल्मकारों द्वारा एफएफओ पोर्टल पर किए गए सभी आवेदनों तक पहुंच बनाने के लिए यूआरएल, लॉग इन आईडी और पासवर्ड प्रदान किया जाता है। एफएफओ इन अनुमतियों के अनुरूप सुविधाएं प्रदान करता है।

4. फिल्मांकन सुगम बनाने के लिए भारतीय पुरातत्व

सर्वेक्षण और रेल मंत्रालय का एकीकरण

हालांकि एफएफओ पोर्टल www.ffo.gov.in एएसआई और रेलवे के साथ संबंधित है, इसके बावजूद एफएफओ इस समय दोनों के साथ एकीकरण की प्रक्रिया में है, ताकि फिल्मकार एएसआई और रेलवे की परिसम्पत्तियों पर फिल्मांकन की अनुमति प्राप्त करने के लिए एफएफओ वेब पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इससे फिल्मकार एकल खिड़की के माध्यम से अनुमति का आवेदन करने में समर्थ हो सकेंगे। सफल एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए दोनों के सक्षम प्राधिकारियों के साथ निरंतर बातचीत की जा रही है, जिसके इस वित्त वर्ष तक सम्पन्न हो जाने की संभावना है। एफएफओ ने एएसआई के समस्त केंद्रों में 29 नोडल अधिकारियों की नियुक्ति को भी सुगम बनाया है, ताकि देश भर के विविध एएसआई स्थलों पर अनुमति की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके।

5. समूचे भारत में फिल्मांकन को जमीनी स्तर पर सुगम बनाने के लिए राज्य सरकारों के साथ एकीकरण प्रत्येक राज्य के पास अनुमति प्रदान करने का अपना विलक्षण तरीका होने के मद्देनजर महाराष्ट्र (जिसने अपनी प्रथम एकल खिड़की लॉन्च की है), उत्तराखण्ड, दिल्ली, मध्य प्रदेश, सिक्किम, तमिलनाडु के सक्षम प्राधिकारी एफएफओ पोर्टल के साथ एकीकरण के तौर–तरीकों पर चर्चा करने के लिए बैठक कर चुके हैं। इसका उद्देश्य फिल्मांकन की सुगमता सुनिश्चित करने के लिए एकल खिड़की प्रणाली विकसित करना तथा भारतीय, साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय फिल्मकारों के लिए राज्य में विभिन्न विभागों और स्थानीय निकायों की ओर से फिल्मांकन की अनुमति को मंजूरी देने के कार्य को सरल बनाना है।

6. फिल्म बाज़ार 2019 में 'एक कुशल एकल खिड़की व्यवस्था का सृजन' पर कार्यशाला

इस कार्यशाला का लक्ष्य समर्पित फिल्म प्रकोष्ठ बनाने की जरूरत पर राज्यों को सक्रिय करना है, जो एफएफओ की तरह कार्य करेगा, राज्य के प्रमुख विभागों (पुरातत्व, पर्यटन, गृह, पुलिस, नगर निगम, जिला मजिस्ट्रेट, जिलों के पुलिस अधीक्षक, रेलवे आदि विभागों) के साथ एकीकरण करेगा और अखिल भारतीय एकल खिड़की व्यवस्था की स्थापना करने के लिए एफएफओ के साथ एकीकरण करेगा। इस कार्यशाला में ओडिशा, उत्तर प्रदेश, लक्षद्वीप, उत्तराखण्ड, झारखण्ड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, कर्नाटक, नगालैंड, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना ने भाग लिया। इस कार्यशाला को अन्य लोगों के अलावा असोसिएशन ऑफ फिल्म कमिश्नर्स इंटरनेशनल (एएफसीआई) के अध्यक्ष, विख्यात फिल्मकार मधुर भंडारकर, प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने सम्बोधित किया।

7. अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेना–कांस फिल्म बाज़ार और एएफसीआई सिनेपोज़ियम 2019

भारत में फिल्मांकन को प्रोत्साहन देने के प्रयासों और एफएफओ द्वारा अपने वेब पोर्टल के जरिए अनुमति की प्रक्रिया को सुगम बनाने की दिशा में किए गए प्रयत्नों के तहत, एफएफओ वैश्विक फिल्म समारोहों और कांस फिल्म बाज़ार 2019 जैसे बाज़ारों में भागीदारी और विपणन गतिविधियां करके अंतरराष्ट्रीय फिल्मिंग बिरादरी के साथ संबंध बना रहा है। एफएफओ असोसिएशन ऑफ फिल्म कमिश्नर्स इंटरनेशनल (एएफसीआई) का भी सदस्य है और उसने उनके सालाना शैक्षणिक कार्यक्रम एएफसीआई सिनेपोजियम में भी भाग लिया था।

02 अक्टूबर, 2019 को नई दिल्ली में पर्यटन पर्व का उद्‌घाटन करते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर और केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान

14 जनवरी, 2020 को नई दिल्ली में भारत के राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और बांग्लादेश के फिल्म विकास निगम के बीच समझौता ज्ञापन पर केंद्रीय पर्यारण, वन और जलवायु परिवर्तन और सूचना एवं प्रसारण और भारी उद्यम और लोक उपक्रम मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर और बांग्लादेश के सूचना मंत्री मुहम्मद एच महमूद की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए

7 अंतरराष्ट्रीय सहयोग

भारत और यूनेस्को

भारत, संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियों में से एक, यूनेस्को के संस्थापक सदस्यों में से है। यूनेस्को का मुख्य लक्ष्य शिक्षा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, सामाजिक विज्ञान, संस्कृति और जन-संचार के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। विकासशील देशों की संचार क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए, 1981 में यूनेस्को के महासम्मेलन के 21वें सत्र में संचार के विकास के लिए एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम (आईपीडीसी) की स्थापना को मंजूरी दी गई। भारत ने इसकी अवधारणा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आईपीडीसी और इसकी अंतर सरकारी परिषद का सदस्य रहा है। इसके महासम्मेलन के 35वें सत्र में भारत को मौखिक मतदान के जरिए 2009-2013 की अवधि के लिए आईजीसी का सदस्य चुना गया था।

यूनेस्को के साथ भारतीय राष्ट्रीय समन्वय आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1949 में की गई थी ताकि यूनेस्को के साथ शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक मामलों में कार्य करने के इच्छुक इसके प्रमुख निकायों को एक साथ लाया जा सके और चूंकि पिछले आयोग की कार्य अवधि 4 वर्ष के पश्चात् समाप्त हो गई थी अतः वर्ष 2019 में इसका पुनर्गठन किया गया।

अंतरराष्ट्रीय मीडिया कार्यक्रम

यह मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही नई योजना 'मानव संसाधन विकास' के अंतर्गत आने वाले घटकों में से एक है। इस घटक के अंतर्गत वर्ष 2017-18 से 2019-20 के लिए 45 लाख रु. का परिव्यय आवंटित किया गया है, जिसमें से 15 लाख रु. वित्त वर्ष 2018-19 के लिए रखे गए। इस कार्यक्रम में सूचना तथा फ़िल्म क्षेत्र में मीडिया आदान-प्रदान कार्यक्रम, संयुक्त कार्यसमूह तथा समझौते और अंतरराष्ट्रीय मीडिया सेमिनार/कार्यशालाएं शामिल हैं। कार्यक्रमों के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- मीडियाकर्मियों के बीच महत्वपूर्ण संवाद के माध्यम से देशों के बीच बेहतर समझ को बढ़ावा देने तथा क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने और एक-दूसरे के बारे में जानकारी के प्रसार के लिए मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करना।
- समाज में लोकतांत्रिक मूल्यों और सहिष्णुता को बढ़ावा देने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करना।
- इस योजना का व्यापक उद्देश्य सूचना और मास मीडिया के क्षेत्र में अन्य देशों के साथ निकट संबंध स्थापित करने और विकसित करने की समान इच्छा से प्रेरित होकर सूचना और प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में बेहतर समझ को बढ़ावा देकर विभिन्न देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत करना है।
- भारत और अन्य देशों के बीच संबंधों को मजबूत करना।
- मास मीडिया, ब्रॉडकास्टिंग और फ़िल्म क्षेत्र में भारत तथा अन्य देशों के बीच विचारों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना।
- उच्च श्रेणी का मीडिया प्रशिक्षण
- संकट के समय संचार
- सोशल और मल्टीमीडिया प्रशिक्षण

शंघाई सहयोग संगठन

- बिश्केक में दिनांक 13-14 जून, 2019 के दौरान एससीओ के शीर्ष सम्मेलन के दौरान "कोओपरेशन इन मास मीडिया" विषय पर एससीओ सदस्य राज्यों की सरकारों के बीच सभी सदस्य राज्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। यह करार, एससीओ सदस्य राज्यों की विशेषज्ञ स्तरीय बैठकों के निष्कर्ष हैं।
- दूसरा एससीओ मास मीडिया फोरम : वर्ष 2019 में एससीओ में किरगीज साइड की अध्यक्षता के भाग के रूप में किरगीज़ रिपब्लिक ने बिश्केक में 23 से 26 मई 2019 के दौरान एससीओ देशों के दूसरे मास मीडिया फोरम का संचालन किया। इस फोरम में टी.वी.के. रेड्डी, अपर महानिदेशक, पीआईबी, हैदराबाद और श्री अंकुर लाहोटी, सहायक निदेशक, आईएंडबी मंत्रालय ने भाग लिया।

भारतीय प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष ने देश में ही मास मीडिया क्षेत्र के विकास में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की महत्वपूर्ण भूमिका, मीडिया सहयोग तथा विभिन्न मास मीडिया एजेन्सियों, संगठनों तथा पूरे एससीओ भागीदार राज्यों के संघों के बीच सर्वोत्तम प्रक्रियाओं के आदान-प्रदान की आवश्यकता का उल्लेख किया।

किर्गिस्तान में भारत के राजदूत ने ऐसा प्रभावशाली भाषण देने पर भारतीय शिष्टमंडल को बधाई दी।

देशों के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (सीईपी)

सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम/समझौतों पर भारत सरकार की ओर से संस्कृति मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों/समझौतों का उद्देश्य संबंधों को मजबूत करना है और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संदर्भ में, ये कार्यक्रम/समझौते मास मीडिया, प्रसारण और फ़िल्मों के क्षेत्र में भारत और अन्य देशों के बीच विचारों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देते हैं।

वर्ष 2019-20 के दौरान भारत तथा कोमोरोस, जिम्बाब्वे, ज़ाम्बिया, मालदीव, ताजिकिस्तान, बेनिन, सियरा लेओन, सर्बिया, जॉर्डन जैसे अन्य देशों के बीच हस्ताक्षरित कई सीईपी संस्कृति मंत्रालय से मंत्रालय द्वारा उनका कार्यान्वयन करने के लिए प्राप्त हुए थे।

20 नवंबर, 2019 को गोवा के पणजी में 50वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह (इफ्फी–2019) के उद्घाटन अवसर पर बॉलीवुड के वरिष्ठ निर्देशक एवं प्रोड्यूसर श्री रमेश सिप्पी को भारतीय सिनेमा के लिजेन्ड्स के रूप में सम्मानित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, सूचना एवं प्रसारण और भारी उद्यम और लोक उपक्रम मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर इफ्फी के मुख्य अतिथि महानायक अमिताभ बच्चन, गोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत एवं अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे

18 जुलाई, 2019 को नई दिल्ली में 10वें जागरण फिल्म समारोह के उद्घाटन अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर

8 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण वाले पदों और सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए इस संबंध में जारी किए गए आदेशों/निर्देशों/दिशानिर्देशों के अनुसार सभी प्रयास किए गए हैं। विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयास किए गए हैं। मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/सार्वजनिक उपक्रमों/स्वायत्त निकायों द्वारा पद आधारित सूचियां बनाई जाती हैं।

2. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सेवाओं में आरक्षण और अन्य लाभों के बारे में दिशानिर्देशों और निर्देशों का, सख्ती से अनुपालन करने के लिए सभी मीडिया इकाइयों को भेजा जाता है।

3. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व का प्रतिशत और कर्मचारियों की कुल संख्या 1 जनवरी, 2020 तक निम्नानुसार थी :

श्रेणी	कुल कर्मचारी	अनुसूचित जाति (प्रतिनिधित्व %)	अनुसूचित जनजाति (प्रतिनिधित्व %)	अन्य पिछड़ा वर्ग (प्रतिनिधित्व %)	अन्य (प्रतिनिधित्व %)
क	1935	274 (14.16)	121 (6.25)	134 (7)	1406 (72.66)
ख	9103	1423 (15.63)	796 (8.74)	957 (10.51)	5927 (65.11)
ग	16823	3552 (21.11)	2232 (13.26)	1979 (11.76)	9060 (53.85)
घ	93	33 (35.48)	10 (10.75)	11 (11.82)	39 (41.93)
कुल	**27954**	**5282 (18.89)**	**3159 (11.30)**	**3081 (11.02)**	**16432 (58.78)**

16 सितंबर, 2019 को नई दिल्ली में दूरदर्शन के 60वें स्थापना दिवस समारोह में श्री अमिताभ बच्चन द्वारा वाचिक कविता का लोकार्पण करते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर

9 मंत्रालय की सेवाओं में दिव्यांगजनों का प्रतिनिधित्व

नोडल मंत्रालय/विभाग द्वारा दिव्यांगजनों के संबंध में समय-समय पर सभी मीडिया इकाइयों तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मुख्य सचिवालयों को कड़े तौर पर अमल में लाने के लिए आदेश तथा दिशानिर्देश जारी किए जाते रहे हैं। मुख्य सचिवालय में दिव्यांगजनों के हितों की देखभाल के लिए एक संपर्क अधिकारी की नियुक्ति भी की गई है।

डीओपीटी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर मंत्रालय में दिव्यांगजनों के लिए रिक्त पदों को भरने की विशेष भर्ती प्रक्रिया जारी है। मंत्रालय में वार्षिक आधार पर दिव्यांगजनों के प्रतिनिधित्व का लेखा-जोखा तैयार कर डीओपीटी को प्रेषित किया जाता है। इस दिशा में 01/01/2020 को मंत्रालय में दिव्यांगजनों का समग्र प्रतिनिधित्व और सीधी भर्तियां एवं तरक्की कोटा नीचे दिया गया है :-

पीडब्ल्यूडी रिपोर्ट-I

कार्यक्षेत्र में दिव्यांगजनों का प्रतिनिधित्व दर्शाती वार्षिक सूची

(वर्ष 2019 के लिए, 01/01/2020 तक)

मंत्रालय/विभाग : सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

समूह	कर्मचारियों की संख्या				
	कुल	चिह्नित पद	वीएच	एचएच	ओएच
1	2	3	4	5	6
समूह क	977	21	04	03	07
समूह ख	7255	96	07	19	39
समूह ग एवं घ	7994	108	23	07	50
कुल	**16226**	**225**	**34**	**29**	**96**

नोट :- (1) वीएच का अर्थ विजुअली हैंडिकैप्ड (नेत्रहीन अथवा कमजोर दृष्टि क्षमता वाले व्यक्ति)।

(2) एचएच का अर्थ हीयरिंग हैंडीकैप्ड (बधिर व्यक्ति)।

(3) ओएच का अर्थ ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड (चलन अंगों या प्रमस्तिष्क पक्षाघात से पीड़ित व्यक्ति)।

पीडब्ल्यूडी रिपोर्ट – II

कैलेंडर वर्ष के दौरान नियुक्त दिव्यांगजनों की संख्या दर्शाने वाली सूची

वर्ष 2019 के लिए (01/01/2020 तक)

समूह	पीडब्ल्यूडी के लिए सीधी भर्ती कोटा के अंतर्गत आरक्षित रिक्त पदों की संख्या			सीधी भर्ती कोटा के अंतर्गत नियुक्तियों की संख्या					पीडब्ल्यूडी के लिए प्रोमोशन कोटा के अंतर्गत आरक्षित रिक्त पदों की संख्या			प्रोमोशन कोटा के अंतर्गत नियुक्तियों की संख्या				
	वीएच	एचएच	ओएच	कुल नियुक्तियां	पीडब्ल्यूडी के लिए चिह्नित पदों पर कुल नियुक्तियां	वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच	कुल नियुक्तियां	पीडब्ल्यूडी के लिए चिह्नित पदों पर कुल नियुक्तियां	वीएच	एचएच	ओएच
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
समूह क	02	02	04	02	02	01	01	00	00	00	00	55	00	00	00	00
समूह ख	02	07	06	66	02	01	01	00	00	00	00	06	00	00	00	00
समूह ग एवं घ	13	11	12	11	03	01	01	01	03	02	00	06	00	00	00	00
कुल	17	20	22	79	07	03	03	01	03	02	00	67	00	00	00	00

नोट :- (1) वीएच का अर्थ विज़ुअली हैंडिकैप्ड (नेत्रहीन अथवा कमजोर दृष्टि क्षमता वाले व्यक्ति)।

(2) एचएच का अर्थ हीयरिंग हैंडिकैप्ड (बधिर व्यक्ति)।

(3) ओएच का अर्थ ऑर्थोपेडिकली हैंडिकैप्ड (चलन अंग पक्षाघात से पीड़ित व्यक्ति)

(4) समूह क और ख के पदों में तरक्की के लिए दिव्यांगजनों के लिए कोई आरक्षण उपलब्ध नहीं है। हालांकि, इन पदों पर दिव्यांगजनों को उस मामले में तरक्की के बाद नियुक्ति मिल सकती है यदि उक्त पद दिव्यांग व्यक्तियों की क्षमता के अनुरूप कार्य हो।

23 दिसंबर, 2019 को नई दिल्ली में 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, सूचना एवं प्रसारण और भारी उद्यम और लोक उपक्रम मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में हिंदी पखवाड़ा पुरस्कार वितरण समारोह

10 राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग

देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी, भारत के संविधान में प्रदत्त संघ की राजभाषा है। इस प्रावधान को लागू करने के लिए, सरकार की एक सुनियोजित नीति है जिसके तहत प्रत्येक मंत्रालय/विभाग प्रेरणा और प्रोत्साहन के माध्यम से कार्यालयीन कार्यों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग में वृद्धि लाने का प्रयास करता है।

2. उपर्युक्त दायित्व के मद्देनजर, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी भारत की राजभाषा नीति के अनुसार अपने दिन–प्रतिदिन के कार्यालयीन कार्यों में मूल रूप से हिंदी का उपयोग करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन मुख्य सचिवालय में संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में किया गया है जो मुख्य सचिवालय के साथ–साथ इसके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग की निगरानी करता है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं जिसमें मंत्रालय और इसकी मीडिया इकाइयों/संगठनों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की स्थिति पर चर्चा की जाती है और कार्यालयीन कार्यों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए सुझाव दिए जाते हैं जिससे राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किए जाते हैं।

3. मंत्रालय के विभिन्न नियमित तथा कैबिनेट नोट, संसद प्रश्न और स्थायी समिति आदि से संबंधित महत्वपूर्ण समयबद्ध दस्तावेजों के अनुवाद की जरूरतों को पूरा करने के साथ–साथ राजभाषा को लागू करने के लिए, मंत्रालय के मुख्य सचिवालय में एक निदेशक (राजभाषा), एक उप निदेशक (राजभाषा), दो सहायक निदेशक (राजभाषा), दो वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी और दो कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी के पद स्वीकृत हैं।

4. राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के तहत आने वाले सभी कागजातों/दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में जारी करने, हिंदी में प्राप्त और हिंदी में हस्ताक्षर किए गए पत्रों का हिंदी में ही जवाब देना सुनिश्चित करने के लिए दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारियों को जांच बिंदु बनाया गया हैं। इसके अलावा, मंत्रालय और इसकी मीडिया इकाइयों के विभिन्न अनुभागों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा की जाती है ताकि राजभाषा नीति का बेहतर अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

5. प्रेरणा और प्रोत्साहन के माध्यम से कार्यालयीन कार्यों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए, विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गईं। इस संबंध में, 11 जून 2019 को मंत्रालय में 'गूगल वॉइस टाइपिंग' पर एक कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें 104 अधिकारियों ने भाग लिया। इसके अलावा, 13 से 27 सितंबर, 2019 तक मंत्रालय में हिंदी पखवाड़े का भी आयोजन किया गया। पखवाड़े के दौरान i) निबंध लेखन, ii) कविता पाठ, iii) टिप्पणी और आलेखन, iv) श्रुतलेख, v) अनुवाद, vi) हिंदी का ज्ञान और राजभाषा संबंधी प्रश्नोत्तरी, vii) टाइपिंग, viii) स्टेनोग्राफी और ix) वाद–विवाद जैसी नौ प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिसमें 86 अधिकारियों ने भाग लिया। उक्त विभिन्न प्रतियोगिताओं के पुरस्कार विजेताओं को एक समारोह में नकद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा।

6. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, मूल रूप से हिंदी में टिप्पणी और आलेखन तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए दो प्रोत्साहन योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार और प्रमाण–पत्र से सम्मानित किया जाएगा। मंत्रालय की मीडिया

इकाइयों और अनुभागों के लिए एक नई प्रोत्साहन योजना भी शुरू की गई है। इस योजना में, विजेता मीडिया प्रमुखों और मंत्रालय के अनुभागों को उनके कार्यालयीन कार्यों में हिंदी के प्रयोग से संबंधित वार्षिक कार्यनिष्पादन के आधार पर पुरस्कार/ट्रॉफी प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। कार्यालयीन कार्यों में हिंदी के प्रयोग को सुगम बनाने के लिए, संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में भी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें, हिंदी कार्यशालाएं, हिंदी पखवाड़ा और अन्य विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती हैं।

27 नवंबर, 2019 को पणजी, गोवा में 50वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह (इफ्फी, 2019) का विहंगम दृश्य

इफ्फी के 50वें संस्करण में विश्व सिनेमा से 50 महिला फिल्म निर्माताओं की 50 फिल्मों का प्रदर्शन

11

महिला कल्याण संबंधी गतिविधियां

- राष्ट्रीय महिला आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार महिलाओं के लिए चल रही विकास योजनाओं के कार्यान्वयन की देखरेख करने के लिए मंत्रालय ने 1992 में एक विशेष महिला सेल का गठन किया था। बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य मामले में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार 16 मई, 2002 को इस सेल को पुनर्गठित किया गया जिसके अंतर्गत इसे कार्यस्थलों पर यौन शोषण से जुड़े मामलों की शिकायत समिति के अधिकार दिए गए। 13 जनवरी, 2006 को वाईडब्ल्यूसीए से एक बाह्य विशेषज्ञ को महिला सेल के गैर–आधिकारिक सदस्य के तौर पर शामिल किया गया।

- बाद को, सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों और राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिशों के आधार पर 25.10.2013 को महिला सेल का नाम बदलकर 'आंतरिक शिकायत समिति' कर दिया गया था।

- पिछली बार 13.06.2019 को सर्कुलर नं. बी–11020/17/2011–एडमिन–III (खंड–II) के आधार पर समिति का पुनर्गठन किया गया था। सुश्री अंजु निगम, संयुक्त सचिव (बी), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को आईसीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इसके अलावा, सुश्री कल्पना डेविड, राष्ट्रीय सचिव प्रशासन को भारत की वाईडब्ल्यूसीए की ओर से समिति की गैर–आधिकारिक सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया। मंत्रालय की तीन अन्य महिला सदस्य एवं एक पुरुष सदस्य समिति के आधिकारिक सदस्य होते हैं।

- आंतरिक शिकायत समितियां भी मंत्रालय से संबंधित/अधीन एवं स्वायत्त इकाइयों के तौर पर कार्यरत हैं। समय–समय पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन शोषण से जुड़ी घटनाओं की रोकथाम के लिए केंद्रीय लोक सेवा (संहिता) नियम, 1964 द्वारा जारी दिशानिर्देशों को मंत्रालय द्वारा विमर्श हेतु सभी मीडिया इकाइयों को प्रेषित किया जाता है।

28 अक्टूबर, 2019 को नई दिल्ली में ''सतर्कता जागरूकता सप्ताह'' के अवसर पर मंत्रालय के अधिकारियों को 'सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाते हुए श्री अमित खरे, भूतपूर्व सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

12 सतर्कता संबंधी मामले

मंत्रालय का सतर्कता विभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव की समग्र देखरेख में काम करता है। मंत्रालय के सतर्कता विभाग की कमान संयुक्त सचिव स्तर के एक प्रमुख सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के पास होती है जिनकी नियुक्ति केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की अनुशंसा से मंत्रालय के एक ब्यूरो प्रमुख में से की जाती है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सीवीओ के अधीन एक निदेशक (सतर्कता), एक सह-सचिव (सतर्कता) एवं सतर्कता विभाग होता है। मंत्रालय का सीवीओ मंत्रालय एवं उसके अधीन/संबंधित कार्यालय तथा सीवीसी के साथ-साथ सीबीआई के बीच की कड़ी का कार्य करता है। मंत्रालय के अधीन/संबंधित और स्वायत्त कार्यालयों में, सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों और पंजीकृत सोसाइटियों में भी, पृथक सतर्कता विभाग होते हैं। मंत्रालय का सीवीओ संबंधित एवं अधीनस्थ कार्यालयों, मंत्रालय की सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों में सीवीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार सतर्कता गतिविधियों का संचालन करता है।

2. भ्रष्टाचार के मामलों में कमी लाने के लिए संयुक्त प्रयास किए गए हैं। संवेदनशील पदों पर कर्मचारियों का समयोचित तबादले के प्रयास भी किए जाते हैं। नियमों एवं पद्धतियों के सुचारू संचालन के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित एवं औचक निरीक्षण भी किया जाता है। 1 अप्रैल, 2019 से 31 दिसंबर, 2019 तक, 35 नियमित एवं 16 औचक निरीक्षण किए गए। वहीं विभिन्न मीडिया इकाइयों एवं मंत्रालय के मुख्य सचिवालय में निगरानी के अधीन रखे जाने के लिए 16 क्षेत्रों एवं 56 व्यक्तियों को सूचीबद्ध किया गया। 28 अक्टूबर से 2 नवंबर, 2019 तक, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय एवं उसकी मीडिया इकाइयों द्वारा एक सप्ताह तक सतर्कता जागरुकता सप्ताह का आयोजन किया गया।

3. 1 अप्रैल, 2019 से 31 दिसंबर, 2019 तक मंत्रालय एवं उसकी मीडिया इकाइयों को विभिन्न स्रोतों के माध्यम से 257 नई शिकायतें प्राप्त हुईं। इन शिकायतों की जांच हुई और इनमें से 25 मामलों में शुरुआती जांच के आदेश दिए गए। इसके अलावा, इस दौरान 23 मामलों (नए एवं पुराने) से जुड़ी शुरुआती रिपोर्ट भी प्राप्त की गई। इनमें से 04 मामलों में निर्धारित विभागीय कार्रवाई के अंतर्गत बड़ा जुर्माना एवं 08 मामलों में छोटे जुर्माने की शुरुआत की गई। इस दौरान 06 मामलों में बड़ा एवं 16 मामलों में छोटे जुर्माने की सजा तय की गई। इसी दौरान 17 मामलों में प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत प्रशासनिक कार्रवाई और 1 अधिकारी को प्रासंगिक नियमन प्रावधानों के आधार पर समयपूर्व सेवानिवृत्त कर दिया गया।

31 मई, 2019 को नई दिल्ली में प्रभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से मुखातिब केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर

13 नागरिक चार्टर और शिकायत निवारण तंत्र

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का 'नागरिक/उपभोक्ता' घोषणा-पत्र मंत्रालय की वेबसाइट http://www.mib.gov.in पर मौजूद है। मंत्रालय द्वारा अपने साझीदारों को दी जाने वाली निम्न 12 प्रमुख सेवाएं घोषणा-पत्र में शामिल की गई हैं :

(i) भावी लाइसेंस धारक को डीटीएच सेवाओं के लिए लाइसेंस वितरित करना ;

(ii) मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स को लाइसेंस वितरित करना ;

(iii) भावी लाइसेंस धारक को एचआईटीएस सेवाओं के लिए लाइसेंस वितरित करना ;

(iv) भारत में टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स (टीआरपी) एजेंसियों का पंजीकरण ;

(v) अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग के लिए टीवी चैनलों द्वारा टेलिपोर्ट्स की स्थापना ;

(vi) भारत से अपलिंक्ड किए गए टीवी चैनलों के लिए अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग के लिए मंजूरी प्रदान करना ;

(vii) विदेशों से अपलिंक्ड टीवी चैनलों को डाउनलिंकिंग की मंजूरी प्रदान करना ;

(viii) गैर-सरकारी संस्थाओं (एनजीओ), शिक्षण संस्थानों और कृषि विज्ञान केंद्रों/संस्थानों के लिए सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सीआरएस) की स्थापना ;

(ix) विदेशी पत्रिकाओं/जर्नलों/नियतकालिक पत्रों/नई पत्रिकाओं को विशेष/तकनीकी/वैज्ञानिक श्रेणी में प्रकाशन के लिए विदेशी पूंजी निवेश प्राप्त संस्थाओं को स्वीकृति-पत्र वितरित करना ;

(x) समाचार और समसामयिक घटनाओं/समाचार-पत्रों के भारतीय संस्करण प्रकाशित करने वाली विदेशी पत्रिकाओं की अधिकार प्राप्त संस्थाओं को मंजूरी-पत्र प्रदान करना जिनके पास विदेशी निवेश होने/न होने के बावजूद विदेशी समाचार-पत्र के विदेशी निवेश/प्रतिलिपि संस्करण हैं ;

(xi) शिकायत निवारण तंत्र ; और

(xii) टीवी/सिनेमा और रियलिटी शो/कमर्शियल टीवी धारावाहिक बनाने वाले विदेशी निर्माताओं को स्वीकृति-पत्र प्रदान करना।

शिकायत निवारण तंत्र

मंत्रालय को प्राप्त होने वाली शिकायत याचिकाओं को कंप्यूटरीकृत केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) में पंजीकृत कर संसाधित किया जाता है। प्राप्त सभी याचिकाओं को नियमों के अनुसार स्वीकार किया जाता है और पावती सूचना में शिकायत संख्या, उसके निपटान का अनुमानित समय और जांचकर्ता का संपर्क ब्योरा लिखा होता है। शिकायत याचिकाएं संबंधित मीडिया इकाइयों/दफ्तरों/विभागों को शिकायत पर कार्य करने हेतु भेजी जाती हैं, साथ ही, नियमों के अनुसार शिकायतकर्ता को उचित उत्तर भी भेजा जाता है। इन याचिकाओं पर निरंतर कार्य होता है जिसके अंतर्गत संबंधित विभागों/प्रखंडों को स्मरण-पत्र भेजना और समीक्षात्मक बैठकें आदि करना शामिल होता है। मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी मीडिया यूनिटों, संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कम-से-कम एक कनिष्ठ प्रशासनिक दर्जे के अधिकारी को उस इकाई का लोक शिकायत अधिकारी नियुक्त किया जाता है। महत्वपूर्ण और अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों में, संबंधित मीडिया इकाइयों/कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारी मामले के निपटान के संबंध में बात कर सकते हैं। याचिकाओं पर अंतिम निर्णय को याचिकाकर्ता को डाक या सीपीजीआरएएमएस के जरिए भेजा जाता है।

जन शिकायतों के निपटान के लिए जन शिकायत/कार्यकारी तंत्र को दिशानिर्देश प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग आदि से प्राप्त होते हैं जिन्हें मंत्रालय के तत्वावधान में कार्य कर रही सभी मीडिया इकाइयों/स्वायत्त निकायों आदि को वितरित किया जाता है। जन शिकायतों के निवारण को मंत्रालय के सबसे शीर्ष स्तर पर और मासिक 'प्रगति' बैठकों में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भी देखा जाता है।

शिकायत निवारण के लिए प्रस्तावित समय सीमा

क्रम संख्या	विषय	समय
1.	शिकायतकर्ता को प्राप्ति/अंतरिम उत्तर जारी करना	3 दिन
2.	संबंधित प्रशासनिक खंड/उत्तरदायी केंद्र तक शिकायत याचिका स्थानांतरण में लगने वाला समय	7 दिन
3.	शिकायतकर्ता से शिकायत प्राप्ति या स्पष्टीकरण/अतिरिक्त सूचना, जो भी बाद में प्राप्त हो, की तिथि के बाद उसको दिए जाने वाले अंतिम उत्तर में लगने वाला समय।	2 माह

01-04-2019 से 06-11-2019 तक मंत्रालय की शिकायत स्थिति

01/04/2019 तक प्राप्त	प्राप्त शिकायतें (01/04/2019 से 06/11/2019 तक)	कुल शिकायतें	शिकायत निपटान (01/04/2019 से 06/11/2019 तक)	लंबित शिकायतें 06/11/2019 तक
1029	6009	7038	6489	549

मंत्रालय को प्राप्त अधिकांश शिकायतें निम्न श्रेणियों में होती हैं

क्रम संख्या	शिकायत श्रेणी	01-04-2019 से 06-11-2019 तक प्राप्त शिकायतों की दर
1	डीटीएच ऑपरेटरों एलसीओ/एमएसओ के खिलाफ शिकायतें	45%
2	अन्य मंत्रालयों के विषय में याचिकाएं	19%
3	मिश्रित	7%
4	सलाह एवं प्रश्न	5%
5	विषय-समाचार एवं गैर-समाचार कार्यक्रम प्रसारण	5%
6	पेंशन मामले-पेंशन एवं अन्य भत्तों के निर्गमन में विलंब	4%
7	भ्रष्टाचार एवं कदाचार	2%
8	सेवा मामले-अस्थायी कर्मचारी	2%
9	सेवा मामले-स्थायी कर्मचारी	2%
10	प्रेस-पत्रकारिता मामले	2%
11	फ़िल्म विषयक मामले	1%
12	प्रसारण विषय-विज्ञापन	1%
13	पंजीकरण और शीर्षक सत्यापन	1%
14	प्रेस-विषयक मामले	1%
15	पेंशन मामले - पेंशन की गलत स्थिरता	1%
16	सदस्यता/प्रकाशन विभाग की पत्रिकाओं का प्रकाशन	0.4%
17	सदाशयी नियुक्तियां	0.4%
18	पेंशन मामले-पेंशन का पुनःनिर्धारण	0.4%
19	शोषण और दुर्व्यवहार	0.3%
20	विज्ञापन और प्रचार मामले	0.1%
21	यौन शोषण	0.0%

14 अक्टूबर, 2019 को नई दिल्ली में पुस्तक का लोकार्पण करते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर

15 नवंबर, 2019 को आल इंडिया रेडियो के नए प्रसारण ऑडिटोरियम में प्रसार भारती के अभिलेखों से 'गुरबानी' और 'शबद कीर्तन' का डिजिटल स्वरूप में लोकार्पण करते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, सूचना एवं प्रसारण और भारी उद्यम और लोक उपक्रम मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर। इस अवसर पर केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्यमंत्री श्री बाबुल सुप्रियो एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे

14 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित मामले

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम 2005, प्रत्येक नागरिक को, जन प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले लोकहित से जुड़े मामलों से संबंधित सूचना प्राप्त करने की सुविधा देती है ताकि प्रशासनिक कार्यों में खुलेपन, पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रोत्साहन दिया जा सके। यानी ऐसे मामलों में जो सीधे आमजन से संबंधित या प्रासंगिक हों। सूचना के अधिकार का अर्थ है, इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसी सूचना प्राप्ति जो किसी लोक प्राधिकरण के अधीन हो और इसमें निम्न अधिकार निहित हों –

1. कार्य, दस्तावेज एवं रिकॉर्डों का निरीक्षण ;
2. दस्तावेजों या रिकॉर्डों से नोट, उद्धरण या आधिकारिक प्रतियां प्राप्त करना ;
3. कार्य की प्रमाणीकृत बानगियां प्राप्त करना ;
4. यदि सूचना कंप्यूटर या किसी अन्य उपकरण में मौजूद है तो उसे सीडी या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक विधि अथवा प्रिंट से प्राप्त करना।

मुख्य सचिवालय में आरटीआई अधिनियम का कार्यान्वयन :

मंत्रालय के आरटीआई सेल की स्थापना 4 जुलाई, 1997 को सरकारी कामकाज को अधिक पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाने के आदेश के बाद हुई थी।

आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मंत्रालय, उसके संबंधित कार्यालयों, अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों एवं स्वायत्त निकायों से संबंधित सभी प्रार्थना पत्र, अपीलें और निर्णय आरटीआई सेल के पास पहुंचती हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जारी अपीलों पर निर्णय लेने और सूचना उपलब्ध कराने के लिए 29 सीपीआईओ एवं 21 अपीलीय प्राधिकरणों (एए) की स्थापना की है। सीपीआईओ और अपीलीय प्राधिकरणों की सूची मंत्रालय की वेबसाइट https://www.mib.gov.in पर उपलब्ध है।

वर्ष के दौरान प्राप्त आरटीआई आवेदन एवं अपीलें तथा उन पर की गई कार्रवाई का ब्योरा आगे दिया गया है :

वर्ष	प्राप्त आवेदन एवं अपीलें तथा की गई कार्रवाई
2016	2034
2017	1733
2018	1580

01.01.2019 से 11.11.2019 तक आरटीआई सेल में 1,136 आवेदन–पत्र एवं 95 अपीलें प्राप्त की गई थीं और सभी आवेदनकर्ताओं को उचित जवाब दिया गया। अप्रैल 2013 को https://rtionline.gov.in नामक वेब पोर्टल का शुभारंभ किया गया। एमआईबी को 675 ऑनलाइन आवेदन और 68 अपीलें प्राप्त हुई थी। डाक के जरिए प्राप्त होने वाले आरटीआई आवेदनों को भी आरटीआई वेब पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। 01.01.2019 से 11.11.2019 के अरसे के दौरान आवेदन शुल्क/सूचना शुल्क/निरीक्षण शुल्क के तौर पर 7,440 रुपये प्राप्त हुए थे। इसके अलावा, आरटीआई सेल देश के विभिन्न राज्यों के आगंतुकों से प्राप्त आरटीआई संबंधित प्रश्नों को भी देखता है।

आरटीआई सेल संस्थान के उपभोक्ताओं/ग्राहकों को निम्न सेवाएं भी प्रदान करता है :

(क) ब्रॉशरों, फोल्डरों के माध्यम से संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं और सहयोगी कार्यक्रमों, योजनाओं तथा प्रासंगिक नियमों और कार्यविधियों से जुड़ी सूचना प्रदान करना ;

(ख) ग्राहकों/उपभोक्ताओं को संस्थान की सेवाओं का त्वरित, समयोचित, सुचारू तथा पारदर्शी तरीके से लाभ उठाने में सहयोग प्रदान करना तथा जन इस्तेमाल के लिए फॉर्म आदि उपलब्ध कराना ;

(ग) संस्थान द्वारा विकसित सेवा तथा समय से जुड़े गुणवत्ता मानक संबंधित सूचना जो संस्थान की सेवाओं/योजनाओं/कार्यप्रणाली से संबद्ध होती है ; और

(घ) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत एक सूचना पुस्तिका को संशोधित किया गया था।

आरटीआई आवेदनों के निपटान की प्रक्रिया

आरटीआई के अंतर्गत प्राप्त सभी आवेदनों की जांच की जाती है और जो आवेदन इस मंत्रालय से संबंधित नहीं होते हैं, उन्हें संबंधित मंत्रालय के सीपीआईओ को भेज दिया जाता है और शेष आवेदन मंत्रालय के संबंधित सीपीआईओ को अग्रेषित कर दिए जाते हैं।

लंबित आवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए मौजूदा व्यवस्था के अनुसार सीपीआईओ को अनुस्मारक भेजे जाते हैं ताकि आवेदक को 30 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर सूचना प्रदान करने में कोई त्रुटि न हो जाए।

आरटीआई पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आरटीआई आवेदनों और अपीलों को मंत्रालय के संबंधित सीपीआईओ/एए को ऑनलाइन अग्रेषित कर दिया जाता है। सभी सीपीआईओ और एए को आवेदनों/अपीलों की स्थिति का पता लगाने और ऑनलाइन जवाबों को भेजने के लिए उन्हें यूज़र नेम और पासवर्ड दिए जाते हैं।

आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 4 का कार्यान्वयन

मंत्रालय ने धारा 4(ख)(i) और 4(ख)(ii) के अंतर्गत सभी दायित्वों, जो जन प्राधिकरण के पास मौजूद सभी सूचना को स्वतः प्रकट करने से संबंधित थे, पूरा कर लिया है और उन्हें अपनी वेबसाइट के जरिए आमजन के लिए अपलोड भी कर दिया है। आरटीआई आवेदन, अपीलें और उनके उत्तरों को मंत्रालय द्वारा वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। प्राप्त किए गए, अस्वीकृत किए गए, स्थानांतरित किए गए आवेदनों/अपीलों के आंकड़ों को दर्शाने वाली तिमाही रिपोर्टें सीआईसी की वेबसाइट पर नियमित रूप से अपलोड की जाती हैं।

मंत्रालय के संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में आरटीआई अधिनियम का कार्यान्वयन

मंत्रालय के अंतर्गत सभी संबद्ध/अधीनस्थ/पीएसओ तथा स्वायत्त निकायों द्वारा सीपीआईओ और अपील प्राधिकारियों की नियुक्ति की गई है। ये सभी डीओपीटी द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी निदेशों के अनुसार काम कर रहे हैं।

05 सितम्बर, 2019 को एशिया पैसिफिक प्रसारण संघ के महासचिव श्री जावेद मोताघी केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात करते हुए

16 सितम्बर, 2019 को नई दिल्ली में एक समारोह में दूरदर्शन के 60वें स्थापना दिवस को यादगार बनाने हेतु विशेष रूप से डिजाइन किए गए डाक टिकट का लोकार्पण करते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर

15 लेखांकन और आंतरिक लेखा परीक्षा

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का लेखा संगठन

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव, मुख्य लेखा अधिकारी के तौर पर मुख्य लेखा नियंत्रक और वित्तीय सलाहकार की सहायता से अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं।

2. जीएफआर 2017, के नियम 70 के अनुसार मंत्रालय/विभाग के सचिव, जो मंत्रालय/विभाग के मुख्य लेखा अधिकारी हैं–

   i. अपने मंत्रालय या विभाग के वित्तीय प्रबंधन के लिए जिम्मेदार और उत्तरदायी होंगे।

   ii. यह सुनिश्चित करेंगे कि मंत्रालय को विनियोजित सार्वजानिक निधियों का उपयोग जिस उद्देश्य के लिए वह आवांटित हैं के लिए किया जाता है।

   iii. संबंधित मंत्रालय के उक्त परियोजना उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रदर्शन मानकों का पालन करते हुए मंत्रालय के संसाधनों का प्रभावी, कुशल, किफायती और पारदर्शी उपयोग के लिए जिम्मेदार रहेंगे।

   iv. लोक लेखा समिति तथा अन्य संसदीय समिति के समक्ष निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे।

   v. अधोलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति निर्धारित करने के लिए अपने मंत्रालय को सौंपे गए कार्यक्रमों और परियोजनाओं के प्रदर्शन की नियमित समीक्षा और निगरानी करेंगे।

   vi. वित्त मंत्रालय द्वारा जारी नियमों, दिशा-निर्देशों या हिदायतों के अनुसार अपने मंत्रालय से संबंधित व्यय और अन्य विवरण की तैयारी के लिए जिम्मेदार रहेंगे।

   vii. यह सुनिश्चित करेंगे कि उनका मंत्रालय वित्तीय लेन-देन का पूर्ण और उचित रिकॉर्ड रखता है और प्रणालियों और प्रक्रियाओं को ग्रहण करता है जो हर समय आंतरिक नियंत्रण रखते हैं।

   viii. यह सुनिश्चित करेंगे कि उनका मंत्रालय कार्यों के निष्पादन, साथ ही साथ सेवाओं और आपूर्ति की खरीद के लिए सरकारी खरीद प्रक्रिया का पालन करता है और इसे निष्पक्ष, न्यायसंगत, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और लागत मूल्य पर लागू करता है।

   ix. यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी और उपयुक्त कदम उठायेंगे कि उनका मंत्रालय/विभाग :

      (ए) सरकार के लिये सभी देय राशि एकत्रित करता है; और

      (बी) अनाधिकृत, अनियमित और व्यर्थ व्यय से बचता है।

3. नागरिक लेखा नियमावली के अनुच्छेद 1.3. के अनुसार, मुख्य लेखा नियंत्रक की ओर से मुख्य लेखा अधिकारी जिम्मेदार हैं:

   क) वेतन और लेखा कार्यालयों/प्रधान लेखा कार्यालय के माध्यम से सभी भुगतानों को व्यवस्थित करने उसके आलावा, जहां आहरण और वितरण अधिकारी निश्चित तरह के भुगतान करने के लिए अधिकृत हैं।

   ख) मंत्रालय/विभाग के खातों का संकलन और एकत्रीकरण और निर्धारित प्रारूप में उनको लेखा महानियंत्रक को प्रस्तुत करने, अपने मंत्रालय/विभाग के लिये अनुदान की मांग के लिये वार्षिक विनियोग खाते तैयार करने, और उन्हें मुख्य लेखा प्राधिकरण द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित करवाकर लेखा-परीक्षण और सीजीए को विधिवत प्रस्तुत करना।

   ग) विभाग की विभिन्न अधीनस्थ संरचनाओं द्वारा वेतन एवं लेखा कार्यालयों के भुगतान और खातों के अभिलेखों के आंतरिक निरीक्षण की व्यवस्था करना और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बनाए गए सरकारी मंत्रालयों/विभागों के लेन-देन से संबंधित अभिलेखों का निरीक्षण करना।

4. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का मुख्य लेखा नियंत्रक अपने कर्तव्यों को नियंत्रक/उपनियंत्रक/सहायक लेखा नियंत्रक, 03 प्रा. मुख्यालय में लेखा अधिकारी और चौदह वेतन और लेखा कार्यालयों की सहायता से, जिनमें जीपीएफ/पेंशन के उद्देश्य से प्रसार भारती के साथ संलग्न 06 कार्यालय भी शामिल हैं। जोनल आंतरिक लेखा परीक्षा दल चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और नई दिल्ली में तैनात किए गए हैं, जिनके कार्यों को मुख्यालय में आंतरिक लेखा परीक्षा विंग द्वारा मॉनिटर किया जा रहा है।

5. सिविल लेखा नियमावली के पैरा 1.2.3 के अनुसार, मुख्यालय के प्रधान लेखा कार्यालय में एक प्रधान लेखा अधिकारी की जिम्मेदारियां निम्नलिखित हैं:

क) सीजीए द्वारा निर्धारित तरीके से मंत्रालय/विभाग के खातों का संचयन;

ख) मंत्रालय/विभाग द्वारा नियंत्रित अनुदानों की मांगों के वार्षिक विनियोग खातों की तैयारी, केंद्रीय लेन-देन का विवरण प्रस्तुत करना और नियंत्रक महालेखाकार को केंद्र सरकार (नागरिक) के वित्त खाते के लिए सामग्री उपलब्ध कराना;

ग) भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से राज्य सरकार को ऋण और अनुदान का भुगतान और जहां भी इस कार्यालय का कोई आहरण खाता है, केंद्र शासित प्रदेश सरकार/प्रशासनों को भुगतान करना;

घ) प्रबंधन लेखा प्रणाली के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैनुअल तैयार करना और वेतन और लेखा कार्यालयों को तकनीकी सलाह प्रदान करने के लिए, सीजीए के कार्यालय के साथ आवश्यक संपर्क बनाए रखना और लेखांकन मामलों में समग्र समन्वय और नियंत्रण को प्रभावित करना;

ङ) मंत्रालय/विभाग द्वारा संचालित विभिन्न अनुदानों के तहत व्यय की प्रगति को देखने के लिए मंत्रालय/विभाग के लिए समग्र रूप से विनियोग लेखा परीक्षा रजिस्टर बनाना;

प्रधान लेखा कार्यालय/अधिकारी लेखा संगठन के सभी प्रशासनिक और समन्वय कार्य भी करते हैं और आवश्यक वित्तीय, तकनीकी, लेखांकन सलाह को विभाग के साथ-साथ स्थानीय वेतन और लेखा कार्यालयों और आउट स्टेशन पे एंड एकाउंट्स कार्यालयों को प्रदान करते हैं।

6. लोक लेखा मैनुअल के नियमानुसार सभी वेतन और लेखा कार्यालय संबंधित मंत्रालय/विभाग के भुगतान करते हैं और विशेष परिस्थितियों में अधिकृत विभागीय आहरण और भुगतान अधिकारी भी उक्त मंत्रालय/विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त बैंक की शाखाओं/कार्यालयों से आहरित किए जा सकने योग्य चेकों द्वारा भुगतान करते हैं। ये भुगतान संबंधित मंत्रालय/विभाग के वेतन और लेखा कार्यालय में पृथक श्रेणी में उल्लिखित किए जाते हैं।

प्रत्येक वेतन और लेखा कार्यालय अथवा आहरण और भुगतान अधिकारी जो चेक द्वारा अथवा ई-भुगतान के लिए अधिकृत हैं वे केवल उसी मान्यताप्राप्त बैंक के शाखा विशेष द्वारा ही आहरण करेंगे जोकि संबंधित वेतन और लेखा कार्यालय अथवा आहरण और वितरण अधिकारी से संबद्ध/अधिसूचित है। इसके मुख्य कार्यों में शामिल हैं:

- नॉन-चेक ड्राइंग डीडीओ द्वारा प्रस्तुत ऋण और अनुदान सहायता सहित सभी बिलों की पूर्व जांच और भुगतान।
- निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुरूप निधारित समय पर उपयुक्त भुगतान।
- प्राप्तियों की समय पर वसूली।
- चेक आहरण करने वाले डीडीओ के लिए त्रैमासिक साख पत्र जारी करना एवं अपने वाउचरों और बिलों की जांच करना।
- प्राप्तियों और व्यय के मासिक खातों का संचयन करके चेक आहरण डीडीओ खातों के साथ उन्हें शामिल करना।
- एकीकृत किए गए डीडीओ और सेवानिवृत्ति लाभों के प्राधिकरण के अलावा जीपीएफ खातों का रखरखाव।
- सभी डीडीआर प्रमुखों का रखरखाव।
- बैंकिंग व्यवस्था की ई-भुगतान शैली के माध्यम से मंत्रालय/विभाग को कुशल सेवा प्रदान करना।
- निर्धारित लेखा मानकों, नियमों और सिद्धांतों का पालन।
- समय पर, सटीक, व्यापक, प्रासंगिक और उपयोगी वित्तीय रिपोर्टिंग।

7. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संबंध में विभागीय लेखा संगठन की समग्र जिम्मेदारियां हैं:-

- मंत्रालय के मासिक खातों का एकीकरण और उसे सीजीए को प्रस्तुत करना।
- वार्षिक विनियोग खाते
- केंद्रीय लेन-देन का विवरण
- 'एक नजर में खाता' की तैयारी
- केंद्रीय वित्त खाते जो सीजीए, वित्त मंत्रालय और लेखा परीक्षण के प्रमुख निदेशक को प्रस्तुत किए जाते हैं।
- अनुदान संस्थाओं और स्वायत्त निकायों को अनुदान सहायता प्रदान करना

- यदि आवश्यक हो तो डीओपीटी, वित्त मंत्रालय और सीजीए आदि जैसे अन्य संगठनों के साथ परामर्श करके; सभी पीएओ और मंत्रालय को तकनीकी सलाह प्रदान करना।
- प्राप्ति बजट की तैयारी
- पेंशन बजट की तैयारी
- वेतन एवं लेखा कार्यालय/चेक आहरण डीडीओ की ओर से चेक बुक प्राप्त करना और आपूर्ति करना।
- लेखांकन मामलों और मान्यता प्राप्त बैंक में समग्र समन्वय और नियंत्रण को प्रभावी करने के लिए लेखा कार्यालय के नियंत्रक जनरल के साथ आवश्यक संपर्क बनाए रखना।
- मान्यताप्राप्त बैंक भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से किए गए सभी प्राप्तियों और भुगतान को सत्यापित करना।
- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से संबंधित खातों को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ बनाए रखना और नकदी शेष राशि का मिलान करना।
- शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करना।
- पेंशन/भविष्य निधि और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का त्वरित समाधान।
- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन मंत्रालय, अधीनस्थ और संबद्ध कार्यालयों और उसके अनुदेयी संस्थाएं, स्वायत्त निकाय आदि का आंतरिक लेखा परीक्षण।
- सभी संबंधित प्राधिकरणों/प्रभागों को लेखांकन जानकारी उपलब्ध कराना।
- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का बजट समन्वय कार्य।
- समय-समय पर नई पेंशन योजना की निगरानी और पेंशन मामलों का संशोधन।
- लेखा और ई-भुगतान का कंप्यूटरीकरण।
- लेखा संगठन के प्रशासनिक और समन्वय कार्य।
- केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं के तहत अनुदेयी संस्थानों सहित पीएफएमएस का रोल आउट।
- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में गैर-कर प्राप्ति पोर्टल(एनटीआरपी)।

8. प्रभावी बजटीय और वित्तीय नियंत्रण की सुविधा के लिए वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा प्राधिकरण को लेखांकन जानकारी और डेटा भी प्रदान किया जाता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुदान के विभिन्न उप-प्रमुखों/विषय-प्रमुखों के तहत मासिक और प्रगतिशील व्यय के आंकड़ें, संयुक्त सचिव सहित मंत्रालय के बजट अनुभाग से मीडिया प्रभाग को प्रदत्त बजट प्रावधानों के तहत किए गए खर्च की प्रगति भी सचिव और अपर-सचिव तथा वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय की बेहतर निगरानी के प्रयोजनों के लिए अनुदान को नियंत्रित करने वाले सचिव और वित्तीय सलाहकार और मंत्रालय के प्रमुखों को सप्ताहवार प्रस्तुत की जाती है।

9. लेखा संगठन मंत्रालय के कर्मचारियों के हाउस बिल्डिंग एडवांस, मोटर कार एडवांस और जीपीएफ खातों जैसे लंबी अवधि के अग्रिमों के खातों को भी बनाए रखता है।

10. अधिकारियों और कर्मचारियों के पेंशन अधिकारों के सत्यापन और प्राधिकरण का भुगतान वेतन और लेखा कार्यालयों द्वारा सेवा विशेष और पेंशन कार्यालयों के आधार पर किया जाता है। सभी सेवानिवृत्ति लाभ और भुगतान जैसे- ग्रेच्युटी, छुट्टियों के वेतन के साथ-साथ केंद्र सरकार के कर्मचारी समूह बीमा योजना के तहत भुगतान; डीडीओ से प्रासंगिक जानकारी/बिल प्राप्त होने पर वेतन और लेखा कार्यालयों द्वारा सामान्य भविष्य निधि आदि जारी किए जाते हैं।

आंतरिक लेखा परीक्षण खंड

क. आंतरिक लेखा परीक्षण खंड मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों के खातों के लेखा-परीक्षा का काम करता है वह सुनिश्चित करता है कि इन ऑफिसों में नियमों, विनियमों और प्रक्रियाओं को दिन-प्रतिदिन के कामकाज में पालन किया जाए। आंतरिक ऑडिटिंग एक स्वतंत्र गतिविधि है जिसका मूल उद्देश्य मूल्यांकन के लिए एक व्यवस्थित, अनुशासित दृष्टिकोण लेकर अपने उद्देश्यों को पूरा करना और जोखिम प्रबंधन, नियंत्रण और प्रशासन प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता में सुधार लाने में संगठन की मदद करना है।

यह मूल्य संवर्धन एवं प्रभावी बदलाव से युक्त एवं प्रशासन के विकास का विश्वास और सलाह देने के साथ ही, जोखिम प्रबंधन, नियंत्रण उपायों और बेहतर जवाबदेही सुनिश्चित करता है। इसके साथ ही यह प्रक्रियात्मक गलतियों/कमियों के सुधार हेतु बहुमूल्य जानकारी भी प्रदान करते हुए प्रबंधन, के लिए मददगार

साबित होता है। किसी विभाग/अनुभाग के लेखा की बारंबारता उसकी प्रकृति, कार्य के प्रकार और अनुदान की मात्रा पर निर्भर करता है।

ख. मुख्य लेखा अधिकारी और वित्तीय सलाहकार के समग्र मार्गदर्शन के तहत काम कर रहे आंतरिक लेखा परीक्षण खंड ने एक प्रभावी और आंतरिक लेखा परीक्षा अभ्यास को सुनिश्चित करने के लिए उचित तरीके से प्रशासन संरचनाओं, क्षमता निर्माण और तकनीक को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया है।

ग. लेखा विभाग के महा लेखाधिकारी का पालन करते हुए, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, ओएम नं. जी. 25014/33/2015-16/एमएफ सीजीए आईएडी/306-53 दिनांक- 15.05.17 और ओ/ओ सीजीए द्वारा जारी जेनेरिक इंटरनल ऑडिट मैनुअल (संस्करण 1.0) में निहित प्रावधानों के अनुसार, ऑडिट समिति का गठन एएस एंड एफए (आई-बी) के सचिव (आई-बी) और आंतरिक लेखा परीक्षा समिति की शर्तों के संदर्भ तहत इस मंत्रालय ओ/ओ सीसीए ओएम सं. प्रधान एओ/आई-बी/आईडब्ल्यू (मुख्यालय)/एन जेड/17-18/1016-1065 दिनांक 27.07.2017 में परिभाषित किया गया है।

घ. मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाइयों के तहत पूरे भारत में 620 इकाइयां (प्रसार भारती-552 और गैर-प्रसार भारती-68) स्थित हैं, जो देश की लंबाई और चौड़ाई में फैली हुई हैं, जो आंतरिक लेखा परीक्षा के पूर्वावलोकन में आती हैं।

ड. वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, 303 चिन्हित इकाइयों में से 59 कार्यालयों का ऑडिट किया गया। ऑडिट का मकसद 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण का पता लगाना था। वर्ष 2017-18 के दौरान एक सौ छासठ (166) पैरा (संदर्भ) जुटाए गए।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और प्रसार भारती में 31 मार्च, 2019 को उत्कृष्ट आंतरिक लेखा परीक्षा की उपलब्धता की स्थिति नीचे दी जा रही है:-

I. प्रसार भारती					
क्षेत्र	**31.03.2019 तक बकाया पैरा**	**01.04.2019 से 31.10.19 पैरा बढ़ाया गया**	**31.10.19 तक कुल बकाया पैरा**	**01.04.19 से 31.10.19 के दौरान हटाये गए पैरा**	**31.10.2019 को कुल बकाया पैरा**
दक्षिणी क्षेत्र (चेन्नई)	708	51	759	43	716
पश्चिमी क्षेत्र (मुंबई)	93	0	93	0	93
उत्तरी क्षेत्र (दिल्ली)	197	9	206	8	198
पूर्वी क्षेत्र (कोलकाता)	334	28	362	27	335
कुल (I)	**1332**	**88**	**1420**	**78**	**1342**
II. गैर प्रसार भारती					
क्षेत्र	**31.03.2019 तक बकाया पैरा**	**01.04.2019 से 31.10.19 तक पैरा बढ़ाया गया**	**31.10.19 तक कुल बकाया पैरा**	**01.04.19 से 31.10.19 के दौरान हटाये गए पैरा**	**31.10.2019 को कुल बकाया पैरा**
दक्षिणी क्षेत्र (चेन्नई)	603	19	22	149	473
पश्चिमी क्षेत्र (मुंबई)	440	30	0	0	70
उत्तरी क्षेत्र (दिल्ली)	434	39	3	32	41
पूर्वी क्षेत्र (कोलकाता)	300	55	55	46	309
कुल (II)	**1777**	**143**	**1920**	**227**	**1693**
कुल योग (I + II)	**3109**	**231**	**3340**	**305**	**3035**

आईआरएलए (व्यक्तिगत क्रियाशील लेजर लेखा प्रणाली)

वेतन एवं लेखा कार्यालय (आईआरएलए) अन्य मंत्रालयों के अन्य विभागीय वेतन एवं लेखा कार्यालयों के साथ अस्तित्व में आया है। आईआरएलए प्रणाली (समूह–ए अधिकारियों के लिए व्यक्तिगत क्रियाशील लेजर लेखा) का विचार एक केंद्रीय प्रणाली में सभी सेवा और भुगतान विवरण रखने से उत्पन्न हुआ ताकि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और प्रसार भारती के मीडिया इकाइयों के अधिकारी, जिनके पास एक अखिल भारतीय हस्तांतरण देयता है, अपना वेतन सरलतापूर्वक निकाल सकते हैं। वेतन एवं लेखा कार्यालय (आईआरएलए) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाइयों की सेवा और वेतन रिकॉर्ड और देशभर में विभिन्न शहरों में स्थित प्रसार भारती (दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो) के कार्यालयों का रखरखाव कर रहा है। पीएओ (आईआरएलए) ने एक नई वेबसाइट (https://iis.mib.gov.in/irla/) के लॉन्च के साथ डिजिटल प्लेटफार्म पर ऑन–बोर्ड किया गया है, जिसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के एनआईसी प्रकोष्ठ के परामर्श से विकसित किया गया है । .यह समूह–क अधिकारियों को ऑनलाइन सेवाएं जैसे कि सैलरी स्लिप, इनकम टैक्स फॉर्म–16 और जीपीएफ स्टेटमेंट आदि प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। आने वाले समय में इस वेबसाइट पर और अधिक ऑनलाइन सेवाओं को जोड़ने पर भी विचार किया जा रहा है।

बैंकिंग व्यवस्था

भारतीय स्टेट बैंक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में पीएओ और उसके क्षेत्र कार्यालयों के लिए मान्यता प्राप्त बैंक है। पीएओ/सीडीडीओ द्वारा जारी चेक भुगतान के लिए मान्यता प्राप्त बैंक की नामित शाखा को प्रस्तुत किए जाते हैं। गैर–कर–रसीद पोर्टल (एनटीआरपी) के अलावा संबंधित पीएओ/सीडीडीओ द्वारा मान्यता प्राप्त बैंकों को भी रसीदें दी जाती हैं। मान्यता प्राप्त बैंक में किसी भी बदलाव के लिए वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग, लेखा महानियंत्रक की विशेष स्वीकृति की आवश्यकता होती है।

प्रधान लेखा कार्यालय में प्रसार भारती से जुड़े 06 पीएओ सहित 14 (चौदह) वेतन और लेखा कार्यालय हैं। पांच पीएओ नई दिल्ली में, दो प्रत्येक मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में और एक–एक नागपुर, लखनऊ और गुवाहाटी में स्थित हैं। विभाग/मंत्रालय से संबंधित सभी भुगतान पीएओ/सीडीडीओ के माध्यम से संबंधित पीएओ के साथ किए जाते हैं। आहरण और संवितरण अधिकारी नामित पीएओ/सीडीडीओ को उनके दावे/बिल पेश करते हैं, जो समय समय पर सिविल लेखा नियमावली, रसीद और भुगतान नियमों और सरकार द्वारा जारी किए गए अन्य आदेशों के अनुसार आवश्यक जांच के बाद ई–भुगतान जारी करते हैं।

खातों का कंप्यूटरीकरण

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के विभागीय लेखा संगठन में खातों के कंप्यूटरीकरण की प्रक्रिया वित्त मंत्रालय के लेखा/महालेखाकार द्वारा लेखा समारोह के कंप्यूटरीकरण के साथ शुरू हुई। प्रिंसिपल लेखा कार्यालयों में मासिक खातों के एकत्रीकरण के लिए 'कांटेक्ट' नाम के सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। इस मंत्रालय में सभी पीएओ ने वाउचर स्तर पर इंप्रूव कंप्यूटरीकरण का उपयोग किया। प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा ऑनलाइन स्वीकृति के साथ विवरण के माध्यम से पुट के पीएओ वार समायोजन के बाद नवंबर, 2008 के महीने से मासिक खाते को ओ/ओ सीजीए के लिए प्रस्तुत किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल जैसे विंडो आधारित एप्लिकेशन का उपयोग शीर्षवार विनियोग खातों की तैयारी, केंद्रीय सरकार के वित्त खाते की सामग्री (सिविल) और मंत्रालय को प्रस्तुत करने के लिए मासिक व्यय और रसीद विवरणों के लिए भी किया जाता है।

कॉम्पेक्ट (वेतन और लेखा 2000)

मौजूदा इंप्रूव सॉफ्टवेयर को बदलने के लिए वेतन और लेखा कार्यालय स्तर पर उपयोग के लिए एक बहु उपयोगी सॉफ्टवेयर शामिल किया गया था। यह सॉफ्टवेयर सभी वेतन और लेखा कार्यालयों में कार्य का कंप्यूटरीकरण करने की दृष्टि से विकसित किया गया था। इस सॉफ्टवेयर में निम्नलिखित विशेषताएं थीं:–

1. पूर्व–जांच (एकीकृत भुगतान और लेखा कार्य और स्वचालित चेक मुद्रण)
2. इलेक्ट्रॉनिक बैंक पुनर्समाधान
3. सामान्य भविष्य निधि
4. खातों का संकलन
5. पेंशन मामलों का निपटान
6. व्यय बनाम बजट नियंत्रण

ई–पेमेंट उपक्रम

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सभी वेतन और लेखा कार्यालयों में ई–भुगतान प्रणाली 2011 से सफलतापूर्वक लागू की गई थी।

ई–पेमेंट प्रणाली

चूंकि, आईटी अधिनियम, 2000 डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेजों या डिजिटल तरीके से प्रमाणित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डों अथवा अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों

के अनुरूप ऐसे दस्तावेजों अथवा रिकॉर्डों को प्रमाणित/सत्यापित करता है, इसलिए खातों के नियंत्रक जनरल ने डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित इलेक्ट्रॉनिक परामर्श के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान (ई-भुगतान) करने के लिए कॉम्पेक्ट में एक सुविधा विकसित की थी जिसने भुगतान की मौजूदा प्रणाली को बदल दिया।

विकसित ई-भुगतान प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सेवाओं की एक पूरी तरह से सुरक्षित वेब आधारित प्रणाली थी जो सरकारी भुगतान प्रणाली में पारदर्शिता का परिचय देती है। इस प्रणाली के अंतर्गत देय राशि का भुगतान सरकार द्वारा धनराशि के क्रेडिट कॉम्पेक्ट से प्राप्त डिजिटल स्वामित्व वाली ई-परामर्श के माध्यम से एक सुरक्षित संचार चैनल पर 'सरकारी ई-भुगतान गेटवे (जीईपीजी)' द्वारा सीधे प्राप्तकर्ता के बैंक खाते में किया जाता था। इसे समाप्त करने के लिए आवश्यक कार्यात्मक और सुरक्षा प्रमाण-पत्र एस टीक्यूसी निदेशालय से प्राप्त किए गए थे। सभी केंद्र सरकार के सिविल मंत्रालयों/विभागों में इस प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया था।

जीईपीजी को आगे पीएफएमएस प्रणाली में अपग्रेड किया गया है, जो अनुमोदन की तैयारी, बिल प्रसंस्करण, भुगतान, रसीद प्रबंधन, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, निधि प्रवाह प्रबंधन और वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए खातों के नियंत्रक जनरल की एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली है।

डिजिटल हस्ताक्षर का पंजीकरणः वेतन और लेखा अधिकारी एनआईसी प्रमाणकर्ता प्राधिकरण से डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त करता है। एनआईसी प्रमाणकर्ता प्राधिकरण से प्राप्त डिजिटल हस्ताक्षर एक यूएसबी टोकन में स्टोर किए जाते हैं जिसे आई-की कहा जाता है। पीएओ संबंधित मंत्रालय/विभाग के प्रधान लेखा कार्यालय के माध्यम से पीएफएमएस पोर्टल के साथ डिजिटल हस्ताक्षर पंजीकृत करता है। संबंधित बैंक पीएफएमएस पोर्टल से पीएओ डिजिटल हस्ताक्षर डाउनलोड करते हैं। बैंकों द्वारा पीएओ को प्रदान किए गए ई-भुगतान स्क्रॉल के प्रमाणीकरण के लिए संबंधित बैंकों के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के डिजिटल हस्ताक्षर भी पीएफएमएस पोर्टल पर अपलोड किए जाते हैं।

बिल जमा करनाः आहरण और संवितरण अधिकारी (डीडीओ) ई-भुगतान के लिए बिल के साथ भुगतानकर्ता का अधिकृतपत्र और अनिवार्य विवरण जैसे कि बैंक शाखा का आईएफएससी कोड खाता नंबर, नाम, पता आदि वेतन और लेखा अधिकारी (पीएओ) के पास जमा करता है। उस समय कॉम्पेक्ट से एक टोकन नंबर प्राप्त होता है जो डीडीओ को सूचित किया जाता है।

बिल बनाने का कामः वेतन और लेखा कार्यालय के कम्पैक्ट सिस्टम में बिल बनाने का काम किया जाता है।

डिजिटल हस्ताक्षरः पीएओ द्वारा बिल पास होने के बाद, आई-की का उपयोग करके यह सुरक्षित रूप से हस्ताक्षरित होता है और सिस्टम द्वारा ई-भुगतान प्राधिकरण तैयार किया जाता है।

पीएफएमएस पर अधिकार-पत्र अपलोड करनाः ई-भुगतान प्राधिकरण फ़ाइल (ई-परामर्श) पीएफएमएस पर सुरक्षित वातावरण में अपलोड की जाती है। संबंधित बैंक पीएफएमएस से ई-परामर्श डाउनलोड करते हैं और डिजिटल हस्ताक्षर आदि के आवश्यक सत्यापन के बाद, बैंक लाभार्थियों के खाते को सीबीएस/एनईएफटी/आरटीजीएस का उपयोग करते हुए लागू करते हैं।

ई-स्क्रॉल्सः सभी सफल ई-भुगतानों के लिए बैंक द्वारा जेपीजीपी पर एक डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित इलेक्ट्रॉनिक स्क्रॉल जनरेट और अपलोड किया जाता है। पुनर्समाधान और अन्य एमआईएस प्रयोजनों के लिए पीओएस द्वारा ई-स्क्रॉल डाउनलोड किए जाते हैं और कॉम्पैक्ट सिस्टम में शामिल किए जाते हैं।

ई-भुगतान के फायदे

- डिजिटली हस्ताक्षरित विशिष्ट ई-प्राधिकरण आईडी का उपयोग करके ऑनलाइन निधि ट्रांसफर के कारण समय और मेहनत की बचत।
- भुगतान का सुरक्षित तरीका।
- भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता।
- भौतिक चेकों और उनके मैनुअल संचालन का उन्मूलन।
- प्राप्तकर्ता द्वारा बैंक खाते में चेक के मैनुअल जमा करने की बाधाओं का उन्मूलन।
- समग्र भुगतान प्रसंस्करण दक्षता में वृद्धि।
- भुगतानों का ऑनलाइन स्वतः-मिलान।
- खातों का कुशल संकलन।
- सभी स्तरों पर लेन-देन का पूरा लेखा सत्यापन।

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) शुरुआत में 2008-09 में तत्कालीन योजना आयोग की सीपीएसएमएस नामक योजना व्यवस्था के रूप में शुरू की गई। यह योजना पायलट योजना के रूप में चार राज्य मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब और मिजोरम में चार फ्लैगशिप योजनाओं जैसे एमजीएनआरईजीएस, एनआरएचएम, एसएसए और पीएमजीएसवाई के लिए एक पायलट (मार्गदर्शक) योजना,

के रूप में शुरू की गई। मंत्रालयों/विभागों में एक नेटवर्क स्थापित करने के प्रारंभिक चरण के बाद, केंद्र, राज्य सरकारों और राज्य सरकारों की एजेंसियों के वित्तीय नेटवर्क को जोड़ने के लिए सीपीएसएमएस (पीएफएमएस) का राष्ट्रीय रोल-आउट करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना को भूतपूर्व योजना आयोग एवं वित्त मंत्रालय के तत्वावधान में 12वीं योजना के नवाचार प्रयोग के रूप में शामिल किया गया। वर्तमान में पीएफएमएस, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की योजना है और महालेखा नियंत्रक अधिकारी के आदेशानुसार पूरे देश में लागू की गई है।

2. एमओएफ, डीओआई ओएम नंबर 66 (29) पीफ-II/2016 दिनांक 15/07/2016 के अनुसार, माननीय प्रधानमंत्री ने केंद्रीय योजना कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में बेहतर वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि पैसा निर्धारित समय पर जारी हो और समय-समय पर योजनाओं के धन के उपयोग और उनकी सूचना प्रणाली (पीएफएमएस) व्यय विभाग में महालेख नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्रशासित किया जाता है जो प्रसंस्करण भुगतान, ट्रैकिंग, निगरानी, लेखा, सुलह और रिपोर्टिंग के लिए एक अनंतिम समाधान है। यह योजना प्रबंधकों को रिलीज के ट्रैकिंग और उनके अनंतिम उपयोग की निगरानी के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करता है।

3. जस्ट-इन-टाइम रिलीज़ को लागू करने और फंड के अंतिम उपयोग की निगरानी के निर्देशों का पालन करने के लिए, वित्त मंत्रालय द्वारा केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत सभी लेनदेन/भुगतानों को कवर करने के लिए पीएफएमएस के उपयोग को सार्वभौमिक बनाने का निर्णय लिया गया है। इन योजनाओं की पूरी निगरानी के लिए पीएफएमएस पर सभी कार्यान्वयन एजेंसियों (आईएएस) के अनिवार्य पंजीकरण और इनके द्वारा पीएफएमएस के व्यय, अग्रिम और हस्तांतरण (ईएटी) मॉड्यूल का अनिवार्य उपयोग आवश्यक है। कार्यान्वयन योजना में केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं का पूरा ब्रह्मांड शामिल है, जिसके लिए अंतर-मंत्रालयी स्तर पर प्रत्येक मंत्रालय/विभाग द्वारा निम्नलिखित कदम उठाने की आवश्यकता है:

   (i) सभी केंद्रीय योजनाओं का खाका तैयार करने/आकार देने और पीएफएमएस प्लेटफॉर्म पर लाया जाना है।

   (ii) धनराशि प्राप्त करने और उसका उपयोग करने वाली सभी कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) को पीएफएमएस पर अनिवार्य रूप से पंजीकृत होना चाहिए।

   (iii) सभी पंजीकृत एजेंसियों को भुगतान, अग्रिम और स्थानान्तरण करने के लिए पीएफएमएस मॉड्यूल का उपयोग अनिवार्य किया जाना है।

   (iv) केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के संबंध में व्यय करने वाली सभी विभागीय एजेंसियों को रजिस्टर करना होगा और अनिवार्य रूप से पीएफएमएस मॉड्यूल का उपयोग करना होगा।

   (v) केंद्रीय सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाली सभी संस्थाओं भुगतान/स्थानांतरण/अग्रिम करने के लिए पीएफएमएस मॉड्यूल अपनाना होता है। ऐसा करने पर वे केंद्र सरकार से फंड लेने के लिए उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकेंगी।

   (vi) मंत्रालय को अपने संबंधित सिस्टम/एप्लिकेशन को पीएफएमएस के साथ एकीकृत करने के लिए कदम उठाना होगा।

आदेश-पत्र लागू करने के लिए मॉड्यूल

केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के अनुसार हितधारकों के लिए पीएफएमएस द्वारा विकसित/अविकसित मॉड्यूल निम्नानुसार हैं:

I. कोष प्रवाह की निगरानी

- एजेंसी पंजीकरण
- पीएफएमएस ईएटी मॉड्यूल के माध्यम से व्यय प्रबंधन और फंड का उपयोग
- पंजीकृत एजेंसियों के लिए लेखांकन मॉड्यूल
- ट्रेजरी इंटरफ़ेस
- पीएफएमएस-पीआरआई फंड प्रवाह और उपयोग इंटरफ़ेस
- राज्य योजनाओं के फंड ट्रैकिंग के लिए राज्य सरकारों के लिए क्रियाविधि
- बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की निगरानी (ईएपी)

II. प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) मॉड्यूल

- पीएओ से लाभार्थी
- एजेंसी से लाभार्थी
- राज्य कोष से लाभार्थी

III. बैंकिंग के लिए इंटरफेस

- सीबीएस (कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस)
- इंडिया पोस्ट
- आरबीआई (भारतीय रिजर्व बैंक)
- नाबार्ड और सहकारी बैंक

संवर्धित आदेश–पत्र लागू करने के लिए मॉड्यूल

1. पीएओ कंप्यूटरीकरण–ऑनलाइन भुगतान, भारत सरकार की प्राप्तियां और सरकार का लेखा।
   - प्रोग्राम डिवीजन मॉड्यूल
   - डीडीओ मॉड्यूल
   - पीएओ मॉड्यूल
   - पेंशन मॉड्यूल
   - जीपीएफ और एचआर मॉड्यूल
   - जीएसटीएन सहित रसीदें
   - वार्षिक वित्तीय विवरण
   - नकदी प्रवाह प्रबंधन
   - गैर–नागरिक मंत्रालयों के साथ इंटरफेस
2. गैर–कर रसीद पोर्टल।

अन्य विभागीय पहल

पीएफएमएस की क्षमता का लाभ उठाने के लिए, कई अन्य विभागों ने अपने विभागों के लिए आवश्यकतानुसार उपयोगिताओं का लाभ लेने के लिए पीएफएमएस से संपर्क किया हैः–

(i) एफसीआरए के तहत फंड प्राप्त करने वाली एजेंसियों की निगरानी के लिए एमएचए (फॉरेनर्स डिवीजन) की निगरानी

(ii) सीबीडीटी पैन सत्यापन

(iii) जीएसटीएन बैंक खाता सत्यापन

कार्यान्वयन रणनीति

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के चरणबद्ध कार्यान्वयन के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा एक कार्ययोजना तैयार और अनुमोदित की गई है।

बेहतर वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से

- जस्ट इन टाइम में (जेआईटी) धनराशि जारी
- अंतिम उपयोग सहित निधियों के उपयोग की निगरानी

रणनीति

- पीएफएमएस का सार्वभौमिक रोल–आउट जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ शामिल है–
- पीएफएमएस पर सभी कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) का अनिवार्य पंजीकरण और
- सभी आईएएस द्वारा पीएफएमएस के अग्रिम व्यय और अंतरण (ईएटी) मॉड्यूल का अनिवार्य उपयोग।

I. केंद्रीय क्षेत्र (सीएस) की योजनाओं/लेनदेन के लिए कार्यान्वयन रणनीति

जिन गतिविधियों को पूरा करना हैः

- आईए द्वारा अनिवार्य पंजीकरण और ईएटी मॉड्यूल का उपयोग
- योजनाओं की सभी प्रासंगिक सूचनाओं का मानचित्रण
- पीएफएमएस पर प्रत्येक योजना का बजट अपलोड करना
- प्रत्येक योजना के कार्यान्वयन पदानुक्रम की पहचान करना
- पीएफएमएस के साथ नरेगासॉफ्ट, आवाससॉफ्ट जैसी विशिष्ट योजनाओं के सिस्टम इंटरफेस का एकीकरण
- प्रशिक्षकों की तैनाती और प्रशिक्षण

II. केंद्रीय सहायक राज्य योजना (सीएएसपी) के लिए कार्यान्वयन रणनीति

राज्यों द्वारा की जाने वाली गतिविधियां

- पीएफएमएस के साथ राज्य खजाना एकीकरण
- (पीएफएमएस) पर सभी एसआईए का पंजीकरण (प्रथम स्तर और नीचे)
- संबंधित केंद्रीय योजनाओं के साथ राज्य योजनाओं का मानचित्रण
- पीएफएमएस पर राज्य योजनाओं का विन्यास
  - राज्य योजनाओं के घटकों का विन्यास करना
  - प्रत्येक राज्य योजना के पदानुक्रम को पहचानें और विन्यास करें
- योजना आधारित सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग के साथ पीएफएमएस का एकीकरण
- प्रशिक्षकों की तैनाती और प्रशिक्षण
- कार्यान्वयन के लिए निरंतर समर्थन

वर्तमान में, सभी चौदह (14) पे एंड एकाउंट्स कार्यालय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जीपीएफ और पेंशन के लिए प्रसार भारती से जुड़े छह (06) पीएओ पीएफएमएस पर सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। सभी भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से किए जाते हैं और ई–भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा किए जाते हैं।

I. पीएफएमएस कर्मचारी सूचना प्रणाली (ईआईएस) मॉड्यूल

यह मॉड्यूल सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सभी आहरण एवं संवितरण कार्यालयों में लागू किया गया है

II. पीएफएमएस का सीडीडीओ मॉड्यूल

पीएफएमएस के सीडीडीओ मॉड्यूल को सभी बीस (20) चेक डिसबर्सिंग सूचना एवं प्रसारण के आधुनिकता वाले कार्यालयों में रोल आउट किया गया है।

III. गैर कर राजस्व की प्राप्ति के लिए ऑनलाइन पोर्टल (भारत कोश)

- गैर–कर प्राप्ति पोर्टल (एनटीआरपी) का उद्देश्य भारत सरकार (जीओआई) को देय गैर–कर राजस्व का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए नागरिकों/कॉरपोरेट/अन्य उपयोगकर्ताओं को एक–स्टॉप विंडो प्रदान करना है।
- भारत सरकार के गैर–कर राजस्व में विभिन्न विभागों/मंत्रालयों द्वारा एकत्रित प्राप्तियों का एक बड़ा समूह शामिल है। मुख्य रूप से ये प्राप्तियां/रसीद लाभांश, ब्याज रसीदें, स्पेक्ट्रम शुल्क, आरटीआई आवेदन शुल्क, छात्रों द्वारा प्रपत्र/पत्रिकाओं की खरीद और नागरिकों/कॉरपोरेट/अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा इस तरह के अन्य भुगतान से आती हैं।
- ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक भुगतान आईटी वातावरण में पूरी तरह से सुरक्षित सुविधा है यह आम लोगों/नागरिकों को ड्राफ्ट बनाने के लिए बैंकों में जाने के कष्ट से बचाता है और फिर सरकारी कार्यालयों में सेवाओं का लाभ उठाने के लिए साधन जमा करने में मदद करता है। यह प्रेषण में परिहार्य देरी को रोकने में भी मदद करता है। सरकारी खातों में उपकरण के साथ–साथ बैंक खातों में इन उपकरणों के विलंबित जमा में अवांछनीय बाधाओं को समाप्त किया जाता है।
- एनटीआरपी ऑनलाइन भुगतान प्रौद्योगिकियों जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड का उपयोग करके पारदर्शी वातावरण में तत्काल भुगतान की सुविधा प्रदान करता है।
- एनटीआर पोर्टल, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से 01 नवंबर, 2016 से कार्यात्मक रहा है।
- 01.04.2019 से 31.10.2019 तक की अवधि के लिए चालू वित्त वर्ष (2019–20) में मंत्रालय के गैर–कर राजस्व का संग्रह ₹591.77 करोड़ है और इसमें से भारतकोश के माध्यम से ₹573.59 (लगभग 95 प्रतिशत) करोड़ का संग्रह केवल एनटीआर ई–पोर्टल द्वारा किया गया है।

IV. पीएफएमएस का व्यय, अग्रिम और स्थानांतरण (ईएटी) मॉड्यूल

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सभी छह (06) स्वायत्त निकाय पीएफएमएस के व्यय अग्रिम हस्तांतरण (ईएटी) मॉड्यूल पर निर्भर हो गए हैं।

मंत्रालय की नई पहलः

1. पीएओ/सीडीडीओ कार्यशाला/सम्मेलन

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पीएओ के कार्य से संबंधित विभिन्न प्रमुख मुद्दों पर विचार–विमर्श हेतु 25 और 26 अप्रैल, 2019 को सूचना भवन, नई दिल्ली में एक कार्यशाला/सेमिनार का आयोजिन किया गया। लेखा मुख्य नियंत्रक ने वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन, बीओसी/पीआईबी जैसे विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए निधि के हस्तांतरण हेतु अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली, स्वीकृति की सूचना देना, आपत्ति पुस्तक (ओबी) में दर्ज की जाने वाली मदें जैसे मामलों पर प्रस्तुतीकरण दिया। तदनुसार, प्रधान एओ (प्रशा.), प्रधान एओ (बीएंडए) तथा प्रधान एओ (आईएडब्ल्यू) से संबंधित कार्यसूची की मदों जैसे, जेम (जीईएम) के माध्यम से खरीद, पेंशन मामलों का पुनरीक्षण, सेवानिवृत्त व्यक्तियों के पेंशन मामलों का निपटारा, सेवा सत्यापन, आरटीआई मामले, एनपीएस की निगरानी, कर्मचारियों का रोटेशनल ट्रांसफर, वेतन और लेखा कार्यालयों द्वारा मासिक खातों को समय पर जमा करना, पीएओ द्वारा प्रधान एओ को समय पर समायोजन प्रमाण पत्र

कार्यशाला की झलक

आंतरिक लेखापरीक्षा संबंधी अंतरक्षेत्रीय कार्यशाला

प्रस्तुत करना, पीएओ द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सस्पेंस (8658–00–108) की मंजूरी, पीएओ के पास मौजूद विभिन्न पीएओ/बकाया सस्पेंस बैलेंस/निष्क्रिय फंडों के खातों के प्रतिकूल शेष, ई–लेखा और पीएफएमएस से असंगत डीडीओ कोड को निष्क्रिय करना, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में पीएफएमएस के विभिन्न मॉड्यूलों की कार्यान्वयन स्थिति तथा वेतन और लेखा कार्यालयों की प्रशिक्षण आवश्यकता, आंतरिक लेखापरीक्षा एवं लेखा परीक्षा रिपोर्टों की गुणवत्ता संबंधी मिशन, लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय–सीमाएं, बकाया ऑडिट पैराग्राफों का अनुपालन, बकाया ऑडिट पैरा का परिसमापन, जोनल आईएपी के त्रैमासिक टूर कार्यक्रम के पूर्वानुमान और वार्षिक समीक्षा पर विस्तार से चर्चा की गई।

2. आंतरिक लेखा परीक्षा संबंधी अंतर क्षेत्रीय कार्यशाला

आंतरिक लेखा परीक्षा की भावी कार्यनीतियों (रोडमैप) और आंतरिक लेखा परीक्षा दलों के कार्यों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए लेखा मुख्य नियंत्रक, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की अध्यक्षता में आंतरिक लेखा परीक्षा की एक दिवसीय अंतर क्षेत्रीय कार्यशाला, पत्र सूचना कार्यालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई। लेखा मुख्य नियंत्रक, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने वार्षिक, द्विवार्षिक और त्रैवार्षिक के संदर्भ में इकाई की लेखा परीक्षा की आवधिकता के लिए बुनियादी मानदंड, समय पर वार्षिक और त्रैमासिक लेखा परीक्षा योजनाओं का पूर्वानुमान लगाना, लेखा परीक्षा रिपोर्टों की गुणवत्ता, लेखा परीक्षा की कार्यप्रणाली और पीएओ की लेखा परीक्षा, लंबे समय तक बकाया लेखा परीक्षा टिप्पणी/टिप्पणियों का परिसमापन आदि जैसी विभिन्न बिंदुओं पर भी अपने विचार व्यक्त किए।

3. हिंदी पखवाड़ा

लेखा मुख्य नियंत्रक का कार्यालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में रोज़मर्रा के कार्यों में हिंदी भाषा के प्रयोग पर विशेष ज़ोर देते हुए सितंबर, 2019 में हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। इस दौरान हिंदी प्रश्नोत्तरी, हिंदी निबंध लेखन, हिंदी वाद–विवाद आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए।

4. सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) में ऑनलाइन भुगतान प्रक्रिया में बढ़ी हुई सुरक्षा परतों का प्रवर्तन

पीएफएमएस प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए, कोष संचालन हेतु निम्नलिखित विशेषताएं लागू की जा रही हैं:

क. वेतन और लेखा कार्यालयों (पीएओ) द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर डालने से पहले बिना वास्तविक बिल के साथ प्रत्येक भुगतान अनुरोध का सत्यापन।

ख. पीएफएमएस के पीएओ और डीडीओ मॉड्यूल पर काम करने वाले अधिकारियों द्वारा उपयोगकर्ता पंजीकरण के लिए एनआईसी/जीओवी डोमेन ई–मेल आईडी का उपयोग।

ग. ऐसे उपयोगकर्ता/उपयोगकर्ताओं को तत्काल निष्क्रिय करना, जो अब सक्रिय नहीं रहे हैं।

घ. स्थायी स्थानांतरण/अधिवर्षिता के समय पीएओ/एएओ उपयोगकर्ता प्रकार की यूजर आईडी/डिजिटल की को निष्क्रिय करना।

ड. पीएफएमएस पर ओटीपी आधारित लॉग इन सिस्टम का चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वयन।

5. देशभर में पेंशन अदालत

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने विभिन्न जगहों पर 23 अगस्त, 2019 को पेंशन अदालतें आयोजित कर इक्कीस (21) मामलों का मौके पर ही निपटान कर दिया।

6. 2016 से पूर्व के पेंशन मामलों में संशोधन

केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप लगभग 26,133 पेंशन मामलों को अंतिम रूप देकर 30.09.2019 तक केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ) को भेज दिया गया है।

मंत्रालय का लेखा संगठन

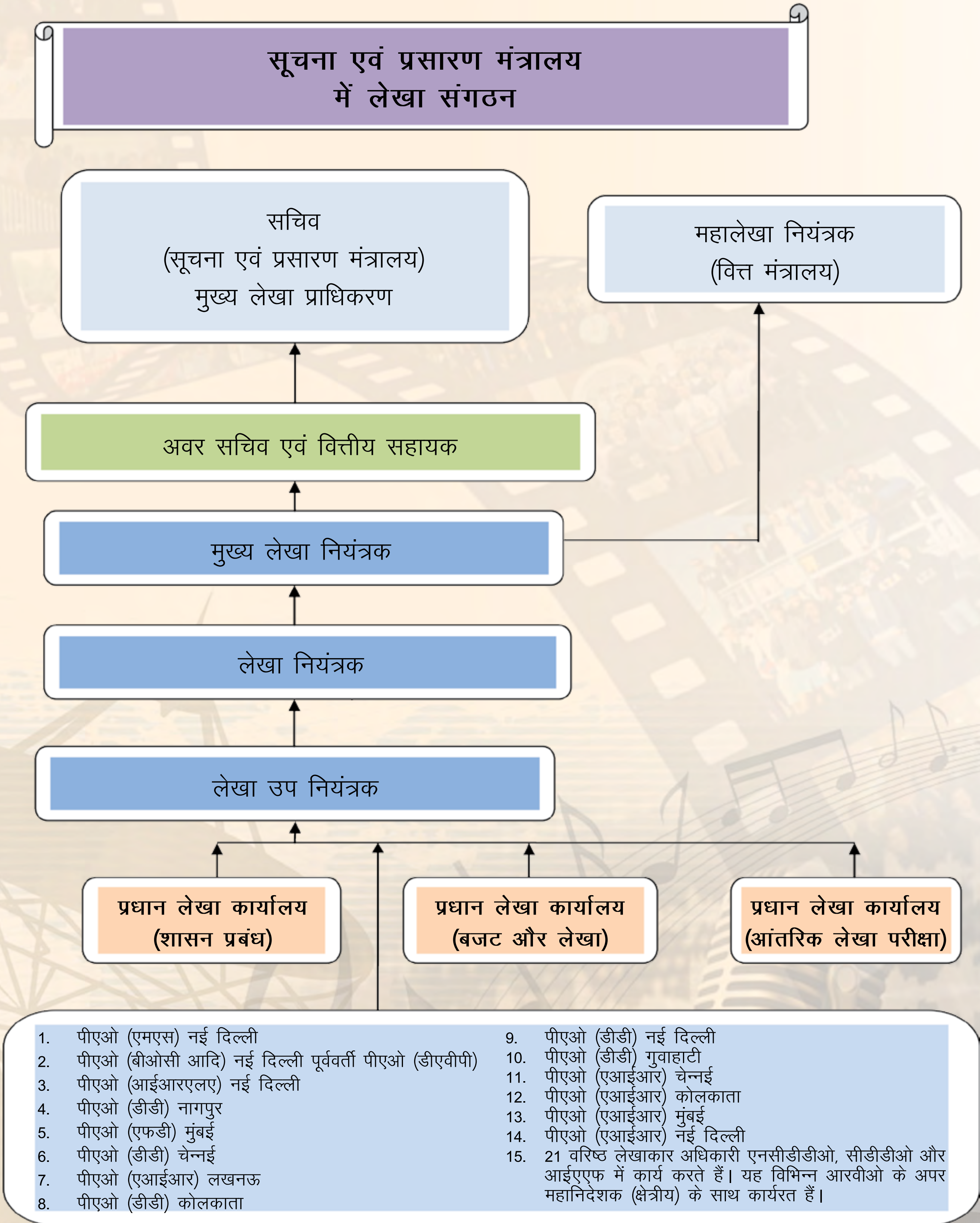

30 अगस्त, 2019 को कोच्चि में मलयाला मनोरमा समाचार सम्मेलन, 2019 में 'न्यू इंडिया : गवर्नमेंट एंड मीडिया' सेशन में भाग लेते केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर

02 नवंबर, 2019 को नई दिल्ली में 50वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह (इफ्फी–2019) के प्रेस कान्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर

16 लेखा पैरा

[क] सीएंडएजी लेखा पैरा-शून्य

[ख] लोक लेखा समिति (पीएसी) सिफारिशें

क्र.सं.	रिपोर्ट सं. और वर्ष	विषय	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से संबंधित सिफारिशों की सं.	की गई कार्रवाई
1.	**74वीं रिपोर्ट (16वीं लोक सभा) 2017**	**19वें कॉमनवेल्थ गेम्स 2010**	**6** (सिफारिश सं. 59-64)	लेखा परीक्षा द्वारा विधिवत् पुनरीक्षित अंतिम एटीआर दिनांक 10.07.2019 को पीएसी को भेज दी गई है। इसे 23.07.2019 को एपीएमएस पोर्टल पर अपलोड किया गया है।
2.	**94वीं रिपोर्ट (16वीं लोक सभा) 2018**	**वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि तक एसआरएफटीआई, कोलकाता के सीबीएफसी के कार्य और शैक्षणिक गतिविधियां**	**14** (सिफारिश सं. 1-7 और 8-14)	**सिफारिश सं. 1-7 (सीबीएफसी)**- लेखा परीक्षा द्वारा विधिवत् पुनरीक्षित अंतिम एटीआर दिनांक 09.11.2018 को पीएसी को भेज दी गई है। इसे 30.11.2018 को एपीएमएस पोर्टल पर अपलोड किया गया है। **सिफारिश सं. 8-14 (एसआरएफटीआई)**- लेखा परीक्षा द्वारा विधिवत् पुनरीक्षित अंतिम एटीआर दिनांक 09.11.2018 को पीएसी को भेज दी गई है। इसे 13.11.2018 को एपीएमएस पोर्टल पर अपलोड किया गया है।
3.	**121वीं रिपोर्ट (16वीं लोक सभा) 2018**	**वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि तक एसआरएफटीआई, कोलकाता के सीबीएफसी के कार्य और शैक्षणिक गतिविधियां**	**6** (सिफारिश सं. 5,8,11,14,17,20)	**सिफारिश सं. 5 और 20 (एसआरएफटीआई)**- लेखा परीक्षा द्वारा विधिवत् पुनरीक्षित अंतिम एटीआर लोक सभा सचिवालय पीएसी शाखा को दिनांक 30.10.2019 को भेज दी गई है। इसे 12.12.2019 को एपीएमएस पोर्टल पर अपलोड किया गया है। **सिफारिश सं. 8,11,14 और 17 (सीबीएफसी)**- लेखा परीक्षा द्वारा विधिवत् पुनरीक्षित अंतिम एटीआर लोक सभा सचिवालय, पीएसी शाखा को दिनांक 03.10.2019 को भेज दी गई है। इसे 15.11.2019 को एपीएमएस पोर्टल पर अपलोड किया गया है।

29 दिसंबर, 2019 को राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द ने राष्ट्रपति भवन में श्री अमिताभ बच्चन को फिल्मों में पांच दशक में उनके बहुमूल्य और उत्कृष्ट योगदान के लिए दादा साहिब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। इस अवसर पर ली गई सामूहिक तस्वीर

17 कैट के फैसलों/आदेशों पर अमल

वर्ष 2018–19 के लिए मंत्रालय के प्रमुख सचिवालय और विभिन्न मीडिया इकाइयों के सीएटी मामलों से संबंधित निर्णयों/आदेशों के कार्यान्वयन संबंधी सूचना निम्न है :

क्रम संख्या	मीडिया इकाइयां	वर्ष 2017–18 के लिए सीएटी से प्राप्त निर्देशों की संख्या	वर्ष 2017–18 के लिए कार्यान्वित निर्णयों/निर्देशों की संख्या
1	प्रमुख सचिवालय*	4	4
2	बीओसी	#	#
3	डीपीडी	0	0
4	पीआईबी	0	0
5	आरएनआई	0	0
6	फोटो विभाग	0	0
7	न्यू मीडिया विंग	0	0
8	पीसीआई	0	0
9	आईआईएमसी	1	1
10	डीजी : एआईआर (सीसीडब्ल्यू सहित)	98	47
11	डीजी : डीडी	22	15
12	बीईसीआईएल	0	0
13	सीबीएफसी	5	3
14	एसआरएफटीआई	1	1
15	एफटीआईआई	#	#
16	फ़िल्म प्रभाग	4	4
17	एनएफडीसी	0	0
18	एनएफएआई	0	0
19	सीएफएसआई	0	0
20	डीएफएफ	#	#
21	पीएओ	0	0
22	ईएमएमसी	0	0
	कुल	**135**	**75**

*प्रमुख सचिवालय से संबंधित सूचना में एमयूसी–II/आईआईएस/टीवी–इनसैट/बीए–ई/बीए–पी/एफ(एफ)/एफ(सी)/एफ(आई) डेस्क्स/सेक्शन्स शामिल नहीं हैं।

01 दिसंबर, 2019 को नई दिल्ली में ''फ्यूचर रोडमैप ऑफ दूरदर्शन नेटवर्क'' पर दूरदर्शन की क्षेत्रीय इकाइयों के प्रमुखों के साथ परिचर्चा करते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, सूचना एवं प्रसारण और भारी उद्यम और लोक उपक्रम मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर

18 योजना परिव्यय

बजट अनुमान (2019–20)

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संबंध में 2019–20 के लिए परिव्यय 900.00 करोड़ रुपये था।

(रु. करोड़ में)

क्र. सं	क्षेत्र	जीबीएस
1	सूचना क्षेत्र	238.00
2	फ़िल्म क्षेत्र	165.00
3	प्रसारण क्षेत्र	497.00
	कुल	**900.00**

2. केंद्रीय क्षेत्र योजना 2019–20 का योजनावार अलग–अलग विवरण संलग्न है।

3. 162.65 करोड़ रुपये के साथ पूर्वोत्तर घटक 900.00 करोड़ रुपये की कुल केंद्रीय क्षेत्र योजना व्यय के 18.17 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है। पूर्वोत्तर घटक का अलग–अलग विवरण निम्न प्रकार है:

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	जीबीएस
1	सूचना क्षेत्र	21.65
2	फ़िल्म क्षेत्र	25.80
3	प्रसारण क्षेत्र	115.20
	कुल	**162.65**

सूचना और प्रसारण मंत्रालय
बजट अनुमान का विवरण 2019–20 (योजनावार)

(रु. करोड़ में)

क्र. सं	योजना का नाम	वित्त मंत्रालय द्वारा अंतिम प्रारूप देने के आधार पर अनुमानित बजट 2019–20	वित्त मंत्रालय द्वारा अंतिम प्रारूप देने के आधार पर अनुमानित बजट 2019–20	वित्त मंत्रालय द्वारा अंतिम प्रारूप देने के आधार पर अनुमानित बजट 2019–20
	सूचना क्षेत्र			
क	**जारी योजनाएं**			
1	अंतरराष्ट्रीय मानकों (रु. करोड़ में) आईआईएमसी आईआईएमसी) के अनुरूप का उन्नयन (आईआईएमसी)	2.00	1.50	00
2	मीडिया आधारभूत ढांचा विकास कार्यक्रम (एमआईडीपी)			
2.1	एमआईडीपी (आईआईएमसी को छोड़ कर)	25.15	21.00	0.05
2.2	आईआईएमसी के नये क्षेत्रीय केंद्र खोलना आईआईएमसी	11.00	9.50	2.00
	कुल – एमआईडीपी	**36.15**	**30.50**	**2.05**
3	विकास संचार और सूचना प्रसार (डीसीआईडी)	**237.77**	**200.00**	**19.60**
4	मानव संसाधन विकास			
4.1	मानव संसाधन के लिए प्रशिक्षण (प्रसार भारती को छोड़कर) (मुख्य सचिवालय)	4.05	4.05	0.00
4.2	अंतरराष्ट्रीय मीडिया कार्यक्रम (मुख्य सचिवालय)	0.15	0.15	0.00
4.3	संबंधी अध्ययन, सेमिनार, मूल्यांकन आदि (मुख्य सचिवालय)	0.65	0.50	0.00

क्र. सं	योजना का नाम	वित्त मंत्रालय द्वारा अंतिम प्रारूप देने के आधार पर अनुमानित बजट 2019–20	वित्त मंत्रालय द्वारा अंतिम प्रारूप देने के आधार पर अनुमानित बजट 2019–20	वित्त मंत्रालय द्वारा अंतिम प्रारूप देने के आधार पर अनुमानित बजट 2019–20
4.4	फ़िल्म मीडिया इकाइयों का मानव संसाधन विकास एफटीआईआई, एमआरएफटीआईआई, सीबीएफसी	0.84	0.80	0.00
4.5	व्यवसायिक सेवाओं के लिए भुगतान	0.53	0.50	0.00
	कुल (एचआरडी)	**6.22**	**6.00**	**0.00**
	कुल जोड़ (सूचना क्षेत्र)	**282.14**	**238.00**	**21.65**
	फ़िल्म क्षेत्र			
5	राष्ट्रीय भारतीय सिनेमा संग्रहालय (एफडी)	0.00	0.00	0.00
6	फ़िल्म क्षेत्र से संबंधित ढांचागत विकास कार्यक्रम			
6.1	सीबीएफसी और प्रमाणन प्रक्रिया का उन्नयन, आधुनिकीकरण और विस्तार (सीबीएफसी)	1.50	2.50	0.00
6.2	सिरीफोर्ट परिसर का उन्नयन (डीएफएफ)	1.00	0.02	0.00
6.3	फ़िल्म प्रभाग के भवन बुनियादी ढांचे का उन्नयन (एफडी)	0.02	0.02	0.00
6.4	जयकर बंगला सहित एनएफएआई के बुनियादी ढांचे का उन्नयन और डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना (एनएफएआई)	3.00	3.00	0.00
6.5	एफटीआईआई के उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए अनुदान सहायता (एफटीआईआई)	26.00	17.00	0.00
6.6	एसआरएफटीआई में बुनियादी ढांचा विकास (एसआरएफटीआई)	50.00	30.00	23.00
	कुल फ़िल्मों से संबंधित मूलभूत विकास कार्यक्रम	**81.52**	**52.54**	**23.00**
7.	**फ़िल्मी सामग्री के जनसंचार का विकास और प्रसार**			
7.1	भारत तथा विदेश में फ़िल्म महोत्सवों और फ़िल्म विक्रय के जरिए भारतीय सिनेमा का संवर्धन (मुख्य सचिवालय)	2019–20 के डीसीडीएफसी के योजना के अंतर्गत सिंगल लाइन बजट का निर्णय मंत्रालय ने लिया है।		
7.2	विभिन्न भारतीय भाषाओं में फ़िल्मों और वृत्तचित्रों का निर्माण (मुख्य सचिवालय)			
7.3	फ़िल्म संग्रहालय का बेवकास्टिंग (एफडी)			
7.4	संग्रहणीय फ़िल्म एवं फ़िल्म सामग्री का अधिग्रहण (एनएफएआई)			
7.5	पायरेसी निरोधी पहल (मुख्य सचिवालय)			
	कुल (संचार विकास और फ़िल्म सामग्री प्रसार)	**92.98**	**69.48**	**2.80**
8	राष्ट्रीय फ़िल्म विरासत मिशन (मुख्य सचिवालय)	40.00	22.48	0.00
9	एनिमेशन, गेमिंग और वीएफएक्स के उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना (मुख्य सचिवालय)	40.00	20.50	0.00

क्र. सं	योजना का नाम	वित्त मंत्रालय द्वारा अंतिम प्रारूप देने के आधार पर अनुमानित बजट 2019–20	वित्त मंत्रालय द्वारा अंतिम प्रारूप देने के आधार पर अनुमानित बजट 2019–20	वित्त मंत्रालय द्वारा अंतिम प्रारूप देने के आधार पर अनुमानित बजट 2019–20
	कुल (फिल्म क्षेत्र)	**254.50**	**165.00**	**25.80**
	प्रसार क्षेत्र			
क.	**मुख्य सचिवालय**			
10.	इलेक्टॉनिक मीडिया मॉनटिरिंग सेंटर को मजबूत करना (ईएमएमसी)	17.36	17.30	0.00
11.	भारत में सामुदायिक रेडियो को सहायता (सीआरएस सेल)	4.20	3.80	0.20
12.	मंत्रालय में बुनियादी ढांचा सहायता प्रकोष्ठ का नाम बदलकर डिजिटलीकरण मिशन किया गया (डीएएस) सेक्शन	4.00	2.00	0.00
13.	ब्रॉडकास्टिंग विंग का ऑटोमेशन (बीपी एंड एल) सेक्शन	0.90	0.90	0.00
	कुल (मुख्य सचिवालय)	**26.46**	**24.00**	**0.20**
बी	**प्रसार भारती**			
14.	प्रसार भारती के लिए अनुदान सहायता (प्रसारण के मूलभूत सुविधा का विकास)	347.69	473.00 (2019–20 का बीआईएनडी योजना के तहत सिंगल लाइन बजट का निर्णय मंत्रालय ने लिया है।)	
15.	किसान चैनल के लिए प्रसार भारती को अनुदान सहायता	51.26		
16.	अरुण प्रभा चैनल के लिए प्रसार भारती को अनुदान सहायता	106.00		
	कुल प्रसार भारती	**504.95**	**473.00**	**115.00**
	कुल (प्रसारण क्षेत्र)	**531.41**	**497.00**	**115.20**
	कुल केंद्रीय क्षेत्र योजनाएं	**1068.05**	**900.00**	**162.65**

18 जुलाई, 2019 को नई दिल्ली में 10वें जागरण फिल्म समारोह का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर

19 मीडिया इकाई–वार बजट

मांग सं. 59 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

रु. हजार में

मीडिया इकाई/गतिविधि का नाम	बीई 2019-20	आरई 2019-20	बीई 2020-21
राजस्व अनुभाग			
श्रेणी 1 केंद्र का स्थापना व्यय (गैर–योजना व्यय)			
मुख्य शीर्ष– '2251'– सचिवालय सामाजिक सेवाएं			
मुख्य सचिवालय (पीएओ सहित)	**686800**	**771399**	**888331**
मुख्य शीर्ष– '2205'– कला एवं संस्कृति			
सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए सिनेमैटोग्राफिक फ़िल्मों का प्रमाणन			
फ़िल्म प्रमाणन अपीलीय अधिकरण	4100	4600	4900
केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड	104800	89300	124800
कुल मुख्य शीर्ष '2205'	**108900**	**93900**	**129700**
मुख्य शीर्ष– '2220'– सूचना और प्रचार			
फ़िल्म प्रभाग	529600	479120	535800
भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय	61300	60400	94800
फ़िल्म समारोह निदेशालय	138600	114710	140400
न्यू मीडिया विंग (पूर्व में अनुसंधान, संदर्भ एवं प्रशिक्षण विभाग)	23200	15770	17200
ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्यूनिकेशन (बीओसी)	1817400	1609755	1864700
पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)	893200	879180	996100
भारत के समाचार–पत्रों के पंजीयक	86500	65335	78100
फोटो प्रभाग	0	0	0
प्रकाशन विभाग	398000	340772	443000
रोज़गार समाचार	173781	152060	151650
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर (ईएमएमसी)	11500	8249	182500
संचार विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों को वार्षिक सदस्यता शुल्क का भुगतान (आईपीडीसी)	2100	2100	2100
प्रसारण विकास के लिए एशिया प्रशांत संस्थानों को योगदान (एआईबीडी)	2869	2900	2869
एसोसिएशन ऑफ मूविंग इमेजिस आर्किविस्ट्स को वार्षिक सदस्यता शुल्क का भुगतान (एमएआई)	40	40	40
एनएफएआई द्वारा अंतरराष्ट्रीय संगठनों की सदस्यता के लिए योगदान	210	210	210
निजी एफएम रेडियो स्टेशन	20500	10500	20500
कुल मुख्य शीर्ष '2220'	**4158800**	**3741101**	**4529969**
कुल केंद्र का स्थापना व्यय	**4954500**	**4606400**	**5548000**

रु. हजार में

मीडिया इकाई/गतिविधि का नाम	बीई 2019-20	आरई 2019-20	बीई 2020-21
श्रेणी 2 केंद्रीय क्षेत्र योजनाएं (विशेष व्यय)			
सूचना क्षेत्र			
भारतीय जन–संचार संस्थान (आईआईएमसी) का उन्नयन अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार करना	15000	12900	
आईआईएमसी के नए क्षेत्रीय केंद्र खोलना	95000	124700	
मीडिया बुनियादी ढांचा विकास कार्यक्रम (एमआईडीपी)	210000	235700	
संचार और सूचना प्रसार विकास (डीसीआईडी)	2000000	1876300	2200000
मानव संसाधन विकास	60000	38000	
कुल (सूचना क्षेत्र)	**2380000**	**2287600**	**2200000**
फ़िल्म क्षेत्र			
फ़िल्म क्षेत्र से संबंधित बुनियादी ढांचा विकास कार्यक्रम (आईडीपीएफएस)	681500	656100	
संचार विकास और फ़िल्म सामग्री का प्रसार (*)	538700	633900	1155000
राष्ट्रीय फ़िल्म विरासत मिशन	224800	36100	
चैंपियन सेवा क्षेत्र कार्यक्रम	205000	200	
एनिमेशन, गेमिंग और वीएफएक्स के उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना		5000	300000
कुल (फ़िल्म क्षेत्र) प्रसारण क्षेत्र	**1650000**	**1331300**	**1455000**
भारत में सामुदायिक रेडियो को सहायता	38000	38000	45000
इलेक्टॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर को मजबूत करना (ईएमएमसी)	173000	204000	
मंत्रालय में बुनियादी ढांचा सहायता प्रकोष्ठ का नाम बदलकर डिजिटलीकरण मिशन किया गया।	20000	30000	
ब्रॉडकास्टिंग विंग का ऑटोमेशन	9000	9000	
प्रसारण बुनियादी ढांचा नेटवर्क विकास	4730000	2354000	3700000
कुल (प्रसारण क्षेत्र)	**4970000**	**2635000**	**3745000**
कुल केंद्रीय क्षेत्र योजनाएं	**9000000**	**6253900**	**7400000**
इनमें से एनई आवंटन	**1626500**	**1051500**	**740000**
स्तंभशीर्ष के तहत आवंटन	**135400**	**55200**	**135600**

रु. हजार में			
मीडिया इकाई गतिविधि का नाम	**बीई 2019-20**	**आरई 2019-20**	**बीई 2020-21**
श्रेणी 3 अन्य केंद्रीय व्यय (स्वायत्त निकाय) (गैर–योजना व्यय)			
भारतीय जन–संचार संस्थान (आईआईएमसी) को अनुदान सहायता	264900	256900	613000
भारतीय प्रेस परिषद को अनुदान सहायता (पीसीआई)	74500	90000	89000
भारतीय बाल फ़िल्म सोसायटी (सीएफएसआई) को अनुदान सहायता	39000	39000	39000
भारतीय फ़िल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई) को अनुदान सहायता	328500	308700	494000
सत्यजीत फ़िल्म और टेलीविजन संस्थान, (एसआरएफटीआई) कोलकाता को अनुदान सहायता	197100	199100	675500
प्रसार भारती को अनुदान सहायता	28893600	28893600	28893600
कुल अन्य केंद्रीय व्यय (स्वायत्त निकाय)	**29797600**	**29787300**	**30804100**
कुल मांग सं. 59	**43752100**	**40647600**	**43752100**

28 नवंबर, 2019 को पणजी, गोवा में 50वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह (इफ्फी–2019) के समापन समारोह पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम

20

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का सांगठनिक चार्ट

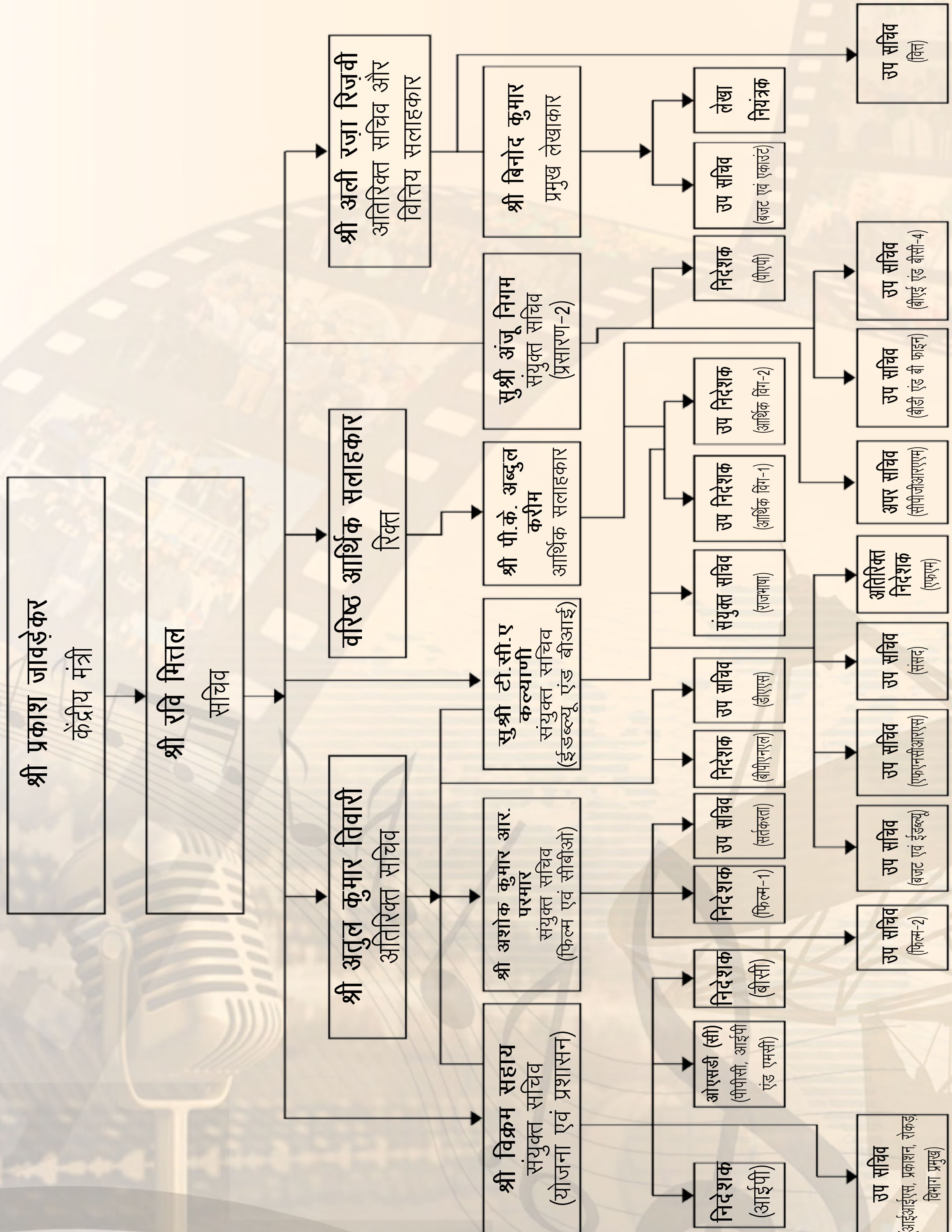

मंत्रालय में पद

सचिव	सचिव
ए.एस	अतिरिक्त सचिव
ए.एस. और एफ.ए	अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार
वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार	वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार
जे. एस. (पी एण्ड ए)	संयुक्त सचिव (नीति और प्रशासन)
जे. एस. (बी–I)	संयुक्त सचिव (प्रसारण – I)
जे. एस. (बी–II)	संयुक्त सचिव (प्रसारण – II)
जे. एस. (एफ)	संयुक्त सचिव (फ़िल्म)
जे. एस. (ईडब्ल्यू)	संयुक्त सचिव (आर्थिक स्कंध)
आर्थिक सलाहकार	आर्थिक सलाहकार
सीसीए	मुख्य लेखा नियंत्रक
निदेशक (आईपी एण्ड एमयूसी)	निदेशक (सूचना नीति और मीडिया इकाई समन्वय)
निदेशक (फ़िल्म – I)	निदेशक (फ़िल्म – I)
निदेशक (फ़िल्म – II)	(फ़िल्म – II)
निदेशक (बीसी)	निदेशक (प्रसारण सामग्री)
निदेशक/संयुक्त निदेशक (ओएल)	निदेशक/संयुक्त निदेशक (राजभाषा)
निदेशक(बीपी एंड एल एंड बीए–पी(I)	निदेशक (प्रसारण, नीति और कानून/प्रसारण प्रशासन कार्यक्रम – I)
निदेशक (वित्त)	निदेशक (वित्त)
निदेशक (बी एण्ड ए) उपसचिव (बीएफए)/(ईए)	निदेशक (बजट और लेखा), उपसचिव (बजट और लेखा), उपसचिव (वित्त प्रभाग)
डीएस (बीडी एण्ड बी वित्त)	उप सचिव (प्रसारण विकास और प्रसारण वित्त)
डीएस (प्रशासन, रोकड़, एच ओ डी)	उप सचिव (प्रशासन, रोकड़, विभागाध्यक्ष)
डीएस (डीएएस)	उप सचिव (डिजिटल एडरेसेबल प्रणाली)
डीएस (एफएम)	उप सचिव (फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन)
डीएस (सतर्कता और संसद)	उप सचिव (सतर्कता और संसद)
डीएस (बीए – ई और बीसी – IV)	उप सचिव (प्रसारण प्रशासन इंजीनियरिंग और प्रसारण, सामग्री–IV)
ओएसडी (सी एण्ड पीपीसी एण्ड आईपी एण्ड एमसी)	ऑफिसर ऑन स्पेशल डयूटी (समन्वय, नीति आयोजन सैल, सूचना नीति और मीडिया समन्वय)
सी. ए	लेखा नियंत्रक
यूएस (प्रशासन I, II, III, IV और एचओओ)	अंडर सचिव (प्रशासन I, II, III, IV) और हैड ऑफ आफिस
यूएस (आईआईएस)	अपर सचिव (भारतीय सूचना सेवा)
यूएस (एमयूसी I)	अपर सचिव (मीडिया इकाई समन्वयन I)
यूएस (एमयूसी II)	अपर सचिव (मीडिया इकाई समन्वयन II)
यूएस (प्रेस)	अपर सचिव (प्रेस)

यूएस (सतर्कता)	अपर सचिव (सतर्कता)
यूएस (रोकड़ और संसद)	अपर सचिव (रोकड़ और संसद)
यूएस (एनएमसी और एनएमडब्ल्यू)	अपर सचिव (न्यू मीडिया प्रकोष्ठ, न्यू मीडिया विंग)
यूएस (पीपीसी एण्ड आईपी एण्ड एमसी)	अपर सचिव (नीति आयोजन प्रकोष्ठ और सूचना नीति और मीडिया समन्वयक)
यूएस (बीसी I, II, III)	अपर सचिव (प्रसारण सामग्री I, II, III)
यूएस (इन्सैट)	अपर सचिव (भारतीय उपग्रह टेलीविजन)
यूएस (डीएएस)	अपर सचिव (डिजिटल एडरेसेबल सिस्टम)
यूएस (बीपी एण्ड एल)	अपर सचिव (प्रसारण, नीति और कानून)
यूएस (बीडी एण्ड बी फिन)	अपर सचिव (प्रसारण विकास और प्रसारण वित्त)
यूएस (बीएपी I)	अपर सचिव (प्रसारण प्रशासन कार्यक्रम I)
यूएस (बीएपी II)	अपर सचिव (प्रसारण प्रशासन कार्यक्रम II)
यूएस (बीए ई)	अपर सचिव (प्रसारण प्रशासन इंजीनियरिंग)
यूएस (बीसी IV)	अपर सचिव (प्रसारण सामग्री IV)
यूएस (एफ I और III)	अपर सचिव (वित्त I और वित्त III)
यूएस (फिन. II)	अपर सचिव (वित्त II)
यूएस (बी एण्ड ए)	अपर सचिव (बजट और लेखा)
यूएस एफ [(एफ) एण्ड एफ (I) I एण्ड एफ (सी)]	अपर सचिव (फ़िल्म समारोह फ़िल्म उद्योग और फ़िल्म प्रमाणन)
यूएस [(एफ(ए) एण्ड एफ (पीएसयू) एण्ड एफ (एफटीआई)]	अपर सचिव (फ़िल्म प्रशासन और फ़िल्म सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम और एफटीआई)
डीडी (ओएल)	उप निदेशक (राजभाषा)
डीडी (ईडब्ल्यू I)	उप निदेशक (आर्थिक प्रकोष्ठ I) और आरटीआई
डीडी (ईडब्ल्यू II)	उप निदेशक (आर्थिक प्रकोष्ठ II)
डीडी (सीआरएस)	उप निदेशक (सामुदायिक रेडियो स्टेशन)
डीसीए	लेखा उप नियंत्रक
ए.डी. (ओएल I)	सहायक निदेशक (राजभाषा I)
ए.डी. (ओएल II)	सहायक निदेशक (राजभाषा II)
एस. ओ. (प्रशा. I)	अनुभाग अधिकारी (प्रशासन I)
एस. ओ. (प्रशा. II)	अनुभाग अधिकारी (प्रशासन II)
एस. ओ. (प्रशा. III)	अनुभाग अधिकारी (प्रशासन III)
एस. ओ. (प्रशा. IV)	अनुभाग अधिकारी (प्रशासन IV)
एस. ओ. (रोकड़)	अनुभाग अधिकारी (रोकड़)
एस. ओ. (संसद)	अनुभाग अधिकारी (संसद)
एस. ओ. (एमयूसी I)	अनुभाग अधिकारी (मीडिया इकाई प्रकोष्ठ I)
एस. ओ. (एमयूसी II)	अनुभाग अधिकारी (मीडिया इकाई प्रकोष्ठ II)

एस. ओ. (सतर्कता)	अनुभाग अधिकारी (सतर्कता)
एस. ओ. (आईपी एण्ड एमसी)	अनुभाग अधिकारी (सूचना नीति और मीडिया समन्वयक)
एस. ओ. (पीपी प्रकोष्ठ)	अनुभाग अधिकारी (नीति आयोजन प्रकोष्ठ)
एस. ओ. (प्रेस)	अनुभाग अधिकारी (प्रेस)
एस. ओ. (आई आई एस)	अनुभाग अधिकारी (भारतीय सूचना सेवा)
एस. ओ. (आई आई एस)	अनुभाग अधिकारी (भारतीय सूचना सेवा))
एस. ओ. एफ (एफ)	अनुभाग अधिकारी (फ़िल्म समारोह)
एस. ओ. एफ. (एफटीआई)	अनुभाग अधिकारी (फ़िल्म [फ़िल्म और टेलीविजन संस्थान])
एस. ओ. एफ. (ए)	अनुभाग अधिकारी (फ़िल्म [प्रशासन])
एस. ओ. (सी)	अनुभाग अधिकारी (फ़िल्म [प्रमाणन])
एस. ओ. (I)	अनुभाग अधिकारी (फ़िल्म [उद्योग])
एस. ओ. एफ. (पीएसयू)	अनुभाग अधिकारी (एफ [पीएसयू फ़िल्म सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों में])
एस. ओ. (बीसी I)	अनुभाग अधिकारी (प्रसारण सामग्री I)
एस. ओ. (बीसी II)	अनुभाग अधिकारी (प्रसारण सामग्री II)
एस. ओ. (बीसी III)	अनुभाग अधिकारी (प्रसारण सामग्री III)
एस. ओ. (बीसी IV)	अनुभाग अधिकारी (प्रसारण सामग्री IV)
एस. ओ. बी (डी)	अनुभाग अधिकारी (प्रसारण सामग्री विकास)
एस. ओ. बी (फिन.)	अनुभाग अधिकारी (प्रसारण वित्त)
एस. ओ. (बीपी एण्ड एल)	अनुभाग अधिकारी (प्रसारण नीति और कानून)
एस. ओ. (बीए पी)	अनुभाग अधिकारी (प्रसारण प्रशासन और कार्यक्रम)
एस. ओ. (बीए ई)	अनुभाग अधिकारी (प्रसारण प्रशासन और इंजीनियरिंग)
एस. ओ. (एफएम प्रकोष्ठ)	अनुभाग अधिकारी (फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन प्रकोष्ठ)
एस. ओ. (सीआरएस प्रकोष्ठ)	अनुभाग अधिकारी (सामुदायिक रेडियो स्टेशन प्रकोष्ठ)
एस. ओ. (इन्सैट टीवी)	अनुभाग अधिकारी (भारतीय उपग्रह टेलीविजन)
एस. ओ. (फिन. I एण्ड III)	अनुभाग अधिकारी (वित्त I और III)
एस. ओ. (फिन. II)	अनुभाग अधिकारी (वित्त II)
एस. ओ. (पीसी प्रकोष्ठ)	अनुभाग अधिकारी (योजना समन्वयन प्रकोष्ठ)
एस. ओ. (बी एण्ड ए)	अनुभाग अधिकारी (बजट और लेखा)
एस. ओ. (पीएमएस)	अनुभाग अधिकारी (निष्पादन प्रबंधन अनुभाग)
एस. ओ. (एनएमसी)	अनुभाग अधिकारी (न्यू मीडिया सेल)
एस. ओ. (आरटीआई)	अनुभाग अधिकारी (सूचना का अधिकार)
पी एण्ड ए ओ	वेतन और लेखा अधिकारी

सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित महत्वपूर्ण वेबसाइट लिंक

संगठन का नाम	वेबसाइट यूआरएल
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	https://mib.gov.in
ब्यूरो ऑफ आउटरीच और संचार	https://davp.nic.in
केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड	https://www.cbfcindia.gov.in
फ़िल्म समारोह निदेशालय	https://dff.nic.in https://iffigoa.org
फ़िल्म डिवीजन	https://filmsdivision.org
भारतीय राष्ट्रीय फ़िल्म संग्रहालय	https://www.nfai.gov.in
न्यू मीडिया विंग	https://mib.gov.in/information/new-media-wing
पत्र सूचना कार्यालय	https://pib.nic.in
प्रकाशन विभाग	https://www.publicationsdivision.nic.in
भारत के समाचार–पत्रों के पंजीयक	https://rni.nic.in
आकाशवाणी	https://allindiaradio.gov.in https://www.newsonair.com
ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कन्सलटेंट इंडिया लि.	https://www.becil.com
भारतीय बाल फ़िल्म समिति	https://www.cfsindia.org
दूरदर्शन	https://doordarshan.gov.in
प्रसार भारती	https://prasarbharti.gov.in
भारतीय फ़िल्म और टेलीविजन संस्थान	https://www.ftiindia.com
फ़िल्म प्रमाणन अपीलीय अधिकरण	https://mib.gov.in/film/film-certification-appellate-tribunal
भारतीय दूरसंचार संस्थान	https://iimc.nic.in
भारतीय फ़िल्म विकास निगम	https://www.nfdcindia.com
भारतीय प्रेस परिषद	https://presscouncil.nic.in
सत्यजित रे फ़िल्म और टेलीविजन संस्थान	https://srfti.ac.in
फ़िल्म सुविधा कार्यालय	https://ffo.gov.in

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के खंड–2 का प्रकाशन रोका जाना

लोकसभा सचिवालय के ओ.एम. संख्या 61/2/ईसी/2009 दिनांक 18.12.2009 द्वारा सूचित संसदीय प्राक्कलन समिति की अनुशंसाओं के अनुसरण में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के खंड–2 का प्रकाशन वर्ष 2009–10 से बंद कर दिया गया है।

हालांकि यह मंत्रालय की वेबसाइट **www.mib.gov.in** या **www.mib.nic.in** पर उसी प्रारूप में उपलब्ध है, जैसे कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के खंड–2 में पहले प्रकाशित किया जाता था।

प्रिंटर्स: जेके ऑफसेट ग्राफिक्स, नई दिल्ली